



# भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

[राजस्थान तथा अन्य विश्वविद्यालयों के बी० एड० के  
नवीन पाठ्यक्रमानुसार]

अनुपूरक

लेखक

रामचेलाम चौधरी

राधावल्लभ उपाध्याय

प्राध्यापक

माल शिक्षण-संस्थान, अजमेर

विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

प्रकाशक  
विनोद पुस्तक मन्दिर  
कार्यालय : राष्ट्रीय रायब मार्ग, आगरा-२  
बिक्री-केन्द्र : हॉलिगटन रोड, आगरा-२

[ सर्वाधिकार सुरक्षित ]  
प्रथम संस्करण : १९७१  
मूल्य : २.००

कम्पोजिंग : हिन्दी कम्पोजिंग ग्रुह, आगरा-२  
मुद्रण : कैलाश प्रिन्टिंग प्रेस, आगरा-२  
[ २/१०/७० ]

## अनुक्रमणिका

### अध्याय १

#### अध्यापक-शिक्षा

महत्त्व १, अध्यापक-शिक्षा का बदलता हुआ अर्थ २, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों की तैयारी ४, अध्यापक-शिक्षा में संगठनों का योगदान १६, वित्तीय समस्याएँ १८, अभ्यासार्थ प्रश्न २६ ।

### अध्याय २

#### उच्च शिक्षा

ब्रिटिश-काल में उच्च शिक्षा २८, कोठारी आयोग ३४, उच्च शिक्षा का वर्तमान स्वरूप ३७, महाविद्यालयों का वर्गीकरण ३७, विश्व-विद्यालयों का वर्गीकरण ३८, विश्वविद्यालय तथा शासन का प्रबन्ध ३९, संगठन ३९, प्रशासनिक संस्थाएँ ४०, उच्च शिक्षा की समस्याएँ ४१, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की सूची ४६, अभ्यासार्थ प्रश्न ४७ ।

### अध्याय ३

#### स्त्री-शिक्षा

ऐतिहासिक रूपरेखा ४८, आधुनिक युग ४९, स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति ५२, विद्यालयों में बालिकाओं का प्रवेश ५३, प्राथमिक शिक्षा ५४, निम्न माध्यमिक स्तर ५६, माध्यमिक स्तर, ५६, स्त्री-शिक्षा की समस्याएँ ५७, समस्याओं का समाधान ६१, विशिष्ट पाठ्यक्रम का स्वरूप ६४, अभ्यासार्थ प्रश्न ६६ ।



## अध्याय ४

## शिक्षा और राष्ट्रीय उन्नति

आर्य समाज की स्थापना १३. आर्य समाज का धर्म १८  
 शिक्षा का लक्ष्य आर्य समाज का विभाग १६ राष्ट्रियता का  
 अर्थ ३३, राष्ट्रियता के लिए शिक्षा के माध्यम ३३  
 राष्ट्रियता के लिए शिक्षा के माध्यम के माध्यम ३३ आर्य समाज  
 का धर्म १८।

## अध्याय १

### अध्यापक-शिक्षा

महत्त्व

दुर्भाग्य से भारतीय शिक्षा-पद्धति में अध्यापक-शिक्षा को वह महत्त्व नहीं प्राप्त हो सका है, जो उसे मिलना चाहिए। लगभग दस वर्ष पूर्व इंग्लैंड में अध्यापक-शिक्षा के विशेष महत्त्व को स्वीकार करते हुए पी० गेरे ने (एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग आफ टीचर्स) कहा था कि—“अध्यापक प्रशिक्षण का दायित्व केवल प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर नहीं है; जनता को इस ओर ध्यान देना चाहिए।” वास्तव में वे राष्ट्र की सेवा में अपना कर्तव्य-पालन कर रहे हैं और राष्ट्र को अधिकार है कि वह इस बात की जाँच करे कि उसके अध्यापक भलीभाँति शिक्षित हैं—शिक्षक जितने अच्छे होंगे, उतना ही सुन्दरान उनका कार्य होगा।” यदि अध्यापक की शिक्षा पर्याप्त नहीं है, तो समस्त शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। इसलिए हमें यह देखना होगा कि अध्यापकों की तैयारी, उनका दृष्टिकोण और प्रत्यक्ष अनुभव जिसके बल पर वे व्यापार का कार्य भविष्य में करने जा रहे हैं, कितने अच्छे हैं।

वर्तमान दशक में अध्यापक-शिक्षा की ओर भारत में सरकार का ध्यान बढ़ा हुआ है। भारतीय शिक्षा-आयोग (कोठारी आयोग) ने अपने प्रतिवेदन के चौथे अध्याय में अध्यापक-शिक्षा के महत्त्व का उल्लेख इस प्रकार किया है—

“शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम होना अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक-शिक्षा पर धन लगाने से बहुत अधिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि करोड़ों लोगों की शिक्षा में होने वाले लाभ और उन्नति को देखते हुए अध्यापक-शिक्षा पर होने वाला व्यय नगण्य है। दूसरे प्रभावों (ट्रेनिंग) के अभाव में एक अध्यापक उसी प्रकार पढ़ाने का यत्न करता है जिस तरह वह अपने प्रिय अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया है और इस प्रकार वह शिक्षण की पुरानी परम्परागत विधियों को स्थायी बनाता जाता है। आज की परिस्थिति में जब नयी

२। भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

और प्रगतिशील शिक्षण-विधियों की आवश्यकता है, इस प्रकार दृष्टिकोण प्रगति के मार्ग में बाधक है। इस परिस्थिति में एक प्रभावशाली अध्यापक-शिक्षा द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है, जो अध्यापक को अध्यापन में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों का महत्व समझा सके और उनकी भावी व्यावसायिक क्षमता के विकास को नींव डाल सके।

दृष्ट है कि उपेक्षित अध्यापक-शिक्षा जिस भी राष्ट्र की शिक्षा-मंडलि की आधार-शिला है और उसकी ओर अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यापक-शिक्षा अध्यापकों को केवल कुछ कुशलताएँ ही नहीं प्रदान करती बल्कि उसके द्वारा उनके दृष्टिकोण और वर्तित्व में परिवर्तन होता है, उनमें व्यावसायिक ईमानदारी बढ़ती है और वह अपने कुशल हाथों द्वारा ऐसे नार्मल तैयार करने में सफल होते हैं, जो देश का भविष्य बना सकते हैं।

अध्यापक-शिक्षा का बदसूरत हुआ अर्थ भारत में अध्यापक-शिक्षा की प्रक्रिया न तो नयी है और न कही बाहर से प्रयोग की निर्वाह हुआ और उसका परिमार्जन रूप वापस आया, ठीक उसी प्रकार बसुएँ भारत में उपभोगियों के लिए आयी थी।

भारत में अध्यापक-शिक्षा का अर्थ तीन मोदानों से होकर विकसित हुआ। सर्वप्रथम, अध्यापक-शिक्षा 'नित्य अध्यापक' के रूप में, द्वितीय मोदान में यह 'अध्यापक प्रशिक्षण' के रूप में और तृतीय मोदान में 'अध्यापक-शिक्षा' के रूप में स्वीकृत हुई।

इन परम्परा की जड़ें गहरी हैं, जहाँ जो छात्र बरिष्ठ होने से और शिक्षा के मार्ग से बाकी भागे बड़े चलने से, उन्हें कुशलता के आदेश में तबाना छात्रों को पढ़ाना पड़ता था; जब कुशलता, गुण और उपाध्याय परदेन के लिए चले जाने से, तो अध्यापन का दायित्व इन बरिष्ठ शिक्षकों को सौंप दिया जाता था। इस प्रकार 'नित्य-अध्यापक' की परम्परा वही शिक्षण एक छात्र प्राल करने हुए अध्यापक बाने का प्रतिष्ठान प्राप्त करता था। मात्र भी दीनत बानेओ से प्रतिष्ठानाओं को शिक्षाप्रसारण (पुनरिध टीकर) बढ़ने हैं बानेति बहू शिक्षाओं की हैमिपन में अध्यापन का नाम बरगत है।

हजारों वर्षों तक नित्य-अध्यापक की परम्परा हम देश में चलती रही। ऐसी जगहों से जब शिक्षितों के पैर भारत की भूमि पर जन, तो उनकी यही की जीवन परम्पराओ का अध्यापन किया। इन ऐतिहासिक से १७८७ ई. में अध्यापकों की मीशरी की हम परम्परा के साथ मधने और मजान के एक तीतर शिक्षा में हम का एक प्रदीप किया। उन प्रदीप के आधार पर निम्न सवा उमगा एक भेज हमें

पहुँचा जहाँ उसे पढ़कर सहस्रका मच गया। अध्यापको की तैयारी में इसका प्रयोग किया जाने लगा। वही पद्धति मॉनीटोरियल सिस्टम, बेल-लकास्टर प्रणाली, शिष्या-ध्यापक प्रणाली तथा स्नातको प्रणाली आदि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके विकास का वर्णन श्री एम० सत्यानन्दन के शोध ग्रन्थ—'हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन मद्रास प्रेसीडेंसी' में पढ़ा जा सकता है।

शिष्याध्यापक परम्परा में अध्यापक की शिक्षा का एकमात्र अर्थ यह था कि नया अध्यापक उस शिक्षण-विधि का अभ्यास करे जो उसके गुरुजनों ने इस्तेमाल की थी। एक शब्द में, अध्यापक शिक्षा 'अनुकरण-मात्र' थी। इस प्रकार का अर्थ अत्यन्त सकुचित कहा जा सकता है।

(ख) अध्यापक-प्रशिक्षण—अपने दूसरे दौर में अध्यापक-शिक्षा का अर्थ हुआ, अध्यापक को नाना प्रकार की शिक्षण-विधियों का ज्ञान कराना। यूरोप में इस परम्परा का विकास हुआ। १९वीं शताब्दी में शिक्षण-कला पर अनेकानेक प्रयोग यूरोप में हुए और आज भी वे प्रयोग यूरोप तथा अमरीका में जारी हैं। यूरोप में जेस्वीट आन्दोलन के फलस्वरूप अध्यापक-प्रशिक्षण को महत्व प्राप्त हुआ। जेस्वीट सगठन ने शिक्षण-कला का ज्ञान अध्यापको को कराना प्रारम्भ किया। हर्बार्ट ने शिक्षण कला का वैज्ञानिक स्वरूप निर्धारित किया। हर्बार्ट के अतिरिक्त पेस्तालाजी, फ्रोबेल, माटेसरी, हेलेन पार्लेस्ट, डेवी तथा अन्य शिक्षाविदों ने नयी-नयी शिक्षण-विधियों का विकास किया। उधर शिक्षा के सम्बन्ध में नाना प्रकार के चिन्तन प्रारम्भ हुए, जिसमें वार्शनिकों, समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा योगदान किया। इसके फलस्वरूप शिक्षा की सैद्धांतिक ज्ञानराशि इकट्ठी होने लगी। अध्यापक-प्रशिक्षण का अर्थ यह हुआ कि भावी अध्यापक को एक ओर नाना प्रकार की शिक्षण-विधियों, शिक्षा की विभिन्न विचारधाराओं और मत-मनान्तरों तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कराया जाय और वक्ष्य-शिक्षण के लिए मुख्यतः हर्बार्ट की शिक्षण-विधि का अभ्यास कराया जाय। इतना हो जाने पर वह एक कुशल अध्यापक बन जायगा।

अध्यापक-प्रशिक्षण का, इस प्रकार, अर्थ है भावी अध्यापक को अध्यापन-पेशे के लिए तैयारी, भौतिकोपायों की शक्ति प्राप्त कराना, प्रशिक्षण की उपाधि दिलाना, शिक्षण की कुछ निश्चित योग्यताएँ उत्पन्न करना आदि। स्पष्ट है कि अध्यापक-प्रशिक्षण अध्यापक-शिक्षा का एक सकुचित वाद्य है और इसीलिए यह आवश्यक समझा गया कि 'अध्यापक-शिक्षा' का एक बृहत् विचार विकसित किया जाय, इसके फलस्वरूप अध्यापक-शिक्षा अपने तीसरे सोपान पर पहुँची है।

(ग) अध्यापक-शिक्षा—ज्ञान-विज्ञान की आसधारण उन्नति, युद्ध की समाप्ति-नाओं से उत्पन्न संकट, नये आदर्शों और मूल्यों की स्थापना और बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से शिक्षा का उत्तरदायित्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है और उसी अनुपात में अध्यापक पर दायित्व का बोझ भी बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति

४ | भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

में एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता है जो विविष्ट प्रकार की शिक्षा या कुछ ही केवल यी० ए० अथवा एम० ए० की सामान्य डिग्री प्राप्त करने वाला और एक-दो पाठ्य-विषयों का ज्ञान अध्यापक नहीं बन सकता। अध्यापन का व्यवसाय सेवा की भावना से परिपूर्ण है, उसके लिए कुछ विविष्ट प्रकार की कुशलताएँ और अभिवृत्तियाँ अपेक्षित हैं, मानव सम्भाव को परत और सामाजिक जीवन के अन्तर्द्वन्द्व से उसका परिचय होना जरूरी है। अतः अध्यापक एक उसी प्रकार का विशेषज्ञ होना चाहिए जिस प्रकार का इंजीनियर, डाक्टर और वकील होता है। उसे अब 'मानवीय इंजीनियर' कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को तैयार करने वाली शिक्षा को 'अध्यापक-शिक्षा' का नाम दिया गया है।

पीटर्स, वॉट तथा फारवेल (इन्ट्रोड्यूसन टू टीचिंग) का कहना है कि अध्यापक-शिक्षा का अर्थ अध्यापक-प्रशिक्षण के अर्थ में कहीं अधिक व्यापक है। अध्यापक-शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौर से होकर गुजरने पर अध्यापक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वह अध्यापक के मन और मस्तिष्क को अनुदारता में मुक्त करती है। भविष्य में अध्यापक बनने की आकांक्षा रखने वाले नवपुत्रों और नवपुत्रियों जब प्रशिक्षण सस्थाओं में आते हैं, तो सच्ची अध्यापक-शिक्षा उनके ऊपर विविष्ट प्रकार के प्रभाव डालती है। ज्ञानवर्धन तथा कुशलता के बढ़ने, छात्रों की आवश्यकताओं की जानकारी, छात्रों के लिए पाठ्य-सामग्री की तैयारी एवं चयन, छात्रों की आवश्यकताओं तथा कमजोरियों की जानकारी आदि हो जाने से अध्यापक में आत्म-विश्वास बढ़ता है, मन उदार बनता है, सहानुभूतिपूर्वक दूसरों को समझने की योग्यता आती है, कल्पना-शक्ति के बन पर विचारों पर अग्रण करने की आवृत्ति बढ़ती है; सर्वोत्तम ढंग से अध्यापन कार्य करने की सान्ना बढ़ती है, छात्रों की प्रेरणा देने, उनके भीतर प्रमुख शक्तियों को जगाने और स्वयंपूर्वक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के साथ-साथ जीवन-दर्शन स्वीकार करने बतने की शक्ति अध्यापक में आती है—यह सब परिणाम अध्यापक-शिक्षा के द्वारा उत्पन्न होते हैं।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों की तैयारी

जीवन में शिक्षा की व्यापकता के कारण उसके कई स्तर हो गये हैं, जैसे शिशु एवं बाल शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सामाजिक शिक्षा या प्रौढ शिक्षा। इन सभी स्तरों पर शिक्षा के दायित्व अलग-अलग हैं। इसलिए हर स्तर पर शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों की तैयारी भिन्न-भिन्न ढंग में होना जरूरी है। इस दृष्टि से हर स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान प्रशिक्षण सस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए।

(क) शिशु एवं बाल-शिक्षा अथवा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए वर्तमान प्रशिक्षण सस्थाएँ—राज्य तथा सार्वजनिक सस्थाओं की ओर से ऐसे प्रशिक्षण विद्यालय बनाये जा रहे हैं जिनमें बच्चों की शिक्षा देने में समर्थ अध्यापकों को तैयार किया जाता है। इन स्तर पर नर्सरी, किंडरगार्टन, मोंटेसरी और बालवादी जैसी शिक्षा

संस्थाएँ काम कर रही हैं। इनमें काम करने वाले अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक समझा जाता है।

**उद्देश्य**—इस स्तर के प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं : अध्यापक को बाल-प्रकृति का ज्ञान कराना, बच्चों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, बच्चों की आदतें अच्छी बनाने के उपाय बताना, भाषा तथा सामान्य गणित की योग्यताओं का विकास करना, कला तथा मौन्दर्धानुभूति अध्यापक में जगाना आदि।

**पाठ्यक्रम**—इन संस्थाओं में अध्यापकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम 'कार्यकेंद्रित' होता है। उन्हें कला-कोशल की व्यावहारिक क्रियाएँ सीखनी पड़ती हैं। सैद्धान्तिक विषयों के अन्तर्गत, सामुदायिक जीवन का संगठन, सामाजिक सेवा, बाल-स्वभाव का अध्ययन, बाल-शिक्षा का इतिहास, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम का संचालन-संगठन, सफाई तथा स्वास्थ्य, प्रकृति का अध्ययन जिसमें बागवानी और पशुपालन शामिल हैं, भाषा और साहित्य, संगीत और कला-कोशल आदि विषय आ जाते हैं।

**शिक्षण-विधि**—अध्यापकों को व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दोनों प्रकार का ज्ञान कराया जाता है। कलाओं में पढ़ाई होती है और अध्यापकों को किडरगार्टन, मॉन्टेसरी और नर्सरी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धान्तों और व्यवहार का परिचय दिया जाता है। इन पद्धतियों पर चलने वाले स्कूलों में अध्यापकों को अभ्यास कराने के लिए भेजा जाता है, जहाँ कुशल अध्यापक-शिक्षकों के निरीक्षण में प्रशिक्षणार्थी काफी समय तक अभ्यास जारी रखते हैं। अध्यापकों को कला-कोशल, संगीत, बागवानी तथा सामाजिक सेवा का अभ्यास कराया जाता है।

(ख) जर्मन अथवा फ्राइमरी ट्रेनिंग स्कूल—स्वतन्त्रता के बाद सार्वजनिक शिक्षा में नया मोड़ आया और नये संविधान में निरक्षरता को दूर करने के लिए प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का आदर्श मान्य ठहराया गया। यह आदर्श हम अभी तक पूरा नहीं कर पाये परन्तु प्राथमिक शिक्षा का अभूतपूर्व विकास बीस वर्षों में हुआ। इस विकास के अनुरूप अध्यापकों की विशाल सेना खड़ी करना जरूरी था। यदि प्राथमिक शिक्षा को सफल होना है तो यह सारी सेना कुशल तथा प्रशिक्षित होनी चाहिए। इस विचार से प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या बढ़ी। स्वतन्त्रता के बाद अंग्रेजों द्वारा चलायी गयी प्राथमिक शिक्षा को पनपने दिया गया और साथ ही महात्मा गांधी द्वारा प्रशंसित वैसिक शिक्षा को सरकार ने लोकप्रिय बनाना चाहा। इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों को तैयार करने के लिए वैसिक और गैर-वैसिक ट्रेनिंग स्कूल—दो प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ चलने लगीं।

**उद्देश्य**—प्राथमिक स्तर के ट्रेनिंग स्कूलों में अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य हैं : अध्यापकों के अध्यापन विषय के ज्ञान में वृद्धि करना; बाल-मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा उनको छात्रों की प्रकृति का ज्ञान कराना; बाल-शिक्षण की प्रमुख विधियों का परिचय

## ६। भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

देना; स्कूलों में प्रशिक्षणाधिकारियों को ले जाकर शिक्षण-कला का अभ्यास कराना, हस्तकला और सज्जित कलाओं के प्रति रुचि जाग्रत करना, सामुदायिक जीवन में भाग लेने की अभिवृत्ति पैदा करना और सामाजिक सेवा का अभ्यास कराना आदि।

बुनियादी ट्रेनिंग स्कूलों में अध्यापक-शिक्षा को नया मोड़ देने की कोशिश की गयी। सन् १९५२ में 'हिन्दुस्तानी तामीली सभ' ने अपने पाठ्यक्रम का नया संस्करण अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए निकाला जिसमें बुनियादी शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ अध्यापक की शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये :

(क) मातृ-व्रतित्व हित के लिए सहकारिता पर आधारित सामुदायिक जीवन का अनुभव भावी अध्यापक को कराना। (ख) नयी तालीम के सामाजिक लक्ष्यों को समझना और स्वीकार करना। (ग) समुचित एवं सघटित व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यापक की शारीरिक, बौद्धिक, रोम्यार्थमय और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहन देना। (घ) बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक और भावार्थमय आवश्यकताओं के पूरा करने में अध्यापक को समर्थ बनाना।

इसी प्रकार सन् १९५६ में बुनियादी शिक्षा के मूलांकन के लिए नियुक्त समिति ने बुनियादी ट्रेनिंग स्कूलों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किये। जैसे— अध्यापक में जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की आत्मनिर्भरता पैदा करना, शिक्षा के क्षेत्र की हस्तगतता में दक्षता पैदा करना, बच्चों के शिक्षण की कला और विज्ञान में जो उत्पादन-केन्द्रित हो, अध्यापक को निपुण बनाना, अध्यापक में किसी हानोयोग के साथ साथ शिष्यों को सहस्रगन्धित करने की योग्यता पैदा करना, उनमें बर्तमान के द्रवि त्रासकता पैदा करना, राष्ट्र-निर्माण तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुभूति उत्पन्न करना, अध्यापक के सगठित व्यक्तित्व को बनाना ताकि उनमें छात्र भी वैसा ही व्रतित्व पावे हो।

सन् १९६० में भारत सरकार ने 'भारत में प्राथमिक अध्यापकों की शिक्षा पर राष्ट्रीय उपाध' (मेथीनार) का आयोजन किया जिसमें निदेश भी जे० पी० मायन थे। इस अवसर पर महत्वाधीन शिक्षा-अग्री भी वादुत्तम थीमानी ने अपने भाषण में अध्यापक-शिक्षा को नए आयाम दिये और नये लक्ष्यों की ओर इशारा किया, यथा—

प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व को हमने दृष्टिगत कर के अध्यापक को हम प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उनमें बहुमुखी मनोवृत्ति तथा सीमित विचारधारा की जड़ न पड़े, उनमें राष्ट्रप्रेम, आत्मनि हो, उनके मन में समाज का निर्माण करने की कल्पना हो, वह उन बच्चों और युवकों की शिक्षा पर अपने को समर्पित करें, वह छात्रों में वैसी ही आवश्यकता पैदा करने का योगदान दें।

वास्तव में— प्राथमिक स्तर पर अध्यापक-शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में शिक्षा के 'मूल्य', 'शिक्षा के उद्देश्य', 'आवश्यक शिक्षण विधियाँ', 'विद्यार्थियों

पाठ्य-विषयों को पढ़ाने की विधियाँ, 'विद्यालय-संगठन,' और 'स्वास्थ्य-शिक्षा' आदि विषय शामिल हैं। डा० सलामुतुल्ला ने इन विषयों के अलगाव पर विन्ता व्यक्त की है। उनका विचार है कि इन सभी विषयों का परस्पर सम्बन्ध है। इधर शिक्षा के गिरते हुए स्तर को ध्यान में रखकर डॉक्टर साहूब का मत है कि पाठ्यक्रम में पाठ्य-विषयों के तत्त्वों का समावेश किया जाय ताकि इन विषयों के ज्ञान में अध्यापक का पिछड़ाव न दूर हो। उन्होंने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत, सामान्य शिक्षा का उच्च स्तरीय ज्ञान रखने की सलाह दी है। अध्यापक को पाठ्य विषय का उच्च ज्ञान प्रदान किया जाय। सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम उन्होंने इस प्रकार प्रस्तावित किया है—

(क) साहित्य और जीवन का परिचय देने के लिए साहित्य समीक्षा, साहित्य को मुख्य प्रवृत्तियों, प्रतिनिधि गद्य-पद्य को रचनाएँ और बाल-साहित्य का अध्ययन कराया जाय।

(ख) गणित की शिक्षा इस प्रकार दी जाय कि अध्यापक जीवन में गणित का महत्व समझे, गणित की अभिवृत्ति तथा निम्नलिखित विधियों से वे परिचित हो जायें।

(ग) अध्यापकों को सामूहिक और मानवीय सम्बन्धों का ज्ञान कराने के लिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास की कहानी बतायी जाय और उन्हें भाषा तथा सामाजिक संस्थाओं के विकास का इतिहास बताया जाय।

(घ) उन्हें विज्ञान तथा विज्ञान से उत्पन्न नयी दुनिया का परिचय दिया जाय।

(ङ) हर प्रकार की कलाओं का परिचय दिया जाय।

प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिक्षणाम्यास उसका प्रमुख अंग है। शिक्षणाम्यास के दौरान अध्यापक को शिक्षण, छात्र-जीवन तथा कक्षा-शिक्षण की परिस्थितियों से अवगत कराया जाता है। इसी प्रकार माध्यामिक जीवन बिताना पाठ्यक्रम का प्रमुख अंग है। अध्यापकों को छात्रावास, विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और सरस्वती यात्रियों में शामिल होना पड़ता है।

शिक्षण विधि—ज्ञानात्मक विषयों को पढ़ाने के लिए कक्षाओं में भाषण-विधि का प्रयोग किया जाता है। वहीं-वहीं इन भाषणों के अतिरिक्त समस्याओं पर विचार-विमर्श और कक्षाओं को छोटे-छोटे दलों में बाँटकर ट्यूटोरियल की व्यवस्था की जाती है। शिक्षणाम्यास के पूर्व आदर्श पाठ दिये जाते हैं और छात्राध्यापक जब अपना अभ्यास जारी रखते हैं, तो उनके शिक्षण का निरीक्षण किया जाता है। सामुदायिक क्रिया-कलापों में भाग लेने की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब कार्यक्रमों में निर्देशन तथा पथ-प्रदर्शन की विधि काम में लायी जाती है।

(ग) साम्प्रदायिक स्तर में लिए अध्यापक-शिक्षा—साम्प्रदायिक शिक्षा-स्तर के अध्यापकों की शिक्षा के लिए सबसे अधिक प्रयत्न आजादी के बाद हुए है और कई प्रकार की संस्थाओं का उदय हुआ है। आजादी से पूर्व प्रान्तों के शिक्षा-विभागों की ओर से मैजिस्ट्रेट और पोस्ट-मैजिस्ट्रेट विधि प्राप्त कर पुराने माने व्यक्तियों को अध्यापन



८ | भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

का प्रतिफल देने के लिए ट्रेनिंग प्रारम्भ करने पर। इन ट्रेनिंग पाठकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर लगभग ४०० बी० टी० की शिक्षा दीया जाता था। बी० टी० की विदेशी विद्यालयों में अध्ययन शिक्षा का महत्व महत्वपूर्ण रहा होगा। इन विद्यालयों की अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया और साथ ही उनकी शिक्षा के लिए शासनायक शिक्षा को अनिवार्य करवा करके बी० टी० की शिक्षा दीया प्रारम्भ किया। यही लक्ष्य अन्तर्गत शिक्षा का अधिकतम प्रयत्न करने में करने के लिए एम० एड० के कोर्स विदेशी-य में लागू किए। इन प्रकार शिक्षा का का बर्तमान दिशा में गहरा बढ़ावा मिला। विदेशी विद्यालयों में शिक्षा माध्यमी कोष-कार्य प्रारम्भ किया।

स्वायत्तता के बाद बढ़े गये विदेशी विद्यालयों में प्रवेश गरी बी० एड० के कोर्स लागू कर दिये। यही लक्ष्य अन्तर्गत प्रशिक्षण के विदेशी विद्यालय में प्रवेश करने के लिये गण्य केन्द्रीय सरकार ने अध्यापक-शिक्षा में रचित प्रशिक्षण की और केन्द्रीय शिक्षा को प्रतिष्ठान के लिये, जैसे हैदराबाद का केन्द्रीय अर्थ-शिक्षा प्रबन्धन और माध्यमी का केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा प्रबन्धन।

माध्यमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा को रचना देने का प्रयास सरकार ने प्रारम्भ किया। इसलिए बुनियादी शिक्षा को गहरा बनाने वाले माध्यमिक स्तरों के अध्यापकों की शिक्षा के लिए तीन विशेष प्रचार के ट्रेनिंग कालेज लगे, जैसे तालुक भी बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज यहाँ कोर्स दो वर्षों का है। अन्य स्थानों पर

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रायः एक वर्ष का ही रखा गया और उगे पूरा करने पर बी० एड० की डिग्री मिलती है। विदेशों में जा कर शिक्षा-विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी ने देखा कि अमरीका में अनुसंधान के लिये पाठ्यक्रम अध्यापक-शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें हाई स्कूल पाठ करने की कोई भी सीमा नहीं है और साथ ही साथ अध्यापक की शिक्षा भी प्रायः तक कोई सीमा नहीं है। अध्यापक-शिक्षा का यह स्वरूप अपना आवश्यक सिद्ध हुआ कि कुलतः विश्वविद्यालय में इन प्रकार का पाठ्यक्रम अपने शिक्षा-विभाग में अपनाया।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहु-उद्देशीय चरित्र माध्यमिक विद्यालयों के खोलने का विचार जोर पकड़ने लगा। इन विद्यालयों के लिए अध्यापक तैयार करना एक विशेष समस्या थी। इसलिए भौतिक बोध एवं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् (एन० सी० ई० बार्ड टी०) ने अजमेर, भोपाल, मुम्बई और मैसूर में एक-एक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय (रीजनल कालेज आफ एजुकेशन) खोले जिनमें कुलतः

विश्वविद्यालय के अनुकरण पर चतुर्वर्षीय संघटित पाठ्यक्रम अपनाया गया। यहाँ कृषि, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान और भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों का परीक्षण चार वर्ष तक होता है और साथ ही इन विषयों का उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान किया जाता है।

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा पर एक नवीन प्रयोग यह हुआ है कि बी० ए० का कोर्स पत्राचार द्वारा पूरा कराया जाता है। अप्रशिक्षित अध्यापकों को जो नौकरी में लगे हैं, प्रशिक्षण देने के लिए यह कार्यक्रम अपनाया गया है। गर्मी की लम्बी छुट्टियों में दो वर्ष प्रशिक्षणार्थी कालेज में जाकर ठहरते हैं जहाँ उन्हें शिक्षण तथा फोल्ड वर्क का अभ्यास कराया जाता है और पाठ्य-विषयों पर भाषण भी दिये जाते हैं। शेष सत्र में पत्राचार द्वारा उन्हें प्रमुख विषयों की शिक्षा दी जाती है।

१. एक वर्ष का द्विरी कोर्स—सामान्य रूप से सारे भारत में अध्यापक-शिक्षा का एक वर्ष का पाठ्यक्रम चलता है। यह परम्परागत रूप है।

उद्देश्य—राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एक वर्ष के द्विरी कोर्स के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित हैं

(अ) अध्यापक में वैयक्तिक तथा सामाजिक गुण पैदा करना, जैसे आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी वाणी, शिष्ट व्यवहार, विनम्रता, सादरी, उदारता, आलोचनात्मक चिंतन, निर्भीकता, दृढ़ता, धर्म करने की आवृत्ति, कर्तव्यपालन, उत्तरदायित्व की भावना, सोद्देश्यता और सच्चे दिल से काम करने की प्रवृत्ति, सच्चाई, ईमानदारी, निष्पक्षता, अनुशासन, प्रेम, सहानुभूति, आत्मापालन, राष्ट्र तथा प्रजातन्त्र के प्रति प्रेम, और नेतृत्व-शक्ति आदि।

(आ) बच्चों के क्रिया-कलाप तथा समाज-सेवा में रुचि पैदा करना।

(इ) अपने व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकास में रुचि लेना।

(ई) बच्चों के प्रति सहानुभूति तथा समझने की अभिवृत्ति पैदा करना।

(उ) राग्य, शिष्टा-संस्था, अभिभावकों, छात्रों और समाज के प्रति मैत्री तथा सहयोग की अभिवृत्ति उत्पन्न करना।

(ऊ) शैक्षिक कार्यक्रमों तथा समस्याओं के प्रति शोधात्मक तथा प्रयोगात्मक अभिवृत्ति पैदा करना।

(ए) विद्यालय तथा छात्रों की भलाई के आगे अपने व्यक्तिगत लाभ को ह्यामने की अभिवृत्ति पैदा करना।

(ऐ) अपने पेशे के प्रति स्वस्थ तथा स्वीकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना।

यह उद्देश्य बड़े व्यापक हैं और प्रशिक्षण महाविद्यालयों की अध्यापक-शिक्षा इन उद्देश्यों को पूरा करती है, इस विषय में बड़ा सन्देह है। डॉ० बी० एस० मायूर के मत में वर्तमान अध्यापक-शिक्षा का कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक अभिवृत्ति बनाने में समर्थ नहीं है।

# भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

पाठ्यक्रम—विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम की अलग-अलग रूपरेखा गई है। आमतौर से पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है, (क) सिद्धान्त भाग, (ख) अभ्यास भाग। एजब विश्वविद्यालय ने क्रान्तिकारी परिवर्तन इस क्षेत्र में किये हैं। उनके यहाँ पूरा पाठ्यक्रम चार भागों में विभाजित है, यथा—

भाग १—सत्रीय कार्य, जिसके अन्तर्गत शैक्षिक विषयों पर उपनिषदों में भाग लेना, अभ्यास के लिए नियत विद्यालय के प्रशासन के किसी अंग का आलोचनात्मक अध्ययन करना, और साप्ताहिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करना, आ जाते हैं। साथ ही समाज-सेवा, पर्यावरण में परिवर्तन, श्यामपट्ट कार्य का अभ्यास, और शौकिया कार्य आते हैं।

भाग २—हस्तकला का अभ्यास, जिसके अन्तर्गत किसी प्रमुख दस्तकारी के मिष्ठान्तों का ज्ञान और उसमें निपुणता का अभ्यास कराया जाता है।

भाग ३—अनिवार्य सिद्धान्तिक शिक्षा के अन्तर्गत ७ प्रश्नपत्रों की पढ़ाई होती है। वे प्रश्नपत्र हैं—शिक्षा के सिद्धान्त, शिक्षा मनोविज्ञान तथा निर्देशन, भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ, शिक्षण की सामान्य विधियाँ, विद्यालय-संरचना और प्रशासन, किन्हीं दो पाठ्य विषयों के अभ्यापन की विधियों के लिए दो प्रश्न-पत्र।

भाग ४—शिक्षण-अभ्यास के अन्तर्गत प्रतिभाषी को ५० पाठ पढ़ाना तथा २० पाठों का निरीक्षण करना पड़ना है।

राजस्थान विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों की अभ्यास-शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो रहे हैं। सारे पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया जाता है—एक सिद्धान्त और दूसरा अभ्यास। राजस्थान विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम इस प्रकार है—

निष्ठान्त भाग के अन्तर्गत ५ अनिवार्य प्रश्नपत्र पढ़ाये जाते हैं, यथा—शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार तथा शिक्षा की समस्याएँ एवं स्वाध्याय शिक्षा, मनोवैज्ञानिक आधार तथा सूत्राकरण, भारतीय शिक्षा की समस्याएँ एवं स्वाध्याय शिक्षा, विद्यालयी विषयों को पढ़ाने के सिद्धान्त एवं विधियाँ, दो प्रश्नपत्र। एक प्रश्नपत्र वैकल्पिक है जो उन अभ्यासों के लिए है जो किसी एक क्षेत्र में शिक्षण-प्रणाली चर्चते हैं, जैसे—शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, बुनियादी शिक्षा, प्रयोग-क्षेत्र शिक्षा आदि। शिक्षण-अभ्यास के अन्तर्गत छात्राभ्यास को ४० पाठ पढ़ाने पड़ते हैं, २ आलोच्य पाठ होते हैं और २० पाठों का निरीक्षण करना पड़ना है। इसके अनिवार्य उक्त बना, दम्पकारी, मयात्रमेवा तथा खेनकूद का अभ्यास करना पड़ना है।

एम० ए० का कोर्स—उच्चमन्त्रीय अभ्यास-शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों तथा उच्च कोटि के शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एम० ए० का कोर्स मुना है जिसमें बहुत सीमित संख्या में अभ्यास भर्ती किये जाते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण-प्रणाली है। शिक्षा-दर्शन, उच्च शिक्षा-मनोविज्ञान, शोध की विधियाँ,

अनिवार्य विषय हैं और दो या तीन क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रश-  
न निर्धारित हैं । विशिष्टीकरण के क्षेत्र हैं — अध्यापक-शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा,  
मूल्यांकन, शैक्षिक प्रशासन और पाठ्यक्रम आदि । शैक्षणिक भाग में पाँच प्रश्नपत्र  
पढ़ाये जाते हैं और व्यावहारिक भाग के अन्तर्गत एक शोध-योजना पूरी करके शोध-  
प्रबन्ध लिखना पड़ता है ।

२. चतुर्वर्षीय द्वितीय पाठ्यक्रम — यह पहले बताया जा चुका है कि कुरुक्षेत्र  
विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इस पाठ्यक्रम को अपनाया और बाद में रीजनल कालेजों  
में इसी प्रकार का पाठ्यक्रम चालू हुआ । डा० गुलाबचन्द चौरसिया ने (म्यू एच इन  
टीचर एजुकेशन) में बताया है कि अध्यापक-शिक्षा में इस पाठ्यक्रम में नया मोड़  
आया है । इसके तीन लाभ बताये गये हैं : एक, इसके द्वारा अध्यापक की सामान्य  
शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का संघटन हो जाता है । दूसरे, चार वर्षों तक अध्यापक-  
शिक्षा जारी रहने से व्यावहारिक प्रशिक्षण अधिक प्राप्त होता है और बाल-अध्ययन,  
शिक्षण का प्रेक्षण, सामुदायिक अनुभव और शिक्षणाभ्यास के अवसर अधिक मिलते  
हैं । तीसरे, अध्यापक-प्रशिक्षकों को भावी अध्यापक को निर्देशन देने रहने में आसानी  
होती है, उन्हें अच्छे शिक्षक सिद्ध होने वालों को प्रोत्साहन देने तथा असफल अध्यापकों  
को हतोत्साहित करने में सुविधा होती है ।

उद्देश्य — रीजनल कालेजों के सम्बन्ध में प्रकाशित साहित्य और राजस्थान  
■ रीजनल कालेज की विवरण-पत्रिका में कहीं भी चार वर्ष के इस पाठ्यक्रम के उद्देश्यों  
का उल्लेख नहीं है । श्री देवेगोवदा (एजुकेशन आफ टीचर्स इन इंडिया, मया०  
एम० एन० मुकर्जी) और डा० गुलाबचन्द चौरसिया (म्यू एच इन टीचर एजुकेशन)  
जो रीजनल कालेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं और अभी भी हैं, के लेखों के आधार पर  
इस प्रकार की अध्यापक-शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण हम कर रहे हैं

१. अध्यापन-कला और अध्यापन-विषयों का एक साथ ज्ञान प्रदान करके  
सम्पूर्ण अध्यापक तैयार करना ताकि भावी अध्यापक किसी प्रकार भी  
अध्यापन-कौशल तथा पाठ्य-विषयों के नवीनतम ज्ञान की दृष्टि में  
पिछड़ा न रह सके ।
२. अध्यापन-कला तथा पाठ्य-विषयों के विशेषज्ञ विद्वानों का एक साथ सगम  
करके प्रशिक्षण के उत्तमोत्तम अवसर प्रदान करना ।
३. अध्यापक-प्रशिक्षकों को कालेज के बाहर शिक्षा संस्थाओं में भेजकर  
तरोताजा रखना ताकि अध्यापक-शिक्षा का कार्यक्रम किसी भी दृष्टि से  
पिछड़ा न रहे ।
४. कालेजों के साथ एक आदर्श बहुद्देशीय विद्यालय जोड़कर विभिन्न  
शिक्षण-विधियों की जाँच करने तथा नये-नये प्रयोग करने के अवसर  
प्रदान करना ।

५. अध्यापक-शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक-प्रशिक्षकों को पूर्ण स्वाधीनता और उत्तरदायित्व देकर नया शिक्षा-दर्शन विकसित करने की प्रेरणा देना; उनकी हर प्रकार की योग्यता का पूर्ण उपयोग करने के अवसर देना।
६. आन्तरिक मूल्यांकन पर निर्भर करने से छात्राध्यापकों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना।
७. नौकरी में लगे अध्यापकों की शिक्षा, क्षेत्रीय सेवा, शोध कार्य, शिक्षण-सामग्री की तैयारी और विवरण की व्यवस्था करना।
८. शिक्षण के अनुकूल छात्राध्यापकों में व्यक्तित्व गुण, अभिवृत्ति एवं कीर्तन पैदा करना।
९. सिद्धान्त और व्यवहार में समन्वय पैदा करना। 'इन्टरनिंग' अर्थात् छात्राध्यापकों को स्कूलों में स्थायी रूप से कुछ समय ठहरा कर शिक्षण व पूरा अनुभव कराना।
१०. विदेशों में शिक्षक-प्रशिक्षकों को भेजकर उनकी योग्यता बढ़ाना और छात्राध्यापकों को स्कूलों में स्थायी रूप से कुछ समय ठहरा कर शिक्षण व

नवीनतम ज्ञान से परिचित कराना, विदेशों से शिक्षाविदों को बुलाकर नयी प्रवृत्तियों से सबको अवगत कराना।

पाठ्यक्रम—चतुर्वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में छात्राध्यापक को विज्ञान, प्राविधि, वाणिज्य, कृषि, हस्तकला और भाषाओं के साथ-साथ शिक्षा-साहित्य भी पढ़ना होता है। शिक्षा-साहित्य के अन्तर्गत सामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा-मनोविज्ञान, वर्तमान इन टीचिंग, शिक्षा के आधार और समस्याएँ तथा शिक्षण की विशेष विधियाँ और छात्राध्यापन आते हैं। यह पढ़ाई सैद्धान्तिक विषयों से सम्बन्ध रखती है। जहाँ तक समय तथा ध्यान का प्रश्न है, सैद्धान्तिक और व्यावसायिक शिक्षा को समान रूप से परा किया जाता है।

पाठ्यक्रम सह्यायी क्रियाएँ भी निर्धारित हैं। छात्राध्यापकों को काफ़ी समय तक उन स्कूलों में जाकर रहना पड़ता है, जहाँ वे शिक्षण का अभ्यास करते हैं। अपने प्राध्यापकों के नेतृत्व में यह लोग विद्यालयी जीवन का पूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसे सेन-कूद, हाँडरी, फीस लेना, अनुशासन, हर तरह के रजिस्ट्रो का उपयोग तथा अन्य समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव। छात्राध्यापकों को शैक्षिक सरस्वती-यात्राओं और शिविरों में भाग लेना पड़ता है। शोध-योजनाएँ भी उन्हें पूरी करनी पड़ती हैं।

माध्यमिक अध्यापक-शिक्षा में प्रयुक्त शिक्षण-विधियाँ—एक वर्ष तथा चार वर्ष की अध्यापक-शिक्षा के डिग्री कोर्स में प्रयुक्त शिक्षण-विधियों में 'व्याख्यान' की प्रधानता है। सिद्धान्त-विषयक पढ़ाई कक्षाओं में होती है। प्राध्यापक कक्षाओं प्रापण देकर पाठ्य-विषय को सुबोध बनाते हैं परन्तु अब हम विधि के साथ विधियों का समन्वय करना प्रारम्भ किया गया है। विचार-विमर्श, पर्यवेक्षण, निमित्त अध्ययन, पुस्तकालय का प्रयोग, उपनिषद्, भाषण-माला और वर्कशॉप की

विधियों का प्रयोग आरम्भ हो गया है। चार वर्ष के कोर्स में शिक्षण-विधियों को उन्नत करने की चेष्टा जोरों पर है। मूल्यांकन की नयी विधियों का प्रयोग आरम्भ हुआ है। छात्राध्यापको को शोध-योजनाओं में लगाया जाता है और उन्हें शोध का अनुभव कराया जाता है।

३. प्रीम्कालीन पत्राचार-पाठ्यक्रम—पत दशक में अध्यापक-शिक्षा में गतिरोध देखकर और विशेष रूप से यह अनुभव करके कि अध्यापकों की सख्या तो शिक्षा प्रसार के कारण बढ़ रही है परन्तु प्रशिक्षण की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण अधिकांश छात्र अप्रशिक्षित हैं, प्रीम्कालीन पत्राचार-पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई। कई विश्वविद्यालयों, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम की अपनाया है। राजस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रीजनल कालेज और जोधपुर विश्वविद्यालय की ओर से इस प्रकार के पाठ्यक्रम कुछ अन्तर के साथ चालू किये गये हैं। इन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत छात्राध्यापको को दो वर्ष की गर्मी की छुट्टियों में उन महाविद्यालयों में जाकर ठहरना पड़ता है, जहाँ यह पाठ्यक्रम चलता है। बीच में वे अपने विद्यालयों में जाकर भौकरी करते रहते हैं और पत्राचार के द्वारा उन्हें पाठ्य-विषयों का ज्ञान कराया जाता है। इस कोर्स में केवल उन अध्यापकों को प्रशिक्षण पाने का अवसर दिया जाता है जो अप्रशिक्षित रह गये हैं और अध्यापन-कार्य कर रहे हैं।

उद्देश्य—(१) सरते में अध्यापक-शिक्षा का प्रवर्धन करना।

(२) भौकरी में लगे अप्रशिक्षित अध्यापको को उस समय प्रशिक्षण देना जब वे छुट्टी में हों और इस प्रकार उनकी छुट्टियों का सदुपयोग अध्यापक-शिक्षा में करना।

(अन्य उद्देश्य वही है, जो अध्यापक-शिक्षा के सम्बन्ध में कई बार लिखे जा चुके हैं।)

पाठ्यक्रम—प्रीम्कालीन तथा पत्राचार कोर्स में सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षा का क्रम निर्धारित है। सैद्धान्तिक शिक्षा के अन्तर्गत दो प्रश्न-पत्र दो पाठ्य-विषयों के लिए हैं जिनकी शिक्षण-विधि के साथ उन विषयों का ज्ञान भी कराया जाता है। अन्य विषय हैं—वर्षाव इन टीचिंग, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज-शास्त्रीय आधार (दो प्रश्न-पत्र)।

व्यावहारिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्राध्यापक को कक्षाओं में जाकर पाठ पढ़ाने का अभ्यास करना पड़ता है। विषयों के विमोचन उन पाठों का निरीक्षण करते हैं। पत्राचार द्वारा भेजे गये पाठों को पढ़ाकर प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजने पड़ते हैं। छात्राध्यापक को कुछ नियत कार्य (असाइनमेंट) पूरे करने पड़ते हैं, जैसे—विद्यालयी पाठ्यक्रम की समीक्षा, प्रचलित शिक्षा-पद्धति की समीक्षा, पुस्तक-समीक्षा, सहायक-सामग्री का निर्माण, केस-स्टडी, क्रियात्मक शोध, पाठ्येतर क्रियाओं का संगठन और निचालय-प्रशासन का आलोचनात्मक अध्ययन आदि।

## १४ | भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

**शिक्षण-विधि**—दीक्षापदान एवं पत्राचार दोनों में भाषण-विधि का प्रयोग उस समय होता है जब दीक्ष्य संस्थान चमका है और विद्यार्थियों को आमंत्रित करने, कक्षाओं में उनमें पहुँचाया जाना है। इस समय ट्यूटोरियल, निरीक्षण घूमनामय, अध्ययन और विचार-विमर्श की विधियों का प्रयोग भी होता है। पत्राचार द्वारा जो पाठ्य-सामग्री छात्राध्यापकों को भेजी जाती है, उसका अध्ययन वे स्वयं करते हैं, यह स्वाध्याय की विधि है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग उस समय होता है, जब वे लोग प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजते हैं।

छात्राध्यापक अपने स्तूब में जहाँ बैठ पाता है, शिक्षणाम्पास करता है, वही या प्रशिक्षित बरिष्ठ अध्यापक या प्रबन्धाध्यापक या छात्र-सम के प्रतिनिधि महारिचालय का कोई अध्यापक उसके पाठों का निरीक्षण करता है, कम-से-कम पाँच पाठों का निरीक्षण अवश्य किया जाता है। निरीक्षक छात्राध्यापकों के साथ बैठकर उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करता है। छात्राध्यापक समय-समय पर उसका परामर्श लेता है।

**सामान्य समीक्षा**—साप्ताहिक अध्यापकों की शिक्षा के क्षेत्र में काफी क्रान्ति आयी है परन्तु इस स्तर पर बहुत-सी त्रुटियाँ भी हैं। जैसे, एक वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरान्त अध्यापक में बहुत कम परिवर्तन दृष्टिपूर्वक होता है। प्रशिक्षण में जो भी कार्यक्रम है, वह आदर्शशदी है और स्तूबों में उसका व्यवहार नहीं हो पाता है। कुछ नियुक्तार्थ, जैसे—पाठ-नियोजन, प्रश्न पूछना, क्यामपट का प्रयोग आदि, अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार चतुर्वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम बहुत गरीब है। शिक्षा-आयोग (कोठारी) ने इस पाठ्यक्रम को खानू रखने का अनुमोदन किया है परन्तु उसके मत में एकवर्षीय पाठ्यक्रम द्वारा ही अध्यापक-शिक्षा पल-पल सकती है। आयोग ने कहा है कि चार वर्ष के पाठ्यक्रम यदि विश्वविद्यालयों में जहाँ हर विषय के विभाग हैं और विशेषज्ञ हैं, चलाने जायें तो लक्ष्य कम बैठेगा। रोजनल कालेज जैसे स्वतन्त्र महाविद्यालयों में अध्यापक-शिक्षा के लिए विभिन्न विषयों को विभाग अलग-अलग मोलना सम्भव नहीं है। साप्ताहिक शिक्षा के लिए अध्यापकों को तैयार करने के चार वर्ष के पाठ्यक्रम पर बड़ी-बड़ी अध्ययन दल ने बड़ा जोर दिया था और भूतपूर्व शिक्षा-मन्त्री छागला ने भी इसका समर्थन किया था। तब से अध्यापक-प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद ने इस पाठ्यक्रम को जारी करने की माँग कई बार की है।

श्रीधरकाशीन पत्राचार कीमें का समर्थन शिक्षा मन्त्रालय, बड़ी-बड़ी अध्ययन दल, योजना आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल और भी छागला आदि ने किया है, परन्तु इस प्रकार के कोर्स में सबसे बड़ी कमी यह है कि छात्र और अध्यापक के बीच कक्षाओं में जैसा सम्पर्क होता है, वैसा सम्पर्क पत्राचार कीमें में नहीं हो पाता। इसलिए अध्यापक के व्यक्तित्व गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

४ व्यवसाय-स्थित अध्यापकों की शिक्षा—अध्यापन के पेशे में लगे हुए अध्यापकों की शिक्षा की निरन्तरता को बनाये रखने वाले कार्यक्रम को व्यवसाय-स्थित अध्यापक-शिक्षा कहते हैं। श्री एच० एस० लॉरिस ('इन सर्विंग एजुकेशन' शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका) ने कहा है कि वे सारे कार्य, जैसे शैक्षिक यात्राएँ, स्वाध्याय, अध्यापक-शिक्षा के रिफ्रेशर कोर्स, भाषण, उपनिषद् तथा वर्कशॉप में भाग लेते हुए अध्यापक की पेशेवर योग्यता बढ़ाने के सारे उपाय, व्यवसाय-स्थित अध्यापक-शिक्षा कहला सकते हैं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि कोई अध्यापक एक सफल अध्यापक नहीं बन सकता, जब तक वह विद्यार्थी बनकर सीखना न रहे। एक दीप दूसरे दीप को जला नहीं सकता, जब तक वह स्वयं न जले। उन्होंने, इस प्रकार सामान्य परम्परा काव्यमयी भाषा में, व्यवसाय-स्थित शिक्षा का महत्त्व बताया था। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों की जानकारी, अध्यापक का निरन्तर विकास, एक-दो वर्ष के प्रशिक्षण कोर्स की अपूर्णता अध्यापक के पिछड़े दृष्टिकोण को दूर करने की आवश्यकता, आदि के कारण इस प्रकार की अध्यापक-शिक्षा का महत्त्व निरन्तर बढ़ता आ रहा है।

उद्देश्य—(१) व्यवसाय में लगे अध्यापकों की शिक्षा को जारी रखना।

(२) उनमें नये वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करके उनके पिछड़ेपन को दूर करना।

(३) अनुभवी अध्यापकों के समक्ष में एक-दूसरे को लाभान्वित करना।

(४) अध्यापकों के व्यक्तित्व में उन गुणों की अभिवृद्धि करना जो उनके पेशे के अनुकूल हैं।

(५) अध्यापकों में स्वाध्याय, प्रयोग तथा शोध की अभिवृद्धि पैदा करना।  
(अन्य उद्देश्य वही हैं, जो अन्य प्रसंगों में बनाये जा चुके हैं)।

पाठ्यक्रम—व्यवसाय-स्थित शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम हैं, उनमें केवल रिफ्रेशर कोर्स ऐसा है जिसमें पाठ्यक्रम निर्धारित है, और जिसके अन्तर्गत शिक्षा-मनोविज्ञान और शिक्षा समाजशास्त्र, दान्य निर्देशन, मानसिक स्वास्थ्य, परीक्षण तथा मापन, शोध तथा प्रयोगों के निष्कर्ष, सरकारी शैक्षिक नीतियाँ आदि विषय आ जाते हैं।

विधियाँ—व्यवसाय-स्थित शिक्षा के अनेक साधन हैं, जैसे रिफ्रेशर कोर्स जो शिक्षा-विभाग और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाते हैं, ग्रीष्मकालीन सन्धान, विस्तार-सेवा (एक्सटेंशन सर्विस) आदि।

रिफ्रेशर कोर्स में भाषण, प्रदर्शन-यात्रा, व्यावहारिक कार्य, सामूहिक विचार-विमर्श, और शैक्षिक प्रयोगों का प्रत्यक्ष अनुभव कराने की विधियों का प्रयोग होता है। ग्रीष्मकालीन सन्धानों में भाषण, गोष्ठी और विचार-विमर्श का तथा विस्तार



१६। भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

मेधा के द्वारा शोध-योजना, प्रयोग, वर्कशाप, निवृत्त-लेखन और निबंध-पाठ, उपनिषद्, मम्मनन, भाषणमाना, पुस्तकों का आदान-प्रदान, शैक्षिक फिल्म, चार्ट, टेप आदि के प्रयोग, प्रशिक्षण और साहित्य प्रकाशन आदि के उपाय काम में लाये जाते हैं।

**अध्यापक-शिक्षा में अध्यापक-संगठनों का योगदान**

प्रायः यह विश्राम किया जाता है कि अध्यापक बनने की शिक्षा प्रशिक्षण मण्डलों और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभागों में ही मिलती है। ऐसा नहीं है। प्रायः सभी देशों में अध्यापकों के व्यावसायिक संगठन हैं, जो न केवल अध्यापकों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, प्रत्युत वे अध्यापकों की व्यावसायिक श्रमता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, इन संगठनों को अध्यापक-शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाना चाहिए।

भारत में हर राज्य की शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक संघ बने हुए हैं जो राज्य सरकारों द्वारा मान्य हैं। इन सभी प्रकार के अध्यापक-संगठनों का एक राष्ट्रीय महासंघ भी है। यह भारतीय शिक्षक संघ के नाम से पुकारा जाता है। वर्तमान दशक में अध्यापक-प्रशिक्षणों का एक राष्ट्रीय संगठन (नेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर एज्युकेशन) भी जन्म में पुरा है। इस संगठन के संस्थान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह संगठन अध्यापक-शिक्षा को प्रोत्साहन देगा और उन सभी संगठनों से सहयोग करेगा जो अध्यापक-शिक्षा में रुचि रखते हैं। यह अध्यापक-शिक्षा की समस्याओं पर समय-समय पर विचार-विमर्श करने के अवसर प्रदान करेगा और सरकार की योजना-नुसार देकर इन समस्याओं को हल करने में सहायक भिन्न होगा।

अध्यापक-संगठन कई प्रकार से अध्यापक-शिक्षा में सहायता देते हैं। उनका यह कार्य अनोखा-विशेष होता है।

(क) सम्मेलनों, सत्रियों, बालीयों, कार्यविचार और उपनिषद का आयोजन—सम्मेलनों और सत्रियों के आयोजन अध्यापकों की शिक्षा के उत्तम माध्यम हैं। इन अवसरों पर सदस्यों की देश-विदेश से उन्नत मनीषा शक्ति-विचार-कलाओं में परिचय कराया जाता है। विद्वानों के आगमन, परिचर्चाएँ और निवृत्त-लेखन आदि आयोजनों को तथा ज्ञान प्रदान करते हैं। नये प्रयोगों और नवीन शिक्षण-विधियों की जानकारी उन्हें उपलब्ध होती है।

(ख) शिक्षा-साहित्य का प्रकाशन—अध्यापक संगठन स्वामी और आकाशी प्रकाशक के शिक्षा-साहित्य वाले अध्यापकों में बाँटते हैं। इन साहित्यों का सहायक प्रकाशकों की निज-प्रकाश, उनकी सहायकों तथा छात्रों के जीवन में होता है। इस प्रकार वे अपने अध्यापकों को मदद देने में विशेष प्रयत्न करते हैं। अध्यापक संघ की ओर उनकी पुनर्निर्माण प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, भारतीय शिक्षक संघ अनेकों 'इंग्लिश एज्युकेशन' और हिन्दी में 'भारतीय शिक्षा' (दोनों

मासिकी) का प्रकाशन करता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षक-प्रशिक्षक-संगठन की ओर से भी एक जर्नल प्रकाशित होता है। राज्यों में अध्यापकों के संगठन अलग-अलग अपनी पत्रिकाएँ निकालते हैं। इन पत्रिकाओं में अध्यापकों की सामयिक समस्याओं पर विचारोत्तेजक निबंध प्रकाशित होते हैं; इनमें देश-विदेश में होने वाली शैक्षिक प्रगति पर प्रकाश डाला जाता है; कभी-कभी शोध-योजनाओं के परिणाम भी दिये जाते हैं; यह सब प्रकार का साहित्य अध्यापकों की पेशेवर योग्यता में वृद्धि करता है।

(ग) आचार-संहिता—केवल विद्वत्ता और कौशल प्राप्त करके अध्यापक अपने पेशे में सफल नहीं हो सकता। अध्यापक के लिए उच्च कोटि की नैतिकता का पालन आवश्यक है। परिश्रम, ईमानदारी, सेवा की म-बला, छात्रों के प्रति स्नेह, कर्तव्य-पालन, सच्ची तथा एकात्मिक भावना से शिक्षण-कला को विकसित करने का प्रयत्न आदि ऐसे तरंग हैं, जो पेशेवर नैतिकता के अन्तर्गत आते हैं। इन सबके प्रति अध्यापक को उत्तुल करने वाली एकमात्र संस्था है—अध्यापक-संगठन, जो अपने सदस्यों के लिए एक आचार-संहिता तैयार करता है और अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे उस आचार-संहिता के अनुसार आचरण करेंगे। यदि संगठन को यह सूचना मिले कि अमुक सदस्य पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध आचरण करता है, तो उसे सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है या अन्य सदस्य उसे नीची गजर से देखते हैं। इस प्रकार आचार-संहिता उत्तम अध्यापन के लिए प्रेरणा का स्रोत है और साथ ही अध्यापक को पथप्रद होने से बचाती है। अतः, आचार-संहिता अध्यापक-शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। नमूने के तौर पर, इङ्ग्लैण्ड में अध्यापकों के नेशनल यूनियन ने अपनी आचार-संहिता निम्न प्रकार से बनायी है :

१. यदि यूनियन का कोई सदस्य अन्यायपूर्वक नौकरी से हटा दिया गया है, तो अन्य सदस्य उस नौकरी की स्वीकार न करें।
२. किसी शिक्षक पर लगाये गये आरोप के प्रकाशित हुए बिना उसके सम्बन्ध में दूसरा सदस्य शिकायत न करे।
३. प्रारम्भिक विद्यालयों में छात्रों की अतिरिक्त पढ़ाई के लिए लगातार न रोके।
४. विद्यार्थियों की भर्ती के लिए न तो स्वयं कोशिश करे और न अन्य सहयोगियों द्वारा कराये।
५. शिक्षक की हैसियत से विद्यालय के प्रांगण में पढ़ाई के घण्टे के पहले या बाद में किसी अन्य परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को न तैयार करे, आदि।

आचार-संहिता के नियमों के कुछ नमूने प्रदर्शित करते हैं कि अध्यापकों में अनुशासन का भाव इसके द्वारा पैदा होता है। इसी प्रकार समुक्त राज्य अमेरिका के

## १८ | भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

राष्ट्रीय शिक्षक-संगठनों ने अपनी आचार-संहिताएँ बनायी हैं जिनमें विद्यार्थी, समाज, सस्था, अपने पेशे और अनुबन्ध के सम्बन्ध में अध्यापकों के कर्तव्य निर्दिष्ट किये गये हैं। उनका उल्लेख स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं किया जा सकता परन्तु इसमें संदेह नहीं कि अध्यापक-संगठन अपनी आचार-संहिता के द्वारा अध्यापकों की नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करता है।

### विशेष समस्याएँ

१. विद्यालयी कार्य तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच सम्बन्ध का अभाव  
समस्या का स्वरूप—आमतौर पर यह शिकायत की जाती है कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों का कार्यक्रम हवाई है। वहाँ पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए जो भाषण दिये जाते हैं, उनमें जिन सिद्धान्तों की पढाई होती है, शिक्षण की जो विधियाँ बतायी जाती हैं और मनोविज्ञान तथा शिक्षा-दर्शन का जो भी ज्ञान कराया जाता है, उस सब का विद्यालयों के कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं होता। जो भी अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकने के बाद विद्यालयों में अध्यापक बनकर जाते हैं, वे यही कहते हैं कि प्रशिक्षण में जो कुछ बताया गया है, वह सब अत्यवहारिक है। इस आलोचना के मूल में प्रमुख समस्या यह है कि विद्यालयों में जो शिक्षण कार्य होता है उसका सम्बन्ध प्रशिक्षण महाविद्यालयों से बिल्कुल नहीं है। प्रशिक्षण महाविद्यालय जीवन से कटे हुए कल्पनालोक में विचारण करते हैं।

डा० राधाचरणजी की अध्यक्षता में निम्नलिखित विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन में इस ओर मबैत किया गया है। उसमें बताया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान छात्र-अध्यापक केवल कुछ इने-गिने घण्टे विद्यालयों में जाकर पढ़ा देते हैं। शिक्षण की वास्तविक समस्याएँ न तो उनके सामने आती हैं और न वे उन्हें समझने और हल करने की चेष्टा करते हैं।

सामयिक शिक्षा-आयोग (मुद्रालय) ने भी इस समस्या की ओर गंभीर करते हुए इस बात की मस्तुति दी है कि विद्यालय के सम्पूर्ण कार्यक्रम का अनुभव प्रशिक्षणार्थियों को कराना चाहिए। इस संबंध में आयोग ने समुक्त राज्य अमरीका में होने वाले नये परिवर्तनों का उल्लेख किया और कहा है कि उसी प्रकार अध्यापक-शिक्षा को यथार्थकारी होना चाहिए, विद्यालय के समस्त कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर बनाने में ही प्रशिक्षण महाविद्यालयों की पृथक्ता को दूर किया जा सकता है।

इस समस्या पर सबसे अधिक ध्यान भारतीय शिक्षा-आयोग ने दिया है। उसके वर्ष में शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय न केवल विद्यालयों में पृथक् है, बल्कि विश्वविद्यालयों तथा एक-दूसरे में भी अलग है। विद्यालयों में अध्यापक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अलग होने में यह शिकायत है कि जो भी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पढ़ा है, वे उन शिक्षण

विधियों का प्रयोग नहीं करते, जो उन्हें बताया गया है और न वे उस पेशेवर नैतिकता का पालन करते हैं जो अध्यापन की सफलता के लिए एक अनिवार्य सर्त है। इस प्रकार अध्यापक-शिक्षा का कोई फल समाज को नहीं मिलता या यो कहें कि राष्ट्र का अपार धन नष्ट होता है। चूँकि प्रशिक्षण महाविद्यालयों का कार्यक्रम यथार्थवादी नहीं है, विद्यालयों का विश्वास उन्हें प्राप्त नहीं है। विद्यालयों की ओर से अध्यापक-प्रशिक्षण में कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता। शिक्षा के क्षेत्र में यह आम धारणा बन गयी है कि प्रशिक्षित अध्यापक में अपेक्षित कार्यकुशलता नहीं पैदा होती। इस सम्बन्ध में डा० बी० एम० माधुर का कथन है—

“प्रशिक्षण की प्रभावशीलता के बारे में क्या कहा जाय ? यह प्रायः प्रश्न किया जाता है कि प्रशिक्षण महाविद्यालय में ठहरने से भावी अध्यापक में क्या कोई उपयोगी परिवर्तन होता है ? अध्यापक-प्रशिक्षण की कसौटी यह है कि क्या तथा विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों में प्रशिक्षित अध्यापक कहीं तक सफल होता है। इस कसौटी की जाँच के लिए कोई शोधकार्य तो नहीं रिया गया है परन्तु सामान्य धारणा यही है कि प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो कुछ बताया जाता है वह न तो व्यवहार करने में उपयोगी है और न उसका व्यवहार होता है।”

इस प्रकार की धारणा से अध्यापक-शिक्षा की विफलता सिद्ध होती है और सामान्य जनता का विश्वास उस पुर में हटता है।

अध्यापक-प्रशिक्षण की समस्याओं तथा विद्यालयों के बीच अन्तर्गम्य होने से दोनों की ज्ञान सम्बन्धी समृद्धि बन्द हो जाती है। यदि दोनों के बीच सम्बन्ध नहीं है, तो एक ओर विद्यालय की अपनी समस्याओं के हल करने में ट्रेनिंग कालेज की सहायता नहीं मिलती, वहाँ जो भी शोध तथा प्रयोग होते हैं, उनके निष्कर्षों की जानकारी से होने वाले ज्ञान से विद्यालय वंचित रहते हैं, दूसरी ओर ट्रेनिंग कालेजों को विद्यालय की समस्याओं की जानकारी नहीं हो पाती और वे अपने शोधकार्य को यथार्थ रूप नहीं दे सकते। इस प्रकार शिक्षा की जो शक्तिशीलता भिन्ननी चाहिए, वह नहीं मिल पाती।

समस्या का हल—राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय आयोजित ने स्कूलों और ट्रेनिंग कालेजों के बीच अलगव्य दूर करने के लिए एक सुभाव यह दिया था कि छात्राध्यापकों को कम से कम १२ सप्ताह तक स्कूलों में जाकर अपने अध्यापकों के निरीक्षण में शिक्षणाभ्यास करना चाहिए। छात्रों को उन विधियों में अवगत कराना चाहिए जो विद्यालयों में प्रचलित हो। मिडलान्ड-विषयों की शिक्षा स्कूलों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दी जानी चाहिए।

मुद्रालय माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस समस्या के निराकरण के लिए यह बताया कि शिक्षणाभ्यास के अन्तर्गत केवल अध्यापन ही नहीं, बल्कि बच्चों के क्रिया-कलाप और सामाजिक कार्यों में भाग लेने को भी शामिल करना

## २० | भारतीय शिक्षा की सामाजिक समस्याएँ

पाहि। दैनिक जानकों में जो कुछ पाया जाय उसका प्रतीक निदानों में किया जाय और यह देना चाह कि बौद्ध-जीनने विद्यालय स्वीकार्य हो सकते हैं। छात्र-स्वायत्तों को विद्यार्थियों की समस्याओं और आवश्यकताओं में अवधान बताया जाय। विद्यार्थियों के समस्त लाभों, जैसे बच्चों के खेल, रेकॉर्ड रखने और सामाजिक जीवन आदि, में छात्राध्यक्षों को भाग लेने को कहा जाय। विद्यालयी तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय के जीवन के बीच समानताएँ पाटने का एक सर्वोत्तम उपाय यह है कि प्रशिक्षण महाविद्यालय के साथ एक प्रयोगात्मक सामाजिक श्रम युक्त हो। इस रूप में छात्राध्यक्ष बर्द गलाह तक युवा समय समीक्षा करने हुए विद्यालय के जीवन का सामाजिक अनुभव प्राप्त करें।

प्रशिक्षण महाविद्यालय और विद्यालयों के बीच समानता दूरी को पाटने के लिए कोठारी शिक्षा-आयोग ने बर्द उपयोगी सुझाव दिये हैं। उनका विवरण निम्न-लिखित है

(१) हर प्रशिक्षण महाविद्यालय के परीक्ष में स्थित श्रमों के बीच समानता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण समस्त श्रमों का सम-समर्पण करे और वहाँ के अध्यापकों की कार्यक्रम के नियोजन में सहभाग्य करे, शिक्षण की उत्तम विधियों का प्रयोग करायें। इस विचार की सरचना के लिए यह आवश्यक है कि हर प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक विस्तार सेवा-केन्द्र अपना विभाग अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाय और उसके काम में सर्वोत्तम के अनिवार्य सभी अध्यापक भाग लें।

(२) हर प्रशिक्षण महाविद्यालय के पुराने छात्रों का एक संगठन हो जिनमें अध्यापक और उनके पूर्वपूर्व छात्र सदस्य हों। यह प्रशिक्षण के उपरान्त छात्राध्यक्ष अपनी नीकरी में आकर अध्यापन कार्य करने लगे और उन्हें कोई कठिनाई हो या उन्हें ऐसा जान पड़े कि जो भी दैनिक कालेज में बताया गया है वह अध्यापक है तो सम्मेलनों में उन पर विचार किया जाय। प्रशिक्षण महाविद्यालय की ओर से पर्याप्त अध्ययन (फालो-अप) किया जाय और यह जांच की जाय कि छात्राध्यक्ष सकलतापूर्वक पढ़ रहे हैं या नहीं। इस प्रकार के संगठन से उन सभी अन्तर्गतों को प्रेरणा मिलेगी जो स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के संगठन से उन सभी परिस्थितियों से परावृत्त दैनिक कालेज को आदर्शवादी शिक्षण विधियों का प्रयोग बन्द कर देने है।

(३) श्रमों और प्रशिक्षण महाविद्यालयों के बीच अलगाव को समाप्त कर का एक उपाय इनटर्नेशिप (छात्राध्यक्षों को किसी विद्यालय में पूरे समय स्थायी से दो-बार महीने रहकर शिक्षण कार्य के अतिरिक्त समस्त विद्यालयी कर्मों अनुभव कराना) है। प्रशिक्षण महाविद्यालय के सहयोगी विद्यालयों का सम-सम-इसमें सदेह नहीं कि यह एक अन्धीर समस्या है। इसको हल कि

प्रशिक्षण-कार्य का सफल होना कठिन ॥ हमारे विचार से एक उत्तम उपाय जो इस समस्या को हल करने में सहायक हो सकता है, यह है कि प्रशिक्षक-अध्यापक संगठन बनें। इसके प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापक और पाठ-पढोस के तथा सहयोगी स्कुलों के अध्यापक अनिवार्य रूप से सदस्य हों। इस प्रकार के संगठन के अन्तर्गत प्रत्येक पाठ्य-विषय के अध्यापकों की उपममितियाँ बना दी जायें जो उस विषय के शिक्षण की सफलता के लिए उपयुक्त उत्तमोत्तम विधियों पर प्रयोग करें तथा शिक्षण से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करें। शिक्षण के दौरान स्कुलों के अध्यापकों को जो कठिनाइयाँ आयें, जैसे बड़ी कक्षाओं को पढ़ाना, विशेष समस्याओं वाले छात्रों को पढ़ाना, अनुशासनहीनता, पाठ्य-पुस्तकों की चुरियाँ और पाठ्य-सामग्री की तैयारी, अन्य पाठ्येतर क्रियाओं का संगठन आदि, उन्हें ट्रेनिंग कालेज के अध्यापक हल करें। इन समस्याओं को एम० एड० स्तर पर शोध का विषय बनाया जा सकता है।

इस अलगाव को दूर करने की पहन प्रशिक्षण महाविद्यालयों की ओर से होनी चाहिए। अपने सहयोगी विद्यालयों के श्रेष्ठ अध्यापकों को प्रदर्शन-पाठ देने के लिए कहना चाहिए और छात्राध्यापकों को उनकी कक्षाओं में ले जाना चाहिए ताकि वे उनके शिक्षण को देख सकें। प्राध्यापकों को स्कुलों में लिए पाठ्य-सामग्री, सहायक उपकरण तथा निर्देशन कार्यक्रम तैयार करके भेजना चाहिए। स्कुलों के सामाजिक कार्यक्रमों में अध्यापकों और आचार्यों को भाग लेना चाहिए। यह सब न तो कठिन है और न व्यय-साध्य; आवश्यकता इस बात की है कि प्रशिक्षण महाविद्यालय अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें और सघनबासी अभिशुक्ति पंदा करें।

## २. अध्यापकों की सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति तथा प्रतिष्ठा की समस्या

समस्या का स्वरूप—भारत में अध्यापक की प्रतिष्ठा प्राचीनकाल से अब तक समझ में ऊँची रही है। प्राचीनकाल में गुरुकुलों के अध्यापकों ने ही भारतीय दर्शन और साहित्य की रचना की। उन्होंने जीवन के ऐसे मूल्यों की रचना की जिन पर हम आज भी गर्व करते हैं। महाकाव्यों और धर्मग्रन्थों में ऐसे आख्यान अनेक हैं जो यह विद्व करते हैं कि अध्यापक के आगे शासक और विजेता नतमस्तक होते थे; उनके आगे ही मिहिरान से उतर कर नीचे आ बैठते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और परशुराम ऐसे ही अध्यापक थे। समाज में उनको जो सम्मान प्राप्त था वह सम्राटों को भी न प्राप्त था। फिर भी एक बात स्पष्ट है : प्राचीन अध्यापक त्यागी-तपस्वी बनकर ही जीवन व्यतीत करता था, उसके पास धन-रूपति जमा नहीं होने थे। भौतिक सुख से दूर रहकर अध्यापन कार्य करना उसका आदर्श था। उसे शिक्षावृत्ति पर निर्भर करना पड़ता था। यही नहीं उस काल में अध्यापन को व्यवसाय नहीं माना जाता था और उन लोगों को जो अध्यापन को धन पैदा करने का साधन मानते थे, बड़ी नीची नजर से देखा जाता था।

अब वर्तमान काल में अध्यापक की स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया है। हर स्तर पर भारत में शिक्षा-प्रसार के कारण अध्यापकों की विशाल सेना खड़ी हो गयी है। त्याग-तपस्या का आदर्श धूमिल पड़ गया है क्योंकि अब अध्यापक के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया है। उसे अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करना पड़ता है, सम्मानों की शिक्षा और उनके विवाह का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। समाज में अज्ञान का आदर नहीं है, आदर है भौतिक माधनो का। इसलिए समाज में सम्मानपूर्ण जीवन बिताने के लिए अध्यापक को धन की आवश्यकता अनुभव होती है। समाज में धन और पद की प्रतिष्ठा है, यदि एक व्यक्ति करोड़पती है या बहु शासन में महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, जो समाज उसके पद पूजता है। ऐसी दशा में वैरागी-संन्यासी बने अध्यापक की ओर कोई देखना भी नहीं पसंद करता। यद्यपि अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, परन्तु उमरा सर्वत्र निरादर ही होता है। प्रशासक, नेता, छात्र और अभिभावक सभी अध्यापक को हीन दृष्टि से देखते हैं। आज सामाजिक दृष्टि से अध्यापक बहुत नीचे गिरा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत के अध्यापक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाया है। फल यह हुआ है कि आजादी के बाद उत्पन्न नवयुवकों की पीढ़ी को अध्यापक का नेतृत्व नहीं मिला पाया और आज वही पीढ़ी समाज के लिए गिरदर्द बन गयी है। अध्यापकों की सामाजिक, और आर्थिक विपन्नता एक बहुत बड़े प्रश्न-चिन्ह के रूप में हमारे सामने खड़ी है।

सांघ्यिक शिक्षा-आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अध्यापक की इस दुर्दशा की ओर इस प्रकार संकेत किया है—

“हमें विश्वास है कि अपेक्षित शिक्षा-पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तत्त्व ‘अध्यापक’ है—उसकी शैक्षिक योग्यता, उसके व्यक्तित्व गुण, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण, और समाज तथा स्कूल में उसकी प्रतिष्ठा।”

आयोग के सदस्यों ने सारे देश का भ्रमण करके देखा कि अध्यापकों की सेवा की सुरक्षा नहीं है, यद्यपि उनके वेतनमानों में सुधार किया गया है तथापि अन्य देशों के वेतनमानों से कम हैं, अध्यापक की योग्यता अधिक है और बढ़ती हुई महँगाई के कारण वेतन-वृद्धि से कोई लाभ नहीं हुआ है।

अनेक शिक्षाविदों का ध्यान अध्यापक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति की तरफ़ गया है। उन सबका विचार है कि अध्यापक आर्थिक स्थिति में अविश्वस्य सुधार आवश्यक है। प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के वेतन बैंक और केन्द्रीय नगरपालिकाओं में काम करने वाले चपरासियों से भी कम। सांघ्यिक स्तर पर जिन शैक्षिक योग्यताओं के अध्यापक काम करते हैं, उनका वेतन साधारण कर्मचारियों से कम है जो कम योग्यता रखते हैं, परन्तु बड़े बड़े दायित्वों

सचिवालयों में काम करते हैं। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन प्रशासन में लगे उच्चधिकारियों से कम हैं यद्यपि भौतिक योग्यता में वे बड़े-बड़े हैं—यही कारण है कि अध्यापन के पेशे में उच्च कोटि के विद्वान प्रवेश करना स्वीकार नहीं करते। अध्यापकों को वे अनेक सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं हैं, जो राजकीय कर्मचारियों या उच्च व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को प्राप्त हैं, जैसे भुगतन बिक्रित्ता और आवास आदि। अब अध्यापक का ध्यान इस ओर गया है और वे अपनी प्रतिष्ठा के लिए सपर्यशील हैं। गत ५ वर्षों में, भारत के प्रत्येक राज्य में हर स्तर के अध्यापकों ने अपनी इस स्थिति को सुधारने के लिए हड़तालें कीं। अब यह स्पष्ट है कि यदि शीघ्र ही अध्यापक की आर्थिक दशा में सुधार न हुआ तो देश को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिना आर्थिक सुधार के सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा भी अध्यापक को नहीं प्राप्त होगी।

इस समस्या के महत्त्व को सरकार अभी स्वीकार नहीं कर रही है। जब श्री छागला ने भारत सरकार का शिक्षा मन्त्रालय संभाला, तो उन्होंने सर्वप्रथम अध्यापक की दुर्दशा की ओर ध्यान दिया था। उन्होंने बार-बार यह कहा था कि अध्यापकों के वेतनमानों में अविनम्य वृद्धि कर दी जाय और प्राथमिक स्तर पर यह सुधार तुरन्त लागू किये जायें। उनके वेतनमानों में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होते ही परिवर्तन होने चाहिए। श्री छागला ने भारतीय शिक्षा-आयोग की नियुक्ति की और उस आयोग ने हर स्तर के अध्यापकों के लिए वेतनमान स्थिर किये, परन्तु अनेक राज्यों में अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।

डा० सम्पदैन ने (पार्लेमेन्ट आफ एजुकेशनल रीक्रान्स्ट्रक्शन) अध्यापकों की सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा पर विचार करते हुए लिखा है कि अध्यापक की स्थिति में भारी गिरावट आयी है। आज अध्यापक एक वेतनभोगी कर्मचारी है और सरकारी नौकरी करके एक गुलाम बन चुका है। वह अपने महान् उद्देश्य को भूल चुका है। अपने युग की चुनौती का सामना करने में वह बिल्कुल असमर्थ है। नये समाज की रचना करने में यह सहायक नहीं है। वर्तमान काल में देश के भीतर ग्याय और अन्याय, सहयोग और शोषण, मानवता और दानवता के बीच जो भीषण संघर्ष चल रहा है, उसे वह केवल तटस्थ दर्शक की भाँति देख रहा है। सभी समाज ने उसे प्रतिष्ठा नहीं प्रदान की है।

समस्या का हल—अध्यापकों की सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने कई ठोस उपाय सुझाये हैं। वे निम्न-लिखित हैं :

१. केन्द्रीय वेतन आयोगों के प्रतिवेदनो और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जैसी संस्थाओं के प्रतिवेदनो को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की योग्यता के अनुरूप उनके वेतनमान निर्धारित कर दिये जायें।



बढ़ती हुई उपभोक्ता वस्तुओं की दरो और जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए वेतन निश्चित किया जाय।

२. अध्यापकों की आर्थिक चिन्ताओं को दूर करने के लिए निम्नो तत्व-योजना लागू की जाय जिसके अन्तर्गत स्थायी भविष्य निर्धि, वृद्धि और बीमा की अनिवार्यता हो।
३. अध्यापकों की सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति निश्चित करने के लिए उनकी नियुक्ति और स्थायीकरण पर सरकारी विभाग दृष्टि रहे।
४. अध्यापकों के लिए, उनके बच्चों की मुफ्त शिक्षा, आवास-सुविधाएँ, यात्रा कर में छूट, छुट्टियाँ बिताने के लिए भत्ते, चिकित्सा की सुविधा और छुट्टियों के उदार नियम आदि की सुविधा हो।
५. अध्यापकों की आय-वृद्धि के लिए उन्हें ट्रेनिंग करने से रोका जा परन्तु उसके स्थान पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों को पढ़ाने पारिश्रमिक, मासुदायिक योजनाओं में भाग लेने पर या गाँवों में घर चलाने पर वेतन दिया जाय।
६. अध्यापकों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उनको सम्झी सेवा के आधार पर सम्मान दिया जाय, उत्सवों में उन्हें आमन्त्रित किया जाय और शैक्षिक मामलों में उनकी सलाह ली जाय।

उक्त आयोग के मुद्दाओं से सरकार को कुछ संकेत मिला और केन्द्रीय सरकार ने अध्यापकों का सम्मान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चलाना शुरू किया। इस योजना को बार्मान्ति करने में दूरदर्शिता से काम नहीं लिया गया। वहीं-ही पुरस्कारों के प्रदान करने में पूर्ण निष्पक्षता से काम नहीं लिया गया। समाज ने पुरस्कार अध्यापकों को वह सम्मान नहीं दिया, जो उन्हें मिलना चाहिए। इसी प्रकार सरकार ने 'अध्यापक-दिवस' मनाने की प्रथा चलाई। यह दिवस उन दिन मनाया जाता है, जिस दिन प्रसिद्ध शिक्षाविद् और महान् अध्यापक रामकृष्णानन्द का जन्मदिन पड़ता। जिस प्रकार अध्यापकों द्वारा टिकट बेचने की प्रथा चलाई गयी है, उससे अध्यापकों का सम्मान घटा है। बागव में अध्यापक दिवस अभिभावकों और समाज के बच्चों द्वारा मनाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अध्यापकों की स्थिति को ऊँचा उठाने के उनकी आर्थिक दशा को सुधारना आवश्यक माना है, परन्तु केवल आर्थिक सुधार बने में अध्यापक का व्यावसायिक और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा—मन्देहास्य है। कुछ विद्वानों का मत है कि उनके सम्मान के प्रश्न का समाधान के हाथ में है। डॉ० मधुदेन का मत है कि अध्यापक की प्रतिष्ठा पर निर्भर है कि वह वहाँ तक गच्छे की समस्याओं में दिलचस्पी रखता है। की मज्जा बहुत कुछ उन समय हमारे सामने निम्न हो जाती है, जब हम

देशों में अध्यापकों के कारनामे देखते हैं। रूस में अध्यापकों ने 'राष्ट्र निर्माता' बनकर दिना दिया है कि वे राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। रूस का अध्यापक सच्चे अर्थों में समाज का पप-प्रदर्शक, दार्शनिक और भिन्न है। बोदिस किम (रशिया गोज़ द्व स्कूल) के एक उद्धरण से यह बात स्पष्ट है—

“रूसका (अध्यापक) का घर व्यावसायिक विचारों का केन्द्र है, एक गैर-सरकारी परामर्श-केन्द्र है जहाँ कृषि से लेकर बच्चे के नामकरण तक के विषयों पर सलाह मिल सकती है। जहाँ समाज और अध्यापक के बीच इस प्रकार के सम्बन्ध बन गये हैं, वहाँ न तो अध्यापक के घर में और न स्कूल में किसी प्रकार का अभाव होगा। न तो स्कूल और न अध्यापक—किसी की ओर भी समाज उपेक्षा की दृष्टि न रहेगा।”

रूस में अध्यापकों की ऐसी स्थिति हमारे लिए ईर्ष्या का विषय नहीं है क्योंकि हमारे देश में प्राचीन काल से अध्यापकों की महानता और उनके सम्मान की परम्पराएँ मौजूद हैं; वे पत्थर की मकीरें हैं, जो मिट नहीं सकतीं। हाँ, आज के अध्यापक को पैरों की धूल का त्याग करना होगा, उसे चाकरी वृत्ति को तिलाञ्जलि देनी होगी और उसे देश तथा राष्ट्र में होने वाली क्रांति में भाग्य बनकर अपनी भूमिका अदा करनी होगी। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित विचार उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं :

(१) यदि यह मानकर चलें कि सामाजिक और धार्मिक स्थिति को ऊँचा करने में अध्यापक का अपना प्रयत्न आवश्यक है, तो अब समय आ गया है कि अध्यापक अपने गम्भीर दायित्व को पहचानें। उसे नये समाज का निर्माण करना है। उसे उन सभी हानिकारक तत्त्वों का सामना करना है जो शिक्षा के काम को कटिनि बनाते हैं, जैसे सामुदायिक साधन जिनके अन्तर्गत फिल्म, रेडियो, समाचार पत्र और माहिद्य आ जाते हैं तथा जो नवयुवक और नवयुवतियों पर बुरे सत्कार डाल रहे हैं। वैज्ञानिक, प्राविधिक और भौतिक उन्नति के साथ-साथ, प्रजातांत्रिक विचारधारा के उन्नयन से मनुष्य का जीवन सर्वथा बदल गया है। उस जीवन के अनुसार अपने रहन-सहन में परिवर्तन आवश्यक है। अध्यापक को यह अनुभव करना चाहिए कि उसके छात्र सभी मुन्नी होंगे, जब वे इन परिवर्तनों के लिए तैयार हो जायें। अध्यापक को उन सभी सांस्कृतिक परम्पराओं की रक्षा करनी है, जो हमारी मूल्यवान् धरोहर हैं। इस प्रकार नये राष्ट्र के निर्माण में उन्हें आगे बढ़कर हिस्सा लेना है।

(२) सोवियत रूस और चीन में अध्यापक स्वस्थ तरीके से राजनीति में भाग लेता है। भारत में इस बात पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि अध्यापक को राजनीति से तटस्थ रहना चाहिए। यदि राजनीति का अर्थ किसी प्रकार राज्य सत्ता को हथियाना है, तो अध्यापक को अवश्य राजनीति से अनजब रहना चाहिए, परन्तु यदि राजनीति का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्वजनहिताय शासन चलाना और प्रजा को मूल्य और समृद्धि की ओर ले जाना, तो उसे राजनीति से कभी

## ६। भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

अलग नहीं रहना चाहिए। सत्ता में दूर रहकर सत्ता पर नियंत्रण रखना उसे पथ-प्रदर्शन देना, अध्यापक का कर्तव्य है। यदि वह, इन अर्थों में, 'राजनीतिज्ञ' बने तो उसका सम्मान बढ़ेगा। उसकी सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधरेगी।

(३) अध्यापक-संगठन इस समस्या को हल करने में सहायक हो सकते हैं। दुर्भाग्य में इस प्रकार के संगठनों की बुरी नज़र से देखा जाता है। प्रशासकों को अध्यापक-संगठन में 'ट्रेड यूनियन' की घूँब आती है। उन्हें भय है कि अध्यापक संघबद्ध होकर सघर्ष की ओर अग्रसर होंगे। यह भय निराधार भी नहीं है। यदि अध्यापक को उसके अधिकार नहीं मिलते, अथवा समाज उसकी ओर उपेक्षा-दृष्टि से देखता है, तो अध्यापक को अपने संगठन का सहारा लेना पड़ेगा। यदि परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होनी हैं या पैदा की जाती हैं कि अध्यापक दीन-हीन बना रहे, तो अध्यापक इस विश्वास को लेकर चले कि वह एक ऊँचे पेशे का ध्येय है और उसे मजदूरी की तरह सप नहीं बनाना चाहिए—यह एक भूल होगी। इस प्रकार का विश्वास एक प्रकार की अप्रीम है, जिसको लेकर वह बेमुश्किल रहेगा। इस युग में सर्वत्र शक्ति की पूजा होती है और अध्यापक को शक्ति अर्जन करनी चाहिए जिसका माध्यम 'संगठन' है, परन्तु वह शक्ति परवीडन के लिए नहीं किन्तु 'पररक्षणार्थ' होनी चाहिए।

(४) अध्यापक को उसका उचित स्थान प्रदान करने के लिए समाज और सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली कदम यह होगा कि अध्यापक को शिक्षा-नीति के निश्चय करने में सम्मिलित बनाया जाय। जैसे राष्ट्र निर्माण कहा जाता है, जो ज्ञान, त्याग और दूरदर्शिता में कम नहीं, जो केवल सत्य का अनुगामी है, उसे 'शिक्षा-नीति' का निश्चय करते समय उपेक्षित किया जाता है। शिक्षा-नीति का निश्चय वे लोग करते हैं, जो 'राजनीतिज्ञ' बहुल होते हैं, जो बंद कमरों में बैठकर हवाई किले बनाते हैं, जिन्हें नयी पीढ़ी की आकांक्षाओं का कोई ज्ञान नहीं और जो केवल बहाने कर सकते हैं। अध्यापक को एक कठगुत्तरी की शक्ति देकर असंगठित बना दिया गया है। क्या पाठ्य-सामग्री, क्या मूल्यांकन, क्या शिक्षण-विधि और क्या प्रशासन—सभी कुछ अध्यापकों के वश में नहीं है, वह केवल आजापालक गुलाम है। यदि उसे ऊँचा सम्मान देने में समाज की ईमानदारी दिलायी है, तो उसे 'स्वतंत्र' करना होगा, छात्रों के माध्य-निर्माण के लिए उसे दृष्ट देनी पड़ेगी। ऐसा करने से अध्यापक की सच्ची प्रतिष्ठा होगी, केवल पुरस्कार देने या अनुदान देने से कुछ न होगा।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

१. अध्यापक-शिक्षा के मूल के सम्बन्ध में आपका क्या मन है ? अध्यापक-शिक्षा को राष्ट्र की शिक्षा की उत्तमता बढ़ाने में कहाँ तक सहायक बनाया जा सकता है ?
२. भारत में अध्यापक-शिक्षा के विभाग पर एक सक्षम निबन्ध लिखिए।

१. 'अध्यात्म-विज्ञान' का माग्यर्षे स्पष्ट करने हुए, उनके गृहेष्वो पर अपने विचार लिखिए ।
४. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अध्यात्म-विकास की मशिन स्पष्ट रेखा प्रस्तुत कीजिए और उनकी कमियों पर प्रकाश डालिए ।
२. अध्यात्म-विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले जातिवादी प्रयोगों का वर्णन कीजिए । इस प्रकार के प्रयोग क्यों गलत माने जाते हैं ?
६. "अध्यात्म-विज्ञान में अध्यात्म संदेशों का योगदान"—इस विषय पर एक निबंध लिखिए ।
७. 'अध्यात्म-विज्ञान के अनुपात' की समझ का विवेचन कीजिए तथा उनके हम करने के उपाय बताइए ।
८. अध्यात्मों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता के उपायों पर अपने विचार प्रकट कीजिए ।

**उच्च शिक्षा**

कारण के दर्शनन हम उच्च शिक्षा-व्यवस्था को अपात माहमनगारी  
रूपधरतो के पहुँचना। उन्होंने धार्मिक स्थानों के साथ-साथ शिक्षा-केन्द्रों को भी मज-  
बूत किया। यही मुख्यमात्र कारणों ने कुछ स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिए मदद-  
गो रूपधरा की जिनमे इस्लाम धर्म के विद्वानों को शिक्षा मुख्य रूप से दी जानी थी।  
हम दरारों में शिक्षा का माध्यम जरूरी अवकाश पारती था।

का जो स्वरूप एवं व्यवस्था विद्यमान है वह दुसरे दर  
१०. वे प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली की उत्तरेषा की  
दृष्टि से अनुपयोगी मानकर सदैव हेम दृष्टि से देखा है

इन विद्यालयों के प्रति सदैव सशक्त रहे। इसीलिए ब्रिटिश शासकों ने ऐसी शिक्षा-नीति का निर्धारण किया जो भारतीय नागरिकों को पाश्चात्य सम्पत्ता, रीति-रिवाज में दुबोकर ऐसा रूप प्रदान करे कि वे सदैव ब्रिटिश शासन के प्रति बफादार रहें। ब्रिटिश भारत में, उच्च शिक्षा के विकास को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :

- (१) १७८१ से १८२३ तक।
- (२) १८२४ से १८८२ तक।
- (३) १८८३ से १९१६-१७ तक।
- (४) १९१७ से १९४७ तक।
- (५) १९४७-४८ से १९७० तक।

## १. सन् १७८१ से १८२३ तक

इस काल में उच्च शिक्षा का अधिक विकास नहीं हो सका। इसका मूल कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी की दूषित राजनीति थी। कम्पनी के शासक भारत में उच्च शिक्षा के विकास के पक्ष में नहीं थे। उनको तो हार्डस्कूल तक शिक्षा ग्रहण किये हुए भारतीय नागरिकों की आवश्यकता थी जो जीवन भर लिपिक के पद को सुगोमित करते हुए सदैव गुलामी का जीवन व्यतीत करते रहें। इसके साथ ही उनमें एक दूषित भावना यह भी थी कि उच्च शिक्षा भारतीय नागरिकों में बौद्धिक विकास एवं राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दे सकती है। इस अवधि में उच्च शिक्षा का प्रारम्भ कलकत्ता मदरसा की स्थापना से हुआ जिसकी स्थापना १७८१ में हुई। इस मदरसे का शिलान्यास हेस्टिंग्स ने किया था। इस मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना था। इस काल में कई अंग्रेजी और प्राच्य—मरकाठी और बिज्जी—महाविद्यालय खुले। आरम्भ में ये संस्थाएँ माध्यमिक विद्यालयों के रूप में स्थापित की गईं किन्तु बाद में वे शीघ्र ही कालेज के रूप में परिवर्तित हो गईं। इस अवधि में स्थापित होने वाले प्रमुख कालेज बनारस संस्कृत कालेज (१७६१), हिन्दू कालेज, कलकत्ता (१८१७), श्री रामपुर कालेज (१८१८), स्कटिश चर्च कालेज, कलकत्ता (१८३०), विलसन कालेज, बम्बई (१८३२), एलफिन्स्टन कालेज, बम्बई (१८३५), क्रिश्चियन कालेज, मद्रास (१८३७), सेण्ट जोस कालेज, आगरा (१८३२) थे। इस काल में विश्वविद्यालय आरम्भ करने के प्रयत्न अवश्य हुए किन्तु सफलता न मिल सकी। वैसे १८३६ में मद्रास के तत्कालीन राज्य-पाल लार्ड एलफिन्स्टन ने मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोर्ट आफ डायरेक्टर के पास एक प्रस्ताव भेजा था, किन्तु यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

## २. १८२४ से १८८२ तक

इस अवधि में सन् १८२४ का बुढ़ चोपणा-मन प्रमुख था जिसने भारतीय

## अध्याय २

### उच्च शिक्षा

भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था आदि काल से ही रही है। वैदिक काल में गुरुकुलों एवं आश्रमों के रूप में अनेक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अपना कार्य कर रहे थे। ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों के लण्डन, मद्रास आदि भी उपस्थित हैं जो अपने में एक लम्बा इतिहास समोये बैठे हैं। प्राचीनक विश्वविद्यालयों में तत्कालीन की प्रसिद्धि सम्मने अधिक थी। मद्रास दूर-दूर के छात्र अध्ययन हेतु आते थे। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अधिक प्रगति हुई। इस युग के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में नालन्दा, काण्ची, विक्रमशिला तथा जलन्धी का नाम उल्लेखनीय है। इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी स्वतन्त्र थे जो अपने यहाँ के योग्य छात्रों को उपयुक्त विश्वविद्या-लयों में भेजते थे। इन विद्यालयों में प्रवेश पाना सरल काम नहीं था। प्रत्येक विश्व-विद्यालय में एक मेधावी छात्र को द्वारपाल की पदवी से विभूषित किया जाता था जिसका प्रमुख कार्य प्रवेश से पूर्व छात्रों की परीक्षा देना होता था।

भारत में प्रचलित इस उच्च शिक्षा-व्यवस्था को आषाढ आक्रमणकारी मुसलमानों ने पहुँचाया। उन्होंने धार्मिक स्थानों के कुछ स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में शिक्षा का माध्यम करवा दिया। अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली की आलोचना की और उसको अपनी शासकीय दृष्टि से अनुपयोगी मानकर सर्वेष्ट रूप से दूर कर दिया। वे इसे मुसलमान शासकों ने कुछ स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में शिक्षा का माध्यम करवा दिया। अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली की आलोचना की और उसको अपनी शासकीय दृष्टि से अनुपयोगी मानकर सर्वेष्ट रूप से दूर कर दिया। वे इसे मुसलमान शासकों ने कुछ स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में शिक्षा का माध्यम करवा दिया।

### ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा

भारत में आज शिक्षा का जो स्वरूप एवं व्यवस्था विद्यमान है वह मुख्य रूप से अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली की आलोचना की और उसको अपनी शासकीय दृष्टि से अनुपयोगी मानकर सर्वेष्ट रूप से दूर कर दिया। वे इसे मुसलमान शासकों ने कुछ स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में शिक्षा का माध्यम करवा दिया। अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली की आलोचना की और उसको अपनी शासकीय दृष्टि से अनुपयोगी मानकर सर्वेष्ट रूप से दूर कर दिया।

विश्वविद्यालय कानून के नाम से प्रसिद्ध है। इस कानून में निम्नलिखित बातें मुख्य थीं।

(१) विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने के साथ ही शिक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए उनको प्राध्यापक नियुक्त करने का अधिकार भी दे दिया गया।

(२) विश्वविद्यालयों के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई। वह कम से कम ५० और अधिक से अधिक १०० रहे। इन सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्ष रहा।

(३) सिन्डीकेटों को कानूनी स्वीकृति दी जाय तथा इसमें विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व हो।

(४) कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की सीनेट के सदस्यों की संख्या २० तथा अन्य नये विश्वविद्यालयों की सीनेट के सदस्यों की संख्या १५ होनी चाहिए।

(५) इस कानून के अनुसार सरकार सीनेट द्वारा बनाये कानून को संशोधित एवं परिवर्तित कर सकती थी।

(६) गवर्नर जनरल को यह अधिकार भी दिया गया कि वह विश्वविद्यालय के क्षेत्र निश्चित कर दे।

वैसे भारतीयों द्वारा इस कानून को सन्वेहारमक दृष्टि से देखा गया तथा इसकी आलोचना की गई, किन्तु यह सत्य है कि इस कानून ने भारतीय उच्च शिक्षा में कई उल्लेखनीय परिवर्तन किये।

लार्ड कर्जन के सुधार के कुछ वर्षों के बाद उच्च शिक्षा के पुनर्निरीक्षण की फिर से आवश्यकता पड़ी। सरकार ने २१ फरवरी, १९१३ को शिक्षा नीति पर अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया जिसकी प्रमुख विचारों इस प्रकार थी :

१. विश्वविद्यालयों में शिक्षण-व्यवस्था में सुधार किया जाय।
२. विश्वविद्यालयों में विस्तार किया जाय और लगभग प्रत्येक प्रान्त में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय क्योंकि ५ विश्वविद्यालय और १८५ कालेज देश की आवश्यकता की पूर्ति में असमर्थ हैं।
३. शिक्षण-कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया जाय।
४. विश्वविद्यालयों में छात्रावासों की व्यवस्था की जाय।

भारत में सन् १८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद सन् १९१६ तक किसी नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई। किन्तु कॉलेजों की संख्या में अवश्य वृद्धि हुई जो १९१० तक १८५ तक पहुँच गई थी।



शिक्षा के इतिहास में एक नया एवं महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। इस घोषणापत्र ने भारतीयों की उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। इनके बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की। साथ ही यह भी घोषणा की कि इनकी स्पर्धालु सन्तान विश्वविद्यालय पर आधारित होनी चाहिए। इस घोषणापत्र में निर्दिष्ट सिफारिशों के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सन् १८५७ में विश्वविद्यालय खोले गये। इनका शासन सीनेट को सौंपा गया। सीनेट का गठन कुलपति तथा सदस्यों के द्वारा होता था। स्थानीय राज्यपाल कुलपति होते थे। सीनेट के सदस्य दो प्रकार के होते थे—पदेन तथा सामान्य। सदस्यों की नियुक्ति जीवन भर के लिए होती थी। बाद में सिलीकेट की व्यवस्था की गई परन्तु अधिनियम में इसका उल्लेख न था।

विश्वविद्यालय किराये के भवनों में चलते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता प्राप्त करने वाले छात्रों की परीक्षा लेकर उन्हें उपाधियाँ प्रदान करना था। ये विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, चिकित्सा, कानून, और द्वितीय-रिग आदि के प्रमाण-पत्र प्रदान करते थे। उस समय परीक्षाओं का स्तर सन्तान विश्वविद्यालय के समान ही था। सन् १८८२ में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालयों के साथ ही कालिजों की संख्या में भी वृद्धि हुई। सन् १८८२ में कालिजों की संख्या ६८ थी।

उस समय के विश्वविद्यालयों में अनेक दोष भी थे। प्रथमतः विश्वविद्यालय केवल परीक्षा-संचालन करते थे। इनमें अध्ययन-प्रध्यापन का कार्य नहीं चलता था। अतः उच्च शिक्षा के प्रसार में वे कोई काम न कर सके। द्वितीय, इन विश्वविद्यालयों को कालिजों की कार्यवाही को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं था। तृतीय, सदस्यों की संख्या अत्यधिक थी और वे लाजवन्त सदस्य होते थे।

३ सन् १८८३ से १९१६-१७ तक

सन् १८८२ में नियुक्त प्रथम शिक्षा आयोग ने भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उसका एक सुझाव कालिजों को दिये जाने वाले अनुदान के बारे में था। उसने सिफारिश की कि कालिजों की सहायता देते समय कार्य की आवश्यकता एवं कार्यक्षमता, कालिज के पूर्ण व्यय, प्रध्यापकों की दक्षता और संख्या पर विशेष ध्यान रखा जाय और समय-समय पर अवन-निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं फर्नीचर आदि के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाय। इसके अतिरिक्त आयोग ने छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा उठाने का सुझाव भी दिया।

सन् १८९६ में लार्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसने उच्च शिक्षा के पु-संगठन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। १९०२ में नियुक्त इस आयोग ने अपनी रिपोर्टें ६ माह में प्रस्तुत कर दीं। इसी के आधार पर लार्ड कर्जन ने सन् १९०४ में एक कानून बनाया जो भारतीय

विश्वविद्यालय कानून के नाम से प्रसिद्ध है। इस कानून में निम्नलिखित बातें मुख्य थीं :

(१) विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने के साथ ही शिक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए उनको प्राध्यापक नियुक्त करने का अधिकार भी दे दिया गया।

(२) विश्वविद्यालयों के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई। वह कम से कम ५० और अधिक से अधिक १०० रहे। इन सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्ष रहा।

(३) मिस्ट्रीकेटो को कानूनी स्वीकृति दी जाय तथा इसमें विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व हो।

(४) कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की सीनेट के सदस्यों की संख्या २० तथा अन्य नये विश्वविद्यालयों की सीनेट के सदस्यों की संख्या ११ होनी चाहिए।

(५) इस कानून के अनुसार सरकार सीनेट द्वारा बनाये कानून को संशोधन एवं परिवर्तित कर सकती थी।

(६) गवर्नर जनरल को यह अधिकार भी दिया गया कि वह विश्वविद्यालय के क्षेत्र निश्चित कर दे।

जैसे भारतीयों द्वारा इस कानून को सन्वेष्टात्मक दृष्टि में देखा गया, इसकी आलोचना की गई, किन्तु यह सत्य है कि इस कानून ने भारतीयों के मन में कई उल्लेखनीय परिवर्तन किये।

लार्ड कर्जन के सुधार के कुछ वर्षों के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फिर से आवश्यकता पड़ी। सरकार ने २१ फरवरी, १९१३ को कानून अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया जिसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

१. विश्वविद्यालयों में शिक्षण-व्यवस्था

विश्वविद्यालय	कलिय
कलकत्ता	५८
मद्रास	५३
इलाहाबाद	३३
पंजाब	२४
बम्बई	१७

सन् १९१६ में प० मदनमोहन मालवीय ने बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय धनी तथा निर्धन सभी प्रकार के हिन्दुओं के दान से बना था। इसके निर्माण के लिए राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। १९१७ में मैसूर तथा पटना में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई।

#### ४. सन् १९१७ से १९४७ तक

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति होने से लोगों का ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ। उस समय तब शिक्षा में अनेक दोष उत्पन्न हो गये थे। उच्च शिक्षा में स्थापित दोषों को दूर करने के लिए सन् १९१७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नियुक्ति की गई। इस आयोग को देश के अन्य विश्वविद्यालयों की जाँच करने का भी अधिकार दिया गया। विश्वविद्यालय के कार्य के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये

- (१) एकात्मक, निरामात्मक एवं वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाय।
- (२) स्नातक का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो तथा इसके साथ ही 'ग्रामर्स बोर्ड' भी आरम्भ किया जाय।
- (३) प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थी बहुराज तथा शारीरिक शिक्षा का महत्त्व नियुक्त किया जाय।
- (४) विश्वविद्यालयों में विभिन्न उच्च विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
- (५) विश्वविद्यालयों को राजकीय नियंत्रण से मुक्ति मिलनी चाहिए।
- (६) विश्वविद्यालयों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों की नियुक्ति की जाए।
- (७) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा रीढ़ों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखितों की सर्वाधिकार निर्माण किया जाए।

इस आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत में अनेक नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जो निम्नलिखित हैं

रगून और ढाका—१९२०, लखनऊ और अलीपुर—१९२१, दिल्ली—१९२२, नागपुर—१९२३, आन्ध्र—१९२६, आगरा—१९२७, अन्नामलय—१९२९, ट्रावनकोर—१९३७, उत्कल—१९४३, सायर—१९४६, सिंध तथा राजपूताना—१९४७। इस अवधि में कॉलेज एंव छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई।

५. सन् १९४७-४८ से १९६६ तक

विभाजन के बाद स्वतन्त्र भारत में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जिनके नाम सबसे पीछे दिये गये हैं। सन् १९४७ में वहाँ २० विश्वविद्यालय थे वहाँ १९६६ में इनकी संख्या बढ़कर ६४ हो गई थी। सन् १९६५-६६ तक महाविद्यालयों की संख्या २,५६५ थी।

विभाजन के पश्चात् उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना डा० राधा-कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग की स्थापना थी। इस आयोग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए -

- (१) विश्वविद्यालयीय शिक्षा इष्टरमीडिएट के पश्चात् प्रारम्भ की जाए।
- (२) आगस में एक वर्ष पश्चात् तथा स्नातक परीक्षा के दो वर्ष पश्चात् स्नातकोत्तर उपाधि दी जाए।
- (३) विश्वविद्यालय में सामान्य शिक्षा के सिद्धान्तों के अध्ययन की व्यवस्था की जाए।
- (४) आयोग ने विश्वविद्यालय के अध्यापकों को चार धैनियों में विभाजित किया और सुझाव दिया कि इनकी वेतन-दरों में साम्य होना चाहिए।
- (५) विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हों—शैक्षणिक, सम्बद्ध तथा संघात्मक।
- (६) महाविद्यालय के वार्षिक कार्य-दिनों की न्यूनतम संख्या १८० रहे।
- (७) पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएँ सुसज्जित तथा साज-सम्मान से सज्जित हों।
- (८) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुसन्धान की विधियों का प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाए।
- (९) विश्वविद्यालयों को धन का वितरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करे।
- (१०) जब सम्भव हो तब शीघ्र ही उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को अपनाया जाय।
- (११) सभी संस्थाओं में एन० सी० सी० दल का संगठन हो।

## कोठारी आयोग

भारत सरकार के १४ जुलाई, १९६४ के प्रस्ताव के अनुसार इस शिक्षा आयोग का गठन हुआ जिसका उद्देश्य सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय प्राप्ति, शिक्षा के प्रायोगिक स्तर और गठनको के सम्बन्ध में नीतियों के लिए राय देना था। इस आयोग के अध्यक्ष डा० दीनानाथ कोठारी थे। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणा के लिए जो सुझाव दिये वे निम्नलिखित हैं।

(१) वर्तमान विश्वविद्यालयों में से ६ विश्वविद्यालयों को १९६६-६७ में अनुसूचित कार्य हो। इनमें से कम से कम एक दृष्टि, एक टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय अवश्य हो।

(अ) इनमें अध्ययन की नियुक्ति राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाए।

(आ) गुण विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन केन्द्रों के समुह स्थापित किये जायें।

(इ) इन विश्वविद्यालयों के आकर्षण और अनुसंधान क्षेत्रों में परस्पर सम्पर्क रहे। अनुदान आयोग बहुत बने।

(२) मुख्य विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों में परस्पर सम्पर्क रहे। मुख्य विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता करे।

(अ) मुख्य विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके अन्य विश्वविद्यालयों में अध्ययन अवसरों में नियुक्त किया जाए।

(आ) मुख्य विश्वविद्यालयों में अन्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए आमन्त्रित किया जाय।

(इ) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय अपने लिए अध्ययन को सुन्दर कुछ समय के लिए मुख्य विश्वविद्यालय में भेज दें।

(३) सम्बद्ध महाविद्यालयों के विकास के लिए प्रयत्न किये जायें।

(अ) सम्बद्ध महाविद्यालयों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया जाए।

(आ) जहाँ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में यदि कोई पुराना तथा बड़ा महाविद्यालय हो तो उसे स्वयंसेवक महाविद्यालय का पद दे दिया जाना चाहिए। ऐसे महाविद्यालय पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रवेश के नियम सम्बन्धी कार्य स्वयं करेंगे।

(इ) शिक्षण एवं मूल्यांकन में सुधार के लिए आयोग के मुख्य सुझाव

(अ) कक्षा कार्य में से कुछ घण्टों की कमी करके उस बचे हुए समय में स्वाध्याय, लेख लिखने तथा अनुसंधान के कार्य करवाये जायें।

(आ) अच्छे पुस्तकालय बनाने पर जोर दिया जाए।

(इ) अध्यापकों की नियुक्तियाँ सत्र के आरम्भ में कर दी जायें।

(ई) शिक्षा सस्थान विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण-विधियों के सम्बन्ध में शोधकार्य करें।

(उ) विश्वविद्यालयों में बाह्य परीक्षाओं के स्थान पर आन्तरिक एवं क्रमिक मूल्यांकन पद्धति को अपनाया जाए।

(५) १० वर्ष की आयु की आयु से शैक्षणिक भाषाएँ विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम बना दी जायें।

(अ) पूर्व-स्नातक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ हों और स्नातक-स्तरीय स्तर पर अंग्रेजी माध्यम हो।

(आ) आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए।

(इ) अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य प्रमुख पुस्तकालयीय भाषाओं के अध्यापन की भी सुविधा होनी चाहिए।

(ई) छात्र सेवाओं के अन्तर्गत छात्रों के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएँ, आवास सुविधा, निर्देशन एवं परामर्श आदि आयोजित की जायें।

(७) बढ़ती हुई छात्र अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिए भी आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये :

(अ) अनुशासनहीनता को कम करने के लिए विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक, सरकार एवं राजनैतिक दलों को अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए।

(आ) इस प्रकार के प्रणामन एवं परामर्श की व्यवस्था की जाए कि छात्रों के असंतोष के कारण शांत करके उनका उपचार किया जा सके।

(इ) महाविद्यालयों में बौद्धिक एवं सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

(ई) विश्वविद्यालयों में अध्यापक, विद्यार्थी और प्रशासन की दल-बन्धियाँ समाप्त करके अच्छा वातावरण बनाया जाए।

■ प्रवेश में सम्बन्धित सुझाव—(अ) विश्वविद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी योग्यताओं का निश्चय किया जाए।

(आ) परीक्षाओं के बच्चों के आधार पर प्रवेश की व्यवस्था की जाए।

(इ) विश्वविद्यालयों में प्रवेश परिपक्व प्रवेश के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए स्थापित किये जाएँ।

३६ | भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

(ई) स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान के प्रवेश के लिए कठोर नियम बनाये जाएँ।

(उ) जनता की माँग होने पर स्नातक स्तर तक अलग स्त्री महाविद्यालय स्थापित किए जाएँ।

६. नये विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में सुझाव—(अ) बम्बई, बनारस, दिल्ली तथा मद्रास में अनुर्य पञ्चवर्षीय योजना तक दो-दो विश्वविद्यालय होने चाहिए।

(आ) उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है।

१०. पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण—(अ) स्नातक स्तर पर सामान्य, विशेष एवं मानस के पाठ्यक्रम होने चाहिए।

(आ) पी० एच०डी० करने वाले छात्र को दो या तीन वर्ष तक कार्य करना चाहिए।

(इ) पी० एच०डी० की उपाधि के मूल्यांकन के तरीके में सुधार की आवश्यकता है।

११. विश्वविद्यालयों का अभिलासन—(अ) विश्वविद्यालय की प्रभुता बनाये रखने की ओर ध्यान देना चाहिए। यह प्रभुता विद्यालयों के चुनाव, अध्यापकों की तरफ़ी, पाठ्यक्रम के निर्माण और शोध के लिए समस्याओं के ध्यान में देखी जानी है।

(आ) विश्वविद्यालयों की प्रभुता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

(इ) राज्य सरकारों की विश्वविद्यालयों की पर्याप्त अनुराग देनी चाहिए।

(ई) अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय के विभाग कार्यक्रम को ध्यान में रखकर अनुदान देना चाहिए।

(उ) विश्वविद्यालयों को सरकार तथा जनता द्वारा हिमाय-विनाश की जीव करने में मुक्त रखा जाए।

१२. उपबन्धन की सुनाय तथा कार्यक्रम—उपबन्धन का चुनाव विभिन्न या बुनियाद के हाथ में होना चाहिए। इस पर प्रसिद्ध शिक्षा सारणी एवं मुसल प्रशासक की निर्दिष्ट होनी चाहिए। उपबन्धन का कार्यक्रम पाँच वर्ष का हो। यह पर नैतिक होना चाहिए।

१३. विश्वविद्यालय के विभाग में सर्वव्यवस्था सुधार—(अ) कोटों द्वारा विश्वविद्यालय की नीति निर्धारण सम्बन्धी कार्य होना चाहिए। हमने १०० में अधिक सराव नही होने चाहिए।

(भा) कार्यकारिणी परिषद् में १५ से २० तक सदस्य हों एवं उपकुलपति इसका अध्यक्ष होना चाहिए ।

(द) पाठ्य-विषयों तथा मानदण्डों के निर्धारण का कार्य एकेडेमिक काउन्सिल के हाथ में होना चाहिए ।

(ई) विश्वविद्यालयों में योजना एवं मूल्यांकन के लिए एक बोर्ड बनाया जाय ।

१४. सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए सुझाव—(अ) महाविद्यालयों को मान्यता राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने के बाद ही विश्वविद्यालय को देनी चाहिए ।

(आ) सभी विश्वविद्यालयों में एक-एक सम्बद्ध महाविद्यालय परिषद् होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय को यह परामर्श दे कि किस महाविद्यालय को मान्यता दी जाए ।

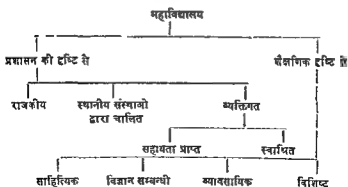
(इ) गैर-सरकारी महाविद्यालयों को विशेष सुविधा, साधन एवं स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए ।

## उच्च शिक्षा का वर्तमान स्वरूप

उच्च शिक्षा के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए निम्नलिखित विषयों की वर्षा अधिक सहायक मिट्टी होगी—(१) महाविद्यालयों का वर्गीकरण, (२) विश्व-विद्यालयों का वर्गीकरण, (३) विश्वविद्यालय और शासन का परस्पर सम्बन्ध, (४) विश्वविद्यालय का संगठन ।

### महाविद्यालयों का वर्गीकरण

प्रशासन की दृष्टि से महाविद्यालयों का वर्गीकरण निम्नलिखित हो सकता है





महाविद्यालय १९५६-६० के अनुसार<sup>१</sup>

	आर्थिक रूप विवरण महाविद्यालय	आवृत्त महाविद्यालय	विशेष शिक्षा महाविद्यालय
राष्ट्रीय	१६०	१६१	१२
स्थानीय महाविद्यालय	१	४	—
महाविद्यालय	१६१	१६५	१२
(i) महाविद्यालय	१६१	१६५	१२
(ii) विश्वविद्यालय	१६१	१६५	१२
कुल महाविद्यालय	१६१	१६५	१२

### विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण

भारत में इस समय तीन प्रकार के विश्वविद्यालय हैं—(१) सामान्य, (२) संशोधन, और (३) व्यावसायिक।

व्यावसायिक विश्वविद्यालय—व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की विधिविनियमित शिक्षण कार्य होनी है :

- ऐसा विश्वविद्यालय आर्थिक तथा शैक्षणिक होना है।
- इसका क्षेत्र शिक्षा भी एक केन्द्र में सीमित रहना है।
- शिक्षण कार्य विश्वविद्यालय के अपने विभागों अथवा महाविद्यालयों द्वारा होता है।
- ऐसा विश्वविद्यालय अपना प्रबन्ध, प्रशासन एवं अध्ययन का परिचालन स्वयं करता है।

सामान्य विश्वविद्यालय—सामान्य विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

- विश्वविद्यालय का क्षेत्र एक केन्द्र में ही सीमित रहना है। अतः उसके अधीन महाविद्यालय पाम-पाम रहते हैं।
- प्रत्येक महाविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर का कार्य होता है।
- विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय अध्ययन कार्य चलाते हैं।
- विश्वविद्यालय का नियंत्रण होने के कारण महाविद्यालयों को आन्तरिक स्वतन्त्रता में कमी हो जाती है।

**सम्बद्ध विश्वविद्यालय**—इस प्रकार के विश्वविद्यालय की कुछ विशेषताएँ अधोलिखित हैं :

- (i) ये विश्वविद्यालय बाहरी महाविद्यालयों की मान्यता प्रदान करते हैं।
- (ii) ऐसे विश्वविद्यालयों का कार्यक्षेत्र दूर-दूर मयूरों एवं गाँवों तक विस्तृत होता है।
- (iii) पाठ्यक्रम का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।
- (iv) महाविद्यालयों के सफल होने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करता है।
- (v) विश्वविद्यालय समय-समय पर महाविद्यालयों का निरीक्षण करता है और देखता है कि महाविद्यालय मान्यता प्राप्त नियमों का पालन कहीं तक कर रहे हैं।

### विश्वविद्यालय तथा दासन का प्रबन्ध

भारत में कुछ विश्वविद्यालयों पर सीधे केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है। ये विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली, अलीपुर, तथा विश्व भारती हैं। इनके अनिर्दिष्ट क्षेत्र विश्वविद्यालय प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं। प्रान्तीय सरकार इन विश्वविद्यालयों की स्थापना करती हैं तथा इनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। इनके अनिर्दिष्ट अन्य सभी क्षेत्रों में ये विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होते हैं।

### विश्वविद्यालय का संगठन

विश्वविद्यालय का संगठन निम्न प्रकार से होता है :

विश्वविद्यालय का प्रधान कुलपति होता है। बहुधा राज्य का राज्यपाल ही कुलपति होता है। जिन प्रान्तों में एक से अधिक विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ एक को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों को कुलपति के निर्वाचन का अधिकार प्राप्त है।

कुलपति के बाद उपकुलपति का स्थान है। यही विश्वविद्यालय का मुख्य शासक होता है। इसकी नियुक्ति सर्वत्र एकसी नहीं है। कहीं ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, कहीं इनका निर्वाचन सिण्डिकेट द्वारा और कहीं सीनेट द्वारा होता है। इनका कार्यकाल ३ वर्ष से ५ वर्ष तक होता है। आरम्भ में यह पद अवैतनिक था किन्तु बाद में कार्य की जटिलता एवं अधिकता को देखते हुए वैतनिक बनाया गया।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में सञ्चालन तथा नियन्त्रण करने वाली समिति को अधिकरण (Court) कहते हैं। इसी को सीनेट के नाम से भी पुकारते हैं। अधिकरण में आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। इसके सदस्य पदेन, मनोनीत एवं निर्वाचित होते हैं। अधिकरण द्वारा वार्षिक एवं दैनिक कार्यों का अन्तिम निर्णय किया जाता है।

धीरे-धीरे के बाद आर्थिक विद्या परिषद् (Academic Council) तथा निरीक्षक आने लगे। प्रथम परिषद् का गठन केवल सी.एन.ए. द्वारा ही हुआ है। निरीक्षक को निरीक्षण परिषद् (Inspective Council) भी कहते हैं। यह विश्वविद्यालय की प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है।

प्रशासनिक कार्यवाही

विश्वविद्यालय में व्यवस्था को प्रशासनिक कार्यवाही है। इसका अर्थ है प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थापक कार्यवाही के अन्तर्गत रखना।

१. अन्तर-विश्वविद्यालय परिषद्— इस परिषद् की स्थापना १९५७ में प्रथम बार कला विश्वविद्यालय आयोग में किया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों के कार्य में समन्वय स्थापित करना था। सन् १९२६ में शिक्षा में हुए एक सम्मेलन में इसकी स्थापना का निर्णय किया गया। इस परिषद् का प्रधान कार्यवाही केन्द्र में रखा गया। परिषद् के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

- (i) भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों के कार्य में समन्वय स्थापित करना।
- (ii) अन्तर-विश्वविद्यालय स्तर पर सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- (iii) अध्ययन के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।
- (iv) भारतीय विश्वविद्यालयों की उपाधियों को विदेशों में मान्यता प्राप्त करने में सहायता करना।
- (v) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि भेजना।
- (vi) भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली उपाधियों की परस्पर मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- (vii) विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए सम्मेलन बुलाना।

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—सर्वोच्च योजना ने एक प्रस्ताव विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में दिया। उसी का परिणाम यह हुआ कि सन् १९४५ में एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति की नियुक्ति की गई। दुर्भाग्यवश यह समिति केवल ५ वर्ष तक ही कार्य कर सकी। किन्तु राष्ट्रीय आयोग ने पुनः इस आयोग की स्थापना के लिए सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर सन् १९५३ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गयी।

के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :

१. केन्द्रीय सरकार को उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के मागदण्ड को ठीका करने के विषय में परामर्श देना ।
२. विश्वविद्यालयों को आर्थिक अनुदान देना ।
३. केन्द्रीय सरकार के अनुसार उच्च शिक्षा सम्बन्धी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करना ।
४. केन्द्रीय या राज्य सरकारों को किसी विश्वविद्यालय की शिष्यों की भाग्यता के विषय में परामर्श देना ।
५. उच्चमध्य धनराशि को भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में वितरित करना ।
६. नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में सुझाव देना ।
७. किसी विश्वविद्यालय के विस्तार के सम्बन्ध में सुझाव देना ।

सन् १९५६ में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे एक स्वतन्त्र संस्था का स्थान प्राप्त हो गया है । इस आयोग का संयटन इस प्रकार है—(अ) अध्यक्ष, (आ) मंत्री, (इ) नौ सदस्य । नौ सदस्यों में विश्वविद्यालयों के उपकुलपति—३, भारत सरकार द्वारा मनोनीत—२, नामजद प्रमुख शिक्षाशास्त्री—४ सदस्य होते हैं ।

### उच्च शिक्षा की समस्याएँ

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जायेगा—

१. उच्च शिक्षा के प्रसार की समस्या—यह तो आँखों से स्पष्ट ही है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय की शिक्षा का विस्तार अधिक हुआ है । सन् १९४८ में भारत में बना एक विज्ञान वाणिज्य के छात्रों की संख्या १,७६,१७३ थी । यह १९५७ में बढ़कर ६,२३,४०७ हो गई । इसी प्रकार संख्या में वृद्धि व्यावसायिक महाविद्यालयों में भी हुई । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारतीयों में उच्च शिक्षा पाने की इच्छा बलवती हुई है ।

शिक्षा विकास की एक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि स्वतन्त्रता के बाद व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार अधिक हुआ है । इसके प्रसार के पीछे तीन पंचवर्षीय योजनाएँ रही हैं जिनमें देश के आर्थिक विकास के कार्यक्रम की योजना थी । इनके साथ ही साहित्यिक एवं वाणिज्य शिक्षा का भी प्रसार हुआ । कुछ भी हो, यह तो निश्चित ही है कि इस प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर गिरा है । निम्न तालिका से प्रथम तीन योजनाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि स्पष्ट होती है :

तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि कला, वाणिज्य तथा विज्ञान के स्नातक स्तर पर १९५०-५१ में १६१,००० छात्रों की संख्या थी जो १९६५-६६ में बढ़कर ७५६,००० हो गई । यह वृद्धि ६६ प्रतिशत प्रति वर्ष की गति से हुई ।

उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६
कला, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक स्तर पर	१९१	३२२	४३४	७५६
कला, विज्ञान एवं अनुसंधान में स्नातकोत्तर स्तर पर	१८	२८	५१	८६
व्यावसायिक स्नातक	५०	८२	१४७	२२७
स्नातकोत्तर	५४	८६	१६०	२४६

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सन् १९५०-५१ में संख्या १८००० से बढ़कर १९६५-६६ में ८६,००० हो गई। यह वृद्धि ११ प्रतिशत वार्षिक हुई। यदि भविष्य में होने वाली छात्र संख्या की वृद्धि को देखें तो हमकी ISI पर द्वारा की गई भविष्यवाणी का अवलोकन करना होगा जिसमें गणना द्वारा बताया गया है कि १९७५ तथा १९८५ में विज्ञानी वृद्धि सम्भव है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है।

शिक्षा का प्रकार	सम्भावित प्रवेश (हजारों में)	
	१९७५-७६	१९८५-८६
१. स्नातक (मानविक)	१,३५०	२,१४२
२. स्नातक (व्यावसायिक)	४८१	६७२
३. बानुन शिक्षा स्नातक	५०	७६
४. स्नातकोत्तर	३२१	६९०
योग	२,२०२	४,१९०

इस प्रकार विश्वविद्यालयों में बढ़ती जा रही भीड़ के अनुसार महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्थान विस्तार एवं शिक्षा साधनों में वृद्धि नहीं हुई है। आज हर नगर के विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश पाना बड़ा हो गया है।

इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि आवश्यकानुसार नवीन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके साथ ही महाविद्यालयों की प्रवेश-संख्या को बढ़ाया जाए। विश्वविद्यालयों की स्थापना राजनीतिक दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। यह ऐसी अवस्था उत्पन्न हो नहीं अनेक मूल्य तथा शिक्षण विधियों के महाविद्यालय हो। नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से कोयलरी काल में उत्पन्न की समस्या दूर है।

२. छात्रों के चयन की समस्या—स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में विश्व-विद्यालयीय शिक्षा के योग्य एवं अयोग्य सभी प्रकार के छात्र प्रवेश चाहते हैं। इनके दो दुष्परिणाम हुए हैं—एक तो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थान का अभाव तथा दूसरे उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट। अतः यह भाग की जाती है कि विश्वविद्यालयों में केवल योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। इस विषय में श्री चिन्तामणि देशमुख ने भी कहा था कि “अब वह समय आ गया है जबकि हमें निर्णय करना है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा केवल योग्य छात्रों को दी जाए।” यदि वर्तमान गति से अगले २० वर्ष में भी उच्च शिक्षा के विस्तार की कल्पना की जाय तो १९५१-५६ में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या ७-८ लाख के लगभग होगी। यह संख्या देश के विकास के लिए आवश्यक मानव-शक्ति की दोगुनी होगी। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में यह सम्भव नहीं है कि उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए इतने धन की व्यवस्था की जा सके और न यह सम्भव है कि इन गति से निकलने वाले समस्त स्नातकों को उचित नियुक्ति मिल सके। अतः यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा में चुने हुए प्राध्यापकों को प्रवेश दिया जाए। योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर शिक्षा के स्तर का ऊँचा उठना स्वाभाविक है। कोठारी आयोग भी सर्वेक्षण के आधार पर इन निष्कर्षों पर पहुँचा कि अधिकांश जनमत अब इस विचार की पुष्टि करता है कि सभी प्रकार के छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश न दिया जाए।

उच्च शिक्षा में चुने हुए छात्रों को प्रवेश देने के लिए तीन तत्वों पर ध्यान देने के लिए कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है :

१. एक संस्था में अध्यापकों एवं अन्य सुविधाओं के अनुसार ही रिक्त स्थान निश्चित किये जायें।
२. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताएँ निश्चित की जायें।
३. प्रवेश के इच्छुक एवं उपयुक्त छात्रों में से सर्वोत्तम का चयन सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जाए।

इसके साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालय की सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रत्येक विभाग में प्रवेश के स्थान सुविधाओं को ध्यान में रखकर निश्चित कर देने चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालयों को कुछ आदर्श निश्चित करने चाहिए जो स्थान निश्चित करने समय मार्ग-दर्शन करें। इनमें से कुछ ये हैं—अध्यापक-छात्र का अनुपात, स्व-अध्ययन के लिए उपयुक्त सुविधाएँ, पुस्तकालय पुस्तक, पुस्तकालय की क्षमता आदि।

चयन की विधि—साधारणिक स्तर पर शिक्षा का स्तर ऊँचा उठने पर महा-विद्यालयों में प्रवेश की आवश्यक बातों को पूरा करने वाले छात्रों की संख्या उनके निश्चित स्थानों से कहीं अधिक होगी। अतः विद्यालयों के सामने उनमें से छांटने की समस्या भी सामने आयेगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को अपनी परम्परा एवं स्थानीय दशाओं के अनुसार उपयुक्त प्राप्तिव्यो में से उत्तम छात्रों का चयन करने की अपनी विधि का निर्माण करना चाहिए। कुछ विधियाँ चयन के लिए निर्मलक्षित हो सकती हैं।

परीक्षाओं के अंक—बैसे परीक्षा के अंकों को आवश्यक प्रवेश के लिए एक प्रमाण माना जाता है किन्तु बोध द्वारा पता चला है कि विद्यालय के अंक एवं महाविद्यालयों में सफलता के मध्य सह-सम्बन्ध अधिक सार्थक नहीं आता है। इन अंकों की विश्वसनीयता कम होती है। किन्तु जब तक मध्य आधार नहीं बनता तब तक अंकों के साथ-साथ प्रवेश के समय कुछ अन्य विधियों की ओर ध्यान देना चाहिए।

परीक्षा अंकों के साथ, विद्यालय के आलेख, छात्र की उन क्षमताओं में कुशलता जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, आदि को चयन का आधार बनाया जा सकता है। प्रवेश में पूर्ण साक्षात्कार एवं अभिव्यक्ति परीक्षा की भी सहायता ली जा सकती है।

कोठारी आयोग ने एक सुझाव यह भी दिया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रवेश परीपद का गठन किया जाए। इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक-सम्बद्ध महा-विद्यालयों के अध्यापक एवं प्रशासक वर्ग के प्रतिनिधि हों। एक सुझाव यह भी था कि अनुदान आयोग को एक केन्द्रीय परीक्षण सप्लन की स्थापना करनी चाहिए जो चयन के लिए आवश्यक परीक्षाओं का निर्माण करे।

३. शिक्षा के स्तर की समस्या—आजकल बहुधा लोग यह कहते हुए पापे जाते हैं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का दालपण नीचा है। इसका मूल कारण अध्यापन स्तर का बोरो-बीरो नीचे गिरते जाना है। शैक्षणिक मानदण्ड की पिराबट के मुख्य कारण योग्य अध्यापकों का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षण-यन्त्रियाँ, अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सम्पर्क की कमी हैं।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् जिन गति से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है उस गति के साथ योग्य अध्यापकों का पर्याप्त महत्वा में उपलब्ध होना एक समस्या हो गई है। अन्य उच्च वेतन वाले पर योग्य व्यक्तियों के आकर्षण के केन्द्र बने रहते हैं। परिणाम यह होता है कि होनहार नवयुवक अध्यापक बनना पान्द नहीं करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि महाविद्यालयों एवं विश्व-विद्यालयों के अध्यापकों के लिए आकर्षक वेतन रखे जायें। इसके साथ ही नये नियम वृत्ति के पद हों। इनमें से कुछ विद्यालयों को अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाए।

नये अध्यापकों को शिक्षण-पद्धति का थोड़ा ज्ञान अवश्य मिलना चाहिए। इसके लिए अल्प अवधि का पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा अध्यापन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समीक्षित किया जाय। इसके साथ ही अध्यापकों को प्रति सप्ताह २० से कम घण्टे पढ़ाने का भार दिया जाये। उनके बैठने, शोधकार्य करने की सुविधा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य निकट सम्पर्क स्थापित होने के लिए आवश्यक है कि एक कक्षा वर्ग में ५० से अधिक छात्र न हों।

शिक्षा के स्तर की गिरावट का एक कारण खिचड़ी भाषा का माध्यम होना है। आजकल अधिकांश अध्यापक अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा का मिश्रित रूप अपनाते हैं। परिणाम यह होता है कि छात्र का न तो एक भाषा पर अधिकार ही हो पाता है और न मौखिक चिंतन का प्रोत्साहन ही मिलता है। अतः अब तो अध्यापकों को भी क्षेत्रीय भाषा पर इतना अधिकार करना चाहिए कि वे उसके माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकें।

४. अनुशासन एवं सामाजिक समायोजन—विद्यार्थियों में बढ़ रही अनुशासन-हीनता आजकल माता-पिता, राजनैतिक नेता एवं विद्याशास्त्रियों के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। इसके कारणों एवं उपचार के सम्बन्ध में बहुत कुछ निष्ठा-पड़ा गया है किन्तु यह धीमारी कम होने की अपेक्षा बढ़ती ही जाती है। छात्र असन्तोष के प्रमुख कारण भविष्य की अनिश्चितता, पाठ्य सहायमी कार्यक्रमों का असन्तोषजनक रूप, अध्ययन एवं अध्यापन की अपर्याप्त सुविधाएँ, अध्यापक एवं विद्यार्थियों में सम्पर्क का अभाव, अध्यापकों में कुशलता का अभाव, संस्था के प्रधान में दहता, कुशलता एवं कल्पना-भक्ति की कमी, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों में दलबन्दी, राजनैतिक दलों का दखन आदि हैं। इसके साथ ही प्रौढ़ों में अनुशासन का अभाव एवं नागरिक उत्तरदायित्व के प्रति चेतना की कमी भी छात्रों को प्रभावित करती है।

वर्तमान राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि नवयुवक एवं नवयुवतियाँ सम्य व्यवहार करना सीखें। जैसे छात्र असन्तोष को दूर करने का उत्तरदायित्व केवल विद्यालयों का ही नहीं है। किन्तु फिर भी शिक्षा संस्थाओं को कुछ-न-कुछ करना चाहिए। इसके लिए उन शैक्षिक अभावों को दूर करना आवश्यक है जो इस असन्तोष को बढ़ावा देते हैं, तथा एक परामर्श एवं प्रशासकीय सेवा का गठन किया जाए जो ऐसी घटनाओं को होने से रोक सके। इस सेवा संगठन में अध्यापक, छात्र एवं उप-नृत्तपति को सदस्य बनाया जाए।

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्र सेवाओं का गठन किया जाए। इन सेवाओं में स्वास्थ्य सेवा, निर्देशन एवं परामर्श सेवा, छात्र क्रियाएँ एवं छात्र सभ प्रमुख हैं। ये ही सेवाएँ छात्रों में सामाजिक समायोजन में सहायक हो सकती हैं।



विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की सूची<sup>१</sup>

स्थापना वर्ष	विश्वविद्यालय	महाविद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष	विश्वविद्यालय	महाविद्यालयों की संख्या
१८५७	कनकलता विश्वविद्यालय	१६८	१८५२	एस० बी० विद्यापीठ	१३
	बम्बई	५८		जादवपुर	४
	मद्रास	१५७	१८५६	कुरुक्षेत्र	३६
१८८७	इलाहाबाद	६	१८५७	विक्रम	४१
१८९६	बनारस हिन्दू	१८		गोरखपुर	२१
	मैसूर	६३		जवहरपुर	७५
१८९७	पटना	१०	१८५८	वार्नरिय	२८
१८९८	उस्मानिया	६१		मराठवाडा	४
१८९९	अलीगढ़ मुस्लिम	४	१८६०	प० प्र० कृषि	४३
१९०१	लखनऊ	१८		बर्धमान	—
१९०२	दिल्ली	४१	१८६०	कल्याणी	४४
१९०३	नागपुर	८४		भागलपुर	३५
१९०४	आन्ध्र	६१		रांची	२८
१९०५	आगरा	१४३	१८६१	दरभंगा संस्कृत	५
१९०६	अग्रामलाई	—	१८६२	पंजाब कृषि	६
१९०७	केरल	१४०		पञ्जाबी	३
१९०८	उत्कल	७२		उड़ीसा कृषि	१६
१९०९	सागर	७७		उ० बंगाल	२०
१९१०	राजस्थान	७५		रवीन्द्र भारती	३४
१९११	पंजाब	१४६		मयघ	२
१९१२	गोहाटी	३४		जोधपुर	११
१९१३	जम्मू और काश्मीर	—	१८६४	उदयपुर	५१
१९१४	रङ्गूनी	४६		शिवाजी	१७
	पूना	५३		इन्दौर	३०
	कर्नाटक	६		जीवाजी	३
	एम० एम० पूना	१२५		कृषि विज्ञान हेबल	६
१९१०	मुजरात	८		बंगलौर	—
१९११	विश्व भारती	४४	१८६५	जवाहरलाल नेहरू	८
१९१२	बिहार	२८		कृषि	३४
१९१४	वैकेटेश्वर	—	१८६६	द्विगुण्ड	—
				मदुराई	—



## अध्याय ३

### स्त्री-शिक्षा

भारतीय संस्कृति और साहित्य इन बातों के प्रमाण हैं कि यहाँ धार्मिक मान्यताओं के समाज में नारी की सम्माननीय स्थान प्राप्त होना रहा है। किन्तु भारत में शिक्षा के क्षेत्र पर जब से कुछ विदेशियों के चरण पड़े, यहाँ के लोगों में स्त्री-शिक्षा, उसकी स्वतंत्रता आदि के बारे में दृष्टिकोण बदलता चला गया। सन् १९४७ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से लोगों की रुढ़िवादी सामाजिक मान्यताएँ धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही हैं और आज देश में स्त्री-शिक्षा की प्रवृत्ति के प्रति भारतवासियों की रुचि बढ़ती जा रही है। इसकी पुष्टि के लिए भारतीय मंत्रिपरिषद् की यह धारा ही पर्याप्त होनी जिसमें विद्यों की पुरुषों के समान ही अधिकार दिये हैं और यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष में कोई विभेद नहीं किया जायेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६ के अनुसार "राज्य किसी नागरिक के विवेक केवल धर्म, वंश, निग, जाति, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" इस परिवर्तित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति आज राष्ट्रीय जीवन में स्त्री-शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार कर रहे हैं। किन्तु श्रेष्ठ बात विषय यह है कि स्त्री-शिक्षा के प्रति जन चेतना होने लगी है और तीव्र गति से अपने पथ पर अग्रसर नहीं हो रही है। इसके पीछे निहित कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक है कि स्त्री-शिक्षा के इतिहास का सिद्धान्तोपन किया जाय।

### ऐतिहासिक रूपरेखा

हिन्दू युग—प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा की दशा से सम्बन्धित पर्याप्त साधन

"The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them"

—Article 15 of the Constitution of Free India

उपलब्ध न होने से यह पता लगाना कठिन है कि उस समय में स्त्री-शिक्षा का प्रसार कैसा था, स्त्री-शिक्षा के प्रति जन-साधारण की क्या विचारधारा थी? वैसे उस युग में भी मैनेजी और मार्गी जैसी विदुषी पैदा हुईं किन्तु इनके आधार पर ही प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा के प्रसार के बारे में अनुमान लगाना तर्कगम्य प्रतीत नहीं होता।

**बौद्ध युग**—इस युग में स्त्री-शिक्षा के प्रति रुचि प्रकट करके इनको सगठित करने का प्रयास किया गया है। इस युग के इतिहास का अध्ययन करने में ज्ञात होता है कि उस समय बौद्ध विहारों में भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहा करते थे। इनकी शिक्षा की मूलोपकरण व्यवस्था थी। इनमें प्रेरणा पाकर हिन्दुओं ने भी स्त्री-शिक्षा के सगठन के लिए प्रयास किये। किन्तु एम० एन० मुकर्जी के अनुसार हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान के समय स्त्री-शिक्षा के प्रयासों को एक बड़ा धक्का लगा क्योंकि इसके प्रधान थी शहराचार्य स्त्री शिक्षा के बट्टर विरोधी थे।

**मुस्लिम युग**—मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना में भारत में चम्प रहे स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों को अत्यधिक डेरा पहुँची। इसके दो प्रमुख कारण थे जो वर्तमान युग में सामाजिक कुप्रथा के रूप में मान्य हैं—प्रथम पर्दा प्रथा और द्वितीय बाल-विवाह। मुस्लिम साम्राज्य में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उपर्युक्त दोनों प्रथाओं का श्रीगणेश हुआ। उपर्युक्त प्रथाएँ हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों वर्गों में प्रचलित थी। इन प्रथाओं का कुप्रभाव यह था कि बालिकाओं की शिक्षा प्राथमिक स्तर तक ही सीमित रही। केवल उच्च वर्ग की बालिकाएँ प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा मकानों में जाकर प्राप्त करती थी।

## आधुनिक युग

**ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में**—कम्पनी के शासन काल में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता रही। इनका कारण यह था कि कम्पनी को अपने शासकीय कार्यों के लिए शिक्षित युवकों की आवश्यकता थी, न कि शिक्षित युवनियों की। उस समय स्त्री-शिक्षा की दशा का विवरण करते हुए एडम्स महोदय प्रतिवेदन में लिखते हैं कि "समस्त स्थापित शिक्षा संस्थाएँ केवल पुरुषों के लाभार्थ ही हैं और सम्पूर्ण महिला जगत अज्ञानता रूपी अंधकार में विचरण करता है।" परिणामस्वरूप, इस काल में बालिकाओं की शिक्षा कुछ इने-गिने ऊँचे वर्ग के परिवार तक ही सीमित रही।

इस युग में मिशनरियों द्वारा सर्वप्रथम स्त्री-शिक्षा का आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। टेम्पेहेयर ने सन् १८२० में इस प्रकार की एक पाठशाला सर्वप्रथम कसकसा में स्थापित की। तबसे अधिक प्रेरणास्पद कार्य बंगाल की शिक्षा परिषद् ■ प्रधान जे० ई० डी० वेम्पून का रहा जिन्होंने १८४६ में अपनी सम्पूर्ण आय से एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। सन् १८५४ तक बालिकाओं के लिए मद्रास में १५६, बम्बई में ५६ और बंगाल में १८८ विद्यालय कार्य करने लगे थे।

सन् १८५८ से १९०१-०२ तक

कम्पनी का शासन समाप्त होने पर भारत का शासन-मूल ब्रिटिश सरकार ने सम्हाला। सन् १८५४ के बृहद घोषणा-पत्र में भी स्त्री-शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए इसके प्रसार के लिए सुझाव दिये गये। ब्रिटिश शासन ने इस घोषणा-पत्र के आदेश को स्वीकार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। सरकार द्वारा अनेक स्थानों पर बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई। सन् १८७० में इंग्लैंड की सुधारक मेरी कारपेन्टर के भारत आगमन पर उनके प्रयत्नों से सर्वप्रथम महिला शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई।

सन् १८८२ में शिक्षा आयोग का गठन किया गया जिसके प्रधान विलियम हटर थे। इस आयोग ने तत्कालीन स्त्री-शिक्षा की दयनीय दशा को व्यक्त करते हुए लिखा है : "बहु स्पष्ट है कि स्त्री-शिक्षा अभी तक अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है।" इस बात की आवश्यकता है कि हर प्रकार से इसकी प्रगति के लिए प्रयास किये जायें।<sup>1</sup> आयोग ने स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये—(१) १२ वर्ष की आयु से ऊपर की बालिकाओं के शिक्षा-शुल्क में कमी की जाय और प्रोत्साहन हेतु कुछ बीस दी जाय। (२) अनुदान देने की शर्तों में बालिका विद्यालयों की निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाय। (३) बालिका विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए महिला में शिक्षण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। (४) विधवा महिलाओं को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीन नीति के फलस्वरूप आयोग की इन सिफारिशों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किये गये। सन् १९०१-०२ में बालिकाओं के लिए १२ कानेज, ४६७ माध्यमिक विद्यालय तथा ४६२८ प्राथमिक विद्यालय थे। प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाली छात्राओं की मर्यादा लगभग चार लाख थी। इसके अनिर्दिष्ट ४५ प्रतिशत तत्प्राप्त थी जिनमें १२३३ महिलाएँ अध्ययन-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी।

१९०२ से १९२१ तक

धीरे-धीरे स्त्री-शिक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता समाप्त होने लगी। इसी समय में लोगों में राष्ट्रीय जागरण की भावना बनने लगी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय जन बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे। सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया। इसी युग में तांडे बर्जन्स ने भी स्त्री-शिक्षा के मा को प्रवर्धन बनाने का प्रयास किया। १९१३ के शिक्षा-नीति समन्वयी सरकारी प्रस्ताव

1 "It will have been seen that female education is still in an extremely backward condition and that it needs to be fostered in every legitimate way"

■ सुभाषों ■ परिणामस्वरूप स्त्री-शिक्षा की प्रगति हुई । इस काल में कुछ महिला विद्यालयों की स्थापना के भी प्रयत्न विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये । सन् १९०४ में श्रीमती ऐनी बेमेन्ट ने 'सेटुल हिन्दु गर्ल्स स्कूल' की स्थापना बाराणसी में की । इसी प्रकार महर्षि अत्रा साहब बाबू ने सन् १९१६ में पूना में एम० एन० डी० टी० बीमेन्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कर स्त्री-शिक्षा के प्रचार में अग्रणीय सहयोग दिया । व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति के लिए सन् १९१६ में दिल्ली में 'सेडी हाइंग्र मेडीकल कॉलेज' की भी स्थापना की गई ।

सन् १९२२ से १९३६-३७ तक

इस अवधि में स्त्री-शिक्षा की बहुमुखी प्रगति हुई । इस प्रगति में पीछे देश के कर्मठ नेताओं, समाज सेवकों और स्वयं महिलाओं के प्रयत्न थे । भारत में सन् १९२६ में 'अग्निव भारतीय स्त्री मण' का गठन किया गया । इस मण ने भी सरकार से माँग की कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान विधि प्रचार की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय । इस अवधि की सर्वप्रमुख विशेषता सह-शिक्षा थी । इस प्रकार की शिक्षा का विरोध करने वालों की संख्या निरन्तर घटती जा रही थी । सन् १९३७ में सभी प्रकार के बालिका विद्यालयों की संख्या लगभग ३३,६८६ थी ।

सन् १९३७ से १९४६-४७ तक

इस अवधि में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की अत्यधिक प्रगति हुई । इस प्रगति के कई कारण थे । एक तो राष्ट्रीय ज्वाति अधिक हुई और दूसरे महात्मा गांधी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ-साथ सामाजिक कार्यों पर भी जोर दे रहे थे । इन सामाजिक कार्यों में से एक कार्य स्त्रियों की शिक्षा भी थी । इस काल में राष्ट्रीय भावना का संचार पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं एवं बालकों में भी हुआ । वे भी स्वाधीनता संग्राम में यातनाओं की परवाह किये बिना बूढ़ पड़ें । उनमें नवीन चेतना का संचार हुआ । अनेक महिलाएँ कार्यालयों में कार्य करने लगीं । आर्थिक स्वतन्त्रता के उपयोग की सलसा ने भी स्त्रियों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट किया । दिव्य बालिका से स्त्री-शिक्षा की प्रगति स्पष्ट होती है :

शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं की संख्या

स्तर	१९०१-०२	१९२१-२२	१९३१-३२	१९४६-४७
प्राथमिक	३,४४,७१२	११,८६,२२४	१९,४४,०७०	२७,११,२३०
माध्यमिक	६०७३	२६,१६३	१,९६,१७०	४,४२,५०३
बालिका	१६६	६०३	२,६८४	२०,३०४
व्यावसायिक	२,४७३	१०,८३१	१७,५६८	४८,६६३

५२ | भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

इस काल में सह-शिक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कांतिन स्तर पर १९४६-४७ में लगभग २० प्रतिशत बालिकाएँ सह-शिक्षण वाली गस्थाओं में अध्ययन करती थीं। यह प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर और भी अधिक था। बिन्नु माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम था।

सन् १९४७ से १९४९-६० तक

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद स्त्री-शिक्षा की प्रगति की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष सद्य रखे गये। आँकड़े देखने से ज्ञात होता है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा पिछड़ी हुई दसा में है। शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों एवं बालिकाओं का अनुपात क्रमशः इस प्रकार है :

प्राथमिक स्तर ५ २, माध्यमिक स्तर ४ १, कांतिन स्तर ६ : १,  
व्यावसायिक शिक्षा का स्तर ७ : १।

सन् १९६० से १९७० तक

शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समय-समय 'शिक्षा आयोगों एवं समितियों का गठन किया। इसी प्रकार के एक आयोग का १ सन् १९६४ में हुआ जिसके अध्यक्ष श्री कोझरी थे। इस आयोग ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए शिक्षा के विविध पहलुओं पर उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किये। स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में भी इस आयोग ने उचित सुझाव देकर इसके प्रसार में अत्यधिक सहयोग दिया। स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सुझाव इस प्रकार हैं :

१. बाले आने वाले कुछ वर्षों में स्त्री-शिक्षा को एक प्रमुख कार्यक्रम का रूप मिलना चाहिए ताकि बालक आ सकें।
२. इस प्रयोजन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की रचना की जाय और उनके लिए आवश्यक घनताधि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाये।
३. केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर विभिन्न प्रशासकीय सेवा का गठन स्त्री-शिक्षा का निरीक्षण करने के लिए किया जाय।

स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति

स्त्री-शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए मई, १९५८ में भारत सरकार ने स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति नियुक्त की। इसकी अध्यक्ष श्रीम दुर्गाबाई देवमुख भी। इस समिति ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिये :

१. केन्द्रीय एवं प्रत्येक राज्य सरकार में एक प्रशासन मण्डल की आवश्यकता है जो स्त्री-शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की देखभाल करे। इस मुद्दा के कारण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद् की स्थापना सन् १९५६ में हुई।
२. प्रत्येक राज्य में स्त्री-शिक्षा की देखभाल के लिए एक सह-संचालक की नियुक्ति की जाय।
३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्त्री-शिक्षा के लिए पृथक से अनुदान देने की व्यवस्था करनी चाहिए।
४. सह-शिक्षण वाली पाठशालाओं में जहाँ शिक्षिकाओं की नियुक्ति सम्भव न हो, शाला माताओं की नियुक्ति की जाय।
५. निर्धन माता-पिता की बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए।
६. महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
७. उच्च शिक्षा में स्त्रियों के लिए अधिक स्थानों का प्रवर्ध हो।
८. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अधिक ऐच्छिक विषयों की सुविधा हो।

### विद्यालयों में बालिकाओं का प्रवेश

विद्यालयों में प्रविष्ट बालिकाओं के आँकड़ों का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि इसमें कई लाभ हैं—एक तो हमको यह ज्ञात होगा कि भारत के सभी राज्यों में प्रवेश की सख्या समान है या उसमें अधिक असमानता है, दूसरे हमें यह पता होगा कि बालक और बालिकाओं की संख्या में क्या अन्तर है तथा तीसरा यह कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के बालक-बालिकाओं की संख्या में कितना अन्तर ज्ञात होगा।

आँकड़ों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि भारत के सभी राज्यों में विद्यालय में प्रविष्ट बालिकाओं की संख्या में अधिक अन्तर है। हमें यह अधिक प्रगतिशील राज्य केरल है। यहाँ पर ६-१२ की आयु वर्ग की बालिकाओं की ६९.७ प्रतिशत बालिकाएँ विपरीत



६-११ आयु वर्ग की प्रवेश निम्ने हुए बालिकाएँ<sup>१</sup>

राज्य	१-४ बालिकाओं की प्रवेश (सालों में)		५-११ आयु वर्ग की बालिकाओं का प्रतिशत	
	१९६०-६१	१९६४-६५	१९६०-६१	१९६४-६५
भारत प्रवेश	१०२१	१०००	६६७	७७७
आसाम	१०५	६०६	६०००	६६६
बिहार	६३७	१०००	२६००	४,६७
गुजरात	२३६	१००१	३७०३	७१६
जम्मू-काश्मीर	०३७	०७८	२१०	६६,७
केरल	८४५	१२३३	६६७	४३८
मध्य प्रदेश	३६८	१०००	४८०	६३,१
मद्रास	६४२	२२००	२६६	७५,३
महाराष्ट्र	६६३	२१७०	५०१	८८१
मैसूर	६६८	१५३६	२३६	४६३
उड़ीसा	४२७	४५०	३६३	५५,२
पंजाब	३०६	७८६	१५३	४८,४
राजस्थान	१,१५५	७१०	१६६	४१६
उत्तर प्रदेश	७८८	२१५०	४८४	६०,७
बंगाल	६४६	१३३२		

सन् १९६४-६५ में द्वितीय अगिल भारतीय सर्वेक्षण शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध में किया गया था। उस सर्वेक्षण के द्वारा सघृहीत आँकड़ों का विश्लेषण करने पर प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार हैं :

### प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या ४,७२,४०,५६६ थी। इसमें से ३,०१,४०,४८२ छात्र और १,७१,००,११४ छात्राएँ थी। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं का प्रतिशत ३६.२० था।

1. The Indian Year Book of Education, 1964, p. 159.

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में अध्ययन करने वाले छात्र एवं छात्राओं के प्रतिशत में अधिक अन्तर था। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में ६५.७४ प्रतिशत छात्र और ३४.२६ प्रतिशत छात्राएँ थी तथा नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिशत ५६.७० था और बालिकाओं का प्रतिशत ४३.३० था जो निम्न तालिका से स्पष्ट है।

प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं का प्रतिशत

क्षेत्र	छात्र	छात्राएँ
ग्रामीण	६५.७४	३४.२६
नगरीय	५६.७०	४३.३०

देश के अधिकांश राज्यों में अध्ययन करने वाली छात्राओं का प्रतिशत ४० से अधिक है किन्तु बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत ३७ और ४० के मध्य है।

यदि आयु सीमा के आधार पर देखा जाय तो ६-१० की आयु वाली अनुमानित समस्त लड़कियों की ५४.७० प्रतिशत लड़कियाँ प्राथमिक स्तर पर अध्ययन कर रही थी। विभिन्न प्रान्तों के इस प्रतिशत में अन्तर अत्यधिक है। सबसे कम प्रतिशत २३.०६ बिहार में है जबकि सबसे अधिक प्रतिशत ११.१४१ केरल में है। बिहार में इस आयु वर्ग की प्रति ५ बालिकाओं में से केवल एक बालिका प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश पाये हुए है।

कक्षानुसार I से V तक बालिकों का प्रतिशत वितरण

क्षेत्र		वर्ग				
		I	II	III	IV	V
ग्रामीण	छात्र	३७.७५	२०.८०	१६.८१	१३.७४	१०.८६
	छात्राएँ	४५.३७	२१.२१	१५.१७	१०.६०	७.३४
नगरीय	छात्र	२७.८४	२०.३२	१८.७२	१७.२२	१५.६०
	छात्राएँ	२६.४२	२१.१८	१८.८१	१६.५०	१४.०८
योग	छात्र	३५.८२	२०.७१	१७.१८	१४.४२	११.८७
	छात्राएँ	४१.२०	२१.२१	१६.१२	१२.३६	६.१०

## ५६ | भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

उपयुक्त सारिणी से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की प्रथम कक्षा में नामांकित प्रति ६ बालिकाओं में से केवल एक बालिका श्वी कक्षा में पहुँचती है। इससे नगरीय क्षेत्र का अनुपात सन्तोषजनक है जहाँ प्रथम कक्षा में नामांकित प्रति २ बालिकाओं में से एक बालिका श्वी कक्षा में पहुँचती है।

### निम्न माध्यमिक स्तर

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि निम्न माध्यमिक स्तर में VI, VII और VIII कक्षाएँ सम्मिलित की जायेंगी। सन् १९६५ में निम्न माध्यमिक स्तर पर ७८,१५,५६५ बालक और ३०,०६,२०४ बालिकाएँ प्रवेश पाये हुए थी जिनका प्रतिशत क्रमशः ७२.२२ और २७.७८ था। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का प्रतिशत ३६.२० था। इससे स्पष्ट है कि निम्न माध्यमिक स्तर पर प्रतिशत कम है। निम्न तालिका से ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के बालक-बालिकाओं का प्रतिशत स्पष्ट है।

क्षेत्र	बालक	बालिकाएँ
ग्रामीण	७८ ००	२२ ००
नगरीय	६३ ८७	३६ १३

ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालक-बालिकाओं में अधिक प्रतिशत बालकों का है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में बालिकाओं का प्रतिशत अधिक है।

यदि इस आधार पर अध्ययन करें कि प्रति १०,००० जनसंख्या में से कितने बालक-बालिकाएँ निम्न माध्यमिक स्तर पर अध्ययन-रत हैं तो हम पायेंगे कि २०७ छात्र-छात्राएँ इस स्तर पर अध्ययन करते थे। इसमें से १५२ बालक और ५५ बालिकाएँ थी। इस प्रकार लगभग तीन सड़कों के प्रतिकूल एक सड़की विद्यालय में थी।

### माध्यमिक स्तर

माध्यमिक स्तर पर कुल छात्रों की संख्या ६२,२७,०७५ थी। इसमें से ५७,७२,६११ लड़के और १४,५४,४६४ लड़कियाँ थी। कुल संख्या का २३.३६ प्रतिशत बालिकाएँ थी। इस स्तर पर बालक और बालिकाओं के मध्य अनुपात १० : ३ था।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लड़के-लड़कियों की संख्या का प्रतिशत निम्न तालिका में स्पष्ट है :

क्षेत्र	बालक	बालिकाएँ
ग्रामीण	८३ ४२	१६ ५८
नगरीय	७१ ३१	२८ ६९
योग	७६ ६४	२३ ३६

ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का प्रतिशत बहुत कम था। ग्रामीण भागों में लड़के-लड़कियों का अनुपात ५ : १ है। यदि प्रत्येक राज्य का पृथक् रूप में अध्ययन करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का स्थान आता है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले समस्त छात्रों में से १७८ प्रतिशत भाग लड़कियों का था। लड़के-लड़कियों का अनुपात ५५ : १ था।

नवरीय क्षेत्र में लड़कियों का प्रतिशत २८.६६ था। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लड़कियों का प्रतिशत कम ही था किन्तु केरल में दोनों की संख्या लगभग समान थी।

इसी प्रकार प्रति १० हजार जनसंख्या में से ८२ बालक नवी-वसवी कक्षा में पढ़ते थे। इसमें से ६३ लड़के और १९ लड़कियाँ थीं।

### स्त्री-शिक्षा की समस्याएँ

स्त्री-शिक्षा के प्रसार के लिए भारत सरकार एवं प्रांतीय सरकारों ने अनेक प्रयत्न किये किन्तु उनकी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत स्त्री-शिक्षा की प्रगति के लिए जो सक्षम निर्धारित किये गये उन तक अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके मार्ग को अवरुद्ध करने वाले कारणों का विश्लेषण करना उपयुक्त रहेगा ताकि उन समस्याओं के समाधान के उपायों पर विचार किया जा सके। प्रमुख समस्याओं का विवरण निम्नलिखित है।

#### प्रमुख समस्याएँ

अशिक्षा घातक कटुता	बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा	बालिका विद्यालयों का अभाव	अनुपयुक्त पाठ्यक्रम
सरकार की उदासीनता	अविकसित क्षेत्र	ग्रामीण	अध्यापिकाओं का अभाव
			शिक्षा में अपव्यय

### १. अशिक्षा

अधेजी शासन की दोषपूर्ण नीति का परिणाम आज हमको शिक्षा जगत में दृष्टिगत होता है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत की १६.६ प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित थी। वैसे शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत अब अधिक बढ़ चुका है। सन् १९५६ में किये गये एक सीमित सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि भारत में ५६.३ प्रतिशत व्यक्ति ही अशिक्षित रह गये हैं। यह आँकड़े भी इस सत्य को प्रकट करते हैं कि भारत की आधे से अधिक जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा के महत्त्व को नहीं समझते हैं। वे बालक-बालिकाओं की शिक्षा को निरर्थक तथा समय का अपव्यय मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक यही धारणा बनी हुई है कि बालिकाओं

का बर्ग-क्षेत्र पर है तथा यह तो पराया धर्म है। अतः इनको मिश्रित करने में कोई आधिक लाभ की सम्भावना नहीं है। इस भावना के बनीभूत अमिश्रित लोग अपनी बालिकाओं को विद्यालयों में बिना ग्रहण करने के लिए नहीं भेजते हैं।

## २ धार्मिक कट्टरता

अभिधा के विस्तृत साम्राज्य के कारण आज भी हमारे मयात्र में अन्य-विश्वास और तद्दिवादिना का धोमबाजा है। अधिकांश भारतीय आज भी प्राचीन विचारों तथा परम्पराओं के चोकर हैं। अनेक अमिश्रित हिन्दू वर्तमान युग में भी इस धर्म में विश्वास करते हुए पाये जाते हैं।

प्राप्ते तु दृष्टमे कर्षे यन्तु कन्या न यच्छति ।  
मासि जाति रजस्तस्याः पिना निवर्ति शोणितम् ॥

इसी प्रकार की धार्मिक कट्टरता मुसलमानों में भी विद्यमान है। वे रजोदर्शन पूर्व ही बालिकाओं का विवाह करने के लिए उत्प्रेषित रहते हैं क्योंकि उनके आचारानुसार प्रतिमास का रजोदर्शन घुनाहू है। इसका परिणाम यह होता है कि अल्प आयु में विवाह सम्पन्न होने से बालिकाओं को पूर्ण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है।

## ३ सरकार की उदासीनता

स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अर्बजी शासन ने जो उदासीनता की नीति अपनाई उसका प्रभाव आज भारत सरकार पर भी देखने को मिलता है। सन् १९३५-३६ में विदेशी सरकार ने भारत के अनेक प्रान्तों में बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले धन में कमी कर दी। यही नीति भारत सरकार का मार्ग-दर्शन कर रही है। एक ओर और भारत सरकार स्त्रियों की शिक्षा के प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है और दूसरी ओर बालकों की शिक्षा की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा पर कम धन व्यय करती है। सरकार की यह पक्षपातपूर्ण नीति स्त्री-शिक्षा के प्रसार में बाधा बनी हुई है। वैसे अब अनेक प्रान्तों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा नि शुल्क कर दी है, किन्तु सरकार की दोषपूर्ण नीति यहाँ भी पर-सक्ति होती है कि यदि शिक्षा नि शुल्क ही कर दी है तो इसको अनिवार्य भी किया जाय।

## ४ बाल-विवाह एवं पर्दा-प्रथा

भारतीय समाज में बाल-विवाह एवं पर्दा-प्रथा बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति में अवरोधक हैं। अनेक माना-पिता अल्प आयु में ही अपनी पुत्रियों का विवाह सम्कार करते इस उत्तरदायित्व से मुक्त होने का विचार रखते हैं। इसी प्रकार पर्दा-प्रथा बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखती है। आज भी अनेक कट्टर-पक्षी अपनी बालिकाओं को उन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजते हैं,

जहाँ पढ़े की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। पढ़े की समस्या मुख्यतः मुसलमानों में अधिक प्रचलित है। जिन स्थानों पर बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय नहीं हैं वहाँ की अधिकांश बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाना पड़ता है।

## ५. अविकसित ग्रामीण क्षेत्र

भारत एक कृषि-प्रधान देश होते हुए भी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र अविकसित हैं। इनमें रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक दशा दयनीय है। भारत के दो-तिहाई गाँवों में प्राथमिक विद्यालय भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बालक-बालिकाओं को शिक्षित करने का विचार उपहासजनक है। निर्धन जनता से यह कैसे आशा की जा सकती है कि अपनी संतान को बाहर रखकर शिक्षा पर होने वाले व्यय के भार को सहन कर सके। देश के अनेक ग्रामीण भागों में तो श्रमिकों को पारिवारिक भी इतना कम मिलता है कि उनको अपने परिवार के सदस्यों की उदरपूर्ति की चिंता सदैव घेरे रहती है। ऐसे निर्धन व्यक्तियों से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे बालिकाओं को विद्यालय भेजें जबकि वे अपने बालकों तक को विद्यालय भेजने का साहस नहीं कर पाते हैं।

## ६ बालिका विद्यालयों का अभाव

यह सत्य तो सर्व-विदित है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिका विद्यालयों का पूर्ण अभाव है। अधिकांश गाँवों में बालकों के लिए ही विद्यालय हैं जिनमें ही बालिकाओं को भी अध्ययन के लिए जाना पड़ता है। माध्यमिक स्तर पर माता-पिता अपनी बालिकाओं को बालकों के विद्यालय में भेजना पसन्द नहीं करते हैं। परिणाम-स्वरूप, बालिकाओं को अपनी आगे पढ़ने की इच्छा पर कुठाराघात करना पड़ता है।

## ७ अध्यापिकाओं का अभाव

अध्यापिकाओं का अभाव भी स्त्री-शिक्षा के विकास में अवरोधक के रूप में है। प्रतिशित अध्यापिकाओं का पर्याप्त सख्या में उपलब्ध होना तो एक बड़ी समस्या है ही किन्तु अप्रशिक्षित अध्यापिकाएँ जुटाना भी एक समस्या है। अध्यापिकाओं के इस अभाव के कई कारण हैं। अनेक स्त्रियाँ शिक्षित होने हुए भी अपने माता-पिता अथवा पति की अनिच्छा के कारण नौकरी नहीं कर सकती हैं। एक कारण स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा है। इतनी शैक्षिक योग्यता की स्त्रियाँ बहुत कम ही उपलब्ध होती हैं जो अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश पा सकें। अभी तक अनेक भारतीय परिवारों में स्त्रियों द्वारा नौकरी करना परिवार की मान-हानि समझा जाता है। नगरो में तो महिला अध्यापिकाएँ सरलता से प्राप्त हो जाती हैं किन्तु गाँवों में आवास एवं अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण स्त्रियाँ वहाँ नौकरी करना पसन्द नहीं करती हैं। इसके साथ ही महिला प्रतिश्रम विद्यालयों के अभाव के कारण प्रशिक्षित महिलाओं का अभाव सदैव बना रहता है।



अध्यापकों एवं माता-पिता का भ्रोषण न कर सकें। यदि पचायन समितियाँ अपनी दलगत राजनीति से ऊँचे उठकर कार्य करें तो वे स्थानीय व्यक्तियों से आर्थिक एवं शारीरिक सहयोग प्राप्त कर विद्यालय भवन तथा आवश्यक सामग्री का प्रवन्ध करने में सफल हो सकती हैं।

बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी सिफारिश करते हुए लिखा है—“हमारा विचार है कि जहाँ सम्भव हो वहाँ बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालय स्थापित किये जायें, क्योंकि ये विद्यालय मिश्रित विद्यालयों की अपेक्षा सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए सम्भवतः अधिक उत्तम अवसर प्रदान करते हैं और सभी राज्यों को ऐसे विद्यालय पर्याप्त संख्या में स्थापित करने चाहिए।”<sup>1</sup>

उपर्युक्त सिफारिश किये हुए आयोग को लगभग १७ वर्ष हो गये परन्तु सरकार ने इस ओर मराहनीय कार्य नहीं किया। प्राथमिक स्तर पर तो सह-शिक्षा चल भी सकती है किन्तु माध्यमिक स्तर पर भारतीय जनता सहशिक्षा के पक्ष में न होने से सरकार को नगरो एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पृथक् माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए।

## २. सहशिक्षा

भारतीय समाज की परम्पराएँ आदिकाल से ही ऐसी रही हैं कि यहाँ पुत्र्य और स्त्रियों के कार्य क्षेत्र पृथक्-पृथक् रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ की भौगोलिक दशाएँ इन प्रकार की हैं कि यहाँ के बालक-बालिकाओं में गौदनावस्था का ज्वार सीधे ही उत्पन्न हो जाता है। परिणामस्वरूप, सदैव यह भय बना रहता है कि पुत्रक-पुत्रनियाँ गौदनावस्था के लुमार के वशीभूत हो मर्यादा का भतिक्रमण कर पक्ष-क्षप्ट न हो जायें।

पश्चिमी देशों में यह प्रथा प्राचीन समय से चली आती है। ग्रीस और रोम की पाठशालाओं में भी सहशिक्षा की प्रथा थी। परन्तु रोमन कैथोलिक पादरियों के प्रभाव के कारण लड़कियों के लिए मध्यकाल में पृथक् कांवेन्ट बने। किन्तु १८वीं सदी के अन्त में वेस्टालोत्री के सहशिक्षा के विचारों ने इसे काफी प्रोत्साहन दिया। वर्तमान समय में यदि हम पश्चिमी देशों के विद्यालयों की ओर दृष्टिपात करें तो हम इसी मनीजे पर पहुँचेंगे कि वहाँ अधिकांश सरचार्ज सहशिक्षण वाली हैं।

भारत में लोकमत अभी सहशिक्षा के पक्ष में नहीं है। स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति ने १९५८ में सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त प्रश्नावली में सहशिक्षा के बारे में लोगों

1. We are of the opinion that where it is possible separate schools for girls should be established as they are likely to offer better opportunities than in mixed schools to develop their physical, social and mental aptitudes and all states should open such schools in adequate numbers.”—Report of the Secondary Education Commission, p 59.



के विचार प्राप्त करने के लिए कुछ प्रश्न सम्मिलित किये थे। लोगों के उत्तरों का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि ८२.७ प्रतिशत लोग प्राथमिक शिक्षा में गृहशिक्षण के पक्ष में थे। निम्न माध्यमिक स्तर पर ४६.४ प्रतिशत लोग इसके पक्ष में थे। उच्चतम माध्यमिक स्तर पर केवल १८.२ प्रतिशत लोग ही इसके पक्ष में थे। उच्चतम शिक्षण से निष्कर्ष निम्नलिखित है कि प्राथमिक और निम्न माध्यमिक स्तर पर लोकमत सहशिक्षण के पक्ष में है। किन्तु माध्यमिक स्तर पर लोकमत इसके पक्ष में नहीं है।

हमारे जैसे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर सहशिक्षण एक उपयोगी कदम है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए आवश्यक है कि सहशिक्षा को सफल बनाने के प्रयत्न किये जायें। आर्थिक दृष्टि से भी यह प्रयोग आवश्यक है। दूसरी ओर एक बात यह भी सहशिक्षा के पक्ष को प्रबल बनाती है कि देश में ऐसे गाँवों की संख्या अधिक है जहाँ अलग-अलग विद्यालय चलाने के लिए पर्याप्त संपत्ति सड़के-मड़कियाँ भी नहीं मिल पाते हैं। जब यह प्रयोग प्राथमिक स्तर पर सफलतापूर्वक चलने लगे तो जहाँ जहाँ लोकमत माध्यमिक स्तर पर सहशिक्षा के पक्ष में बनाया जाय।

### ३ अध्यापिकाओं की पूर्ति

यदि सहशिक्षा प्रणाली को सफल बनाना है तो आवश्यक है कि सभी विद्यालयों में कुछ अध्यापिकाएँ अवश्य होनी चाहिए। अभी तक अध्यापिकाओं का प्रतिशत बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अध्यापिकाओं का अभाव और भी अधिक है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, आवास तथा साधन-सामग्री आदि अनेक समस्याएँ हैं। सरकार को इस क्षेत्र में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो सकें। यहाँ उन कुछ उपायों पर विचार करना उपयुक्त रहेगा जिनके द्वारा अधिक महिलाओं को अध्यापन व्यवसाय की ओर आकर्षित किया जा सके।

(१) कम वेतन होने से महिलाएँ इस व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होती हैं। सरकार को अधिक वेतन देकर स्त्रियों को अध्यापन वृत्ति की ओर आकृष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कुछ विशेष भत्ता की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। वर्तमान समय में नगरों में ये महिलाएँ पर्याप्त सहायता उपलब्ध हो जाती हैं किन्तु गाँवों में नहीं होती हैं। अतः विशेष भत्ते का आयोजन उनको गाँवों की ओर आकृष्ट कर सकता है।

(२) गाँवों में अध्यापिकाओं को आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार को विद्यालय के निकट ही कुछ मकान भी बनवाने चाहिए। बच्चों के समितियों को अपने क्षेत्र में इस सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए। एक विद्यालय में निवृत्तवर्ती जितने गाँवों के बालक-बालिकाएँ पढ़ने के लिए आते हैं उन सभी गाँवों के निवासियों की सहायता से आवास हेतु उचित प्रकार के मकान बनवाने चाहिए किन्तु

यह कार्य तभी सम्भव है जबकि पचायन के सदस्य लोगो का सहयोग प्राप्त करने के लिए अच्छा बानावरण तैयार करें ।

(३) सरकार को चाहिए कि नियुक्ति की आयु सम्बन्धी सीमा में महिलाओ को कुछ छूट दे कुछ अधिक आयु वाली महिलाओ को भी नियुक्ति मिलनी चाहिए ।

(४) यदि सरकार द्वारा अध्यापको की पत्नियो को यह सुविधा दी जाय कि वे दोनो एक ही स्थान पर कार्य करें तो अनेक ऐसी महिलाएँ अध्यापन व्यवसाय के लिए प्राप्त हो सकती हैं जो शिक्षित हैं किन्तु दूर-दूर होने के भय से मौकरी नहीं करना चाहती ।

(५) जब तक निर्धारित योग्यता वाली अध्यापिकाएँ प्राप्त नहीं होती तब तक आवश्यक शिक्षा-योग्यता वाली स्त्रियों को नियुक्त किया जाय तथा उनको शिक्षा योग्यता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाय ।

(६) प्रारम्भ में यदि प्रशिक्षित अध्यापिकाएँ उपलब्ध न हों सकें तो अप्रशिक्षित महिलाओ को नियुक्ति दी जाय और उनको अल्प-सामयिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया जाय ।

#### ४ पाठ्यक्रम में सुधार

बालिकाओ के लिए पाठ्यक्रम कैसा होता चाहिए ? यह विषय विवादास्पद बना हुआ है । कुछ विद्वानो का मत है कि बालिकाओ के लिए पृथक् पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है । अपने इस विचार की पुष्टि के लिए वे निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं

१. बालक और बालिकाओ की मानसिक शक्ति में कोई अन्तर नहीं होता है ।
२. भारत जैसे निर्धन देश में अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था तथा सुविधाएँ जुटाना सम्भव नहीं है ।
३. कृषि, तकनीकी, व्यापार आदि पाठ्यक्रम से बालिकाओं को वंचित रखने का तात्पर्य है कि भारत की वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियो में भी पशोभ रचना ।
४. यह धारणा गलत है कि स्त्रियो का कार्यक्षेत्र तो घर में है ।

इसके विपरीत, बालिकाओ के लिए विविष्ट पाठ्यक्रम की माँग करने वालो का विचार है कि दोनो को एक ही सा पाठ्यक्रम रखने से बालिकाओ को कोई लाभ नहीं हो पाता है । बालको के पाठ्यक्रम वा अध्ययन करने से बालिकाओ की शिक्षा में भी बालको की शिक्षा के शेष प्रकट होने लगते हैं । इनसे से एक दोष बेरोजगारी का है । जब बेरोजगारी पुरुषों के लिए इतनी हानिकारक है तो वह स्त्रियों

६४ | भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

के लिए भयानक हो सकती है।<sup>1</sup> श्रीमती दुर्गाबाई देवगुन की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी बालिकाओं के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी। वर्तमान भारत में तो हम अपने सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को पुनरात्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पश्चिमी देशों का अनुकरण कर रहे हैं। यही दृष्टा शिक्षा क्षेत्र में भी है। हमारे यहाँ शिक्षा का प्रारूप पूर्णतः पश्चिमी देशों की शिक्षा-प्रणाली के अनुसार ही है। पश्चिमी देशों में पुरुष और स्त्रियों के लिए समान पाठ्यक्रम है। इसी आधार पर भारत में भी कुछ इसी समान पाठ्यक्रम के पदापाती हैं। डा० मोरिस ब्रूय ने पश्चिम में प्रचलित स्त्री-शिक्षा की आलोचना करते हुए लिखा है—“भारत में स्त्रियों में नवजीवन का संचार हो रहा है और वे स्वयं से पूछती हैं कि हम पश्चिम क्या सीख सकती हैं? पश्चिमी देशों में स्त्रियों की शिक्षा सन्देशात्मक दृष्टि में जाती है। पश्चिम में अभी तक स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा स्पष्ट एवं सतोषजनक कुछ भी नहीं है जो पूर्वी क्षेत्रों का प्रदान किया जा सके।”

**विशिष्ट पाठ्यक्रम का स्वरूप**

इस पर विचार करना उचित होगा कि यह विशिष्ट पाठ्यक्रम क्या हो। कुछ विषयों का बालिकाओं के जीवन में अनिवार्य सम्बन्ध होने से बालिकाओं की शिक्षा के अभिन्न अंग से प्रतीत होते हैं। ऐसे विषयों में से कुछ विषय गृह विज्ञान, सिनाई-बुनाई, दात मनोविज्ञान, संगीत, नृत्य, नसिंग आदि हैं। इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं को घर में बाहर भी अनेक कार्यों में हाथ बटाने की आवश्यकता हो रही है इसलिए विशिष्ट पाठ्यक्रम में इसका भी प्रावधान करना होगा। इसी प्रकार बालिकाओं को अपनी रचित, शक्ति एवं स्वभाव के अनुसार वैयक्तिक विषय चुनने की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने गृह विज्ञान की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। आयोग ने लिखा है कि एक शिक्षित बालिका जो अपने साधनों के अनुसार अपने गृह का सुचारु रूप से तथा कुशलपूर्वक प्रबन्ध नहीं कर सकती है, वह अपने परिवार के सुख तथा समृद्धि में अपना योगदान नहीं कर सकती है।<sup>2</sup> इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये आयोग ने गृह विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की है।

- 1 Some of the objectionable features of boys' education are slowly developing in the education of girls too..... Unemployment among men is bad enough, unemployment among women will be terrible.—S N Mukerji, *Education in India, To-day and Tomorrow*, pp 247-48.
- 2 “An educated girl who can not run her home smoothly and efficiently, within her resources can make no worthwhile contribution to the happiness and the well-being of her family to raising the social standards in her country”—Report of the Secondary Education Commission, p. 58.

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, किन्तु माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों पर उसमें कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं। माध्यमिक स्तर पर वाक-शास्त्र, सिलाई-कढ़ाई, गृह-विज्ञान, बाल-मनोविज्ञान आदि विषयों को सम्मिलित किया जाय और उच्च शिक्षा के स्तर पर चित्रकला, गृह-अर्थशास्त्र, गृह-प्रबन्ध और नर्सिंग आदि विषयों को स्त्री-शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाय।

## ५. आर्थिक सहायता

स्त्री-शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक है कि सरकार अपने विकास के कार्यक्रमों में स्त्री-शिक्षा को प्रमुख स्थान प्रदान करे तथा स्त्री-शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने का प्रावधान रखे। स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति ने भी यह सिफारिश की कि सरकार द्वारा स्त्री-शिक्षा पर अधिक धन व्यय किया जाना चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा को अनेक राज्यों में निःशुल्क करने के प्रयत्न अवश्य किये गये हैं, किन्तु इसके साथ ही निर्धन बालिकाओं को पुस्तकें, पोशाक तथा आने-जाने की सुविधा आदि की भी सहायता मिलनी चाहिए।

## ६. विद्यालय चलो अभियान

सरकार द्वारा धीमावकाश में प्रति वर्ष नए-एक सामो में सर्वेक्षण करवाकर यह ज्ञात करना चाहिए कि कितनी बालिकाएँ आधु के माघार पर विद्यालय में प्रवेश पाने योग्य हो गई हैं। सरकार द्वारा सत्रारम्भ से पूर्व ही विद्यालय चलो अभियान सप्ताह का आयोजन करना चाहिए। इस विधि द्वारा अभिभावकों को प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार के आयोजनों को सफल बनाने के लिए स्थानीय नेताओं का सहयोग अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

## ७. समाज में उचित दृष्टिकोण का विकास

सरकार द्वारा स्त्री-शिक्षा के प्रसार के लिए चाहे जितने प्रयत्न कर लिये जायें किन्तु यदि उनकी जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो उनकी सफलता की आशा करना व्यर्थ ही है। सरकार को ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए जिनके द्वारा समाज में व्याप्त रुढ़िवादिता, धार्मिक अन्धविश्वास, बालविवाह आदि जैसी घुराइयों को समूल उखाड़ फेंका जाय। जनता को स्त्री-शिक्षा के आन्दोलन में जुट जाना चाहिए। उसे स्त्री-शिक्षा के प्रति चिर-काल से विरासत में प्राप्त होने वाले अपने संकुचित दृष्टिकोण को पूर्णतया परिवर्तित कर देना चाहिए।

इसके साथ ही भारतीय स्त्रियों में भी शिक्षा के प्रति व्याप्त सकुचन दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक है। उसमें स्वयं शिक्षा के प्रति रुझान एवं रुचि उत्पन्न होनी चाहिए।

अभ्यासाध्य प्रश्न

१. २०वीं शताब्दी में हुई स्त्री-शिक्षा की प्रगति का वर्णन लिखिए ।
२. भारत में स्त्री-शिक्षा के पिछड़ेपन के कारणों पर प्रकाश डालिए ।
३. स्त्री-शिक्षा के प्रसार में बाधक समस्याएँ कौन-कौनसी हैं ? उनका समाधान के लिए अपने सुझाव दीजिए ।
४. स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति के प्रमुख सुझाव क्या थे ? उनका आ-आपसक विवरण लिखिए ।

## अध्याय ४

### शिक्षा और राष्ट्रीय उन्नति

#### भारतीय शिक्षा की व्यर्थता

वर्तमान भारतीय शिक्षा का ढाँचा अंग्रेजों की देन है। उन्होंने इस देश पर शासन करते समय शिक्षा-प्रसार का कार्य दो दृष्टियों से आरम्भ किया था : (१) वे चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने, बोलने और लिखने वाले कुछ भारतीय कर्मचारी तैयार हो जायें जो प्रशासन के कार्य में उनकी सहायता करें, (२) उनके अपने देश में शिक्षा-प्रसार तीव्र गति से चल रहा था और भारतीय प्रजा के लिए उदारता और परोपकार की दृष्टि से वे शिक्षा-प्रसार चाहते थे। यह दोनों उद्देश्य संकुचित थे। इसलिए भारत की शिक्षा-प्रणाली को वह बुनियादी आधार नहीं मिल सका, जो राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के लिए आवश्यक होगा है। चित्तन के खोखलेपन के कारण शिक्षा भी खोखली रही।

राष्ट्रीय आन्दोलनों के प्रारम्भ होने पर इस शिक्षा-प्रणाली का विरोध आरम्भ हुआ। विशेष रूप से गांधीजी जिनके मन में एक शक्तियानी और समृद्धिशाली भारत की स्पष्ट कल्पना थी और जो स्वतन्त्र चित्तन की शक्ति रखते थे, इस शिक्षा-प्रणाली के विरोधी थे और उनका मत था कि केवल कलक पैदा करने वाली शिक्षा किसी प्रकार भी देशभक्त, परिश्रमी, ईमानदार और लगन से काम करने वाले नागरिक नहीं पैदा कर सकती। इसलिए उन्होंने अपने अनुभव और चित्तन के बल पर 'बुनियादी शिक्षा' का एक मौलिक विचार देश के समस्त प्रस्तुत किया। उनका दावा था कि यह बुनियादी शिक्षा इस देश में नये समाज को जन्म देगी जिससे राष्ट्र का कल्याण होगा। यह नया समाज होगा। 'सर्वोदय समाज'—एक ऐसा समाज जिसमें हर एक घटक स्वतन्त्र होगा क्योंकि वह आत्मनिर्भर होगा। हर एक व्यक्ति को उन्नति करने का न केवल अवसर मिलेगा, वरन् बुनियादी शिक्षा पाकर उसकी सारी शक्तियाँ अनिवार्य रूप से विकसित होगी। इस समाज में किसी प्रकार का 'शोषण' न होगा, उसमें

६८ | भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

कोई 'यंग' न होगा। यह सब बुनियादी शिक्षा के परिणामस्वरूप समझ होगा। गांधी का वह स्वप्न बिखर गया। राष्ट्र ने 'बुनियादी शिक्षा' को नहीं अपनाया, अपनाने का साहस न था, पिछी-पिछी लोक पर बैलगाड़ी जिस तरह चन्ती है, उसी तरह देश ने अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली को जारी रखा। बहुत से लोग (जिनमें हुमायूँ कबीर, श्री छागला, तथा अन्य बहुत से अंग्रेजी समर्थक शामिल हैं) इस प्रणाली के समर्थक बन बैठे परन्तु उनका यह मोह परम्परा का मोह है जो मनुष्य को कोई भी नये प्रयोग करने से रोकता है।

कुछ भी हो, अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली जारी है और स्वतन्त्रता के बाद जो नयी पीढ़ी तैयार हुई है, वह दफतरो, कारखानों, खेतों और व्यावसायिक संस्थानों में उत्तर-दायित्वपूर्ण ढङ्ग में कर्तव्य-प्राप्तन में असमर्थ है। 'घण्टाघार' की अधिकता इस बात का प्रमाण है कि भारत का सामान्य और औसत नागरिक अपने 'स्व' को भूलकर राष्ट्र के हित में बलिदान करने की भावना नहीं रखता। फल यह हुआ कि हमारी तीन पञ्चवर्षीय योजनाएँ राष्ट्र के निर्माण में सफल नहीं हुईं। नेतागण इस योजनाओं की सफलता की गर्वपूर्वक चर्चा करते हैं परन्तु अयोग्य शक्ति और धन का व्यय करके उसके अनुपात में उपलब्ध सफलता नगण्य है। सरकार ने प्रशासन के बल पर जो विकास करने चाहे, वे विकसित हुए, नयी-नयी योजनाएँ, जैसे सामुदायिक विकास सड़क, पंचायत राज, सहकारिता, सरकारी उत्पादन-केन्द्र सभी घाटे में चल रहे हैं। ऐसा क्यों? कोई भी योजना हो, वह 'जनशक्ति' और 'मानवीय साधनों' में चलनी है। यदि मनुष्य ही विवृत है, तो योजना बेकार जायगी। मनुष्य का निर्माण शिक्षा करती है। वर्तमान भारतीय शिक्षा-प्रणाली यही नहीं करती, वह 'मानव' नहीं 'दानव' तैयार करती है, जो राष्ट्र की पीठ में छुरा भोवता है।

ऐसी दशा में यह प्रश्न विचारणीय है कि हमारी भारतीय शिक्षा किस प्रकार राष्ट्र की उत्पत्ति में 'साधक' बने? अभी तो वह 'बाधक' ही है। यदि गांधीजी के सुझाव लिये हल राष्ट्र के कर्मचारी को व्यावहारिक लगते हैं, तो उन्हें आगे बढ़कर कोई नया प्रयोग मन्त्रबूती और धर्म के साथ करना चाहिए।

**भारतीय शिक्षा-आयोग का प्रथम**

स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा की वस्तुनिष्ठता की जाँच करने के लिए दो आयोग सरकार ने नियुक्त किये, एक था राष्ट्राध्यक्षजी की अध्यक्षता में नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग और दूसरा था श्री मुदानियर की अध्यक्षता में नियुक्त माध्यमिक शिक्षा-आयोग। दोनों ही आयोगों ने अपने अपने अधिकार-क्षेत्र की शिक्षा-प्रणाली जाँच-परखाने की, बुराइयों का उन्मूलन किया और सुधार के उपाय बताये। आयोगों मन्त्रय विभाग के पान्थु उनका चिन्तन 'शिक्षा' के क्षेत्र में बन्द रहा। परन्तु अभी कोई भी चिन्तन गहनशील होता है, उसकी सावधानता सदैव की शिक्षाप्रणाली में होने लगे वा गान्य है कि शिक्षा के गुण-दोषों की परल राष्ट्र के शिक्षण मन्त्र में

चाहिए। दोनों आयोगों ने राष्ट्रीय दृष्टि से शिक्षा-प्रणाली की उपयोगिता के प्रश्न पर विचार नहीं किया। संभवतः इसका कारण यह था कि वे दोनों आयोग स्वतन्त्रता के अष्टादशवर्षों के जन्म के, जब आजादी के १५ वर्ष बीत गये, तो विद्वानों का ध्यान इस ओर गया कि राष्ट्रहित की दृष्टि से हमारी शिक्षा-प्रणाली क्यों वांछित फल नहीं दे रही है। यही कारण था कि १९६४-६६ में भारतीय शिक्षा-आयोग डा० कोठारी की अध्यक्षता में इस महत्वपूर्ण पहलु पर विचार करने बैठा। इस विषय पर विचार करने का समय आ गया था।

भारतीय शिक्षा-आयोग ने प्रथम बार इस बात पर ध्यान दिया कि किस प्रकार भारतीय शिक्षा उन्नतिशील और विकासोन्मुख भारत के सदस्यों की पूर्ति में सहायक हो। इसके अध्यक्ष डा० कोठारी ने तत्कालीन शिक्षा-मंत्री श्री छाबला को, आयोग के प्रतिवेदन के साथ सलग्न पत्र में लिखा था—

“शिक्षा हमेशा महत्वपूर्ण रही है परन्तु गायब मनुष्य के इतिहास में इतनी अधिक नहीं, जितनी आज है। विज्ञान पर आधारित दुनिया में किसी भी देश के समस्त विकासारम्भक कार्य में, इसके कल्याण, प्रवृत्ति और सुरक्षा में शिक्षा और शोध का महत्त्व अत्यधिक है। विज्ञान से व्याप्त सत्कार की विशेषता यह है कि आगे आने वाली दुनिया के स्वरूप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस बात से एक ऐसी नीति पर जोर देना आवश्यक है जो संप्रसारणशील हो, लचीली हो ताकि बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल यह अपने को ढाल सके। इससे प्रयोगात्मकता और नये आविष्कार की महत्ता मिट्ट है। यदि मैं कहूँ, तो यह कहूँगा कि कोई एकमात्र आवश्यकता यदि देश की है, तो वह यह है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के दक्षियानुमीपन को दूर किया जाय। आज की तीव्र गति से परिवर्तनशील दुनिया में, एक बात निश्चित है कि बरते हुए कल की शिक्षा-प्रणाली आज की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती और आगे आने वाले कल की आवश्यकता को तो वह हरगिज पूरा नहीं कर सकती।”

स्पष्ट है कि वर्तमान दशक में पहुँचकर विद्वानों ने उसी बात का अनुभव किया जिसे गांधी ने अब से ५० वर्ष पहले अनुभव किया था। और, देर आये दुस्त आये।

## शिक्षा का एकमात्र दायित्व—राष्ट्र का विकास

अब से शिक्षा का क्रम आरम्भ हुआ, शिक्षा के दायित्व अथवा उद्देश्य पर चर्चा आरम्भ हुई। इस चर्चा के दो केन्द्र रहे हैं : एक है, शिक्षा के उद्देश्य शाश्वत हैं और दूसरा, शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील हैं। शाश्वत दायित्व का अन्तर्गत इस प्रकार के विचार आते हैं—जैसे शिक्षा आत्मविकास, ब्याक्तित्व विकास, जीवन की तैयारी, सर्वाङ्गीण जीवन की तैयारी, रोटी-रोटी कमाने की तैयारी की प्रक्रिया। शिक्षा हमेशा से यह कुछ करती आयी है और करती रहेगी; शिक्षा एक साध्य है। दूसरे मत में शिक्षा का दायित्व बदलता रहेगा, यह एक प्रयोजनवादी (प्रैम्प्टिक) विचार है।





राष्ट्र की उन्नति, वास्तव में, इस बात पर निर्भर है कि उसके नागरिक कहीं तक कर्मठ, ईमानदार, सगन से काम करने वाले और ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न हैं। ऐसे नागरिक ही राष्ट्र को ससार का सिरमौर बना सकते हैं। ऐसे नागरिकों के न होने से ही हमारी सारी योजनाएँ विफल हुई हैं और यह सब इसीलिए हुआ कि हमने शिक्षा के दायित्व को समझा नहीं है, हमने यह जाना नहीं है कि कैसे शिक्षा एक राष्ट्र की शक्ति को बदल सकती है।

**राष्ट्र-निर्माण का दायित्व क्यों ?**

यह पढ़ने ही स्पष्ट किया जा चुका है कि एक विकासशील राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ होता है। सोवियत रूस में क्रान्ति के पश्चात् छात्रों और अध्यापकों ने शैक्षिक शिक्षा का कार्यक्रम जारी रखते हुए, सड़क बनाने और रेल की पटरी बिछाने तक के काम किये थे। गांधीजी भी चाहते थे कि अध्यापक और छात्र मिलकर भारत में सफाई, निरक्षरता को मिटाने, समाज-सुधार करने तथा इसी प्रकार के अन्य रचनात्मक काम भूमि छुट्टियों में करें। वर्तमान सरकार भी यह चाहती है कि विद्यालयों में श्रमदान हो, छात्रगण देहाती में जाकर कुछ काम करें। परन्तु इसका कुछ पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र-निर्माण का दायित्व हमारी वर्तमान शिक्षा पर क्यों है, इसकी विवेचना आवश्यक है।

हमारा देश बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रचलित परम्पराओं में अकड़े हुए हैं। दूसरी ओर इस बात का मोह भी बढ़ता जा रहा है कि हम सब कुछ—सम्यक्ता और संस्कृति भी—विज्ञानों से उधार लेकर पुनर्निर्माण करें। यह दोनों प्रवृत्तियाँ घातक हैं। कोई भी देश अपने उपस्थान काल में अपनी पुरानी संस्कृति की घरोर को फेंककर चल नहीं सकता, इस प्रकार वह अपनी जड़ें काट लेता। देश की सम्यक्ता और संस्कृति में एक बल देने की क्षमता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उन सांस्कृतिक परम्पराओं में जो कुछ सहायता और भूत है उसे दूर किया जाय। एक ओर संस्कृति को ज़िन्दा रखना और दूसरी ओर चीर-फाड़कर मुर्दा मांस को अलग करना, एक बड़ा नाजुक काम है, परन्तु इसके बिना राष्ट्र आगे बढ़ नहीं सकता। वर्तमान शिक्षा की यह एक बड़ी जिम्मेदारी है।

इस समय हमारा देश वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्रांति में होकर गुजर रहा है। हम क्रांति के फलस्वरूप जीवन-पद्धति में बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। यदि इन परिवर्तनों की अनुभूति और उनके अनुकूल जीवन व्यतीत करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, तो राष्ट्र की शक्ति में विस्फोट नहीं हो सकता। शिक्षा का काम यह है कि वह इन परिवर्तनों की अनुभूति जन-समाज में पैदा करे। होता यह है कि वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के कारण भौतिक साधन बढ़ते हैं और उनकी यह माँग होती है कि हम नये तरीके से जीवन व्यतीत करें, परन्तु परम्पराओं से चिपका समाज ऐसा नहीं करता और पिछड़ता जाता है। इस प्रक्रिया की सामाजिक पिछड़ापन (सोशल

## ७२ | भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ

सैग) कहते हैं। हमारे देश में यह प्रक्रिया चल रही है। जब यह पिछड़ापन बढ़ जाता है, और अज्ञानक प्रगतिशील समाज से हमारा भेल हो या टक्कर हो, तो सहसा पिछड़ेपन की अनुभूति होती है और उसे दूर करने की उदात्त सालसा क्रान्ति के रूप में पूट पड़ती है। क्रान्ति का स्वागत है; हमारे देश में ऐसा हो तो कोई बाधाबर्ध नहीं परन्तु क्रान्ति सफल नहीं होती, असन्तोष से उत्पन्न भाव घर को ही जना सकती है, एक क्रान्ति से अनेक क्रान्तियों का सिनसिला प्रारम्भ हो जाता है और पिछड़ापन दूर नहीं होता, उल्टे जो शक्ति पैदा होती है, वह राष्ट्र-निर्माण में काम न आकर विध्वंस के कार्य में लगती है। हमारे देश में छात्रों की अनुशासनहीनता और विद्रोह, हड़तालें, तोड़-फोड़ और नफसलबाड़ी आन्दोलन इस प्रक्रिया के संछाप हैं, युवकों की शक्ति का शोषण हो रहा है। यदि शिक्षा का काम राष्ट्र-निर्माण करना है, तो उसे परिवर्तनों की इस चुनौती का सामना करना होगा और राष्ट्र की ऊर्जा को सपप्य से रोकना होगा।

हमारे देश में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई है। इससे एक परिवर्तन यह हुआ कि साधारण से साधारण जन को राष्ट्र के हर काम में हिस्सा लेने का अधिकार है; प्रशासन में वह भाग लेता ही है। यह एक बहुत बड़ी बात है। सो० ई० एम (स्टोरी आफ सिविलीजेशन) में कहा था कि प्राचीन काल की सभ्यताओं का अंग हुआ ? हा० इकबाल ने भी एक विचार प्रस्तुत किया था—'पूतानो, मिस, रोमन सब मिट गये जहाँ में, अब तक भगर हैं' बाकी नामों निहाँ हमारा यह नामोनिशान क्या बाकी है, दूसरे क्यों मिट गए ? श्री जोश ने इस प्रश्न का समाधान किया है, उनका कहना है कि पुरानी सभ्यताओं के चंद सम्राटों और उनके कुछ प्रतिभाशाली अनुयायियों ने बताया था, वे मर गये, सभ्यताएँ भी मर गयीं। परन्तु जिस संस्कृति और सभ्यता का निर्माण जन-साधारण के हाथों हुआ हो, वह मरती नहीं। हमारे देश की जानदार परम्परा यह रही है कि यहाँ की सभ्यता-संस्कृति को बनाने वाले सम्राट बरी थे, वे साठो-करोड़ों केनाम यरीब श्रद्धिमुनि थे, जिनके मर्न हुआ में अब भी पूँजेते हैं, जिनकी बायो अबर-अमर है। वे अपने नाम के सिक्के चलाना नहीं चाहते थे। आज प्रजातन्त्र ने हमको दुबारा यह अवसर दिया है कि हम सब साधारण जन अपनी सभ्यता-संस्कृति को बनायें और राष्ट्र को ऊँचा उठायें। यही पर शिक्षा का बाध जाना है। हमारी शिक्षा का काम है कि राष्ट्र-हित में वह जनसाधारण को इतना विवक्षित कर दे कि वह राष्ट्र-निर्माण में हिस्सा ले सके और प्रजातन्त्र को सफल बना सके।

राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र के भीतर रहकर और बाहर की ओर से भी नहीं बढ़े हो सकता। हम एक मिथ्या गर्व के साथ बढ़ा करते हैं कि यातायात के का विनाश होने से दुनिया छोटी पड़ गयी है, यह एक शोषण विचार है जो सदा बहुत बड़ा है और हर राष्ट्र विचारों के दायरे में बन्द रहकर सभ्यता को बढ़ा रहा है, विचारों की दूरी ज्यों-की-त्यों बाध है। ऐसा न होना।

साम्यवाद, प्रजातन्त्रवाद, आधिनायकवाद और उनकी शाखाएँ उपशाखाएँ न होंगी। विचारों की दूरी के कारण टकराव की संभावनाएँ हैं और युद्ध की स्थिति में राष्ट्र का विकास कैसे होगा ? शिक्षा का काम इस बात की ओर जनसाधारण का ध्यान बार-बार आकृष्ट करना है।

छात्रों और अध्यापकों से केवल 'धर्मदान' कराने से काम नहीं चलेगा। यह तो एक शुरुआत है। बाकी नागरिकों में श्रम, साहस, मनोबल और उनके साथ-साथ राष्ट्र को उभार उठाने की प्रबल आकांक्षा पैदा करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण और वर्तमान में एकमात्र दायित्व है।

**राष्ट्र-निर्माण के लिए शिक्षा के लक्ष्य**

यदि हम यह स्वीकार करके चलते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र-निर्माण है तो यह निश्चय करना पड़ेगा कि राष्ट्र-निर्माण के क्या प्रमुख लक्ष्य या आधार हैं, जिन्हें शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। इस सदर्भ में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा-आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित लक्ष्यों का विवरण देना आवश्यक है।

(१) आयोग का मत है कि राष्ट्र के निर्माण की प्रथम समस्या है, साक्षात्त में आत्मनिर्भरता। इस देश में साक्षात्त की भारी कमी है। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि खेती की उन्नति करने के सारे उपायों के बावजूद अन्न की कमी बनी रहेगी और निवृत्त भविष्य में अन्य देशों से भी अन्न मँगाना असम्भव होगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वे देश भी अन्न का निर्यात न कर सकेंगे। अतः शिक्षा का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों में इस बात की चेतना पैदा करें कि वे जनसंख्या के बढ़ने की समस्या के प्रति जागरूक रहें। साथ ही उनमें इतनी क्षमता तथा योग्यता हो कि वे अन्न के उत्पादन को बढ़ावें।

(२) आयोग का मत है कि भारत की उन्नति की दूसरी समस्या है—आर्थिक प्रगति और स्वतन्त्र-प्रतिष्ठित रोजगार। एक गरीब देश कभी तरक्की नहीं कर सकता और भारत गरीब है। देश में बेहद बेरोजगारी है। प्रशिक्षित जन भी बेरोजगार हैं। यहाँ के लोगों को इतना भी भोजन नहीं मिल पाता जितना कि एक नागरिक के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय आय बहुत कम है। ऐसी दशा में देश की उन्नति कैसे हो सकती है ? इसलिए राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा को एक काम यह करना है कि वह ऐसे नागरिक पैदा करे, जो उत्पादन में सक्षम हों; उत्पादन-केन्द्रित शिक्षा के द्वारा नागरिकों को व्यवसायों का ज्ञान कराया जाय ताकि वे रोजगार पा सकें और उन्हें सरकार का मुँह न ताकना पड़े।

(३) आयोग का मत है कि भारत की उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा है—सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता का अभाव। जब तक भारत का समाज कई स्तरों पर बँटा है, समुदाय, धर्म, भाषा और जातियों के नाम पर वह समाज विभाजित है, तब तक राष्ट्रहित के लिए कोई सघटित प्रयत्न नहीं हो सकता। भारतीय समाज में 'राष्ट्र' की कोई कल्पना ही नहीं है। ऐसी दशा में शिक्षा का कार्य यह है कि वह नागरिकों



कि किसी स्त्री की तरफ भाँस उठाकर न देखे, बख़्क ब्रह्मचर्य का पालन करे, मदिरा-पान, विवासिता, कुटेब से दूर रहकर सयमपूर्ण जीवन बिताये । ऐसे व्यक्ति की कल्पना से चरित्र का राष्ट्र-निर्माण से जो सम्बन्ध है, वह धूमिल जान पड़ने लगता है । वास्तव में चरित्र का अर्थ व्यापक है । वह यह है कि कुछ शाश्वत मूल्यों पर पूर्ण आस्था के साथ प्रनोमनों में बचते हुए दृढ़ रहना, उन मूल्यों की रक्षा के लिए हर तरह का त्याग करना । वे मूल्य हैं—निर्भीक्तापूर्वक सत्य पर दृढ़ रहना; ईमानदारी से, जहाँ भी प्रसिद्ध पर काम रहे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना और इस मार्ग में आने वाले प्रसोमनों, जैसे अनुचित साधनों में धन पैदा करना, भोग-विवास की लाजसा से कोई छूट देना या किसी को लाभ पहुँचाना आदि, से मुक्त रहना, अधिकाधिक परिश्रम करके अपने काम को पूरा करना और उसे कलात्मक ढङ्ग से करना, अपने स्थान पर ग्यायो-चित्त व्यवहार करना; जन-सेवा के लिए हर समय तत्पर रहना अर्थात् यह अनुभव करना कि मुझे जनसेवा के लिए बेलन या लाभ मिल रहा है, राष्ट्र के प्रति बफादारी रखना । इन मूल्यों का सम्बन्ध किसी प्रकार की कुलसता से नहीं है, इनका सम्बन्ध मनुष्य के मन से, उसकी अभिवृत्ति से है । मन का परिष्कार और इन अभिवृत्तियों की उत्पत्ति ही चरित्र-निर्माण है । हमारी शिक्षा-योजनाओं में इन सूक्ष्म परिवर्तनों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है ।

उक्त प्रकार से चरित्र-निर्माण की ओर ध्यान देने से हमारी शिक्षा कोई फल नहीं दे रही है । जब तक हमारे नागरिक निर्भीक, सत्यपरायण, ईमानदार, कर्मठ, श्वायप्रिय, कर्त्तव्य-परायण तथा जन-मेवा की भावना से परिपूर्ण नहीं बनते, राष्ट्र कभी भी ऊँचा नहीं उठ सकता है । केवल कुछ कुशल इन्जीनियर, डाक्टर, प्रशासक तथा तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करने से देश को लाभ नहीं मिल सकता । हम ऐसे कुशल जनों की शिक्षा पर देश के भीतर और बाहर विदेश में, सालो-करोड़ों रुपए व्यय करते हैं परन्तु वे देश की सेवा के लिए वापस नहीं लौटते, या लौटकर मुल-मालसा से विदेश चले जाते हैं (जिसे ब्रैन ड्रैन के नाम से पुकारा जाता है), यदि यहाँ रहे भी तो भ्रष्टाचार में फँसकर सार्वजनिक धन का अपव्यय करते हैं । इफ़रों में, वीकी में, प्रशासकीय पदों पर, यहाँ तक कि विदेशों के दूतावासों में भारत के नागरिक राष्ट्र के प्रति निष्ठा का अभाव प्रदर्शित कर रहे हैं, जनता को परेशान करते हैं । यदि राष्ट्र का निर्माण करना है, तो पहले इन बुनियादी बातों की ओर ध्यान देना होगा । दानवी प्रकृति के विशेषज्ञ जिन्हें तैयार करने की योजनाएँ बन रही हैं, राष्ट्र को बरबाद करके छोड़ेंगे । आज देश की इन विशेषताओं की अपेक्षा योग्य ईमान-दार नागरिकों की बड़ी आवश्यकता है, परन्तु इस ओर शिक्षा के क्षेत्र में उदासीनता है । इस प्रसंग में २१ जुलाई, १९७० को पटना विश्वविद्यालय की स्वर्णजयन्ती के अवसर पर वर्तमान राष्ट्रपति श्री० श्री० श्री० गिरि के उद्घाटन भाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है । अब जान पड़ता है कि राजनीतिज्ञों की भाँसें खुल रही हैं । राष्ट्रपति के भाषण में 'चरित्र के सफ़ट' (प्रवर्धित आक्र केरेक्टर) का उल्लेख है ।

उत्प्रेत है। उन्होंने छात्रों को डिग्री देने के स्थान पर मानव-समाज की सेवा, शारीरिक धर्म के काम, और आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने की चर्चा की है। राष्ट्रपति ने वही बातें कही हैं, जो गांधीजी ने पचास वर्ष पहले कही थीं। खेद तो यह है कि हमारा राष्ट्रपति भी शिक्षा-प्रणाली में कोई हेर-फेर करने में असमर्थ है। शिक्षा की भ्यर्थता को हमारे नवयुवक छात्र समझने लगे हैं। पटना विश्वविद्यालय के इस समारोह में छात्रों ने बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री और केन्द्रीय शिक्षामंत्री को बोलने नहीं दिया।

अस्तु, हमें राष्ट्र-निर्माण के लिए शिक्षा के दायित्वों में, विज्ञान तथा तकनीकी प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकता तथा अन्य महत्वपूर्ण बातों के साथ-साथ चरित्र-निर्माण को स्वीकार करना चाहिए और इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

राष्ट्र-निर्माण की दृष्टि से एक आवश्यक तथ्य यह होना चाहिए कि हमारे नागरिक हर प्रकार से 'स्वतन्त्र' हो। यह ठीक है कि राजनैतिक दृष्टि से देश स्वतन्त्र हो गया है परन्तु हमसे केवल 'शरीर' स्वतन्त्र हुआ है, 'आत्मा' नहीं। सामान्य भारतीय विचारों की गुलामी से मुक्त नहीं हुआ। अशिक्षित जन परम्पराओं के गुलाम हैं, हजारों वर्षों से उनके जीवन में एक ही बात सामने रही है—परिवार में पैदा होना, बड़े होना, विवाह, कोई रोजगार कर लेना और फिर शान्तिपूर्वक मर जाना, उन्होंने राष्ट्र और समाज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। शिक्षित जनो में दूसरी प्रकार की गुलामी है, कोई गांधी या गुलाम तो कोई क्रांतिकारक का, कोई धार्मिक ग्रन्थों का गुलाम तो कोई भाषा का गुलाम। जिस देश में जनसंख्या बढ़ रही हो, वहाँ के एक समाज में मुशिक्षित लोग अभी भी एक साथ चार पत्तियों रखने की वकालत करें, तो उन्हें कैसे स्वतन्त्र कहा जाय ? फिर भी ऐसे मुशिक्षित जन हैं जो बरसी हुई परिस्थितियों के सदर्भ में विचार कर नहीं सकते। हो सकता है कि वे उन अशिक्षित ममज्ञ का सम्मान नो देने के अर्थ के गुलाम हो, पर गुलामी तो है। यदि राष्ट्र का निर्माण करना है, तो नयी परिस्थितियों के सदर्भ में सोचना होना और परम्पराओं की दासता से मुक्त होना पड़ेगा। इस प्रकार की शक्ति शिक्षा के द्वारा पैदा करना आवश्यक है। डा० सम्पूर्णानन्द ने अपने एक निबन्ध (नोतिशयोलॉजिकल अन्वैश्वर्य इन एजुकेशन) में कहा है—

“हमारे लिए शिक्षा शुद्ध रूप से एक प्रयोजनवादी विषय है, साध्य से साधनों को जोड़ने का प्रयत्न है, यह साध्य आज की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होमे। यह परिस्थितियाँ एक युग से दूसरे युग में बदलती रही हैं; इन परिस्थितियों की रफ़्तार अभी बहुत तेज़ और कभी बहुत कम रही है, यह परिवर्तन इस देश में एक प्रकार के और दूसरे देश में दूसरे प्रकार के हुए हैं और यदि हमारा दृष्टिकोण यह है कि शिक्षा प्रयोजनवादी आधार पर बदलती है, तो फिर शिक्षा का कोई दार्शनिक या यन्त्रनिष्ठ मूल्य नहीं है। शिक्षा विद्वत्

एक काम कर सकता है, वह यह है कि परिस्थिति के अनुसार वह साधनों का उपयोग करे... परन्तु यह केवल एक पक्ष है।"

कहने का तात्पर्य यह है कि बदलते हुए समाज में या विकसित राष्ट्रीय राष्ट्र में, उसकी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है, जब उस समाज के लोग विचार करने में स्वतन्त्र हो, और तभी वे परिवर्तनों के महत्व को समझ सकेंगे। इसलिए राष्ट्र-निर्माण की दृष्टि से शिक्षा का स्वतन्त्र रूप से विचार करने की शक्ति नागरिकों में पैदा करनी चाहिए।

### राष्ट्रोन्नति में शिक्षा द्वारा योगदान के उपाय

भारतीय शिक्षा-आयोग ने राष्ट्रहितकारिणी शिक्षा की रूपरेखा पर बड़े विस्तार से विचार किया है और वे विचार उसके प्रतिवेदन के रूप में सुलभ हैं। जिज्ञासुओं को इस प्रतिवेदन को आघोषात पढ़ना चाहिए। तथापि आयोग के विचारों का कुछ सारांश नीचे प्रस्तुत है।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्र-निर्माणकारी शिक्षा के दो पहलुओं पर विशेष बल दिया है, एक पहलू है भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना में सुधार और दूसरा है शिक्षा के द्वारा कुछ विशेष परिणाम उत्पन्न करने की दिशा। आयोग ने एक ओर शिक्षा की संरचना और प्रशासकीय मशीन को दुस्तर्ज करने पर बल दिया है, इसके लिए उसने शिक्षा-प्रणाली को कई स्तरों पर संघटित करने का मुझाव दिया है, हर स्तर के लिए समय निश्चित किया गया है और उसके लिए कार्यक्रम स्थिर किया गया है। शिक्षा में ज्ञान पैदा करने के लिए एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक शिक्षा के लिए साधारण विद्यालय (कॉमन स्कूल) की कल्पना है; केन्द्र राज्य और जिला स्तर पर प्रशासन में संघटन और निरीक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक के महत्व को स्वीकार करके आयोग ने हर स्तर के अध्यापकों की शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति के लिए वेतन-मान, काम की दशाएँ और सुविधाएँ निश्चित की हैं। साथ ही अध्यापकों की क्षमता बढ़ाने के लिए आयोग ने अध्यापक-शिक्षा के अलग-अलग, अध्यापक-परीक्षकों और संस्थाओं के बारे में विचार करके उपयोगी मुझाव दिये हैं। यद्यपि इन सबका राष्ट्र-निर्माण से सीधा सम्बन्ध प्रकट नहीं होता, तथापि इसमें नदेह नहीं कि आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति तभी हो सकती है, जब प्रशासन, शिक्षा के स्तरों पर कार्य का संघटन और अध्यापकों की दशा में पहले मुझाव करके शिक्षा-प्रणाली में ज्ञान फूँकी जाय।

शिक्षा का दूसरा पहलू है, उसका कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की पूर्ति से ही राष्ट्र-निर्माण की दिशा में जन-समाज आगे बढ़ सकता है। राष्ट्र-निर्माण की एक आवश्यक शक्ति है, छायात्र में आत्मनिर्भरता। इस शक्ति की पूर्ति के लिए आयोग ने कृषि-शिक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें अन्तर्गत विद्यालयों में कृषि की शिक्षा, पालिटेक्नीक स्कूलों में कृषि की विशेष शिक्षा, कृषि-विश्वविद्यालयों में कृषि



[illegible][illegible][illegible]

राष्ट्रोन्नति के लिए आयोग ने राजनैतिक आधुनि को चौथा मुख्य आधार माना है। इस आधार को पुष्ट करने के लिए शिक्षा कम में प्रजातान्त्रिक भावना को उत्पन्न करने की प्रक्रिया पर बल दिया गया। स्वस्थ, सज्ज और उद्बुद्ध नागरिक तैयार करने के लिए, शारीरिक शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, रचनात्मक शक्तियों के उन्नयन, समाज सेवा तथा सैनिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की आवश्यकता बतायी गयी है। विषयबहुत्व की भावना उत्पन्न करने के लिए पाठ्य-पुस्तकों में परिवर्तन करने की मलाह दी गयी है। विदेशी भाषाओं के अध्ययन से हम पश्य की पुष्टि की जा सकती है।

संक्षेप में, आयोग ने राष्ट्रोन्नति के व्यापक सदस्य में शिक्षा की उपयोगिता पर विचार किया है। उसने स्वीकार किया है कि भारत में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास करने की अत्यन्त आवश्यकता है। यद्यपि संकुचित राष्ट्रीयता अन्ताराष्ट्रीय युद्धों को जन्म देती है और एक सभ्य राष्ट्र को आक्रामक बना देती है, तथापि हममें सन्देह नहीं कि राष्ट्रीयता की भावना में बहुत बड़ी शक्ति होती है; किसी भी राष्ट्र में जब यह भावना पैदा हो जाती है, तो वह बड़ी तेजी तथा उत्साह से शक्ति-अन्न के काम में जुट जाता है। जर्मनी, इटली, जापान, चीन और इजरायल के उदाहरण हमारे सामने हैं। स्वयं भारत में राष्ट्रीयता का विस्फोट जब हुआ, तो अंग्रेजों को भागना पड़ा; चीन को अपना आक्रमण बन्द कर देना पड़ा और पाकिस्तान ने मुंह की खापी। राष्ट्रीयता का भाव दो बातों पर निर्भर है, एक है देश की संस्कृति को समझना और उस पर अभिमान तथा दूसरी है, इस बात का विश्वास कि भविष्य हमारा उज्ज्वल है और हमें भारत को राष्ट्रों की अगली पंक्ति में बिठाना है। इन दोनों भावों की शिक्षा के द्वारा उत्पन्न करना है। देश के विभिन्न भागों में स्थित शिक्षा संस्थाओं के बीच अलग-अलग दूर करके, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थाएँ खोलकर, देश के विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृतियों में बीच आदान-प्रदान और उन्हें समझने की चेष्टा करके यह काम पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार नयी पीढ़ी में शिक्षा के द्वारा ही यह भाव पैदा किया जा सकता है कि भविष्य हमारा है, देश में विकासार्थक कार्यों में नयी दुनिया बनने वाली है जिसमें सभी गुली होंगे।

शिक्षा पर सार्वजनिक धन व्यय होना है और शिक्षा की अच्छाई या बुराई से होने वाले लाभ-हानि का फल आम जनता को भोगना पड़ता है। इसलिए अब समय आ गया है कि सामान्य जन भी शिक्षा की समर्थनता पर विचार करे और उसकी अपर्याप्तता की आलोचना करे; शिक्षा अब फन्द विशेषज्ञों की कपौनी नहीं है। इसलिए हमें भी इस बात पर विचार करने का आग्रह है। एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तो यह दिखायी देता है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए ईमानदार और पारश्र्वान नागरिकों का होना आवश्यक है और दुर्भाग्य से हम प्रकार के नागरिक शिक्षा पैदा नहीं करती।

नागरिकता की भावना भारत में है ही नहीं, इसका कारण है कि यहाँ हर

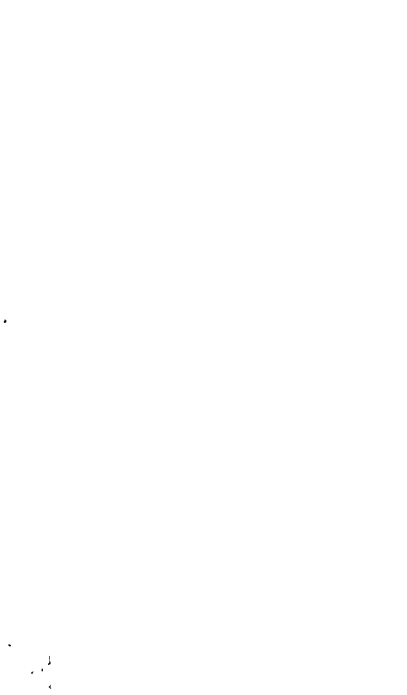
मनुष्य वैयक्तिक स्तर पर अपना जीवन व्यतीत करता है, वह अपने में इस प्रकार केन्द्रित है कि अपने पड़ोसी के हितों का बलिदान करने में उसे सकोच नहीं होता। राष्ट्रीय सम्पत्ति को वह अपनी सम्पत्ति नहीं समझता, दफ्तर में पते और रोशनी पर वेदर्श में बिजली खर्च की जाती है क्योंकि नर्मचारी को यह अनुभूति नहीं कि यह राष्ट्र के धन का अपव्यय है। बैंको, सरकारी दफ्तरों और प्रतिष्ठानों में अधिकारीगण अपनी सुख-सुविधा के लिए फूलर, फर्नीचर, तथा अन्य उपकरण भेजाते हैं न कि कार्य-क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से। विकास योजनाओं के चलाने में भारी अपव्यय इसीलिए हुआ है कि अधिकारियों ने बिना निरीक्षण किये भत्ते बनाये हैं; घर बने हैं, तो वे टूट गये, सड़कें बनीं तो खुद गयीं। यह सब इसलिए हुआ कि सरकारी कर्मचारी नागरिकता का अर्थ नहीं समझते। कोई भी शिक्षा-प्रणाली राष्ट्र-निर्माण में सहायक नहीं हो सकती यदि वह मानवीय साधनों (ह्यू मैन रिसोर्सेज) को एकत्र नहीं करती। यदि शिक्षा नवयुवकों और नवयुवतियों में मानवता का भाव नहीं पुष्ट करती, तो वे लोग उत्तरदायित्व के पदों पर अपने कर्तव्य-पालन में सचेष्ट नहीं रह सकते और देश की उन्नति एक आकाश-कुसुम मात्र रहेगी।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

१. "वर्तमान भारतीय शिक्षा इतिहास के प्रवाह के विरुद्ध है।" इस कथन पर प्रकाश डालिए।
२. शिक्षा किम प्रकार देश की उन्नति में सहायक हो सकती है? कुछ उदाहरण देकर अपने विचारों की पुष्टि कीजिए।
३. कोटारी शिक्षा-आयोग ने शिक्षा-प्रणाली में किन तत्त्वों पर जोर दिया है, जो देश की उन्नति में साधक हैं? उनके सामग्र्य में अपना मत प्रकट कीजिए।
४. शिक्षा क्रम में किन उपायों का अवलम्बन करके शिक्षा और राष्ट्रीय उन्नति के बीच तानभंग बैठाया जा सकता है? आप अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट कीजिए।

















১৯৬৯ 'কিড-কল্যাণ' প্রতিষ্ঠান  
 শিল্পক  
 প্রতিষ্ঠান: কল্যাণ  
 প্রতিষ্ঠান: কল্যাণ  
 শিল্প





नवार्थ और नि शुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रश्न किया तो हमारे  
 म धन नहीं जुटता (यद्यपि फीज, पुनिम तथा मिबिन प्रशामन पर आज बंद करके  
 खर्च किया जाता है) और यदि प्राथमिक शिक्षा की थोड़ी बहुत व्यवस्था करते हैं,  
 वह सस्ती, हल्की, माध्यम और व्यर्थ होती है। अध्यापकों की वर्द्धिया मंता छोटी  
 र मकने में हम असमर्थ हैं। माध्यमिक शिक्षा इनको लचर है कि वह स्वयं और  
 योग्य नागरिक नहीं पैदा कर पाती और छात्रों को इतना मगर्थ नहीं बनाती कि वे  
 उच्च अध्ययन में कुशल मिट्ट हो सकें। उच्च शिक्षा में शोध के नाम पर खूब धन  
 बहाया जा रहा है पर छात्र अनुशासनहीन बन रहे हैं और उनका ज्ञान उथला होता  
 है और वे अपनी योग्यताओं को आकांक्षाएँ पूरी करने में असमर्थ बनकर निराशा और  
 शोभ में आन्दोलित हो रहे हैं। तकनीकी शिक्षा का हाल यह है कि तकनीकी ज्ञान  
 प्राप्त जन रोजगार नहीं पाता। उन्हें केवल सरकारी नौकरी की चाह है, स्वावलम्बी  
 होकर वह कोई उत्पादन का कार्य नहीं कर सकता। हमारे देश की परम्पराओं में  
 विमुख शिक्षा चरित्र का उत्पादन नहीं कर पाती, इस धर्म-परम्परा में शिक्षा धर्म-  
 निरपेक्ष है। भारत में १५ सम्पन्न भाषाएँ हैं पर शिक्षा के क्षेत्र में हम विदेशी भाषा  
 अंग्रेजी की माला जड़ रहे हैं। भारतीय भाषाओं के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं,  
 पर सरकार अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए प्राणपण से संचिष्ट है। देशप्रेम पैदा न करके  
 शिक्षा मनुष्य को व्यक्तिवादी बना रही है जिसमें देश की एकता पर प्रहार हो रहा  
 है। सबसे बड़े खेद की बात यह है कि शिक्षा की अदभुत तथा बलवती परम्पराएँ  
 हमारे देश में प्राचीनकाल में चलती आ रही हैं पर विदेशी शिक्षा के मोह में हम उन  
 बहुमुख्य परम्पराओं में अनभिज्ञ हैं। पश्चिम की थोड़ी नकल करके हम गैली मारते  
 हैं परन्तु वहाँ के नैतिक दर्शन का सर्वाङ्ग ज्ञान भी हमें नहीं है।  
 अस्तु, अनेक समस्याएँ शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान हैं। उनका परिचय और  
 समाधान बताने के लिए इस पुस्तक की रचना की गयी है। लेखकों के कई वर्षों के  
 अनुभव और परिश्रम का यह फल है। पुस्तक के सभी अध्याय विचारोत्तेजक हैं।  
 पाठ्य-सामग्री सर्वाङ्गीणता की दृष्टि से बाहे पूर्ण न हो पर आत्मनिर्भर इसमें अवश्य  
 मिलेगा। प्रतिभे के लिए सप्रज्ञ छात्रों को भारतीय शिक्षा की समस्याओं के प्रति  
 संचिष्ट करना इस पुस्तक का एक प्रमुख लक्ष्य है। गवर्नमान विश्वविद्यालय के  
 बी० एड० परीक्षा के लिए निर्धारित चतुर्थ प्रश्न-पत्र के पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले  
 छात्राध्यापकों के लिए यह विवेक रूप में उपयोगी है। ऐसी पुस्तक में उनका लाभान्वित  
 होना निश्चित है।

पाठकों में सेवकगण आशा करते हैं कि वे सहृदयतापूर्वक इस पुस्तक का पढ़ेंगे  
 और उद्दारापूर्वक त्रुटियों की ओर सुकेन करेंगे ताकि उनका परिमार्जन भविष्य में  
 किया जा सके।

चरर-पुष्पिमा  
 मग १९६८

चौधरी  
 उपाध्याय

## अनुक्रमणिका

### अध्याय १

#### प्राथमिक शिक्षा का इतिहास

१-१६

१६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में देशी शिक्षा १, देशी शिक्षा की जाँच २, देशी शिक्षा की अवनति के कारण ३, ईसाई पादरियों की चेष्टाएँ ४, कलकत्ता महरमा की स्थापना ४, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना ४, सन् १८१६ से सन् १८५४ तक ५, ब्रुड का घोषणा-पत्र ७, घोषणा-पत्र की प्रमुख मिकारिमें ७, सन् १८५४ में सन् १८८८ तक प्राथमिक शिक्षा का विकास ८, सन् १८८२ का शिक्षा आयोग ९, कार्य-क्षेत्र एवं उद्देश्य ९, मुभावा ९, अध्यापकों का प्रशिक्षण १०, सन् १८८२ में सन् १९०२ तक प्राथमिक शिक्षा का विकास १०, सन् १९०२ से सन् १९१० तक, सन् १९२१ से १९३७ का 'द्विष सामन', सन् १९३७ में १९४७ तक प्रान्तीय स्वशासन १२, योजना की समीक्षा, स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास १३, अध्यापार्थ प्रदन १६ ।

### अध्याय २

#### भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

१७-३६

अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता १७, प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवार्यता के लिए प्रारम्भिक प्रयास १८, सन् १८६० में १९१८ तक अनिवार्यता के लिए आन्दोलन १९, प्रान्ती में शिक्षा अनिवार्य करने के प्रयत्न २१, स्वतन्त्रता के उपरान्त अनिवार्य शिक्षा २२,

प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य बनाने में कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ २३, नि शुल्क अनिवार्य शिक्षा-प्रसार के लिए मुद्भव ३०, अभ्यासार्थ प्रश्न ३८, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न ३८ ।

## अध्याय ३

४०-५२

## ✓ विदेशों में प्राथमिक शिक्षा

इंग्लैण्ड में प्राथमिक शिक्षा ४०, प्राथमिक शिक्षा के स्तर ४१, संयुक्त राज्य अमरीका में प्राथमिक शिक्षा ४४, शिक्षा और स्थानीय इकाइयाँ ४५, संयुक्त राज्य में प्राथमिक शिक्षा का संगठन ४५, संबन्धित हम की प्राथमिक शिक्षा ४८, संबन्धित शिक्षा के सोपान ४६, अभ्यासार्थ प्रश्न ५२ ।

✓ अध्याय ४  
बुनियादी शिक्षा

५३-७६

वर्धा शिक्षा योजना का जन्म ५४, जाकिर हुसैन समिति ५४, जाकिर हुसैन रिपोर्ट की रूपरेखा ५५, पाठ्य-क्रम का रूप ५५, खैर समितियाँ ५६, मार्जेंट योजना ५६, बुनियादी शिक्षा का स्वरूप ५८, विभिन्न दर्शन और बुनियादी शिक्षा ६०, बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त ६०, बुनियादी शिक्षा की वर्तमान स्थिति ६५, बुनियादी शिक्षा की समस्याएँ व कठिनाइयाँ ६७, बुनियादी शिक्षा की ममालोचना ७०, बेमिक शिक्षा की कठिनाइयाँ को दूर करने के उपाय ७२, अभ्यासार्थ प्रश्न ७६, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न ७६ ।

## अध्याय ५

७७-८८

## ✓ माध्यमिक शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास

सन् १८५४ से १८८८ तक ७७, सन् १८८८ का भारतीय शिक्षा आयोग ७८, लार्ड कर्जन और माध्यमिक शिक्षा ७९, सन् १९०६ का शिक्षा-नोति सम्बन्धी मन्त्रालय प्रस्ताव ७९, कलकत्ता विश्व-विद्यालय आयोग (१९१३) ८१, सन् १९०५ से १९०९ तक माध्यमिक शिक्षा की प्रगति ८२, द्वंद्व प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति (१९०२-१९३७) ८२, मार्जेंट योजना १९६६, ८५, अभ्यासार्थ प्रश्न ८६ ।



### अध्याय ६ ✓ माध्यमिक शिक्षा आयोग

आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य ८७, आयोग के मुद्दाव—माध्यमिक शिक्षा के दोष ८८, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य ८९, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन ८९, भाषाओं का अध्ययन ९०, पाठ्य-पुस्तकें ९०, माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम ९१, पाठ्यक्रम के विषय ९२, अध्यापन विधि ९४, चरित्र-निर्माण की शिक्षा ९४, माध्यमिक शिक्षा में मार्ग-प्रदर्शन एवं परामर्श ९४, छात्रों का शारीरिक कल्याण ९५, परीक्षा एवं वार्षिक मूल्यांकन ९५, अध्यापकों की उन्नति ९५, अध्यापकों का प्रशिक्षण ९६, प्रशासन की समस्या ९६, माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन ९७, दोष ९८, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुद्दावों का प्रभाव ९८, अभ्यासार्थ प्रश्न ९९, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न ९९ ।

#### अध्याय ७

#### बहु-उद्देशीय विद्यालय

१०१-११३

बहु-उद्देशीय विद्यालयों के लिए प्रयास १०२, पाठ्य-पुस्तकें दोषों में बहु-उद्देशीय विद्यालय १०२, मधुक्त राज्य अमेरिका १०४, बहु-उद्देशीय विद्यालय का अर्थ १०४, बहु-उद्देशीय विद्यालय की रचना १०५, बहु-उद्देशीय विद्यालय के उद्देश्य १०५, बहु-उद्देशीय विद्यालयों में लाभ १०६, बहु-उद्देशीय विद्यालयों की समस्याएँ १०६, मुद्दाव १११, अभ्यासार्थ प्रश्न ११२, राजस्थान विश्व-विद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न ११३ ।

१११

#### अध्याय ८

#### ✓ शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन ८ ११४-१२१

अपव्यय तथा अवरोधन का अर्थ ११४, अपव्यय और अवरोधन के कारण—शारीरिक या व्यक्तिगत कारण ११५, सामाजिक कारण ११६, विद्यालय से सम्बन्धित कारण ११७, आर्थिक कारण ११८, दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन ११९, अपव्यय एवं अवरोधन-निवारण के उपाय—प्राथमिक स्तर पर ११९, माध्यमिक स्तर के लिए मुद्दाव १२०, सामान्य मुद्दाव १२१, अभ्यासार्थ प्रश्न १२१, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न १२१ ।

## शिक्षा का प्रबन्ध करने वाली संस्थाएँ १२२-१३१

स्था के प्रकार—राज्य द्वारा स्थापित एवं नचालित विद्या-  
 १२३, केन्द्रीय सरकार—शिक्षा मन्त्रालय १२४, मुख्य  
 मन्त्रालय १२४, रेलवे मन्त्रालय १२४, प्रांतीय सरकार १२४,  
 प्रांतीय नियंत्रण के दोष १२५, स्थानीय संस्थाओं द्वारा  
 चालित विद्यालय १२५, धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित विद्यालय  
 १२७, व्यक्तिगत प्रबन्ध-समितियों द्वारा संचालित विद्यालय  
 १२७, व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों की कठिनाइयाँ—राजनीतिक  
 प्रभाव १२६, आर्थिक समस्या १२६, विद्यालय-भवनो का अभाव  
 १२६, क्रीडागण का अभाव १३०, प्रयोगशालाओं का अभाव  
 १३०, छात्रावास का अभाव १३०, राष्ट्रीय विद्यालयों की  
 स्वतन्त्रता का समाप्त होना १३०, योग्य अध्यापकों का अभाव  
 १३०, आकर्षक वेतन-शृंखला का न होना १३१, नौकरी की  
 सुरक्षा का अभाव १३१, ग्रामीण क्षेत्रों में मुविद्याओं का अभाव  
 १३१, अभ्यासार्थ प्रश्न १३१ ।

## तकनीकी शिक्षा

१३२-१५१

तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता १३२, तकनीकी शिक्षा का  
 इतिहास १३३, मुस्लिम काल में तकनीकी शिक्षा १३३, ब्रिटिश-  
 शासन काल में तकनीकी शिक्षा १३३, पञ्चवर्षीय योजनाएँ और  
 तकनीकी शिक्षा १३६, नवीन योजनाएँ १४१, तकनीकी शिक्षा  
 की समस्याएँ १४२, विदेशों में तकनीकी शिक्षा १४६, अभ्यासार्थ  
 प्रश्न १५०, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में  
 पूछे गये प्रश्न १५१ ।

## भारत में भाषा-समस्या

१५२-१७०

भाषा का महत्त्व १५२, भाषा-समस्या का इतिहास १५३,  
 माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुद्दाव १५६, केन्द्रीय शिक्षा सलाह-  
 कार परिषद् का मुद्दाव १५७, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्  
 का मुद्दाव १५८, भावात्मक एकता समिति का मुद्दाव १६०,

कोटारी आयोग के मुझाव १६१, विभिन्न भाषाओं का महत्त्व १६३, विभिन्न प्रान्तों में हिन्दी का स्थान १६६, प्रादेशिक भाषाओं का स्थान १६७, अन्य देशों के उदाहरण १६७, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न १६६ ।

अध्याय १२

### ✓ पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण १७१

पाठ्य-पुस्तकों का महत्त्व १७२, प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों के दोष १७६, पाठ्य-पुस्तकों के सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुझाव १७७, आयोग की आलोचना १८०, पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता १८१, पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण में लाभ १८२, विभिन्न राज्यों में पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण १८३, राजस्थान में पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण १८५, पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण में उत्पन्न समस्याएँ १८६, राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के उपाय १८८, अभ्यासार्थ प्रश्न १९०, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न १९० ।

अध्याय १३

### ✓ धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा १९१-२०४

धर्म क्या है १९१, धर्म तथा शिक्षा १९२, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य १९३, धर्म-शिक्षा का इतिहास १९४, धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता १९६, विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का रूप १९८, समिति द्वारा विभिन्न स्तर पर मुझाव १९९, नैतिक शिक्षा २००, अभ्यासार्थ प्रश्न २०२, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न २०३ ।

अध्याय १४

### भारत में शैक्षिक प्रशासन की समस्याएँ २०५-२३८

भारतीय शैक्षिक प्रशासन की रूपरेखा २०६, भारतीय शिक्षा का शैक्षिक प्रशासन पर प्रभाव २१०, शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण २१२, विकेन्द्रीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २१२, विकेन्द्रीकरण के पक्ष में दिये जाने वाले तर्क २१३, विकेन्द्रीकरण

क्या होता है २१४, भारतीय वैश्विक प्रणाली में विवेकीकरण  
 का प्रयत्न २१६, विवेकीकरण में निहित गति २१८, भारतीय  
 वैश्विक प्रणाली में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति २२०, भारतीय वैश्विक  
 प्रणाली में अमानवीयता २२३ अमानवीयता की उद्भावना  
 २२३, अमानवीयता की उत्पत्ति के कारण २२६, अमानवीयता  
 की दूर करने के उपाय २२६, वैश्विक प्रणाली में समावेशन की  
 समस्या २२७, नियन्त्रण और निर्गमन की समस्या २२८,  
 समस्या का स्वरूप २२८, समस्या-प्रणाली के उपाय २३३, अन्त्या-  
 मार्थ प्रश्न २३७, राष्ट्रप्रधान विवेकीकरण की ओर २४०  
 परीक्षा में पूरे गये प्रश्न २३८ ।

अध्याय १५

२३६-२६६

### ✓ भारत में प्रौढ़ एवं सामाजिक शिक्षा

प्रौढ़ एवं सामाजिक शिक्षा के विकास का परिचालन २६०  
 सामाजिक शिक्षा और सामुदायिक विकास-मार्ग योजना २६३  
 सामाजिक शिक्षा में कार्यरत महत्वात्त नया बतमान स्थिति २६८  
 बतमान समय में सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता और प्रारम्भ  
 २७०, सामाजिक शिक्षा के लक्ष्य २७३ सामाजिक शिक्षा के  
 माप में उत्पन्न बाधाएँ और समस्याएँ २७८ समस्याओं का हल  
 २८० अन्त्यामार्थ प्रश्न २८६ राष्ट्रप्रधान विवेकीकरण की ओर  
 २८० परीक्षा में पूरे गये प्रश्न २६६ ।

अध्याय १६

२६७-२८७

### ✓ भारत के पशुचिकित्सक

पशुचिकित्सक क्या है २६७ भारत में पशुचिकित्सक की  
 व्यवस्था और उनका महत्त्व परिचालन २७३ भारत के पशुचिकित्सक  
 कृषि २७३ पशुचिकित्सक कृषि का कार्यक्रम तथा विवरण २७४  
 पशुचिकित्सक कृषि २७६ पशुचिकित्सक कृषि का हल २७८  
 पशुचिकित्सक कृषि द्वारा उत्पन्न समस्याएँ २८१, पशुचिकित्सक  
 कृषि का महत्वात्त का हल २८३ पशुचिकित्सक कृषि का हल २८३  
 कृषि का हल २८३ पशुचिकित्सक कृषि का हल २८३  
 पशुचिकित्सक कृषि का हल २८३

अध्याय १७

✓ भारत में राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता

और शिक्षा

२६२-३२३

राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की प्रक्रिया २६२, राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि २६५, राष्ट्रीय एकता को सुनौती देने वाली वापार्त् २६८, वाणिज्यिक मकद और राष्ट्रीय एकता ३०५, शिक्षा की जिम्मेदारी ३०७, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की अभिवृद्धि ३०८, उपकुलपति सम्मेलन, जवहूर १९६१ में सर्वोच्च वैश्विक उपाय ३०९, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन द्वारा मुभाये मये उपाय ३१०, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ३११, कुछ विद्वज्जनों के विचार ३१३, भारतीय शिक्षा आयोग ३१५, शिक्षकों का उलगादित्व और उसका निर्वाह ३१८, राज्य का दायित्व ३२१, अध्यापार्थ प्रश्न ३२२, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ३२२ ।

अध्याय १८

✓ पाश्चात्य वैश्विक विचारधारा का सिहावलोकन ३२४-३६६

सिहावलोकन का महत्त्व ३२४, पाश्चात्य वैश्विक विचारधारा की निम्नरता ३२५, रूसी ३१९, वेस्टमार्की ३३२, हरबार्ट ३३७, फ्रीडल ३४३, हरबार्ट स्वयं ३४८, जॉन ड्यूवी ३५२, पाश्चात्य चिन्तन का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव ३६१, वैश्विक मूर्तों में परिवर्तन ३६१, नये वैश्विक त्रिवार-कलाप ३६२, समन्वय का प्रयत्न ३६३, अध्यापार्थ प्रश्न ३६४, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न ३६५ ।

अध्याय १९

✓ प्राचीन गुरुकुल प्रणाली और आधुनिक

भारतीय शिक्षाविद्

३६७-३९१

गुरुकुलों के प्रति ध्यानाकर्षण ३६७, गुरुकुल प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ३६८, वर्तमान भारत को आवश्यकताएँ तथा उनके अनुरूप गुरुकुल प्रणाली का गन्धोषन ३७३, स्वामी दयानन्द द्वारा अनुमोदित शिक्षा-प्रणाली तथा गुरुकुल ३७४,

श्रीनन्दनाथ ठाकुर और गुरुकुल ३७६, गुरुकुल के मन्दन में  
 गांधीजी के विचार ३८४, आचार्य कर्वे के विचार ३८८,  
 अभ्यामार्थ प्रश्न ३९०, राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड०  
 परीक्षा में पूछे गये प्रश्न ३९० ।

अध्याय २०

✓ प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य ३९२-४१६

प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्त्व ३९२, भारतीय शिक्षा के  
 प्रमुख आदर्श ३९४, भारतीय शिक्षा के उद्देश्य ४१३, अभ्यामार्थ  
 प्रश्न ४१६ ।

## अध्याय १

### प्राथमिक शिक्षा का इतिहास

भारतवर्ष की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान क्योंकि यह स्तर ही आधुनिक शिक्षा का आधार होता है। स्वतन्त्रता के बाद भारतीय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को प्रजातन्त्र की सफलता के निम्न आवश्यक मानकर इस पर की ओर विशेष ध्यान दिया है। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने में पूर्व अपने देश की प्राथमिक शिक्षा के इतिहास का जवाबदेही बनाना अति आवश्यक है।

भारतवर्ष में शिक्षा का इतिहास २५०० ई० पू० में १७५७ ई० तक तीन मुख्य भागों में विभक्त करके अध्ययन किया जाता है। ये प्रमुख काल निम्न-वर्णित हैं

१. वैदिक युग— २५०० ई० पू० में ५०० ई० पू० तक।
२. बौद्ध युग— ५०० ई० पू० में १२०० ई० तक।
३. मुस्लिम युग— १२०० ई० में १७५७ ई० तक।
४. ब्रिटिश युग।

इन युगों में वर्तमान कक्षा व्यवस्था के समान कक्षाएँ नहीं चलती थी। वैदिक काल में गुरुकुल-आश्रम के छात्र बालावरण में छात्र अध्ययन किया करते थे। उस समय का पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि आज की शिक्षण विधियों में भिन्न थी। बौद्ध तथा मुस्लिम युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म-प्रचार था। यही ब्रिटिश युग में प्राथमिक शिक्षा के इतिहास का विस्तृत वर्णन दिया जायेगा।

#### १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में देशी शिक्षा

जिस समय अंग्रेज भारत में पधारे उस समय हमारे देश में देशी शिक्षा का विस्तार स्पष्ट था। इन देशी विद्यालयों का देश में जाल-जाल बिछा हुआ था। इन विद्यालयों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता था—प्रथम, उच्च शिक्षा के

विद्यालय और द्वितीय, तृतीयक विद्यालय। उच्च विद्यालयों की संख्या देश में बहुत कम थी और ये जनसाधारण की शिक्षा के माधन नहीं थे। दूसरी और तृतीयक विद्यालय जो कि जनसाधारण की शिक्षा देने के एक महत्वपूर्ण माधन थे, की संख्या अधिक थी। देशी शिक्षा के मजदूर के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाएँ थीं

(१) गुरु गृह—इस युग में भी ब्राह्मण अपने घरों में छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे।

(२) संस्कृत विद्यालय—ये विद्यालय दान के सहारे चलते थे।

(३) संस्कृत प्रत्येक मस्जिद के साथ एक मक़तब छात्रों के अध्ययन के लिए होता था।

इन देशी विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नता, पढ़ना तथा गणित सिखाया जाता था। इनके अनिश्चित कुछ धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। भार वर्त में छ वर्ष की आयु के बालकों को इन शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता था। जब पाठे मर बालक किसी विद्यालय में प्रवेश ले सकता था तथा दशानुसार उसको छोड़ भी सकता था। एक-सिधकीय संस्थानों अधिक चलती थी। अध्यापकों को प्रतिदिन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः कुशल अध्यापक कम ही संस्था में प्राप्त होते थे। उन दिनों में विद्यालयों की दृष्टि में भवन-निर्माण नहीं हुए थे। प्रायः ये विद्यालय गाँव के मन्दिर, सिधक-मक़ान या मस्जिद में चला करते थे।

### देशी शिक्षा की जीव

जब ईस्ट इण्डिया कंपनी का शासन भारत के कुछ भागों में स्थापित हो गया तो अंग्रेज पदाधिकारियों ने शिक्षा के विस्तार का पता लगाने के लिए सन् १८०० में सन् १८४२ के मध्य देशी विद्यालयों का सर्वेक्षण करवाया। जीव के दोष मद्रास गंगाल तथा बम्बई थे।

मद्रास—मद्रास में देशी शिक्षा में सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य मर धामस मुन ने किया था। उसकी जीव के आधार पर पता चलता है कि उस समय मद्रास में १२,४६८ देशी विद्यालय थे। स्त्री शिक्षा का प्रसार नहीं के बराबर था। जीव बाद मुग़लों ने स्वीकार किया कि शिक्षा का प्रतिपात हमारे देश इंग्लैंड में कम हुआ भी योरोप के अनेक देशों में कहीं अधिक है।

बम्बई—इस प्रान्त के तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन ने १० मार्च, १८२२ बम्बई प्रान्त की देशी शिक्षा की जीव करवाई। यह जीव-मक़ान संस्था की सहायता में सम्पन्न हुआ। इनके प्रतिवेदन के आधार पर उस समय ४६,८१,७३५ जनसंख्या की ज़ियमें में ३५,१५३ छात्र और १०५ प्रान्त में १,७०५ देशी विद्यालय थे। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय में १५ छात्र अध्ययन करते थे।



बंगाल—बंगाल प्रान्त में देशी शिक्षा की जांच का कार्य विनियम एडम ने किया। पांच जिलों का सर्वेक्षण करने के बाद रिपोर्ट में बताया कि इन जिलों में २,५६७ विद्यालय थे।

देशी पाठशालाओं ने जनसाधारण में शिक्षा-प्रसार करने में बड़ा योग दिया। अस्तु अंग्रेज साम्राज्य की नींव हड़ होने में देशी विद्यालयों की प्रगति अवहट्ट हो गई।

### देशी शिक्षा की अवनति के कारण

देशी शिक्षा की अवनति के निम्नलिखित कारण थे

(१) अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाने पर अंग्रेजों को प्रशासन में महायत्ना देने के लिए अंग्रेजी भाषा जानने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। अतः अंग्रेजी का अध्ययन करने में राजपद प्राप्त करने में सरलता होती थी। परिणामतः शासनवासी अपने बच्चों को देशी विद्यालयों की अपेक्षा अंग्रेजी विद्यालयों में भेजना अधिक उपयुक्त समझते थे।

(२) अंग्रेजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा के साथ ही साथ पाठ्य-पुस्तकों आदि की सुविधा भी प्रदान की जाती थी। अतः निर्धन शासनवासी अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकर्षित हुए।

(३) देशी विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों को अल्प वेतन मिलता था अतः योग्य व्यक्ति इन देशी पाठशालाओं में कार्य करना पसन्द नहीं करते थे।

(४) अंग्रेजों के आने से पूर्व देशी शिक्षा समस्याओं को देशी रियासतों का संरक्षण प्राप्त था। अंग्रेजों ने इन रियासतों का अस्तित्व समाप्त कर दिया। परिणाम-स्वरूप इन विद्यालयों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बन्द हो गई।

(५) अंग्रेजी शिक्षा में अधिक लाभ देखने हुए अंग्रेजों ने देशी शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा को अधिक प्रोत्साहित किया।

### ईसाई पादरियों की चेष्टाएँ

यूरोपीय जानियों के आगमन के समय ही, ईसाई पादरी भी भारत आए। आरम्भ में इनका मुख्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। धर्म-प्रचार का सबसे उत्तम साधन प्राथमिक शिक्षा को माना गया। अतः आरम्भ में अनेक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये तथा प्रत्येक को ईसाई मण्डलों के केन्द्र के साथ जोड़ दिया गया। इन ईसाई मण्डलों ने इस देश में शिक्षा व्यवस्था को नया रूप देकर भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नवीनता ला दी। ईसाई स्कूलों की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

१. धर्म शिक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी और बाइबिल पाठ्य-पुस्तक की भाँति प्रयोग में लाई जाती थी।
२. इन विद्यालयों में प्रयुक्त पाठ्यक्रम विस्तृत था। पाठ्यक्रम में व्याकरण, भूगोल, इतिहास आदि विषयों को सम्मिलित किया गया।

भारतीय शिक्षा की सामायक -

भारतीय शिक्षा

प्राचीन हिन्दू पाठ्य-पुस्तकें प्रयोग में लाई जाती थी ।  
 कक्षाएँ नियमित रूप में लगती थी । रविवार को छुट्टी का दिन घोषित किया ।  
 शिक्षा-प्रथा को जन्म दिया ।  
 प्राचीन भारत में शिक्षा दो जाती थी ।  
 प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रति उच्च पर उमने

कथा-प्रथा को जन्म दिया ।  
कथा-प्रथा को जन्म दिया ।

इन्होंने कथा-प्रथा को जन्म दिया ।  
मानु-भाषा के माध्यम में शिक्षा दी जाती थी ।  
इन्होंने पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में  
आज-काल के राज-न्याय के सिद्धांत की शिक्षा

इन्होंने कथा-प्रथा को जन्म दिया।  
मानु-भाषा के माध्यम में शिक्षा दी जाती थी।  
१८६३ में पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में शिक्षा के आधार पर उमन अ  
कम्पनी ने मनु १९६८ के आज्ञा-ग्रन्थ के आधार पर अनेक स्कूलों की  
क केन्द्रों के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए अनेक स्कूलों की  
की। उसके उपरान्त ही मनु १७१५ में प्रथम प्रान्त में, मनु १७१६ में  
और मनु १७३१ में कलकत्ता में प्रथम विद्यालयों की स्थापना हुई। ये  
में अनेक बच्चों तथा भारतीय ईसाइयों के बच्चों को प्रवेश देने  
की शक्ति और भारतीयों को आर्कापित करने के लिए भारतीय

की। उसके उपरान्त कलकत्ता में  
और मई १७३१ में कलकत्ता में  
प्रमुख रूप में अंग्रेज बच्चों तथा भारतीयों को जर्जरित करने के  
रतबर्ग में ईसाई धर्म की ओर भारतीयों को जर्जरित करने के  
रतबर्गों को धानवृत्तियों की ओर आर्षिक नया राजनीतिक स्थिति भारतवर्ष  
में अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नया अधिकार स्थापित हो गया। जन  
रतबर्गों को धानवृत्तियों की ओर आर्षिक नया अधिकार स्थापित हो गया। जन

[illegible][illegible]

कमबला मरता था।  
उप बनेन होस्टल ने बनवाता है न  
की स्थापना में होस्टल भारतीय युवकमानों की प्रेरणा  
मान सब न्याय-विभाग के लिए योग्य शिक्षित युवकमानों से  
मद में कामगी ने इस विद्यालय का अपने प्रशासन में ले दिया।  
बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में १९६१ में बनारस के तत्कालीन  
प्रेसिडेंट ब्रजबाल शर्मा ने बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य के सम्बन्ध में  
'सुभा' के लिए पत्र लिखा था 'एक एक विद्यार्थी को स्थापना के उद्देश्य के दो प्रमुख पत्र  
१. प्रथम पत्र कि हिन्दू श्रेष्ठ समाज में प्रेम करने लगे हुए, एक  
२. भी भारतीय प्रजातन्त्र की रक्षा हो सकेगी तथा सामाजिकता के महामंद

इन कालेजा की स्थापना तथा बाद में कम्पनी का संरक्षण प्राप्त होने में है कि कम्पनी अपनी तटस्थता की नीति को अधिक समय तक स्थिर न रखे। ईसाई मण्डलों को धार्मिक प्रचार तथा शिक्षा-प्रसार के लिए कम्पनी की ओर लने वाला प्रोत्साहन बन्द हो गया।

१८१३ से सन् १८५४ तक

ईस्ट इण्डिया कम्पनी शिक्षा के सम्बन्ध में तटस्थता की नीति को सम्ये तक स्थिर न रख सकी। सन् १८१३ के आजा-यत्र के अनुसार शिक्षा को का एक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य स्वीकार किया गया तथा मुझव दिया कि प्रति शिक्षा पर एक लाख रुपये व्यय किये जायें। आजा-यत्र में शिक्षा की नीति के म्ध में लिखा है—

“ प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपया अलग रखा जायेगा और यह धन भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन, साहित्य के विकास और पुनरुत्थान के लिए तथा ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिकों में विज्ञान के प्रसार के लिए व्यय किया जायेगा।”<sup>१</sup>

इस आजा-यत्र का प्रमुख दोष यह था कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि धनराशि को किस प्रकार व्यय किया जाय। परिणामतः यह धन कार्य में नहीं गया। सन् १८१३ के आजा-यत्र के उपरान्त भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में कुछ तब उत्थान हो गये और वे बहुत दिनों तक चलते रहे। विवाद के प्रमुख विषय न थे

१. उद्देश्य—शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या हो ? यह प्रश्न अधिक तद्वस्त रहा। कुछ लोगों का विचार था कि जनसाधारण को शिक्षा की हेतना करके उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय। दूसरा समुदाय चाहता था जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाय।

२. माध्यम—शिक्षा का माध्यम निर्दिष्ट करने के लिए भी विद्वान् एक मत थे। एक वर्ग इन बात का पक्षपाती था कि प्राच्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षा जाय। दूसरा वर्ग कहता था कि शिक्षा का माध्यम आधुनिक भारतीय भाषाएँ हैं। तीसरा मत यह था कि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाय।

“ A sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India ” (Based on Nurullah & Naik)

३. साधन (Agencies)—शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व सरकार का हो या व्यक्तिगत प्रयत्नो पर छोड़ दिया जाय।

४ लक्ष्य—विवाद का चौथा विषय था कि प्राचीन साहित्य तथा विज्ञान को या पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानों को पाठ्य विषय बनाया जाय। उपर्युक्त विवादग्रस्त विषयों के आधार पर भारत में दो दलों का जन्म हुआ।

(१) प्राच्य शिक्षावादी (Orientalists)—इस समुदाय के व्यक्ति मस्कृत, अरबी और फारसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। ये लोग प्राच्य विद्या के पक्षपाती थे।

(२) पाश्चात्य शिक्षावादी (Occidentalists)—इन लोगों का मन था कि भारतवासियों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी भाषा के माध्यम में दी जाय। राजा राममोहन राय भी इसी मन के समर्थक थे। प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा विवाद को समाप्त करने के लिए गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लार्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। लार्ड मैकाले ने अपना विवरण-पत्र २ फरवरी, सन् १८३५ को प्रस्तुत किया। उसने पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान के अध्ययन का मुद्दा दिया। वह अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का पक्षपाती था। उसने भारतीय भाषाओं को साहित्य की दृष्टि से बड़ा निर्धन बताया। ऐसा प्रतीत होता है कि लार्ड मैकाले ने यहाँ की भाषाओं के साहित्य का अध्ययन किये बिना ही ऐसा मुद्दा दिया। लार्ड मैकाले ने कहा कि "हम भारत में ऐसे व्यक्तियों के वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं जो राग और रक्त में भरे ही भारतीय हों, परन्तु खान-दान, रहन-सहन, आचार-विचार तथा बुद्धि में पूरे अंग्रेज रहें।"

बेंटिक ने सन् १८३५ के मैकाले के आज्ञा-पत्र की सभी बातें स्वीकार कर ली। मैकाले ने ही निस्पन्दन मिडान्त (Downward Filtration) को जन्म दिया। इस मिडान्त के अनुसार उच्च वर्ग को ही शिक्षा प्रदान की जाय तथा यह जाता की जाय कि उच्चवर्ग से शिक्षा स्वतः निम्न वर्ग तक पहुँच जायेगी। आकर्षण ने भी इस मिडान्त को सरकारी नीति का रूप दे दिया। फलस्वरूप, जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करने के कर्तव्य में अपने को विमुक्त कर लिया। परन्तु इस मिडान्त का कोई सामग्रद फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पढ़े-लिखे उच्चवर्ग के लोग दिन प्रतिदिन माधारण जनता में दूर जाने लगे। लार्ड मैकाले के मुद्दा का प्रभाव आज हम अपने देश में प्रत्यक्ष देख सकते हैं—

१ भारतवर्ष में पहले में ही चले जा रहे वर्ग-विभेद को प्रोत्साहन मिला। अंग्रेजों ने शिक्षा को उच्चवर्ग तक ही सीमित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि निम्न वर्ग अशिक्षित हो रहा। आज भी भारतवर्ष की लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है।

२. अंग्रेजी साहित्य तथा आमत भाषा के अध्ययन में हम माँग अपनी सस्कृति तथा भाषाओं को भूल बैठे। आमत भाषा के शिक्षा का माध्यम होने में भारतीय भाषाएँ साहित्य तथा शब्दकोष की दृष्टि से मजबूत नहीं हो सकी। इसका ही परिणाम यह है कि आज भाषा सम्बन्धी समस्या किन्ना उच्च रूप धारण किये हुए है।

३. हमारे देश की परम्परागत शिक्षा-पद्धति मल्टि-अप्ट कर दी गई।

### बुड का घोषणा-पत्र

१६ जुलाई, सन् १८५८ में कम्पनी के सचिवों ने बुड का घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। चार्ल्स बुड उस समय 'बोर्ड आफ कन्ट्रोल' का प्रधान था, अतः उसके नाम पर ही इसका नामकरण बुड का घोषणा-पत्र हुआ। यह घोषणा-पत्र लगभग १०० अनुच्छेदों का है। घोषणा-पत्र में सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षा का प्रसार करना कम्पनी का कर्तव्य है।

“बहुत से प्रमुख विषयों में शिक्षा में बढ़कर हमारी दृष्टि को आकर्षित करने वाला अन्य कोई विषय नहीं है। यह तो हमारे पुनीत कर्तव्यों में से एक है।”<sup>१</sup>

### घोषणा-पत्र की प्रमुख सिफारिशें

१. शिक्षा का उद्देश्य—घोषणा-पत्र में शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा गया कि शिक्षा द्वारा भारतीयों की बौद्धिक एवं चार्ित्रिक उन्नति करने के माध्यम ही ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना या जो राज्य की सुरक्षा बना सकें और राजपदों पर विश्वास के साथ नियुक्त किये जा सकें।

२. पाठ्यक्रम—मल्लत और अरबी भाषा की महत्ता को स्वीकार करते हुए उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। परन्तु पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों को भारतीयों के लिए उपयोगी माना गया।

३. माध्यम—अंग्रेजी तथा प्राच्य भाषाओं को माध्यम बनाने का सुझाव दिया। जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्राच्य भाषाओं को उपयुक्त माना गया। इसमें लिखा गया कि “हम अंग्रेजी तथा प्राच्य दोनों ही प्रकार की भाषाओं की शिक्षा के माध्यम के रूप में देखते हैं” “अतः हमारी अभिनाया है कि भारत के समस्त विद्यालयों में उन्हें साथ-साथ फैलने-फूलने देने।”<sup>२</sup>

1. “Among many subjects of importance, none can have a stronger claim to our attention than that of education. It is one of our most sacred duties” —Wood's Despatch
2. We look, therefore, to the English language and to the Vernacular languages of India together as the media. ... and it is our desire to see them cultivated together in all schools in India.” —Wood's Despatch

४. प्रथम चरम विद्यालयों की स्थापना — शिक्षा मण्डल का मुद्दा रूप में जाने के लिए प्रथम चरम विद्यालयों की स्थापना का मुद्दा दिया। उनके अनुसार प्राथमिक विद्यालय के गणनाई मिडिल स्कूल, फिर हाईस्कूल और अन्य में कठिन या अंतरविद्यालय हो।

५. जन-शिक्षा विभाग — प्रत्येक प्रान्त में जन-शिक्षा विभाग की स्थापना की गिरफ्तारी की गई। इसका प्रधान जन-शिक्षा सचिव नियुक्त किया जाय। उनकी सहायता के लिए निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक रखे जायें।

६. जन-शिक्षा प्रसार — बुद्ध ने मंत्रालय के निम्नलिखित मिशन की आज्ञा देना चाहिए। इस कार्य के लिए प्राथमिक विद्यालयों तथा मिडिल स्कूलों की सहायता में वृद्धि करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त घोषणा-पत्र में सहायता, अनुदान, अध्यापकों का प्रशिक्षण प्राथमिक भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन आदि के सम्बन्ध में उपयोगी मुद्दा दिए गये।

बुद्ध के शिक्षा-घोषणा-पत्र का एक प्रमुख दोष यह है कि इसने प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य बनाने के सम्बन्ध में कोई ठोस मुद्दा नहीं दिया।

सन् १८५४ से सन् १८८२ तक प्राथमिक शिक्षा का विकास

सन् १८५७ में राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हो जाने में बुद्ध के घोषणा-पत्र की सिफारिशों कार्यान्वित नहीं की जा सकी। इस स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद कम्पनी का शासन समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह भारतीय शासन की बागडोर पार्लियामेंट के हाथ में पहुँच गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बागडोर हाथ में लेने के बाद स्टैनले की नियुक्ति भाग्य मंत्री नामक नवीन पद पर की। सन् १८५६ में स्टैनले ने एक नवीन आज्ञा-पत्र प्रकाशित किया। इस आज्ञा-पत्र में स्टैनले ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मुद्दा दिए

१. प्रथम मुद्दा यह दिया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार करे तथा उसका प्रबन्ध स्थानीय सस्थाओं के हाथ में दिया जाय।
२. प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए धनभाव की स्थिति में सरकार के स्थानीय कर लगाना चाहिये। इसकी शिक्षा-कर का नाम दिया।
३. सहायता अनुदान प्रणाली को उच्च शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित रखा जाय।
४. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये जायें।

इसके द्वारा बताया गई अनुदान प्रणाली का एक दोष यह था कि गाँवों से वसूल किया गया पैसा सहरो में खर्च किया जाता था। सन् १८७१ में सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल कर अनुदान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए मुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय कर तथा केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलना चाहिए। सन् १८७१ में भारतवर्ष में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या १६,४७३ थी जिनमें ६,०७,३२० छात्र अध्ययन करते थे। सन् १८८२ में विद्यालयों की संख्या बढ़ कर ८२,६१६ हो गई और पढ़ने वाले छात्रों की संख्या २०,६१,५४१ तक पहुँच गई। सन् १८८२ में भारत में साक्षरता का प्रतिशत १.२ था जबकि उसी वर्ष दक्षिण में प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क थी।

### सन् १८८२ का शिक्षा आयोग

३ फरवरी सन् १८८२ को लार्ड रिपन ने गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य सर विनियम हन्टर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग को 'हन्टर कमिशन' के नाम से भी पुकारते हैं।

### कार्य-क्षेत्र एवं उद्देश्य

१. भारत में प्राथमिक शिक्षा की जाँच करके यह पता लगाना कि प्राथमिक शिक्षा की क्या वृद्धि है। उसके विकास के लिए उपाय बताना।
२. मिशन स्कूलों का क्या स्थान है।
३. सरकार की महायत्ना अनुदान प्रणाली की समीक्षा करना।
४. भारत में राजकीय विद्यालयों की आवश्यकता का पता लगाना।

### सुझाव

प्राथमिक शिक्षा की नीति—(१) प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए।

(२) प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ रहनी चाहिए।

(३) सरकार को पिछड़ी जाति एवं आदिवासियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए।

(४) प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावहारिक विषयों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया।

प्राथमिक शिक्षा का संगठन—दक्षिण में सन् १८७६ के शिक्षा-अधिनियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध 'बाउण्टी काउन्सिल' को सौंप दिया गया था। लार्ड रिपन भारतवर्ष में दक्षिण के इस संगठन को खाना चाहता था। उसने भारत में नगरपालिकाओं और जिला परिषदों का निर्माण करवाया। प्राथमिक शिक्षा का भार, व्यवस्था, व्यय, निरीक्षण आदि सभी स्थानीय संस्थाओं को दिया गया।





प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ६२,६०४ थी परन्तु १९१० में यह बढ़ कर १,१८,२६२ तक पहुँच गई ।

- लार्ड कर्जन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा रखना चाहता था ।
- ३. प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि, दारिद्र्यक व्यायाम को सम्मिलित किया जाय ।
- ४. पाठ्यक्रम का सम्बन्ध स्थानीय वातावरण में होना चाहिए । इसीलिए उसमें ग्रामीण और शहरी प्राथमिक शिक्षा में अन्तर रखने का सुझाव दिया ।
- ५. अध्यापकों के प्रशिक्षण की अवधि २ वर्ष की करने तथा उनके पाठ्यक्रम में कृषि को स्थान दिव्य जाने की महत्त्वपूर्ण सिफारिश कर्जन ने की ।
- ६. परीक्षाफल के अनुसार महायत्ना अनुदान को समाप्त करके शिक्षकों की योग्यता, विद्यालयों की कार्यक्षमता और छात्रों की संख्या आदि के आधार पर महायत्ना देने की प्रणाली प्रचलित की ।

सन् १९०५ में लार्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा किये जाने पर भारतवर्ष में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ । लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति का तीव्र विरोध किया गया । भारतीय जनता द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की माँग की गई । इसी समय श्री गोपान कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क बनाने की चेष्टा की । १९ मार्च, सन् १९१० को गोखले ने इस सम्बन्ध में इम्पीरियल काउन्सिल में एक प्रस्ताव भी रखा । परन्तु उनको इस क्षेत्र में सफलता न मिल सकी । सन् १९१६ में श्री बिठ्ठल भाई पटेल ने बम्बई की विधान सभा में अनिवार्य शिक्षा विधेयक पारित करवाया ।

### सन् १९२१ से १९३७ का 'द्वैध शासन'

१९१७ ई० में भारत के मंत्री श्री माटेमू और वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने भारत का भ्रमण किया । माटेमू तथा चेम्सफोर्ड ने १९१८ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीयों को थोड़ी मात्रा में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन प्रदान किया जाय । इसके सुझाव के आधार पर ही सन् १९२१ में द्वैध शासन की स्थापना हुई । इसके अन्तर्गत प्रान्तों के विषयों को दो भागों में विभाजित किया—

१. सुरक्षित (Reserved),
२. हस्तान्तरित (Transferred) ।

शिक्षा हस्तान्तरित विषय होने के कारण इसका उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ गया । परन्तु भारतीय मंत्रियों को अपने कार्य में सफलता न मिल सकी

क्योंकि वित्त विभाग अग्रेजों पर था तथा प्रशामन कर्मचारी वर्ग पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था।

**हर्टोग समिति**— सन् १९२६ में साइमन कमीशन ने मर फिनिप हर्टोग की अध्यक्षता में एक महायुक्त समिति का निर्माण भारतीय शिक्षा की जाँच करने के लिए किया। हर्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास का मुद्दा दिया। इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा अपेक्ष्य एवं अवरोधन की ओर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ अन्य मुद्दाय ये हैं

- १ शिक्षण व्यवसाय को आकर्षित बनाने के लिए अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाय।
- २ प्राथमिक शिक्षा की अवधि कम में कम चार वर्ष हो।
- ३ विद्यालयों का निरीक्षण ठीक प्रकार में करने के लिए निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय।
- ४ अनिवार्य शिक्षा को एकदम लागू न किया जाय।
- ५ प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को आ हाथ में लेना चाहिए।

**सन् १९३७ से १९४७ तक प्रान्तीय स्वशासन**

सन् १९३७ में ११ प्रान्तों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करके प्रान्तीय स्वशासन की नींव रखी गई। समस्त प्रान्तीय विषय लोकप्रिय भारतीय मंत्रियों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रविष्ट कर दिये गये। इन ११ प्रान्तों में से ७ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की स्थापना हुई। इसी समय १९३७ में गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा का सूत्रपात किया। इस योजना में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ होने से भारतीय मंत्रियों का उत्साह ढीला पड़ गया।

विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सरकार द्वारा बनाई गई युद्धोत्तर विकास की अनेक योजनाओं में शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए तत्कालीन भारतीय शिक्षा मन्त्रालय मर जॉन सार्जेंट को एक स्मृति-पत्र तैयार करने के लिए कहा गया। सार्जेंट ने सन् १९४४ में अपना स्मृति-पत्र केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। इसको सार्जेंट योजना के नाम से पुकारते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए ठोस मुद्दाय दिये गये हैं जोकि निम्नलिखित हैं

१. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

(अ) पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ३ से ६ वर्ष की आयु के बालकों के लिए की जाय।

- (ब) यह शिक्षा नि शुल्क प्रदान की जाय ।
- (ग) इस स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य बालको को सामाजिक शिष्टाचार सिखाना होना चाहिये ।
- (द) प्रशिक्षित अध्यापिकाएँ इन विद्यालयों में रखी जायें ।

## २. प्राथमिक शिक्षा

(क) ६ से १४ वर्ष की आयु के बालको के लिए नि शुल्क अनिवार्य शिक्षा हो जिसका हर बुनियादी शिक्षा होना चाहिये ।

(ख) अधिक संख्या में उपस्थिति-अधिकारी (Attendance officers) निरीक्षण करने के लिए रने जायें ।

(ग) बुनियादी शिक्षा को जूनियर बेमिक तथा सीनियर बेमिक दो भागों में बाँटा गया ।

(घ) मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाने का मुझाव दिया ।

(ङ) प्रशिक्षित अध्यापको को नियुक्ति पर विरोध बन दिया ।

## योजना की समीक्षा

के० जी० मँयदन ने हम योजना को अधिक महत्वपूर्ण बताया है । उन्होंने हमको राष्ट्रीय शिक्षा की विस्तृत योजना कह कर पुकारा है ।

श्री एम० एन० मुकजी ने योजना के सम्बन्ध में कहा है कि “यह योजना भारतीय शिक्षा व्यवस्था के दोषों की ओर ही लक्ष्य नहीं करती, बल्कि उस में सुधार के उपायों पर भी प्रकाश डालती है ।”

हम योजना का एक दोष यह है कि हममें शारीरिक शिक्षा की पूर्ण अवहेलना की गई है । नूरुल्लाह और नायक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यह योजना प्राप्त किये जाने वाले आदर्शों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है परन्तु शिक्षा विकास की योजना पर प्रकाश नहीं डालती है ।<sup>१</sup>

## स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास

सन् १९४७ में भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ । भारतवासियों के हान्य में देश की बागडोर आने पर नवीन उत्साह उत्पन्न हुआ । देश का बहुमुखी विकास करने का स्वप्न पूरा करने की भारतीयों ने क्षप्य ली । भारतीय नेताओं ने शिक्षा के महत्त्व को समझा तथा शिक्षा के प्रसार के लिए कार्यक्रम तैयार किये गये । प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन हम निम्नलिखित तालिका में कर सकते हैं

1. “It is pointed out that the scheme merely describes the ideal to be reached and does not give a detailed programme of development”—Nurrullah and Naik

प्राथमिक शिक्षा की प्रगति

वर्ष	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या	प्राथमिक शिक्षा पर खर्च (रुपये में)	प्राथमिक विद्यालयों में प्रति छात्र खर्च (रुपये)
१९४६-४७	१३७९९	१३,०३६,०४०	१०६,८६६,३०३	१६७
१९४७-४८	१४,०३६	१६,०००,८९९	१०३,६३०,००३	२६१
१९४८-४९	१४,०३६	१६,०००,८९९	१०३,६३०,००३	२६१
१९४९-५०	१४,०३६	१६,०००,८९९	१०३,६३०,००३	२६१

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतवर्ष में प्राथमिक विद्यालय तथा उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। गणराज्य में प्राथमिक शिक्षा पर वर्ष १९४९-५० की अपेक्षा वर्ष १९६०-६१ में लगभग ३३ करोड़ रुपये अधिक व्यय किया। छात्रों की संख्या में वृद्धि से स्पष्ट है कि भारत के जनसाधारण में शिक्षा व प्रति व्यक्ति प्रवेश की अभिवृद्धि का निर्माण हुआ है।

प्रबन्ध भारतावध में प्राथमिक विद्यालयों का प्रबन्ध तीन स्तरों के द्वारा है (१) प्रांतीय सरकार, (२) स्थानीय संस्थान, और (३) व्यक्तिगत प्रबन्ध मण्डल। प्रजातन्त्रीय प्रशासनिक ढांचा होने के कारण प्राथमिक विद्यालयों का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं को दिया जा रहा है जिससे कि प्रशासन का विवेकशीलता हो सके।

प्रबन्ध के अनुसार प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	राजकीय	जिला परिषद	नगर-पालिका	व्यक्तिगत संस्थाएं, महापौरा, प्रांत	योग
१९४६-४७	४६,६०२	३८,८३६	७,६६०	६७,५६१	१०४,८२६
१९४७-४८	४६,२६०	३८,८३६	६,९५७	६७,५५७	१०४,६१०
१९६०-६१	७३,५६६	३८,८३६	६,७६१	६६,२०७	१८५,३७०

राजस्थान प्रांत में प्रबन्ध के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का विभाजन इस प्रकार था (वर्ष १९६०-६१ के अनुसार)

राजकीय विद्यालय	जिला परिषद	नगरपालिका	व्यक्तिगत प्रबन्ध	योग
१,१२५	१३,०४६	१७	३२२	१४,५४८

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि राजस्थान में जिला परिषदों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय अधिक चलाये जा रहे हैं। गाँवों के प्राथमिक विद्यालयों का प्रबन्ध पंचायत

समितियों को मौज दिया गया है। राजस्थान में लगभग १३८५ जनसंख्या के पीछे एक प्राथमिक विद्यालय है तथा औसतन एक प्राथमिक विद्यालय में ६१ बच्चों का प्रवेश है। एक प्राथमिक विद्यालय में औसतन ६१ वर्ष की मीन क्षेत्र के बालक अध्ययन करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में २८ वर्ष की मीन क्षेत्र में एक विद्यालय है। इसमें जाना होता है कि राजस्थान में अभी और विद्यालयों की आवश्यकता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर शिक्षा समिति या आयोग नियुक्त किये गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए एक परिपद की भी स्थापना की है।

अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद्—इस परिषद् की स्थापना १ जुलाई, १९५७ को की गई। इस परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

- १ प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजना बनाना।
- २ केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को परामर्श देना।
- ३ प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का सर्वेक्षण करना।
- ४ प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम तथा साहित्य तैयार करना।
- ५ अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहन देना।

इस परिषद् के २३ सदस्य होंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा मन् १९६६ में शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं पर विचार करने तथा सुझाव देने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर दोनार्सह कोठारी, अध्यक्ष, विद्वद्विद्यालय अनुदान आयोग थे। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव दिये।

१. मन् १९७५-७६ तक ५ वर्ष की प्रभावपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हर बालक के लिए हो।
२. मन् १९८५-८६ तक ७ वर्ष की शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए हो।
३. प्रत्येक प्रान्त को प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजनाएँ बनानी चाहिए।
४. कक्षा १ में ७ तक अवधाय को कम किया जाय।
५. प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा किया जाय। कुछ विषयों में सम्बन्धित सूचनाएँ प्रदान करना ही इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि इसका उद्देश्य देश के लिए एक उपयोगी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण युवक तैयार करना होना चाहिए।
६. (अ) एक वर्ष की मीन क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए।  
(ब) निश्चित आयु होने पर बालक का प्रवेश पहली कक्षा में प्रचार, परामर्श या कानूनी महामना के द्वारा अवश्य होना चाहिए।  
(ग) स्वीकृत आयु तक पहुँचने तक छात्र को विद्यालय में रोकना जाय।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ

3. 1945년 12월 1일
1. 1945년 12월 1일
2. 1945년 12월 1일
3. 1945년 12월 1일
4. 1945년 12월 1일
5. 1945년 12월 1일
6. 1945년 12월 1일
7. 1945년 12월 1일
8. 1945년 12월 1일
9. 1945년 12월 1일
10. 1945년 12월 1일
11. 1945년 12월 1일
12. 1945년 12월 1일
13. 1945년 12월 1일
14. 1945년 12월 1일
15. 1945년 12월 1일
16. 1945년 12월 1일
17. 1945년 12월 1일
18. 1945년 12월 1일
19. 1945년 12월 1일
20. 1945년 12월 1일
21. 1945년 12월 1일
22. 1945년 12월 1일
23. 1945년 12월 1일
24. 1945년 12월 1일
25. 1945년 12월 1일
26. 1945년 12월 1일
27. 1945년 12월 1일
28. 1945년 12월 1일
29. 1945년 12월 1일
30. 1945년 12월 1일
31. 1945년 12월 1일
32. 1945년 12월 1일
33. 1945년 12월 1일
34. 1945년 12월 1일
35. 1945년 12월 1일
36. 1945년 12월 1일
37. 1945년 12월 1일
38. 1945년 12월 1일
39. 1945년 12월 1일
40. 1945년 12월 1일
41. 1945년 12월 1일
42. 1945년 12월 1일
43. 1945년 12월 1일
44. 1945년 12월 1일
45. 1945년 12월 1일
46. 1945년 12월 1일
47. 1945년 12월 1일
48. 1945년 12월 1일
49. 1945년 12월 1일
50. 1945년 12월 1일
51. 1945년 12월 1일
52. 1945년 12월 1일
53. 1945년 12월 1일
54. 1945년 12월 1일
55. 1945년 12월 1일
56. 1945년 12월 1일
57. 1945년 12월 1일
58. 1945년 12월 1일
59. 1945년 12월 1일
60. 1945년 12월 1일
61. 1945년 12월 1일
62. 1945년 12월 1일
63. 1945년 12월 1일
64. 1945년 12월 1일
65. 1945년 12월 1일
66. 1945년 12월 1일
67. 1945년 12월 1일
68. 1945년 12월 1일
69. 1945년 12월 1일
70. 1945년 12월 1일
71. 1945년 12월 1일
72. 1945년 12월 1일
73. 1945년 12월 1일
74. 1945년 12월 1일
75. 1945년 12월 1일
76. 1945년 12월 1일
77. 1945년 12월 1일
78. 1945년 12월 1일
79. 1945년 12월 1일
80. 1945년 12월 1일
81. 1945년 12월 1일
82. 1945년 12월 1일
83. 1945년 12월 1일
84. 1945년 12월 1일
85. 1945년 12월 1일
86. 1945년 12월 1일
87. 1945년 12월 1일
88. 1945년 12월 1일
89. 1945년 12월 1일
90. 1945년 12월 1일
91. 1945년 12월 1일
92. 1945년 12월 1일
93. 1945년 12월 1일
94. 1945년 12월 1일
95. 1945년 12월 1일
96. 1945년 12월 1일
97. 1945년 12월 1일
98. 1945년 12월 1일
99. 1945년 12월 1일
100. 1945년 12월 1일

## अध्याय २

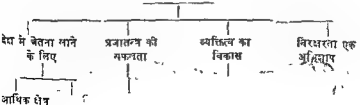
### भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

सन् १९४७ में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात्, प्रजातन्त्रात्मक मूल्य प्रणाली अन्तर्गत का निश्चय किया गया। प्रजातन्त्रीय देश में बालक को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। अतः आवश्यकता यह रहती है कि प्रत्येक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग मोक्ष-सुमार्ग कर करे जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को चुनकर जा जाय जो उस पक्ष के लिए योग्य हों। यही कारण है कि आज शिक्षा प्रसार में महत्त्व पहले की अपेक्षा अधिक अनुभव किया जाने लगा है। इसी विचार में रित होकर यहाँ के नेताओं ने मविधान में भी सार्वभौमिक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया है।

#### अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता

आज भारत का प्रत्येक शिक्षाभास्त्री शिक्षा को अनिवार्य करने का मुद्दा पता है। अतः यहाँ अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता पर विचार करना उपयुक्त होगा। भारतवर्ष में शिक्षा को अनिवार्य करना निम्नलिखित दृष्टियों से आवश्यक है -

#### अनिवार्य शिक्षा



(१) देश में जेना लाने के लिए— शिक्षा एक ऐसा माध्यन है जो कि देश में नवीन जागृति एवं जेना लाने में अधिक सहयोग देता है। भारतवर्ष जो वषों तक विदेशियों का परगचीन रहा, धीरे-धीरे सामाजिक बुराद्वों का घर बनता गया एवं अधिक दृष्टि में इसकी दशा घोरनीय होती गई। स्वतन्त्र भारत को विद्व के अन्य विकासशील देशों की धँषी में लाने के लिए यहाँ सामाजिक प्रान्ति तथा अधिक विराम की आवश्यकता है। भारत प्राकृतिक खोन की दृष्टि में धनी है परन्तु उनका सही उपयोग करने के लिए शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। उद्योग-धंधों की स्थापना करके औद्योगिक प्रान्ति का धीगलेन करना है। इसी प्रकार नवीन समाज का निर्माण करना है। तन्मे समाज की आवश्यकता है जिसका प्रत्येक सदस्य परस्पर प्रेम तथा सहयोग की भावना रखता हो, जो परिवर्तन की स्वीकार करता हो तथा अर्थविद्वाम एवं ऋणवादिता में समित न हो।

(२) प्रजातन्त्र की सफलता के लिए प्रजातन्त्र में दो प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है एक ता जे जो बुझल नेतृत्व कर सकें और दूसरे जे व्यक्ति जो नेताओं का विवेकपूर्ण अनुकरण करने हो। बुझल नेतृत्व के गुणों का विकास एवं पुष्टिपूर्ण अनुकरण करने वाला का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए योग्य, सचेत, ईमानदार नागरिकों का होना पर आवश्यक है। शिक्षा अनिवार्य करके ही पारी जनसाधारण की प्रजातन्त्रीय मिश्रण में प्रवेश करवाया जा सकता है।

(३) व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा ही एक प्रमुख माध्यन है जिस द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास सम्भव है। मनुष्य का मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का विकास होना चाहिए तभी हम मनुष्य की अन्तिम का शक्ति का विकास कर सकें। प्रत्येक बालक कुछ ज्ञानसाधन गुणों का भूक इस भंगार में जन्म होता है इन गुणों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देश के विकास के लिए हमें इन गुणों का विकास ही व्यक्तियों में कर गाने है जिसकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा जनसमूह की सेवा का पूरा विकास हुआ हो।

(४) निरक्षरता को मिटाने के लिए निराक्षरता देश के लिए बड़ी हानि है। अक्षरता के माध्यमिक शिक्षा व शिक्षा काई प्रयत्न नहीं किया जा सकता है कि व्यक्तित्व-प्रान्ति के समय देश में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी। अन्तिम व्यक्तिक शक्ति, समर्थ, मातृशिक्षा और कर्म-संस्कार इन में सम्मिलित रहते हैं। अब शिक्षा का अनिवार्य एवं निरक्षरता को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवार्यता के लिए प्रारम्भिक प्रयास

(क) विविध पद्धति—यह एक बलवत् विचार है, जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक बालक को शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जा सके।



सामने प्रस्ताव रखा कि काजून बनाकर भारत के प्रत्येक गाँव को एक स्कूल सापित करने के लिए राष्ट्र किया जाय। इसमें प्रत्येक गाँव के बालक, बालिका को शिक्षा प्रदान करने में मुक्तिदा रहेगी।

(ख) कंस्टेन विगेट—यह बम्बई प्रान्त का राजस्व भव्येक्षण कमिश्नर था। उसने भी भारत में शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए प्रयास किया। इसने १८५२ में सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि भूमि के राजस्व पर ५% कर लगाया जाय और उसमें ग्रामीण बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(ग) टी० सी० होप—श्री टी० सी० होप गुजरात के शिक्षा निरीक्षक थे। उसने १८५८ में सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि स्थानीय कर लगाकर अनिवार्य शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया जाय।

(घ) श्री दास्त्री—सन् १८८४ में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए बड़ीच के शिक्षा निरीक्षक श्री दास्त्री जी ने भी सरकार को उचित नवाह दी।

सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को अव्यावहारिक बनाकर उनको अस्वीकृत कर दिया। भारतीय जनता पर यह दोषारोपण भी लगाया कि यहाँ के लोग अनिवार्य शिक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। अतएव सरकार ने इन मुद्दों को समय में बहुत आगे बढ़ाया।

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीयों में राजनीतिक चेतना विकसित हुई। अब भारतीय नेताओं ने शिक्षा को राजनीतिक आवश्यकता माना। सन् १८७० में द्रगलैण्ड ने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। इसमें भारतवासियों को यह तर्क प्रस्तुत करने की मिला कि शिक्षा को अनिवार्य करना *Juriprudine* के प्रतिकूल नहीं है। दूसरे, सन् १८८५ में भारतीय कांग्रेस की स्थापना ने शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए बल रहे जागृताओं को बन मिला। तीसरे, भारतवर्सी विदेश भ्रमण के अवसर पर योरोपीय देशों की प्रगति की झलक में प्रभावित होकर शिक्षा की अनिवार्यता अधिक अनुभव करने लगे। चौथे, धीरे-धीरे हड़बदीता के समाप्त होने, बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार, पर्दा प्रथा की समाप्ति आदि के कारण तथा विद्वती जाति के लोगों की आगे बढ़ने की भावना ने अनिवार्य शिक्षा के आन्दोलन को तीव्र करने में सहयोग दिया।

सन् १८९० से १९१८ तक अनिवार्यता के लिए आन्दोलन

(क) बड़ीचा का नेतृत्व—भारतवर्ष में शिक्षा को अनिवार्य करने का सर्व-प्रथम प्रयास बड़ीचा के नरेश महाराज सायाजीराव गायकवाड ने किया। उन्होंने प्रारम्भ में प्रयोग के रूप में अमरीली नगर के एक तालुक के ९ गाँवों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। यह शिक्षा मात्र ३ बारह वर्ष तक के बालकों तथा सात

में दस वर्ष तक की शालिकाओं के लिए अनिवार्य की गई। यह कार्य १८६३ में प्रारम्भ किया गया। इस प्रयास में सरकारों ने मिलाते हुए अमरीकी नाम्बुका के ५२ ग्रामों में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सन् १९०६ में एक अधिनियम द्वारा राज्य के सभी बालकों के लिए शिक्षा वा अनिवार्य बना दिया गया।

(ख) बम्बई के प्रयत्न - बड़ोदा-नरेश के इस प्रयत्न में देश-भरों की प्रेरणा मिली। बम्बई में मराठि विष्मनलाल गोतलवाड तथा इराहीम रहीमलुल्ला ने सर्व-प्रथम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सरकार का कर्तव्य है। इस आन्दोलन के कारण बम्बई सरकार ने १९०६ में अनिवार्य शिक्षा के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्ति की। इस समिति ने जांच करने के बाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करना अनुचित बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षा को अनिवार्य करने पर अपने बच्चों को स्कूल न भेजने वाले अभिभावकों को दण्डित किया जायेगा। इसका परिणाम होगा कि सरकार तथा जनता के मध्य तनाव बढ़ेगा।

(ग) गोमले के प्रयत्न - महाराजा सायजीराव सायकवाड ने प्रेरणा लेकर गोपालकृष्ण गोमले ने कहा कि जब एक छोटी गियामन शिक्षा को अनिवार्य तथा निशुल्क बना सकती है तब माधन-मध्यम अथवा सरकार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य क्यों नहीं बना सकती? उन गोमले ने केन्द्रीय धारा सभा में १९ मार्च सन् १९१० में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा। परन्तु सरकार के आश्वासन पर गोमले ने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया। सरकार ने अपने आश्वासन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कोई पग नहीं उठाया तो इस उदासीन नीति को देखकर १६ मार्च, १९११ को केन्द्रीय धारा सभा में गोमले ने अपना प्रसिद्ध विधेयक रखा। इस विधेयक की प्रमुख बातें निम्न-लिखित थीं

- १ प्राथमिक शिक्षा उन क्षेत्रों में अनिवार्य की जाए जहाँ पहले से ही पर्याप्त संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं।
- २ स्थानीय संस्थाएँ प्रांतीय सरकारों की स्वीकृति लेकर ही इस नियम को लागू करें।
- ३ स्थानीय संस्थाएँ शिक्षा-कर जमा सकती हैं।
- ४ ६ वर्ष से १० वर्ष की आयु के बालकों को विद्यालय में भेजना अनिवार्य हो। ऐसा न करने वाले अभिभावकों को दण्डित किया जाए।
- ५ सम्पूर्ण देश का भार स्थानीय संस्थाएँ तथा सरकार १ २ के अनुपात में उठाएँ।

पण्डित मदनमोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना आदि प्रमुख नेताओं का सहयोग मिलने पर भी यह विधेयक १३ बोटों के विरोध में ३८ बोटों में गिर

या। इस प्रश्नार का आभाव गोयले जी को पहने में ही था, जैसा कि उन्होंने पत्रे बन्धु में एक स्थान पर कहा—

“श्रीमान जी मैं जानता हूँ कि सभ्य तक मेरा विधेयक अस्वीकृत हो जायेगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है और न मैं दुःख ही अनुभूत करूँगा। मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि इस वर्तमान पीढ़ी के लोग अपनी अमकलताओं के द्वारा ही देश की सेवा करने की आशा कर सकते हैं।”<sup>1</sup>

### भारत में शिक्षा अनिवार्य करने के प्रयत्न

बम्बई प्राथमिक अधिनियम—सन् १९१८ में गोयले के प्रयत्नों में सफल होकर बिट्टल भाई पटेल ने बम्बई की व्यवस्थापिका सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य बम्बई प्रान्त में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना था। यह विधेयक पास हो गया। पटेल ने अपने अधिनियम में गोयले द्वारा दी गई श्रुतियों को मूधारण—प्रथम तो गोयले के त्रिन की यह आलोचना की गई कि ग्रामीण क्षेत्र अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं। इसीलिए पटेल ने केवल नगर-पालिका क्षेत्र में शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कहा। दूसरा, गोयले ने सरकार को दो-तिहाई आर्थिक सहायता देने को कहा जबकि पटेल ने प्रान्तीय सरकारों को स्वतन्त्र दवा कि वे इच्छा होने पर आर्थिक सहायता दे सकती हैं। इस दूसरे मुद्दे पर सरकार के पक्ष को निर्वाण बना दिया। परिणाम यह हुआ कि १९१८ में यह कानून (Law) बन गया।

अनिवार्य शिक्षा के एक्ट बम्बई के बाद फिर विभिन्न प्रान्तों में बनाये गये जिनका विवरण पृष्ठ २२ की तालिका में स्पष्ट है।

सन् १९३१ से १९३७ ई० तक प्राथमिक शिक्षा का प्रश्नार कम हुआ क्योंकि हर्टाग समिति ने शिक्षा के गुणात्मक विकास पर अधिक बल दिया। सन् १९३७ में ११ प्रान्तों में से ६ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बना। इन प्रान्तों में भारतीय नेताओं ने शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयत्न किया। इसके बाद मार्लेट रिपोर्ट में भी ५ या ६ में १४ वर्ष तक समस्त बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने पर बल दिया।

1. My Lord, I know that my bill will be thrown out before the day closes. I make no complaints. I shall not feel even depressed. I have often said that we of the present generation in India can only hope to serve our country by our failures.  
—Speeches (1920 edition), pp. 445-46

व दस वर्षों तक की शिक्षाओं के लिए अनिवार्य की गई। यह सब प्राथमिक किया गया। दस प्रयोग में सफलता मिलने पर अगली ही प्रयोग में शिक्षा का अनिवार्य कर दिया गया। मनु १६०६ में एक राज्य के सभी बालकों के लिए शिक्षा का अनिवार्य बना दिया गया।

(ख) बम्बई के प्रयास - बम्बई-प्रेस के दस प्रयोग में मिली। बम्बई में एक शिक्षक-संघ गोंय-संघ तथा दूसरा प्रत्येक सरकार का ध्यान दस प्रयोग प्राप्त किए गए कि सरकार का अनिवार्य है। दस प्रयोगों में कारण यह अनिवार्य शिक्षा के प्रयोग पर विचार करने के लिए एक समिति ने जोष करने के बाद अनिवार्य प्रावधानों को बनाया। उन्होंने बताया कि शिक्षा को अनिवार्य करने से बनें सभी अनिवार्यता का दर्जा दिया जाएगा सरकार तथा जनता के साथ न्याय होगा।

(ग) गोवले के प्रयास - मराठवाड़ा में गोपालकृष्ण गोवले ने कहा कि जब तक देश में शिक्षा नहीं बढ़ती है जब मापन-मपन अनिवार्य क्यों नहीं बना सकती? अतः यह

## भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

इस धारा में हमको अपने सबिधान के कुछ अनुच्छेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। सबिधान के अनुसार यह शिक्षा सभी वर्गों के लिए अनिवार्य होगी। सबिधान इस प्रकार प्रजापति के सिद्धान्त—अवसरों की समानता—की सुरक्षा करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को वैश्विक विकास का अवसर तथा अधिकार प्राप्त है। सबिधान में यह उल्लेख है कि—“सरकार किसी व्यक्ति, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकती है।”<sup>1</sup> इस धारा की रक्षा के लिए ही सरकार ने सबिधान की २९वीं धारा के द्वारा यह स्पष्ट किया कि—“धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भी मन्त्र किसी व्यक्ति को प्रवेश देने के लिए मना नहीं कर सकती है जो कि राज्य द्वारा या राज्य की आधिकारिक सहायता के दल पर चल रही है।”<sup>2</sup> इन धाराओं में स्पष्ट है कि प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर ही अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

### प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ

(१) राजनीतिक बाधाएँ—स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य एवं नि:शुल्क बनाने के लिए सबिधान में इसको सम्मिलित करके अपना कर्तव्य पूरा किया। परन्तु सरकार सबिधान की ४५वीं धारा को सम्पूर्ण देश में सफलतापूर्वक लागू करने में सफल न हो सकी। इसके कुछ राजनीतिक कारण हैं। अंग्रेजों ने सन् १९४७ में यहाँ में जितने समय भारत को दो भागों में विभाजित किया। विभाजन के फलस्वरूप एक नवीन राष्ट्र, पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के जन्म ने सरणार्थी समस्या को जन्म दिया। सरकार का ध्यान पाकिस्तान में आये हुए पीड़ित लोगों के आवास, भोजन-वस्त्र, जीविका आदि की व्यवस्था पर लगा। इसी प्रकार एक समस्या ६०० देशी राज्यों के एकीकरण की थी। इनके अनिरुद्ध कश्मीर की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, चीन के आक्रमण की समस्या आदि सरकार के सामने आईं। भारतीय पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेता भी अनेक बातों को लेकर सरकार की आलोचना करते रहे परन्तु इन्होंने भी सरकार का ध्यान सबिधान की ४५वीं धारा की ओर खींचने का प्रयास नहीं किया। सरकार को भी इन जटिल समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त समय और धन खर्च करना पड़ा। चीन एवं

- 1 “The state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them”  
—Article 15—Indian Constitution
- 2 “No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them”

—Clause (2) of Article 29—Indian Constitution.



## भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

इस धारा में हमको अपने मविधान की कुछ विशेषताओं का आर सकेत मिलता है। मविधान के अनुसार यह शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होगी। मविधान इस प्रकार प्रजातन्त्र के सिद्धान्त—अवसरों की समानता—की गुरदा करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को वैश्विक विकास का अवसर तथा अधिकार प्राप्त है। मविधान में यह उल्लेख है कि—“सरकार किसी व्यक्ति, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकती है।”<sup>2</sup> इन धारा की रक्षा के लिए ही सरकार ने मविधान की २९वीं धारा के द्वारा यह स्पष्ट किया कि—“धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भी मस्या किसी व्यक्ति को प्रवेश देने के लिए मना नहीं कर सकती है जो कि राज्य द्वारा या राज्य की अधिक म्हायता के ढल पर चल रही है।”<sup>3</sup> इन धाराओं में स्पष्ट है कि प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर ही अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

### प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ

(१) राजनीतिक बाधाएँ—स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य एवं निशुल्क बनाने के लिए मविधान में इसका मम्मिलिन करके अपना कर्तव्य पूरा किया। परन्तु सरकार मविधान की २९वीं धारा को सम्पूर्ण ढल में मफलतापूर्वक लागू करने में मफल न हो सकी। इसके कुछ राजनीतिक कारण हैं। अंग्रेजों ने मन् १९४७ में यहाँ में जाते समय भारत को दो भागों में विभाजित किया। विभाजन के फलस्वरूप एक नवीन राष्ट्र, पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के जन्म ने मरणाधीन समस्या को जन्म दिया। सरकार का ध्यान पाकिस्तान में भाये हुए पीड़ित लोगों के आवास, भोजन-वस्त्र, जीविका आदि की व्यवस्था पर मगा। इसी प्रकार एक समस्या ६०० देशी राज्यों के मकीकरण की थी। इनके अतिरिक्त कश्मीर की समस्या, लाछास की समस्या, चीन के आक्रमण की समस्या आदि सरकार के सामने आईं। भारतीय पार्लियामेंट में विरोधी ढल के नेता भी अनेक बानों को लेकर सरकार की आलोचना करते रहे परन्तु इन्होंने भी सरकार का ध्यान मविधान की ४९वीं धारा की ओर खींचने का प्रयास नहीं किया। सरकार को भी इन जटिल मस्याओं के समाधान पर पर्याप्त समय और धन खर्च करना पड़ा। चीन एवं

1 “The state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them”  
— Article 15—Indian Constitution

2 “No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them”

—Clause (2) of Article 29—Indian Constitution.





भारत में अनिवार्य शिक्षा मकाननापूर्वक लागू नहीं हो पा रही है। निम्न तालिका में यह स्पष्ट हो जायेगा कि स्थानीय मस्यारों के निपटण में अधिक विघटन है।

## प्रश्न के अनुसार प्राथमिक विद्यालय

(प्रतिशत में)

वर्ष	राजकीय	स्थानीय मस्यारों	अभिमान मस्यारों
१९६६-६०	७६७	६७६	३३६
१९६१-६७	७०५	६६४	३०१
१९६५-६६	७३३	४११	२५६
१९६६-६६	७७२	६६१	२३७
१९६०-६१	७७७	५५७	२२१

(४) अप्रशिक्षित शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में शिक्षा अधिकारियों का सक्षम सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। इन अधिकारियों में प्रशासकीय क्षमताओं की कमी, सम्पना शक्ति एवं समस्याओं के समाधान की योग्यता का अभाव होने में ये शिक्षा नियमों को व्यावहारिक रूप देने में असमर्थ रहे। इन अधिकारियों ने अनिवार्य शिक्षा के सर्वेक्षण में कोई रुचि नहीं दिखाई। उपस्थित अधिकारियों के अप्रशिक्षित होने में विघटन होने वाली उम्र के बच्चों की ठीक जनगणना नहीं हो पाती है। ये उपस्थिति अधिकारी साधारण जनता के प्रति कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ये जनसाधारण को शिक्षा का महत्व तथा अनिवार्य शिक्षा के नियमों का ज्ञान कराते बिना दण्ड दिवाने में गौरवान्वित होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनता में शिक्षा के प्रति पूर्ण उत्पन्न हो जाती है। अभी तक उपस्थित अधिकारी अथवा महामक इन्स्पेक्टरों की कमी होने में सभी विद्यालयों का निरीक्षण भी सम्पूर्णजनक रूप में नहीं हो पाता है क्योंकि एक अधिकारी के गान लगभग १०० में अधिक विद्यालय निरीक्षण के लिए होते हैं। ये अधिकारी अध्यापकों के साथ मानवीय व्यवहार के स्थान पर अफसराना रूप अपनाते हैं। ये उनकी समस्याओं एवं कठिनाइयों को समझते एवं दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं करते।

निरीक्षक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की कोई सुविधा नहीं है। बी० एड० या एम० एड० में तो उनको गैरान्तिक ज्ञान ही प्रदान किया जाता है। इनसे सम्बन्धित एक समस्या कार्य-भार की अधिकता है। शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की, परन्तु उस गति के साथ निरीक्षक अधिकारियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई।

(५) अध्यापकों की समस्या— प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में मफलता प्राप्त न होने का एक कारण अध्यापकों की कमी है। अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के लिए, एक विज्ञान मस्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है। भारत के अनेक प्रांतों में इस समय प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत बहुत कम है। यह निम्न तालिका में स्पष्ट है

प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षा के अध्यापक (१९६०-६१)

राज्य	प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत
आन्ध्र	३६.३
गुजरात	३५.६
मध्य प्रदेश	५१.०
महाराष्ट्र	४६.८
मैसूर	४३.४
उड़ीसा	३८.५
राजस्थान	५०.८
पंजाब	३८.१

प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के कारण प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक विकास नहीं हो पा रहा है।

अध्यापकों में सम्बन्धित दूसरी समस्या पर्याप्त सख्या में अध्यापकों की पूर्ति है। निम्न तालिका में सन् १९६५ में १९७५ तक अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता स्पष्ट है

अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता का योग (१९६५-७५)

१९७५-७६ तक छात्रों की सख्या का अनुमान	छात्र-अध्यापक अनुपात के आधार पर १९६५-७५ के बीच अतिरिक्त अध्यापकों की माँग
	३५.१ ४०.१ ४५.१ ५०.१ (हजार में)
१ ६—११ वर्ष की आयु के १०० प्रतिशत	
११—१४ " " ५० " २,००७	१,६११ १,३०६ १,०६१
६—११ वर्ष की आयु के १०० प्रतिशत	
११—१४ " " ७५ " २,३२०	१,८८६ १,५५० १,२८१
३ ६—११ वर्ष की आयु के १०० प्रतिशत	
११—१४ " " १०० " २,६३७	२,१६१ १,७६४ १,५०१

शोधी तथा शोधार्थी पचवर्षीय योजनाओं के समय में ४५१ के छात्र-अध्यापक अनुपात के अनुसार प्रतिवर्ष २६१,००० और ३६८,००० के मध्य अध्यापकों की आवश्यकता होगी। अध्यापन व्यवसाय की ओर योग्य व्यक्तियों के आकर्षण में होने के कुछ कारण हैं जो कि निम्न रेखाचित्र में स्पष्ट हैं।

### अध्यापन व्यवसाय की समस्याएँ

अल्प वेतन	गर्भवो में सुविधाओं की कमी	समान की समस्या	अध्यापिकाओं की सुविधा की कमी	समाज में उचित मान की कमी
-----------	----------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

उत्पुल्ल अभुविधाओं के कारण प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में गड़बड़ता प्राप्त नहीं हो रही है। अल्प वेतन के कारण योग्य व्यक्तियाँ अध्यापन व्यवसाय में आना पसन्द नहीं करती हैं। कुछ प्रांतों में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का वेतन निम्न प्रकार है।

बिहार	५०-७-३०-२-६०
केरल	६०-४-६०-५-१००
उत्तर प्रदेश	१५-०-६५-२-६५
राजस्थान	३५-४-६५-५-१३०-५-१६०

उत्पुल्ल वेतन शृंखला सन् १९६३ के अनुसार है। इनमें कम वेतन पर परिवार का भरण-पोषण करना अध्यापक के लिए असम्भव है। अल्प वेतन होने से अध्यापन व्यवसाय को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। राजस्थान विद्या-विद्यालय के उपकुलपति श्री एम० बी० माथुर ने एक अध्यापक वाले विद्यालयों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में लगभग ४० प्रतिशत प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल एक अध्यापक वाले विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में मात्र-मात्र की कमी है तथा इनमें मिडिल स्कूल पाठ्य व्यक्ति अध्यापन करते हैं जिनको सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में भी कम वेतन मिलता है।

लड़कियों के विद्यालयों के लिए अध्यापिकाएँ प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। हमारे देश में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति विपरीत विचारधारा होने से पर्याप्त शिक्षित महिलाएँ इन विद्यालयों के लिए नहीं मिल पाती हैं। इसके साथ एक कारण यह है कि गाँवों में रहने की उचित व्यवस्था का अभाव एवं यात्रायात्र के साधनों की कमी के कारण शिक्षित महिलाएँ गाँवों में जाना पसन्द नहीं करती हैं।

(६) आर्थिक समस्या : धन का अभाव शिक्षा की अनिवार्य बनाने में एक बड़ा बाधा है। आर्थिक मदद का अभाव है।

(७) जनता की निर्धनता : भारत के लोगों की सामान्य जनता की आर्थिक दृष्टि से काफी सीमित है। कि इससे वास्तव में अनिवार्य करने के अभाव का विद्यार्थी नहीं बनता है। कि इससे अर्थ का अभाव ही बड़ी समस्या है। जिससे शिक्षा की आवश्यकता नहीं रहती है। कि निर्धन वर्ग के अपने बच्चे बच्चे में शिक्षा का महत्व में समर्थ नहीं हो पाते हैं। कि वे शिक्षा का अभाव की महापिता का है।

(८) सरकार के समर्थन का अभाव : प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य की निम्नलिखित उपायों के बिना राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सरकारों में पर्याप्त शिक्षा महापिता नहीं मिली। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का उन्मूलक के अभाव में राष्ट्रीय सरकारों पर आता परन्तु उनके अभाव के बिना कोई प्रयत्न नहीं किया। प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक महापिता के निम्न निम्न हैं।



केन्द्रीय सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई भी सीधी महापिता नहीं देती है। केन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों का उनके विभागों की योजनाओं की कार्यान्वयन करने के लिए महापिता देती है जिसमें प्राथमिक शिक्षा का विकास भी सम्मिलित रहता है। वर्तमान समय में भारत अपनी राष्ट्रीय आय का केवल २४ प्रतिशत ही शिक्षा पर व्यय करती है जो प्राथमिक शिक्षा पर लगभग ०.८३ प्रतिशत ही व्यय होता है। इसी प्रकार शिक्षा पर व्यय होने वाले सम्पूर्ण धन का केवल ३५.३३ प्रतिशत ही प्राथमिक शिक्षा पर सन् १९६०-६१ में व्यय किया गया। राजस्थान प्रान्त में यह प्रतिशत ३६.७८ रहा।

प्रांतीय सरकारों शिक्षा पर कुल व्यय का ५६.४ प्रतिशत ही प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करती है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। एक सर्वमान्य विचारधारा यह है कि प्रांतीय सरकारों को अपने राजस्व का २० प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना चाहिए और शिक्षा पर सम्पूर्ण व्यय का दो-तिहाई भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाय। इस दृष्टि में भारत के अनेक राज्य इस प्रकार महापिता करने में लगे रहे हैं।

स्थानीय संस्थाओं पर धन का अभाव अधिक है। इसका कारण है कि भू-राजस्व पर कर बहुत कम वसूल किया जाता है। नगरों में सम्पत्ति पर शिक्षा कर लगाया जा सकता है। परन्तु राजनैतिक अवस्था मदम्यों को यह कार्य करने में रोकती है।

के० जी० सैयदन ने कहा है कि—“शिक्षा के प्रति राष्ट्रीयता के मामले में सरकार द्वारा मौलवी बंटी जैसा व्यवहार किया ही गया है परन्तु प्राथमिक शिक्षा तो शिक्षा परिवार की जिम्मेदार मन्ता रहो है।”

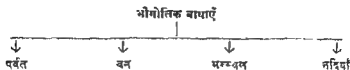
(३) विद्यालय-भवन की समस्या—प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी। परन्तु अपने देश में विद्यालय-भवन की अत्यधिक कमी है। सरकार के द्वारा निम्न भवन बहुत कम हैं। इनमें कुल छात्रों का ३० प्रतिशत ही शिक्षा ग्रहण कर पाता है। अधिकांश विद्यालय किराये के मकानों में चलते हैं जिनकी दशा बहुत खराब है। गाँवों में प्राथमिक विद्यालय पचायत घरों में, मन्दिरों में या धनी व्यक्तियों की चौपाल में चलते हैं। ये विद्यालय-भवन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। नगरों में अधिकांश विद्यालय कोराहल-पूर्ण वातावरण में स्थित हैं। इन विद्यालय भवनों में प्रकाश तथा हवा की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि में अनेक भवन ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहाँ दुर्गन्ध का साम्राज्य है। छात्रों को खेदों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। के० जी० सैयदन ने प्राथमिक स्कूलों की दशा के बारे में कहा है कि—“आप अपने मन में एक कच्ची भौपड़ी की कल्पना कीजिए जिसमें एक या दो कमरे हों, जिसकी दीवारें रंगी और फर्श पर धूल के ढेर हों, जिसमें कुछ फटे-पुराने टुकड़ों या ढूटी-भूटी डेस्कों या कुर्सियों को छोड़कर कोई फर्नीचर न हो। इन गन्दे और अनुपयुक्त स्थान में बेचारे अध्यापक में बच्चों को शिक्षा देने की आशा की जाती है।”

४. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम—प्राथमिक विद्यालयों में अभी तक वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है जो कि अंग्रेजों ने अपने समय में स्वीकृत किया। इसीलिए यह राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताओं तथा जनमाधारण की सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं को दूर करने के अनुपयुक्त है। वर्तमान पाठ्यक्रम में निम्नलिखित दोष हैं।

(१) सकीर्ण जीव-एक-मासिक, (२) पुस्तकीय शिक्षा की प्रधानता, (३) प्राचीन क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल न होना, (४) स्थानीय वातावरण की अवहेलना, (५) ‘करके सीखना’ सिद्धान्त को ध्यान में न रखना, (६) पाठ्यक्रम का संगठन अमनोबैज्ञानिक।

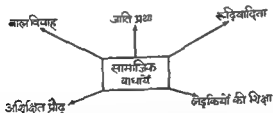
प्रत्येक छात्र में रचनात्मक कार्य करने की भूमि प्रवृत्ति होती है। इस भूमि प्रवृत्ति का विकास करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, परन्तु वर्तमान पाठ्यक्रम इन ओर कोई ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार का नीरस पाठ्यक्रम छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ रहता है।

(६) भौगोलिक बाधाएँ—पुनः भौगोलिक बाधाएँ प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में रूकावट डालती हैं।



उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट ऐसे निरस्तृत पर्वतीय प्रदेश हैं कि इन क्षेत्रों में पर्वतों के कारण आवागमन की सुविधा नहीं है, जनसंख्या कम एवं गाँव बिखरे हुए हैं। इन गाँवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना तथा उनका निरीक्षण करना एक बठिन कार्य है। राजस्थान के मरुभूमि प्रदेश में भी गाँव दूर-दूर स्थित हैं। गर्मियों के दिनों में तो इन प्रदेशों में दिन में चलना बहुत कठिन है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है। इस कारण बालक अपने विद्यालय में नहीं जा पाते हैं।

(१०) सामाजिक समस्याएँ—प्राकृतिक वानावरण की भानि ही सामाजिक वानावरण भी अनिवार्य शिक्षा को प्राप्त करने में एक बाधा है।



भारतवर्ष में जाति प्रथा अभी तक इतनी जटिल है कि उच्च वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्तियों के बच्चों के साथ एक ही विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना पसन्द नहीं करते हैं। आज भी गाँवों में, हरिजन छात्रों को विद्यालय में प्रवेश करने में अनेक बठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

बाल-विवाह भी सार्वभौम शिक्षा के विस्तार में रूकावट डालता है। वैसे न बनाकर बाल-विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया गया है परन्तु अभी तक यह प्रथा क्षेत्रों में विद्यमान है।

रुझावों के कारण सभी शिक्षा के प्रति लोगों की विपरीत विचारधारा रही है। यह शिक्षा को भारतीय पसन्द नहीं करते हैं। मुसलमान पर्दा प्रथा पर विशेष बल देते हैं। इन सबके कारण प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

(११) भाषा समस्या—संविधान के अनुसार भारतवर्ष को १४ भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। परन्तु इनके अतिरिक्त हमारे देश में अनेक बोझिल बोझी बोली है। संविधान के अनुसार मातृभाषिक प्राथमिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा के माध्यम में ही जानी चाहिए। परन्तु प्रत्येक क्षेत्र में कुछ भिन्न भाषा वाले लोगों की उपस्थिति एक समस्या उत्पन्न कर देती है। कुछ भाषाएँ विशेष रूप में आदिम जातियों के मातृभाषा और लिपि की दृष्टि में निर्बल हैं। अब किम भाषा के माध्यम में शिक्षा दी जाय यह एक समस्या बनी हुई है।

(१२) अपठ्य और अवरोधन—प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में अपठ्य और अवरोधन एक जटिलतम समस्या है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ६६ प्रतिशत अपठ्य होता है। १०० छात्रों में से चौथी कक्षा में केवल ४४ छात्र पढ़ते हैं। इसी प्रकार १६६२-६६ में अवरोधन के कारण १०० छात्रों में चौथी कक्षा में प्रविष्ट हुए उनमें से केवल ३६७ प्रतिशत ही चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। अपठ्य या अवरोधन असफल होने या माना-पिता द्वारा बीच में ही बच्चा छूट पड़ने में पढ़ने बिठा देने से होता है।

(१३) नवीन विद्यालयों की स्थापना—नगरों की अपेक्षा गाँवों में प्राथमिक शिक्षा के लिए नवीन स्कूलों की स्थापना करना एक कठिन कार्य है। देश के दौ-निहाई गाँवों में विद्यालय नहीं है। परन्तु इसमें सम्बन्धित एक समस्या गाँवों में जनसंख्या का कम होना है। जब छोटे-छोटे गाँवों में एक विद्यालय स्थापित करना भारत जैसे विविध देश के लिए सम्भव नहीं है।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में और भी अनेक समस्याएँ हैं।

(१) दोषपूर्ण अनिवार्य शिक्षा अधिनियम—भारतवर्ष में जो अधिनियम शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए लागू किये गये वे प्रायः गोखले के मुद्राओं पर आधारित हैं। वे बहुत पुराने हैं। उस समय में अब परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं। अब इनमें सुधार की आवश्यकता है। गोखले या पटेल के अधिनियम अभिभावकों की स्वेच्छा पर अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने पर जोर देने हैं परन्तु आज आवश्यकता इस बात की है कि इस जोर कठोर कदम उठाये जायें। गोखले के अधिनियम में अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय मन्त्रालयों पर छोड़ दिया था परन्तु स्थानीय सरकारें इस कार्य को करने में उत्साहित प्रतीत नहीं हुई। गोखले के अधिनियम में एक दोष आयु में सम्बन्धित है। उसने ६-१० वर्ष की आयु के बच्चों

के लिए तथा पहले नगरों में शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए कहा। परन्तु सर्विधान के अनुसार जब शिक्षा केवल नगरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसका प्रसार गाँवों में करना होगा जहाँ देश की ८० प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

(२) **औरुखों की कमी**—अनिवार्य शिक्षा को सफल बनाने के लिए गाँवों तथा नगरों में रहने वाले लड़के एवं लड़कियों के बारे में सही औरुखें उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार यह औरुखें भी एकत्रित नहीं किये गये कि कौन-सी स्थितियों में विद्यालय नहीं है। अनिवार्य स्कूल बालों आयु के बच्चों की जनगणना नहीं की जाती है।

(३) **प्रान्तीय सरकार द्वारा असहयोग** प्रान्तीय सरकारों ने अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। इन कानूनों को बलपूर्वक लागू नहीं किया गया। कुछ प्रान्तों में अनिवार्य शिक्षा कानून को अवहेलना करने वालों पर मुकदमा नहीं चलाया गया। परिणामतः अभिभावकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

### निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा-प्रसार के लिए सुझाव

सर्विधान की ४३ वीं धारा के अनुसार ६-१४ वर्ष की आयु के समस्त बालकों को शिक्षा को अनिवार्य बनाने का लक्ष्य सन् १९६० में रखा गया। परन्तु उपर्युक्त कारणों से लक्ष्य-प्राप्ति नहीं हो सकी। आज सम्पूर्ण देश में सर्विधान के इस निर्देश को पूर्ण करने की चर्चा है। योजना आयोग के सदस्यों का मत है कि ६-११ वर्षों की अनिवार्य शिक्षा की ओर सर्वप्रथम ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

(१) **अनिवार्य शिक्षा की स्थिर नीति** सरकार को सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा के प्रति एक निश्चित तथा स्थिर नीति का पालन करना चाहिए। सरकार को बुनियादी शिक्षा योजना तथा अनिवार्य शिक्षा को एक साथ चलायित नहीं करना चाहिए, परन्तु प्रथम स्थान अनिवार्य शिक्षा योजना को देना चाहिए। सरकार को इस योजना की पूर्ति के लिए एक सीमा निश्चित कर देनी चाहिए। बांग्लादेशी आयोग ने सर्विधान की ४३ वीं निर्देश की पूर्ति के लिए निम्न सुझाव दिए

(अ) **शुल्क** राज्य और यह एक कि आवश्यक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए एक योजना बनानी चाहिए। इसका निमाण बच्चे समग्र स्थानीय स्थानों और समुदायों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। योजना वह लक्ष्य सर्विधान के निर्देश की पूर्ति सीधे-सीधे करना जाना चाहिए।

(आ) **शुल्क** राज्य या शिक्षा की अपनी शक्तानुसार प्रवर्धित करने में सहायता की जान। शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक सर्विधाया या चर्च के अभाव के कारण प्रवर्धित होना नहीं चाहिए।

(इ) **प्रवर्धित** योजना में तथा कुछ नगरों में सर्विधान की निर्देश १९४८-४९ में पूर्ण हो चकता परन्तु सम्पूर्ण देश में पाँच वर्षों की शिक्षा की योजना



१९७५-७६ तक हो जानी चाहिए और ७ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा १९८५-८६ तक पूर्ण की जाय।

प्रान्तीय सरकारों को नवीन परिस्थितियों के अनुसार अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का निर्माण करके प्रत्येक स्थानीय मन्त्रालय पर उसको कार्यान्वित करने के लिए दबाव डाला जाय।

(२) शिक्षा-प्रशासन में सुधार—यह ठीक है कि शिक्षा प्रान्तीय सरकारों का विषय है और केन्द्रीय सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई नीति उत्तरदायित्व नहीं रखती है परन्तु कुछ तर्क इस बात की पुष्टि करते हैं कि केन्द्रीय सरकार अपने को शिक्षा के प्रसारण सम्बन्धी कार्य में अलग नहीं कर सकती है। केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकार के साथ सहयोग तथा सहकारिता की नीति अपनानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्न कार्य करने चाहिए

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य संचालित करना चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र में गुणात्मक विकास हो सके।

(२) प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रान्तों में जो भिन्नता विद्यमान है उनको दूर करने का प्रयास किया जाय। निर्धन राज्यों को अन्य विकसित राज्यों के बराबर जाने के लिए विशेष सहायता दी जाय।

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा Pilot Project संचालित की जायें जिनका सामान्यीकरण सभी प्रान्तों द्वारा किया जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा में सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों के उत्तरदायित्व निम्न-निम्न हैं

१. सरकार पूरे राज्य के लिए एक शिक्षा नीति निर्धारित करे।
२. सम्पूर्ण प्रान्त के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था का निर्माण करे।
३. प्रत्येक प्रान्त में शक्तिशाली प्रशासकीय विभाग हो क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना प्रान्त का उत्तरदायित्व है। स्थानीय मन्त्रालयों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए अथवा शिक्षा विभाग होना चाहिए।
४. राज्य सरकारों के द्वारा स्थानीय मन्त्रालयों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाय।
५. राज्य सरकारों का कर्तव्य यह भी है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित करें।

(३) स्थानीय संस्थाओं में सुधार—प्रजातंत्रीय विद्यालय के अनुसार प्रशासन में विकेन्द्रीकरण करना अनिवार्य की दृष्टि में उचित है। परन्तु इन स्थानीय मन्त्रालयों



- (इ) प्राथमिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार में आर्थिक सहायता प्राप्त करना जिससे कि देश के सभी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का समान प्रसार हो।
- (ई) शिक्षा के लिए मुनस स्थानीय निधि को बढ़ाया जाय। यह निम्न प्रकार हो सकता है
  - (१) शिक्षा-कर लगाया जाय, (२) वर्तमान स्थानीय राजस्व का एक बड़ा भाग प्राथमिक शिक्षा के लिए निश्चित किया जाय, (३) स्थानीय सस्थाओं की भाय के स्रोतों में वृद्धि करना, (४) धनी व्यक्तियों से दान के रूप में धन एकत्रित किया जाय।
- (उ) प्रांतीय सरकारें अपने राजस्व का विशेष भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया करें।
- (ऊ) ७ वर्ष की शिक्षा के स्थान पर ४ वर्ष की शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए प्रयत्न किये जायें। इंग्लैण्ड ने भी प्रारम्भ में ६-१० बयोंवर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया था।

५. अध्यापकों की समस्या का हल—अध्यापकों की कमी से अनिवार्य शिक्षा प्रसार अवलब्ध नहीं होना चाहिए। इन सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय काम में ले चाहिए

(अ) कम योग्यता प्राप्त व्यक्ति, जैसे दली कक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियों को अध्यापन वसाय में प्रवेश दिया जाय। बाद में धीरे-धीरे इनको अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जायें। मैक्सिको में जब प्रतिवर्ष १००० प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये तो उत्साही, सम्बन्धित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

(आ) पारी-प्रणाली (Shift System) को प्रारम्भ किया जाय। मार्च १९६३ केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय परियोजना की ३०वीं मीटिंग में अध्यक्ष पद से तत्कालीन मन्त्री शिक्षा श्री डा० कामरुज्जाम खान ने कहा था—“दो—पारी प्रणाली की नि ही सभी सम्भव उपाय इन अवधि में प्रयोग में लाये जाएँ।”<sup>१</sup>

(इ) जब तक अध्यापकों की कमी है, प्रति अध्यापक छात्रों की संख्या बढ़ा दी जाय। सभी विकसित देशों में प्रारम्भ में एक अध्यापक को ५० से अधिक छात्र पढ़ाने होते थे। यह तथ्य निम्न तालिका से स्पष्ट है

“... I would however urge upon you, in the meantime, to adopt all possible measures such as the double shift system.”

—Dr. K. L. Shrivasth.

## अध्यापक-द्वारा अनुदान

देण	मन्	प्रति अध्यापक के पात्र द्वारा की गयी
पुनर्-निर्देश	१८६६	६०
हस्त-लिखित	१९०४	८०
आपन	१९०३	६०
विद्यार्थी-निर्देश	१९०४	३०
अर्थ-नीति	१९०३	६०

६. विद्यालय-भवन तथा पाठ-भवन की प्रकल्प यह है कि हमारे देश में विद्यालय-भवन प्रमाण लय इस की दृष्टि में उपयुक्त नहीं है। परन्तु अभी प्रयोगशील दशा में प्रारम्भ में विद्यालय-भवन को हमारे देश में बुरी दशा थी। मन् १९०५ में मन् के दायित्व धर्म में पुनर्निर्देश में बने हुए विद्यालय-भवन थे। हमको अपने देश में धर्म-दायित्व, मन्-द्वारा तथा मन्-द्वारा में बने हुए विद्यालयों पर लम्बा अनुभव नहीं करना चाहिए क्योंकि इन-निर्देश में विद्यालय देश में पुनर्निर्देश के नीचे बना करने थे। विद्यालय-भवन के लक्ष्य में निम्न सुझाव है

(अ) स्वच्छ आवास के नीचे मान्य-निर्देशन की भाति बसाएँ बनाई जायें।

(आ) सरकार द्वारा विद्यालय-भवन के लिए कर्जा (Loan) दिया जाय।

(इ) स्थानीय धनी व्यक्तियों को दान देने के लिए उत्साहित किया जाय तथा जो व्यक्ति दान देने में असमर्थ हो उनको धार्मिक भ्रम करने का परामर्श दिया जाय।

(ई) सरकार द्वारा या स्थानीय मन्त्रालयों द्वारा विद्यालयों को प्रति ३ वर्ष बाद एक सर्वेक्षण करवा कर आवश्यकतानुसार आवश्यकता का सामान देना चाहिए।

७. बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान—लड़कों की अवस्था अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने में लड़कियों की प्रगति बहुत कम है। मन् १९६६ में ६-११ बयोंवर्ग की कुल लड़कियों का ५६.४ प्रतिशत ही प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहा था जबकि हमी बयोंवर्ग के १० प्रतिशत लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। सविधान के ४५ वें निर्देश की पूर्ति के लिए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोटारी आयोग ने स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति द्वारा १९५८ में दिए गये सुझावों पर ही विशेष बल दिया

(अ) रुढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए जनता को शिक्षित करना।

(आ) बालिकाओं की निशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों आदि की व्यवस्था की जाय।

(इ) महिला अध्यापकों की नियुक्ति करना।

(ई) सम्मिलित विद्यालयों को लोकप्रिय बनाना और जहाँ सम्भव हो वहाँ पृथक् बालिका विद्यालय स्थापित करना।

(उ) उन अध्यापिकाओं को विशेष मुविधान देना जो गाँवों में सेवा करने को तैयार हैं।

(ऊ) ११-१३ बच्चों की लड़कियों के लिए अतिरिक्त समय में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय जो कि मधेनू कार्य के कारण पूरे समय विद्यालय में नहीं रह सकती हैं।

८. पाठ्यक्रम में सुधार—आदर्शवादी पाठ्यक्रम के स्थान पर यथार्थवादी पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम को स्थानीय वातावरण के अनुसार बनाया जाय। पाठ्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक विषयों को अधिक स्थान दिया जाय। भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश है। अतः ग्रामीण बालकों को कृषि का अध्ययन अनिवार्य रूप में करवाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के निम्न तीन आधार हैं—(१) मनोवैज्ञानिक आधार, (२) सामाजिक आधार, (३) देश की आवश्यकताएँ।

९. विद्युड़ी तथा आदिम जाति की शिक्षा पर ध्यान—सन् १९६१ की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या का १४.७ प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति के लोगों का है। इसी प्रकार आदिम जातियों भी कुल जनसंख्या का ६.८ प्रतिशत है। परन्तु इनकी शिक्षा की अब तक उपेक्षा ही होती रही है। सविधान के ४५वें निर्देश की पूर्ति तभी सम्भव है जबकि सरकार इनकी शिक्षा के प्रसार की भी व्यवस्था करे। आदिम जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए १९६०-६१ में केन्द्रीय आयोग ने निम्न सुझाव दिये

(अ) विद्यालयों के साथ छात्रावास की व्यवस्था की जाय। दो मील से अधिक पैदल चलकर बालक विद्यालय में न आये।

(आ) निर्धनता की बाधा को दूर करने के लिए इन बच्चों को भ्रष्टाचार भोजन, वस्त्र, पुस्तकें आदि निशुल्क दी जायें।

(इ) हस्तकला को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाय।

(ई) अध्यापक को आदिम जातियों की भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

(उ) जनता में अनिवार्य शिक्षा का प्रचार किया जाय।

१०. अपव्यय और अवरोधन—अपव्यय और अवरोधन को दूर करने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाय। प्राथमिक विद्यालय की प्रथम दो कक्षाओं में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं की जाय। खेल-विधि के द्वारा शिक्षण हो।

प्रतिष्ठित व्यापारिक हो वा कि छोटी क मात्र मन्वीरानिक इन म व्यापारिक व  
वृत्तों क आता शिक्षा म मन्वीरानिक शिक्षा आत ।

३३. राष्ट्रीय आन्दोलन को आवागमन मातृश्र्च दल म अनिवार्य शिक्षा  
क विषय आन्दोलन प्राथमिक शिक्षा आव । इस आन्दोलन क मात्र मात्र प्रीठ शिक्षा  
वा विचार भी आवागमक है । शिक्षा क द्वाारा ही अनमय वा अनिवार्य शिक्षा के  
अनुष्ठान बनाना वा मन्वीरानिक है । प्रीठ शिक्षा क प्रचार न भारतीय जनता म व्यापक  
कविचारिता मन्वीरानिक होनी और माता शिक्षा आन वृत्तों का विद्यालय प्रदन म विवि  
मन्वीरानिक है । अनिवार्य शिक्षा क विषय अनमय प्रचार करने हेतु आवागमकी, समाचारनय  
मन्वीरानिककाएँ उभय माधय बन मन्वीरानिक है ।

### अभ्यागार्थ प्रश्न

१. विभी भा दल म शिक्षा का अनिवार्य तर्क निरूपक बनान को आव-  
गमकता पर अन्त विचार लिखित ।
२. भारतवर्ष म प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य तर्क निरूपक बनान के  
विषय किम मन्वीरानिक प्रयत्न का बचन कीटित ।
३. विन कायला म अन्वीरानिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना  
मन्वीरानिक मातृश्र्च नही हो मन्वीरानिक है ?
४. 'भारतीय मन्वीरानिक का प्राथमिक शिक्षा का प्रमाणनगीत देने मे अनि-  
वार्य शिक्षा मन्वीरानिक हो वा नहीं है' इस बचन मे आन वृत्तों तर्क  
मन्वीरानिक है ?
५. प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं मन्वीरानिक उनक समाधान के उपाय  
बनाइत ।

### राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा मे पूछे गये प्रश्न

1. Discuss the problem of compulsory primary education in India. What inspiration can we derive from the experiences of other countries of the world ? (1962)
2. Discuss the problems of Primary Education in your State with reference to the following issues, illustrating your answer with the experiences of U S S R, U S A, U K, or any State in India, where possible, also making your own suggestions
  - (a) Principles governing the opening of new Primary Schools, with regard to the population of the locality or distance a child has to walk.

- (b) Enrolment Drives—their organization and effects.
- (c) Timely appointment of teachers (specially lady teachers) particularly in villages
- (d) School buildings
- (e) School equipment
- (f) Availability of Text-books
- (g) Working hours and the possibility of children's participation in domestic affairs.
- (h) Provision of midday meals
- (i) Associating local community with schools
- (j) Inspection or supervision of schools (1963)

- 3 'Man is more important than materials' Enumerate the deficiencies in ordinary primary schools in Rajasthan in point of material, and show how a good Inspector of Schools can take up a school improvement programme effectively by
  - (a) Mobilizing the community resources,
  - (b) Inspiring the school-teacher,
  - (c) Organizing an efficient supervisory procedure. (1964)
- 4 Formulate the two most fundamental problems in the field of primary education in India, analyse them and suggest measures for solving them (1965)
5. भारत में प्राथमिक शिक्षा की (अ) प्रसारणात्मक (expansion), और (ब) गुणात्मक (qualitative) उन्नति से सम्बन्ध रखने वाली संस्थाएँ कौन-सी हैं ? इन दोनों में से किसी एक समस्या का विवेचन कीजिए और उसे सुधारने के उपाय बताइए । (१९६६)
6. भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन अत्यधिक हड़तालही समस्याएँ हैं ? अपने ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन कीजिए कि ऐसी ही समस्याओं का समाधान किस ने किस प्रकार किया है ? (१९६८)

## अध्याय ३

### विदेशों में प्राथमिक शिक्षा

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में रुकावट डालने वाली समस्याओं का अध्ययन पिछले अध्यायों में किया गया। विश्व के अन्य देशों में भी शिक्षा को अनिवार्य बनाने समय इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। आज उन देशों में अनिवार्य शिक्षा सफलतापूर्वक चल रही है। इंग्लैण्ड, संयुक्त राज्य अमरीका और रूस विद्व के महान् देश हैं। इन देशों में किन प्रकार शिक्षा को अनिवार्य किया तथा वहाँ की शिक्षा व्यवस्था एवं संगठन किस प्रकार का है, आदि बातों का अध्ययन हमको अपने यहाँ की समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है। तुलनात्मक शिक्षा अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके द्वारा अध्यापकों को हमारे देशों की शिक्षा प्रणालियों, उनके गुण एवं दोषों का ज्ञान होता है। अपने देश की शिक्षा-प्रणाली के निर्माण एवं सुधार करने के लिए हम हमारे देशों के अनुभवों से लाभान्वित हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस अध्याय में इंग्लैण्ड, संयुक्त राज्य अमरीका और रूस की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का वर्णन किया जायेगा।

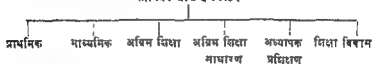
### इंग्लैण्ड में प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा-संगठन—इंग्लैण्ड की प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन करने से पूर्व वहाँ का शिक्षा-संगठन तथा व्यवस्था समझना आवश्यक है। सन् १९४४ से पूर्व 'शिक्षा-बोर्ड' के अधिकार में ही सम्पूर्ण देश की शिक्षा का नियंत्रण था। परन्तु सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार 'शिक्षा बोर्ड' का नाम 'शिक्षा मन्त्रालय' कर दिया गया और इसके प्रधान को शिक्षा मंत्री के नाम से पुकारते हैं। शिक्षा सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट शिक्षा मंत्री द्वारा मन्द में रखी जाती है। विश्वविद्यालयों तथा स्वतन्त्र स्कूलों पर शिक्षा मंत्री का कोई अधिकार नहीं होता है। मंत्री की सहायता के लिए एक सभामन्त्रि होता है। इसके अतिरिक्त इनके नीचे एक स्थायी सचिव, एक उप-सचिव, तथा अनेक सहायक सचिव होते हैं। ये सभी राजकीय कर्मचारी होते हैं।



हर संजैस्टोज इन्स्पेक्टर—ये उच्च योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं। ये शिक्षा मन्त्रालय और शिक्षा अधिकारियों के मध्य मध्यस्थता का कार्य करते हैं। इनका संगठन निम्न प्रकार होता है

### सोनियर चीफ इन्स्पेक्टर



सोनियर चीफ के नीचे १० क्षेत्रीय निरीक्षक होते हैं। इनके नीचे साधारण निरीक्षक होते हैं।

स्थानीय शिक्षा अधिकारी—इंग्लैण्ड में इन समय स्थानीय शिक्षा मन्त्रालयों की संख्या १४६ है। इनमें से ६७ वाउन्टी काउन्सिल्स और ८३ वाउन्टी बरी काउन्सिल्स हैं। शिक्षा के अनिरिक्त स्वास्थ्य, मदक तथा अन्य बातों के लिए भी ये ही जिम्मेदार हैं। इनके लिए मददस्व जनमत में निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक स्थानीय शिक्षा अधिकारी में एक शिक्षा समिति का निर्माण किया जाता है जोकि शिक्षा की देखभाल करती है। शिक्षा समिति का मुख्य अधिकारी 'चीफ एड्युकेशन ऑफिसर' या शिक्षा मन्त्रालय कहलाता है। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के निम्नलिखित कार्य होते हैं

१. नर्सरी स्कूलों की स्थापना करना।
२. अपने क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक एवं अग्रिम शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करना।
३. मुख्य शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति।
४. आवश्यकतानुसार बच्चों के भोजन अथवा दूध का प्रबन्ध करना।

शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था—शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय शिक्षा अधिकारी तथा केन्द्र दोनों ही व्यय करते हैं। अब स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भी अनुदान मिलने लगा है। स्थानीय अधिकारी करो में प्राप्त आय से भी शिक्षा पर व्यय करते हैं।

### प्राथमिक शिक्षा के स्तर

इंग्लैण्ड में ५ वर्ष की अवस्था से १५ वर्ष की अवस्था तक बच्चों के लिए शिक्षा नि शुल्क और अनिवार्य है। शीघ्र ही उसको १६ तक बढ़ाने की योजनाएँ हैं। सन् १८४४ के एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को वैज्ञानिक ढंग में सुसंगठित किया गया। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के तीन स्तर हैं जो कि निम्नलिखित हैं

१. नर्सरी विद्यालय या नर्सरी कक्षाएँ—२ वर्ष से ३ वर्ष तक के बालकों के लिए।



- (२) बालकों के शब्द-भण्डार को बढ़ाने के प्रयत्न किये जाते हैं जिससे कि वे बातचीत भली-भाँति कर सकें।
- (३) बालकों को श्रवण तथा निरीक्षण शक्ति को विकसित करना।
- (४) स्वस्थ आदतों का निर्माण तथा सामाजिक कुशलता का प्रदर्शन।

सभी इन्फैन्ट स्कूलों में महिलाएँ अध्यापन कार्य करती हैं। इन विद्यालयों में सह-शिक्षा प्रचलित है। सामूहिक खेल या भ्रियामो का आयोजन होता है जिसमें कि छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास हो सके।

**जूनियर विद्यालय**—इन विद्यालयों में ७ वर्ष से ११ वर्ष की आयु के बालक पढ़ने के लिए जाते हैं। इनमें से कुछ के साथ इन्फैन्ट कक्षाएँ जुड़ी रहती हैं और कुछ पृथक् होते हैं।

इन स्तर पर बालकों के सर्वांगीण विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्राकृतिक निरीक्षण द्वारा बालक बहुत-सी चीजों को देखकर समझते हैं। मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे कि छात्र सभी बातों को सुगमता से सीख एवं समझ सकें। जूनियर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय निम्न-लिखित हैं।

(१) भूगोल, (२) विज्ञान, (३) पणित, (४) इतिहास, (५) संगीत, (६) स्वास्थ्य शिक्षा, (७) वागवानी, (८) गृह विज्ञान (बालिकाओं के लिए)। धार्मिक व्यायाम भी कराया जाता है।

### प्राथमिक विद्यालयों का संगठन

**प्राथमिक विद्यालय दो प्रकार के होते हैं**

१. **ऐच्छिक विद्यालय**—ये विद्यालय वर्ष द्वारा संचालित होते हैं। इनमें धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। ये विद्यालय भी दो प्रकार के होते हैं।

(अ) **सहायता प्राप्त**—इनका चलाना तथा भवन को उचित अवस्था में रखना प्रबन्धकों का कार्य है।

(आ) **निर्भरित विद्यालय**—ये विद्यालय स्थानीय अधिकारियों द्वारा चलाये जाते हैं। वैसे ये प्रबन्धकों द्वारा स्थापित होते हैं परन्तु स्थानीय अधिकारियों को दे दिये जाते हैं। इन विद्यालयों में धर्म की शिक्षा सप्ताह में केवल दो दिन दी जाती है।

२. **काउन्टी विद्यालय**—ये विद्यालय स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थापित किये जाते हैं। इन विद्यालयों में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है।

**अनिवार्य शिक्षा**—अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजें। इंग्लैण्ड में अनिवार्य शिक्षा कानून का पालन न करने पर अपराधी अभिभावक पर दस पौण्ड का आर्थिक

दण्ड या एक महीने की सजा मिल सकती है। वहाँ पर १२ वर्ष में कम आयु का बालक कहीं भी नौकरी नहीं कर सकता है। इस देश में अन्धे, बूढ़े, बहरे या जिन मन्द बुद्धि वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय हैं जहाँ उनका भेजना अनिवार्य है। हमारे देश की अपेक्षा वहाँ इस कानून का चलन अधिक कठोरता से किया जाता है।

**विद्यालय का प्रबन्ध**—यूनिवर्सिटी विद्यालय के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व वहाँ के मुख्याध्यापक पर ही रहता है। मुख्याध्यापक अध्यापकों को सप्ताह में पाठ्यक्रम निश्चित करता है। इसी कारण वहाँ के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में समानता नहीं मिलती है। मुख्याध्यापक अध्यापकों के कार्य का निरीक्षण करता है। निरीक्षण का समय-समय पर अपनी बहुमुख्य सप्ताह दिया करते हैं। एक कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या ४० निर्धारित की गई है। परन्तु कभी-कभी स्थानाभाव या छात्रों की संख्या बढ़ने पर ४० से भी अधिक छात्र एक कक्षा में हो जाते हैं। प्रातः विद्यालय खुलने पर सामूहिक प्रार्थना करना सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है।

द्वार्लैण्ड में अभिभावक-शिक्षक समितियों की स्थापना की ओर आजकल अधिक ध्यान दिया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानाध्यापक होता है। इस प्रकार अभिभावकों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक रचे जाते हैं। इन अध्यापकों को सभी प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। बच्चों के लिए बोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है। भोजन के लिए थोड़ी फीस ली जाती है। विद्यालय-स्वास्थ्य-सेवाएँ—बच्चों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए है। छात्रों के दाँतों की भी जाँच होती है। ११ वर्ष की आयु पर एक परीक्षा होती है जिसे ११-परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के द्वारा यह निर्द्वय किया जाना है कि छात्र किम माध्यमिक विद्यालय के योग्य है।

### संयुक्त राज्य अमरीका में प्राथमिक शिक्षा

**शिक्षा प्रशासन**—संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा राज्य सरकारों के अधीन है। परन्तु फिर भी मधीय सरकार शिक्षा की उन्नति में रुचि लेती हैं। मधीय सरकार का आर्थिक दृष्टि में या अन्य किसी क्षेत्र में राज्य की शिक्षा पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है मधीय सरकार शिक्षा सम्बन्धी शोधकार्य, शिक्षा सेवाएँ तथा अनुदानों के कार्यक्रमों का प्रशासन सम्हालती है। संयुक्त राज्य अमरीका में १० राज्य हैं और अपने अन्दर शिक्षा का प्रसार एवं उन्नति करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। इसीलिए इस सम्बन्ध में राज्यों में अलग-अलग तरीके हैं। अधिकांश राज्यों में राजकीय शिक्षा बोर्ड बनाया गया है। यह बोर्ड प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों की शिक्षा सम्बन्धी नीतियाँ बनाता है। प्रत्येक राज्य में मुख्य राजकीय स्कूल अधिकारी (Chief State School Officer) की नियुक्ति की जाती है या शिक्षा



(३) प्राथमिक विद्यालय—इसमें पहली, दूसरी, तीसरी कक्षाएँ सम्मिलित रहती हैं।

(४) माध्यमिक विभाग—इसके अन्तर्गत चौथी, पाँचवी और छठवी कक्षाएँ होती हैं।

(५) उच्च विभाग—सातवी और आठवी कक्षाएँ इसमें सम्मिलित हैं।

प्रारम्भ में उपनिवेशवाद के कारण प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं हो सकी। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के बालकों तक ही सीमित थी। परन्तु जब में प्रजातन्त्रीय घामन व्यवस्था अनाई गई, यह अनुभव किया गया कि प्रजातन्त्र की सफलता के लिए सभी देशवासियों का शिक्षित होना आवश्यक है। राज्य सरकारों ने शिक्षा को अनिवार्य बनाया। इस देश में घर्म-निरपेक्ष शिक्षा दी जाती है। धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक भेदभाव को त्याग कर समस्त छात्रों को समान शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा समाजप्रधान है। इस शिक्षा के दो क्षेत्र हैं— प्रथम बालक, और दूसरा समाज, जिसमें बालक जीवन व्यतीत करता है। बालक को सामाजिक अनुभवों का ज्ञान कराना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। अतः अभिभावकों को विद्यालय की उपनिषद् सगटन में सहयोग देने के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य—संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- (१) बच्चों में पुष्ट भाषा होवने व लिखने की योग्यता पैदा करना।
- (२) उनकी आत्मोन्नतात्मक एवं निरीक्षण शक्ति को विकसित करना।
- (३) बच्चों के स्वास्थ्य के विकास पर ध्यान देना।
- (४) अवकाश के समय की रचनात्मक कार्य में व्यतीत करने का प्रशिक्षण।
- (५) छात्रों का नैतिक विकास एवं चरित्र निर्माण करना।

विद्यालय कार्यक्रम राष्ट्रीय या राज्य सरकारों द्वारा किसी प्रकार का पाठ्यक्रम निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। प्रत्येक राज्य अपने स्तर के लिए पाठ्यक्रम का मुद्धान देता है। यहाँ के विद्यालयों में पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम अध्यापक, पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, अभिभावक आदि की समितियों द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए विद्यालयों की पाठ्यक्रमों में अधिक समानता नहीं मिलती है।

पाठ्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में विज्ञान, सांख्यिक अध्ययन, विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, गणित, कला तथा पारोक्षिक शिक्षा आदि विषय शामिल किए जाते हैं। विज्ञान विषय सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। इसके अन्तर्गत भौतिक, पृथ्वी, मनुष्य विज्ञान, जन्तुवैज्ञान का अध्ययन कराया जाता है। पारोक्षिक शिक्षा के लिए वेनचर, मूल तथा मुद्रिका आदि का उपयोग होता है।

गणित का अध्ययन आगमन तथा निगमन विविधों द्वारा कराया जाता है। बच्चों की भाषा कला के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मुलेस के मुधार के लिए मुन्नाव दिये जाते हैं। विद्यालयों को अध्यापन में महत्वक सामग्री से पूर्णतः सुसज्जन रखा जाता है।

**छात्र की प्रगति**—यहाँ पर छात्र को अपनी आयु के समूह में रखा जाता है। बच्चों की वार्षिक सफलताओं के आधार पर आये की कक्षा में चढ़ाया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धान्त पर ध्यान दिया जाता है। वर्ष में अधिकांश समय के लिए किसी बालक के अनुपस्थित रहने या अस्वस्थ रहने पर उसको उसी कक्षा में रोक दिया जाता है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक छात्र का प्रगति-आलेख रखा जाता है।

**अध्यापक**—म्युन राज्य अमरीका में प्राथमिक विद्यालयों में ग्रेजुएट शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। अध्यापकों के वृत्तिक विकास के लिए प्रधानाचार्य भी व्यवस्था करते हैं। प्रधानाचार्य अध्यापकों की भीटिंग करते हैं तथा उच्च शिक्षा सम्पादनों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं। बर्कदाप और अध्ययन सम्मेलन का अध्यापकों के लिए आयोजन किया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने वाले विद्यालयों की संख्या १३० है।

**अन्य सेवार्थ**—प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्न अनेक सेवार्थ कार्य कर रही हैं



(१) **मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम**—म्युन राज्य अमरीका के कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्कूल आहार कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। बच्चों को पीछे भोजन एवं दूध दिया जाता है। इसके लिए छात्रों में थोड़ा पुरस्क भी दिया जाता है।

(२) **विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम**—यहाँ पर विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों के स्वास्थ्य की परीक्षा ली जाती है। इसके बाद प्राथमिक एवं माध्यमिक अवधि में तीन बार स्वास्थ्य परीक्षा ली जाती है। बच्चों की नेत्र-उपनि, दन्त-चिकित्सा एवं ध्वन-शक्ति के उपचार की विशेष रूप में व्यवस्था होती है।





विविध। इनमें से मध्य का भाविगत कानून बनाने का काम करता है। ये दोनों मिलकर मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करती हैं। यह मन्त्रिपरिषद् ही देश की मता है जो कि देश का शासन करती है। यह अखिल स्वीय मन्त्रिपरिषद् के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य करती है—(अ) सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना, (आ) अनिवार्य विद्या के लिए कानून बनाना, (इ) विद्यालयों को निश्चित करना। यह अखिल स्वीय मन्त्रिपरिषद् शिक्षा के लिए तीन भागों में विभक्त है—(१) अखिल स्वीय जन-शिक्षा विभाग, (२) अखिल स्वीय मस्तिष्क शिक्षा, (३) मस्तिष्क-शिक्षा प्रवर्धन समिति।

इन तीनों में से प्रथम अखिल स्वीय जन-शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा का एक प्रणाली में मान्यता है। इस देश में मान्यता प्रदान होने में मता के कारण में विश्वास किया जाता है।

### सोवियत शिक्षा के स्तर

बाल वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा	उच्चतर शिक्षा (४-६ वर्ष)		माध्यमिक विद्यालय (११ वर्ष) मुख्य शाला में
	माध्यमिक औद्योगिक विद्यालय (४ वर्ष)	माध्यमिक	
	अष्ट वर्षीय	विद्यालय (१० वर्ष)	
	विद्यालय		
किण्टरपार्टन			पूर्व प्राथमिक
मॉडल केन्द्र (केंद्र)			मिडिलरी



पाठ्यक्रम—प्रारम्भिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कहानी, विज्ञान, भूगोल, कृतिक विज्ञान, ऐतिहासिक अवशेषों का निरीक्षण सम्मिलित हैं। शिक्षा का माध्यम तुलना होती है। प्राथमिक विद्यालय की दूसरी कक्षा में ही सभी भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाता है। चौथी कक्षा में सभी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। सोवियत संघ में प्राथमिक विद्यालय दो प्रकार के हैं

- (१) ४ कक्षाओं वाले प्राथमिक विद्यालय,
- (२) ७ कक्षाओं वाले प्राथमिक विद्यालय।

इनमें ४ कक्षाओं तक पाठ्यक्रम समान रहता है। दसमोण क्षेत्रों में ४ कक्षाओं से प्राथमिक विद्यालय अधिक हैं। सप्तवर्षीय विद्यालयों की अंतिम ३ कक्षाओं में छात्रों को व्याकरण, सभी साहित्य, प्राणिशास्त्र और वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र और भौतिक विज्ञान का अध्ययन करवाया जाता है। बच्चों में कलात्मक प्रवृत्ति और स्वा-प्रेम का विकास किया जाता है। मंगोल शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती है।

सब में बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। वर्ष में ३ बार प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य की परीक्षा होती है। रोगी बालक की चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाता है।

प्राथमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अध्यापक पद पर नियुक्त किये जाते हैं। अध्यापक की इच्छा पर ही स्वानान्तरण किया जाता है। अध्यापक शिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है। इनको बालमनोविज्ञान तथा शिक्षण विधियों का ज्ञान कराया जाता है। शिक्षक इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चों का किस स्तर तक विकास हो चुका है। बच्चों की अन्तःप्रेरणा में सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। बच्चों के लिए पाठ्यक्रम महत्वासी क्रियाओं का आयोजन होता है। अध्यापक इनके आयोजन में सहायता देते हैं।

बच्चों को मजदूर एकता का पाठ प्रारम्भ में ही सिखाया जाता है। बच्चों के मन में प्रारम्भ में ही ईश्वर के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाता है। सामुदायिक भावना को विकसित किया जाता है। सामूहिक गान और सामूहिक वाचन करवाये जाते हैं जिससे कि बच्चों में एकता की भावना उत्पन्न हो।

विद्यालय खुले स्थान में होते हैं। इन विद्यालयों में खेलने के लिए मैदान भी रखे जाते हैं। विज्ञान के लिए प्रयोगशालाएँ एवं पुस्तकालय भी होते हैं।

अनिवार्य शिक्षा कानून—१४ अगस्त, १९३० को अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाया गया। इस कानून के द्वारा प्रत्येक बालक के लिए ६ वर्ष शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। सन् १९३४ में सम्पूर्ण देश में सप्तवर्षीय शिक्षा अनिवार्य कर दी। सन् १९४६ में संघ के गाँवों के लिए भी सप्तवर्षीय शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया।

सन् १९५२ में कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ नगरों में १० वर्षीय शिक्षा का कानून लागू कर दिया ।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

- १ इंग्लैण्ड के प्राथमिक शिक्षा के संगठन का वर्णन कीजिए ।
- २ जनिवार्थ शिक्षा को इंग्लैण्ड में किस प्रकार सफल बनाया गया ?
- ३ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय इकाइयों शिक्षा का प्रबन्ध किस प्रकार करती हैं ?
- ४ हमारे देश में स्थानीय समस्याएँ यू० एम० ए० की स्थानीय इकाइयों के अनुभवों में क्या लाभ उठा सकती हैं ?
- ५ संयुक्त राज्य अमेरिका में छात्रों को क्या-क्या सुविधाएँ दी जाती हैं ?
- ६ हम में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किस प्रकार किया गया ? हमारा देश उन उपायों में कैसे लाभ उठा सकता है ?

## अध्याय ४

### बुनियादी शिक्षा

भारतवर्ष की तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों ने गांधीजी के मस्तिष्क में बुनियादी शिक्षा का बीजारोपण किया। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए शिक्षा का उत्तरदायी ठहराया। गांधीजी ने तत्कालीन शिक्षा का दोषपूर्ण माया तथा उसको राष्ट्र-निर्माण के लिए उपयुक्त न समझा। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि "मैं यह अनुभव करता हूँ कि शिक्षा को वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण ही नहीं, हानिकारक भी है। अधिकांश लड़के अपने माता-पिता एवं पशु-पक्षी-पक्षियों को त्याग देते हैं, धुरी जादू को ग्रहण कर लेते हैं। वे जो कुछ भी सीखते हैं उसे शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी कह सकते हैं।" अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ही नहीं थी बल्कि हमने समाज में वर्गभेद पैदा कर दिया। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत में बाबू समाज का निर्माण किया। वे भारतीय बाबू हाथ-पैर में न केवल कुछ करने में असमर्थ थे, परन्तु ऐसा करने में वे अपना अपमान भी समझते थे। गांधीजी की विचारधारा इसके विपरीत थी। उन्होंने एक बार कहा था कि—“मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष की अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। सस्कृति की नींव पर ही शिक्षा का भवन बनाना चाहिए। छात्रों के चलने-फिरने, उठने-बैठने तथा वेशभूषा में सस्कृति का प्रभाव परबलित होना चाहिए।”

देश में दरिद्रता, बेकारी और अशिक्षा का मोलवाला था। अतः महात्मा गांधी सामाजिक तथा आर्थिक संगठन में परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने बगैरीन, स्वावलम्बी, अहिंसक समाज की कल्पना की थी। इस प्रकार के समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने विदेशी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता अनुभव की जिसका आधार भारतीय सस्कृति हो, जो पुस्तकीय न हो बल्कि रचनात्मक कार्यों पर निर्भर

हो, जो धारीरिक धम का प्रतिक्षण दे, जो अधिक व्यग्रपूर्ण न हो। गांधीजी ने ३१ जुलाई सन् १९३७ में 'हार्ग्वन' नामक पत्रिका में शिक्षा के प्रति निम्न विचार प्रकट किये

"शिक्षा में मेरा मतलब है बालक और मनुष्य की सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का सर्वांगीय विकास। साधारणतः स्वयं शिक्षा नहीं है। अतः मैं बालक की शिक्षा का आश्रम उसे एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर करना चाहता हूँ।"

उपयुक्त वर्णन के आधार पर तरकनीन शिक्षा में व्याप्त दोषों का वर्णन सक्षिप्त रूप में इस प्रकार है

- १ शिक्षा का जीवन के व्यावहारिक पक्ष में सम्बन्ध नहीं था।
- २ शिक्षा में सहयोग और सहकारिता को स्थान प्राप्त नहीं था।
- ३ पुस्तक प्रधान शिक्षा थी।
- ४ सम्पूर्ण ज्ञान को सख्त रूप में प्रदान किया जाता था।
- ५ शिक्षा अधिक लचीली थी।
- ६ मानुभाषा की शिक्षा का माध्यम न बनाकर अंग्रेजी की यह गौरवपूर्ण पद प्राप्त था।
- ७ सामान्य जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी।

**वर्धा शिक्षा योजना का जन्म**—२२ अक्टूबर सन् १९३७ को वर्धा में मारवाडी हाई स्कूल की रजत जयंती का समारोह होने जा रहा था। इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों में शिक्षा-शास्त्री तथा विद्वानों को बुलाया गया। इन समारोह में मातृ प्रान्तों के शिक्षा मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया। इन रजत जयंती समारोह को अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का रूप दिया गया। इस अवसर पर गांधीजी ने सभी के समक्ष अपनी वर्धा शिक्षा योजना को स्पष्ट किया। इस सम्मेलन में निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुए

- १ सम्पूर्ण देश में प्रत्येक बालक के लिए ७ वर्ष की अनिवार्य नि-मुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
- २ शिक्षा का माध्यम मानुभाषा रखा जाय।
- ३ किसी उत्पादक हस्तकला के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाय।
- ४ विद्यालय में छात्रों द्वारा किये गये उत्पादन से अध्यापकों के वेतन का प्रबन्ध हो।

**जाकिर हुसैन समिति**—उपयुक्त प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद जामिया मिलिया के उप-कुलपति डा० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। इन प्रस्तावों के आधार पर इस शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना तथा पाठ्यक्रम तैयार करना इस समिति के प्रमुख कार्य थे। इस समिति ने दिसम्बर सन् १९३७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जाकिर हुसैन रिपोर्ट की रूपरेखा—इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की रूपरेखा निम्नलिखित थी

१. सम्पूर्ण ज्ञान का केन्द्रबिन्दु कोई उद्योग होना चाहिए तथा शिक्षा इस उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए।
२. यह योजना स्वावलम्बी है। इस स्वावलम्बन के दो रूप हैं  
(अ) प्रथम तो यह योजना छात्रों को आत्मनिर्भरता का पाठ सिखायेगी,  
(ब) द्वितीय इसने अध्यापक का वेतन भी निकल सकेगा।
३. शारीरिक श्रम अवश्य करवाया जाये जिससे कि वे हाथ में कार्य करने में सक्षम न करें।
४. स्थानीय परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुकूल ही शिक्षा दी जाय।
५. प्रजातन्त्र के लिए उत्तम नागरिक बनाने के अवसर इस शिक्षा योजना में होने चाहिए।
६. शिक्षा का अहिंसामयक रूप होना अति आवश्यक है।  
इसके अनुरित्त इस समिति ने जो सुझाव दिये वे इस प्रकार हैं  
(अ) ७ से १४ वर्ष की आयु के सभी बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाय।  
(आ) पाठ्यक्रम का स्तर अर्बजों को छोड़कर अन्य सब में हाईस्कूल के बराबर रहे।  
(इ) शिक्षण का माध्यम मातृभाषा रहे।  
(ई) किसी हस्तकला के माध्यम से सभी विषयों की शिक्षा दी जाय।

### पाठ्यक्रम का रूप

१. केन्द्रीय दस्तकारी में से एक विषय, जैसे—(अ) कटाई, बुनाई, (आ) बड़ई-सीरी, (इ) फल और सब्जी की बागबानी, (ई) कृषि, (उ) चमड़े का कार्य, (ऊ) अन्य कोई दस्तकारी जो शिक्षाप्रद होने के साथ-साथ स्थानीय वातावरण के अनुकूल हो।
२. मातृभाषा।
३. गणित।
४. सामाजिक अध्ययन (इतिहास—भूगोल—नागरिक शास्त्र)।
५. सामान्य विज्ञान।
६. संगीत और चित्रकला।
७. हिन्दुस्तानी (उर्दू और देवनागरी लिपि द्वारा)।

इस रिपोर्ट को फरवरी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिए रखा। कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपने प्रांतों में इस योजना को कार्यान्वित्त करना प्रारम्भ कर दिया।

परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ होने तथा कांसंगो मंत्रिमंडलों द्वारा स्थापन दिये जाने के कारण यह योजना विधिवत हो गई।

छेर समिति— सन् १९३८ में 'केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड' ने वर्ल्ड के मुख्य पाँच शिक्षा मंत्री थी वी० जो० मेर की अध्यक्षता में इस योजना की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की। प्रथम छेर समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये

- १ बुनियादी शिक्षा को सर्वप्रथम सामोण क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जाय।
- २ ६ में १४ वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य की जाय।
- ३ पाँचवी कक्षा अथवा ११ वर्ष की आयु के बाद ही विद्यार्थी को बुनियादी स्कूल में अन्य स्कूल में जाने की अनुमति दी जाय।
- ४ बुनियादी शिक्षा के अन्त में वास्तु परीक्षा का बन्धन न रखा जाय। जातिरिक्त परीक्षाओं के आधार पर ही प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायें।

द्वितीय छेर समिति—सन् १९३९ में द्वितीय छेर समिति की स्थापना की गई। इसने जो सुझाव दिये वे इस प्रकार हैं

- १ बुनियादी विद्यालयों का पाठ्यक्रम ८ वर्ष का रखा जाय। इसमें प्रथम ५ वर्ष जूनियर बेसिक तथा अन्तिम ३ वर्ष सीनियर बेसिक स्कूल के नाम से पुकारे जायें।
- २ जूनियर बेसिक शिक्षा को समाप्त करने के बाद ही सीनियर बेसिक विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश दिया जाय।
- ३ उच्च बेसिक पाठ्यक्रम में लड़कियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाय।
- ४ स्कूलों में उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक एजेन्सी की स्थापना की जाय।
- ५ बुनियादी विद्यालयों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाय।

सार्जेंट योजना—सन् १९४४ में 'युद्धोत्तर-शिक्षा-युननिर्माण योजना' प्रकाशित हुई। इसी को सार्जेंट योजना के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि तत्कालीन शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने इस योजना के तैयार करने में महत्वपूर्ण भाग लिया था। सार्जेंट ने छेर समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। उन्होंने भी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा के पद पर नई तालीम को बिठाने की सिफारिश की। सार्जेंट ने स्वावलम्बन के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा कभी भी स्वावलम्बी नहीं हो सकती है परन्तु इसके साथ-साथ 'शिक्षा के द्वारा ज्ञान' के सिद्धान्त का समर्थन किया।



**बुनियादी शिक्षा स्थायी समिति**—केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय परिषद् ने अपने २२वें अधिवेशन में एक केन्द्रीय बुनियादी समिति की स्थापना के लिए निर्धारण की। निर्धारण के आधार पर इस समिति को स्थापित किया गया। इस समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

- १ केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को बुनियादी शिक्षा के लिए सलाह देना।
- २ केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्य का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना।
- ३ बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का समाधान अनुसन्धान कार्य द्वारा ढूँढना।

**अनुमान निर्धारण समिति**—सन् १९५५ में केन्द्रीय सरकार ने अनुमान निर्धारण समिति नियुक्ति की। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशों की

- १ बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार को एक केन्द्रीय अनुसन्धान मन्त्रालय की स्थापना करनी चाहिए।
- २ ग्रामों की समाज-सेवा संस्थाओं का सहयोग बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए अति आवश्यक है।
- ३ प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालयों द्वारा उत्तर-स्नातक-प्रशिक्षण महा-विद्यालय स्थापित किये जायें।
- ४ प्रत्येक राज्य सरकार को अल्प समय में अपने राज्य के समस्त प्राथमिक विद्यालयों एवं प्रशिक्षण विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों में बदल देना चाहिए।
- ५ बुनियादी विद्यालयों में उत्तीर्ण छात्रों को हाईस्कूलों में पढ़ाने की पूरी सुविधा देनी चाहिए।
- ६ बुनियादी विद्यालयों में छात्रों को दस्तकारी मिलाने के लिए कुशल कारीगर नियुक्त किये जायें।

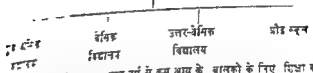
**बुनियादी विद्यालयों के विभिन्न स्तर**—सन् १९८५ में संवत्प्राम में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन बुनियादी शिक्षा के भावी कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में गांधीजी ने अपने भाषण में कहा—

“बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र मात्र नौ चौदह वर्षों के बच्चों को दिला तक हो सीमित नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा मानव-जीवन में सर्वाधान में आरम्भ होकर मृत्युपर्यन्त तक चलती है।”

... का स्तर का निर्धारण उनके बुनियादी विद्यालयों के निम्न स्तर ...

### बुनियादी विद्यालय

स्तर



**प्रारंभिक शिक्षा**—यह वर्ष में कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का स्तर है जो उन्हें आवश्यक है। इस स्तर पर शिक्षा का प्रधान उद्देश्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास करना है। इस शिक्षा का मकसद बालकों के लिए माता-पिता तथा समाज का सहयोग करना है।

**बैंगिक विद्यालय**—यह विद्यालय सात वर्ष से १४ वर्ष तक के बालकों के लिए है। यह अनुसूचित जाति बालकों के अन्तर्गत आते हैं।

**उत्तर-बैंगिक विद्यालय**—इन विद्यालयों की स्थापना १५ से १८ वर्ष तक के बालकों के लिए आवश्यक है। इस शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य ये हैं

१. इस स्तर पर भी दस्तकारी को ही शिक्षा का केन्द्र बनाना चाहिए।
२. छात्रों की विभिन्न रुचियों की समुचित के लिए विचार करना चाहिए।
३. शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा में हो।
४. दस्तकारी ऐसी हो कि प्रत्येक छात्र अपना निजी व्यवसाय कर सके।

**प्रौढ स्कूल**—बुनियादी शिक्षा को मकसद बनाने के लिए आवश्यक है कि बालकों के बचपन के माता-पिता एवं प्रौढ समाज को सहयोग देना चाहिए। यह शिक्षा का महत्व एवं स्वरूप स्पष्ट किया जाना चाहिए।

“मैं चाहता हूँ कि बुनियादी शिक्षा एवं कटाई-बुनाई के मध्य का अन्तर आपको स्पष्ट हो जाय। एक बढ़ई मुझे लकड़ी का काम सिखाता है, मैं इस कार्य को mechanically सीखूँगा और इसके परिणामस्वरूप मैं विभिन्न औजारों का उपयोग सीख जाऊँगा। परन्तु वह मेरा बौद्धिक विकास नहीं करेगा। अगर वही कार्य बढ़ई के कार्य का वैज्ञानिक प्रतिक्षण प्राप्त व्यक्ति मुझे सिखाये तो वह मेरी बुद्धि को भी प्रेरित करेगा। मैं इस प्रकार एक कुशल कारीगर हो नहीं बनूँ एक इंजीनियर भी बन जाऊँगा क्योंकि वह विशेषज्ञ मुझे गणित सिखायेगा, विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ी का अन्तर समझायेगा, स्थान जहाँ मैं बैठे आती हूँ, बताएगा, इस प्रकार भूगोल तथा कृषि का ज्ञान देगा। औजारों के नमूने खींचना तथा ज्यामिति कक्षा सिखायेगा। मानसिक प्रशिक्षण के साथ-साथ शारीरिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए। बुनियादी शिक्षा में बुद्धि को प्रेरित करने को मुख्य साधन शारीरिक श्रम होना चाहिए।”<sup>१</sup>

भारत सरकार ने सन् १९५६ में ‘The Concept of Basic Education’ पुस्तक प्रकाशित कर बुनियादी शिक्षा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इन्होंने भी जाकिर हुसैन समिति द्वारा बुनियादी शिक्षा का स्पष्ट किया गया रूप ही स्वीकार किया है। यहाँ पर बुनियादी शिक्षा की कुछ विशेषताओं को स्पष्ट किया जा रहा है

(१) बुनियादी शिक्षा जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा है। अहिंसक समाज का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इसीलिए उत्पादक, रचनात्मक एवं समाज के लिए उपयोगी कार्य को बुनियादी शिक्षा का आधार बनाया है जिसको सभी जाति एवं वर्ग के लड़के एवं लड़कियाँ निःशर्क रूप में करें।

(२) किसी दम्नकारी या प्रभावशील अध्यापन केवल सम्बन्धित ज्ञान को अर्जित करने तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि यह छात्रों के चरित्र एवं व्यक्तित्व के विकास में अधिक सहयोग देता है। इसके अध्यापन में बालकों में समाज के लिए उपयोगी कार्यों के प्रति सम्मान एवं प्रेमभाव पैदा किया जाता है। छात्रों द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं के विग्रह में प्राप्त घन विद्यालय को चमकाने, भव्यान्न भोजन, कुर्मी, मेज या अन्य सामान के खरीदने पर ध्यान दिया जायेगा।

(३) दस्तकारी या चमन करने में उदारता की आवश्यकता है। ऐसी दम्नकारी को चुनना चाहिए जो बौद्धिक विकास में तथा ज्ञान-बुद्धि में सहयोग दे तथा कार्य-क्षमता में निपुण बनाये। इसके साथ-साथ दस्तकारी विद्यालय के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। जहाँ यह धारणा कि कटाई-बुनाई प्रारम्भ करने में ही बुनियादी विद्यालय हो गया, पूर्णतः गलत है।

(४) बुनियादी शिक्षा में ज्ञान का सम्बन्ध क्रिया, व्यावहारिक अनुभव और निरीक्षण से स्थापित करना चाहिए। ज्ञान सम्बन्धित रूप में प्रदान करना चाहिए। इसीलिए पाठ्यक्रम के विषयों को महसम्बन्ध के तीन केन्द्र— हस्तकला, प्राकृतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण—में सम्बन्ध स्थापित करते हुए पढ़ाना चाहिए। अगर अध्यापक ऐसा नहीं करता है तो इसका कारण यह है कि या तो अध्यापक में आवश्यक योग्यता का अभाव है या पाठ्यक्रम में अनावश्यक चीजें सम्मिलित करदी है जो इस स्तर के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। जहाँ पर महसम्बन्ध द्वारा पढ़ाना सम्भव न हो तो अध्यापक को forced correlation स्थापित न करके अन्य किसी विधि द्वारा अध्यापन करना चाहिए।

(५) किसी उत्पादक कार्य या दस्तकारी पर विशेष धन देने में तात्पर्य यह नहीं है कि बुनियादी विद्यालय में पाठ्य पुस्तक के अध्ययन की अवहेलना की जाय। अतः अन्य विद्यालयों की भाँति ही बुनियादी विद्यालय में उत्तम पुस्तकालय का होना आवश्यक है।

(६) बुनियादी शिक्षा विद्यालय तथा समाज के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है जिससे कि बच्चों को सामाजिकता एवं सहयोग का ज्ञान कराया जा सके। बुनियादी विद्यालयों में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। दूसरे, छात्रों को स्थानीय समाज में कुछ सामाजिक कार्य करना चाहिए। बुनियादी विद्यालयों में छात्रों को प्रजातन्त्रीय जीवन की शिक्षा देने के लिए छात्र मण्डल का निर्माण किया जाय।

### विभिन्न दर्शन और बुनियादी शिक्षा

शिक्षा पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता रहा है। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद प्रमुख विचारधाराएँ हैं जिन्होंने समय-समय पर शिक्षा के उद्देश्य, रचना तथा पद्धति को प्रभावित किया है। बुनियादी शिक्षा का अध्ययन करने में ज्ञात होता है कि गांधीजी भी इनवादों में प्रभावित हुए और उन्होंने बुनियादी शिक्षा में इन तीनों विचारधाराओं को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया।

**प्रकृतिवाद-** रूसो, पेस्टालोजी तथा हर्बर्ट स्पेंसर आदि दार्शनिक इस विचारधारा के पोषक माने जाते हैं। ये बालक को मनुष्य का सधु रूप नहीं मानते हैं। उनका स्वयं का अपना ही व्यक्तित्व होता है। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एमील' में अपने शिक्षा सम्बन्धी विचार प्रकट किये हैं। प्रचलित दमनात्मक शिक्षा का विरोध करते हुए रूसो ने कहा है—“उम शिक्षा कोई नाश नहीं जो बालक की क्षमताओं और रुचियों के अनुकूल नहीं होती है। ऐसी शिक्षा को वनपूर्वक बालक पर थोपना, उसके साथ अभ्यास करना है। यह तो पशुओं की ही शिक्षा हो गई।” रूसो ने बाल-केन्द्रित शिक्षा पर बल दिया है। उसके अनुसार बालक की प्राकृतिक क्षक्तियों और रुचियों

का स्वतंत्र रूप में विकास ही सच्ची शिक्षा है। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक को समाज में दूर हो रखना चाहिए, क्योंकि बालक सभी बुराइयों को समाज में भीखता है। हमों का मत था कि "परमात्मा सब कुछ अच्छा ही उत्पन्न करता है परन्तु मनुष्य ही उसको बिगाड़ देता है।" इसलिए वह बालक का शिक्षण समाज में दूर रखकर प्रकृति की गोद में चाहना था।

गांधीजी भी रुढ़िगत शिक्षा-प्रणाली एवं शिक्षण-विधियों के विरुद्ध थे। वे भी प्रकृतिवादियों की भाँति बच्चे के स्वतंत्र व्यक्तित्व में विश्वास रखते थे। यहाँ गांधीजी का हमों में केवल एक स्थान पर मतभेद है। गांधीजी समाज को प्रधानता देते थे। उनके अनुसार मनुष्य समाज में रहकर ही अपनी विशेषताओं का विकास कर सकता है। गांधीजी भी हमों की भाँति प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम में कर्मेन्द्रियों और उनके द्वारा ज्ञानेन्द्रियों के शिक्षण के समन्वय के पक्षपाती थे। इसीलिए बुनियादी शिक्षा रचना में प्रकृतिवादी है।

**आदर्शवाद—**आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक मुकरान, प्लेटो, कान्ट, फिजे आदि हैं। इन्होंने भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मिकवाद पर अधिक बल दिया है। आदर्शवादी विचारधारा का शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रभाव है

(अ) आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य आत्म-साक्षात्कार (Self-realization) ही है।

(आ) प्रकृतिवाद के विपरीत आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति की समस्त सुपुष्प शक्तियों का विकास एक समाज में ही हो सकता है क्योंकि वह समाज का एक अंग होता है।

(इ) बालक का सर्वांगीण विकास अथवा व्यक्तित्व का मनुष्यिक विकास करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। बालक का विकास शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों में होना आवश्यक है।

(ई) आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति ही शिक्षा का लक्ष्य है। मर्य, शिव, मुन्दरम की अनुभूति कराना आवश्यक ही नहीं परन्तु अनिवार्य भी है।

(उ) आदर्शवादी विद्यालय को एक बाग, बालक को एक कोमल पौधा तथा अध्यापक को मानी मानता है।

गांधीजी आदर्शवाद में अधिक प्रभावित हुए। उनके अनुसार अपने ईश्वर का जगाकर सृष्टि के माय एकाकार कर देना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गांधी जी ने समाज को प्रधानता देते हुए कहा है कि जो ईश्वर की पूजा करना चाहता है वह सामाजिक सेवा कार्यों में लगे। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों में चरित्र के विकास पर विशेष जोर दिया। आध्यात्मिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया। गांधीजी आदर्शवादियों की भाँति मनुष्यिक व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। उपर्युक्त वर्णन में स्पष्ट है कि बुनियादी शिक्षा उद्देश्यों में आदर्शवादी है।

(४) बुनियादी शिक्षा में ज्ञान का सम्बन्ध क्रिया, व्यावहारिक अनुभव और निरीक्षण में स्थापित करना चाहिए। ज्ञान समन्वित रूप में प्रदान करना चाहिए। इसीलिए पाठ्यक्रम के विषयों को मह्यम्बन्ध के तीन केन्द्र—हस्तकला, प्राकृतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण—से सम्बन्ध स्थापित करते हुए पढ़ाना चाहिए। अगर अध्यापक ऐसा नहीं करता है तो इसका कारण यह है कि या तो अध्यापक में आवश्यक योग्यता का अभाव है या पाठ्यक्रम में अनावश्यक चीजें सम्मिलित कर दी हैं जो इन स्तर के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। जहाँ पर मह्यम्बन्ध द्वारा पढ़ाना सम्भव न हो तो अध्यापक को forced correlation स्थापित न करके अन्य किसी विधि द्वारा अध्यापन करना चाहिए।

(५) किसी उत्पादक कार्य या दस्तकारी पर विशेष बल देने से तात्पर्य यह नहीं है कि बुनियादी विद्यालय में पाठ्य पुस्तक के अध्ययन की अवहेलना की जाय। अतः अन्य विद्यालयों की भांति ही बुनियादी विद्यालय में उत्तम पुस्तकालय का होना आवश्यक है।

(६) बुनियादी शिक्षा विद्यालय तथा समाज के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देना है जिसमें कि बच्चों को सामाजिकता एवं सहयोग का ज्ञान करा जा सके। बुनियादी विद्यालयों में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। दूसरे, छात्रों को स्थानीय समाज में कुछ सामाजिक कार्य करना चाहिए। बुनियादी विद्यालयों में छात्रों को प्रजातन्त्र जीवन की शिक्षा देने के लिए छात्र मण्डल का निर्माण किया जाय।

### विभिन्न दर्शन और बुनियादी शिक्षा

शिक्षा पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता रहा है। प्रगतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद प्रमुख विचारधाराएँ हैं जिन्होंने समय-समय पर शिक्षा के उद्देश्य, रचना तथा पद्धति को प्रभावित किया है। बुनियादी शिक्षा का अध्ययन करने में ज्ञान होता है कि गांधीजी भी इन बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने बुनियादी शिक्षा में इन तीनों विचारधाराओं को समन्वित करने का प्रयत्न किया।

प्रगतिवाद रूसो, पेस्टालोन्जी तथा हर्बर्ट स्पेंसर आदि दार्शनिक इस विचारधारा के पोषक माने जाते हैं। ये बालक को मनुष्य का लघुरूप नहीं मानते हैं। उनका स्वयं का अपना ही व्यक्तित्व होता है। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एमील' में अपने शिक्षा सम्बन्धी विचार प्रकट किये हैं। प्रचलित दमनात्मक शिक्षा का विरोध करी हुए रूसो ने कहा है—“यह शिक्षा कोई मांस नहीं जो बालक की क्षमताओं और गरिमा के अनुकूल नहीं होती है। ऐसी शिक्षा को बलपूर्वक बालक पर थोपना, उसके मांस अन्धकार करना है। यह तो पशुओं की भी शिक्षा हो गई।” रूसो ने बाल-वैज्ञान शिक्षा पर बल दिया है। उसके अनुसार बालक की प्राकृतिक क्षमता और रसिकता

का स्वतन्त्र रूप में विकास ही मक़्सी शिक्षा है। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक को समाज से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बालक सभी बुराइयों को समाज में सीखता है। हमों का मत था कि "परमात्मा सब कुछ अच्छा ही उत्पन्न करता है परन्तु मनुष्य ही उसको बिगाड़ देता है।" इसलिए वह बालक का शिक्षण समाज से दूर रखकर प्रकृति की गोद में चाहता था।

गांधीजी भी सृजित शिक्षा-प्रणाली एवं शिक्षण-विधियों के विरुद्ध थे। ये भी प्रकृतिवादियों की भाँति बच्चे के स्वतन्त्र व्यक्तित्व में विद्वत्ता रखते थे। यही गांधीजी का हमों में केवल एक स्थान पर मनभेद है। गांधीजी समाज को प्रधानता देते थे। उनके अनुसार मनुष्य समाज में रहकर ही अपनी विशेषताओं का विकास कर सकता है। गांधीजी भी हमों की भाँति प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम में बर्मेन्द्रियों और उनके द्वारा ज्ञानेन्द्रियों के शिक्षण के समन्वय के पक्षपाती थे। इसी-लिए बुनिवादी शिक्षा रचना में प्रकृतिवादी है।

आदर्शवाद—आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक मुकरान, प्लेटो, कान्ट, फ्रिंके आदि हैं। इन्होंने भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मिकवाद पर अधिक बल दिया है। आदर्शवादी विचारधारा का शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रभाव है

(अ) आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य आत्म-साक्षात्कार (Self-realization) ही है।

(आ) प्रकृतिवाद के विपरीत आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति की समस्त सुपुन्य गतिधियों का विकास एक समाज में ही हो सकता है क्योंकि वह समाज का एक अंग होता है।

(इ) बालक का सर्वांगीण विकास अथवा व्यक्तित्व का मनुजित विकास करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। बालक का विकास शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों में होना आवश्यक है।

(ई) आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति ही शिक्षा का लक्ष्य है। मर्य, शिव, मुन्दरम् की अनुभूति करना आवश्यक ही नहीं परन्तु अनिवार्य भी है।

(उ) आदर्शवादी विद्यालय को एक वाग, बालक को एक कोमल पौधा तथा अध्यापक को माँगी मानता है।

गांधीजी आदर्शवाद में अधिक प्रभावित हुए। उनके अनुसार अपने ईश्वर को जगाकर सृष्टि के माय सृकाकार कर देना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गांधी जी ने समाज को प्रधानता देते हुए कहा है कि जो ईश्वर की पूजा करना चाहता है वह सामाजिक सेवा कार्यों में लगे। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों में धर्म के विकास पर विशेष जोर दिया। आध्यात्मिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया। गांधीजी आदर्शवादियों की भाँति मनुजित व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। उपर्युक्त वर्णन में स्पष्ट है कि बुनिवादी शिक्षा उद्देश्यों में आदर्शवादी है।

**प्रयोजनवाद**—प्रयोजनवादी अच्छा उमी को मानते हैं जो उपयोगी हो। डीवी, फिजिकल तथा जेम्स इस विचारधारा के पापक हैं। प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धान्त ये हैं

(अ) विचार की अपेक्षा क्रिया पर जोर दिया जाता है। ये पुस्तकीय शिक्षा के विरुद्ध है। ये शालक को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में रतकर अनुभव अर्जित करने का प्रतिक्षण देने हैं। (आ) प्रयोजनवादी सामाजिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार करते हैं। इसीलिए विद्यालय को समाज का एक रूप मानते हैं। (इ) शालक स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण वातावरण के अनुसार करता है।

गांधीजी ने भी प्रयोजनवाद की भाँति 'क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करने' के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। इसीलिए उत्पादक उद्योगों को बुनियादी शिक्षा में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ये समवाय द्वारा ज्ञान को समन्वित रूप में देने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार, विभिन्न विषयों को पृथक् रूप में नहीं पढ़ाना चाहिए। बुनियादी शिक्षा की पद्धति प्रयोजनवाद के सिद्धान्तों के अनुसार ही है।

### बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त

(१) राष्ट्रवादी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा—देश की तत्कालीन सामाजिक दशा ने गांधीजी में इस विचार का बीजारोपण किया कि भारतवर्ष में शिक्षा का प्रसार किये बिना देश का हित नहीं है। शिक्षित व्यक्तियों में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना का विकास शीघ्र किया जा सकता है। शिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा शिक्षित वर्ग को पराधीनता की बुराइयों का ज्ञान शीघ्र कराकर देश में राजनीतिक एवं सामाजिक प्रगति लाई जा सकती है। अतः गांधीजी इस बात के पक्षपाती थे कि देश में सार्वभौमिक शिक्षा होनी चाहिए। गांधीजी ने इस योजना के अन्तर्गत ७ से १४ वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का आयोजन रखा। प्रजातन्त्र की सफलता शिक्षा प्रसार पर ही निर्भर रहती है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से चला सकते हैं। गांधीजी का कथन था कि "जनमाधारण की अनिच्छा भारत का पाप और कलक है। अतः उसका अन्त करना आवश्यक है।"

(२) हस्तकला द्वारा शिक्षा—भारत के लिए नवीन शिक्षा की रूप-रेखा प्रस्तुत करते हुए गांधीजी ने ३१ जुलाई मन् १९३७ के 'हरिजन' में लिखा था— "माधुरता स्वयं शिक्षा नहीं है। अतः मैं बच्चे की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर और जिस समय में वह अपनी शिक्षा प्रारम्भ करता है, उसे उत्पादन करने योग्य बनाकर प्रारम्भ करना चाहता हूँ।" केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है परन्तु इसके साथ-साथ हाथों को शिक्षित करने में ही पूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। अतः हाथ-वर्क की शिक्षा बुद्धि की शिक्षा के साथ होनी चाहिए।



हस्तकला की शिक्षा से छात्रों में नैतिक और आत्मिक शक्तियों का विकास होगा। उनमें आत्म-विश्वास का गुण पैदा होगा। इनके द्वारा दारिद्र्यिक श्रम के प्रति घृणा की भावना कम होगी तथा बालक आत्मनिर्भर बन सकेगा। शिक्षा को अधिक मर्चाली बनने में रोका जा सकता है।

(३) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा—बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम रखा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि बालक स्वाभाविक रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। यह अपने विचारों को भी सभ्यता में अभिव्यक्त कर सके। अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाने में छात्रों का बहुत सा समय इस भाषा को सीखने में लगता था। इसने पर भी अंग्रेजी भाषा पर अधिकार नहीं हो पाता है। मातृभाषा के माध्यम होने पर बालक अपने समय तथा शक्ति को दूसरे कार्यों में लगा सकते हैं। अंग्रेजी भाषा को माध्यम रखने में बालक में मानसिक दमना का जन्म होता है। अपने देश की सम्प्रदाय तथा संस्कृति को समझने तथा उनको विकसित करने के लिए भारतीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाना उपयुक्त है।

(४) स्वावलम्बी शिक्षा—बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण मिश्रण शिक्षा का स्वावलम्बी होना है। गांधीजी का कथन था कि—“शिक्षा को स्वावलम्बी होना चाहिए अर्थात् शिक्षा से पूँजी के अनिर्भर बह सव धन मिल जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया गया है।” शिक्षा में आत्मनिर्भरता आने का प्रमुख कारण देश की निर्धनता थी। जब भी भारतीयों ने शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अंग्रेजों में माँग की तो उन्होंने धन की कमी बताने हुए माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया। गांधीजी का विश्वास था कि स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार को ही शिक्षा का प्रबंध करना होगा। अनेक क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण कार्य करने में सरकार शिक्षा पर पर्याप्त धन व्यय नहीं कर सकती है, अतः शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। यहाँ स्वावलम्बी शिक्षा में दो तात्पर्य हैं—प्रथम, शिक्षाकाल में बालक में जीवनोपार्जन की क्षमता का विकास करना जिससे कि वह भी शिक्षित वर्ग में बेकारी की समस्या का शिकार न हो जाय, दूसरे अर्थ में, शिक्षा के स्वावलम्बन में तात्पर्य है कि छात्रों द्वारा निर्मित संस्थानों के बचने पर होने वाली आय में अध्यापकों का वेतन या अन्य व्यय चल सके।

(५) शिक्षा का जीवन से सम्बन्धित होना—ग्राहिर ह्यूमन समिति के अनुसार “जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, हमने इस मिश्रण पर विशेष बल दिया है कि सब प्रकार की शिक्षा वास्तविक जीवन के दृग्ग, उसे हस्तकला जैसा सामाजिक और भौतिक वातावरण में सम्बन्धित करके ही दी जाय।” नत्कालीन शिक्षा का प्रमुख दोष यह था कि यह अपने इस उद्देश्य की अवहेलना कर रही है कि छात्र को भावी जीवन के लिए वास्तविक परिस्थितियों एवं वातावरण में रमकर प्रशिक्षण दिया जाय। इसमें केवल बौद्धिक शक्तियों के विकास को ही महत्व प्रदान किया जाता है। गांधीजी चाहते थे कि शिक्षा जीवन में पूर्णतः सम्बन्धित होनी चाहिए। हस्तकला के

चुनाव के लिए उनका विचार था कि यह बालक के स्थानीय एवं सामाजिक वातावरण में से चुनी जानी चाहिए।

(६) सहसम्बद्ध शिक्षण—बुनियादी शिक्षा में सहसम्बद्ध शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें सभी विषयों को हस्तकला पर केन्द्रित करके पढ़ाया जाता है। इसीलिए बुनियादी शिक्षा को हस्तकला-प्रधान शिक्षा कहते हैं। विभिन्न हस्तकलाओं में एक-दो हस्तकलाओं का चयन करके बालक उन पर कार्य प्रारम्भ करता है। अध्यापक इन हस्तकलाओं में अन्य विषयों को सम्बन्धित करके ज्ञान प्रदान करता है। ऐसा करने में विषय सरलता में समझ में आ जाता है।

(७) स्वतन्त्रता प्रधान प्रणाली—वर्तमान शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि इसमें परीक्षा उत्तीर्ण करने का लक्ष्य होने में छात्रों को मुख्य तथ्यों को रटने का प्रोत्साहन दिया जाता है। छात्र रचनात्मक कार्य करने तथा आत्म-अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बुनियादी शिक्षा में अध्यापक एक छात्रों को कार्य करने की स्वतन्त्रता रखती है। अध्यापक को अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने एवं नवीन शिक्षण विधियों के अनुसार प्रस्थापन करने की स्वतन्त्रता रहती है। छात्रों को स्वतन्त्र रूप में हस्तकला का कार्यक्रम बनाने और उसको कार्यान्वित करने को छूट रहती है। इसमें उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है तथा अपनी गति के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है।

(८) नागरिकता का आदर्श—बुनियादी शिक्षा में बालक को एक कुशल नागरिक बनने के प्रशिक्षण हेतु अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। भारत जैसे प्रजातन्त्रीय देश के लिए, ऐसे कुशल नागरिकों का होना अनिवार्य आवश्यक है जो अपने कर्तव्य एवं अधिकारों को भली प्रकार समझते हों। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को मानसिक, नैतिक, कलात्मक एवं शारीरिक शक्तियों का विकास करे। बुनियादी शिक्षा में इन सभी क्षेत्रों के विषय पर ध्यान दिया जाता है। प्रजातन्त्र की सफलता एवं समाज को भलाई के लिए ऐसे नागरिक पैदा करने चाहिए जो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं प्रेम रखते हों तथा आत्म-समय एवं सहनशीलता के गुणों का विकास हों। बुनियादी शिक्षा हस्तकला के माध्यम से इन गुणों के विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। छात्र जब किसी क्रिया में सामूहिक रूप में भाग लेते हैं तो वे अपने कर्तव्य को भीषते हैं तथा उनमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने की इच्छा बढ़ती है।

(९) अहिंसा—बुनियादी शिक्षा का अंतिम आधारभूत सिद्धान्त है—अहिंसा। यहाँ अहिंसा में तात्पर्य प्रत्येक प्राणी में सहानुभूति एवं प्रेम उत्पन्न करना, धनी एवं निर्धन व्यक्तियों का भेद समाप्त करना और उच्च तथा निम्न वर्गों में समता लाना है। बुनियादी शिक्षा में छात्र श्रिया को समूह में पूरा करने में सहयोग की भावना में प्रेरित होते हैं। उनमें यह विचार समाप्त हो जाता है कि कोई भी हस्त उपयोग किसी जानि में सम्बन्धित है। जानि-भावना तथा ऊँच-नीच की भावना समाप्त होती है।

क्योंकि सभी वर्गों के छात्र उम्र क्रिया में बिना भेद-भाव के भाग लेते हैं। ऐसे छात्र सुयोग्य नागरिक बनकर अहिंसा की भावना पैदा करेंगे। अहिंसा तो व्यवहार में प्रकट होनी चाहिए और जीवन के अन्तिम व्यवहार तक उसका अस्तित्व रहना चाहिए। बुनियादी शिक्षा इस लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक सहयोग दे सकेगी।

### बुनियादी शिक्षा की वर्तमान स्थिति

बुनियादी शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन दो आधारों पर किया जाएगा

(अ) सख्यात्मक विकास, (आ) गुणात्मक विकास।

(अ) सख्यात्मक विकास (Quantitative Expansion)—स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व अंग्रेजों की दोषपूर्ण एवं अवहेलनापूर्ण नीति के कारण बुनियादी शिक्षा का अधिक प्रसार न हो सका। द्वितीय विश्वयुद्ध ने भी इस नवीन प्रयोग की मफलता-पूर्वक लागू करने में बाधा उत्पन्न कर दी। भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने के बाद यहाँ की केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों ने इसको राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली घोषित कर दिया। इस घोषणा ने प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष निधि रखने के लिए योजना आयोग के मदस्यों को बाध्य किया। निम्न तालिका से बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में किये गए प्रयत्नों के परिणाम स्पष्ट हैं

सन् १९५०-५१ से बुनियादी शिक्षा की प्रगति

बुनियादी विद्यालय	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६ (लक्ष्य)
<b>१. विद्यालय</b>				
(अ) जूनियर बेसिक स्कूल	३३,३७६	४२,६७१	१,००,०००	१,५३,०००
(आ) कुल प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर बेसिक स्कूलों का प्रतिशत	१५.६	१५.४	२६.२	३६.६
(इ) सीनियर बेसिक स्कूल	३८८	४,८४२	११,६४०	१६,७००
(ई) कुल माध्यमिक विद्यालयों में सीनियर बेसिक स्कूलों का प्रतिशत	२.६	२२.३	३०.२	२८.६
<b>२. छात्र</b>				
(अ) कक्षा प्रथम में आठ तक के छात्रों की संख्या (नामों में)	२२.७	२६.४६	४०.६३	५६.३६

(आ) कक्षा प्रथम में जाठ तक के  
कुल छात्रों का बुनियादी  
विद्यालयों में प्रतिशत

१३१

१७२

२३३

—

३. बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय  
(अ) बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों  
की संख्या

११८

४२०

७१५

१४२८

(आ) कुल प्रशिक्षण संस्थानों में  
बुनियादी प्रशिक्षण संस्थानों का  
प्रतिशत

१५

५६

७०

१००

तालिका में स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर बेसिक विद्यालयों का प्रतिशत १५.६ में घटकर १५.८ हो रहा गया। परन्तु द्वितीय योजना में यह प्रतिशत बढ़कर २६.२ हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इनकी वृद्धि की गति द्वितीय योजना में भी कम रहेगी जैसा कि तालिका में अंकित लक्ष्य में स्पष्ट है। इसमें स्पष्ट है कि जिस गति में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ेगी उस अनुपात में जूनियर बेसिक स्कूल नहीं बढ़ेंगे। सीनियर बेसिक विद्यालयों की दशा इसमें भी अधिक शोचनीय है। १९५०-५१ में प्रथम योजना में २२.३ प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु द्वितीय योजना में ३०.२ प्रतिशत वृद्धि हुई। तीसरी योजना के लक्ष्य के अनुसार यह प्रतिशत द्वितीय योजना में १.३ प्रतिशत कम है। इसमें स्पष्ट है कि सीनियर बेसिक स्कूलों की ओर सरकार का ध्यान अधिक नहीं है।

बुनियादी शिक्षा जो कि सार्वभौमिक शिक्षा कहलाती है, प्रथम तीन योजनाओं में मनोपजनक प्रगति नहीं कर सकी। प्रथम योजना में प्रथम में आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले कुल छात्रों के केवल १७.२ प्रतिशत छात्र ही बुनियादी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे। यह प्रतिशत द्वितीय योजना में २३.३ हो गया। मन् १९५५-५६ में ६ वर्ष में १४ वर्ष की आयु के सभी बालकों का ८० प्रतिशत भाग परम्परागत विद्यालयों में पढ़ रहा था। १९६०-६१ में यह ४८.३ प्रतिशत हुआ और १९६५-६६ में ६० प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। बुनियादी विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले का प्रतिशत प्रथम योजना में ४.१ से बढ़कर ६.६ हुआ। इस प्रकार २.५ प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि परम्परागत विद्यालयों में ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यही बात द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं के बारे में है। इसमें स्पष्ट है कि प्रथम दो योजनाओं में बुनियादी शिक्षा को प्रगति परम्परागत शिक्षा के समान भी नहीं हुई।

बुनियादी शिक्षा के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है सरकार ने बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना के क्षेत्र में प्रगति का कार्य किया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी प्राथमिक अध्या-

अथ विद्यालयों को बुनियादी शिक्षा के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रहा । परन्तु मुख्यतमक विकास में गुणात्मक विकास में महयोग नहीं मिल रहा है । कारण यह है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण को वर्तमान दसाएँ सतोपजनक नहीं प्रशिक्षण विद्यालयों में योग्य अध्यापकों का अभाव, भवन तथा साज-सामान की है । प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम भी उच्चकोटि का नहीं है ।

(आ) गुणात्मक विकास (Qualitative Development)— बुनियादी शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक विकास की ओर सरकार का विशेष ध्यान नहीं है । अनेक प्रान्तों विद्यालयों का नाम परिवर्तित करके बुनियादी विद्यालय कर दिया है । परन्तु उनमें भी को बुनियादी पाठ्यक्रम उपयुक्त शिक्षण विधियों के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है । विद्यालयों में हस्तकला के स्थान पर नकली से केवल बनाई का काम कराया जाता है । इससे स्पष्ट है कि हस्तकला के सम्बन्ध में ही गहन धारणाएँ पैदा हो गई । कुछ व्यक्ति कहते हैं कि उत्पादक कार्य के अन्तर्गत उपयोगी वस्तुओं का निर्माण या चाहिए जबकि दूसरे लोगों का विचार है कि यह भी नैव विधि का ही दूसरा नाम है । बुनियादी विद्यालयों के अध्यापकों को सह-सम्बन्ध विधि का पर्याप्त ज्ञान होना है । वे समवाय विधि का प्रयोग ठीक प्रकार में नहीं कर पाते हैं । इस क्षेत्र महान अनुसंधान कार्य की आवश्यकता है ।

### बुनियादी शिक्षा की समस्याएँ व कठिनाइयाँ

यहाँ उन सभी कठिनाइयों पर विचार करना उर्कमग्न होया जिनके कारण बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक सफलता एवं प्रगति न हो सकी ।

(१) धन का अभाव—गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में कहा था : “यह तो एक स्वावलम्बी शिक्षा प्रणाली है । छात्रों में विद्यालय में हस्तकला के रूप में कुछ उत्पादन कार्य करवाया जायेगा । इस प्रकार छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं के बने में विद्यालय को जो आय होगी उससे अध्यापकों का वेतन निकल सकेगा ।” परन्तु बुनियादी विद्यालयों का सर्वेक्षण करने में पता चला है कि इन बातों की कोई सम्भावना नहीं कि बुनियादी विद्यालय आत्मनिर्भर हो सकें । मन् १९५०-५१ में काङ्ग्रेस के बुनियादी विद्यालय का अध्ययन करने में जान हुआ कि वह विद्यालय ६६ शिक्षक तक ही आत्मनिर्भर था जबकि उसका सम्पूर्ण भारत में बाएर्थ विद्यालय माना जाता है । मन् १९५८ में बुनियादी शिक्षा की द्वितीय राष्ट्रीय समीक्षा के अवसर पर विनोबाजी ने कहा कि १४ वर्ष तक की आयु के छात्रों को शिक्षा पर व्यय करना राज्य का उत्तरदायित्व है । अब विद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादक काम को माध्यम नहीं बनाना चाहिए । बुनियादी शिक्षा में परम्परागत शिक्षा में अपेक्षा अधिक धन की आवश्यकता होती है । इस समय तीन प्रकार के कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है—(१) सामान्य ज्ञानों को बुनियादी शालाओं में बदलना, (२) नवीन बुनियादी विद्यालय खोलना, और (३) अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के

विषय। परन्तु भारत सरकार पर्याप्त धन व्यय नहीं कर पा रही है। इसका कारण हमारा देश में अनेक विधायक कार्यों का जाना है।

(२) अध्यापक बुनियादी शिक्षाविद्यालयों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की भी गण संख्या है। इसके लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो विभिन्न विषयों का किसी हस्तकार्य में सम्बन्धित करके पढ़ा सकें। बुनियादी शिक्षा के अध्यापक को बालक तथा स्थानीय समाज के प्रति उचित अभिवृत्ति रखनी चाहिए। उसे बालक में रुचि पैदा करनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा के लिए ऊँची योग्यता का व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों को जीवन की सामाजिक परिस्थितियों में रसकर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ-साथ अध्यापक समाज की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हो। सर्व शिक्षाओं का प्रजातन्त्रीय नागरिक बनने में सहायता दे सकें। कम वेतन, समाज में दृष्टि में देखना आदि कारणों में योग्य व्यक्ति इन व्यवसायों को ओर आकर्षित ही नहीं होते हैं। सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ है कि अधिपत्तर दबी बच्चा उत्तीर्ण व्यक्ति ही अध्यापन कार्य कर रहे हैं। अनेक प्रान्तों में केवल एक ही वर्ष का प्रशिक्षण योग्य है। यह जबकि कम है।

(३) सरकार की उदासीनता—सरकार की उदासीनता के कारण सरकार प्राथमिक बेमिक शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान नहीं दे रही है। बच्चों को भी आज भी सरकार अपना ध्यान उच्च शिक्षा की ओर केन्द्रित किये हुए है। यह इसमें स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए तो आयोगों की नियुक्ति की, परन्तु इन आयोगों ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई सुझाव नहीं दिए जबकि यह स्तर ही उच्च शिक्षा का आधार है।

(४) बेमिक शिक्षा के प्रति जनता की धारणा—बुनियादी शिक्षा के प्रति भारतीय जनता की उचित धारणा न होने में अभी तक ये लोग परम्परागत चली आ रही शिक्षा प्रणाली को प्रधानता देते हैं। उनको बेमिक शिक्षा का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है। कर्ताई-बुनाई को ही वे बुनियादी शिक्षा मानते हैं। परिणामस्वरूप, उनका विश्वास बन गया है कि अगर बच्चों को विद्यालय में कर्ताई-बुनाई के लिए भेज तो इसमें अच्छा है कि घर पर ही उनमें कार्य करवायें। सरकार ने बेमिक शिक्षा के विषय में साधारण जनता को कुछ भी नहीं समझाया।

(५) उच्च वर्ग के व्यक्तियों का दृष्टिकोण—निम्नवर्ग के व्यक्ति सर्वत्र उच्चवर्ग के व्यक्तियों का अनुकरण करने आये हैं। भारतवर्ष में आज भी उच्च वर्ग के व्यक्ति अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल तथा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं जबकि वे ही लोग बेमिक शिक्षा के महत्त्व पर लम्बे-लम्बे भाषण देते हैं। ये लोग अपने बच्चों का जनसाधारण के बच्चों के साथ वर्ग-विभेद के कारण पढ़ाना पसन्द नहीं करते हैं। अभी तक उच्च वर्ग के लोग धार्मिक धर्म को धृष्टा की दृष्टि में देखते हैं। कुछ व्यक्ति बेमिक शिक्षा प्रणाली को राजनीति के प्रभाव में भी धृष्टा करने लगे हैं। अन्य राजनीतिक दलों के लोग बेमिक शिक्षा को कांग्रेस को देव

समझते हैं। अतः ये लोग अपने राजनीतिक विचारों का प्रचार करने समय जन-साधारण में बुनियादी शिक्षा को आलोचना करके जनता धारणा पैदा करने हैं। साम्यवादी इस योजना का विरोध करने हैं। उनके विरोध का कारण हस्तकलाएँ हैं जो कि उनके मतानुसार समय के अनुकूल नहीं हैं। वे तो अब मशीनों की प्राथमिकता देते हैं। अब तक जनता में से ऊँच-नीच का भेद-भाव समाप्त नहीं होता तथा गन्दा राजनीतिक प्रचार बन्द नहीं होता तब तक बेमिक स्कूल समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगे।

(६) प्रशासन सम्बन्धी—बुनियादी शिक्षा को प्रशासनिक वर्ग की भी महानुभूति प्राप्त नहीं हो सकी। यहाँ के प्रशासनिक कर्मचारियों ने इस नवीन योजना में कोई रुचि ही नहीं ली जबकि किसी भी योजना की सफलता या असफलता प्रशासन पर निर्भर रहती है। नवीन योजना होने में इसे कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाईएँ एक समस्याएँ आने आईं। परन्तु प्रशासनिक वर्ग में पर्याप्त योग्यता एवं कल्पना शक्ति के अभाव के कारण वे इन समस्याओं एवं उनके समाधान के उपायों को समझ भी नहीं सके। बेमिक शिक्षा की मूल्यांकन समिति ने अपने मन् १९५६ के प्रतिवेदन में कहा है—“किसी भी प्रान्त में यह नहीं देखा गया कि जन-शिक्षा के संचालक के लिए बुनियादी शिक्षा महत्त्व का विषय हो और न उनमें से कोई अपने प्रान्त की बुनियादी शिक्षा की समस्याओं में परिचित था।”<sup>१</sup> इन कर्मचारियों की बुनियादी शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट न होने से ये लोग पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कार्य के लिए साज-सामान एवं कच्चा मान विद्यालयों की नहीं भेजते हैं और न अभी तक संसार माल को बेचने की विधि ही निर्दिष्ट कर पाये हैं। विद्यालयों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी अध्यापकों की शिकायतों को दूर नहीं कर पाते हैं। ये लोग अध्यापकों के साथ बैठकर उत्पन्न समस्याओं पर विचार भी नहीं करते हैं।

(७) विद्यालय-भवनों का अभाव—बेमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक कठिनाई विद्यालय-भवनों का अभाव है। जिस गति में छात्रों की संख्या बढ़ रही है उस गति में विद्यालय-भवनों का निर्माण नहीं हो रहा है। वे भवन जिनमें आजकल विद्यालय चल रहे हैं, अच्छी दशा में नहीं हैं। वे अस्वस्थ एवं अस्वच्छ वातावरण में स्थित हैं। ग्रामीण विद्यालयों की दशा तो और भी अधिक खराब है। वहाँ पर कक्षाएँ वृक्षों के नीचे, भीपड़ियों या मन्दिर आदि में लगती हैं। ऐसे भवनों में बेमिक विद्यालय चलाना कठिन है। बेमिक विद्यालय में तो पर्याप्त स्थान चाहिए जिसमें

1. "In none of the states did we find a Director of Public Instruction to whom Basic Education was an issue of the utmost importance nor did we find any of them fully conversant with the problems of Basic Education in their respective states"—Report of the Assessment Committee on Basic Education, p. 8.





(१) बुनियादी शिक्षा का स्वावलम्बी न होना—कुछ लोगों का मत है कि वैमिक शिक्षा कभी भी स्वावलम्बी नहीं हो सकती है। मार्वेन्ट रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा कभी भी स्वावलम्बी नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि छात्रों के द्वारा तैयार मान कभी भी मुख्य कारीगरों द्वारा निर्मित माल के सामने नहीं टिक सकता है। बालको द्वारा निर्मित वस्तुएँ बाजार में बिकने लायक नहीं हो सकती हैं।

कुछ विद्वानों का मत है कि अगर इसी मिष्ठान्त पर चल दिया गया तो शिक्षण समस्याएँ शिल्प कुटीर केन्द्र बन जायेंगे। बुनियादी शिक्षा के आर्थिक इस योजना का व्यावहारिक को अपेक्षा आदर्शवादी अधिक मानते हैं। छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं को आय में विद्यालय का खर्चा या मिश्रणों का वेतन निकाल सकेगा, यह कल्पनाओं का जमीन बान लगती है। आकरि दुर्सन र्मार्मिन ने भी बाद में यह स्वीकार करते हुए कहा कि "यद्यपि वैमिक शिक्षा आत्म-निर्भर नहीं हो सकती है, परन्तु तो भी इसकी आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रीय संगठन में यह अधिक सहायक हो सकती है।"

(२) बच्चे की अपेक्षा उद्योग-वैज्ञानिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयोगों एवं आविष्कारों ने इस बात पर जार दिया है कि बाल-केन्द्रित शिक्षा होनी चाहिए। बालक की योग्यता, रुचि, अनियोग्यता आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के मिष्ठान्त के आधार पर ही अध्यापक को कक्षा में अध्यापन करना चाहिए। परन्तु बुनियादी शिक्षा में उद्योग पर अधिक जोर दिया जाना है। इसमें सम्पूर्ण शिक्षा का आधार या माध्यम उद्योग ही होता है। परिणामस्वरूप, बालक की रुचियों एवं योग्यता की अपेक्षा होती है।

उद्योग-प्रधान शिक्षा होने में शिक्षा का स्तर भी गिरता है। इसमें ५१ घण्टे के दैनिक कार्यक्रम में ३ घण्टे ०० मिनट केन्द्रीय दम्तकारी के लिए निर्धारित किये गए हैं। केवल २ घण्टे अन्य विषयों का अध्ययन करने के लिए बचते हैं। इतने कम समय में अन्य विषयों में सम्बन्धित पर्याप्त ज्ञान छात्रों को नहीं दिया जा सकता है।

(३) अस्वाभाविक समवाय—वैमिक शिक्षा पर एक आरोप समवाय में सम्बन्धित है। समवाय स्वाभाविक तथा सहज होना चाहिए। परन्तु यह भी ध्यान देने योग्य है कि सभी विषयों का ज्ञान केन्द्रीय उद्योग में समवाय करके नहीं दिया जा सकता है। अधिक सीखना करने पर समवाय अस्वाभाविक हो जाता है। इसके साथ एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि क्या कम योग्यता का अध्यापक जोरि की या १०वीं कक्षा उत्तीर्ण है, सभी विषयों का ज्ञान प्रधान उद्योग में समवाय करके दे सकेगा। बुनियादी शिक्षा के विद्वानों ने इस दोष को स्वीकार किया और नयी तालीम के मन् १९३६ के सम्मेलन में निर्णय किया—“वैमिक शिक्षा प्रणाली में समवाय

का प्रयोग शिक्षण के समय जबदेस्ती नहीं करना चाहिए। गमवाय को प्रमुख हस्तकला तक हो सीमित न करके इनको छात्रों के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से भी स्थापित किया जाय।”

(४) धार्मिक शिक्षा की अवहेलना— बुनियादी शिक्षा आध्यात्मिक पक्ष की अवहेलना करके भौतिक पक्ष पर अधिक जोर देती है। इस शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं है। वैसे धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी के विचार थे कि “वैसिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को स्थान न देने का कारण यह है कि आजकल जिस ढंग में धर्म सिखाये जाते हैं उसमें एकता के स्थान पर परस्पर घमनस्पदता है। परन्तु मेरा विचार है कि प्रमुख मिडलान्त नौ सभी धर्मों के समान ही होने हैं जो कि प्रत्येक बच्चे को सिखाये जाने चाहिए।”

**वैसिक शिक्षा की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय**

बुनियादी शिक्षा एक नवीन शिक्षा पद्धति होने के कारण सम्पूर्ण देश में एक साथ लागू नहीं की जानी चाहिए थी। सरकार ने इस क्षेत्र में विवेकपूर्ण निश्चय नहीं किया। नवीन शिक्षा योजना होने में इसके लागू करने में अधिक धन व्यय होना स्वाभाविक ही था। इसी सरकार ने संविधान में १० वर्ष के अन्दर ही सम्पूर्ण देश में १४ वर्ष तक की आयु के बालकों की शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क बनाने का निश्चय किया। इस प्रकार सरकार के समक्ष दो कार्य हो गये। प्रथम तो परम्परागत प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी विद्यालय में बदलना तथा दूसरे अनिवार्य निशुल्क अधिनियम को लागू करना। परिणामस्वरूप, इस कार्य पर अधिक धन व्यय होता निश्चित ही था। सरकार को पहले एक कार्य हाथ में लेना चाहिए था। अच्छा यह रहता कि सरकार अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की निश्चित अवधि में लागू करने का प्रयास करती तथा इसके साथ ही प्रत्येक प्रान्त में कुछ निश्चित स्थानों पर बुनियादी विद्यालयों की स्थापना इनके स्थापित करने एवं अन्य कठिनाई को ज्ञात करने के लिए करती जिससे कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए पहले से ही विचार कर लिया जाता। बाद में इस योजना को सम्पूर्ण देश में लागू किया जाता। ऐसा करने में एक समस्या यह भी नहीं होती कि बुनियादी विद्यालय के छात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश नहीं प्राप्त कर पाते हैं।

१ पाठ्यक्रम में सुधार—बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार इस प्रकार किया जाय जिसमें कि शिक्षा का स्तर ऊँचा उठ सके तथा इस जानोचना को दूर किया जा सके कि परम्परागत शिक्षा के पाठ्यक्रम का स्तर ऊँचा है। भारत एक प्रजातन्त्रीय देश है। अतः बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को लोकतन्त्रीय समाज की नागरिकता का पाठ गिसाना है। इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम ऐसे छात्रों को अवसर प्रदान करे कि वे अपनी समस्याओं, अधिकारों एवं उत्तरदायित्व को समझ सकें, इसके साथ ही छात्रों को उन दक्षताओं, ज्ञान और

अभिवृत्तियों के शिक्षण का अवसर भी पाठ्यक्रम को प्रदान करना चाहिए जो कि प्रजातन्त्रीय जीवन के लिए आवश्यक हैं। बुनियादी पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम उत्पादक, सामाजिक, सार्वजनिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक क्रियाओं की सूची तैयार करनी चाहिए। डॉ० मलामनुस्वामी ने पाठ्यक्रम की रचना के सम्बन्ध में लिखा है “कि उपर्युक्त क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया द्वारा क्या अनुभव सीखने योग्य प्रदान किये जायेंगे उनका अनुसन्धान द्वारा पता लगाया जाय। ये ही अनुभव इस प्रकार विकसित किये जायें कि वे व्यक्तियों के जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की मनुष्टि कर सकें। अनुसन्धान द्वारा इन आवश्यकताओं का भी पता लगाया जायगा। वे ही इन अनुभवों के क्षेत्र को निर्दिष्ट करेंगी जोकि नागरिकता का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक है। बाद में छात्रों की परिपक्वता के अनुसार ही इन अनुभवों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया।”<sup>1</sup> पाठ्यक्रम में उद्योग के समान ही अन्य विषयों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय।

२ अध्यापकों का प्रशिक्षण—बुनियादी शिक्षा की सफलता अधिकतर अध्यापकों पर निर्भर है। उन अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। इसके सम्बन्ध में प्रथम बात यह है कि बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों में १०वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाय क्योंकि अध्यापकों की सामान्य शिक्षा योग्यता पर ही अध्यापक के प्रशिक्षण का विकास निर्भर रहता है। इसके लिए एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी जाय कि उसके बाद कम योग्यता के व्यक्तियों को प्रवेश न दिया जाय। इसके साथ ही प्रशिक्षण-अवधि को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। १०वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रशिक्षण अवधि २ वर्ष की हो तथा मिडिल उत्तीर्ण के लिए तीन वर्ष की अवधि हो। इन प्रशिक्षण विद्यालयों में पाठ्यमहगामी कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाय। शिक्षण की नवीन विधियों का ज्ञान छात्रों को करवाया जाय। प्रशिक्षण विद्यालयों में अध्यापक ऐसी शिक्षण विधि प्रयोग में लायें जिसमें कि छात्रों को सभी बातें स्पष्ट हो जायें। वे उनको समझते जायें। इन छात्रों के लिए पुस्तकों की रचना की जाय। अभी तक बुनियादी प्रशिक्षण के लिए साहित्य का अभाव है। सेवाकालीन प्रशिक्षण (Inservice training) की सुविधा भी होनी चाहिए। इसके द्वारा इन अध्यापकों को नवीन विधियों का ज्ञान कराया जा सकता है। इस प्रशिक्षण की अवधि दो या तीन माह की हो तथा इसमें अध्यापकों को सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ शिक्षण अभ्यास भी कराया जाय।

मूल्यांकन समिति ने बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय के लिए निम्न आवश्यक सिद्धान्तों का सुझाव दिया

(अ) बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय को एक लोकतन्त्रीय सहकारिक मर्यादा होना चाहिए।



जिनके द्वारा समाज के विभिन्न मण्डल जैसे पचायत, भारत मेवक गमाज, भारत स्काउट्स आदि विद्यालय के कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान कर सके। निरीक्षकों को अध्यापकों के समक्ष विभिन्न नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन देना चाहिए। छोटे विद्यालयों में निरीक्षकों को सभी अध्यापकों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। परन्तु बड़े विद्यालयों में उनको सामूहिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उनको विचार गोष्ठी, सम्मेलन, दार्शनिक भ्रमण आदि मण्डल करने चाहिए।

४. अनुसन्धान—जाकिर हुसैन समिति ने अपने प्रतिवेदन में एक सिफारिश यह की थी कि प्रत्येक प्रान्त में अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की जाय। बुनियादी शिक्षा एक नवीन योजना होने में अनेक समस्याओं एवं कठिनाइयों का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। बुनियादी शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसन्धान की आवश्यकता अधिक है

(i) शिक्षण विधि—बुनियादी शिक्षा में सह-सम्बन्ध के मिडाल को अध्यापकों को स्पष्ट करना अति आवश्यक है। अनुसन्धान द्वारा यह विधि स्पष्ट की जानी चाहिए, (ii) पाठ्यक्रम, (iii) मूल्यांकन, (iv) दस्तकारी, (v) अध्यापक शिक्षण आदि अन्य क्षेत्र हैं जिनमें अनुसन्धान की आवश्यकता है।

५. बुनियादी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार—यह एक नवीन योजना होने से भारतवासी इसके प्रति समर्पित रहे। उन्होंने इसको सफल बनाने में उद्यतता प्रदर्शित नहीं की। इसका कारण यह भी है कि उनको इन योजना का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं था। किसी नवीन योजना को सफल बनाने में जनमत को अनुकूल बनाने के लिए प्रथम प्रयास होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षालयों के कार्यक्रमों का विस्तार समाज तक किया जाय। इसमें हमारा साक्ष्य है कि विद्यालय के कार्यक्रमों में जनता भाग ले व जनता के कार्यक्रमों में विद्यालय का प्रवेश हो। बुनियादी शिक्षा की उपयोगिता स्पष्ट करने के लिए प्रदर्शनी, शिक्षा मेले, उत्सवों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। अध्यापक जनमत तैयार करने में अधिक सहयोग दे सकते हैं। अध्यापक-अभिभावक सच स्थापित करने चाहिए। अभिभावक दिवस का आयोजन प्रत्येक विद्यालय में किया जाय जहाँ पर अभिभावकों को बुनियादी विद्यालयों के कार्यक्रम में अवगत कराया जा सके।

६. उद्योग या दस्तकारी—बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में हस्तकला को प्रमुख स्थान प्राप्त है। किसी हस्तकला का चुनाव करने के लिए उनमें दो बातों का होना आवश्यक है।

(अ) शिक्षा की दृष्टि से हस्तकला उपयोगी होनी चाहिए।

(आ) दूसरे, हस्तकला बालक के सामाजिक बनावरण से सम्बन्धित होनी चाहिए। यह विन्दु स्पष्ट करता है कि ग्रामीण और नागरिक क्षेत्र की दस्तकारी भिन्न होनी चाहिए।

अब एक प्रश्न यह उठता है कि किम कक्षा में दस्तकारी को प्रारम्भ किया जाय। विद्वानों का मत है कि निम्न स्तर पर छात्रों द्वारा कच्चे माल का अपव्यय अधिक होता है। ये अधिक परिपक्व न होने में कच्चा माल अधिक बिगाड़ने हैं और जना होने पर भी किमी उपयोगी तथा बिक्री के योग्य वस्तु का निर्माण नहीं कर पाते हैं। अतः लागो का मुभाव यह है कि उत्तर-बुनियादी स्तर में ही दस्तकारी को प्रारम्भ किया जाय। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् को एक उपमिति ने मुभाव दिया कि प्रथम दो कक्षाओं में सफाई, बागवानी आदि में सम्मिलित क्रियाएँ ही छात्रों में करवाई जायें। धीरे-धीरे इन क्रियाओं के करने में छात्रों में हस्तकार्य करने की कुशलता बढ़ेगी। इस मुभाव के अनुसार बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में मुधार की आवश्यकता है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

१. बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों का विवेचन कीजिए। इन सिद्धान्तों को कहाँ तक काम में लाया जा सकता है ?
२. बुनियादी शिक्षा के विभिन्न आधारों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
३. बेसिक शिक्षा के प्रसार में प्रमुख क्या कठिनाइयाँ आई हैं ? केन्द्रीय तथा राजस्थान सरकार ने उनको दूर करने के क्या उपाय किये हैं ?
४. "बुनियादी शिक्षा भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं मनो-वैज्ञानिक ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित करेगी।" आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ?
५. "बुनियादी शिक्षा में कोई नवीनता नहीं है, यह तो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का ही समन्वित रूप है।" इस कथन पर अपने विचार सुक्तिमग्न ढंग में प्रकट कीजिए।
६. बुनियादी शिक्षा योजना की असफलता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए।

### राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

1. What is the ideology behind Basic Education ? How far, in your opinion, can Basic Education fulfil the objectives of a national System of Education ? (1961)
२. बुनियादी शिक्षा के प्रसार में कौन-कौनसी विशेष कठिनाइयाँ रही हैं ? इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

## अध्याय ५

### माध्यमिक शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास

भारत की शिक्षा व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस का महत्व दो दृष्टियों में है—(१) प्रथम तो माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने वाली एक कड़ी है। (२) दूसरे, माध्यमिक शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण शिक्षा है जिसकी प्राप्ति करके छात्र में आत्मनिर्भरता का विकास होता है। शिक्षा की इस महत्वपूर्ण कड़ी का विकास अंग्रेजों के आगमन के बाद हुआ। प्राचीन भारत में प्राथमिक विद्यालय या फिर उच्च विद्यालय हुआ करने थे। ईसाई मिशनरियों के आगमन के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आरम्भ हुए। इन मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। सन् १८१३ के आज़ा-यत्र ने भी उन्हें देश में धर्म प्रचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी थी। इन मिशनरियों ने भारत में सर्वप्रथम कक्षा व्यवस्था प्रारम्भ की थी। इनके समय में भी वर्तमान माध्यमिक शिक्षा जैसा स्वरूप नहीं था। उस समय कुछ माध्यमिक शालाओं को स्कूल तो कुछ को विश्वविद्यालय के नाम से पुकारते थे। बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रान्त में मिशनरियों द्वारा विद्यालयों की स्थापना प्रमुख रूप में की गई। इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। सन् १८१४ के बाद धीरे-धीरे सरकार द्वारा भी माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की गई। परिणामतः मिशनरी स्कूलों की संख्या एवं महत्व कम होने लगा।

सन् १८५४ से १८८२ तक

बुढ़ के शिक्षा घोषणा-पत्र के आदेशानुसार इस युग में माध्यमिक शिक्षा ने पर्याप्त उन्नति की। इस युग में सरकार द्वारा अनेक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। इसके साथ-साथ सरकार द्वारा व्यक्तिगत प्रयासों को अनुदान सहायता द्वारा नवीन विद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सन् १८१४ में माध्यमिक

विद्यालयों की संख्या १९६ में बढ़कर सन् १८८२ में १,६६३ तक पहुँच गई। सन् १८८० तक भाग्यीयों द्वारा स्थापित विद्यालयों की संख्या १३४१ तक पहुँच गई थी। उस समय चले गये माध्यमिक विद्यालयों में अनेक दोष थे जो निम्नलिखित हैं—

(i) प्रतिष्ठित अध्यापकों का अभाव था, (ii) औद्योगिक शिक्षा का अभाव था, (iii) मातृभाषाओं की उपेक्षा तथा अंग्रेजी का जोर था, (iv) निरीक्षकों की संख्या कम थी, (v) धनाभाव के कारण विद्यालय सर्वसाधारण सज्जित नहीं थे, (vi) जीवन की दृष्टि में शिक्षा उद्देश्यहीन थी, (vii) परीक्षा का प्रभाव बढ़ने लगा।

### सन् १८८२ का भारतीय शिक्षा आयोग

इस आयोग के प्रधान सर विनियम हट्टर थे।<sup>1</sup> इस आयोग के सदस्यों ने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण करके शिक्षा सम्बन्धी असन्ती समस्याओं को जानने का प्रयत्न किया तथा २ वर्ष परिश्रम करने के बाद भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में अधिक उपयोगी सुझाव दिया जोंकि इस प्रकार का माध्यमिक शिक्षा में दो प्रकार का पाठ्यक्रम हो।

(अ) यह पाठ्यक्रम साहित्यिक विषयों के अध्ययन पर अधिक जोर देता हो, इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को विद्वत्विद्यालय के लिए तैयार करना होना चाहिए।

(आ) यह औद्योगिक पाठ्यक्रम हो, जिसमें व्यापारिक और व्यावसायिक विषयों का सम्मिलित किया जाय।

इस आयोग ने एक सुझाव यह भी दिया कि माध्यमिक विद्यालयों को जनता के हाथों में सौंप देना चाहिए। सरकार को राजकीय विद्यालय स्थापित नहीं करने चाहिए। सरकार का महावता अनुदान प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए। परन्तु जिन स्थानों की जनता धनाभाव के कारण विद्यालय स्थापित न कर सके तो ऐसे स्थानों पर सरकार विद्यालयों का निर्माण कर सकती है।

सन् १८८२ में सन् १९०२ तक माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक विस्तार हुआ। आयोग के सुझाव के निर्णय सरकार माध्यमिक शिक्षा के प्रकार में अंतर रही। इस प्रकार का इस निम्नलिखित आँकड़ों से समझ सकते हैं—

सन्	माध्यमिक विद्यालय
१८८०	३,६१६
१९००	५,१२६

सन्	माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या
१८८०	२,९६,९००
१९००	६,००,८९८

जिससे कि पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव का स्वीकारता किया गया परन्तु औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों पर ध्यान नहीं देना सके। छात्र अधिकतर 'अ' कार्य का ही अध्ययन करते थे। इस कारण माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित दोषों का जन्म



उठाने के लिए प्रसिध्द महाविद्यालयों की स्थापना हो गई। सन् १८८२ में भारत में केवल दो प्रसिध्द महाविद्यालय थे परन्तु १९०० में इनकी संख्या बढ़ कर ६ हो गई। माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम रही। इस प्रकार अंग्रेजी का आधिपत्य स्थापित हो जाने में भारतीय भाषाओं का विकास अवलुप्त हो गया।

### साई कर्जन और माध्यमिक शिक्षा

राष्ट्रीय जागरण के समय सन् १८९९ में साई कर्जन भारत का गवर्नर-जनरल होकर आया। वह एक बुद्धिमान प्रशासक तथा वास्तव्य सम्मता का महान् पुजारी था। उसने भारत की शिक्षा में भी रूचि ली। उसका विचार था कि भारतीय छात्रों को पुनर्मज्जित करने के लिए शिक्षा में सुधार किया जाना अनिवार्य है। इसी हेतु उसने सन् १९०१ में शिक्षा में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन १५ दिन तक चला। सन् १९०० में साई कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सन् १९०४ में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का निर्माण किया।

### सन् १९०४ का शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव

११ मार्च सन् १९०४ को साई कर्जन ने अपनी शिक्षा-नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। साई कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु भी अनेक कार्य किये क्योंकि भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर देश में माध्यमिक विद्यालय भारतीयों द्वारा संचालित होने थे। धनभाव के कारण इन विद्यालयों की संख्या बर्न्तोजनक नहीं थी। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा था। माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए साई कर्जन के सुझाव निम्नलिखित थे

(१) शिक्षा विभाग द्वारा सहायता प्रदान करना - भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर सहायता प्राप्त विद्यालय ही शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में रहने थे। परन्तु गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय अपनी इच्छानुसार कार्य करते थे। परिणामतः इन विद्यालयों में अनेक दोष उत्पन्न हो गये। इन दोषों को दूर करने के लिए नैम नियम बनाये गये जिसमें सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में रहे। सन् १९०४ के प्रस्ताव में कुछ सारे शिक्षा-विभाग में सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित कर दी गई। ये सारे निम्नलिखित थे

१. विद्यालय की स्थापना उम्र स्थान पर की जाय जहाँ उसकी माँग अधिक हो।
२. विद्यालय की समिति का गठन उचित प्रकार में हो।
३. पर्याप्त संख्या में अध्यापक हो और वे शिक्षण कार्य में रूचि लेते हो।
४. विद्यालय में आवश्यक विषयों के अध्यापन की उचित व्यवस्था हो।
५. विद्यालय शुल्क दर इतनी हो कि पंडों के विद्यालय पर बुरा प्रभाव न पड़े।

१ विद्यापीठा व स्वायत्त प्रशासन और अनुशासन की उचित व्यवस्था हो ।

(२) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्यक्ष सन् १९०६ में पूर्ण विश्वविद्यालय की मॉडेल बनायी गयी थी । इस विद्यालयों के द्वारा जो कई बातें की गयीं वे मान्यता प्राप्त नहीं होयीं थी । सन् १९०६ में मध्यम माध्यमिक विद्यालयों के लिए आवश्यकता थी कि वे अपने निष्ठा के विश्वविद्यालयों में मान्यता प्राप्त करें । इन प्रकार माध्यमिक विद्यालयों पर विद्या विज्ञान और विश्वविद्यालयों का नियंत्रण था ।

(३) गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के द्वारा के प्रथम वर्ष की प्रविष्टि मना दिया गया । जो छात्र गैर मान्यता प्राप्त मिडिल स्कूल में उचित हाई माध्यमिक शिक्षा प्रथम वर्ष तक नहीं दिया जा रहा । इसका परिणाम यह हुआ कि मिडिल स्कूल में सरकार में मान्यता प्राप्त करने में ।

(४) माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता उचित नहीं करने में माध्यमिक विद्यालयों के गुणवत्ता प्रकाश के लिए निर्माता-निर्देश आदेश दिए

- १ माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक रंगे जायें ।
- २ माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यावहारिक विषयों को सम्मिलित किया जाय ।
- ३ मिडिल स्कूल की बधाओं में विद्या का माध्यम भाग्योप भाग्योप हो ।
- ४ प्रादेशिक स्तर में जादों राजकीय विद्यालयों की स्थापना की जाय किमें गैर-राजकीय विद्यालयों तक जो अपना भादों मानें ।
- ५ गैर-राजकीय विद्यालयों का विधान-मुधार के लिए अधिक सहायता अनुदान दिया जाय ।
- ६ निरीक्षण के लिए निरीक्षकों को मक्या में वृद्धि की जाय ।

सन् १९१३ का विद्या नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव- -११ फरवरी सन् १९१३ को सरकार ने विद्या-नीति सम्बन्धी अपना प्रस्ताव पारित किया । इस प्रस्ताव के अन्तर्गत माध्यमिक विद्या के विभाग के लिए निम्नलिखित विचारों की गईं

- १ माध्यमिक विद्या के क्षेत्र में सरकार को पूर्ण रूप में नहीं हस्तक्षेप चाहिए ।
- २ राजकीय विद्यालयों की मक्या में वृद्धि न की जाय ।
- ३ अध्यापकों का वेतन निर्दिष्ट कर दिया जाय ।
- ४ परीक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम में सुधार किया जाय ।
- ५ माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक ही अध्यापक नियुक्त किये जायें ।
- ६ गैर-राजकीय विद्यालयों को पर्याप्त सरकारी सहायता अनुदान दिया जाय ।

७. राजकीय विद्यालयों में छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा का प्रबन्ध किया जाय।
८. पाठ्यक्रम में विज्ञान तथा मनुष्य प्रशिक्षण जैसे आधुनिक विषयों को स्थान दिया जाय।
९. छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाय।
१०. माध्यमिक विद्यालयों की कार्यक्षमता में कृटि करने के लिए उन पर कठोर नियन्त्रण रखा जाय।

### कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (१९१७)

१४ मितम्बर, १९१७ को इस आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग के अध्यक्ष सी०एम० विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० माइकेल मैकमर बनाये गये। इसीलिए अध्यक्ष के नाम पर इसको मैकमर आयोग के नाम से भी पुकारते हैं। इस आयोग ने मार्च १९१९ में अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया। विश्वविद्यालय आयोग होने हुए भी इसने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सुझाव दिये। आयोग ने सर्वप्रथम देश के शिक्षा अधिकारियों का ध्यान माध्यमिक शिक्षा के दोषों की ओर आकर्षित किया।

१. माध्यमिक विद्यालयों का वेतन कम होने से योग्य व्यक्ति इस व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।
२. विद्यालयों में महत्वपूर्ण विषयों की अवहेलना की जाती है।
३. माध्यमिक शिक्षा में विस्तार के अनुसार ही गुणात्मक उन्नति नहीं हुई है।
४. माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन सामग्री का अभाव रहता है।
५. माध्यमिक विद्यालयों पर परीक्षाओं का भय छाया रहता है।
६. धन की कमी के कारण अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों की कार्यक्षमता घट रही है।

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये

१. बी० ए० के कोर्स की अवधि ३ वर्ष की कर दी जाय।
२. इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय में पृथक् कर दिया जाय।
३. इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाय।

४. इंटर की कक्षाओं में नवीन विषय, जैसे चित्रित, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, कृषि और कला आदि की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

५. प्रत्येक प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाय।

### सन् १९०५ से १९२१ तक माध्यमिक शिक्षा की प्रगति

राजकीय नियंत्रण अधिक बढ़ा होने पर भी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी का मिलना था। अधिक संख्या में भारतीय बच्चे विद्यालयों में प्रविष्ट हुए और तदनुसार विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। यह वृद्धि निम्नलिखित आंकड़ों में स्पष्ट है

१९०५	५,१२४	माध्यमिक विद्यालय।
	५,६०,१२६	छात्रों की संख्या।
१९२१	७,५३०	माध्यमिक विद्यालय।
	११,०६,८०३	छात्रों की संख्या।

इसी प्रकार भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक एवं औद्योगिक विषयों को स्थान दिया गया। एक नवीन परीक्षा जिसका नाम 'स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट' रखा गया, प्रारम्भ की गई। १९१०-११ में सम्पूर्ण भारत में मेट्रीकुलेशन परीक्षा में १६,६६२ और सर्टिफिकेट परीक्षा में १०,१६१ छात्र बैठे थे। इनमें सर्टिफिकेट परीक्षा की लोकप्रियता स्पष्ट होती है।

इस काल में भी अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी रही। परिणामस्वरूप भारतीय भाषा में विकसित न हो सकी। मिडिल स्कूल की कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी।

अध्यापकों के प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दिया गया। १९१२ तक १५ प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित हो चुके थे।

### द्वंद्व शासन में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति (१९२२-१९३७)

माटेयू-जेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर सन् १९२१ में द्वंद्व शासन की स्थापना की गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रान्तों के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया (क) मंत्रित, (ख) हस्तान्तरित। शिक्षा को हस्तान्तरित विषय बनाया गया। परिणामस्वरूप, शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय अगियों के हाथ में आ गया। परन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण भारतीय मन्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इच्छानुसार कार्य न कर सके। इसका विरोध होने में सन् १९२७ में माइमन आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग की एक उपसमिति भारतीय शिक्षा की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई। इस

उपसमिति के अध्यक्ष सर फिलिप हर्टाग थे। इन्होंने १९२६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हर्टाग समिति ने निम्नलिखित दोष बताये

१. मेट्रीकुलेशन परीक्षा की प्रधानता।
२. अनुत्तीर्ण छात्रों की विनाश संस्था।

हर्टाग समिति ने सर्वेक्षण के बाद बताया कि अभी तक विद्यालयों के मस्तिष्क में यही विचार रहता है कि माध्यमिक शिक्षा तो छात्रों को विश्वविद्यालय के लिए तैयार करती है। यह जीवन के लिए तैयारी की शिक्षा प्रदान नहीं करती है। दूसरी बात जिसकी ओर हम आयोग ने सकेत किया, वह परीक्षाओं का आतंक है। छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही अपना ध्येय मानते हैं। इसी प्रकार दूसरा दोष अधिक मर्यादा में छात्रों का अनुत्तीर्ण होना है। इसका कारण पाठ्यक्रम का समुचित होना है। छात्र अपनी रूचि एवं योग्यता के आधार पर विषय का चयन नहीं कर पाते हैं। पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषय सम्मिलित नहीं किये गये। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों में घन एवं छक्ति का अपभ्रंश होता है। इन दोषों को दूर करने के लिए हम समिति ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव दिये

१. माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम को औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषय सम्मिलित करके विस्तृत किया जाय।
२. मिडिल स्कूल के पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किये जायें जो छात्रों को पनोपार्जन के योग्य बना सकें।
३. शिक्षा की गुणवत्ता में उन्नति के लिए अध्यापकों के वेतन एवं सेवा-प्रतिबन्धों में सुधार किया जाय।
४. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाय।
५. प्रशिक्षण महाविद्यालयों की दसा में भी सुधार किया जाय, उनमें अभिनवन पाठ्यक्रम (Refresher Course) की व्यवस्था की जाय।
६. गैर-राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों को अस्थायी नियुक्ति दी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक समिति अध्यापकाय का वेतन बढ़ा लेती है। अध्यापक को अपने पद की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनसे सन्धि (Agreement) भरवाना चाहिए।
७. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे वैकल्पिक विषय दिये जाय जिससे छात्र अपनी रूचि के अनुसार पढ़ सकें।

सन् १९०० में १९१३ के बीच माध्यमिक शिक्षा की प्रगति निम्नलिखित ढीरता में स्पष्ट है

	सन् १९०१	सन् १९१३
१ मापदण्ड प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	३,४१०	१३,०५६
२ माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या	११,०६,८०३	२२,८३,८३०

### माध्यमिक शिक्षा (१९३७-१९४७)

इस काल में द्वितीय विश्वयुद्ध होने में माध्यमिक शिक्षा की नींव प्रगति नहीं हो सकी। इस काल की प्रगति निम्नलिखित आँकड़ों में स्पष्ट है

	सन् १९३७	सन् १९४७
१ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	१३,०५६	१३,६०३
२ माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या	२२,८३,८३०	२६,८१,६८१

सन् १९४७ में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में कमी होने का कारण यह है कि युद्ध माध्यमिक विद्यालय विभाजन के कारण पाकिस्तान में चले गये। इस काल में मन्द गति के निम्नलिखित कारण हैं

- १ विश्वयुद्ध के कारण यह आर्थिक मंदी का काल था। अतः सरकार ने बहुत से विद्यालयों की अनुदान महाकता में कमी कर दी।
- २ युद्ध के कारण महँगाई बढ़ गई। मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना असम्भव हो गया।

इस काल की माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित दोष थे :

- १ शिक्षा का स्तर गिरता गया। इसका कारण अधशिक्षित अध्यापकों का अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश था।
- २ यह महँगाई का समय था, परन्तु अध्यापकों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई। परिणामस्वरूप, उनमें असन्तोष फैल गया।

३. माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए कोई उपाय नहीं किया गया।
४. योग्य अध्यापकों के अभाव के कारण छात्रों में अनुशासनहीनता फैल गई।

### साजेंट योजना, १९४४

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर सरकार ने शिक्षा के लिए युद्धोत्तर विकास की योजना बनाई। इस कार्य के लिए तत्कालीन भारतीय शिक्षा मन्त्रालय सर जॉन साजेंट की नियुक्ति की। साजेंट ने मई १९४४ में अपना प्रतिवेदन 'केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय परिषद्' के समक्ष प्रस्तुत किया। इस योजना को तीन नामों में पुकारा जाता है—(अ) भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना, (आ) साजेंट योजना, (इ) केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय परिषद् का प्रतिवेदन। यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा में लेकर विश्वविद्यालय तक की समस्याओं, उनके समाधान एवं उन समस्याओं के निवारण के उपाय भी बताये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं

१. हाईस्कूल की शिक्षा ११ से १७ वर्ष की आयु के बालकों के लिए हो। ११ वर्ष से कम आयु के बालकों को इन स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेगा।
२. इन विद्यालयों में बांग्म एवं प्रतिभाशाली छात्रों को ही प्रवेश दिया जाय।
३. पचास प्रतिशत छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाय। निर्यत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाय।
४. हाईस्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होय। अंग्रेजी की शिक्षा द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में प्रदान की जायगी।
५. हाईस्कूल दो प्रकार के होंगे—साहित्यिक तथा प्रावधिक।
६. साहित्यिक हाईस्कूलों में—(i) मातृभाषा, (ii) अंग्रेजी, (iii) आधुनिक भाषाएँ, (iv) भारत और विश्व का इतिहास, (v) भारत एवं विश्व का भूगोल, (vi) गणित, (vii) विज्ञान, (viii) अर्थशास्त्र, (ix) कृषि, (x) कला, (xi) शारीरिक शिक्षा विषय होंगे। इनके अनतिरिक्त प्राच्य भाषाओं और मानविक शास्त्र के विषय भी होंगे।
७. प्रावधिक हाईस्कूलों में—(i) काष्ठकला, (ii) धातुकला, (iii) ड्राइंग, (iv) वाणिज्य, (v) बुक-बिन्डिंग, (vi) गार्टमेंट, (vii) टाइप-राइटिंग, (viii) व्यापार प्रणाली आदि विषय पढ़ाये जायेंगे।
८. कालिकाओं को गृह-विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जायेगी।
९. इस योजना के अनुसार अध्यापकों को केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय परिषद् द्वारा स्वीकृत वेतन दिया जायेगा।
१०. नये प्रतिष्ठान महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

स्वातन्त्र्योत्तर काल—इस काल में एक समिति और तीन प्रसिद्ध आयोगों ने माध्यमिक शिक्षा पर अपने विचार प्रकट किये । ये आयोग एवं समितियाँ निम्न हैं :

१. ताराचन्द समिति—सन् १९४८ में ताराचन्द जी की अध्यक्षता में शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई । इस समिति ने सुझाव दिया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अवधिकाल १२ वर्ष का हो । इस १२ वर्ष की अवधि का विभाजन इस प्रकार हो—५ वर्ष जूनियर वैमिक, ३ वर्ष सीनियर वैमिक तथा ४ वर्ष उच्चतर माध्यमिक । उच्चतर माध्यमिक स्कूल बहुउद्देशीय बनाने का सुझाव दिया । इस समिति का एक महत्त्वपूर्ण सुझाव माध्यमिक शिक्षा की जाँच करने के लिए आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में था ।

२. विश्वविद्यालय आयोग—सन् १९४८ में विश्वविद्यालय शिक्षा की जाँच करने के लिए डा० राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई । इस आयोग ने सन् १९४९ में सर्वेक्षण करने के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इस आयोग का प्रधान कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय की शिक्षा तक सीमित था, परन्तु आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया । प्रथम सुझाव था कि बिना इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण किये किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश न दिया जाय । दूसरा सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारा जाय ।

३. माध्यमिक शिक्षा आयोग—केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् और ताराचन्द समिति के सुझाव पर केन्द्रीय सरकार ने २३ सितम्बर, १९४२ में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की । इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० लक्ष्मन स्वामी मुशालियर थे । इस आयोग के सुझावों का विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में किया जायेगा ।

४. कोठारी आयोग—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री कोठारी जी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक विशिष्ट प्रकार के आयोग की नियुक्ति की । इस आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय तीनों शिक्षा-स्तरों का अध्ययन करने के बाद अपने सुझाव दिये ।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

१. हुन्टर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए क्या सुझाव दिये थे ?
२. लार्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा के विकास में योगदान का मूल्यांकन कीजिए ।
३. पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का वर्णन कीजिए ।
४. रात्रस्यान में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए किये गये प्रयत्नों का वर्णन कीजिए ।



## अध्याय ६

### माध्यमिक शिक्षा आयोग

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में तीव्र गति के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन प्रारम्भ हुए। इन परिवर्तनों के साथ शिक्षा का सामना करना पड़ा। इन परिवर्तनों के लिए माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई। सन् १९४८ में सर्वप्रथम 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्' ने सरकार को माध्यमिक शिक्षा की जाँच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का सुझाव दिया। सन् १९५१ में इस परिषद् ने अपनी माँग को पुनः दुहराया। परिणामस्वरूप, सरकार ने २३ सितम्बर, १९५२ को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसको मुद्रालय आयोग के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष डाक्टर ए० लक्ष्मण स्वामी मुद्रालय थे। इनके अतिरिक्त आयोग के प्रमुख सदस्यों में प्रधानाचार्य जॉन रिम्डी, श्रीमती हसामेहता, के० जी० संवरन तथा प्रधानाचार्य ए० एन० कपूर थे।

#### आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य

माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई

- १ भारत में वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की दशा का प्रत्येक दृष्टिकोण से अध्ययन करना।
- २ माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार के लिए सुझाव देना  
(अ) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, विषय-वस्तु और उसका संगठन।  
(आ) माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बुनियादी व उच्च शिक्षा के साथ सम्बन्ध निश्चित करना।  
(इ) माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन व उन्नति के लिए अपने सुझाव देना।  
(ई) माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अन्य समस्याओं के समाधान बनाना।



(ख) व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि—आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा औद्योगिक विकास किया जा रहा है। इन उद्योगों में कार्य करने के लिए व्यावसायिक कुशलता प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। अतः माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाय कि वह छात्र में किसी व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि करे और इस प्रकार उसको जीविकोपार्जन के लिए स्वावलम्बी बना सके।

(ग) रसक्तिध का विकास—माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना हो, अतः शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार में की जाय कि छात्र के जन्म-जात गुणों का विकास हो सके और इन गुणों को वह व्यावहारिक दृष्टि में प्रयोग में ला सके। छात्रों का साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।

(घ) नेतृत्व का विकास—प्रजान्त्र में दो प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है : एक तो नेतृत्व करने वाले होते हैं और दूसरे उनका अनुकरण करने वाले। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार में की जाय जो कि ऐसे नेताओं का निर्माण करे जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में जनता का पथप्रदर्शन कर सकें। इसके साथ ही अनुकरण करने वाली जनता भी नहीं हानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य उनकी चिन्तन शक्ति एवं विवेक का विकास करना हो, जिससे वे विवेकपूर्ण अनुकरण कर सकें।

(ङ) माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन—आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए

- (अ) माध्यमिक शिक्षा ११ से १७ वर्ष तक की आयु के बालक एवं बालिकाओं के लिए होनी चाहिए।
- (आ) माध्यमिक शिक्षा की अवधि ७ वर्ष की होनी चाहिए।
- (इ) प्राथमिक या जूनियर सेनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक की माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ होनी चाहिए।
- (ई) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि ४ वर्ष की हो।
- (उ) इष्टरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करके उसकी ११वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में और १२वीं कक्षा को द्वितीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जाय।
- (ऊ) द्वितीय पाठ्यक्रम ३ वर्ष का कर दिया जाय।
- (ए) जो छात्र १०वीं कक्षा उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश ले उनके लिए एक वर्ष का पूर्व-विश्वविद्यालय कोर्स (Pre-University Course) रखा जाय।
- (ऐ) छात्रों की विभिन्न रुचियों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाय।

आयोग ने प्रश्नावली की महायता में तथा विभिन्न प्रान्तों का भ्रमण कर माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके २६ अगस्त, १९५१ को १४ अध्यायो में विभाजित २८४ पृष्ठ का एक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

## आयोग के सुझाव

आयोग द्वारा विभिन्न समस्याओं पर प्रकट किये गये विचार एवं सुझावों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है

(१) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र—आयोग ने सरकारी माध्यमिक शिक्षा में विद्यमान दोषों का वर्णन अपने प्रतिवेदन में निम्न प्रकार से किया

(अ) माध्यमिक शिक्षा मकोर्ण है और इसका जीवन में कोई सम्बन्ध नहीं है।

(आ) माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है।

(इ) कक्षाएँ बड़ी होने से शिक्षक-छात्र सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है।

(ई) अंग्रेजी भाषा के कारण छात्रों की क्षति नष्ट होती है।

(उ) अत्यन्त प्राचीन शिक्षण की रीतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं।

(ऊ) माध्यमिक शिक्षा संकुचित और एक-मार्गीय होने से छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं करती है।

(ए) वर्तमान शिक्षा छात्रों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करने में असफल रही है।

(ऐ) दोषपूर्ण शिक्षण-विधियों के कारण छात्रों में स्वतन्त्र चिन्तन क्षति का विकास नहीं हो पाता है।

(ओ) परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है और इसका आतंक छात्र एवं अध्यापक दोनों पर छाया रहता है।

(औ) पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है। छात्र अपनी रचि एवं योग्यता के आधार पर पाठ्य-विषयों का चयन नहीं कर पाते हैं।

(२) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य—भारतवर्ष की वर्तमान अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए

(क) प्रजातंत्रवादी नागरिकता की भावना का विकास—भारतवर्ष विश्व का एक बड़ा जनतंत्रात्मक देश है। यहाँ के प्रजातंत्र की मजबूती लोगों की शिक्षा पर निर्भर करती है। शिक्षा इस प्रकार की हो जो देश के लिए योग्य, मजबूत, ईमानदार नागरिक तैयार करे। इन आदर्श नागरिकों में राष्ट्र-प्रेम, भावधर्म एवं नेतृत्व में स्पष्टता, सामाजिकता, अनुमानन, सहयोग की भावना आदि गुण अवसर होने चाहिए। अतः शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में उपर्युक्त गुणों का विकास करना होना चाहिए।

न—(i) सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम (केवल प्रथम दो वर्षों के लिए)

(ii) सामान्य विज्ञान गणित सहित (केवल प्रथम दो वर्षों के लिए)

म—निम्नलिखित में से एक हस्तकला

(i) कटाई एवं बुनाई, (ii) काष्ठकला, (iii) धातुकला, (iv) बाग-बानी, (v) मिलाई का कार्य, (vi) कपौदाकारी, (vii) मिट्टी का काम ।

(ख) वैकल्पिक विषय

निम्नलिखित ७ वर्षों में से किसी एक वर्ग के तीन विषय चुनने होंगे

वर्ग १—मानव विज्ञान (Humanities)

(i) एक शास्त्रीय भाषा, या (अ-ii) से से न सीखी भाषा, (ii) भूगोल, (iii) इतिहास, (iv) अर्थशास्त्र तथा नागरिकशास्त्र, (v) मनोविज्ञान तथा तर्क-शास्त्र, (vi) गणित, (vii) संगीत, और (viii) गृह विज्ञान ।

वर्ग २—विज्ञान (Science)

(i) भौतिक शास्त्र, (ii) रसायन शास्त्र, (iii) जीव शास्त्र, (iv) भूगोल, (v) गणित, (vi) जीव-विज्ञान तथा स्वास्थ्य-विज्ञान के तत्त्व (जीव शास्त्र के साथ नहीं) ।

वर्ग ३—तकनीकी (Technical)

(i) व्यावहारिक गणित और वैश्विकीय कला, (ii) व्यावहारिक विज्ञान, (iii) यांत्रिक इंजीनियरिंग के तत्त्व, (iv) विद्युत इंजीनियरिंग के तत्त्व ।

वर्ग ४—वाणिज्य (Commerce)

(i) व्यावहारिक अर्थशास्त्र, (ii) बहीखाता, (iii) वाणिज्य भूगोल तथा अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र के तत्त्व, (iv) आयुतिथि तथा टक्का ।

वर्ग ५—कृषि (Agriculture)

(i) सामान्य कृषि, (ii) पशु-पालन, (iii) बागबानी, (iv) कृषि रसायन तथा वनस्पति विज्ञान ।

वर्ग ६—सूक्ष्म कलाएँ (Fine Arts)

(i) कला का इतिहास, (ii) कला तथा रूपांकन, (iii) चित्र कला, (iv) प्रति-रूपण, (v) संगीत, (vi) नृत्य ।

वर्ग ७—गृह-विज्ञान (Home Science)

(i) गृह-अर्थशास्त्र, (ii) पाक-कला, (iii) शिशु-पालन और मातृ-कला, (iv) गृह-प्रबंध ।

- ३ छात्रों को सामुदायिक जीवन का पाठ सिखाने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं का समावेश किया जाय जिससे छात्रों को सामुदायिक जीवन की समस्याओं को समझने का अवसर मिल सके।
- ४ छात्रों को अवकाश के समय का सदुपयोग सिखाने के लिए पाठ्यक्रम में कुछ मनोरंजक क्रियाओं को स्थान दिया जाय।
- ५ सभी विषयों का समन्वित ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय परस्पर सम्बन्धित होने चाहिए।

### ७. पाठ्यक्रम के विषय

(१) मिडिल अथवा सीनियर बेंसिक स्कूलों का पाठ्यक्रम—आयोग ने सुझाव दिया कि उपर्युक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं होता चाहिए। मिडिल स्तर पर विषयों पर अधिक जोर देना चाहिए। इस स्तर पर निम्नलिखित विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया

(अ) भाषाएँ, (आ) सामाजिक अध्ययन, (इ) सामान्य विज्ञान, (ई) गणित, (उ) कला तथा संगीत, (ऊ) हस्त उद्योग, (ए) प्रायोगिक विज्ञान।

(२) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विषय—इस पाठ्यक्रम की विविधता का सुझाव दिया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि इस स्तर पर पाठ्यक्रम के विषयों को दो भागों में बाँटा जाय—प्रथम अनिवार्य विषय (Core subjects), दूसरे वैकल्पिक विषय। आयोग ने इन वैकल्पिक विषयों को ७ भागों में विभाजित किया।

#### (क) अनिवार्य विषय (Core subjects)

अ—(i) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा तथा एक राष्ट्रीय भाषा का विभिन्न पाठ्यक्रम।

(ii) निम्नलिखित भाषाओं में से एक भाषा

(क) हिन्दी (जिनको मातृभाषा हिन्दी नहीं है)

(ख) प्राथमिक अंग्रेजी (जिनकोने मिडिल स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया)

(ग) उच्च अंग्रेजी (जिनकोने अंग्रेजी का अध्ययन किया है)

(घ) हिन्दी के अनिवार्य एक अन्य भारतीय भाषा।

(ङ) अंग्रेजी के अनिवार्य एक प्राचुरिक विदेशी भाषा।

(च) एक राष्ट्रीय भाषा।

(ग) उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को निरीक्षक बनाया जाय ।

(घ) निरीक्षक समिति बनाई जाये जिसमें तीन सदस्य होने चाहिए ।

(३) व्यक्तिगत विद्यालयों का प्रबन्ध—(क) विद्यालयों की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होनी चाहिए और प्रधानाध्यापक इनका स्थायी सदस्य होना चाहिए ।

(ख) शिक्षा-विभाग के नियमों के अनुसार छात्रों में शुल्क लिया जाय ।

(ग) विद्यालयों को मान्यता तभी दी जाय जब वे मान्यता सम्बन्धी शर्तों को पूरा कर दें ।

(४) विद्यालय-भवन—(क) एक विद्यालय में ७५० से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए ।

(ख) कक्षा के कमरे में प्रत्येक छात्र को कम से कम १० वर्ग फीट स्थान देना आवश्यक है ।

(ग) गाँवों में केन्द्रीय स्थान पर तथा भवरो में शोरमुक्त के बनावट में दूर विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए ।

(घ) प्रत्येक विद्यालय में सहकारी स्टोर होने चाहिए ।

(५) कार्यकाल—(क) जलवायु के अनुसार कार्य-समय निर्दिष्ट करना चाहिए ।

(ख) वर्ष में विद्यालय २०० दिन अवश्य खुलना चाहिए । दो माह का वीष्मा-वकाश हो ।

(६) आर्थिक सहायता—(क) प्रांतीय सरकारों के द्वारा विद्यालयों की अनुदान दिया जाना चाहिए ।

(ख) विद्यालय के भवन पर किसी प्रकार का कर न लगाया जाय ।

(ग) विद्यालय के सामान पर चुंगी न लगे ।

(घ) तकनीकी विद्यालयों के लिए कारखानों पर कर लगाया जाय ।

## माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन

मुद्रानिर्धार आयोग के प्रतिवेदन के गुण

१ आयोग का यह कार्य सराहनीय है कि उसने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किये ।

२. बातों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर विविध पाठ्यक्रम का मुझाव देकर आयोग ने एक प्रान्तिकारी परिवर्तन की माँग की ।

३ बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का मुझाव शिक्षा में एक नवीन प्रयोग है । ये विद्यालय छात्रों के अज्ञित ज्ञान को प्रयोग में लाने का अवसर प्रदान करते हैं ।

६. समान योग्यता एवं समान कार्य करने वालों को समान वेतन दिया जाय।
७. अध्यापकों के लिए त्रिमुखी लाभ-योजना—पेंशन, प्राविष्ट फंड और जीवन-बीमा की सुविधा कार्यान्वित की जाय।
८. अध्यापकों को ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति न दी जाय।
९. अध्यापकों को निम्न सुविधाएँ दी जाय—
  - (i) बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, (ii) आवास की सुविधा, (iii) शिक्षा सम्प्रेषण में जाने की सुविधा, (iv) मुफ्त चिकित्सा, (v) प्रीमियावकाश में भ्रमण के लिए किराये में रियायत।

१४. अध्यापकों का प्रशिक्षण—आयोग के सुझाव निम्न प्रकार थे

१. दो प्रकार के प्रशिक्षण विद्यालय हों—(अ) प्रथम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए। इनका प्रशिक्षण काल २ वर्ष का होना चाहिए। (आ) दूसरे विद्यालय स्नातकों के लिए हों। इनका प्रशिक्षण काल अभी १ वर्ष का रहे, बाद में इसको २ वर्ष का कर दिया जाय।
२. प्रशिक्षण काल में छात्राध्यापकों को छात्रवृत्तियाँ दी जायें।
३. प्रशिक्षण संस्थानों में अभिनवन पाठ्यक्रम, सधुगहन पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था की जाय।

(१५) प्रशासन की समस्या—प्रशासन के क्षेत्र में आयोग के निम्नलिखित सुझाव हैं

- (१) शिक्षा का संगठन—(क) शिक्षा मंत्री को प्रशासन की समस्याओं पर परामर्श देने का उत्तरदायित्व शिक्षा सचालक पर होना चाहिए।
- (ख) केन्द्र व प्रान्तों में शिक्षा समीक्षायें गठित की जायें। ये समीक्षायें शिक्षा के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनायें।
- (ग) माध्यमिक शिक्षा परिषद् में २५ से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। इस परिषद् का प्रधान उम प्रान्त का शिक्षा सचालक हो।
- (घ) इस परिषद् की एक उपसमिति परीक्षाओं की व्यवस्था करे।
- (ङ) प्रत्येक प्रान्त में अध्यापकों के प्रशिक्षण की योजना तथा उसके कुशल संचालन के लिए 'शिक्षक-प्रशिक्षण परिषद्' की स्थापना की जाय।
- (२) निरीक्षण—(क) विद्येय विषयों के लिए अलग-अलग निरीक्षकों की नियुक्ति की जाय।
- (ख) निरीक्षकों को चाहिए कि वे अध्यापकों को समय-समय पर उचित परामर्श दें।



स्वीकार ही नहीं किया। राजस्थान प्रान्त ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया। यहाँ पर दो कार्य प्रमुख रूप से किये गये

- १ हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करना।
- २ बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना।

राजस्थान में इस समय दो प्रकार के विद्यालय हैं

- १ पहले माध्यमिक विद्यालय जिनमें ६वी, १०वी कक्षाओं तक ही अध्ययन की सुविधा होती है।
- २ दूसरे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिनमें ११वी कक्षा भी होती है।

इस समय दो परीक्षाएँ होती हैं—पहली मेकेण्डरी और दूसरी हायर-मेकेण्डरी परीक्षा। मेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। इसके बाद पूर्व-विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही छात्र स्नातक कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। हायर मेकेण्डरी स्कूल के छात्र ३ वर्ष के बाद दूसरे प्रकार की परीक्षा में बैठते हैं। परन्तु उनको प्रथम दो वर्ष के लिए निश्चित विषयों में परीक्षा १०वी कक्षा में देनी होती है, जो हायर मेकेण्डरी परीक्षा, भाग १ कहलाती है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

- १ माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए मुशानियर आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं? इन सिफारिशों का वर्तमान शिक्षा-संगठन पर क्या प्रभाव पड़ा है?
- २ शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों पर प्रकाश डालिए।
- ३ हमारी शिक्षा पद्धति में माध्यमिक शिक्षा को सबसे कमजोर कड़ी कहा गया है। इसकी प्रमुख खराबियों को बताइए।
- ४ आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठन के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की व्याख्या कीजिए।

राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

1. Discuss the recommendations of the Secondary Education Commission regarding improvement in the economic and social status of the teacher (1961)
2. Estimate the effect of reorganization of Secondary Education in Rajasthan. What suggestions do you have to offer for complete success in the Scheme? (1962)

४. भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के ग्रामीण विद्यालयों में कृषि को अनिवार्य विषय बनाने का उत्तम सुझाव दिया।
५. आयोग का यह सुझाव उपयोगी है कि शिक्षण विधियों में श्रिया व प्रमुख ध्यान दिया जाय।
६. वर्तमान समय में छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता एक चिन्ता का विषय है। छात्रों को अनुशासन की श्रिया और चार्चितक शिक्षा में निरूप आयोग ने सुझाव देकर एक सत्रात कार्य किया है। आज देश में नैतिकता का अभाव है।
७. अध्यापकों की दसा सुधारने के लिए उनके वेतन, प्रशिक्षण तथा सेवा शर्तों के विषय में प्रत्यक्ष सुझाव दिए हैं।
८. आयोग ने विद्यालयों में पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण क्रियाओं के आश्रयन का सुझाव देकर छात्रों के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता को स्पष्ट किया है।
९. गरीबी में सुधार तथा मौखिक एवं भावनात्मक निर्देशन की व्यवस्था का सुझाव देकर आयोग ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

## बोध

१. इण्टरमीडिएट कक्षाओं को छोड़कर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में १ वर्ष बढ़ाने का सुझाव उपयोगी होने हुए भी समस्यापूर्ण था क्योंकि इन कार्य के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी।
२. आयोग ने स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए कोई महत्वपूर्ण सुझाव नहीं दिया है।
३. दो भाषाओं के साथ अन्य आन्तरिक श्रियाएँ का अध्ययन तथा एक वर्ष के तीन विषयों का अध्ययन अनिवार्य होना पाठ्यक्रम बहुत भारी हो जाता है।
४. सामक और चार्चितक के पाठ्यक्रम में कोई भेद नहीं है।
५. आयोग ने व्यक्तिगत विद्यालयों की प्रत्यक्ष समिति के सदस्यों की योजना के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिया है।

उपरोक्त बातों के होने हुए भी यह निश्चित मान्य है कि भाषाएँ के अनेक सुझाव अत्यन्त उपयोगी और व्यावहारिक हैं।

## राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों का प्रभाव

शिक्षा एक प्राचीन विषय है। अतः माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों को प्रतिष्ठित विभिन्न विद्यालयों में निष्पन्न प्रभाव में हुई। कुछ भाषाओं में एक सुझाव का प्रभाव किया। परन्तु कुछ भाषाओं में एक सुझाव का प्रभाव नहीं किया। इससे कुछ भाषाएँ ही हैं जिससे आयोग के सुझावों का

## अध्याय ७

### बहु-उद्देशीय विद्यालय

यह निश्चिन्ता है कि देश की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ वहाँ की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती हैं। स्वतन्त्रता में पूर्व शिक्षा के उद्देश्य आज के लोकतन्त्रीय भारत में शिक्षा के उद्देश्यों में भिन्न थे। ब्रिटिश शासन काल में माध्यमिक शिक्षा का एक ही प्रधान उद्देश्य था—“अपने राजकीय तथा व्यापारिक कार्यालयों में काम करने के लिए लिपिक तैयार करना।” अंग्रेजों ने देश के आर्थिक विकास में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामस्वरूप, यहाँ पर आर्थिक उन्नति के लिए नवीन उद्योगों की स्थापना भी नहीं की गई। इन सब का प्रभाव शिक्षा पर यह पड़ा कि माध्यमिक शिक्षा में साहित्यिक पक्ष की प्रधानता रही। माध्यमिक विद्यालयों के दो कार्य थे—प्रथम, प्रणालीगत कार्य में सहायता देने वाले स्वामिभक्त कर्मचारी तैयार करना और द्वितीय, छात्रों को विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए तैयार करना। यहाँ पर तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजों के द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया गया और न व्यावसायिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक शिक्षा एक-मार्गीय (Unilateral) बनकर रह गई। इस प्रकार की शिक्षा विभिन्न अभिव्यक्तियों वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करती है। स्वतन्त्रता के पश्चात् देश के सभी क्षेत्रों—राजनीतिक, आर्थिक, एवं सामाजिक आदि में तीव्र गति से परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण देश में विभिन्न शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की माँग बढ़ती जा रही है। एक-मार्गीय शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई माँग की पूर्ति नहीं हो सकती है, अतः यह आवश्यक ही नहीं परन्तु अनिवार्य हो गया है कि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ही शिक्षा के रूप में भी परिवर्तन लाया जाय।

- 3 Examine the desirability and the possibility of evolving a programme of secondary education with emphasis on vocational training in India You are advised to make use of your knowledge of secondary education in other countries in formulating your point of view (1968)
- 4 Highlight some of significant contributions made by our schools in realising the proper goals of education If you feel the schools have not been able to make such significant contribution analyse the reasons for the failure and suggest measures for remedying them (1965)
- ५ भविष्य के सामाजिक स्वरूप की कल्पना करने हुए विचारण कीजिए कि आपके विचार में राष्ट्र को कौन-सी नवीन आवश्यकताएँ हैं जिनके अनुकूल सामाजिक शिक्षा को होना चाहिए । (१९६६)
- ६ आपके विचार में भारत तथा राष्ट्रधाम में सामाजिक शिक्षा को कौन-कौन-सी प्रमुख समस्याएँ हैं ? हाँ तो वे उनके समाधान के लिए क्या-क्या प्रयास किए गये हैं ? उन दिनों यह मुद्दों ने आप कहीं तक महसूस हैं ? (१९६७)

विविध पाठ्यक्रम पढ़ाने की व्यवस्था है उनको इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में अलग-अलग नाम से पुकारते हैं।

**इंग्लैण्ड**—इंग्लैण्ड में निम्नलिखित प्रकार के माध्यमिक विद्यालय पाये जाते हैं

**माध्यमिक विद्यालयों के प्रकार**

कम्प्रीहेन्सिव स्कूल	बहुमुखी विद्यालय	ग्रामर स्कूल	तकनीकी स्कूल	माडर्न स्कूल
(Comprehensive Schools)	(Multilateral Schools)	(Grammar Schools)	(Technical Schools)	(Modern Schools)

इंग्लैण्ड में ग्रामर स्कूल माध्यमिक शिक्षा के पुराने विद्यालय हैं। इन विद्यालयों की स्थापना १७वीं सताब्दी में प्रारम्भ हुई। ग्रामर स्कूल छात्रों को विषय-विद्यालय की शिक्षा के लिए तैयार करते हैं। इन विद्यालयों में अंग्रेजी साहित्य, आधुनिक विदेशी भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला और संगीत विषय पढ़ाये जाते हैं। धार्मिक शिक्षा का अध्ययन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होता है। तकनीकी माध्यमिक विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाने की व्यवस्था होती है। ग्रामर स्कूलों की अपेक्षा तकनीकी विद्यालयों की संख्या कम ही है। इसका कारण ज़रूरत ग्रामर स्कूलों का तकनीकी विद्यालयों की अपेक्षा उच्च कोटि का सम्झनी है। जहाँ जहाँ अभिभावक अपने बच्चे को ग्रामर स्कूल में प्रवेश नहीं दिना सकना है उनको फिर तकनीकी स्कूल में प्रवेश दिनाता है। तीसरे प्रकार के माध्यमिक विद्यालय मेकेंड्रो माडर्न स्कूल हैं। इन विद्यालयों की स्थापना माध्यमिक शिक्षा का नवीनीकरण करने के उद्देश्य में की गई है। ये विद्यालय धीमे ही जन्मा में लोकप्रिय हो गये क्योंकि इनमें सामान्य शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। २०वीं सताब्दी के उत्तरार्द्ध में डिमार्गीय (Bilateral) विद्यालयों की स्थापना की गई। इन विद्यालयों में तथा ग्रामर, तकनीकी या माडर्न स्कूलों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। डिमार्गीय विद्यालय में ग्रामर, तकनीकी या माडर्न स्कूल में से किसी दो का सम्मिलित रूप पाया जाता है। कम्प्रीहेन्सिव स्कूल भी अधिक संख्या में स्थापित हुए। इन विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा को एक ही विद्यालय में व्यवस्था करना था परन्तु ये विद्यालय भी उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सके। इंग्लैण्ड में बहुमुखी विद्यालयों की स्थापना भी की गई है। किसी विशेष वर्ग के सभी छात्रों को शिक्षा प्रदान करना ही इन विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य है। बहुमुखी विद्यालयों में तीनों प्रकार के विद्यालयों की प्रमुख बात सम्मिलित रहती है। इंग्लैण्ड में बहुमुखी विद्यालय अधिक लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं।

## बहु-उद्देशीय विद्यालयों के लिए प्रयास

समय समय पर भारतीय नवजात न शिक्षा के संकटन में परिचरित करने के लिए प्रयास में आसक्त किया। इन अनुशासक पर शिक्षा आयोग का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा के संकटन में परिचरित करने का दिशा नियुक्त की जाया रही है।

(१) प्रथम आचार्य नरेन्द्रदेव समिति—इस समिति की नियुक्ति सन् १९३६ में हुई थी। आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश की कि विभिन्न माध्यमिक तथा अभिजातिकाओं के छात्रों के लिए विविध पाठ्यक्रम तैयार किया जाय। विभिन्न पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव था कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का भाग चरम में विभाजित किया जाय—(१) साहित्यिक, (२) वैज्ञानिक, (३) श्रमोन्मुख, (४) व्यावहारिक। माध्यमिक विद्यालयों में उपर्युक्त सभी वर्ग पढ़ाने की व्यवस्था हो।

(२) सारायण्डे समिति—सरययण-प्राप्ति के पश्चात् सन् १९६८ में तारायण्डे समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने की सिफारिश की। इसके माध्यम से ही सुझाव दिया कि माध्यमिक विद्यालयों की बहुमुखी बनाना तब परम्परा अनुसूची (Unai-ai-ral) विद्यालय समाप्त नहीं किया जाय। परिस्थितियों के अनुसार ये विद्यालय भी पालन हो।

(३) द्वितीय आचार्य नरेन्द्रदेव समिति—उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् १९५०-५१ में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में दूसरी बार शिक्षा समिति गठित की। इस समिति ने बहु-उद्देशीय विद्यालय स्थापित करने तथा उनमें विविध पाठ्यक्रम के अध्यापन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सुझाव दिया। इसके माध्यम ही सर्वोच्च विद्यालय अधिक समस्या में मानने के लिए भी सिफारिश की, जिनमें देश में तब-नीकी शिक्षा का प्रसार हो सके।

(४) माध्यमिक शिक्षा आयोग—भारत सरकार ने सन् १९५२-५३ में तारायण्डे समिति की सिफारिश के आधार पर मुद्राविषय की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। इन आयोग में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा अन्य सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए कहा गया। पिछले अध्याय में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का वर्णन किया गया है। उन सिफारिशों में से एक प्रमुख सिफारिश बहुमुखी विद्यालयों की स्थापना में सम्बन्धित है। कुछ प्रांतीय सरकारों ने आयोग के सुझावों को कार्यान्वित किया और बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का कार्य आरम्भ कर दिया।

## पाश्चात्य देशों में बहु-उद्देशीय विद्यालय

पाश्चात्य देशों में ईंग्लैण्ड और अमेरिका ही ऐसे देश हैं जहाँ पर बहु-उद्देशीय विद्यालय चल रहे हैं। इन देशों में मनोवैज्ञानिक विकास अधिक होने से विविध पाठ्यक्रम की आवश्यकता बहुत पहले ही अनुभव कर ली गई थी। जिन विद्यालयों में

## बहु-उद्देशीय विद्यालय की रचना

मुदालियर आयोग के पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझावों का वर्णन पिछले अध्याय में दिया गया है। आयोग ने जिस विविध पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सिफारिश की है उसके अध्यापन की सुविधा जिन विद्यालयों में प्रदान की जाएगी, उनको बहु-उद्देशीय विद्यालय के नाम से पुकारते हैं। इनमें दो प्रकार के विषय होते हैं—(१) अनिवार्य, (२) वैकल्पिक।

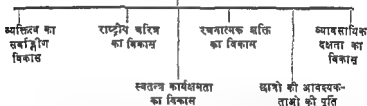
अनिवार्य विषय—(अ) भाषाएँ, (आ) सामान्य विज्ञान और गणित, (इ) सामाजिक अध्ययन, (ई) हस्तकला।

वैकल्पिक विषय—वैकल्पिक के अन्तर्गत विषयों के ३ समूह बनाए गये हैं। इनमें से अपनी रुचि के अनुसार छात्र एक समूह में से तीन विषयों को चुनेगा। ये समूह निम्नलिखित प्रकार हैं (१) मानवीय विषय, (२) विज्ञान, (३) तकनीकी विषय, (४) वाणिज्य विषय, (५) कृषि, (६) कलित कलाएँ, (७) गृह-विज्ञान।

## बहु-उद्देशीय विद्यालय के उद्देश्य

जून १९५७ में नईनीताल में एक विचारगोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में सदस्यों ने बहु-उद्देशीय विद्यालयों के उद्देश्यों के सम्बन्ध में विचारविनिमय किया। सदस्यों ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्दिष्ट किये

### उद्देश्य



- बहु-उद्देशीय विद्यालयों को छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का प्रयास करना चाहिए। विद्यालयों में छात्रों के केवल मानसिक या बौद्धिक विकास की ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। वहाँ तो ऐसा वातावरण, परिस्थितियाँ तथा ऐसी सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए जिनमें बालक के व्यक्तित्व के सभी अंगों का विकास हो।
- विद्यालयों को छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना चाहिए तथा उनकी क्षमताओं का राष्ट्रीय चरित्र एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माण की दिशा में निर्देशित करना चाहिए। आज देश में सभी स्तरों पर इस बात की चर्चा की जाती है—आज के नवयुवक राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माण के स्थान पर विध्वन करके अधिक करते हैं। इसका कारण उनमें राष्ट्र-प्रेम का अभाव है। बहु-उद्देशीय विद्यालय छात्रों की क्षमताओं को उचित कार्य करने को प्रेरित करेंगे।

## मनुष्य राज्य अमरीका

मनुष्य राज्य अमरीका में 'कॉन्ग्रेसि-नल' विद्यालय अधिक लोकप्रिय है। इनमें ४ वर्ष के लड़के को पढ़ाने की सुविधा होती है। जैसा कि हमके नाम में स्पष्ट है, ये सामाजिक स्तर की सभी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाओं में सुसज्जित होते हैं। यहाँ पर छात्रों को अनेक विषय पढ़ाने की सुविधा होती है। इन प्रकार छात्रों को अपनी सभी तथा अभिव्यक्तियों के अनुसार विषय चुनने की स्वतन्त्रता रहती है। ये विद्यालय प्रजातन्त्र विद्यालयों पर आधारित हैं क्योंकि यहाँ पर सभी भाँति विज्ञान तथा एथ के छात्रों का उचित दिया जाता है। छात्रों का सामाजिकता का पाठ पढ़ाने के लिए कॉन्ग्रेसि-नल विद्यालयों में अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं।

भारतवर्ष शिक्षा का एक बड़ा प्रजातन्त्रिय देश है। यहाँ के नागरिकों का प्रजातन्त्र का पाठ सिखाने की एक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। मनुष्य राज्य अमरीका के 'कॉन्ग्रेसि-नल' विद्यालय प्रजातन्त्रिय व्यवस्थापकों की अनुसरण हैं तथा प्रजातन्त्रिय सामान्य व्यवस्था की एक व्यवस्था तथा प्रजातन्त्रिय नागरिक बनाते में अधिक सहायक है। इन भारतवर्ष की एक भी इन प्रकार के बहुत प्रयोगों विद्यालय अधिक प्रचलित रहेंगे।

## बहु-उद्देशीय विद्यालय का अर्थ

मनुष्य राज्य व्यवस्था में भारतवर्ष का सामाजिक छात्रों के परामर्शकों की आवश्यकताओं के प्रकाश में एक व्यवस्था कायम किया है। यहाँ पर परामर्शकों की आवश्यकता का एक प्रमुख बिंदु यह है कि छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की भी पर्याप्त जगह मिले। इन सभी का पूर्ण ध्यान के लिए विविध परामर्शकों का सुव्यवस्थापन करना। इससे एक परामर्शकों को पढ़ाने की व्यवस्था की एक बहु-उद्देशीय विद्यालयों की व्यवस्था की एक व्यवस्था में परिवर्तित की। सामाजिक शिक्षा कायम की बहु-उद्देशीय विद्यालयों का अर्थ स्पष्ट करने की एक विधा है। बहु-उद्देशीय विद्यालयों का अर्थ है, (१) छात्रों तथा प्रजातन्त्रियों का एक सुव्यवस्था की एक विविध प्रकार के परामर्शकों का व्यवस्थापन करना है। यह व्यवस्था छात्रों की व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं के ध्यान में रखी जायेगी तथा प्रजातन्त्रिय व्यवस्था में व्यवस्था व्यवस्थापकों द्वारा प्रजातन्त्रिय व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट करने की एक विधा है। मनुष्य राज्य



(१) सामाजिक लाभ—वर्तमान युग में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर अधिक बल दिया जाना है नाकि छात्र में सभी सामाजिक गुणों का विकास करके उसको समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाया जा सके। भारतवर्ष में आज ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो भारतीय समाज में व्याप्त दुर्गुणों को दूर कर सके और उसके विकास में सहयोग दे सकें। ऐसे नवयुवक तैयार करना तो विद्यालयों का ही कार्य है। इसीलिए आजकल विद्यालयों को समाज का नयु रूप कहा जाता है। बहु-उद्देशीय विद्यालय सामाजिक पक्ष के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। इनसे निम्नलिखित सामाजिक लाभ है

(अ) राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति—स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक विकास हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, इन विभिन्न क्षेत्रों के लिए बुद्धिमत् कार्यकर्त्ताओं की भाग बढ़ रही है। बहु-उद्देशीय विद्यालय कृषि, वाणिज्य तथा प्राथमिक कार्य में दक्ष नवयुवक तैयार करते हैं।

(आ) सामुदायिक एकता का विकास—हमारे समाज में स्थितियों और मूल्यों के मध्य निरन्तर बढ़ती हुई पृथक्ता एक बड़ा दोष है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावनों की सुरक्षा तथा उनकी उत्पत्ति करने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को सामुदायिक एकता का पाठ पढ़ाया जाए। ये विद्यालय सामूहिक रूप में कार्य करने को प्रोत्साहन देते हैं।

(इ) बेकारी की समस्या—भारतवर्ष के शिक्षित वर्ग में बढ़ रही बेकारी की समस्या एक चिन्ता का विषय है। बहु-उद्देशीय विद्यालय छात्रों को एक हस्तकला में दक्ष बनाकर उनको जीविकोपार्जन के योग्य बना देते हैं। शिक्षा समाप्त करने के बाद उनको किसी व्यवसाय में प्रवेश के समय तक बेकार बैठकर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

(ई) वर्ग-भेद की भूलतः—आज हमारा समाज अनेक वर्गों में बँटा हुआ है। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के व्यक्तियों में घृणा करते हैं। परिणामस्वरूप, सामाजिक एकता की शक्ति का ह्रास होता है। बहु-उद्देशीय विद्यालयों में सभी वर्गों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो परस्पर मिलन में उनमें एक-दूसरे के प्रति प्रेम बढेगा।

(उ) शारीरिक श्रम का सम्मान—यहाँ अग्रेजों के समय में बौद्धिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। परिणामस्वरूप, शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम में घृणा करने लगे। बहु-उद्देशीय विद्यालयों में छात्रों को विभिन्न हस्त-कलाएँ सीखनी पड़ेंगी। धीरे-धीरे छात्र इस प्रकार हस्त-कार्य करने में रुचि लगे तथा यह भावना भी दूर होगी कि कोई कार्य किसी जाति विशेष से सम्बन्धित है। वे तो प्रत्येक कार्य को हस्तकला के रूप में देखेंगे।

(२) शैक्षिक लाभ—बुनियादी विद्यालयों से निम्नलिखित शैक्षिक लाभ हैं :

विद्यार्थियों को छात्रों में स्वतन्त्र रूप में कार्य करने की योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए। आज विद्यालयों में अध्यापक इस प्रकार की शिक्षण विधि अपनाने हैं कि छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। छात्रों में यह विरोधाभास पैदा नहीं हो पाता है कि वे स्वयं भी कुछ कार्य कर सकते हैं।

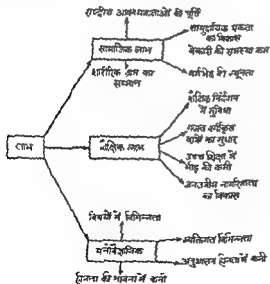
छात्रों में रचनात्मक मूलप्रवृत्ति के विकास के लिए वर्तमान माध्यमिक विद्यालयों में कुछ भी नहीं किया जाता है। बहु-उद्देशीय विद्यालयों का एक उद्देश्य छात्रों को रचनात्मक और समाज के लिए हितकर कार्य करने की शिक्षा देना होना चाहिए।

माध्यमिक विद्यालयों को सभी प्रकार के छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ये विद्यालय विरहविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को तैयार करने तथा इसके साथ ही उन छात्रों को जो कि माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् अध्ययन समाप्त कर देते, स्वावलम्बन की शिक्षा दें।

विद्यालयों को छात्रों में एक मित्र की इसनी दक्षता उत्पन्न कर देनी चाहिए कि वे उसमें सम्बन्धित व्यवसाय को कर सकें।

## ये विद्यालयों से लाभ

राष्ट्रीय विद्यालयों में अनेक लाभ हैं जो कि निम्नलिखित रेखाचित्र से स्पष्ट हैं



(१) सामाजिक लाभ—वर्तमान युग में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर अधिक बल दिया जाना है ताकि छात्र में सभी सामाजिक गुणों का विकास करके उनकी समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाया जा सके। भारतवर्ष में आज ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सक और उनके विकास में सहयोग दे सकें। ऐसे नवयुवक तैयार करना तो विद्यालयों का ही कार्य है। इसीलिए आजकल विद्यालयों को समाज का लघु रूप कहा जाता है। बहु-उद्देशीय विद्यालय सामाजिक पक्ष के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। इनमें निम्नलिखित सामाजिक लाभ हैं

(अ) राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति—स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक विकास हो रहा है। परिणामस्वरूप, इन विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यकर्त्ताओं की मांग बढ़ रही है। बहु-उद्देशीय विद्यालय कृषि, वाणिज्य तथा प्रावधिक कार्य में दक्ष नवयुवक तैयार करते हैं।

(आ) सामुदायिक एकता का विकास—हमारे समाज में व्यक्तियों और समूहों के मध्य निरंतर बढ़ती हुई घृणता एक बड़ा दोष है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय माधनों की सुरक्षा तथा उनकी उन्नति करने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को सामुदायिक एकता का पाठ पढ़ाया जाए। ये विद्यालय सामूहिक रूप में कार्य करने को प्रोत्साहन देते हैं।

(इ) बेकारी की समस्या—भारतवर्ष के निश्चित वर्ष में बढ़ रही बेकारी की समस्या एक चिन्ता का विषय है। बहु-उद्देशीय विद्यालय छात्रों को एक हस्तकला में रस बनाकर उनकी जीविकोपार्जन के योग्य बना देते हैं। शिक्षा समाप्त करने के बाद उनकी किसी व्यवसाय में प्रवेश के समय तक बेकार बैठकर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

(ई) वर्ग-भेद की मूलता—आज हमारा समाज अनेक वर्गों में बँटा हुआ है। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के व्यक्तियों से घृणा करते हैं। परिणामस्वरूप, सामाजिक एकता की शक्ति का हानि होता है। बहु-उद्देशीय विद्यालयों में सभी वर्गों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो परस्पर मिलन में उनमें एक-दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा।

(उ) शारीरिक धर्म का सम्मान—यहाँ अंग्रेजों के समय में शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। परिणामस्वरूप, निश्चित व्यक्ति शारीरिक धर्म से घृणा करने लगे। बहु-उद्देशीय विद्यालयों में छात्रों को विभिन्न हस्त-कलाएँ सीखनी पड़ेंगी। धीरे-धीरे छात्र इन प्रकार हस्त-कार्य करने में रसि लेगे तथा यह भावना भी दूर होगी कि कोई कार्य किसी जानि विरोध से सम्बन्धित है। वे तो प्रत्येक कार्य को हस्तकला के रूप में देखेंगे।

(२) शैक्षिक लाभ—बुनियादी विद्यालयों में निम्नलिखित शैक्षिक लाभ हैं :

(अ) शैक्षिक निर्देशन में सुविधा—इन विद्यालयों में विभिन्न विषयों का समावेश होता है जिसके कारण विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए चुनाव करने में अधिक सहायता की जा सकती है।

(आ) गलत वर्गीकृत छात्रों में सुधार—इन विद्यालयों में उन छात्रों की समस्या का समाधान सरलता से हो जाता है जो गलत विषयों का चयन कर लेते हैं। गलत वर्ग चुनने वाले छात्र को दूसरे वर्ग में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(इ) उच्च शिक्षा में भीड़ की कमी—भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा का एक दोष अपने में ही पूर्णता का अभाव था। माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्र के समक्ष समय का सदुपयोग करने का एक ही उपाय था कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। इन प्रकार विश्वविद्यालयों में छात्रों की भीड़ बढ़ जाती है। बहु-उद्देशीय विद्यालय छात्र को किसी हस्तकला में निपुण बनाकर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। ये छात्र इसके द्वारा जीवन-यापन कर सकते हैं और अग्रिम शिक्षा का विचार त्याग सकते हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालयों में भीड़ की कमी हो जाती है।

(ई) जनतंत्रीय नागरिकता का विकास—सभी छात्र यहाँ मानुषिक रूप में कार्य करते हैं, परिणामस्वरूप उनमें परस्पर प्रेम और महानुभूति की भावना का विकास होता है। वे यहाँ पर कर्तव्य पूरा करने का पाठ सीखते हैं। यहाँ कुछ अनिवार्य विषय पढ़ाये जाते हैं जिनका अध्ययन करना जनतन्त्र के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है।

(३) मनोवैज्ञानिक लाभ—इसमें निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक लाभ हैं।

(अ) विषयों में विभिन्नता—इन विद्यालयों में विभिन्न विषयों का अध्यापन होता है। इस प्रकार छात्रों को अपनी रचि एवं योग्यता के अनुसार अध्ययन के विषयों का चयन करने में सुविधा रहती है।

(आ) व्यक्तिगत विभिन्नता—वर्तमान समय में व्यक्तिगत विभिन्नता के निदान पर अधिक बल दिया जाता है। इसीलिए इन विद्यालयों में इस निदान के आधार पर ही शिक्षण होता है। छात्रों की रचियों, क्षमताओं एवं योग्यता के आधार पर उनको हस्तकला की शिक्षा दी जाती है।

(इ) अनुशासनहीनता में कमी—माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की किमोरावस्था होती है। इस अवस्था में छात्रों की विभिन्न रचियों को रचनात्मक कार्य की ओर लगाना चाहिए। यदि उनकी रचियों का ध्यान नहीं रखा गया तो उनमें अनुशासनहीनता बढ़ती जाएगी। बहु-उद्देशीय विद्यालयों में छात्रों की रचियाँ का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें छात्रों में अनुशासनहीनता कम होगी।

(ई) होनता की भावना में कमी—अधिकज्ञान तथा विज्ञान तथा व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्र माहिर्य और कला के छात्रों को हीन दृष्टि से देखते हैं।

जब सभी वर्गों के छात्र एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे, एक-सा ही क्राफ्ट कार्य करेंगे और माप-नाप लेते-लेगे तो उनमें हीनता की भावना समाप्त हो जाएगी।

### बहु-उद्देशीय विद्यालयों की समस्याएँ

मुद्रांतियर आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतवर्ष में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई परन्तु इनको स्थापित करने एवं इनको सफल बनाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

१. आयोग ने पाठ्यक्रम की विभिन्नता के लिए इनका माप-वर्गों में विभाजित किया। सम्पूर्ण देश में शिक्षा का समान स्तर बनाने के लिए निर्देश दिया कि यही विविध पाठ्यक्रम सभी प्रांतों में लागू किया जाय। देश के कुछ प्रांतों ने इस मुद्दाब को स्वीकार किया तथा 'अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्' के सह-योग में निर्दिष्ट किया कि विभिन्न कक्षाओं में इन विषयों का क्रमता अद्य पढ़ाना है? आयोग के इस मुद्दाब में दो प्रमुख दोष हैं—

(अ) सभी राज्यों में शिक्षा का समान स्तर न होना।

(आ) पाठ्यक्रम के निर्माण में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। शिक्षा का स्थानीय आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देने से यह शिक्षा स्थानीय समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। गांधीजी ने भी बुनियादी शिक्षा में हस्तकला के चुनाव के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखने पर विशेष बल दिया है परन्तु आयोग ने तो कुछ हस्तकलाओं को निम्न दिया है चाहे वे किसी स्थान के उपयुक्त हैं या नहीं।

२. हस्तकला को गौण स्थान—आयोग का मुद्दाब था कि प्रत्येक छात्र को एक हस्तकला का अध्ययन अनिवार्य रूप में करवाया जाय और उसको उसमें इनका निपुण बना दिया जाय कि वे स्वतन्त्र रूप से उस उद्योग को चला सकें, परन्तु वेब का विषय है कि इन विद्यालयों में निकले छात्र स्वतन्त्र रूप में हस्त-उद्योग को चलाने की क्षमता नहीं रखते हैं। इनका कारण विद्यालयों में हस्त-उद्योग सिखाने के लिए पर्याप्त सामानों का अभाव है। हस्त-उद्योग कला विद्यालयों में नहीं पाये जाते हैं और जिनमें उद्योग-कला हैं, वे नाम-मात्र के लिए हैं क्योंकि महँगे यंत्र होने से वे सुगम्य नहीं हो पाते हैं। इस कारण हस्तकला का पाठ्यक्रम में गौण स्थान होता जा रहा है।

३. विद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी समस्या—देश में अनेक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहु-उद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है तथा इनके साथ ही नवीन बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना भी की जा रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २,४४६ बहु-उद्देशीय विद्यालय स्थापित करने का मसदा सरकार ने रखा परन्तु इन बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना के

निरुद्ध न होकर विचार नहीं किया गया कि किस विद्यालयों को बहु-उद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित किया जायगा तथा किस स्थानों पर नवीन बहु-उद्देशीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, अनेक ऐसे स्थानों पर बहु-उद्देशीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं जहाँ उनकी आवश्यकता अधिक नहीं या जहाँ पर छात्रों की संख्या अधिक नहीं है। अनेक ऐसे विद्यालयों को बहु-उद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित किया है जिनके पास समुचित स्थान नहीं है या भवन का समर्थन है।

४. समय-सारिणी की समस्या बहु-उद्देशीय विद्यालयों में विविध पाठ्यक्रम होने में प्रधानाध्यापकों के समय उपयुक्त समय-सारिणी बनाने की भी कठिनाई है। इन कठिनाई के दो कारण हैं।

(i) प्रधानाध्यापक का अनेक विषयों के व्यावहारिक महत्त्व का ज्ञान नहीं है।

(ii) पहले की अध्यापक पाठ्य-विषयों की समस्या में कूटि हानी है।

बहु-उद्देशीय विद्यालय के पाठ्यक्रम में अनेक व्यावहारिक विषय सम्मिलित किए गये हैं। प्रधानाध्यापकों को इन विषयों के महत्त्व का ज्ञान न होने में इन विषयों की समय-सारिणी में पर्याप्त समय नहीं देने है। अधिकांश प्रधानाध्यापक पुरानी शिक्षा प्रणाली के अनुसार कार्य करते रहते हैं। अब वे सामान्य शिक्षा के विषयों को प्रधानता देते हैं। बहु-उद्देशीय विद्यालय में मान बलों के विभिन्न विषय तथा अतिवादी विषय होने में इनकी समस्या में इनकी कूटि हो गई है कि सीमित समय में ही इनकी व्यवस्था करना कठिन कार्य हो जाता है।

५. पाठ्य-पुस्तकों का अभाव माध्यम विद्यालयों के लिए पहले से ही पाठ्य-पुस्तकों की समस्या थी। इन बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना से तो पाठ्य-पुस्तकों की कमी और अधिक हो गई। वैकल्पिक विषयों की समस्या अधिक बढ़ गई तथा इनमें से जिन विषयों में छात्रों की संख्या कम होगी है, उनके लिए पुस्तकें कम लियी गई। अनेक नवीन विषयों के लिए पाठ्य-पुस्तक प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव की गई।

६. शिक्षकों की समस्या—देश में प्रसिद्धित अध्यापकों का अभाव पहले से ही बना हुआ है परन्तु इन बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना से योग्य अध्यापकों का मिलना और भी अधिक दुष्कर हो गया है। विज्ञान तथा प्रावधिक विषयों के लिए अध्यापकों का अभाव बना ही रहता है। इसका कारण न्यून वेतन होने से इन विषयों के शक्ति अध्यापन व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। हस्तकला के लिए भी अध्यापकों की समस्या बनती रहती है।

७. निर्देशन की समस्या—विविध पाठ्यक्रम की सुविधा होने पर विद्यालय में निर्देशन सेवा भी होनी चाहिए ताकि छात्रों को विषयों का चुनाव करने समय उचित परामर्श दिया जा सके। हमारे यहाँ के बहु-उद्देशीय विद्यालयों में निर्देशन

मेंवा प्रारम्भ नहीं की गई है तथा जहाँ यह कार्य कर रही है उनके लिए प्रशिक्षित निर्देशन अधिकारी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अभी तक प्रमापीकृत परीक्षाओं (Tests) का अभाव बना हुआ है। इनके बिना छात्रों की योग्यताओं एवं रक्षियों का मापन नहीं हो पाता है।

८. अभिभावकों का विरोध—धीरे-धीरे अभिभावक भी बहु-उद्देशीय विद्यालयों का विरोध करने लगे हैं। इसका कारण यह है कि अनेक वर्ग वर्ग के बच्चों पर अध्यापक और प्रधानाध्यापक एक मन नहीं हो पाते हैं। छात्र की योग्यता तथा अभिरुचि के आधार पर छात्र को वांछित वर्ग लेने का मुझाव दिया जाता है, परन्तु अभिभावक विज्ञान वर्ग दिववाने पर जोर देना है। ऐसे अवसर पर प्रधानाध्यापक को एक जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के मतभेद में अभिभावक इन विद्यालयों का विरोध करने लगे हैं।

९. पाठ्य-विषयों की अधिकता—विविध पाठ्यक्रम होने से छात्र को अनिवार्य या आन्तरिक तथा वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होता है। इनका भार इतना अधिक है कि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम हो गया है। अधिक विषय होने से छात्र सभी विषयों में सम्योपजनक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परिणाम-स्वरूप, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। बहु-उद्देशीय विद्यालय की अपेक्षा पुराने ढंग के विद्यालय फिर से लोकप्रिय होते जा रहे हैं।

## मुझाव

बहु-उद्देशीय विद्यालयों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का अध्ययन करने में स्पष्ट है कि जायोग के इस मुझाव को सफल बनाने के लिए इन समस्याओं के समाधान पर विचार करना होगा।

१. पाठ्यक्रम में मुझार—यह ठीक ही है कि सम्पूर्ण देश के लिए समान पाठ्यक्रम पढ़ाना सर्वसम्मत नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के त्रिम रूप का वर्णन किया है उसको उगी रूप में सभी प्रांतों में पढ़ाया जाय। पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में निश्चय करने समय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा अन्यथा विद्यालय स्थानीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही हस्तकला का चुनाव करना चाहिए।

२. हस्तकला के लिए कर्मशालाएँ—हस्त-उद्योग को बहु-उद्देशीय विद्यालय में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। ऐसा न होने से माध्यमिक शिक्षा अपूर्ण ही रहेगी। इन विद्यालयों में हस्त-उद्योग के लिए कर्मशालाएँ बनाई जायें। इन कर्मशालाओं की पूर्णतः सुसज्जित किया जाय। हस्त-उद्योग के अभ्यास के लिए छात्रों को अधिक अवसर दिया जाय। जब तक कर्मशालाएँ नहीं बनती हैं, किंगी निकटवर्ती फैक्ट्री में प्रायोगिक और कर्मशाला सम्बन्धी कार्य किया जा सकता है। स्थ में इगी प्रकार में

किया जाता है। जहाँ प्रत्येक छात्र को कुछ समय निष्कृति की पंथी में कार्य करना होगा। इस प्रकार छात्र नौकरी की कार्य-प्रणाली में परिचित हो जाता है और दूसरे विद्यालय में कार्यवाही स्थापित करने के लिए वे विद्यालय बच जाता है।

३. योग के क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना—नवीन बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना उन्नीसवीं शताब्दी के बाद जहाँ उनकी योग अधिक है। नवीन विद्यालय स्थापित करने में पूर्व कुछ बातों पर विचार करना चाहिए—(i) आवागमन की सुविधा, (ii) समुचित स्थान का चुनाव। प्राथमिक विद्या की व्यवस्था उन विद्यालयों में की जाये जिनके निकट कोई फँटरी या स्थान हो। सरकार को मध्यम देश का सर्वेक्षण करने आवश्यक स्थानों का पता लगाना चाहिए जहाँ बहु-उद्देशीय विद्यालय स्थापित किये जा सकते हैं। उपर्युक्त बातों को ही पुराने माध्यमिक विद्यालयों को बहु-उद्देशीय विद्यालय में परिवर्तन करने समय ध्यान में रखना चाहिए। जिन विद्यालयों के पास धन की कमी न हो, भवन सम्बन्धी समस्या न हो तथा साथ ही छात्रों की संख्या अधिक हो उनको ही बहु-उद्देशीय विद्यालय बनाना चाहिए।

४. आदर्श समय-सारिणी—विषयों की अधिकतर तयार हस्त-पुस्तक के कारण प्रधानाध्यापक समय-सारिणी बनाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। सरकार को विशेषज्ञों से आदर्श समय-सारिणी का निर्माण करवा कर प्रधानाध्यापकों के पास मार्ग-प्रदर्शन हेतु भेजना चाहिए। प्रधानाध्यापकों को समय-सारिणी बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए अध्यापकता में कुछ शिक्षकों का आयोजन करना चाहिए। हमारे देश में अभी तक इस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं किया गया है।

५. पाठ्य-पुस्तकों का प्रबंध—सरकार को पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन में रुचि लेनी चाहिए। लेखकों को पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ प्रांतीय सरकारों ने पुस्तकों का प्रकाशन अपने हाथ में ले लिया है परन्तु उनमें अभी और अधिक सुधार की आवश्यकता है। लेखकों को पुस्तक लेखन का सतोषजनक पारितोषिक मिलना चाहिए।

६. प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रबंध—बहु-उद्देशीय विद्यालयों में कार्य करने के लिए कुछ विषयों के अध्यापक प्राप्त नहीं होते हैं। सरकार को इस प्रकार के प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करने चाहिए जहाँ पर विज्ञान तथा प्राथमिक विषयों के अध्यापक तैयार किये जा सकें। हमें भारत सरकार ने क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की है परन्तु भारत जैसे देश के लिए जहाँ घनाभ्यक्त है, नवीन प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करने के स्थान पर पुराने प्रशिक्षण विद्यालयों को ही विकसित किया जाता तो कम धन में ही यह कार्य सम्भव हो जाता। बहु-उद्देशीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाने चाहिए—(i) अधिक योग्य तथा उच्च नैतिक योग्यता वाले अध्यापकों के लिए आकर्षक वेतन की व्यवस्था की जाय, (ii) इन अध्यापकों को नौकरी की सुरक्षा का



आश्वासन दिया जाय, (iii) प्रशिक्षण मस्थानों में बहु-उद्देशीय विद्यालयों के लिए अध्यापक तैयार किये जायें, (iv) अब्यापकों को दक्षिक योग्यता बढ़ाने की सुविधाएँ दी जायें।

७. निर्देशन अधिकारियों का प्रशिक्षण—बहु-उद्देशीय विद्यालयों में निर्देशन सेवा की व्यवस्था करना अति आवश्यक है, परन्तु इस निर्देशन कार्य के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने हैं। आवश्यकता इस बात की है कि निर्देशन अधिकारी तथा जीविकोपार्जन शिक्षकों (Career Masters) को प्रशिक्षण देने के लिए काम में कम प्रत्येक प्रान्त में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाय। भारत सरकार द्वारा प्रमाणीकृत परीक्षाएँ तैयार करनी चाहिए।

८. अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन—अभिभावकों को बहु-उद्देशीय विद्यालयों का महत्त्व स्पष्ट किया जाय। विद्यालयों में निर्देशन सेवा को विकसित किया जाय तथा उनको विश्वास दिलाया जाय कि छात्र को जिस वर्ग का अध्ययन करने का परामर्श दिया है, वह उनके लिए उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध होगा।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

- १ पाठपत्र में की विविधता पर टिप्पणी लिखिए।
- २ मुद्रालय द्वारा मुद्राये गये बहु-उद्देशीय विद्यालयों की क्या प्रमुख विशेषताएँ हैं ?
- ३ बहु-उद्देशीय विद्यालयों के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
- ४ बहु-उद्देशीय विद्यालयों की समस्याओं तथा उनकी दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए।

### राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

1. Discuss the functions of the 'core subjects' and the 'electives' in the Secondary School curriculum, and say what subjects or groups of subjects are to be included under each category. Explain how the aims of the secondary education are to be realised through this curriculum (1963)
2. Suppose that you are the Head of a Higher Secondary institution. Choose a subject and justify its place in the curriculum. Show to what extent the object of keeping the subject in the curriculum is realised, and point out the weaknesses which are observed to remain and the way you will remedy them (1964)
3. क्या आप समझते हैं कि बहु-उद्देशीय विद्यालयों की योजना आपके क्षेत्र में मुचाद रूप में चल रही है ? आपके विचार में इसमें क्या कठिनाई हैं और आप उन्हें किस प्रकार दूर करेंगे ? (१९६६)

## अध्याय ८

### शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन

केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें देश में शिक्षा-उन्नयन के लिए अनेक प्रयत्न कर रही हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए ही संविधान में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा करने का प्रावधान रखा गया है। संविधान के इस प्रावधान की पूर्ति के लिए प्रांतीय सरकार अपने प्रांतों में नवीन विद्यालयों की स्थापना कर रही हैं। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नित नवीन प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। परन्तु अपव्यय एवं अवरोधन के कारण शिक्षा के विस्तार में आसानी से मफलता नहीं मिल रही है।

अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या कोई नवीन नहीं है। सन् १९२७ में ब्रिटिश सरकार ने मायमन कमीशन की नियुक्ति भारत के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे सामाजिक, आर्थिक, दैक्षिक आदि, में हुई प्रगति का निरीक्षण करने के लिए की। मायमन कमीशन ने भारत में शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए एक सहायक समिति पर कमिशन ऑफ़ इन्क्वायरी की अध्यक्षता में सन् १९३६ में बनाई। इस समिति ने ही सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया। समिति के अनुसार अपव्यय तथा अवरोधन में प्राथमिक शिक्षा में अनेक बाध उत्पन्न हो गये हैं जिनके कारण माध्यम-प्रकार के कार्य में बाधा पड़ गई है।

अपव्यय तथा अवरोधन का अर्थ

(१) अपव्यय प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई पूर्ण करने में पूर्ण ही बालक का शिक्षालय में रुका देना अपव्यय कहलाता है। इटाली समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ नं० ६३ पर अपव्यय की परिभाषा इस प्रकार दी है— "By wastage we mean the premature withdrawal of children from school at any stage before the completion of primary course" उदाहरण के लिए,

कोई छात्र विद्यालय में प्रवेश करने के २ या ३ वर्ष बाद विद्यालय छोड़ देना है तो उसकी पढ़ाई अनूरी रह जाती है। विद्यालय छोड़ने के बाद जो कुछ भी उसने सीखा, उसको भूल जाता है। इस प्रकार समय, धन तथा छात्र की क्षति का अपभ्यय होता है।

(२) अवरोधन—किसी छात्र का एक ही कक्षा में एक वर्ष में अधिक रुक जाना ही अवरोधन कहलाता है। हर्टाग मर्मिनि ने अवरोधन की परिभाषा देते हुए लिखा है— "By stagnation we mean the retention in a lower class of a child for a period of more than one year" छात्र के एक ही कक्षा में बार-बार अनुत्तीर्ण होने से उसकी शिक्षा की प्रगति मारी जाती है। छात्र निरुत्साहित भी होता है। अनुत्तीर्ण होने से छात्र का बहुसूक्ष्म समय नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही जब उसके साथी उसमें आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें हीनता की भावना घर कर जाती है। अवरोधन के कारण प्राथमिक विद्यालय के ४ या ५ वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम को छात्र ६ या ७ वर्ष में पूरा करते हैं। अवरोधन में दो हानियाँ होती हैं—(१) एक तो छात्रों के समय एवं शक्ति का अपभ्यय होता है, तथा (२) दूसरे एक ही कक्षा में अधिक छात्रों के अनुत्तीर्ण होने पर नवीन छात्रों का प्रवेश रुक जाता है।

के० जी० मंडन ने अपभ्यय की समस्या को स्पष्ट करने के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। सन् १९५२-५३ में कक्षा १ में शिक्षा प्राप्त करने वाले १०० छात्रों में से सन् १९५५-५६ तक कक्षा ८ में केवल ४३ छात्र ही पहुँच पाये। इस प्रकार ५७ प्रतिशत छात्रों पर धन और समय का अपभ्यय हुआ।

## अपभ्यय और अवरोधन के कारण

### १ शारीरिक या व्यक्तिगत कारण

(अ) अस्वस्थता—हमारे देश में बच्चों की मस्तुलित भोजन प्राप्त नहीं होता है और न सरकार की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण की ही सुविधा है। इसका परिणाम यह होता है कि अनेक बच्चे मम्बी बीमारी के कारण विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। इस अवधि में पाठ्यक्रम का अधिबाध भाग कक्षा में पढ़ाये जाने के कारण ये अस्वस्थ बालक पिछड़ जाते हैं। अस्वस्थता के कारण छात्र एक कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और यह उनके अवरोधन का कारण होती है।

(आ) पढ़ाई में कमबोरी—भारतवर्ष में दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली के कारण अनेक छात्र भाग की कक्षा में संयोगवश चढ़ जाते हैं। इन छात्रों का सम्प्राप्ति का आधार कमबोरी ही रहता है। उच्च कक्षाओं में पहुँचने पर ये छात्र अनुत्तीर्ण होते रहते हैं या कभी-कभी कुछ छात्र बुद्धि कम होते हुए भी उच्च कक्षाओं में ऐसे विषयों का चयन कर लेते हैं जिनको वे समझ नहीं सकते, उदाहरण के लिए, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित बुद्धि-सन्धि होनी चाहिए

पाठ्यक्रम	इंडि-नैटिव का मध्यमान
प्राथमिक	११.४
विज्ञान	१.०८
साहित्य	१.६०
व्याख्यान	१.०४

सबसे पाठ्य विषय का चयन करने के कारण छात्र उसमें कई वर्षों तक अनुत्तीर्ण होते रहते हैं। कभी-कभी सयन पाठ्य विषय का चयन माना-रिना की उस प्रवृत्तिकाशाओं के कारण भी हो जाता है।

(इ) पाठ्यक्रम से अर्थात् प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम इतना जटिल, नीरस और अनुपयोगी होता है कि छात्रों का मन उसको पढ़ने में नहीं लगता है। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम से अनेक विषयों की भरमार कर दी गई है। अधिकांश विषय ऐसे होते हैं जिनमें छात्रों को रूचि नहीं आती है। परिणामस्वरूप, छात्र अधिक मर्यादा में इन विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं।

(ई) अध्यापक के प्रति अर्थात् कभी-कभी कुछ छात्र कुछ अध्यापकों में उनके व्यवहार या अप्रभावशाली क्षमता के कारण घृणा करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब भी वह अध्यापक कक्षा में आता है तो उसके अध्यापन में छात्र रुचि नहीं लेते या अध्यापक के आगे से पूर्व ही कक्षा छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे छात्र उस अध्यापक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय में कमजोर रहते हैं और अधिकतर उस विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यह भी अवरोधन का एक कारण है।

## २. सामाजिक कारण

(अ) कुटुम्बिकता—हमारा समाज परम्परागत दृष्टि में इनका बकड़ा हुआ है कि अनेक कुटुम्ब प्रथाओं के कारण बालिकाओं की शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध किया जाता है। गाँवों में बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालयों का अभाव है। ग्रामीण अभिभावक बालिकाओं को बालकों के विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजने के विरोधी हैं। कभी-कभी दो या तीन वर्ष बाद ही अपनी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बिना ही विद्यालय में हटा लेते हैं। इस प्रकार यह अवरोधन का कारण है।

(आ) पर्व-प्रथा तथा बाल-विवाह—भारतवर्ष में पर्व-प्रथा तथा बाल-विवाह की कुरीति के कारण दूसरी या तीसरी कक्षा में ज्यादातर बालिकाएँ पहुँची कि अभिभावक उसका विवाह कर देते हैं। इस प्रकार उसका अध्ययन पूर्ण नहीं हो पाता है। यह बाल-विवाह बालकों में भी अपभ्यव और अवरोधन का कारण होता है।

(इ) अछूत प्रथा—हमारे देश में अछूत प्रथा के प्रचलन से भी अछूत बालिका की शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है, परन्तु अब धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अधिक परिवर्तन हो रहा है।

(ई) बुरी संगत—विद्यालयों में सभी प्रकार के छात्र पाये जाते हैं। कुछ गन्दी श्रादतो वाले छात्रों का एक समूह बन जाता है जो विद्यालय में बाहर ही अपना समय व्यतीत करते हैं। जब छात्र इस बुरी संगत में फँस जाते हैं तो उनके प्रभाव में आकर कक्षाएँ छोड़ना तो एक सामान्य बात हो जाती है। ये छात्र एक कक्षा में ही दो या तीन वर्ष तक रुके रहते हैं। कभी-कभी पुराने छात्र नवीन छात्रों को तंग करते हैं। इस परेशानी के कारण कुछ छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं।

### ३. विद्यालय से सम्बन्धित कारण

(अ) अप्रभावशाली अध्यापन—प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर नीरम तथा अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। अप्रभावशाली शिक्षण के अनेक कठिन विषयों को समझने में छात्रों को कठिनाई होती है, अप्रभावशाली अध्यापन का कारण योग्य तथा प्रसिद्धित अध्यापकों का अभाव है। प्रशिक्षित अध्यापक भी उपेक्षा की नीति के कारण प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। अध्यापकों द्वारा प्रतिभावशाली तथा मन्द बुद्धि के बालकों को एक ही शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाया जाता है। परिणामस्वरूप, दोनों ही प्रकार के छात्रों को लाभ नहीं हो पाता है। छात्रों को रिपय स्पष्ट न होने पर वे उसमें अनुमीर्ण हो जाते हैं।

(आ) शारीरिक दृष्ट—भारतवर्ष में आज भी नवीन अध्यापक इन मनो-वैज्ञानिक युग में अपने पूर्वज अध्यापकों का अनुकरण करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक छात्रों को छोटी-छोटी बातों पर ही मारने-पीटने लगते हैं। इस प्रकार के अनेक छात्र मिलेंगे जो कि मार-पीट के कारण विद्यालय छोड़ कर घर बैठ जाते हैं।

(इ) अध्यापकों में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का अभाव—कहा यह जाता है कि अध्यापक को छात्र का एक अच्छा मित्र होना चाहिए। उसको छात्र की प्रत्येक कठिनाई समझ कर उसके निवारण हेतु प्रयत्न करना चाहिए, परन्तु आज के अध्यापकों में बच्चों के प्रति स्नेह का अभाव पाया जाता है। उनमें सावैगिक अस्थिरता पाई जाती है। छोटी-छोटी बातों पर ही वे भड़क उठते हैं। इसके साथ ही कार्य करने की इच्छा से तो बराम्ब सा लिया प्रतीत होता है। छात्र अपनी कठिनाई या समस्या लेकर पहुँचता है तो अध्यापक महोदय की भृशुटी तन जाती है, बेहरे पर ऐसा भाव आ जाता है कि छात्र को अपनी बात कहने का साहस तक नहीं होता। अपनी उन समस्याओं के कारण बहुत से छात्र बीच में ही अध्ययन छोड़ देते हैं।

(ई) विद्यालय के वातावरण का आकर्षक न होना—प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ छोटी आयु के बालक अध्ययन हेतु आते हैं उनके लिए विद्यालय का वातावरण आकर्षक होना चाहिए। आरकल विद्यालयों में खेल-कूद की व्यवस्था होने तथा सभी उपकरणों एवं फर्नीचर आदि के अभाव से बच्चों का मन विद्यालय में नहीं लगता



को नहीं समझते हैं। वे अपनी इच्छानुसार चाहे जब तनिक आवश्यकता होने पर बालको को विद्यालय जाने से बन्द कर देने हैं।

(आ) अध्यापिकाओं का अभाव—जिन स्थानों पर बालिका विद्यालय स्थापित भी किये हैं उनके लिए पर्याप्त मक्या में अध्यापिकाएँ न मिलने की समस्या रहती है। पर्याप्त मक्या में अध्यापिकाएँ न होने पर छात्राओं पर मनोपन्नक ध्यान नहीं दिया जा सकता है। उनकी पढ़ाई ठीक नहीं चल पाती है। इसका परिणाम अधिक मक्या में छात्राओं की असफलता होती है।

(इ) विद्यालयों का दूर-दूर होना—भारतवर्ष तो गाँवों का देश है। यहाँ के अनेक गाँवों में प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है। बालकों का दूर-दूर के गाँवों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। कुछ समय बाद अनेक बालक दूरी में ऊँचकर विद्यालय जाना छोड़ देने हैं।

### अव्यय एवं अवरोधन-निवारण के उपाय

#### प्राथमिक स्तर पर

प्राथमिक शिक्षा में अव्यय एवं अवरोधन रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय अधिक महत्वपूर्ण हैं।

(अ) अनिवार्य शिक्षा—सभी बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य की जाय तथा ऐसा अधिनियम बनाया जाय कि शिक्षा की अवधि का पूर्ण किये बिना कोई भी बालक बीच में विद्यालय नहीं छोड़ सके। ऐसा करने वाले बच्चों के अभिभावक पर दण्ड होना चाहिये।

(आ) उपस्थिति अधिकारियों की नियुक्ति—अधिक मक्या में उपस्थिति अधिकारियों की नियुक्ति की जाय। वे अधिकारी ऐसे व्यक्ति हों जो अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करके उनको इस बात के लिए तैयार करें ताकि वे बीच में से ही बालक को विद्यालय जाने से न रोके।

(इ) निम्न छात्रों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र तथा पुस्तकें—जिन बच्चों के पिता निर्धनता के कारण अपने बच्चों की पुस्तकें आदि भी नहीं खरीद पाते हैं, सरकार की ओर से उनको मुक्त भोजन, वस्त्र तथा पुस्तकों की सुविधा मिलनी चाहिए।

(ई) कक्षा में कम छात्र—कक्षा के आकार को बढ़ाया न जाये। एक कक्षा में कम छात्र रहे जायें ताकि अध्यापक छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सके।

(उ) अध्यापक-अभिभावक मध्य—विद्यालयों में अध्यापक-अभिभावक सम्पर्क बनाया जाय जिससे अभिभावकों के साथ भी इस समस्या के निवारण के लिए विचार विमर्श किया जा सके।

(ऊ) शिक्षण-व्यवस्था में सुधार—प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया जाये। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। अध्यापकों को मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि का प्रयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाये।

(ए) एक अध्यापक बाने विद्यालयों की समाप्ति—एक अध्यापक को विद्यालयों को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि एक अध्यापक न तो सभी छात्रों देख-भाल रख सकता है और न पढ़ा ही सकता है।

(ऐ) प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार—ग्रामीण निरक्षर अभिभावकों को शिक्षा महत्व समझाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार किया जाय। इसके प्रचार में सामाजिक समस्याओं का निराकरण होगा। रुढ़िवादित्वा समाप्त होगी।

(ओ) स्वास्थ्य निरीक्षण—गर्भधारण की जाँच में छात्रों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए चिकित्सकों को व्यवस्था की जाय। व्यक्तिगत तथा सरकारी प्रयत्नों में बच्चों के लिए पोष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाय।

### माध्यमिक स्तर के लिए सुझाव

(अ) विविध पाठ्यक्रम—माध्यमिक कक्षाओं में विविध पाठ्यक्रम की इच्छा होती चाहिए ताकि छात्र अपनी विभिन्न आवश्यकताओं, योग्यताओं एवं अभिरुचि के अनुसार पाठ्य-विषयों का चुनाव कर सकें। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निरूपित होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने वर्ष १९५२-५३ में विविध पाठ्यक्रम की सुझाव दिया था।

(आ) दसवीं कक्षा के बाद छात्रों की छुट्टी—दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों को विविध पाठ्यक्रम में से एक पाठ्यक्रम चुनना होगा। इस अवसर पर छात्रों की सहायता की जाय ताकि वे अपनी योग्यता तथा बुद्धि के अनुसार ही पाठ्य-विषय चुनें।

(इ) निर्देशन की व्यवस्था—इस स्तर पर छात्रों को विषयों के चुनाव, व्यवसाय के चुनाव तथा उचित समायोजन के लिए संश्लेषण एवं व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। छात्रों की रुचियों का पता लगाने के लिए विद्यालय में विविध क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कला स्तव, संगीत स्तव, काष्ठ कला, कढ़ाई-बुनाई, बाहरी खेल, बागवानी, प्रकाशन, छात्र सच आदि की व्यवस्था विद्यालयों में हो जिससे छात्र उनमें स्वयंनुसार भाग ले सकें।

(ई) परीक्षा का व्यवस्थित रूप हो—परीक्षा के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह एक अच्छा सेवक तथा बुरा मालिक है (The examination system is a good servant and a bad master)। जाजकल निबन्ध परीक्षाएँ प्रयोग में आती हैं। इनमें अनेक दोष होते हैं। अतः इनके स्थान पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रयोग होना चाहिए। मुद्रालय आयोग ने बाह्य परीक्षाओं की सख्या कम करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही आन्तरिक मूल्यांकन को प्रोत्साहन दिया जाये।

(उ) पुस्तकालय की सुविधा—प्रत्येक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को अच्छे पुस्तकालय की सुविधा दी जाय। इनमें छात्रों को पुस्तकें



पढ़ने में रचि विकसित हानी है। पुस्तकालय का वातावरण ऐसा हो जिसमें छात्रों का अध्ययन की प्रेरणा मिल सके।

(ऊ) योग्य तथा कुशल प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति—प्रधानाध्यापक को कार्य-कुशलता पर विद्यालय को प्रगति निर्भर करनी है। उसमें मजठन शक्ति, दृढ़ता, उत्तम चरित्र, आत्म नियंत्रण, मौलिकता, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुण होने चाहिए। उसके कुशल प्रशासन में विद्यालय में अध्यापन का स्तर ऊँचा उठ सकता है।

(ए) फसल के समय छुट्टी—श्रीष्मावकाश तथा अन्य छुट्टियों में कभी करके फसल बोने या कटने के समय छुट्टियाँ की जायें तो बच्चे घर पर बिना हानि के अपने माता-पिता की कार्य में सहायता कर सकते हैं।

### सामान्य सुझाव

१. काल-विवाह को रोकने के लिए कड़े कानून बनाये जायें।
२. पाठ्यक्रम को मजबूत तथा रोचक बनाया जाय। गणित, विज्ञान आदि कठिन विषयों को छात्रों के सम्मुख आकर्षक ढंग में प्रस्तुत किया जाय।
३. विद्यालयों के वातावरण को रोचक बनाने के लिए विद्यालयों में खेल-कूद, मनोरंजन आदि की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
४. विद्यालयों में विभिन्न हस्तकलाओं की निखाने की व्यवस्था की जाय।
५. विद्यालयों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाय जहाँ छात्र सरलता से पहुँच जायें।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

१. शिक्षा में अव्यय-अवरोधन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।
२. माध्यमिक स्तर पर अवरोधन को रोकने के लिए अपने सुझाव दीजिए।

राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

१. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(अ) शिक्षा में अव्यय एवं अवरोधन (१९६६)।

## अध्याय ६

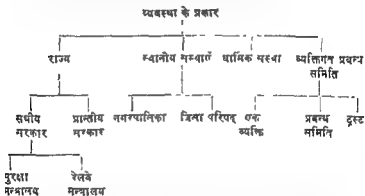
### शिक्षा का प्रबन्ध करने वाली संस्थाएँ

भारतवर्ष प्राचीन काल से ही शिक्षा का केन्द्र रहा है। एक० डब्ल्यू० ओमस ने भी अपनी एक पुस्तक में यह वर्णन किया है कि "भारतवर्ष के अनिरिक्त अन्य कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम होने प्राचीन समय से प्रारम्भ हुआ हो।" हमने स्पष्ट है कि भारतवासी यद्वैव ने शिक्षा के प्रसार में रति तेरे रह है। भारतीय शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करने में स्पष्ट है कि वैदिक काल या बौद्ध काल में यहाँ पर विद्यालयों का रूप कुछ भी रहा हो परन्तु उनका समाज में सभी प्रकार की सुश्रमता प्राप्त होती थी। मुस्लिम काल में भी शिक्षा का प्रसार हुआ। यह हमारी बात है कि मुस्लिम साम्राज्य में कुछ उदार तथा कुछ अनुदार थे। उदाहरण के लिए, अकबर, औरंगजेब आदि अनुदार शासक थे जिन्होंने हिन्दू शिक्षा को नष्ट करके उनके स्थान पर इस्लामी शिक्षा और विज्ञानों का प्रसार किया। ये दो प्रकार के शासकों द्वारा शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की गईं। फिर वहाँ पर पश्चिमी देशों ने व्यापार के लिए प्रवेश किया। परन्तु धीरे-धीरे इनमें से ही कुछ वहाँ के शासक बन गये। इनके साथ ईसाई मिशनरियों ने इस देश में प्रवेश किया। इन मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इसीलिए उन्होंने शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित कीं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में पारम्परिक मिशनरियों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने ही भारत में आधुनिक शिक्षा-संस्थाओं को प्रारम्भ किया। आधुनिक वर्णन में स्पष्ट है कि भारतवर्ष में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना केवल राजा द्वारा ही नहीं की गई परन्तु उदार हृदय तथा शिक्षा प्रीति अनेक धनी-मानों व्यक्ति या धार्मिक संस्थानों द्वारा भी शिक्षा प्रसार हुआ जिससे-संस्थाओं का स्थापित किया गया है।

भारतवर्ष में जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन था तभी न अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा में रुचि ली प्रारम्भ किया। परन्तु उन समय अनेक ऐसे विचारधारा

पाप्य उठ खड़े हुए कि कम्पनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अधिक सतोपजनक कार्य न कर सके। धीरे-धीरे अखीर सरकार भारतवासियों द्वारा बार-बार कहने पर शिक्षा क्षेत्र में रुचि जेने लगी। परिणामस्वरूप, उन्होंने अनेक स्थानों पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने के बाद तब सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह देश में शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करे।

**व्यवस्था के प्रकार**—माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सर्वेक्षण काल में यह देखा कि माध्यमिक विद्यालय सरकार के अतिरिक्त अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा भी चलाये जाते हैं। इसी आधार पर आयोग ने प्रबन्ध एवं व्यवस्था की दृष्टि से माध्यमिक विद्यालयों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया



(१) राज्य द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालय—भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही विद्यालयों की स्थापना राज्य द्वारा होती रही है। माध्यमिक शिक्षा जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है, के विकास में सरकार ने सर्वेसर्वाकार दिया है। अखीर ने भी अपने समय में प्राथमिक या विषयविद्यालय शिक्षा की अपेक्षा माध्यमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने अनेक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। यह दूसरी बात है कि माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य आज की सरकार के उद्देश्य में भिन्न था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् यहाँ की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने भी माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की है।

(अ) केन्द्रीय सरकार—वर्गे शिक्षा प्रान्तीय विषय है तो भी भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार शिक्षा के प्रसार के लिए सर्वे प्रयत्न करती रही है। समय-समय पर शिक्षा आयोगों का गठन करके प्रान्तीय सरकारों का पथ-प्रदर्शन भी केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता रहा है। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र-प्रणामित क्षेत्रों में तो माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए ही हैं परन्तु इसके साथ ही और भी प्रान्तों में उनकी

स्थापना कर अपने उत्तराधिकार का पूरा किया है। केन्द्रीय सरकार के तीन मन्त्रालय प्रमुख रूप से माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना में सक्रिय रवि लेते हैं जो कि निम्नलिखित हैं

- (i) शिक्षा मन्त्रालय,
- (ii) मुरादा मन्त्रालय,
- (iii) रेलवे मन्त्रालय।

**शिक्षा मन्त्रालय**—केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा भी संकेन्द्री विद्यालयों की स्थापना की गई है। इस प्रकार के विद्यालयों में सभी प्रकार की मुविधाएँ अच्चापको एवं छात्रों को उपलब्ध होती रहती हैं। योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है तथा छात्रों के शारीरिक विकास के लिए खेलों की व्यवस्था होती है। पर्याप्त सामग्री और बड़े-बड़े प्रीडामण इन विद्यालयों के अधिकार में होते हैं। अध्यापकों को केन्द्रीय कर्मचारियों का वेतन मिलता है।

**मुरादा मन्त्रालय**—मुरादा मन्त्रालय भी शिक्षा प्रसार में सहयोग देता है। इसके द्वारा देश में 'सैनिक स्कूल' तथा 'किंग जार्ज स्कूल' की स्थापना अनेक स्थानों पर की गई है। कुछ विद्यालय तो सैनिकों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी मुविधा प्रदान करने की दृष्टि से स्थापित किए गये हैं। सैनिक स्कूलों में छात्रों को शिक्षित करके मुरादा मेना के लिए उनको तैयार किया जाता है। इन विद्यालयों में छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए पूर्ण व्यवस्था रहती है।

**रेलवे मन्त्रालय**—रेलवे मन्त्रालय अपने कर्मचारियों को सभी प्रकार की मुविधाएँ प्रदान करता है। इनमें से एक मुविधा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करना भी है। इसीलिए रेलवे मन्त्रालय ने भी देश में कुछ माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की है। इन विद्यालयों में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है।

(ब) प्रान्तीय सरकार—शिक्षा प्रान्तीय विषय होने से इनका प्रसार करना प्रान्तीय सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए प्रान्तीय सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राजकीय माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापित किया है। विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में सभी प्रान्तों में समान नीति नहीं है। कुछ प्रान्तों में राजकीय विद्यालयों की स्थापना आदर्श विद्यालय के रूप में की जाती है ताकि अन्य विद्यालय उनका ही अनुकरण करें और उसी प्रकार की कार्य-व्यवस्था अपने यहाँ भी अपनाएँ। यह नीति उन प्रान्तों में ही अपनाई जाती है जहाँ पर व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों द्वारा स्थापित विद्यालयों की संख्या अधिक होती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में केवल एक माध्यमिक या इन्टरमीडिएट विद्यालय रखा है। इसका कारण वहाँ पर व्यक्तिगत विद्यालयों की संख्या का अधिक होना है। इसके विपरीत, कुछ प्रान्तों में संख्या राजकीय विद्यालयों की है। यह नीति उन प्रान्तों में ही रहती है जहाँ

पर विद्यालयों की संख्या कम होती है या जो राज्य शिक्षा की दृष्टि में पिछड़े हुए हैं। इन प्रान्तों में शिक्षा के प्रसार तथा जनता को कम व्यवपूर्ण शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रान्तीय सरकार को विद्यालय स्थापित करने होते हैं। राजस्थान प्रान्त में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा राजकीय विद्यालयों की संख्या अधिक है। इसका कारण इस प्रान्त का शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पिछड़ा होना है।

राजकीय नियंत्रण के दोष— यद्यप्य मध्य है कि राजकीय विद्यालयों में प्रतिष्ठित एवं योग्य अध्यापक होते हैं, वे साधन-सम्पन्न होते हैं तथा छात्रों एवं अध्यापकों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। राजकीय विद्यालय के अध्यापक को सेवा की सुरक्षा का विश्वास रहता है। इसी विशेषता के कारण योग्य व्यक्ति व्यक्तिगत समस्याओं की अपेक्षा राजकीय समस्याओं में जाना अधिक पसन्द करता है। इतना सब होने हुए भी ऐसी बात नहीं कि राजकीय विद्यालयों में कोई दोष न हो। राजकीय नियंत्रण में दो प्रमुख दोष हैं

(अ) विभागीय नियंत्रण, (आ) स्थानान्तरण।

विदेशों की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते समय हमने यह देखा था कि वहाँ के अध्यापकों को बर्बाद करने की अधिक सम्भ्रमता है। किसी विद्यालय के अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक मिनकर विद्यालय का पाठ्यक्रम निश्चित कर लेते हैं। परन्तु हमारे यहाँ अध्यापकों को विभागीय जादेशों का पालन करना होता है। उनको कार्य करने की स्वतन्त्रता बहुत कम मिलती है। राजकीय विद्यालयों में दूसरा प्रमुख दोष अध्यापकों के स्थानांतरण से सम्बन्धित है। इन विद्यालयों में अध्यापकों को एक विद्यालय में अधिक समय तक नहीं रहने दिया जाता है। परिणामतः अध्यापक उस विद्यालय की समस्याओं में कोई रुचि नहीं लेता है जबकि उस में आशा की जाती है कि वह स्थानीय समाज तथा छात्रों के निकट सम्पर्क में आकर उनकी समस्याओं को समझे तथा उनके विकास के लिए प्रयत्न करे। राजकीय विद्यालय में कोई अध्यापक पहुँचकर जब तक उस शिक्षण-संस्था की कार्य प्रणाली को समझ पाता है तब तक उसको अन्य विद्यालय में भेज दिया जाता है। ये स्थानांतरण भी राजनीतिक कारण या व्यक्तिगत बर्भनस्य के कारण होते हैं।

(२) स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय— कुछ प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं द्वारा भी माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन स्थानीय संस्थाओं में दो प्रमुख हैं जो कि शिक्षा के प्रसार में अधिक सहयोग दे रही हैं— प्रथम नगरपालिका और दूसरी जिला परिषद। नगरों में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना तथा उनका संचालन नगरपालिका या महानगरपालिका करती हैं। परन्तु सभी प्रान्तों में तथा प्रत्येक नगरपालिका में ऐसा नहीं है। उगी प्रकार कुछ जिला परिषदों द्वारा भी माध्यमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं। इनों द्वारा संचालित विद्यालय राजकीय विद्यालयों की भाँति आदर्श विद्यालय नहीं होते हैं। स्थानीय



ने विशिष्ट स्थान प्राप्त नहीं है जिसकी शिक्षा प्रदान की जा सके। कुछ विद्यालयों द्वारा साम्प्रदायिकता की भावना पैदा की जाती है। देश में आज राष्ट्रीय एवं जातिगत एकता की आवश्यकता है। कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित विद्यालय साम्प्रदायिकता की भावना फैलाकर देश की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। धार्मिक संस्थाओं के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति निष्पक्षता से नहीं की जाती है। नियुक्ति के अवसर पर योग्य व्यक्ति की अपेक्षा अपने धर्म के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। अध्यापकों में उनकी इच्छा के विरुद्ध अनेक धार्मिक कार्य कराये जाते हैं। प्रबन्ध समिति सभी अध्यापकों और छात्रों के साथ गणपति-रहित व्यवहार नहीं करती है।

(४) व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों द्वारा संचालित विद्यालय—प्रारम्भ में इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए की गई जिससे इस प्रकार से शिक्षित छात्र अंग्रेजी प्रशासन को उखाड़ फेंकने में सहायता दें। इनकी शिक्षा पद्धति ब्रिटिश पद्धति में भिन्न थी। वर्तमान प्रजातन्त्रीय प्रणाली में व्यक्तिगत प्रबन्ध समिति द्वारा स्थापित विद्यालय प्रजातन्त्रीय विद्यालयों को प्रदर्शित करते हैं। जिस देश के व्यक्ति स्वयं शिक्षा-प्रसार में रुचि ले तथा उनका मजबूत उचित प्रकार से करें यह एक सफल प्रजातन्त्रीय प्रणाली का लक्षण है। भारतवर्ष शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा देश है। अधिकांश व्यक्ति देश के लिए कलक हैं। मजिधान के अनुसार शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों का है। परन्तु भारत जैसे पिछड़े देश में जहाँ पर शिक्षा प्रसार की अभी अत्यधिक आवश्यकता है, राज्य को सहयोग देना अति आवश्यक है। क्योंकि राज्य स्वयं इनके विस्तृत कार्य को नहीं कर सकता है। अतः व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियाँ माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करके देश में शिक्षा के प्रचार सम्बन्धी कार्य में राज्य का हाथ बँटा रही है।

(क) एक व्यक्ति द्वारा स्थापित विद्यालय—देश के विभिन्न भागों में शिक्षा प्रेमी धनी व्यक्तियों ने माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की है। इनके द्वारा स्थापित विद्यालयों की संख्या अधिक धोचनीय नहीं है। परन्तु इस प्रकार के विद्यालय उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होते हैं। वह विद्यालय के कार्यक्रम से सम्बन्धित नीति निर्धारित करता है। विद्यालय को स्थापित करने वाले व्यक्ति इनको अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति मानते हैं। अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं होती है। कुछ लोगों के मतानुसार इस प्रकार के विद्यालयों में अच्छा वातावरण पाया जाता है। एक व्यक्ति ही प्रबन्धक होने में अध्यापकों में गुटबन्दी नहीं पाई जाती है तथा इसके साथ ही अध्यापकों को प्रबन्ध समिति के अनेक सदस्य प्रमत्त नहीं करने पड़ते हैं। मुद्रास्फीयता के कारण से इस प्रकार के विद्यालयों की अधिक आलोचना की है। उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति एक बार विद्यालय की स्थापना करने के बाद फिर उसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। आयोग ने लिखा है कोई भी माध्यमिक विद्यालय एक व्यक्ति

संस्थाओं पर धनभाव के कारण विद्यालयों की मात्र-गामभी पर अधिक धन व्यय नहीं किया जाता है। इन विद्यालयों में एक दोष स्थायी समस्याओं की राजनीतिक गुटबन्दी का प्रभाव है। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या अध्यापक स्वतंत्र नहीं होते हैं। नगरपालिका के सदस्य समय-समय पर विद्यालय की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं। स्थानीय समस्याओं के सदस्य अध्यापकों को अधिक परेक्षण करते हैं। इनकी गुटबन्दी के कारण विद्यालय के अध्यापकों में भी गुटबन्दी हो जाती है और विद्यालय का बनावट बूझा हो जाता है।

साध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्थानीय समस्याओं द्वारा मंचालित विद्यालयों के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि किसी संस्था के विद्यालयों का प्रबन्ध करने के लिए अधिक से अधिक ६ सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनानी चाहिए। समस्याओं के सदस्यों को विद्यालय के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह समिति विद्यालयों में सम्बन्धित नीति निर्धारित किया करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्थानीय संस्था के सभी सदस्य विद्यालयों का निरीक्षण करने पढ़ें और वहीं प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के कार्य में हस्तक्षेप करें।

(३) धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित विद्यालय—बुद्ध धार्मिक समस्याएँ विद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा के प्रसार में प्राचीन समय से ही सहयोग देती रही हैं। भारतवर्ष में आज भी अनेक साध्यमिक विद्यालय इन धार्मिक संस्थाओं के नियन्त्रण में चल रहे हैं। यह सत्य है कि धार्मिक संस्थाएँ विद्यालयों की स्थापना अपने धर्म-प्रचार के लिए करती हैं। परन्तु आज के धर्म-निरपेक्ष राज्य में यह सब करना सम्भव नहीं है क्योंकि सरकार की नीति ही अब यह है कि किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप में नहीं दी जा सकती है। अर्बेज मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत के विभिन्न भागों में साध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जो कि आज भी शिक्षा प्रसारण में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। इन विद्यालयों की भी अब राजकीय आर्थिक अनुदान प्राप्त होता है। वैसे इनको मिशन के द्वारा ही आर्थिक सहायता पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इसी कारण अच्छे भवन, तेल के मैदान तथा अन्य सामग्री आदि की दृष्टि में इन विद्यालयों की स्थिति सतोपजनक है। भारतवर्ष की दूसरी प्रमुख धार्मिक संस्था जार्ज समाज है जिसे देश में अनेक दयानन्द साध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की है। इन विद्यालयों को स्थापित करने का उद्देश्य हिन्दू धर्म की रक्षा करना रहा है। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में जार्ज समाज के विद्यालयों का सहयोग सभी धार्मिक संस्थाओं से अधिक है। इनके अतिरिक्त रामकृष्ण मिशन, सनातन धर्म आदि ने भी विद्यालय स्थापित किए हैं।

टोप—धार्मिक संस्थाओं के द्वारा मंचालित साध्यमिक विद्यालयों में कुछ गुण होने के साथ ही दोष भी अनेक हैं। सर्वप्रथम बात तो भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं। सविधान के अनुसार भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य माना गया है। अब किसी धर्म की शिक्षा छात्रों को नहीं दी जा सकती है। यहाँ किसी विशेष धर्म



को विशिष्ट स्थान प्राप्त नहीं है जिसकी शिक्षा प्रदान की जा सके। कुछ विद्यालयों के द्वारा साम्प्रदायिकता की भावना पैदा की जाती है। देश में आज राष्ट्रीय एक भावात्मक एकता की आवश्यकता है। कुछ धार्मिक मस्थाओं द्वारा स्थापित विद्यालय साम्प्रदायिकता की भावना फैलाकर देश की राष्ट्रीय एकता को समाप्त करते हैं। धार्मिक मस्थाओं के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति निष्पक्षता से नहीं की जाती है। नियुक्ति के अवसर पर योग्य व्यक्ति की अपेक्षा अपने धर्म के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। अध्यापकों में उनकी इच्छा के विरुद्ध अनेक धार्मिक कार्य काबाये जाते हैं। प्रबन्ध समिति मभी अध्यापकों और छात्रों के साथ गठपान-रहित व्यवहार नहीं करती है।

(४) व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों द्वारा संचालित विद्यालय—प्रारम्भ में इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए की गई जिससे इस प्रकार में शिक्षित छात्र अच्युती प्रमाणन से उल्लास फेंकने में सहायता दें। इनकी शिक्षा पद्धति विदेशी पद्धति से भिन्न थी। वर्तमान प्रजातन्त्रीय प्रणाली में व्यक्तिगत प्रबन्ध समिति द्वारा स्थापित विद्यालय प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों को प्रदर्शित करते हैं। जिस देश के व्यक्ति स्वयं शिक्षा-प्रसार में रुचि लें तथा उसका संचालन उचित प्रकार में करें यह एक सफल प्रजातन्त्रीय प्रणाली का सूत्रक है। भारतवर्ष शिक्षा की दृष्टि में पिछड़ा देश है। अनिश्चित व्यक्ति देश के लिए कर्त्तक हैं। मरिद्यान के अनुसार शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों का है। परन्तु भारत जैसे पिछड़े देश में जहाँ पर शिक्षा प्रसार की अभी अत्यधिक आवश्यकता है, राज्य को सहयोग देना अनिवार्य आवश्यक है। क्योंकि राज्य स्वयं इनके विस्तृत कार्य को नहीं कर सकता है, अतः व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियाँ माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करके देश में शिक्षा के प्रचार सम्बन्धी कार्य में राज्य का हाथ बढ़ा रही है।

(क) एक व्यक्ति द्वारा स्थापित विद्यालय—देश के विभिन्न भागों में शिक्षा प्रेमी धनी व्यक्तियों ने माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की है। इनके द्वारा स्थापित विद्यालयों की दशा अधिक धोचनीय नहीं है। परन्तु इस प्रकार के विद्यालय उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होते हैं। वह विद्यालय के कार्यक्रम में सम्बन्धित नीति निर्धारित करता है। विद्यालय की स्थापित करने वाले व्यक्ति इनको अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति मानते हैं। अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को कार्य करने की स्थिति नहीं होती है। कुछ लोगों के मतानुसार इस प्रकार के विद्यालयों में अच्छा वातावरण पाया जाता है। एक व्यक्ति ही प्रबन्धक होने में अध्यापकों में घुटवन्दी नहीं पाई जाती है तथा इसके साथ ही अध्यापकों को प्रबन्ध समिति के अनेक मदस्य प्रमत्त नहीं करने पड़ते हैं। मुद्रानियंत्रण आयोग ने इस प्रकार के विद्यालयों की अधिक आलोचना की है। उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति एक बार विद्यालय की स्थापना करने के बाद फिर उसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। आयोग ने निम्ना है कोई भी माध्यमिक विद्यालय एक व्यक्ति

मंथानों पर धनोन्माद के कारण विद्यालयों की मात्र-गणनीय पर अधिक धन खर्च नहीं किया जाता है। इन विद्यालयों में एक ही स्वतन्त्र संस्थाओं की सामाजिक गुटबन्दी का प्रभाव है। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या अध्यापक स्वतन्त्र नहीं होंगे। नगरपालिका के महसूब समय-समय पर विद्यालय की कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप करने देंगे। स्थानीय संस्थाओं के महसूब अध्यापकों को अधिक परेमान करने देंगे। इनकी गुटबन्दी के कारण विद्यालय के अध्यापकों में भी गुटबन्दी हो जाती है और विद्यार्थी का वातावरण खूबसूरत हो जाता है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्वतन्त्र संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि किसी संस्था के विद्यार्थियों का प्रबंध करने के लिए अधिक से अधिक २ महसूबों की एक कार्यकारिणी समिति बनानी चाहिए। संस्थाओं के महसूबों का विद्यालय के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह समिति विद्यालयों में सम्बन्धित चीजें निर्धारित किया करे। तैयार नहीं होना चाहिए कि स्थानीय संस्था के सभी महसूब विद्यार्थियों का निरीक्षण करने पहुँच करें और यहाँ प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के कार्य में हस्तक्षेप करें।

(१) धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित विद्यालय कुछ धार्मिक मस्जिदों विद्यालयों की स्थापना करने शिक्षा के प्रसार में प्राचीन समय में ही महसूब देती रही हैं। भारतवर्ष में आज भी अनेक माध्यमिक विद्यार्थी इन धार्मिक मस्जिदों के निर्देशन में चल रहे हैं। यह माय है कि धार्मिक मस्जिदों विद्यालयों की स्थापना अपने धर्म-प्रचार के लिए करती है। परन्तु आज के धर्म-निरपेक्ष राज्य में यह कार्य करना सम्भव नहीं है क्योंकि सरकार की नीति ही अब यह है कि किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप में नहीं की जा सकती है। अर्थात् मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत के विभिन्न भागों में माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जो कि आज भी शिक्षा प्रसारण में गतिविधि महसूब दे रहे हैं। इन विद्यालयों को भी अब राजकीय आर्थिक अनुदान प्राप्त होता है। बैसे इनकी मिसन के द्वारा ही अधिक गृहादता पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इसी कारण अब वे भवन, खेल के मैदान तथा अन्य मामलों आदि की दृष्टि में इन विद्यालयों की स्थिति सतोषजनक है। भारतवर्ष की दूसरी प्रमुख धार्मिक मस्जिद आर्य समाज है जिसने देश में अनेक दयानन्द माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की है। इन विद्यालयों को स्थापित करने का उद्देश्य हिन्दू धर्म की रक्षा करना रहा है। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में आर्य समाज के विद्यालयों का सहयोग सभी धार्मिक मस्जिदों से अधिक है। इनके अतिरिक्त रामकृष्ण मिशन, सनातन धर्म आदि ने भी विद्यालय स्थापित किये हैं।

टिप्पणी—धार्मिक मस्जिदों के द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कुछ गुण होने के साथ ही दोष भी अनेक हैं। सर्वप्रथम बात तो भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं। सविधान के अनुसार भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य माना गया है। अतः किसी धर्म की शिक्षा छात्रों को नहीं दी जा सकती है। यहाँ किसी विशेष धर्म

को विविष्ट स्थान प्राप्त नहीं है जिसकी शिक्षा प्रदान की जा सके। कुछ विद्यालयों के द्वारा साम्प्रदायिकता की भावना पैदा की जाती है। देश में आज राष्ट्रीय एवं जातीय एकता की आवश्यकता है। कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित विद्यालय साम्प्रदायिकता की भावना फैलाकर देश की राष्ट्रीय एकता को समाप्त करते हैं। धार्मिक संस्थाओं के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति निष्पक्षता में नहीं की जाती है। नियुक्ति के अवसर पर योग्य व्यक्ति की अपेक्षा अपने धर्म के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। अध्यापकों में उनकी इच्छा के विरुद्ध अनेक धार्मिक कार्य कराये जाते हैं। प्रबन्ध समिति सभी अध्यापकों और छात्रों के साथ गंदापान-रहित व्यवहार नहीं करती है।

(४) व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों द्वारा संचालित विद्यालय—प्रारम्भ में इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए की गई जिससे इस प्रकार के विभिन्न छात्र अपेक्षी प्रमासून को उन्हाड़ फेंकने में सहायता दें। इनकी शिक्षा पद्धति बिदेसी पद्धति में भिन्न थी। वर्तमान प्रजातन्त्रीय प्रणाली में व्यक्तिगत प्रबन्ध समिति द्वारा स्थापित विद्यालय प्रजातन्त्रीय विद्यालयों को प्रदर्शित करने हैं। जिस देश के व्यक्ति स्वयं शिक्षा-प्रसार में रुचि लें तथा उनका संचालन उचित प्रकार में करें यह एक सफल प्रजातन्त्रीय प्रणाली का सूचक है। भारतवर्ष शिक्षा की दृष्टि में पिछड़ा देश है। विभिन्न व्यक्ति देश के लिए कलक हैं। संविधान के अनुसार शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों का है। परन्तु भारत जैसे पिछड़े देश में जहाँ पर शिक्षा प्रसार की अभी अत्यधिक आवश्यकता है, राज्य को सहयोग देना अति आवश्यक है। क्योंकि राज्य स्वयं इनके विस्तृत कार्य को नहीं कर सकता है, अतः व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियाँ माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करके देश में शिक्षा के प्रचार सम्बन्धी कार्य में राज्य का हाथ बँटा रही है।

(क) एक व्यक्ति द्वारा स्थापित विद्यालय—देश के विभिन्न भागों में शिक्षा प्रेमी धनी व्यक्तियों ने माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की है। इनके द्वारा स्थापित विद्यालयों की दशा अधिक धोचनीय नहीं है। परन्तु इस प्रकार के विद्यालय उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होते हैं। वह विद्यालय के कार्यक्रम में सम्बन्धित नीति निर्धारित करता है। विद्यालय को स्थापित करने वाले व्यक्ति इसको अपनी व्यक्तिगत

इसके साथ ही अध्यापकों को प्रबन्ध समिति के अनेक सदस्य प्रमत्त नहीं करने पड़ते हैं। मुदा निम्न आयोग ने इस प्रकार के विद्यालयों की अधिक आलोचना की है। उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति एक बार विद्यालय की स्थापना करने के बाद फिर उसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। आयोग ने निम्ना ॥ कोई भी माध्यमिक विद्यालय एक व्यक्ति

धनाभाव के कारण विद्यालयों की मात्र-मायत्री पर अधिक धन व्यय न  
 है। इन विद्यालयों में एक दोष स्थानीय मन्थाओं की राजनीतिक गुटबन्ध  
 है। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या अध्यापक स्वतन्त्र नहीं होते हैं  
 के सदस्य समय-समय पर विद्यालय की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करें  
 मन्थाओं के सदस्य अध्यापकों को अधिक परेशान करते हैं। इनके  
 गुण विद्यालय के अध्यापकों में भी गुटबन्दी हो जाती है और विद्यालय  
 दूषित हो जाता है।

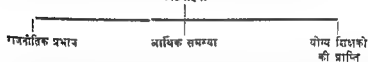
धार्मिक शिक्षा आयोग ने स्थानीय मन्थाओं द्वारा मन्थानित विद्यालयों के  
 भाव दिया कि किसी मन्था के विद्यालयों का प्रवृत्त करने के लिए  
 एक ६ सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनानी चाहिए। मन्थाओं  
 विद्यालय के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह  
 वषों में सम्बन्धित नीति निर्धारित किया करें। ऐसा नहीं होना चाहिए  
 मन्था के सभी सदस्य विद्यालयों का निरीक्षण करने पहुँच पायें और  
 आपक तथा अध्यापकों के कार्य में हस्तक्षेप करें।

धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित विद्यालय—कुछ धार्मिक मन्थाएँ  
 स्थापना करके शिक्षा के प्रसार में प्राचीन समय से ही सहयोग देती  
 चलीं हैं। आज भी अनेक माध्यमिक विद्यालय इन धार्मिक मन्थाओं के  
 चले रहे हैं। यह सत्य है कि धार्मिक मन्थाएँ विद्यालयों की स्थापना  
 के लिए कारणी है। परन्तु आज के धर्म-निरपेक्ष राज्य में यह सब  
 नहीं है क्योंकि सरकार की नीति ही अब यह है कि किसी भी धर्म की  
 रूप में नहीं की जा सकती है। अर्थात् मिशनरियों ने ईसाई धर्म के  
 भारत के विभिन्न भागों में माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जो कि  
 प्रसारण में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। इन विद्यालयों की भी अब  
 एक अनुदान प्राप्त होता है। वैसे इनको मिशन के द्वारा ही अधिक  
 न माना में मिल जाती है। इसी कारण अल्पे भवन, भेष के भेदान  
 नहीं आदि की दृष्टि में इन विद्यालयों की स्थिति सतोषजनक है।  
 दूसरी प्रमुख धार्मिक मन्था आर्य समाज है जिसने देश में अनेक  
 मिक विद्यालयों की स्थापना की है। इन विद्यालयों को स्थापित करने  
 धर्म की रक्षा करना रहा है। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में आर्य समाज  
 सहयोग सभी धार्मिक मन्थाओं में अधिक है। इनके अनिच्छित  
 न, मतानुसार धर्म आदि में भी विद्यालय स्थापित किए हैं।

धार्मिक मन्थाओं के द्वारा मन्थानित माध्यमिक विद्यालयों में कुछ गुण  
 में दोष भी अनेक है। सर्वप्रथम बात तो भारतवर्ष की वर्तमान  
 विधान के अनुसार भारत का धर्म-निरपेक्ष राज्य माना गया है।  
 की शिक्षा छात्रों को नहीं दी जा सकती है। यही नीति है।

प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं होते हैं। अतः इसी के परिणामस्वरूप आज छात्रों में इसकी अनुपामनहीनता बढ़ती जा रही है। व्यक्तिगत प्रवर्धन समितियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका अध्ययन करना आवश्यक है।

### कठिनाइयाँ



**राजनीतिक प्रभाव**—भारतवर्ष में अनेक राजनीतिक पार्टियाँ हैं। ये सभी अपने राजनीतिक निष्ठान्तों का प्रचार करने का प्रयत्न करती हैं। विद्यालय राजनीतिक प्रचार के लिए उपयुक्त माध्यम है। व्यक्तिगत प्रवर्धन समिति द्वारा संचालित विद्यालयों में सरकार ने अधिक सहायता मिलती है। इस कारण प्रवर्धन समितियों के महत्व भी विद्यालय के लिए अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य में राजनीतिक दलबादी में कम जाते हैं। आजकल यह मूलतः परम्परा भी पढ़नी जा रही है कि राजनीति का प्रवेश विद्यालयों में भी हो गया है। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अनुपामनहीनता का एक कारण यह राजनीति भी है। छात्रों द्वारा जिनके भी राजनीतिक दल का हाथ होता है कि राजनीति को विद्यालयों

**आर्थिक समस्या**—प्रवर्धन समिति द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों पर धन का अभाव रहता है। इस कारण वे छात्रों के लिए अनेक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और न समय पर महीने अध्यापकों को वेतन ही मिल पाता है। पहले की अपेक्षा अब धन देने की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। पहले शिक्षा में रचि लेने वाले भी व्यक्ति इन शिक्षण संस्थाओं को धन देकर अपनी उदारता का परिचय देते थे परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार की नीति ने इन धन देने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी कर दी है। सरकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करती जा रही है तथा भी व्यक्तियों पर अनेक कर बढ़ाती जा रही है। परिणामस्वरूप, अब प्रवर्धन समितियों को वर्ष भर कर देने में अधिक कठिनाई का सामना करना होता है। जैसे अब राज्य द्वारा विद्यालयों को कुछ आर्थिक सहायता मिलती है परन्तु यह पर्याप्त नहीं होती है। प्रवर्धन समिति अब इन कमी की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त धन संग्रह नहीं कर पाती है। परिणामस्वरूप, इन समस्याओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं :

(१) विद्यालय-भवनों का अभाव—इन समस्या का अध्ययन तो प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करते समय ही किया था। विद्यालय के भवन

द्वारा नहीं चलाये जाने चाहिए वस्तुिक कम्पनी के नियमानुसार उसकी प्रबन्ध समिति हो जो विद्यालय का प्रबन्ध भोगे।

(ख) प्रबन्ध समिति द्वारा—कुछ विद्यालय समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों की सहायता से स्थापित किये जाते हैं। इनका संचालन करने के लिए कुछ व्यक्तियों की एक समिति गठित की जाती है। इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन कुछ निश्चित अवधि के लिए होता है। इस समिति का उत्तरदायित्व होता है कि वह विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अध्यापकों की नियुक्ति करे। व्यक्तिगत प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित विद्यालयों में भी अनेक दोष पाये जाते हैं।

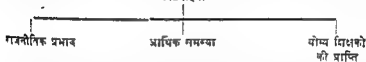
(ग) रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा—कुछ धनी व्यक्ति कार्य-भार की अधिकता से ऐसे 'ट्रस्ट' की स्थापना करते हैं जो कि संस्थापक के नाम से विद्यालय का संचालन करते हैं। इस प्रकार के 'ट्रस्ट' आर्थिक दृष्टि में सम्पन्न होते हैं। अब इनके द्वारा संचालित विद्यालयों की दशा अधिक दयनीय नहीं होती है। कुछ ट्रस्ट अन्य विद्यालयों की आर्थिक समस्या के समाधान के लिए उनको आवश्यक धन प्रदान करते हैं। ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों में भी अनेक दोष पाए जाते हैं। इनका प्रमुख दोष छात्रों को प्रवेश देने में सम्बन्धित है। कुछ ट्रस्ट किसी एक जाति अथवा धर्म के मानने वाले छात्रों की शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं। परन्तु वर्तमान भारत में इनकी परम्परा नहीं चल सकती है क्योंकि संविधान में स्पष्ट लिखा है कि छात्रों को प्रवेश देते समय कोई भी भेदभावात्मकता, धर्म अथवा लिंग के आधार पर उनमें विभेद नहीं कर सकती है। धर्म-निरपेक्ष भारत में इन समस्याओं को अपने नियमों में परिवर्तन करना होगा।

### व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों की कठिनाइयाँ

व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों द्वारा स्थापित विद्यालयों में विद्यमान दोषों के वर्णन में स्पष्ट है कि इनके संचालन में सुधार होना चाहिए। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, राज्य के ऊपर ही शिक्षा प्रचार का भार नहीं होना चाहिए वस्तुिक जनता को भी सहृदयता का परिचय देना चाहिए तभी शिक्षा-सम्बन्धी मुविधाने छात्रों को प्रदान की जा सकती है। स्वतन्त्रता के पश्चात् धीरे-धीरे यह मान बढ़ती जा रही है कि विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। परन्तु यह मान तर्क गत नहीं है। राज्य के राष्ट्रीय प्रसार कार्य के लिए केवल शिक्षा ही भेद्य नहीं है जहाँ पर वह सम्पूर्ण धन व्यय करे। अब स्पष्ट है कि राज्य के लिए सभी विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करना सम्भव नहीं है। प्रबन्ध समितियों द्वारा विद्यालयों में अनेक अवांछनीय कार्य किए जाते हैं। परन्तु इन विद्यालयों में सुधार लाने की आवश्यकता है। आज व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इनके कारण उनकी दशा विचरती जा रही है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न नहीं होने हैं। आयोग द्वारा बनाए गए माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की

गति के लिए प्रयास नहीं होने हैं। अब इसी के परिणामस्वरूप आज छात्रों में इसी अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। व्यक्तिगत प्रवर्ण समितियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका अध्ययन करना आवश्यक है।

### कठिनाइयाँ



**राजनीतिक प्रभाव**—भारतवर्ष में अनेक राजनीतिक पार्टियाँ हैं। ये सभी अपने राजनीतिक मिशनों का प्रचार करने का प्रयत्न करती हैं। विद्यालय राजनीतिक प्रचार के लिए उपयुक्त माध्यम है। व्यक्तिगत प्रवर्ण समिति द्वारा संचालित विद्यालयों को सरकार में आर्थिक सहायता मिलती है। इस कारण प्रवर्ण समितियों के सदस्य भी विद्यालय के लिए अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य में राजनीतिक दलवादी में फँस जाते हैं। आजकल यह चलन परम्परा भी पड़ती जा रही है कि राजनीति का प्रवेश विद्यालयों में भी हो गया है। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अनुशासनहीनता का एक कारण यह राजनीति भी है। छात्रों द्वारा जिनमें भी आन्दोलन प्रारम्भ किये जाते हैं, उनमें किसी न किसी राजनीतिक दल का हाथ होता है। वर्तमान भारत में यह विवाद का विषय बन गया है कि राजनीति को विद्यालयों में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

**आर्थिक समस्या**—प्रवर्ण समिति द्वारा बनाए जा रहे विद्यालयों पर धन का भार रहता है। इस कारण के छात्रों के लिए अनेक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और न समय पर गरीब अध्यापकों को वेतन ही मिल पाता है। पहले की अपेक्षा अब दान देने की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। पहले सिद्धा में रक्षित लेने वाले धनी वर्ग की अति दल विद्यालय मस्याओं को धन देकर अपनी उदारता का परिचय देते थे।

प्रवर्ण समिति अब इन कमी की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त धन सङ्ग्रह नहीं कर पाती है। परिणामस्वरूप, इन समस्याओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं :

(१) विद्यालय-भवनो का अभाव—इस समस्या का अध्ययन तो प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करते समय ही किया था। विद्यालय के भवन

निर्माण के लिए धन का संग्रह न हो पाने के कारण इन विद्यालयों में कमरों की पर्याप्त मर्यादा नहीं है। परिणामस्वरूप, कुछ कक्षाओं को बाहर बँटना होता है। पहले धनी व्यक्ति ही एक-एक कमरा अपने नाम का बनवा कर भवन-निर्माण में सहयोग दिया करते थे। आज भौतिकवाद के युग में व्यक्तियों की धर्म में आस्था कम होनी जा रही है। इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण समस्याओं के रूप में पड़ता है।

(२) स्नेहाभाव का अभाव—पनाभाव के कारण व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों छात्रों के लिए सेवा के संस्कार को व्यवस्था भी नहीं कर पाती हैं। ऐसा न होने से छात्रों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। उनके व्यक्तित्व के एक अंग का विकास नहीं हो पाता है। प्राचीन शिक्षा एवं आधुनिक व्यापार की व्यवस्था न होने से छात्रों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है।

(३) प्रयोगशालाओं का अभाव—विज्ञान के शिक्षण के लिए प्रयोगशालाओं का होना अति आवश्यक है। हमारे देश में विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। परन्तु उनको विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करने की सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। सामयिक विद्यालयों में नाम के लिए प्रयोगशालाएँ हैं परन्तु उनमें मात्र-सामान का अभाव रहता है। पनाभाव के कारण ये शिक्षण समस्याएँ प्रयोगशालाएँ, भूगोल कक्ष आदि का निर्माण नहीं कर पाती हैं। अगर एक बार उनका निर्माण भी कर दिया तो प्रतिवर्ष आवश्यक सामान को नहीं खरीदा जाता है।

(४) छात्रावास का अभाव—इन सामयिक विद्यालयों के पास छात्रावास नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप, छात्रों को नगर में रहना पड़ता है जहाँ पर दुर्गम वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ता है। ये छात्र भेद-वृद्ध में भी भाग नहीं ले पाते हैं।

(५) राष्ट्रीय विद्यालयों की स्वतंत्रता का समाप्त होना—इन विद्यालयों की स्थापना छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने के लिए ही हुई थी। इस से अनेक स्वतंत्रता-प्रेमी व्यक्ति इन समस्याओं को अधिक महत्त्व दे रहे हैं। परन्तु वर्तमान समय में विद्यालय सरकार से अधिक महत्त्व प्राप्त करने हैं। इस कारण इन पर सरकार का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। सरकार की नीति के अनुसार ही इन समस्याओं को कार्य करना पड़ता है। जो उम्मीदी व्यक्ति पहले इन प्रकार की शिक्षण समस्याओं को अधिक महत्त्व दिया करते थे, उनकी दान देने की प्रवृत्ति में अब परिवर्तन आ गया है। इसलिए इन विद्यालयों को धन मिलना कठिन हो गया है। विभागीय हस्तक्षेप के कारण विद्यालयों की स्वतन्त्र परीक्षण करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई जा रही है।

सोपे अध्यापकों का अभाव—व्यक्तिगत प्रबन्ध समिति द्वारा खड़ा जा रहा विद्यालयों में गरीब अध्यापकों का अभाव बना रहता है। इन विद्यार्थियों में सेवा करने के लिए योग्य व्यक्ति तैयार नहीं होते हैं। इसके अनेक कारण हैं यदि



(१) आकस्मिक वेतन-भूलसा का न होना—भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में राजकीय विद्यालयों के अध्यापक तथा निजी संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन समान नहीं है। राजकीय सेवा में अधिक वेतन मिलता है। परिणामस्वरूप, वे व्यक्ति इन राजकीय संस्थाओं में जाने जाते हैं। निजी संस्थाओं में अगर कोई व्यक्ति योग्यता का व्यक्ति पहुँच भी जाता है तो वह थोड़े समय ही वहाँ ठहरता है। नाभाव के कारण अनेक निजी संस्थाएँ समय पर अध्यापकों को वेतन नहीं देती हैं।

(२) नौकरी की सुरक्षा का अभाव—योग्य व्यक्ति इन प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी करने हुए भी नौकरी की असुरक्षा में भयभीत रहते हैं। इन संस्थाओं में भी परम्परा ही यह गई है कि जो अध्यापक विद्यालय के प्रबन्धक की इच्छानुसार कार्य नहीं करता है, उसको सेवा-कार्य से तोड़ा ही मुक्त किया जाता है।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव—नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों का मिलना अधिक कठिन है। नगर में अनेक सुविधाएँ होने में अध्यापकों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षण विषय अध्यापकों का अभाव सर्वत्र बना रहता है।

(४) अध्यापकों को योग्यता बढ़ाने के अवसर नहीं दिये जाते हैं। जो अध्यापक स्नातकोत्तर परीक्षा देना चाहते हैं, उनको परीक्षा की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। इसी प्रकार अध्यापकों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधा या किसी शिक्षा सम्मेलन में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाती है।

### अध्यासाभ्यर्थ प्रश्न

१. राज्य द्वारा चलाये जा रहे माध्यमिक विद्यालयों में क्या दोष पाये जाते हैं ?
२. स्थानीय संस्थाएँ माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध करने में क्या कठिनाइयाँ अनुभव करती हैं ?
३. व्यक्तिगत प्रबन्ध समिति द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों का शिक्षा के प्रसार में क्या सहयोग रहा है ?
४. व्यक्तिगत प्रबन्ध वाले विद्यालयों में कौन-कौनसे प्रमुख दोष पाये जाते हैं ?

राजस्थान विद्वत्विद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

1. What place do privately managed primary and secondary schools occupy in the national pattern of education in this country ? Discuss the special problems which they have to face

(1961)



सम्भव हो सकी है। संयुक्त राज्य अमरीका आज विद्वत् की महान् शक्ति केवल अपनी खनिज सम्पत्ति की अधिकता के आधार पर ही नहीं बना है परन्तु वहाँ के लोगो की तकनीकी दक्षता एवं उनकी मूर्धन्यता का परिणाम है। वर्तमान समय। हम जो कि एक पिछड़ा हुआ देश था, आज वैज्ञानिक प्रगति के कारण चन्द्रलोक तक पहुँचने के प्रयासो में संलग्न है। हम खनिज की दृष्टि में सम्पन्न देश है लेकिन हाँ औद्योगिक विकास अभी हुआ जबकि वहाँ की सरकार ने तकनीकी शिक्षा का खर्च करके अपने देश के व्यक्तियों की कार्यक्षमता एवं तकनीकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि दी। भारतवर्ष खनिज की दृष्टि में निर्धन देश नहीं है। कुछ खनिजो में तो भारत ही विश्व में एकाधिकार सा प्राप्त है परन्तु अंग्रेजो ने अपने स्वार्थ के कारण भारत में तकनीकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप, वहाँ के निवासी अपने वहाँ की प्राकृतिक सम्पत्ति का उचित प्रयोग न करने में अन्य देशो की तुलना में पिछड़ गये। हुमायूँ कबोर का कथन हम सम्बन्ध में सत्य है कि किसी देश अथवा राष्ट्र की सम्पत्ति का आधार विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा है।

### तकनीकी शिक्षा का इतिहास

प्राचीन काल में तकनीकी शिक्षा—हम ज्ञान के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में तकनीकी शिक्षा का अधिक विस्तार था। मोहनजोदडो की खुदाई में पता चलता है कि हजारों वर्ष पूर्व भी हमारे पूर्वज मनु-निर्माण सम्बन्धी ज्ञान रखते थे। कुतुबमीनार के निष्ठुर स्तंभ लोहे का स्तम्भ उस समय के शिल्पकारों के ज्ञान का गुणगान करता है। हमारे देश का स्थान सम्पूर्ण विश्व में विख्यात था। उस काल में तकनीकी ज्ञान किसी विद्यालय मस्था में प्रदान नहीं किया जाता था। उस समय तो विभिन्न जातियों के कार्य एवं व्यवसाय निश्चित थे। पर पर ही पिता अपने पुत्रों को इन व्यवसायो की शिक्षा दिया करता था। वैदिक युग में भी सूत्री-वेदामी वस्त्र बनते थे तथा उनको रँगने एवं छपाई सम्बन्धी कार्य होता था। राजा-महाराजाओ के यहाँ कारीगर लोभ अस्त्र-शस्त्र बनाने का काम करते थे।

मुस्लिम काल में तकनीकी शिक्षा—मुस्लिम शासकों की भोग विलासिता के कारण वहाँ पर खनिज कलाओ को अधिक प्रोत्साहन मिला। इनके समय में रेजम, मरी, दरिया, कालीन, आभूषण आदि सामग्री का निर्माण हुआ। सूती वस्त्र उद्योग इस काल में अधिक विकसित हुआ। उत्तम वस्त्र बनाने वाले कारीगरों को पारितोषिक भी प्रदान किये जाते थे। इनके समय में युद्ध भी अधिक हुए। परिणामस्वरूप, युद्ध की सामग्री का निर्माण अधिक हुआ। बाख्द, गोला आदि के बनने में इस काल में तकनीकी ज्ञान का विस्तार हुआ। आज भी मुस्लिम काल की शिल्प कला अधिक प्रसिद्ध है।

ब्रिटिश शासन काल में तकनीकी शिक्षा—ब्रिटिश काल में वहाँ पर उद्योग-पन्थों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे धीरे-धीरे समाप्त होने लगे। अंग्रेजों की यह

नीति रही कि वही न कभी मान देने दल का मे प्रतिपक्ष और नहीं व निमित्त मान यही के साक्षरों में वेनाथ। भारतीय उद्योगों का दल का गीर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, भारत के अर्थरूप धिक्का हो गया। सबसे अधिक प्राधान्य गृहीत वस्त्र व्यवसाय की पकड़ा। सन् १८१६ में भारत में तत्कालीन अंग्रेज सरकार जनरल ने अर्जन्टा रिपोर्ट में पुनः ममर के पुनर्गठन की दशा का वर्णन दल प्रकार दिया है - "बाणिज्य के इतिहास में गुरुभीय का अर्थ उदाहरण मिलना कठिन हो है। गुरुभीय वस्त्र बुनकरों की दृष्टियों में भारत में धंधा का मन्द कट दिया है।" वस्त्रों की सरकार ने तकनीकी शिक्षा की ओर बाई भी ध्यान नहीं दिया परन्तु कम्पनी के गाछाउर को समाधान का के यही पर इतिहास गाछाउर के विस्तार के साथ अनेक विभागों में वृद्धि हुई। परिणाम-स्वरूप, इनमें काम करने के लिए विदेशियों की आवश्यकता बढ़ी। अंग्रेजों ने भारतीयों को ही इन विदेशी विषयों की शिक्षा देने की व्यवस्था की और ध्यान दिया क्योंकि इतनेवृद्ध में सभी विभागों के लिए विदेशी लाना एक समस्या थी। प्रारम्भ में ईसाई मिशनरियों ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों स्थापित। तदन्तर अंग्रेज सरकार के द्वारा भी व्यावसायिक विद्यालय स्थापित किये गये। इंग्लैण्ड की शिक्षा के लिए बुद्ध कलाएँ बम्बई, मद्रास तथा उदकी में स्थापित हो गई। सन् १८४७ में उत्तर प्रदेश में उदकी में टांगर इंग्लैण्ड की स्थापना की गई। सन् १८४९ में कलकत्ता में तथा १८८० में बंगाल में सिविली नामक स्थान पर इंग्लैण्ड की कालेज स्थापित किये गये।

१८८२ से १९०२ तक—सन् सन् १८८२ में अंग्रेज सरकार ने भारतीय शिक्षा का सुधार करने के लिए कम्पनी आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने प्रथम माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के विभिन्नकरण का सुझाव दिया। आयोग ने पाठ्यक्रम को दो वर्गों में विभाजित किया—(१) साहित्यिक, (२) व्यावसायिक। सन् १८८७ में कांग्रेस ने अपने तीसरे अधिवेशन में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की जोरदार मांग की क्योंकि अब भारतीय नेता भी देश के आर्थिक विकास की ओर मजबूत हो चुके थे। सन् १८८८ में सरकार ने तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रस्तावित किया कि इस शिक्षा के लिए संस्थाएँ स्थापित की जायें। सन् १८८७ में बम्बई में विक्टोरिया जुबली टेक्नीकल इस्टीब्लिश की स्थापना की गई। इस समय तक स्थापित कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ८६५ थी। छठे स्कूलों में ७६६ छात्र अध्ययन कर रहे थे। सन् १९०२ तक सम्पूर्ण भारत में कुल ८८ तकनीकी संस्थाएँ थीं, परन्तु इनमें से अधिकांश देशी कला-कौशल की ही शिक्षा प्रदान करते थे।

- 1 The misery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of the cotton weavers are bleaching the plains of India.—Lord Bentick

सन् १९०२ से १९२१ तक—लार्ड कर्जन ने यह अनुभव किया कि भारत में तकनीकी शिक्षा का विस्तार अधिक नहीं हुआ है और न यहाँ परदेश के उद्योगों की आवश्यकता एवं माँग के अनुसार तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। लार्ड कर्जन ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम उठाये। उन्होंने यहाँ के योग्य तथा कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा देकर विदेशों में तकनीकी शिक्षा सीखने के लिए भेजा। कर्जन ने भारत में कृषि की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए। उसने ग्रामीण विद्यालय में कृषि को अनिवार्य विषय बनाया। सन् १९१७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय कायोग में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में मुझ पर किया कि

(अ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा को सम्मिलित किया जाय।

(आ) इंटरमीडिएट कक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवसाय की सामान्य शिक्षा की व्यवस्था हो।

सन् १९२१ में व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं तथा उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है

व्यावसायिक संस्थाएँ	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या
कानून के कालेज	१३	५,८६५
चिकित्सा कालेज	७	३,८६३
वाणिज्य कालेज	५	६७६
इंजि कालेज	२	३७६
इजीनियरिंग कालेज	५	८०३

सन् १९२१ से १९३७ तक—इस काल की ईंधन-प्राप्तन के नाम में भी पुकारने हैं। इस काल में भारतीयों ने इसका विरोध किया कि भारतीय छात्रों को विदेशों में तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने हेतु भेजा जाय। ऐसा करने में भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास नहीं हो सकेगा। भारतीय नेताओं का विचार था कि देश में ही उच्च तकनीकी शिक्षा के महाविद्यालय स्थापित किये जायें। इस माँग के आधार पर सरकार ने लार्ड लिटन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने विदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की कठिनाई को दूर करने का मुझ दिया तथा भारत में ही तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना के लिए सरकार में अनुरोध किया। इस काल में निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना हुई

(१) बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता—इस संस्था की स्थापना भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चन्द्र बोस ने की थी।

एशोकचर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली—इस मस्या में जाती है। इसके अतिरिक्त अनुगन्धान कार्य भी होता है। स्कूल आफ साइंस—इसकी स्थापना सन् १९२६ में बनवा दी गिधा देने के लिए की गई।

घटसर टेकनॉलॉजिकल इंस्टीट्यूट—इसकी स्थापना कानपुर में हुई।  
यन इंस्टीट्यूट आफ साइंस—टाटा परिवार ने बनलौर में यह किया।

३७ से १९४७ तक—सन् १९३७ में 'केन्द्रीय शिक्षा मलाहकार परिषद्' आधार पर 'ऐबट एण्ड बुड' समिति की नियुक्ति की गई। इस सांख्यिक शिक्षा के लिए उपयोगी मुभाव दिये व्यावसायिक शिक्षा को मार्हात्यिक शिक्षा के समान ही स्तर प्रदान किया जाय।

प्रत्येक प्रान्त की औद्योगिक एवं व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार ही व्यावसायिक शिक्षा का रूप निश्चित किया जाय। व्यावसायिक शिक्षा के लिए पृथक् विद्यालय स्थापित किए जायें। उद्योग, व्यापार और शिक्षा में परस्पर निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रत्येक प्रान्त में 'व्यावसायिक शिक्षा परामर्शदात्री समिति' का गठन किया जाय।

४ व्यावसायिक शिक्षा के पूर्णकालीन तथा अर्धकालीन विद्यालय हो। 'ऐबट एण्ड बुड' प्रतिवेदन में दिये गये मुभावों के आधार पर सरकार ने कार्य किया। इस काल में तकनीकी शिक्षा की प्रगति के निम्ननिम्न कारण थे

(१) बिदवयुड के कारण भारत में नवीन उद्योगों की स्थापना पुनः मायदी करने के लिए की गई। परिणामस्वरूप, तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की बढ़ी।

(२) देश में निम्नी उद्योग के क्षेत्र में भी विकास हुआ। धनी व्यक्तियों ने उद्योग प्रारम्भ किये। अनेक अतिगमन तकनीकी मस्याओं की स्थापना हुई।

(३) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने तकनीकी शिक्षा में रुचि ली। सन् १९४५ में एन० आर० सरकार समिति गठित की गई। इस समिति ने तकनीकी शिक्षा के लिए निम्ननिम्न मुभाव दिये

(१) देश के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्वी भागों में चार बड़े बॉर्डर्स निर्मित किये जायें।  
(२) इन मस्याओं में योग्य अभ्यासक नियुक्त किये जायें।

(३) प्रतिभावाली छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता तथा अन्य सुविधाएँ दी जाएँ।

सन् १९८६ में भारत सरकार ने 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति' का निर्माण किया। इन समिति का कार्य केन्द्रीय सरकार को तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में गलाह देना था।

उत्तातर शिक्षा प्रवर्ति की योजना बनाने का कार्य तत्कालीन भारतीय शिक्षा सलाहकार सर जॉन मार्वेंट को दिया। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में भी सुझाव दिया।

(१) तकनीकी शिक्षा के लिए पूर्णकालिक तथा अर्धकालिक विद्यालय स्थापन किये जायें।

(२) दो प्रकार के हाईस्कूल हों—(अ) साहित्यिक, और (आ) तकनीकी। इन दोनों विद्यालयों में कुछ विषय समान रूप में पढ़ाये जायें। इनके अतिरिक्त तकनीकी तथा व्यावसायिक विद्यालयों में कम्पट-कन्सा, इजीनियरिंग, वाणिज्य, धातु-कला आदि विषयों के शिक्षण की व्यवस्था हो।

(३) मार्वेंट ने भारतीय उद्योगों की आवश्यकता के आधार पर कार्यकर्ताओं को चार भागों में बाँटा :

(अ) उच्च धरोणी—मुख्य कार्याधिकारी तथा अनुसन्धानकर्ता इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। तकनीकी हाईस्कूल का पाठ्यक्रम समाप्त करके ये किसी विश्व-विद्यालय के तकनीकी विभाग में उच्च धरोणी की शिक्षा ग्रहण करेंगे।

(आ) निम्न धरोणी—निम्न कार्याधिकारी जैसे फोरमैन आदि को इन धरोणी में सम्मिलित किया जाता है। तकनीकी हाईस्कूल में शिक्षा ग्रहण करके इन छात्रों को अर्धकालिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय डिप्लोमा लेना आवश्यक होगा।

(इ) कुशल शिल्पकार—तकनीकी हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्तियों को कुशल शिल्पकार माना जाता है।

(ई) अर्द्ध कुशल एवं अकुशल कारीगर—मीनिबर वेसिक शिक्षा प्राप्त किये हुए छात्र इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

सन् १९४७ के पश्चात्—स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में औद्योगिक विकास प्रारम्भ हुए। परिणामस्वरूप, दिन प्रतिदिन तकनीकी व्यक्तियों की माँग अधिक बढ़ने लगी। इनकी माँग की वृद्धि ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। सन् १९४८ में डॉ॰ राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इन आयोग ने तकनीकी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए लिखा है—“पुरुष एवं स्त्रियों को

मानवीय मित्रता की सामयिक समस्याएँ

...के नगर संरक्षण एवं विकास के लिए आवश्यक निधि है।  
...के लिए आवश्यक निधि है।  
...के लिए आवश्यक निधि है।

... विभिन्न प्रकार की फ...

उन्होंने कहा कि भारत को अधिक महत्व देने के लिए हमें अपने देश के लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है।

कृष्ण-वर्णों को प्रोत्साहित करने के लिए।  
 - कृष्ण-वर्णों को प्रोत्साहित करने के लिए।  
 - कृष्ण-वर्णों को प्रोत्साहित करने के लिए।

६. आयुर्वेद नामने की मिषारिष की।  
आयुर्वेद ने इंद्रोनिर्धारण तथा तकनीकी मस्त्राना  
नग्नानि नामने की मिषारिष की।  
आयुर्वेद ने आयुर्वेद प्रवृत्त करने वाले छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान  
करने का प्रयत्न किया।

2. अपने-को ज्ञान ग्रहण करने वाले छात्रों को अपने-को ज्ञान देने वाले छात्रों को अंतरा-विषयिक आदि को करने के अवसर दिए जाएं।

कृष्ण के अवसर दिए जाएं। निम्न धरोपी के कार्यकर्ता जिन कोरसेन तथा निम्न देने वाली संस्थाओं की मध्या से वृद्धि की जाय। निम्न देने वाली संस्थाओं की व्यवस्था तकनीकी कालों में भी अनुमोदन की व्यवस्था तकनीकी मध्याओं में

3. तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान की व्यवस्था तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीकी मंत्रालयों का प्रावधान किया गया है।

२. उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीकी क्षेत्र में अनुमानित १०० से अधिक छात्रों को प्रवेश न दिया जाय।

उच्च तकनीकी शिक्षा में मुधार हनु मुधार देने के लिए निर्माण किया गए।  
मंडीकरन करियों के १०० से अधिक छात्रों का प्रशिक्षण देना।  
१९५५-५६ के वार्षिक शिक्षा में मुधार हनु मुधार देने के लिए निर्माण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तकनीकी शिक्षा को प्रगति के लिए विचार किया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तकनीकी शिक्षा को प्रगति के लिए विचार किया।

सन् १९५६-५७ के दौरान  
मक निधा अन्वीष को विमुक्ति को यह।  
के क्षेत्र में भी मुख्य रूप से। सर्वप्रथम आयोग ने नकली  
के कारणों पर प्रकाश डाला। निधा के लिए अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं पर क।  
के विस्तार के लिए गम्भीर

१. तकनीकी शिक्षा के लिए  
ध्यान नहीं दिया गया।

१. तकनीकी शिक्षा को प्राधान्य नहीं दिया गया।
२. केन्द्र प्रथम प्राप्ति में तकनीकी शिक्षा को प्राधान्य नहीं दिया।

onal education is the process by which men and  
prepare for exacting responsible service in the pro-  
-1 spirit."—Report of the University Commission,



३. जन-शिक्षा विभाग को किनी योग्य तकनीकी शिक्षा मलाहकार की सेवाएँ प्राप्त न हो सकी ।
४. सरकार के विभिन्न विभागों में परस्पर कोई सम्पर्क नहीं रहता है । परिणामस्वरूप, तकनीकी शिक्षा को समन्वित योजना नहीं बन पायी है ।
५. धनभाव के कारण भी अनेक योजनाएँ पूरी नहीं हो सकी ।

आयोग ने तकनीकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये

१. बहुत बड़ी मक्या में तकनीकी मस्याएँ स्थापित की जाएँ ।
२. तकनीकी मस्याओं की स्थापना यथाम्भव कारखानों के निकट की जाय और उनमें परस्पर सहयोग हो ।
३. अधिनियम द्वारा कल-कारखानों के लिए अनिवार्य कर दिया जाय कि वे तकनीकी विद्यालय के छात्रों की व्यावहारिक जान दें ।
४. तकनीकी शिक्षा के लिए उद्योगों पर उद्योग कर लगाया जाय ।

कोठारी आयोग—२ अक्टूबर, १९६४ को श्री दोस्त सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया । इस आयोग ने भी तकनीकी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं

१. सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा के बीच में बहुत अन्तर नहीं करना चाहिए । वे एक दूसरे के पूरक की तरह कार्य कर ।
२. शिक्षा संस्थाओं एवं उद्योगों का घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए ।
३. जूनियर टेक्निकल स्कूलों का नाम परिवर्तन करके टेक्निकल हाईस्कूल कर दिया जाय ।
४. विद्यालय छात्रों को रोजगार में प्रवेश पाने वाले छात्रों की योग्यता बढ़ाने के लिए अग्रवासी तथा पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।
५. शिल्पियों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये
  - (अ) सन् १९७५ तक इंजीनियर और शिल्पियों का अनुपात १ : २५ तथा १९८६ तक ३ : ४ कर दे ।
  - (आ) सर्वेक्षण आदि के द्वारा इनके पाठ्यक्रम में सुधार किया जाय ।
  - (इ) पोलीटेक्निकों की स्थापना औद्योगिक क्षेत्रों में की जाय ।
  - (ई) इनमें व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जाय ।
  - (उ) लड़कियों के लिए गृहकृ पाठ्यक्रम हो ।

### पंचवर्षीय योजनाएँ और तकनीकी शिक्षा

भारत के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि, के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गईं । आर्थिक विकास के लिए यहाँ पर भारी उद्योग स्थापित किये गये । इन नवीन उद्योगों में कार्य करने के लिए कुशल तथा

## भारतीय शिक्षा का सामाजिक मूल्य

कौशल का आवश्यकता रही। पञ्चवर्षीय पाठशाला का निर्माण  
 तब हीना शिक्षा के विनाश पर भी ध्यान दिया गया।  
 पञ्चवर्षीय योजना प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में वही शुरुआत न  
 हीना पर ध्यान करने के लिए १९६६ का १९६८ की पंचवर्षीय निर्देश  
 योजना में तबनाकी शिक्षा का गौरव देना में विचारित बातें उन विचार  
 प्रणाली विचार

१. १९६९ में संघीय विद्यालयों का विकास किया गया। दुर्दिन  
 दुर्दिन दुर्दिन और शैक्षणिक, महानगर तथा दुर्दिन दुर्दिन और  
 माह, विभागीय तथा अन्य तबनाकी शिक्षा मंत्रालय का विचार किया  
 गया। दुर्दिन दुर्दिन के १९६९ का १९६९ विचार दालें।
२. तबनाकी तथा दुर्दिन दुर्दिन का स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान  
 कार्य के लिए १९७३ भाग अथवा अन्य करने का निर्णय किया।
३. तबनाकी तबनाकी लक्ष्य आधारित विद्यालयों के स्थापना, भारत मूल्य  
 का निर्धारण तबनाकी लक्ष्य मूल्य में परिवर्तन, औद्योगिक मूल्य का  
 निर्धारण करने की योजना का निर्माण किया गया।
४. विद्या में उच्च तबनाकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का अधिक  
 छात्रवृत्तियों देने की व्यवस्था की गई।
५. द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना द्वितीय योजना में तबनाकी तथा आधारितिक  
 शिक्षा पर ध्यान करने के लिए ६८ का १९७३ का निर्णय किया। द्वितीय योजना का  
 भी गया गया।

१. प्रथम योजना काल में स्थापित किए गए तबनाकी विद्यालयों में  
 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना तथा महाविद्यालयों में  
 अनुसंधान कार्य की प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई।
२. देश के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भाग में उच्चतर तबनाकी  
 मंत्रालय स्थापित की जायेगी। इनमें से प्रत्येक मंत्रालय में १२००  
 स्नातक पाठ्यक्रम में तथा ६०० स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त  
 कर सकेंगे।
३. द्वितीय विभाग और तबनाकी शिक्षा प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न  
 भागों में ६ मंत्रालयें द्वितीय स्तर की और २१ मंत्रालयें द्वितीय स्तर की  
 स्थापित की जायेगी।
४. छात्रवृत्तियों की मूल्य ६३३ में बढ़ाकर ८०० कर दी गई।  
 द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में ६५ द्वितीय विभाग कालों की मूल्य बढ़कर १००  
 हो गई तथा ५,८६० के स्थान पर १३,८६० छात्रों को प्रवेश मिला। पालीटेकनिक  
 १९४ से बढ़कर १९६ हो गये।

मृतीय पंचवर्षीय योजना—इन योजना में तकनीकी शिक्षा के लिए १४२ करोड़ रुपये रूने मये । यह कुल शिक्षा व्यय का २५ प्रतिशत है जबकि प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में यह प्रतिशत समस्त १३% एवं १६% था ।

१. इस योजना काल में १७ नये इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने का निश्चय किया । इनमें में ७ क्षेत्रीय महाविद्यालय होंगे ।
२. १७ पानीटैकनिक स्कूल स्थापित किये जायें जिनमें १० छात्रों को प्रवेश देने की क्षमता हो ।
३. २० वर्षों में ६५ वर्ष की अवस्था के छात्रों के लिए पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम होगा ।
४. छीमने योजना में छात्रवृत्ति के लिए ३ करोड़ रुपये रखा गया ।

नवीन योजनाएँ—तकनीकी शिक्षा की प्रगति के लिए सरकार ने निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित की हैं

(१) उच्चतर तकनीकी संस्थाएँ—भारतवर्ष के चारों भागों में से प्रत्येक में उच्चतर तकनीकी संस्था स्थापित करने की मिफारिश 'सरकार' समिति ने की थी । इस समिति ने इन चार उच्च संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी मिफारिश भारत में भारी उद्योगों का विस्तार एवं उनमें कार्य करने वाले उच्च तकनीकियों की माँग के आधार पर की । सन् १९५१ में कलकत्ते के पास मडनपुर नामक स्थान पर सर्वप्रथम भारतीय प्राद्योगिकी संस्था स्थापित हुई । बम्बई, कानपुर तथा मद्रास अन्य स्थान हैं जहाँ पर ये उच्च विद्यालय चल रहे हैं ।

(२) नवीन पाठ्यक्रम—देश में नवीन उद्योग प्रारम्भ होने में नवीन विषयों के अध्ययन की माँग बढ़ रही है । आवश्यकता इस बात की है कि उद्योगों की आवश्यकतानुसार ही पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना चाहिए । अखिल भारतीय प्राद्योगिक शिक्षा परिषद् की मिफारिश के आधार पर निम्नलिखित नवीन पाठ्यक्रम का शिक्षण प्रारम्भ किया गया

- (अ) मुद्रण कला, (आ) धातु कर्म, (इ) नगर-आयोजन, (ई) भवन-निर्माण, (उ) लनित्र-विज्ञान, (ऊ) प्रबन्ध-व्यवस्था ।

सरकार उपर्युक्त विषयों के शिक्षण की व्यवस्था के प्रति जागरूक है । केन्द्रीय सरकार तथा कुछ प्रान्तीय सरकारों ने मिलकर मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद और कलकत्ता में मुद्रण स्कूल स्थापित किये हैं । कुछ संस्थाओं में प्रबन्ध-व्यवस्था सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है । दिल्ली में 'ग्राम-नगर-आयोजन' का प्रशिक्षण देने हेतु विद्यालय स्थापित हुआ है ।

(३) विज्ञान भन्दिरो—प्राचीण क्षेत्रों में विज्ञान का प्रचार करने के लिए विज्ञान भन्दिरो की स्थापना की जा रही है । अब तक सम्पूर्ण देश में ३६ विज्ञान

प्रशिक्षण प्राप्त की। ११ वीं आरम्भिकता बड़ी। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण १९५१ मध्य ही १९५३ में शिक्षा के विभाग पर भी लागू किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में बंगाल सरकार ने १९५१ की शिक्षा पर ध्यान करने का १९५३-५४ बंगाल सरकार का पंचवर्षीय निर्माण था। इस योजना में पंचवर्षीय शिक्षा का ज्ञान दिया में निर्धारित कार्य उन विभाग का कार्य प्रारम्भ किया

१. १९५३ में पंचवर्षीय विद्यालयों का विकास किया गया। दुर्घटन दृष्टीशुद्ध और योजनाओं, लक्ष्यपूर्ण तथा दृष्टिकोण दृष्टीशुद्ध और माईन अग्रेसर तथा अन्य पंचवर्षीय शिक्षा योजनाओं का विस्तार किया गया। दृष्टीनिर्माण के १९५४ का १९५५ पंचवर्षीय विद्यालय।
२. पंचवर्षीय तथा दृष्टीनिर्माण की योजनाएँ शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य के लिए १९५३ लागू किया गया ध्यान करने का निर्धारित किया।
३. पंचवर्षीय पंचवर्षीय पंचवर्षीय विद्यालयों की स्थापना, प्रारम्भ शुरू का हर्नियर पंचवर्षीय ग्राह्यशाला में परिचय, औद्योगिक श्रमों का विद्यालय करने की योजना का निर्माण किया गया।
४. विदेशों में उच्च पंचवर्षीय शिक्षा प्रारम्भ करने वाले छात्रों को अधिक छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वितीय योजना में पंचवर्षीय तथा आवस्यमयिक शिक्षा पर ध्यान करने के लिए १९५५ कार्य निर्धारित किया। द्वितीय योजना का एक उद्देश्य पंचवर्षीय पंचवर्षीय विद्यालयों के लिए सुविधाओं का विस्तार करना भी गया गया।

१. प्रथम योजना ज्ञान में स्थापित किया गया पंचवर्षीय विद्यालयों में स्नानकोष्ठ पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना तथा महाविद्यालयों अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई।
२. देश के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भाग में उच्चतर तथा मध्याह्न स्थापित की जायेगी। इनमें में प्रत्येक मस्थान में स्नानक पाठ्यक्रम में तथा ६०० स्नानकोष्ठ पाठ्यक्रम में निर्माण कर सकेंगे।
३. दृष्टीनिर्माण और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए दो भागों में ६ मस्थानें डिग्री स्तर की और २१ मस्थानें डिग्री स्थापित की जायेगी।
४. छात्रवृत्तियों की संख्या

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में

हो गई तथा ५,८६० के स्थान पर

की ओर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया। सरकार तकनीकी तथा औद्योगिक शिक्षा का प्रसार करने में व्यस्त है परन्तु आसानीत सफलता नहीं मिल रही है। अनेक बाधाओं एवं समस्याओं के कारण तकनीकी शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी रही है। यहाँ पर तकनीकी शिक्षा की समस्याओं पर विचार किया जायेगा।

(१) तकनीकी विद्यालयों का अभाव—स्वतन्त्रता के बाद सरकार ने अनेक तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की परन्तु देश की जनसंख्या एवं उद्योगों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी संख्या को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इस समय सम्पूर्ण देश में केवल २६४ संस्थाएँ हैं। परिणामस्वरूप, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लगभग ६० प्रतिशत छात्र विद्यालयों में प्रवेश पाने में विवश रह जाते हैं।

समाधान—इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि देश में और अधिक तकनीकी विद्यालय प्रारम्भ किये जायें। इन विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों वाले छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए।

(२) संकीर्ण पाठ्यक्रम—हमारे यहाँ के तकनीकी विद्यालयों का पाठ्यक्रम प्रचुर है क्योंकि उनमें छात्रों को केवल तकनीकी शिक्षा ही प्रदान की जाती है। उनका सामान्य शिक्षा का अध्ययन नहीं करवाया जाता है। परिणामस्वरूप, ये तबतक उत्पादन कार्य के सामाजिक उद्देश्यों तथा मानव सम्बन्धों को नहीं समझ पाते हैं। उनकी केवल कारीगर बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए परन्तु इसके साथ ही उनके सामाजिक एवं मानवीय पक्ष के विकास के लिए भी प्रयास किये जायें।

समाधान—पाठ्यक्रम के इस दोष को दूर करने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम कक्षा सामान्य शिक्षा के विषय भी सम्मिलित करने चाहिए। अमरीका में इस संकीर्णता को सामान्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके दूर किया गया है।

(३) शिक्षकों का अभाव—सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा का विस्तार कर रही है। नवीन तकनीकी विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं परन्तु इन विद्यालयों के लिए पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि उद्योगों में अधिक वेतन एवं अन्य सुविधाएँ मिलने में प्रायोगिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति तकनीकी विद्यालयों में कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। वह उद्योगों को ही प्राथमिकता देता है।

समाधान—इस समस्या के समाधान के लिए वेतन को आकर्षक बनाना आवश्यक है तभी योग्य व्यक्ति इन संस्थाओं में कार्य करने के लिए तैयार होंगे। वेतन के अतिरिक्त सामान्य शर्तों में सुधार किया जाय और सुविधाओं में वृद्धि की जाय। जो व्यक्ति इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनको अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के अवसर दिये जायें।

मन्त्रियों की स्थापना हो चुकी है। इसमें एक प्रयोगशाला तथा प्रविष्टित कर्मचारी होने हैं। प्रत्येक का सम्बन्ध एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रहेगा।

(४) छात्रवृत्ति—संघावी निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करके तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने की सुविधा दी जाती है। छात्रवृत्ति के द्वारा ही तकनीकी तथा वैज्ञानिक शोध कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता है। तीन प्रकार की छात्रवृत्तियों का आयोजन किया गया है

- (अ) प्रयोगात्मक प्रशिक्षण वृत्ति,
- (आ) राष्ट्रीय शोध दिव्य वृत्ति,
- (इ) विश्वविद्यालय शोध वृत्ति।

प्रथम प्रकार की वृत्ति दो प्रकार के व्यक्तियों को दी जाती है—(१) स्नातक, (२) डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति। प्रथम को ₹५० ०० तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति को ₹१०० ०० की छात्रवृत्ति दी जाती है। दूसरी योजना में ४०० ०० मासिक की ५० राष्ट्रीय शोध दिव्य वृत्ति का आयोजन रखा गया। विश्वविद्यालय शोध वृत्ति की ५०० शोध वृत्तियाँ रखी गईं जोकि ₹२०० ०० मासिक की थी।

(५) शिक्षक प्रशिक्षण—अब तक तकनीकी विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव रहा है परन्तु तकनीकी क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रवर्ध हो जाने में अब शिक्षकों का अभाव नहीं रहेगा, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इन विद्यालयों के लेन में वृद्धि करके इनको आकर्षक बनाया जाय।

(६) अनुसंधान—भारत सरकार ने सन् १९४२ में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शोध के लिए 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध-परिषद्' की स्थापना की थी। आज यह परिषद् अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन दे रही है। तीसरी योजना में अनुसंधान सम्बन्धी कार्य की उन्नति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम की योजना रखी गई

- १ वर्तमान अनुसंधानशास्त्रियों को सुविधाएँ देकर अनुसंधान कार्य के लिए मजबूत बनाना।
- २ विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करना।
- ३ वैज्ञानिक और औद्योगिक औजारों के निर्माण में अनुसंधान कार्य करना।
- ४ विभिन्न समस्याओं द्वारा किये जा रहे अनुसंधान कार्य में समन्वय रखना।
- ५ अनुसंधानकर्ता को प्रशिक्षण देना।

तकनीकी शिक्षा की समस्याएँ—तकनीकी शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करने में स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने भारत में तकनीकी एवं औद्योगिक शिक्षा की सदैव अवहेलना की। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने भारी उद्योगों के विकास की योजनाएँ बनाई परन्तु इन उद्योगों में कार्य करने वाले तकनीशियों की तैयारी करने

की ओर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया। सरकार तकनीकी तथा औद्योगिक शिक्षा का प्रचार करने में व्यस्त है परन्तु आध्यात्मिक सफलता नहीं मिल रही है। अनेक बाधाओं एवं समस्याओं के कारण तकनीकी शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी रही है। यहाँ पर तकनीकी शिक्षा की समस्याओं पर विचार किया जाएगा।

(१) तकनीकी विद्यालयों का अभाव—स्वतन्त्रता के बाद सरकार ने अनेक तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की परन्तु देश की जनसंख्या एवं उद्योगों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी संख्या को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इस समय सम्पूर्ण देश में केवल २६४ संस्थाएँ हैं। परिणामस्वरूप, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लगभग ६० प्रतिशत छात्र विद्यालयों में प्रवेश पाने में सक्षम रह जाते हैं।

समाधान—इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि देश में और अधिक तकनीकी विद्यालय प्रारम्भ किये जायें। इन विद्यालयों में विभिन्न वायव्यता वाले छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए।

(२) संकीर्ण पाठ्यक्रम—हमारे यहाँ के तकनीकी विद्यालयों का पाठ्यक्रम संकीर्ण है क्योंकि उनमें छात्रों को केवल तकनीकी शिक्षा ही प्रदान की जाती है। उनको सामान्य शिक्षा का अध्ययन नहीं करवाया जाता है। परिणामस्वरूप, ये तब युवक उदात्त कार्य के सामाजिक उद्देश्यों तथा मानव सम्बन्धों को नहीं समझ पाते हैं। उनको केवल कारीगर बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए परन्तु इसके साथ ही उनके सामाजिक एवं मानवीय पक्ष के विकास के लिए भी प्रयास किये जायें।

समाधान—पाठ्यक्रम के इस दोष को दूर करने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम के साथ सामान्य शिक्षा के विषय भी सम्मिलित करने चाहिए। अमेरिका में इस संकीर्णता को सामान्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके दूर किया गया है।

(३) शिक्षकों का अभाव—सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा का विस्तार कर रही है। नवीन तकनीकी विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं परन्तु इन विद्यालयों के लिए पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि उद्योगों में अधिक वेतन एवं अन्य सुविधाएँ मिलने से औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति तकनीकी विद्यालयों में कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। वह उद्योगों को ही प्राथमिकता देता है।

समाधान—इस समस्या के समाधान के लिए वेतन को आकर्षक बनाता आवश्यक है तभी योग्य व्यक्ति इन संस्थाओं में कार्य करने के लिए तैयार होंगे। वेतन के अनिश्चित सामान्य शर्तों में सुधार किया जाय और सुविधाओं में वृद्धि की जाय। जो व्यक्ति इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनको अपनी वैयक्तिक योग्यता बढ़ाने के अवसर दिये जायें।

(८) शिक्षा का माध्यम—नकली शिक्षा के माध्यम की समस्या अभी तक समाप्त नहीं हुई है। नकली शिक्षा में नकली शिक्षा का माध्यम प्रयोग होता है। छात्री भाषाओं का माध्यम बनाने का प्रयास भी कम है। परन्तु व्यापक ही अभी तक एक बात में नहीं है। जैसे उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है परन्तु इन छात्रों का नकली शिक्षा में प्रयोग माध्यम में पढ़ाई में एक बहिष्कार का माध्यम बनता जाता है। उनका समय तथा धन का अपव्यय होता है।

समाधान—यह आवश्यक नहीं है कि देशों का शिक्षा का माध्यम बनाने में ही नकली शिक्षा का प्रयोग हो सकता है। बिना यह कुछ एवं देशों के भी उदाहरण हैं जहाँ शिक्षा का माध्यम अपने देश की भाषा में है। जर्मनी, कम और जर्मनी में नकली शिक्षा का प्रायोगिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। इन देशों में छात्रों का अपने देश की भाषा में ज्ञान दिया जाता है। भारत में भी नकली शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। यह ठीक है कि प्रारम्भ में कुछ बहिष्कार अवश्य होगी परन्तु भारतीय भाषाओं में ही पुनः उपरान्त ज्ञान वह यह बहिष्कार भी दूर हो जायेगी।

(९) वास्तु-पुस्तक का अभाव—हमारे देश में नकली शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम पुस्तक निगम हैं। अधिकांश पुस्तक विदेशों में होती हैं। हमारे अग्रगण्य ज्ञान में पुस्तक और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरी ओर छात्रों की संख्या में प्रतिकूल वृद्धि होती जाने में पुस्तक की माँग भी बढ़ती जा रही है। पुस्तकों के अभाव में छात्र उच्च में विषयों की संशोधन करने में नहीं कर पाते हैं।

समाधान—इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत प्रयत्नोपचार किए हैं कि मनुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन में प्रकाशित नकली शिक्षा पुस्तकों के प्रकाशन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। परिणामस्वरूप, कम मूल्य पर ही पुस्तकें छात्रों को उपलब्ध कराने में सफल हो जाती हैं। सरकार की कुछ पुस्तकों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में करवाना चाहिए। छात्रों को भी मौखिक पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

(१०) अध्ययन समाप्ति के उपरान्त शिक्षा का अभाव—नकली शिक्षा प्रदान करने के उपरान्त नवयुवक किसी व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। धीरे-धीरे इनका ज्ञान सीमित होता जाता है और वे बहुत सी बातें भूल जाते हैं। परिणामस्वरूप, उनकी कुशलता में कमी आ जाती है। इसके साथ ही अपने देश में काम करने हुए वैश्विक योग्यता बढ़ाने के लिए शिक्षा मर्यादा नहीं है जहाँ पर अद्यतनीय पाठ्यक्रम की हो।

समाधान—वर्तमान सताब्दी में दिन-प्रतिदिन तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो अब एक शिक्षा को नवीन ज्ञान प्राप्त करने की मुविधा भी और सरकार को



देना चाहिए। यहाँ पर अशकामोन तथा पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम तकनीकी में ही प्रारम्भ करने चाहिए। इसके साथ ही अभिनव पाठ्यक्रमों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। हमारे देश में अवकाश काल का सदुपयोग करने के लिए उद्योगों की व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार तथा औद्योगिक संस्थाओं को इनके लिए प्रोत्साहन, पुस्तकालय, नमूनाखाना तथा नाट्यप्रदर्शनाएँ बनानी चाहिए।

(७) कर्मशाखा अभ्यास—तकनीकी शिक्षा में छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान अधिक आवश्यकता होती है। विद्यालयों में जो भी मैथानिक ज्ञान छात्रों को प्रदाना है, उसकी व्यावहारिकता की जाँच प्रयोग द्वारा होती है। प्रयोग करने में विद्यालयों में प्रयोगशालाएँ या कर्मशाखाएँ होनी चाहिए। हमारे देश के तकनीकी विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का अभाव है। परिणामस्वरूप छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान तो होता है परन्तु प्रयोगात्मक ज्ञान नहीं होता। जिन विद्यालयों में प्रयोगशालाएँ या कर्मशाखाएँ हैं, वे नाचमाच की हैं क्योंकि उनमें यन्त्री एवं मशीनों का अभाव है।

समाधान—इस कार्य के लिए तीन महत्वपूर्ण सुझाव हैं—(अ) सरकार द्वारा विद्यालयों को सुसज्जित करने हेतु पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। (आ) तकनीकी शिक्षा तथा उद्योगों के मध्य सीधा सम्बन्ध होना चाहिए। तकनीकी विद्यालयों में भारी उद्योग या फैक्ट्री के निकट ही स्थापित किये जायें जिसमें छात्रों को प्रत्यक्ष कार्य करने की सुविधा उनमें मिल सके। (इ) छात्र व्यापारी फर्मों में नौकरी करे। इससे उन्हें वास्तविक लाभ मिलेगा—(१) छात्रों को वेतन के रूप में सहायता मिलती है, (२) उनको स्वाभाविक ज्ञानावरण में प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। (३) वहाँ कार्य करते हुए स्थायी नौकरी भी हो सकती है। विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के सम्पर्क में आने से सामाजिक पक्ष विकसित होगा।

(क) अनुसन्धान—भारतवर्ष में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद शोध-कार्य की ओर ध्यान दिया गया परन्तु अभी तक अनेक क्षेत्र तथा समस्याएँ ऐसी हैं जिनमें शोध और अधिक आवश्यकता है। ऊँचा एवं उद्योग के क्षेत्र में शोध-कार्य सन्तोष-जनक पर्याप्त नहीं हो रहा है।

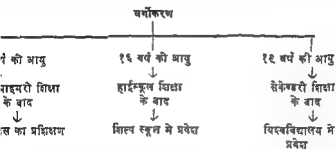
समाधान—सरकार ने इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया है। देश में शोधशाखाएँ स्थापित की गई हैं। शोध-कार्य करने वालों को पूर्ण आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिससे उनको आर्थिक समस्या के कारण शोध से दूर नहीं छोड़ना पड़े। शोधशाखाओं में प्रयोगशालाएँ पूर्णतः सुसज्जित होनी चाहिए।

(६) सरकार, उद्योग तथा तकनीकी शिक्षा में सहयोग—भारतवर्ष में उद्योग विकास-संस्थाओं में परस्पर सम्पर्क नहीं है। परिणामस्वरूप, विद्यालयों को उद्योगों



होशियार के नाम से पुकारते हैं। इन मस्थाओं में उन छात्रों को प्रवेश दिया जाये जो ॥ वर्षीय माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

आयु के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण—वैसे जर्मनी में १८ वर्ष तक की बालक-बालिकाओं के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य तथा है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा १० वर्ष की आयु पर समाप्त होती है। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य और निशुल्क है। इस देश में प्राथमिक शिक्षा हर तेन पर छात्रों को तीन बर्षों में बाँट दिया जाता है



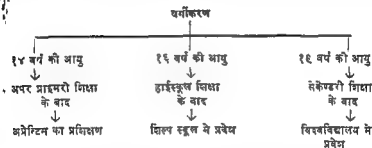
उपरोक्त रेखाचित्र में स्पष्ट है कि १० वर्ष की आयु के बाद छात्रों को तीन में विभाजित कर दिया जाता है। लगभग ८० प्रतिशत छात्र १४ वर्ष की आयु पर प्राथमिक शिक्षा समाप्त करके किसी व्यावसायिक स्कूल में अप्रेंटिस बन जाते हैं। यहाँ पर वे अधिक रूप से ही प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार के छात्र जो १६ वर्ष की आयु तक हाईस्कूल शिक्षा प्राप्त करते हैं और बाद में किसी स्कूल में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तीसरे वर्ग के छात्र १८ वर्ष की आयु के पश्चात् हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त करते हैं और इसके बाद किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। परन्तु विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही कम है। अधिकांश छात्र व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। पर तकनीकी शिक्षा के पूर्णकालीन तथा अर्धकालीन दोनों ही पाठ्यक्रम हैं।

विस्तृत पाठ्यक्रम—जैसा कि हमने अपने यहाँ पर देखा कि तकनीकी शिक्षा देने वाले छात्रों को केवल तकनीकी विषय ही पढ़ाए जाते हैं। उनके सामाजिक मानवीय पक्ष के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, परन्तु यह दोष के पाठ्यक्रम में नहीं है। यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए पाठ्यक्रम में ही व्यवस्था की गई है। व्यावसायिक सामान्य शिक्षा के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः यहाँ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही सामाजिक शिक्षा का भी अध्ययन करना होता है। बालकों के



टेक्नीसी होशपूल के नाम से पुकारते हैं। इन संस्थाओं में उन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो १ वर्षीय माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

आयु के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण—जैसे जर्मनी में १८ वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा १० वर्ष की आयु पर समाप्त होती है। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य और निशुल्क है। इस देश में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेने पर छात्रों को तीन वर्गों में बाँट दिया जाता है



उपरोक्त रेखाचित्र में स्पष्ट है कि १० वर्ष की आयु के बाद छात्रों को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। लगभग ८० प्रतिशत छात्र १४ वर्ष की आयु में अपर प्राइमरी शिक्षा समाप्त करके किसी व्यावसायिक स्कूल में अप्रेन्टिस बन जाते हैं। यहाँ पर वे आंशिक रूप से ही प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार के छात्र वे हैं जो १६ वर्ष की आयु तक हाईस्कूल शिक्षा प्राप्त करते हैं और बाद में किसी शिल्प स्कूल में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तीसरे वर्ग के छात्र १९ वर्ष की आयु तक सेकेंडरी स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करते हैं और इसके बाद किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। परन्तु विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम ही है। अधिकांश छात्र व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर तकनीकी शिक्षा के पूर्णकालीन तथा अर्धकालीन दोनों ही पाठ्यक्रम चलते हैं।

विस्तृत पाठ्यक्रम—जैसा कि हमने अपने यहाँ पर देखा कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को केवल तकनीकी विषय ही पढ़ाए जाते हैं। उनके सामाजिक तथा मानवीय पक्ष के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, परन्तु यह दोष यहाँ के पाठ्यक्रम में नहीं है। यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के मास्त्रुनिक विकास के लिए पाठ्यक्रम में ही व्यवस्था की गई है। व्यावसायिक तथा सामान्य शिक्षा के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः यहाँ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही सामाजिक शिक्षा का भी अध्ययन करना होता है। बालकों के

मार्वादीय विचारों पर ध्यान दिया जाता है। छात्रों को सामान्य शिक्षा पाथिक शिक्षा का अध्ययन अनिवार्य रूप में कराया जाता है।

**व्यावसायिक निर्देशन-** विद्यार्थियों में अध्ययन करने और छात्रव्यावसायिक निर्देशन की सुविधा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा का एक अलग माना जाता है जिसमें छात्र अपनी रूचि तथा अभिरुचि के आधार पर शिक्षा व्यवस्था का चुनाव करते उसमें आवेग बड़ा है। जर्मनी में धर्म मंत्रालय छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन महाविद्यालयों में भेजकर प्रशिक्षण देता है। धर्म का प्रदीपिकाओं प्रादमरी विद्यालय के छात्रों की जीवन मनीषात्मिक तरीका द्वारा करता है। छात्रों के अभिभावकों की सहायता में वह छात्रों के व्यावसायिक निर्देशन का निश्चय करता है।

**व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने की सुविधा—**जर्मनी में तकनीकी शिक्षा में योग्यता बढ़ाने के लिए छात्रों का अनेक सुविधाओं से देती है। यह शिक्षाप्रणाली पक्की है जहाँ पर कर्मचारी शिक्षा उत्तम रूप में चलते हैं। जर्मन व्यवस्थापक पाठ्यक्रम की सुविधा व्यवस्थाओं में नये रूप व्यक्तियों की प्रदान की है। यहाँ एक सुविधा कर्मचारियों का यह भी देती है कि पाँच बरसों की व्यवस्था में नौकरी करने के बाद वह स्वतन्त्रता परीक्षा (Masters Examination) में बैठ सकता है। इसके अनुरूप यहाँ पर कर्मचारियों के मनोरंजन व्यवस्था औद्योगिक नस्थानों में की जाती है।

**उद्योगपतियों का सहयोग—**जर्मनी में उद्योगपतियों ने कुशल कर्मचारियों आवश्यकता अनुभव की है। परिणामस्वरूप, वे नौग भी व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा में रुचि लेने लगे हैं। वे आर्थिक सहायता भी देने हैं। इसीलिए यहाँ तकनीकी शिक्षा अधिक विकसित हो गयी है।

**इस में तकनीकी शिक्षा—**रुप में भी जर्मनी की भांति तकनीकी औद्योगिक शिक्षा की प्रगति अत्यधिक हुई है। लगभग ५० वर्ष पूर्व जो देश बिल्कुल दुर्गम था, आज चन्द्रशेखर की यात्रा में बहुत आगे बढ़ गया है। आज्ञा जाती है कि शीघ्र ही यह अपने मानव को चन्द्रमा पर उतार देगा। हम में उदा के क्षेत्र में अधिक विकास हुआ है। यह सब कुछ तकनीकी ज्ञान से ही सम्भव सका है। यहाँ पर छात्रों को पॉलीटेक्निकल प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा से भिन्न है। पॉलीटेक्निकल प्रशिक्षण द्वारा छात्रों को आधुनिक औद्योगिक और कृषि-उत्पादन की महत्वपूर्ण शाखाओं का ज्ञान कराया जाता है। माथम भी पॉलीटेक्निक शिक्षा के पक्ष में था। उसने एक बार कहा था, "शिक्षा हमारे लिए अर्थ है—(१) दारिद्र्यक विकास, (२) बौद्धिक विकास, तथा (३) पॉलीटेक्निकल शिक्षा। पॉलीटेक्निकल शिक्षा ने उनका तात्पर्य था कि छात्रों को उत्पादन प्रक्रिया का ज्ञान कराने के साथ-साथ उनको उसकी प्रत्येक शाखा में प्रयुक्त उपकरण

का ज्ञान कराना। कम उम्र में माध्यमिकी स्तर के विना इस प्रकार की शिक्षा को आवश्यक समझा गया। सन् १९२० के बाद जर्मनी ने भी पानीटेक्निकल प्रशिक्षण पर बल दिया परन्तु वैज्ञानिक प्रगति के कारण वैज्ञानिक तरीके प्रयोग में लाये जाने लगे। पुरानी विधियों का स्थान नई विधियाँ हाथ लिया जाने लगा। उस समय पानीटेक्निक शिक्षा में लार्गवे हाथ के काम में था। इस शिक्षा को पाठ्यक्रम में इलाक़ा द्वारा स्थान विज्ञान का दिया गया परन्तु १९४५-४६ में पानीटेक्निकल प्रशिक्षण में रूप में पुनः आरम्भ हो गया है।

प्रारम्भिक व्यावसायिक शिक्षा कम में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के विना व्यावसायिक प्रशिक्षक स्कूल और कारखाना प्रशिक्षण के स्कूल भी है। ये स्कूल भिन्न-भिन्न उद्योगों में विभागों के द्वारा संचालित होते हैं। व्यावसायिक या वेल्थे स्कूलों में प्रवेश आयु १४-१५ तथा कारखाना-स्कूलों में १६-१८ वर्ष है। यहाँ निम्नक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इन विद्यालयों में सामान्य शिक्षा का अध्ययन भी कराया जाता है। प्रवासात्मक कार्य के लिए यान्त्रिक मात्रमत्वा में पूर्ण कर्मदानाएँ होती हैं।

माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा इन स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त करके निम्न स्तर तक अधिक माध्यम स्तरों के विद्यार्थी होते हैं। ये लोग उनी स्तर का कार्य करके, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, चित्रकारों के सहायक तथा अन्य उद्योगों में काम करते हैं। सन् १९५४-५६ में इस प्रकार के टेक्निकल स्कूलों की संख्या ३,६४० थी। इन विद्यालयों में मध्यमवर्गीय शिक्षा प्राप्त करने की प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश की आयु-अवधि १४ से ३० वर्ष है। माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण काय ६ से लेकर ४ वर्ष तक का होता है। इन विद्यालयों में भी छात्रों की सामान्य विषयों का ज्ञान कराया जाता है। सामान्य शिक्षा के प्रमुख विषय या पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं वे इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान तथा साहित्य हैं। यहाँ का अध्ययन समाप्त करने पर छात्रों का डिप्लोमा दिया जाता है। माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा की सुविधा भी दी जाती है। परन्तु इस सुविधा की शर्त है कि उस व्यक्ति ने अपने विनिष्ट कार्य में कम से कम ३ वर्ष कार्य किया हो, या वे ही छात्र सीधे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हों।

इस में पर-स्वयंसेवा तथा मजदूरों की कक्षाओं के द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जाती है। सन् १९५६-५७ में पर-स्वयंसेवा के द्वारा शिक्षा देने वाले लगभग ४१ तकनीकी विद्यालय थे। यहाँ पर उपर्युक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों का प्रशिक्षण कार्य बढ़ाने का निश्चय किया गया है।

फँटरी स्कूल—इस में तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए फँटरी स्कूल की भी व्यवस्था है। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षण

चारी तैयार करना है। इन विद्यालयों में उन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो बी कक्षा में साधारण अंक प्राप्त करते हैं। फंक्टरी स्कूल तीन प्रकार के हैं।

(१) प्रथम प्रकार के स्कूल वे हैं जो खनिज उद्योग जैसे अन्य उद्योगों के 'अर्ध'-कुशल कर्मचारी तैयार करते हैं। यहाँ प्रशिक्षण काल ६ माह का होता है।

(२) दूसरे प्रकार के विद्यालयों में दो वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। ये जलय मिल, फंक्ट्री आदि के लिए मिर्कनिक तैयार करते हैं।

(३) तीसरे प्रकार के विद्यालय रेलवे या टेलीफोन विभाग के लिए तैयार करते हैं, इनमें भी दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इंग्लैण्ड में तकनीकी शिक्षा—ब्रिटेन भी एक औद्योगिक देश है। अतः यहाँ व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार अधिक हुआ है। इस देश में तकनीकी शिक्षा की प्रगति धीमी गति से हुई। यहाँ पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना औद्योगिक क्रान्ति के बाद हुई। सन् १८२५ में सबसे पहले तकनीकी स्थापना 'लन्दन मिर्कनिकम इंस्टीट्यूट' के नाम से हुई। धीरे-धीरे अनेक तकनीकी संस्थान स्थापित हो गये। इंग्लैण्ड में पूर्णकालीन एवं सायकलीक शिक्षा संस्थाएँ हैं। पूर्णकालीन कक्षाएँ प्रायः दिन में लगती हैं।

डूनिघर टेक्निकल स्कूल—इंग्लैण्ड में तकनीकी शिक्षा के विस्तार में डूनिघर स्कूलों में अधिक सहयोग दिया है। उनका महत्त्व स्पष्ट होने के कारण ये स्कूलों में अधिक वृद्धि हुई है। इन स्कूलों में बच्चों को १३ वर्ष की अवस्था से शिक्षा दी जाती है और २ या ३ वर्ष तक वे यहाँ अध्ययन करते हैं। इन में सामान्य शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

टेक्निकल कॉलेज—इनमें पूर्णकालीन कक्षाएँ दिन के समय चलती हैं। इन की अवधि २ या ३ वर्ष तक की होती है। इस समय इंग्लैण्ड में ८० टेक्निकल कॉलेज हैं जो ६००० छात्रों को शिक्षा देते हैं। यहाँ पर टेक्निकल ज्ञान तथा विज्ञान विद्यालय परस्पर सहयोग में कार्य करते हैं। इंग्लैण्ड में उद्योगपति एवं कारोबार तकनीकी शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। ये कॉलेज कारखानों एवं उद्योगों हायना में कार्य करते हैं।

संश्लेषिक कार्य—इस कार्य में छात्र काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। बहुत कम अप्रत्यक्ष कर्मचारियों की वर्ष में कुछ महीने तकनीकी शिक्षा का अध्ययन के लिए अवकाश देते हैं। इस प्रकार कई बार पढ़कर वह मर्चेंफिन्ट या पदवी प्राप्ति के लिए परीक्षा देना है। सन् १९४५ में 'गार्ड पार्सी' की रिपोर्ट में संश्लेषिक कार्य की स्थापना तथा उनका विकास करने का सुझाव दिया गया।

### अभ्यासात्मक प्रश्न

१. भारतवर्ष में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता पर एक निबन्ध लिखिए।
२. भारतवर्ष में तकनीकी शिक्षा के विभाग का ऐतिहासिक वृत्त लिखिए।



३. पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए ।
४. भारत में तकनीकी शिक्षा की समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए अपने सुझाव दीजिए ।
५. विदेशों की तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने में हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ।

**राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न**

1. Analyse the problem of the educated unemployed in India. How can technical and vocational education help in its solution ? (1961)
2. After the World-War II, all that Germany and Japan were left with was 'the arms and the brains trained for collective creative work and the courage to face the situation.' What is India doing, and what more should she do educationally in order to occupy a respectable place among the Powers that count ? (1962)
3. Trace the history of vocational and technical education in India and account for its slow progress. Show the impact of the Five Year Plans on its progress during the last decade. (1963)
4. The father of a student of class XI comes to you for advice as to the vocational prospects before him or her. Taking into consideration the various diversified courses into consideration, enlighten the father as to the careers open to the student. (1964)
५. भारत में प्रावधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? इनका निवन्धन और हल बताने हो सकता है ? (१९६४)
६. जर्मनी अथवा रूस की प्रावधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के रूप में वर्णन कीजिए । हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको यहाँ स्वीकार किया जा सकता है ? (१९६५)
७. प्रावधिक शिक्षा की परिभाषा दीजिए । अपने राज्य की विभिन्न प्रकार की प्रावधिक शिक्षा मस्वाओं का वर्णन कीजिए । प्रावधिक शिक्षा द्वारा बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान किम सीमा तक होने का अनुमान है ? (१९६६)

कर्मधारी तैयार करना है। इन विद्यालयों में उन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो गरीबी की दृष्टि से गरीब हों। इन विद्यालयों में छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(१) प्रथम प्रकार के स्कूल वे हैं जो गरीबों के लिए प्रवेश के लिए अर्द्ध-मुक्त कर्मधारी तैयार करने हैं। यहाँ प्रशिक्षण का १ माह का होता है।

(२) दूसरे प्रकार के विद्यालयों में दो वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। विद्यालय में, 'हैंड्री आदि के लिए' मिर्कनिक तैयार करने हैं।

(३) तीसरे प्रकार के विद्यालय में दो या दो-तीनों विभाग के लिए तैयार करने हैं, इनमें भी दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इंग्लैंड में तकनीकी शिक्षा—इंग्लैंड में एक औद्योगिक देश है। अतः यहाँ तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता अधिक है। इस देश में तकनीकी शिक्षा की प्रगति धीमी गति में हुई है। यहाँ पर तकनीकी और व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना औद्योगिक आर्थिक के साथ हुई है। सन् १८२५ में पहले तकनीकी संस्थान की स्थापना 'लन्दन मिर्कनिक इंस्टीट्यूट' के नाम से हुई। यहाँ अनेक तकनीकी संस्थान स्थापित हो गये। इंग्लैंड में पूर्णकालीन एवं माध्यमिक तकनीकी शिक्षा संस्थाएँ हैं। पूर्णकालीन कक्षाएँ प्रायः दिन में लगती हैं।

पूर्णकालीन तकनीकी स्कूल—इंग्लैंड में तकनीकी शिक्षा के विस्तार में पूर्णकालीन तकनीकी स्कूलों ने अधिक सहयोग दिया है। उनका महत्व स्पष्ट होने के कारण उनकी संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। इन स्कूलों में बच्चों को १३ वर्ष की अवस्था में प्रवेश दिया जाता है और २ या ३ वर्ष तक ये यहाँ अध्ययन करते हैं। इन स्कूलों में सामान्य शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

टैक्नीकल कालेज—इनमें पूर्णकालीन कक्षाएँ दिन के समय चलती हैं। इनमें कोर्स की अवधि २ या ३ वर्ष तक की होती है। इस समय इंग्लैंड में ८० टैक्नीकल कालेज हैं जो १००० छात्रों को शिक्षा देते हैं। यहाँ पर टैक्नीकल कालेज तथा माध्यमिक विद्यालय परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं। इंग्लैंड में उद्योगपति एवं व्यापारी तकनीकी शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। ये कालेज कारखानों एवं उद्योगों की सहायता में कार्य करते हैं।

संयोजित कोर्स—इस कोर्स में छात्र काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। बहुत से मालिक अपने कर्मचारियों को वर्ष में कुछ महीने तक तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने के लिए अवकाश देते हैं। इस प्रकार कई बार पढ़कर वह सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्ति के लिए परीक्षा देता है। सन् १९४५ में लार्ड गार्डन की रिपोर्ट में भी संयोजित कोर्स की स्थापना तथा उनका विकास करने का सुझाव दिया गया।

#### अभ्यासार्थ प्रश्न

१. भारतवर्ष में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता पर एक निबन्ध लिखिए।
२. भारतवर्ष में तकनीकी शिक्षा के विकास का ऐतिहासिक वर्णन लिखिए।

३. पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए।
४. भारत में तकनीकी शिक्षा की समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए सुझाव दीजिए।
५. विदेशों की तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

1. Analyse the problem of the educated unemployed in India. How can technical and vocational education help in its solution? (1967)
2. After the World-War II, all that Germany and Japan were left with was 'the arms and the brains trained for collective creative work and the courage to face the situation.' What is India doing, and what more should she do educationally in order to occupy a respectable place among the Powers that count? (1967)
3. Trace the history of vocational and technical education in India and account for its slow progress. Show the impact of the Five Year Plans on its progress during the last decade. (1957)
4. The father of a student of class XI comes to you as to the vocational prospects before him or her. Introduce the various diversified courses into consideration and guide the father as to the careers open to the student. (1967)
५. भारत में प्रावधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के विकास की योजना करना पड़ रहा है? इनका विवरण दीजिए और इनके विकास में क्या बाधाएँ हैं?
६. जर्मनी तथा जपान की प्रावधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का वर्णन कीजिए। हमारे देश की आवश्यकताओं के हिसाब से स्वीकार किया जा सकता है?
७. प्रावधिक शिक्षा का अर्थ क्या है?

## अध्याय ११

### भारत में भाषा-समस्या

#### भाषा का महत्त्व

भाषा मानव-जाति को ईश्वरीय देन है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचार तथा अनुभवों की अभिव्यक्ति करता है। आज साहित्य, संस्कृति एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में जो प्रगति दृष्टिगोचर होती है, वह भाषा का ही परिणाम है। इसके अभाव में मानव भी पशु-जगत् के समान होता और संकेतों के आधार पर या चित्लाकर अपने मन के भाव व्यक्त करता। भाषा के महत्त्व को स्पष्ट करने हुए पी० बी० बैलार्ड ने लिखा है कि "भाषा वह साधन है जिसने अपने निर्माता को शिक्षित बनाया है।" जिस देश या जाति की भाषा जितनी अधिक समृद्ध होती है, उसका साहित्य भी उच्च होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। मानुभाषा भाव-व्यजना का ध्येय साधन है। विचार और वाणी का घनिष्ठ सम्बन्ध होने से एक का विकास होने पर दूसरे का भी विकास होता है। श्री नीताराम जतुर्वेदी ने लिखा है कि—"भाषा के इस वरदान को पाकर मानव समाज यूँगो की विराट बस्ती होने से बच गया है।" भाषा व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहयोग देती है। जिस व्यक्ति को समाज में अपने भाव व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है या जिसका अपने भाव व्यक्त करने के लिए भाषा पर अधिकार नहीं है, उसके अन्दर भावना प्रधियाँ बनती हैं। भावना प्रधियाँ व्यक्तित्व के विकास को रोक देती हैं। रायबर्न ने लिखा है कि "भाषा द्वारा गावैगिक तथा बौद्धिक जीवन की नींव मृदु होती है।"

भारतवर्ष एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर लगभग ५२५ भाषाएँ और बोलियाँ हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश के समस्त एक यह भी समस्या उत्पन्न हुई कि जिस

"a fact a tool that has educated its maker."—P B

भाषा का मानव-बोधन में इतना महत्त्व है, वह कौनगी भाषा होती चाहिए जिसका अध्ययन सभी छात्र करें। भारतवर्ष में आज भी भाषा की समस्या उभर कर धारण किये हुए है। देश में भाषाशास्त्र प्रान्तों का निर्माण हो रहा है। आज राष्ट्र को भुलाकर सभी लोग अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषा के लिए जंग द रहे हैं। समस्या केवल भारतीय भाषाओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमारे देश में अभी तक कुछ अंग्रेज-भक्त अंग्रेजी को ही बनावे रखना चाहते हैं। आज देश में भाषा के प्रश्न पर महान आदि प्रान्तों में जनेक उपद्रव हो रहा है। ये मांग भाषा के प्रश्न को लेकर राष्ट्रीय समिति को नष्ट करने हैं तथा राष्ट्रीय एकता में विघटनकारी नाच पैदा करने हैं। अगर भाषा के प्रश्न को लेकर परस्पर मन-मुटाव बनेंगे, तब लोग परस्पर लड़ेंगे तो देश की एकता का हान होना तथा देश में चलने वाले विकास-कार्य रुक जायेंगे। भारतवर्ष में भाषा के सम्बन्ध में तीन समस्याएँ हैं

१. मधीय भाषा का अध्ययन,
२. अंग्रेजी भाषा का अध्ययन,
३. मिश्रा का माध्यम किस भाषा का बनाया जाय।

### भाषा समस्या का इतिहास

भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना के समय में ही भारतवर्ष में शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन आया। अंग्रेजों ने बच्चों को मातृभाषा का शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया और न उन लोगों ने मातृभाषा के महत्त्व की ओर ध्यान ही दिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साम्राज्य काल में जब यह निश्चित हो गया कि भारतवर्ष में भारतवासियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करना तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करना कम्पनी का ही उत्तरदायित्व है तो उस समय ही वाद-विवाद की समस्या उठ खड़ी हुई कि इन शिक्षण सुस्थाओं में शिक्षा का माध्यम कौनसा बना रहेगी? मतभेद के कारण उस समय अंग्रेज अधिकारियों में दो दलों का निर्माण हुआ। एक दल भारतीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में था तथा दूसरा दल चाहता था कि भारतीय भाषाओं के स्थान पर हिंदी शिक्षा का माध्यम बनाया जाय जिसमें अंग्रेजी भाषा शामिल रहे। यह दल भारतीय भाषाओं के स्थान पर हिंदी शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में था।

केन्द्रीय-  
समिति का  
निर्णय  
१९०५ का  
१९०७ का

बनाने हुए विद्या है कि "यूरोप के एक अखंड युवराज-वंश की एक अवसारी का गार्हस्थ भारत गया अथ के सम्पूर्ण गार्हस्थ से महत्त्वपूर्ण है।" अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा करते हुए उगने एक स्थान पर विद्या है कि - "अंग्रेजी भाषा आध्यात्म भाषाओं में भी सबसे उत्तम है। इस भाषा का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति विश्व की बुद्धिमान जाति का शान्ति विधान ज्ञान-अभिव्यक्ति को प्राप्त कर सकता है।" मार्शल बेंट्लिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया। सन् १८४८ में लार्ड हार्डिज ने घोषणा की कि उन लोगों को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जावेगी जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हों। इससे अंग्रेजी के प्रचार का और भी अधिक प्रोत्साहन मिला।

सन् १८५४ में युद्ध के घोषणा-पत्र में भी अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाने की विचारणा गई थी। इसके साथ ही इन्होंने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वाला छात्रों के लिए ही अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम होगा। अन्य छात्रों के लिए देशी भाषाएँ ही शिक्षा का माध्यम बनी रहेंगी। सन् १८५९ में प्रथम भारतीय शिक्षा अधिनियम की विधुक्ति की गई। इस अधिनियम का मुख्य भाग था कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ हो परन्तु माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही रहे। बीमवी दत्ताय्य के प्रारम्भ में लार्ड कर्जन ने प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की परन्तु राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होने से माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी रही।

राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव—सन् १९०५ के बाद भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन तीव्र गति से आरम्भ हुए। भारतीय नेताओं ने भारतीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण स्थान देने तथा माध्यम के रूप में प्रयोग में लाने की माँग की। अंग्रेजी के विरोध में महात्मा गांधी ने कहा है कि "भारतीय बच्चे सोचते हैं कि बिना अंग्रेजी के राष्ट्रीय सेवा में काम नहीं पा सकते हैं। नाविकाओं की छाती के मे अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता। वे सभी दायता एवं पाठ्यक्रम बनाने की सिफारिश के लिए उतनी ही

आवश्यक है जितना बालक के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध ।"। इस कथन में स्पष्ट है कि गांधीजी मातृभाषा को परीक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में थे । सन् १९१७ में नियुक्त 'कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' ने इन्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ बनाने की ही सिफारिश की । सन् १९२१ में १९३७ के मध्य का शिक्षा का इतिहास देखें तो स्पष्ट होगा कि माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया परन्तु फिर भी कुछ विद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम में शिक्षा दी जाती थी । विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी ही माध्यम थी । सन् १९३७ में भारतीय नेताओं ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली को अपनाने पर विशेष जोर दिया । बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा को माध्यम बनाने पर जोर दिया गया ।

- बनाने के लिए सर जॉन
- हाईस्कूलों में शिक्षा का
- द्वितीय अतिवार्य विषय में

रूप में होगी ।

विश्वविद्यालय आयोग—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने १ नवम्बर, १९४८ को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की । इस आयोग के अध्यक्ष डॉ० एस० राधाकृष्णन् थे । आयोग ने लिखा है कि शिक्षा का यही क्षेत्र सबसे अधिक विवादास्पद है । भारतीय इस क्षेत्र के बारे में एकमत नहीं है । आयोग ने माध्यम के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिये

१. उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा का प्रयोग प्रारम्भ किया जाय ।
२. एक सघीय भाषा का देवनागरी लिपि में विकास किया जाय और इनमें अन्य लोगों में आये हुए शब्दों का भी समन्वय करके इसे समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया जाय ।
३. उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन कराया जाय—(१) प्रादेशिक भाषा, (२) सघीय भाषा और (३) अंग्रेजी ।
४. सघीय एवं प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए सभी प्रयत्न किए जायें ।
५. उच्च शिक्षा के लिए प्रादेशिक भाषाओं के साथ एक या दो विषयों के लिए सघीय भाषा का भी माध्यम के रूप में प्रयोग हो सकता है ।

1. "..... the mother tongue is as natural for the development of the man's mind as the mother's milk is for the development of the infant's body."

६. राज्य सरकारें शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर मधीय भाषा के अध्यापन की व्यवस्था करें।

७. अंग्रेजी भाषा का अध्ययन छात्रों को करवाया जाय ताकि छात्र नवीन ज्ञान के सम्पर्क में रहें।

उपयुक्त मुद्दों का अध्ययन करने में पता चलता है कि आयोग में इस समस्या पर गहन विचार करने के बाद व्यावहारिक मुद्दाय दिया है। मधीय भाषा का सभी प्रदेशों में अनिवार्य रूप से अध्ययन कराने का मुद्दाव राजकीय कार्य सफल बनाने, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करने की दृष्टि से अत्यधिक उपयुक्त है। देश में बंगाल-निक ज्ञान की प्रगति के लिए अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कराने का मुद्दाव वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल है। इसके साथ ही इस नवोदित राष्ट्र को अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने तथा विश्व के अन्य देशों से सम्पर्क बनाये रखने के लिए अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना आवश्यक है।

### माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुद्दाव

सन् १९५२-५३ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भाषा समस्या पर विचार करने के बाद इसके समाधान के लिए मुद्दाव दिये। आयोग ने द्विभाषा सूचन का प्रतिपादन किया।

१. माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों की मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में भिन्न हो तो वहाँ उस भाषा के ४० विद्यार्थी होने पर उन विद्यार्थियों की मातृभाषा के माध्यम में ही शिक्षा की व्यवस्था हो।
२. मिश्रित शूल स्तर पर प्रत्येक छात्र को कम से कम दो भाषाएँ सिखाई जायें। अंग्रेजी तथा हिन्दी की शिक्षा क्रमिक स्तर के बाद दी जाय, परन्तु दोनों भाषाओं का अध्ययन एक साथ न हो।
३. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र कम से कम दो भाषाओं का अध्ययन करे। इनमें से एक भाषा तो छात्र को प्रादेशिक भाषा होगी और दूसरी भाषा का चुनाव वह निम्नलिखित भाषा समूह में से करेगा :
  - (अ) हिन्दी (अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में)।
  - (आ) प्राथमिक अंग्रेजी (जिन्होंने पूर्व-माध्यमिक स्तर पर अध्ययन नहीं किया था)।
  - (इ) उच्च अंग्रेजी (जिन्होंने पूर्व-माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन किया है)।
  - (ई) एक आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी के अतिरिक्त)।
  - (उ) एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी के अतिरिक्त)।
  - (ऊ) एक शास्त्रीय भाषा।



आयोग के सुझावों का आलोचनात्मक अध्ययन—भाष्यमिक शिक्षा भाषा सम्बन्धी सुझावों का अध्ययन करने में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भाषा अधिक व्यावहारिक नहीं है। इस प्रकार भाषाओं का अध्ययन अहिन्दी भाषी प्रदेशों के छात्रों को किसी एक महत्वपूर्ण भाषा के अध्ययन रहना पड़ेगा। अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अगर वह दूसरे समूह में अध्ययन करना है तो वह मधीय भाषा के अध्ययन करने में अधिक परिणामस्वरूप, वह मधीय भाषाओं में नियुक्ति नहीं पा सकता है और न कामों में भाग ले सकता है। इसी प्रकार यदि वह मधीय भाषा का चुन ले तो उसे एक प्रमुख विदेशी भाषा छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल अधिक उपयुक्त नहीं है।

आयोग का अल्प-संख्यकों के सम्बन्ध में सुझाव भी अस्वीकार्य है। अगर किसी विधानसभा में ४० या उससे अधिक छात्र ऐसे हैं जो मातृभाषा के माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अध्यापक प्राप्त कठिन कार्य होगा। वैसे आयोग ने जनतन्त्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों में रूढ़ि हुए इस प्रकार का सुझाव दिया है।

### केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् का सुझाव

त्रिभाषा मूल की 'उपयुक्त' कमियों के कारण इसके स्थान पर प्रतिपादित किया गया। मई १९५६ में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने भाषा के प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोजित हुई। इस त्रिभाषा मूल स्वीकार किया गया। त्रिभाषा मूल के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र अपनी मातृभाषा का अध्ययन करना होगा। ये तीन भाषाएँ इस मूल के अनुसार होंगी।

भाष्य—१. प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम या क्षेत्रीय भाषा होगी।

भाष्य—२. भाषाओं के तीन वर्ग बनाये गये हैं। प्रत्येक वर्ग को एक-एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक छात्र को अपनी मातृभाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होगा।

वर्ग १—(क) मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा का सहित पाठ्यक्रम  
(ख) मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का सहित पाठ्यक्रम  
(ग) क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का सहित पाठ्यक्रम

वर्ग २—(क) अंग्रेजी भाषा, अथवा  
(ख) अन्य कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा।

वर्ग ३—(क) हिन्दी (अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए) अथवा  
(ख) अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए)।

**त्रिभाषा सूत्र की आलोचना : गुण—**आज भी अनेक भारतीय नेता तथा शिक्षा-वाक्ता त्रिभाषा सूत्र को ही भारत में भाषा समस्या का उत्तम समाधान मानते हैं। इस सूत्र के द्वारा द्विभाषा सूत्र की कमियाँ को दूर कर दिया गया है। अहिन्दी भाषी प्रदेश के छात्रों की कठिनाई इस सूत्र ने दूर कर दी है। द्विभाषी सूत्र के अनुसार अहिन्दी भाषी प्रदेश के छात्र हिन्दी लेने पर अंग्रेजी के तथा अंग्रेजी लेने पर हिन्दी के अध्ययन में वंचित रह जाते हैं परन्तु त्रिभाषा सूत्र की सहायता से छात्र अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को सीखने के साथ संघीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन कर सकेगा। इस प्रकार वह केन्द्रीय सेवाओं में स्थान पाने का अधिकारी भी हो जायेगा और अन्तरराष्ट्रीय कार्यों में भी भाग ले सकेगा।

**दोष—**द्विभाषा सूत्र की भाँति त्रिभाषा सूत्र भी कमियों में भुक्त नहीं है। इस सूत्र को प्रयोग में लाने पर अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं

(१) अध्ययन-भार अधिक होना—मुद्रालियर आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पाठ्यक्रम के विषयों को दो भागों में विभाजित किया है एक सौ अनिवार्य विषय जैसे सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान और एक हस्त उद्योग जिनका अध्ययन प्रत्येक छात्र को करना होगा। दूसरे वैकल्पिक विषय जिसके लिए आयोग ने ७ वर्गों—का निर्माण किया है। इनमें से छात्र एक वर्ग का चुनाव करेगा और इस चुने हुए वर्ग में से उसको तीन विषयों का चयन करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक छात्र ६ विषयों का अध्ययन करेगा। इन ६ विषयों के अनिश्चित वह तीन भाषाओं का अध्ययन भी अनिवार्य रूप में करेगा। माध्यमिक स्तर पर ६ विषयों का अध्ययन छात्र के लिए अधिक भार-स्वरूप हो जायेगा।

(२) शिक्षा-स्तर का गिरना—कुछ शिक्षा-वाक्ताओं का मत है कि छात्र को इन भाषाओं के सीखने में अधिक समय एवं शक्ति लगानी होगी। परिणामस्वरूप, वह अन्य विषयों के सीखने में पर्याप्त समय नहीं दे सकेगा। इस प्रकार वह अन्य विषयों में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकने में असमर्थ रहेगा। यह मोक्षना भूल है कि विषयों की संख्या मात्र बढ़ाने में ही शिक्षा का स्तर ऊँचा हो जायेगा।

(३) अधिकांश छात्रों के लिए अंग्रेजी का अध्ययन ध्येय—मुद्रालियर आयोग ने लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूर्ण होनी चाहिए क्योंकि अधिकांश छात्र उच्च स्तर के उच्च शिक्षा समाप्त कर देते हैं और जीविकोपार्जन की तैयारी करते हैं। छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं है। न तो इस स्तर तक उनको इस भाषा का इतना ज्ञान होता है कि वे इस अंग्रेजी की पुस्तक पढ़कर ज्ञान-वृद्धि कर सकें और न जीविकोपार्जन उनका कोई उपयोग होता है।

(४) हिन्दी भाषी प्रान्तों में अहिन्दी क्षेत्रों को भाषा का आलोचकों का मन है कि जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया अहिन्दी क्षेत्रों में इसका अध्ययन अनिवार्य है तो हिन्दी प्रदेश का क्या भाषा के माध्यम में विचार-विमर्श कर सकता है, फिर उसके लिए आ भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप में क्यों रखा जाय ? अहिन्दी क्षेत्र अध्ययन की उपयोगिता हिन्दी क्षेत्र के लिए मूल्य ही रहेगी ।

(५) हिन्दी भाषी प्रान्तों में अन्य १४ भाषाओं के अध्यापन में कठिनाइयाँ—सविधान के अनुसार भारत की १४ भाषाओं को मान्य हिन्दी प्रान्तों में इन भाषाओं के अध्यापन कार्य में सम्बन्धित कुछ कठिनाइयाँ अनुभव की जाती हैं जो कि निम्नलिखित हैं

(अ) किस भाषा का अध्ययन—हिन्दी प्रान्तों के विद्यालयों में यह अनुभव की जाती है कि भारत की अन्य १४ भाषाओं में से अध्यापन की व्यवस्था की जाय ? एक विद्यालय में समस्त भाषाओं करना असम्भव सा प्रतीत होता है जबकि सभी भाषाएँ समान महत्त्व किन्ती एक का चुनाव करना दुष्कर कार्य है ।

(आ) अध्यापकों का अभाव—यदि अहिन्दी भाषी प्रान्तों की अध्यापन आरम्भ कर दिया जाय तो एक समस्या विभिन्न भाषाओं की प्राप्ति में सम्बन्धित होगी । प्रथम तौर पर इन अध्यापकों को अपनी भाषा साथ हिन्दी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए । बिना हिन्दी भाषा का ये अध्यापक न तो छात्रों को अपनी भाषा समझा सकते हैं और न करके उनकी कठिनाइयों का पता लगा सकते हैं । लगभग एक-एक १५ हजार तक अध्यापकों की संख्या की आँका गया है । क्या प्रत्येक इनके अध्यापकों को पाना सम्भव होगा ?

(इ) धन की कमी—अन्य भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति शिक्षा व्यय में वृद्धि अवश्य होगी । धनाभाव के कारण वैसे ही अनेक जगह से पूरे नहीं हो सके हैं । राज्य सरकारें इन पड़े हुए व्यय के आर्थिक सहायता न दे सकेंगी ।

(ई) एक साला में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षण की भी असम्भव सा है । मान लो प्रत्येक कक्षा में छात्रों द्वारा ५ या ६ क्षेत्रों को पढ़ने की इच्छा प्रकट की गई है तो एक घण्टे में इन सभी भाषाओं की व्यवस्था समय चक्र में करना एक कठिन कार्य है ।

आलोचना का एक विषय यह है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के १४ क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन कराने की क्या व्यावहारिक उपयोगिता इस प्रश्न पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो इस निष्कर्ष पर

भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थितियों में अहिन्दी भाषी क्षेत्र की भाषाओं का अध्ययन हिन्दी भाषी क्षेत्र के बच्चा के लिए उपयुक्त रहेगा। जान देना कि भाषा-भेद भक्तता का विनाश करने के लिए ऐसा करना उपयुक्त है। अहिन्दी क्षेत्र के व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उन पर हिन्दी भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा या रहा है। यही विचार उनमें हिन्दो के प्रति घृणा भाव पैदा कर देता है। अगर हम उनकी भाषा का अध्ययन करेंगे तो परस्पर प्रेमभाव बढ़ेगा। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन करने में उनके माहित्य का ज्ञान होगा और हम ज्ञान के आधार पर हम अपनी भाषा के माहित्य में वृद्धि कर सकेंगे। हमारे साथ ही भाषा का भार समान करने की दृष्टि में भी त्रिभाषा मूल उपयुक्त है।

### भाषात्मक एकता समिति का मुद्दा

सन् १९६१ में डा० मधुसूदनमूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण हुआ जिसका देश में भाषात्मक एकता स्थापित करने सम्बन्धी मुद्दा देने का कार्य दिया गया। इस समिति ने इस चीज को स्वीकार किया कि देश में भाषात्मक एकता स्थापित करने में शिक्षा अधिक महयोग दे सकती है। इस समिति ने भारत-वासियों में जाग्रत किया कि वे भाषा विवाद को अधिक उग्र रूप न दें। भाषा-समस्या का समाधान करने के लिए इस समिति ने त्रिभाषा मूल को ही स्वीकार किया। इस समिति ने त्रिभाषा मूल को लागू करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मुद्दा दिए

(१) हिन्दी, अंग्रेजी दोनों का अध्ययन—इस समिति ने विचार व्यक्त किया कि देश के विभिन्न प्रांतों में त्रिभाषा मूल को चलन रूप में अपनाया जा रहा है। कुछ प्रांत तो त्रिभाषा मूल की जाड़ में द्विभाषा मूल को ही अपना रहे हैं। भाषात्मक एकता समिति ने मुद्दा दिया कि त्रिभाषा मूल के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के बाद छात्रों को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप में करवाया जाय।

(२) हिन्दी भाषी प्रदेशों के निवासी दक्षिण भारत की भाषा सीखें—इस समिति ने एक मुद्दा यह दिया कि हिन्दी भाषी प्रदेश के निवासियों को दक्षिण भारत की भाषाओं का अध्ययन करवाया जाय। ऐसा करने में हिन्दी भाषी लोग दक्षिण भारत की भाषा ही नहीं सीखेंगे परन्तु दक्षिण भारत के निवासियों के प्रति प्रेम की भावना भी रखेंगे।

(३) क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने के प्रयत्न—भाषात्मक एकता समिति ने मुद्दा दिया कि प्रादेशिक भाषाओं के शब्द कोष को बढ़ाया जाय जिनमें ये उच्च शिक्षा का माध्यम बन सकें। इसके लिए अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाय। इस अनुसंधान कार्य के लिए ज्वलित भारतीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

(४) विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी ही माध्यम—जब तक क्षेत्रीय भाषाएँ उच्च शिक्षा का माध्यम बनने के योग्य न हो जायें, उम समय तक अंग्रेजी को ही विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाये रखा जाए।

(५) अन्य सुझाव—(अ) हिन्दी भाषा के घट्टे का परिचय अहिन्दी भाषी लोगों को करवाने के लिए इस अन्तरिम समय में रोमन लिपि प्रयोग में लाई जा सकती है।

(आ) हिन्दी की पुस्तकें रोमन लिपि में प्रकाशित की जायें।

(इ) अन्तरराष्ट्रीय साहित्यिको को सम्पूर्ण देश में प्रयोग में लाया जाए।

(६) देश में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अन्तर-प्रादेशिक एवं अन्तर-विश्वविद्यालय सम्बन्ध बनाने की भी अधिक आवश्यकता है। इस कार्य को सम्भव बनाने के लिए अंग्रेजी तथा हिन्दी के पढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

आलोचना—भाषात्मक एकता समिति द्वारा दिये गये कुछ सुझाव जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल हैं परन्तु कुछ सुझाव व्यावहारिक में प्रतीत होते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि हिन्दी भाषी प्रदेश के निवासियों को दक्षिण भारत की भाषाओं का अध्ययन कराने में क्या लाभ है, जब दक्षिण भारत के निवासी हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं तो यही सम्पर्क भाषा हो सकती है। हिन्दी भाषा की पुस्तकें रोमन लिपि में प्रकाशित करना भी उपयोगी नहीं है। ऐसा करने में समय तथा धन का अपव्यय करना मात्र ही है। जब तक छात्र देवनागरी लिपि नहीं सीखेंगे, उनको हिन्दी भाषा का लाभप्रद ज्ञान नहीं हो सकता है।

राष्ट्रीय एकता परिषद्—धीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद् का निर्माण किया गया। इस परिषद् ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि राष्ट्रीय एकता के विकास में एक राष्ट्रभाषा अधिक सहयोग दे सकती है। इस परिषद् ने भी त्रिभाषा सूत्र को ही स्वीकार किया। परिषद् ने स्वीकार किया कि हिन्दी ही सम्पर्क भाषा है और अन्तर-प्रादेशिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए हिन्दी का अध्ययन सभी प्रदेशों में अनिवार्य बनाया जाए।

### कोठारी आयोग के सुझाव

श्री दीनदत्तसिंह कोठारी की अध्यक्षता में २ अक्टूबर सन् १९६४ को शिक्षा आयोग ने कार्य आरम्भ किया। इस आयोग ने देश भर का भ्रमण किया तथा समाज के विभिन्न वर्गों के ६०० व्यक्तियों से शिक्षा समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। शिक्षा आयोग ने भाषा-समस्या के समाधान के लिए भी कुछ सुझाव दिये जो कि निम्नलिखित हैं।

(१) भाषा शिक्षण के सम्बन्ध में नई भाषा नीति विकसित की जाय। यह भाषा नीति सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता में अधिक सहयोग दे सकती है। शैक्षिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से भी इस समस्या का समाधान आवश्यक है।



(४) विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी हो माध्यम—उप तक क्षेत्रीय भाषाएँ शिक्षा का माध्यम बनने के योग्य न हो जायें, उस समय तक अंग्रेजी को ही विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाये रखा जाए।

(५) अन्य सुझाव—(अ) हिन्दी भाषा के धर्मों का परिचय अहिन्दी भाषीों को करवाने के लिए इस अन्तरिम समय में रोमन लिपि प्रयोग में लाई जा ती है।

(आ) हिन्दी की पुस्तकें रोमन लिपि में प्रकाशित की जायें।

(इ) अन्तरराष्ट्रीय साहित्यिकी को सम्पूर्ण देश में प्रयोग में लाया जाए।

(६) देश में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अन्तर-प्रादेशिक एवं अन्तर-विश्वविद्यालय सम्बन्ध बनाने की भी अधिक आवश्यकता है। इस कार्य को सम्भवाने के लिए अंग्रेजी तथा हिन्दी के पढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

आलोचना—भाषात्मक एकता समिति द्वारा दिये गये कुछ सुझाव तो मान परिस्थितियों के अनुकूल हैं परन्तु कुछ सुझाव अभ्यावहारिक में प्रवीण होते। कुछ विद्वानों का मन है कि हिन्दी भाषी प्रदेश के निवासियों को दक्षिण भारत भाषाओं का अध्ययन कराने से बड़ा लाभ है, जब दक्षिण भारत के निवासीन्दी का अध्ययन कर रहे हैं तो यही सम्पर्क भाषा हो सकती है। हिन्दी भाषा की तर्क रोमन लिपि में प्रकाशित करना भी उपयोगी नहीं है। ऐसा करने से समय साधन का अपव्यय करना मात्र ही है। जब तक छात्र देवनागरी लिपि नहीं खेंगे, उनको हिन्दी भाषा का लाभप्रद ज्ञान नहीं हो सकता है।

राष्ट्रीय एकता परिपद—श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कता परिपद का निर्माण किया गया। इस परिपद ने इस तथ्य को स्वीकार किया। राष्ट्रीय एकता के विकास में एक राष्ट्रभाषा अधिक सहयोग दे सकती है। इस परिपद ने भी विभाषा सूत्र को ही स्वीकार किया। परिपद ने स्वीकार किया किन्ही ही सम्पर्क भाषा है और अन्तर-प्रादेशिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए हिन्दी। अध्ययन सभी प्रदेशों में अनिवार्य बनाया जाए।

तेडारी आयोग के सुझाव

श्री दौनतसिंह तौडारी की अध्यक्षता में २ अक्टूबर सन् १९६४ को शिक्षा ायोग ने कार्य आरम्भ किया। इन आयोग ने देश भर का भ्रमण किया तथा मान के विभिन्न वर्गों के १०० व्यक्तियों से शिक्षा समस्याओं पर विचार-विमर्श र्था। शिक्षा आयोग ने भाषा-समस्या के समाधान के लिए भी कुछ सुझाव दिये हैं कि निम्नलिखित हैं

(१) भाषा मिश्रण के सम्बन्ध में नई भाषा नीति विकसित की जाय। यह तथा नीति सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता में अधिक सहयोग दे सकती है। संक्षिप्त, ास्तविक और राजनीतिक कारणों से भी इस समस्या का समाधान आवश्यक है।

(२) व्यावहारिक त्रिभाषा-मूल के आधार—त्रिभाषा-मूल का मतान्वित निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए।

(क) हिन्दी सघीय भाषा होने के कारण मातृभाषा के बाद द्वितीय महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है।

(ग) अंग्रेजी का व्यावहारिक ज्ञान छात्रों के लिए उपयोगी होगा।

(ग) भाषा में प्रवीणता व्यापक तथा मीगने की अवधि पर निर्भर करती है।

(घ) तीन भाषाओं में मीगने के लिए उपयुक्त स्तर निम्न प्राथमिक (कक्षा ८-१०) है।

(ङ) दो अनिरीक्त भाषाओं पढ़ाई जाये।

(च) हिन्दी या अंग्रेजी उस समय लागू की जाये जब उनकी आवश्यकता का अधिकतम प्रेरणा हो।

(छ) किसी भी स्तर पर ४ भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य न किया जाय।

(३) उपर्युक्त सिद्धान्तों पर संशोधित त्रिभाषा-मूल निम्न प्रकार होगा -

(अ) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा,

(आ) सघीय सरकार की सरकारी या सह-सरकारी भाषा (जब तक चले)

और

(इ) एक आधुनिक भारतीय या योरोपीय भाषा जोकि (अ) या (आ) के न आई हो और शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग में आने वाली भाषा के अनिरीक्त हो।

(४) (अ) निम्न प्राथमिक स्तर पर एक भाषा का अध्ययन हो—मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो।

(आ) उच्च प्राथमिक स्तर पर दो भाषाओं का अध्ययन हो—मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा) और सघ सरकार की राजकीय भाषा (या सहयोगी भाषा)।

(इ) निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्र को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा—मातृभाषा (या क्षेत्रीय भाषा), राजकीय या सहयोगी भाषा; और एक आधुनिक भारतीय भाषा।

(ई) हायर सेकेंडरी स्तर पर दो भाषाओं अनिवार्य होंगी।

५) अंग्रेजी भाषा के अनिरीक्त आधुनिक पुस्तकालयी भाषाओं का अध्ययन यों में करवाया जाय।

हिन्दी या अंग्रेजी को सरकारी तथा सह-सरकारी भाषा के रूप में सर्व तक पढ़ाया जाना चाहिए।

(६) उच्च शिक्षा में भाषा का अध्ययन अनिवार्य न हो।



(८) हिन्दी के प्रचार के लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाया जाये परन्तु अनिच्छुक व्यक्तियों पर इसका अध्ययन थोपा न जाये।

(९) प्रत्येक आधुनिक भारतीय भाषा का साहित्य देवनागरी तथा रोमन लिपि में प्रकाशित किया जाए। सभी भारतीय भाषाओं को अन्तरराष्ट्रीय अंक अपनाने चाहिए।

(१०) कक्षा ५ से पूर्व अंग्रेजी भाषा का अध्ययन प्रारम्भ न किया जाए।

(११) शास्त्रीय भाषा, उदाहरण के लिए संस्कृत, अरबी आदि का अध्ययन नवी कक्षा में विकल्प भाषा के रूप में लागू किया जाये।

### विभिन्न भाषाओं का महत्त्व

अंग्रेजी भाषा—भारतीय शिक्षा के इतिहास को देखने में स्पष्ट होगा कि लगभग १०० वर्षों में अधिक समय तक शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का एकाधिकार सा रहा है। स्वतन्त्रता के बाद अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न चल रहे हैं परन्तु अनेक भारतीयों का यह मत है कि भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन भारतवासियों के लिए आवश्यक है। अंग्रेजी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं।

- (अ) अंग्रेजी का अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व अधिक है। विश्व में यह सभी स्थानों पर बोली तथा समझी जाती है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने में इस भाषा का सक्रिय सहयोग रहा है। आज अंग्रेजी विश्व एकता स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण सहयोग दे रही है।
- (आ) अंग्रेजी भाषा का साहित्य सम्पन्न, विशाल और बहुमुखी है। इसके प्रभाव में भारतीय भाषाओं के विकास में सहयोग मिलेगा।
- (इ) अंग्रेजी भाषा का प्रकाशित साहित्य विश्व की अन्य किसी भी भाषा में अधिक है।
- (ई) विज्ञान तथा तकनीकी साहित्य अंग्रेजी भाषा में ही अधिक है। इस क्षेत्र में भारतवर्ष को अभी अधिक प्रगति करनी है। ऐसी दशा में, प्राथमिक ज्ञान के लिए हमें अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए।
- (उ) कुछ भारतवासियों का विचार है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता की केतना उत्पन्न करने वाली भाषा अंग्रेजी ही है। इस राष्ट्रीय एकता में ही भारतवासियों में यह भावना पैदा की कि सभी को मिलकर अंग्रेजी प्रणामन को उखाड़ फेंकने के प्रयत्न करने चाहिए।
- (ऊ) अंग्रेजी भाषा के साहित्य की लोकप्रियता विश्व में अन्य किसी भाषा से अधिक है।

मन् १९५३ की २३, २४ जनवरी को माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी का स्थान निश्चित करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन ने निम्नलिखित मस्तुतियाँ दी थी :

- १ माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए।
- २ इस स्तर पर भाषा का उद्देश्य अच्छा काम-बलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही होना चाहिए।
- ३ यदि कोई छात्र अंग्रेजी भाषा का अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसे अलग में पढ़ाने की सुविधा दी जाये।
- ४ माध्यमिक स्तर पर छः वर्षों तक अनिवार्य रूप में अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाय।

अंग्रेजी भाषा का विरोध—अंग्रेजी भाषा के अध्ययन में देश को लाभ-हानि दोनों हुई हैं। इसके अध्ययन के फलस्वरूप होने वाली हानियों के कारण ही अनेक भारतवासी अंग्रेजी का विरोध करने लगे। उनके विरोध के आधार निम्नलिखित हैं :

- १ अंग्रेजी भाषा ने शिक्षित तथा अधिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के मध्य गहरी खाई पैदा कर दी है।
- २ अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम में अनुचित महत्व देने में मातृभाषा तथा प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन की उपेक्षा की जाने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी यह अंग्रेजी पढ़ा-लिखा वर्ग सामान्य जनो को पैरो तले रौंद रहा है। यही लोग अपनी स्थिति मृदु बनाए रखने के लिए असह्य जनो को दबाये रखना चाहते हैं।
- ३ अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप में करवाने के कारण भारतवासियों में अभी भी दागता की मनोवृत्ति पैदा होती है।
- ४ अनेक छात्रों में भाषा का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता कम होती है। वे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? ऐसे छात्रों के लिए उपरान्त करना असम्भव हो जायेगा, अगर उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य बना दिया जाय।
- ५ अंग्रेजी भाषा में ही माध्यमिक स्तर पर छात्र अधिक मस्या में अनुक्षीण होत हैं जिनमें भारी दार्शनिक-अपभ्रम होता है।
- ६ अंग्रेजी भाषा को अनुचित महत्व देने में अनेक भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में जर्मनी, रूस, जापान आदि देश भी बिना अपना

महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनमें भी तकनीकी ज्ञान मोलने के लिए उनकी भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है।

श्री हुमायूँ कबीर ने अपनी पुस्तक 'स्वतन्त्र भारत में शिक्षा' में भारतीयों के लिए अंग्रेजी भाषा के महत्त्व पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उनका कथन है कि अधिकांश भारतीयों को अविष्य में अंग्रेजी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोग अंग्रेजी के द्वारा आने वाले प्रभावों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से ग्रहण कर सकेंगे क्योंकि निकट अविष्य में सोचे अनुवादों या अप्रत्यक्ष रूप में उन प्रभावों को ग्रहण करना सम्भव होगा। भारतीयों का एक वर्ष ऐसा होगा जहाँ अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग आदि के लिए अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक समझेगा। इन लोगों को काम-बलाऊ अंग्रेजी सिखाने की आवश्यकता होगी।

अंग्रेजी भाषा का स्थान—उपरोक्त विवेचन में स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन प्रारम्भ किया जाय परन्तु इसको पहले जैसा गौरवपूर्ण स्थान नहीं दिया जाय। अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके इसको पढ़ाने के लिए जो घण्टे माध्यमिक विद्यालयों में लगाये जाते हैं, उनमें कमी होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को केवल भाषा का अध्ययन सिखाया जाय जिसमें छात्र बोलचाल तथा व्यवहार की भाषा में निपुण हो जाएँ। अंग्रेजी के स्तर को गिराने में बचाने के लिए इसको पढ़ाने के लिए प्रयास में आने वाली विधियों में परिवर्तन होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के महत्त्व को कम करने के लिए यह भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाया जाय। इसके साथ ही माध्यमिक स्तर को अपने में पूर्ण इकाई बनाया जाय ताकि अनेक छात्र इस शिक्षा को प्राप्त करके स्वावलम्बी बन सकें, वे किसी व्यवसाय में प्रवेश कर सकें और इस प्रकार उन्हें विश्वविद्यालय में अनावश्यक रूप में जाने से रोका जा सके।

हिन्दी का अध्ययन—भारतवर्ष में हिन्दी भाषा का अध्ययन बहुत पहले से हो रहा है परन्तु मुस्लिम काल में हिन्दी की प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि इस युग में उर्दू-फारसी को महत्त्व प्राप्त हो गया। इसके बाद अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का पद प्राप्त हुआ। हिन्दी भाषा की अवहेलना होती रही परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलनों के काल में लोगों ने यह सत्य समझा कि हिन्दी राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण कर सकती है। स्वतन्त्रता के बाद तो सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता और भी अधिक अनुभव की जाने लगी। सम्पूर्ण देश के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों में है।

1. पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश में औद्योगिक विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। इन उद्योगों में कार्य करने के लिए देश के विभिन्न



आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जिन लोगों ने सन् १९४७ में हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने के पक्ष में मत दिया था, वे ही अब इसका विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजों के पक्षपाती स्वार्थवश तथा राजनीतिक कारणों से हिन्दी का विरोध करने हैं। इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं के प्रेमियों की ओर से भी हिन्दी का विरोध किया जाता है क्योंकि उनको आशंका है कि हिन्दी के स्वरूप में उनकी मातृभाषा नष्ट न हो जाय। अब तो हिन्दी विरोधी लोग संविधान में परिवर्तन लाने की बात सोचते हैं। इसका कारण यह है कि इन लोगों को हिन्दी की सर्वमानिक स्थिति के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार को अपने निर्णयों का कार्यान्वित करने के लिए तत्कालपूर्ण कदम उठाने चाहिए।

### प्रादेशिक भाषाओं का स्थान

भारतीय विद्यालयों में अन्य भारतीय भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था होना परम आवश्यक है। भारतीय भाषाओं के अध्ययन में सभी भाषाएँ समृद्ध होंगी। प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा में स्थान देने के लिए सन् १९५६ में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा मिडान्त अपनाने पर जोर दिया परन्तु कुछ लोग इस सिद्धान्त का विरोध करते हुए कहते हैं कि हिन्दी-भाषी क्षेत्र में एक प्रादेशिक भाषा पढ़ने का बाँझ कपो डाला जाये। परन्तु भारत भर में सबको तीन भाषाएँ पढ़ना अनिवार्य होने में मनुगुन रहता है और किसी को ईर्ष्या या चिन्तित का अवसर नहीं मिलता है। त्रिभाषा-मूत्र को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में पहले से नियुक्त भाषा के अध्यापक को भारतीय भाषाएँ पढ़ाई जाएँ। सरकार की ओर से उनकी प्रोत्साहन मिले तथा नगरी में माववालीन या प्रातःकालीन संस्थाएँ स्थापित की जाएँ जिनमें सभी भाषाओं का शिक्षण होता हो।

### अन्य देशों के उदाहरण

भाषा के सम्बन्ध जो समस्या आज हमारे देश के सामने है, वही ही समस्या अन्य देशों के सामने भी आई है। उन्होंने जिन प्रकार इस समस्या का समाधान किया है, उनमें हम भी कुछ लाभ उठा सकते हैं। अब उनका अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि अन्य देशों के अध्ययन से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उनका उदाहरण हम उभी रूप में स्वीकार कर लें। प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं और समस्याओं का समाधान उनको ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

### १. स्विट्जरलैण्ड

यह एक छोटा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग ५० लाख है। इस देश में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है परन्तु यहाँ की एक विशेषता रही है कि अधिक भाषाएँ होते हुए भी यहाँ पर कभी भाषा के ऊपर झगड़े नहीं हुए हैं। सर्वप्रथम डारा



(१) वर्णमाला या व्याकरण रहित भाषाओं को वर्णमाला तथा व्याकरण दिया ।

(२) जिन भाषाओं को वर्णमाना कठिन तथा जर्जस्तानिक थी, उनको सही लिपि देकर सुधारा ।

इस देश में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ रहती हैं । यहाँ माध्यमिक स्तर पर एक विदेशी भाषा का अनिवार्य कर दिया गया है । अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इटलियन तथा स्पेनिश भाषाएँ वे मुख्य विदेशी भाषाएँ हैं जिनकी शिक्षा रूस में देने की व्यवस्था है । इस प्रकार रूस में प्रत्येक छात्र को तीन भाषाएँ पढ़नी पड़ती हैं

(अ) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, (आ) रशियन भाषा, (इ) एक विदेशी भाषा । इससे स्पष्ट है कि रूस में भी त्रिभाषा मूल ही प्रचलित है । भारत तथा रूस की परिस्थितियाँ लगभग समान हैं । रूस की भाँति हमारे देश में भी क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य किया जाय । रूस में जिन प्रकार त्रिभाषा मूल सफलतापूर्वक चल रहा है उसी प्रकार भारतवर्ष में भी त्रिभाषा मूल को कार्यान्वित किया जाय ।

(३) जर्मनी—जर्मन देश दो भागों में विभाजित है । जर्मनी के इन दोनों भागों में प्रत्येक छात्र को जर्मनी भाषा का अध्ययन मातृभाषा के रूप में अनिवार्य करना होता है । इसके अनतिरिक्त प्रत्येक छात्र एक विदेशी भाषा का अध्ययन करता है । जर्मनी के किसी भाग में अंग्रेजी, किसी में रशियन तथा कहीं पर फ्रेंच भाषा की पढ़ाई प्रचलित है । यहाँ पर १० वर्ष की आयु से प्रत्येक छात्र को विदेशी भाषा सीखनी होती है ।

### राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

- Express your views on the Language problem in India. How far can we benefit ourselves from the way other countries have solved their problem ? (1962)
- How many languages should be taught compulsorily at the Secondary School level ? Which languages should these be ? What is the place of English among them ? What should be the place of Hindi in (a) Madras (b) U. P ? (1963)
- Write short notes on—  
(b) The Third language—a political artifice or an educational need ? (1964)

४. बर्तमान में पटन किन नव विभागा मुख क मासिक मर्यादा कया बिचार ?  
 यह बागविरा एवायक कय म किन प्रकार बन ग्या हे ? अन्तर म दूक  
 कय मने गीया एव म परिचर्जन क बिग अरु कया मुखर हे ? (१९९६)
५. कम मने बिग अन्तर म बहुभाषियता की मासिक मर्यादा किन प्रकार  
 बिधा ग्या ? भारतीय अन्त मन्त्रक, विदेशक अन्त म बागविरा की मासिक  
 मासिक म दूभाषी भाषा-बिग कया हानि बाहिग ? (१९९७)
६. भाषा की मासिक म मासिक म बागविरा अन्त म मुखर कया गद ग्या हे ?  
 और मर्यादिक मासिक (Constitutional obligation) क अरु हे ?  
 (१९९८)



## अध्याय १२

### पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

सिधा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्पुल्लित विकास करना है ताकि यह स्वयं के तथा समाज के लिए उपयोगी हो सके। मनुष्य समाज का एक सदस्य है अतः उसमें आशा की जाती है कि वह समाज के विकास में सश्रिय सहयोग दे। मनुष्य को अपना तथा समाज का विकास करने के लिए आवश्यक है कि वह उस परिवेश का समझें जिसमें वह निवास करता है। परिवेश का प्रभाव मनुष्य के ज्ञान-मान, रहन-सहन तथा वस्त्रों पर पड़ता है। यहाँ तक कि उसके विचार एवं दृष्टिकोण भी परिवेश के प्रतिफल होते हैं। मनुष्य में बौद्धिक शक्ति एक ऐसी ईश्वरीय देन है कि इसके कारण ही मानव अपने वातावरण का समझ वाला है और वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करके स्वयं का आनन्दप्रद समायोजन करता है। अनेक वर्षों तक विद्वानों का विचार रहा कि मनुष्य वातावरण का दास होता है। उसको स्वयं वातावरण के अनुकूल बनना होता है परन्तु अपने बौद्धिक ज्ञान के कारण मानव ने आज ऐसे वैज्ञानिक साधनों का आविष्कार कर लिया है जिनके माध्यम से वह वातावरण को अपने अनुकूल बनाकर उस पर विजय प्राप्त करना चला आ रहा है। मनुष्य और वातावरण का संबंध तो आदिकाल से ही बना आ रहा है। परिणामस्वरूप, मानव प्राचीन काल से नवीन अनुभव अर्जित करता आया है। इस प्रकार अर्जित असीमित ज्ञान के भण्डार को स्मृति के आधार पर सुरक्षित रखकर जागे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाना अममभव कार्य था। इस ज्ञान को जागे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाना भी आवश्यक है जिससे वे अपना समय एवं शक्ति उसी ज्ञान के अर्जन में नष्ट न करें। मनुष्य इन वर्षों के अनुभवों की सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त विधि की आवश्यकता अनुभव कर रहा था। उसने लेखन कला की खोज की और फलतः पुस्तकों का आविर्भाव हुआ।

## पाठ्य-पुस्तकों का महत्त्व

आधुनिक काल में पाठ्य-पुस्तकों की उपयोगिता पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है। कुछ विषयों में तो पाठ्य-पुस्तक को शिक्षण विधि के रूप में प्रयोग करने हे। वैसे आधुनिक शिक्षा-दास्त्री पाठ्य-पुस्तकों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उच्च स्थान देने के पक्ष में नहीं है। उनके अनुसार अध्यापक को पाठ्य-पुस्तक पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे तो अध्यापन सामग्री माना प्रकार के साधनों में एकत्रित करके कक्षा में छात्रों को विभिन्न विधियों के द्वारा स्पष्ट करनी चाहिए। आधुनिक विचार-धारा के अनुसार पुस्तकें बातों को पढ़ाने में अध्यापक की केवल सहायता करती हैं। पाठ्य-पुस्तक शिक्षण में चाहे कितने ही दोष हों परन्तु इनका महत्त्व कम नहीं हो सकता है। अध्यापकों एवं छात्रों को पुस्तकों का प्रयोग जति बुद्धिमत्ता के साथ व वैज्ञानिक रूप में करना चाहिए। पाठ्य-पुस्तकों के निम्नलिखित लाभ हैं

(१) निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान—अध्यापक को पाठ्य-पुस्तक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पता सीधेता में लग जाता है। वह पाठ्य-पुस्तक में देखकर पता लगा सकता है कि किसी विषय में उसको कौन-कौनसे उपविषय पढ़ाने हैं? यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पाठ्य-पुस्तकें अध्यापक के सम्मुख पाठ्यक्रम का रेखाचित्र ही प्रस्तुत करती हैं। दोष कार्य तो अध्यापक को स्वयं करना होता है।

(२) पथ-प्रदर्शक के रूप में—पाठ्य-पुस्तक तो पथ-प्रदर्शक के रूप में होती हैं। ये अध्यापक को भटकने में बचाती हैं। पाठ्य-पुस्तक के बिना अध्यापक द्वारा कक्षा के छात्रों के ज्ञान के स्तर में ऊँचा ज्ञान देने की संभावना अधिक रहती है। इसके साथ ही पाठ्य-पुस्तकों से लिये गये तथ्यों का विकास करना तथा उनको स्पष्ट करना अध्यापकों का कार्य है।

(३) सुसम्बन्धित तथा क्रमबद्ध सूचनार्थ—पाठ्य-पुस्तक में तथ्य एवं सूचनार्थ सुसम्बन्धित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। वे विषय का स्पष्ट एवं पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती हैं।

(४) स्वाध्याय की प्रेरणा—छात्रों में स्व-अध्ययन की आदत का निर्माण करना अति आवश्यक है। अध्यापक गृह कार्य देकर तथा सन्दर्भ पुस्तकें बताकर छात्रों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। छोटे-छोटे बच्चों में स्व-अध्ययन की निर्माण पाठ्य-पुस्तकों की सहायता में होता है। छात्र घर पर अपनी को पढ़कर अध्ययन में रुचि लेते हैं। और इस प्रकार उनमें अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित होती है।

(५) पाठ दोहराने में सहायक—कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ पर पाठ्य-पुस्तकों की सहायता में दोहरा सकते हैं। परीक्षा के समय तो

श्री एन० जे० क्रोन बंक ने लिखा है—“पाठ्य-पुस्तक प्राचीन अन्तर्दृष्टि, रीति-रिवाज और तकनीक को भावी पीढ़ी तक पहुँचाने का माध्यम है।”

कम्बई सरकार द्वारा स्थापित पाठ्य-पुस्तक समिति ने इनके सम्बन्ध में निम्न-लिखित विचार प्रकट किये हैं—“एक श्रेष्ठ पाठ्य-पुस्तक छात्रों में ज्ञान के प्रति अनुराग का विकास करती है तथा वह शिक्षा के नव्य को भी पूरा करती है। पाठ्य-पुस्तक तो अध्यापक का एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा वह छात्रों की स्वाभाविक रुचियों का विकास करता है।”

पाठ्य-पुस्तकों का इतिहास—भारतवर्ष में पाठ्य-पुस्तकों का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुद्रण कला का विकास उस समय नहीं हुआ था। वैसे प्राचीन काल में ही मन्त्राज का सचित्र ज्ञान भावी सन्तति तक पहुँचाने के लिए भोजपत्र अथवा ताम्रपत्र प्रयोग में आने लगे हैं। इसके बाद कागज का निर्माण होने पर हस्तलिखित पुस्तकों का आविर्भाव हुआ। इनकी समस्या बहुत कम हुआ करती थी। अंग्रेजों के आगमन के बाद ही पाठ्य-पुस्तकों का नवीन ढंग में गठन प्रारम्भ हुआ। इनका प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा मुद्रण तथा प्रकाश हेतु मशीनों का आविष्कार का लेना था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दामन काल में सन् १८२४ में ‘कलकत्ता शिक्षा प्रेम’ का निर्माण किया गया तथा वेदकृत, अरबी, फारसी के ग्रन्थ प्रकाशित किये गये तथा यूरोप की अनेक विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें प्राच्य भाषाओं में अनुवाद कराकर प्रकाशित की गईं। सन् १८५४ में बुद्ध के धोषणा-पत्र में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए मुआव्द दिये गये परन्तु पुस्तकों को मुधारने के लिए कोई भिक्का-रिध नहीं की। सर्वप्रथम १८७३ में एक समिति द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के कलेक्टर में मुधार करने के लिए मुआव्द दिये गये किन्तु उन मुआव्दों को कार्यान्वित नहीं किया गया। सन् १८८२ के प्रथम भारतीय शिक्षा अध्यापक ने पाठ्य-पुस्तकों के क्षेत्र में न कोई अध्ययन किया और न उनके मुधार हेतु मुआव्द ही दिये। सन् १९१० के बाद भारतीय नेताओं ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारम्भ किया। परन्तु प्रारम्भ में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने की माँग की, पाठ्य-पुस्तकों की ओर ध्यान नहीं दिया। ढींध घास में भारतीय नेताओं को शिक्षा का विषय तो दिया परन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण ये पाठ्य-पुस्तकों में कोई मुधार न कर सके।

सन् १९३७ में प्रथम जाचार्य नरेश्वरदेव समिति ने पाठ्य-पुस्तकों के मुधार के लिए मुआव्द दिये। इस समिति के प्रमुख मुआव्द निम्नलिखित थे

१. शिक्षा की नवीन आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य-पुस्तकों में परिवर्तन कर उनको पुनः सम्पादित किया जाय।
२. राज्य सरकार द्वारा सम्पादकों का एक बोर्ड नियुक्त किया जाय।
३. यह बोर्ड ही नेत्रको से पुस्तकें निम्नवा कर उनके प्रकाशन की व्यवस्था करे।

जनवरी १९४३ में केन्द्रीय विज्ञान मन्त्रालय परिसर की आठवों बंठक में पाठ्य-पुस्तकों में परिष्कार के लिए विचार किया गया। इस परिषद के एक प्रमुख सदस्य श्री शिवाउद्दीन अहमद ने प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों में अनेक दोष बताये।

१. पाठ्य-पुस्तकों अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली नहीं लिखी जाती है। अतः उनमें विषय-वस्तु का प्रस्तुतीकरण वैज्ञानिक दृष्टि में तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं होता है।
२. पाठ्य-पुस्तकों को सीधे बदलने में निर्धन अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए नयी पाठ्य-पुस्तकें खरीदने में अधिक कठिनाई होती है।
३. प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों के कनेक्शन के मुद्धार हेतु प्रयत्न नहीं करने हैं। ये मापारण के अन्तर्गत पुस्तकें निम्नस्तर के अनेक शक्तिमान प्रभाव से पाठ्य-पुस्तकों को स्वीकृत करवा लेते हैं।

केन्द्रीय विज्ञान मन्त्रालय परिसर की इसी बंठक में पाठ्य-पुस्तकों के मुद्धार के एक महत्वपूर्ण मुद्दा दिया गया। उनमें से कुछ मुद्दा निम्नलिखित थे।

१. पुस्तकों को तीन वर्ष में पूर्व न बदला जाय।
  २. कम मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायें।
  ३. अच्छे प्रचलित पुस्तकों में पुस्तकें खरीदी जायें।
  ४. योग्य लेखकों को पुस्तक-लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
- मार्च १९४३ में द्वितीय आचार्य नरेन्द्रदेव समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। इस समिति ने भी पाठ्य-पुस्तकों की स्थिति का अध्ययन किया। इस समिति ने पुस्तकें बदलने के लिए ६ माह में भी कम समय दिया जाता है तथा पाठ्य-पुस्तकों का खर्च करने वाली समिति के सदस्यों को उस विषय का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। कुछ पुस्तकों में मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियाँ या तथ्य सम्बन्धी असुझियाँ पाई हैं। इनके साथ ही समिति ने पाठ्य-पुस्तकों को सीधे बदलने की ओर भी आकर्षित किया।

पाठ्य-पुस्तकों में मुद्धार हेतु समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये।

१. पाठ्य-पुस्तकों के स्वीकृत करने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय तथा प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों को ही उचित पाठ्य-पुस्तक चुनने सम्बन्धी स्वतंत्रता दी जाय।

२. एक बार स्वीकृत पाठ्य-पुस्तक को कम से कम ३ वर्ष तक न बदला जाय।
३. किसी विषय में कोई उपयुक्त पुस्तक न होने पर सरकार को पुस्तक व्यवस्था करनी चाहिए। पुस्तकें लिखने के लिए पर्याप्त समय जाय। उत्तम पुस्तक लिखने वालों को पारितोषिक दिये जायें। इन पुस्तकों का मुद्रण सरकार अपने हाथ में न ले।

सन् १९५२-५३ में ही माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन किया और प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों में व्याप्त दोषों की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस आयोग ने पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में लिखा है कि "हम पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन के प्रचलित स्तर में अत्यधिक असंतुष्ट हैं और हममें सीधे मुद्धार की आवश्यकता अनुभव करने हैं।" सन् १९५४ में फोर्ड फाउण्डेशन के अन्तर्गत एक अन्तरराष्ट्रीय दल ने भारतीय पाठ्य-पुस्तकों का निरीक्षण किया। इस दल ने प्रत्येक प्रान्त में अच्छी पाठ्य-पुस्तकों उपलब्ध कराने के लिए एक पाठ्य-पुस्तक समिति की स्थापना का सुझाव दिया। इस दल ने मताह्व दी कि सरकार पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन अपने हाथ में न ले। इसके स्थान पर उसको अनुसन्धान कार्य अधिक करवाना चाहिए तथा प्रकाशकों एवं लेखकों को पथ-प्रदर्शन करने के लिए उपयोगी नियम निर्धारित करने चाहिए।

सन् १९६६ में कोठारी आयोग ने भी पाठ्य-पुस्तकों के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दिये हैं। आयोग ने बताया कि विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले अनेक विषयों में निम्न स्तर की पाठ्य-पुस्तकें हैं। पाठ्य-पुस्तकों का निम्न स्तर होने के निम्नलिखित कारण हैं

१. उष्णकोटि के विद्वानों की पाठ्य-पुस्तकें लिखने में रस का कम होना। माधुर्य व्यक्तियों द्वारा ही पुस्तकें लिखी जाती हैं।
२. पाठ्य-पुस्तकों की स्वीकृति एवं चुनाव में ईमानदारी का अभाव।
३. पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण एवं उत्पादन में अनुसन्धान कार्य का अभाव।

कोठारी आयोग ने भी पाठ्य-पुस्तकों के मुद्धार के लिए सुझाव दिया जो कि निम्नलिखित हैं

राज्य पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन करे परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इस भारी उत्तरदायित्व के लिए शिक्षा विभाग को भली-भाँति सज्जित होना चाहिए।

पिछले वर्षों में विभिन्न आयोगों ने पाठ्य-पुस्तकों के मुद्धार हेतु अनेक सुझाव दिये परन्तु उनको कार्यान्विष्ट करने के लिए अधिक प्रयत्न नहीं किये गये। यद्यपि शिक्षा विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है परन्तु परिणाम अभी तक निराशाजनक है। इसके अनेक कारण हैं

१. पाठ्य-पुस्तकों के लिखने एवं चयन करने की अनेक कार्यवाहियों का ज्ञान शिक्षा विभाग को न होने से पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन के स्तर में आघातीत मुद्धार न हो सका।
२. पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन एवं चयन सम्बन्धी कार्य कठिन है अब इसको सुचारु रूप में करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है परन्तु पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन के लिए किसी प्रकार की योजनाओं का निर्माण नहीं किया गया।



८. अधिकांश पाठ्य-पुस्तकें ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं जिनका शिक्षा के उस स्तर में कोई सम्बन्ध नहीं होता है। उदाहरण के लिए, विद्वत्विद्यालय के प्राध्यापक माध्यमिक स्तर के छात्रों की मनोगत विवेचनाओं एवं रचियों का ज्ञान न होते हुए भी पुस्तकें लिखते हैं।
९. प्रचलित पाठ्य-पुस्तकें राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता तथा अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की भावनाओं का विकास नहीं करती हैं।
१०. प्रादेशिक भाषाओं के शिक्षा का माध्यम होने में पाठ्य-पुस्तक का स्तर गिर गया है। अब क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने में अपने-अपने क्षेत्रों के लिए ही पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। अब उनका अन्तर्देशीय क्षेत्र समाप्त होने में स्वर्द्धा भी समाप्त हो गई है।
११. पाठ्य-पुस्तकों के आकार, मुद्रणवृष्ट तथा बिल्ड की ओर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

### पाठ्य-पुस्तकों के सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों में व्याप्त दोषों का वर्णन किया। दोषों में पूर्ण पुस्तकों द्वारा न तो छात्रों में पुस्तकों के प्रति प्रेम जाग्रत होता है और न ही वे अध्ययन में रुचि लेते हैं। आयोग ने इन दोषों को दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं।

१. आयोग के अनुसार शिक्षा विभागों को पुस्तकों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। कुछ पाठ्य-पुस्तकें पाठ्य-पुस्तक समितियों के द्वारा प्रकाशित होनी चाहिए। ये पुस्तकें ऊँचे स्तर की होनी चाहिए ताकि प्रकाशकों को सुन्दर एवं उपयोगी पुस्तक का प्रकाशन करने की प्रेरणा मिल सके।
२. पाठ्य-पुस्तकों में सुन्दर तथा उपयुक्त चित्र देने चाहिए। इसके सम्बन्ध में आयोग ने दो सिफारिशें की हैं।
  - (अ) कला का प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नवीन चित्र-कला विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, या वर्तमान चित्रकला विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था की जाय जहाँ पाठ्य-पुस्तकों के लिए चित्र, रेखाचित्र आदि बनाने वाले कलाकारों को प्रशिक्षित किया जा सके।
  - (ब) केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों को चित्रों के ब्लाक्स का पुस्तकालय शोल्कर उसको न्यायित व संरक्षित रखना चाहिए। ये ब्लाक्स पाठ्य-पुस्तक समितियों के अनिश्चित प्रकाशकों को भी उपहार देने चाहिए। इस प्रकार प्रकाशकों को पुस्तकों के प्रकाशन में अधिक रुचि नहीं करना पड़ेगा तथा उच्च कोटि के ब्लाक्स प्राप्त हो पायेंगे।

३. आयोग ने सुझाव दिया कि भाषा व साहित्य के अतिरिक्त अन्य विषयों में मौलिक पुस्तकों रचना उपयुक्त नहीं है। सामंति द्वारा या उन पुस्तकों को स्वीकृत करके सूची प्रकाशित कर देना चाहिए और इस प्रकार प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक को उस सूची में से उपयुक्त पुस्तक का चुनाव करने की स्वतन्त्रता दी जाय।
४. भारत एक धर्म-निर्णय राष्ट्र है। इस राष्ट्र-पुस्तक में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी धर्म या मताद्वय की किसी एक की भावनाओं को चोट पहुँचाये। इसमें देश की एकता सम्मान होगी। किसी राष्ट्र-पुस्तक को धर्म या राजनीतिक दल की विचारधाराओं का प्रकाशित करने का मापन नहीं बनाना चाहिए। राष्ट्र-पुस्तक सामंति व यथेष्ट उत्तरदायित्व है कि वह इन पुस्तकों की जाँच करके देवे। किसी धर्म पर आपत्त करने वाली, किसी मताद्वय की बात पहुँचाने वाले पुस्तक को कभी स्वीकार न करना चाहिए। राष्ट्र-पुस्तकें ऐसी हों चाहिए जो छात्रों को राष्ट्रीय प्रेम तथा अन्तरराष्ट्रीयता की शिक्षा दे सकें जिससे राष्ट्र में रहने वाले निवासियों में परस्पर प्रेम व सहानुभूति की भावना विकसित हो सके और बड़े होने पर बच्चे विदेश के अच्छे नागरिक बन सकें।
५. आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में उच्च मत्ता समिति का निर्माण किया जाय। इस समिति में उन सदस्यों को सम्मिलित किया जाय जोकि किसी प्रलोभन या प्रभाव के चक्कर में बर्दाश्त न करें। इस उच्च मत्ता समिति (High Power Committee) में निम्नलिखित पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाय
  - (अ) उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश,
  - (आ) लोक सेवा आयोग का एक सदस्य,
  - (इ) उच्च शिक्षा का एक उपकुलपति,
  - (ई) प्रदेश का एक प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका,
  - (उ) दो प्रमुख शिक्षाविद् सम्मिलित किये जायें,
  - (ऊ) प्रदेश का शिक्षा सचालक।

इस समिति का सचिव शिक्षा सचालक होगा। समिति अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं अपने सदस्यों में से ही कर लेगी। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष के लिए होगा।

मुद्राभियार आयोग ने इस समिति के कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया है :

१. माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक विषय के लिए पृथक्-पृथक् विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की दो या तीन सदस्यों की समिति नियुक्त करना इस



उच्च सत्ता समिति का ही कार्य होगा। इन समितियों को भीषी गई पुस्तकों के गुण एवं दोषों का विवेचन करना ही इनका कर्म होगा।

२. उच्च शक्ति समिति के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के लिए समीक्षकों की एक सूची तैयार की जायेगी। ये सदस्य पुस्तकों की मधीक्षा किया करेंगे।

३. आवश्यकतानुसार निपुण व्यक्तियों द्वारा पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य अध्ययन योग्य पुस्तकों की रचना करवाना।

४. जहाँ तक सम्भव हो सके, अन्य प्रदेशों की इसी प्रकार की समितियों में सम्पर्क स्थापित करना तथा परस्पर सहयोग देना।

५. विद्यालयों के लिए पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था करना।

६. प्रकाशन की विधियों में प्राप्त धन को सुरक्षित करना।

७. जिन लेखकों की पुस्तकें विद्यालयों के लिए स्वीकृत हो जायें उनको उपयुक्त पारिश्रमिक दिया जाय।

८. बचे हुए धन को भीषे जिसे अनुसार व्यय करना—

(अ) निर्धन तथा दुर्भाग बुद्धि छात्रों को छात्रवृत्ति देना।

(आ) इसी प्रकार के छात्रों को नि मुक्त पुस्तकें देना।

(इ) विद्यालय के बच्चों के लिए शौचालय के भोजन अथवा दूध की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता देना।

(ई) माध्यमिक शिक्षा के अन्य उपयोगी कार्यों में व्यय करना।

१. इन समिति को प्रतिवर्ष अपने कार्य की प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट वर्ष के अन्त में सरकार को देनी होगी।

२. राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध विद्वानों को पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य उपयोगी साहित्य का निर्माण करने के लिए आमन्त्रित किया जाय। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित मन्त्रालयों द्वारा ही यह कार्य पूर्ण हो सकता है।

(अ) विश्वविद्यालय स्तर के लिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा ही कम मूल्य में पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं। यह कार्य विशेष रूप से विदेशी पुस्तकों के प्रकाशन की स्वीकृति लेकर किया जा रहा है।

(आ) विद्यालय स्तर के लिए पुस्तकों के उत्पादन क्षेत्र में N C E R T प्रशसनीय कार्य कर रहा है।

(इ) कौटिली आयोग ने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय स्तर पर पुस्तकों के उत्पादन कार्य के लिए भारत सरकार को एक स्वायत्त मण्डल की स्थापना करनी चाहिए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान की पुस्तकें इसके द्वारा प्रमुख रूप से प्रकाशित की जायें।



(१) विभिन्न क्षेत्रों से सदस्यों को लेना ।

(२) सदस्यों का अपने कार्य-क्षेत्र में ही अत्यधिक व्यस्त होना ।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एच लोकर-नेवा आयोग के सदस्य अधिक कार्य भार होने से अन्य कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं ।

एक आलोचना का बिन्दु यह है कि इस उच्च शक्ति समिति के जिन सदस्यों की चर्चा की गई है उनमें कुछ का शिक्षा जगत् में और विशेष रूप में प्राथमिक या माध्यमिक शालाओं में कोई सम्बन्ध नहीं होता है । अतः उनमें माध्यमिक विद्यालयों के लिए उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों के चुनाव की आशा करना बसत ही है ।

### पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता

भारतवर्ष में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् नियुक्त किये गए माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग ने प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों में व्याप्त दोषों की चर्चा अपने प्रतिवेदन में की है । इन दोषों को दूर करने के लिए इन शिक्षा आयोगों ने सुझाव दिया कि पाठ्य-पुस्तकों का उत्पादन, प्रकाशन, तथा वितरण आदि सम्बन्धी सभी कार्य प्रान्तीय सरकारों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । निम्नलिखित वर्णित कुछ कारण पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं ।

(१) सन् १९३० में जब सविधान का निर्माण हुआ तो उस समय यह निश्चय किया गया कि १० वर्ष के अन्दर ६ वर्ष में १४ वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य हो जाएगी । इस योजना की कार्यान्वित करने में दो बातें हुई—प्रथम तो विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई तथा दूसरे सभी वर्गों के बच्चे विद्यालय जाने लगे । छात्रों की संख्या में वृद्धि होने से पुस्तकों की माँग भी बढ़ी । प्रकाशक इस आवश्यकता की पूर्ति करने में असफल रहे । इसी प्रकार सभी वर्गों के बालक अध्ययन करने आने लगे तो निर्धन बच्चों के लिए सस्ती पुस्तकें मुलभ करना आवश्यक हो गया । प्रकाशक पुस्तकों के मूल्य में कमी नहीं करते । अतः यह आवश्यक हो गया है कि पुस्तकों का प्रकाशन सरकार अपने हाथ में ले ।

(२) बुनियादी शिक्षा का राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली घोषित करके उसको सम्पूर्ण देश में लागू करने का सुझाव दिया गया । बुनियादी शिक्षा किसी न किसी रूप में सम्पूर्ण देश में प्रारम्भ की गई । परन्तु अनेक कारण एवं समस्याओं से यह प्रणाली सफल न हो सकी । बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त पुस्तकों का अभाव है । पुस्तकें बुनियादी शिक्षा के दृष्टिकोण से लिखी ही नहीं गई हैं । प्रकाशकों ने उचित पाठ्य-पुस्तकें लिखवाने का प्रयास नहीं किया । इन पुस्तकों के अभाव से बुनियादी शालाओं में अध्यापन कार्य भी व्यवस्थित रूप में नहीं चल पाता है । यह आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए पुस्तकें लिखाई जायें जिनमें अध्यापकों को उचित निर्देशन हेतु पुस्तकें मिल सकें ।



है। इसके साथ ही ये प्रकाशक कुछ लाभ लेकर ही पुस्तक बेचते हैं। परन्तु सरकार का उद्देश्य पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन में 'न लाभ न हानि' का रहेगा। परिणामस्वरूप, प्रकाशकों को अपेक्षा राजकीय प्रकाशन की पुस्तकों का मूल्य कम होगा। इस प्रकार निर्धन अभिभावक भी पुस्तकें खरीद सकेंगे।

(२) पुस्तकों का राजकीय प्रकाशन होने में सरकार को भी लाभ रहेगा। निर्धन छात्रों को नि:शुल्क पुस्तकों का वितरण करने में सरकार को सहायता मिलेगी।

(३) राजकीय प्रकाशन होने में छात्रों को भी लाभ होगा। प्रकाशकों द्वारा पुस्तकें प्रकाशित होने में कभी-कभी अधिक विमर्श हो जाता है। छात्रों को विमर्श में पुस्तकें मिलने से उन विषय की तैयारी नहीं हो पाती है। राजकीय प्रकाशन का एक उद्देश्य समय पर पुस्तकें प्रकाशित कर छात्रों को उपलब्ध कराना भी है।

(४) कुछ वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करने वाले छात्र तथा अध्ययन करने वाले अभ्यापकों को अच्छे स्तर की पुस्तकें नहीं मिल पाती है। कुछ वैकल्पिक विषयों में छात्रों की संख्या इतनी कम होती है कि प्रकाशक उन विषयों में पुस्तकें प्रकाशित करना लाभप्रद न होने से उपयुक्त नहीं समझते हैं। राजकीय प्रकाशन होने पर सभी विषयों पर समान स्तर की पुस्तकें प्रकाशित करना सरकार का उत्तरदायित्व होगा।

(५) राजकीय प्रकाशन में पुस्तकों में एकसूचना आएगी। अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा पुस्तकें अलग-अलग ढंग से लिखी जाती हैं। इन पुस्तकों में विषय मामूरी के प्रस्तुतीकरण का ढंग भिन्न होता है, पुस्तकों में पाठ्य-सामग्री की व्यवस्था भिन्न-भिन्न ढंग में होती है। राष्ट्रीयकरण होने पर पुस्तकों में अभ्यापक को निर्धारित पाठ्यक्रम का तुरन्त पता लग जाता है।

(६) पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण होने में सरकार राजस्व प्राप्त करने के माध्यम के रूप में इनका प्रयोग में ला सकती है। इन प्रकार में प्राप्त आय को शिक्षा पर व्यय किया जा सकता है।

**विभिन्न राज्यों में पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण**

विभिन्न राज्यों में पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण विभिन्न ढंग में किया है। कुछ प्रान्तीय सरकारों ने पुस्तकों का प्रकाशन, वितरण आदि सभी कार्य अपने हाथ में ले लिये हैं। ये विद्यालय के सभी विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन करती हैं। इसके विपरीत कुछ प्रान्तों में पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण आंशिक रूप में किया गया है। इन प्रान्तों में कुछ कक्षाओं या कुछ विषयों की पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।-

१. पंजाब—१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में यहाँ पर पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बाद आधी शताब्दी तक पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकों में कोई परिवर्धन नहीं हुआ। इन वर्षों में पाठ्य-पुस्तकें वितर्क से प्रकाशित हो पाती थी

और उनका स्तर भी ऊँचा नहीं था। अब सन् १९३५ में प्रकाशकों को पुनः पुस्तक उत्पादन का कार्य दिया गया, परन्तु पञ्जाब सरकार ने फिर में पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है। इस प्रान्त में पुस्तकों का निम्नता, उनका प्रकाशन और वितरण की व्यवस्था करना सरकार के हाथ में है।

२. बिहार—इस प्रान्त में पुस्तकों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया है। पुस्तकों को निम्नवाना, छपवाना और वितरण सरकार के हाथ में है। पुस्तकों की बिंदी में प्राप्त होने वाले लाभ को छात्रवृत्ति के रूप में योग्य छात्रों में वितरित कर दिया जाता है।

३. उत्तर प्रदेश—प्रकाशकों द्वारा ईमानदारी में पुस्तक प्रकाशन कार्य न करने में पुस्तकों का प्रकाशन सरकार ने अपने हाथ में लिया। प्रारम्भ में सरकार ने भाषा की पुस्तकों को ही प्रकाशित किया। अब सभी कला तक की सभी विषयों की पुस्तकें सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। पुस्तकों के वितरण के लिए सरकार को पुस्तक विक्रेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है।

४. आन्ध्र प्रदेश—आन्ध्र प्रदेश में प्रारम्भिक कला तक की सभी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। प्रारम्भ में प्रकाशकों ने इसका तीव्र विरोध किया।

५. मद्रास—यहाँ पर भी पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ परन्तु सन् १९५६ में पुस्तकों का वितरण पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा करवाया गया। जनता ने इसका विशेष अवयव किया।

६. उड़ीसा तथा बम्बई—ये दोनों ही प्रान्त राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं। यहाँ पर प्रारम्भ में पुस्तकों का प्रकाशन सरकार ने स्वयं किया परन्तु सतोपजनक परिणाम न होने पर सरकार ने इनके प्रकाशन का विचार त्याग दिया। इन प्रान्तों के विरोध के कारण निम्न है

- (अ) लेखकों ने सरकार को पुस्तक लिखने में सहयोग नहीं दिया।
- (आ) राष्ट्रीयकरण करने में लेखन कार्य की स्पर्धा समाप्त होती है।
- (इ) सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में भी अनेक दोष होते हैं।
- (ई) शिक्षा क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

७. केरल—इस प्रान्त में पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सन् १९५८-५९ को पुस्तकों का निरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इसकी नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य यह देखना था कि पुस्तकों को कम्प्यूनिज्म विचारों को प्रसारित करने का माधन तो नहीं बनाया गया है। समिति ने बताया कि पुस्तकों द्वारा छात्रों को कम्पुनिस्ट विचारों का ज्ञान कराने का प्रयत्न किया गया है। अन्त में पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार त्याग दिया गया।

## राजस्थान में पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

अन्य प्रान्तों की भाँति राजस्थान सरकार ने भी पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है। इस प्रान्त में सन् १९५४ में जयपुर नगर में राष्ट्रीयकरण पाठ्य-पुस्तक परिषद् की स्थापना की गई। सरकार ने सर्वप्रथम पहली कक्षा में ८ वी कक्षा तक की समस्त पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया। पाठ्य-पुस्तक परिषद् ने निर्णय किया कि १९५७ तक पहली से आठवी कक्षा तक की सभी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो जाय। परन्तु सरकार को इस लक्ष्य-प्राप्ति में सफलता प्राप्त न हो सकी क्योंकि इस अवधि में केवल १४ पुस्तकें ही सरकार द्वारा प्रकाशित हो सकी। राजस्थान में पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए राष्ट्रीयकरण बोर्ड का गठन किया गया है।

१. राष्ट्रीयकरण बोर्ड—पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन, वितरण आदि सभी कार्य इस बोर्ड द्वारा किये जाते हैं। इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं

- (१) राजस्व बोर्ड का सदस्य,
- (२) शिक्षा सचालक,
- (३) वित्त विभाग का उपसचिव,
- (४) शिक्षा विभाग का उपसचिव,
- (५) राजस्थान प्रमाणन सेवा स्तर का अधिकारी (R A S) या उपशिक्षा संचालक के स्तर का अधिकारी।

२. समीक्षक बोर्ड—प्रत्येक विषय में समीक्षक बोर्ड बनाया जाता है। इनमें प्रख्यात शिक्षा शास्त्रियों को समीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उपशिक्षा सचालक के स्तर का अधिकारी इस समीक्षक बोर्ड में यह देखने के लिए रखा जाता है कि पाठ्यपत्र के अनुसार ही पुस्तक लिखी गई है।

३. उच्च शक्ति समिति—एक उच्चशक्ति समिति है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :

- (१) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश,
- (२) राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य,
- (३) राष्ट्रीयकरण बोर्ड का अध्यक्ष।

समीक्षक बोर्ड का निर्णय उच्च शक्ति समिति के पास भेजा जाता है।

४. पाण्डुलिपि आमंत्रित करना—राजस्थान सरकार राजस्थान राजपत्र के द्वारा लेखकों से पाण्डुलिपि आमंत्रित करती है। पाण्डुलिपि देने के लिए लगभग ६ महीने का समय दिया जाता है। यह पाण्डुलिपि टंकण या छपे हुए रूप में होनी चाहिए। पाण्डुलिपि के साथ २० से ४० मुद्रक के रूप में देने होते हैं। यह पाण्डुलिपि लेखक या प्रकाशक दोनों ही जमा कर सकते हैं।

५. पाण्डुलिपि की समीक्षा—पाण्डुलिपि लेखकों एवं प्रकाशकों से प्राप्त होने के बाद समीक्षकों के पास भेजी जाती है। प्रत्येक समीक्षक अपना अलग-अलग प्रतिवेदन देते हैं। मुख्य समीक्षक इन सभी समीक्षाओं का अध्ययन करने के बाद उनको राष्ट्रीय बोर्ड को प्रस्तुत करता है। कभी-कभी मुख्य समीक्षक को राम भण्ड समीक्षकों के विचारों में भिन्न होने पर बहु विस्तृत रूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

६. मुद्रण - पाण्डुलिपि के स्वीकृत होने के बाद उसकी छापाई का प्रबंध किया जाता है। पाठ्य-पुस्तक समिति ही मुद्रण का प्रबंध करती है। सरकार के पास स्वयं के प्रेम पत्रांश न होने में पुस्तकों की छापाई के लिए ग्राइन्ड प्रेसों पर निर्भर रहना पड़ता है।

७. मूल्य निर्धारित करना - पाठ्य-पुस्तक का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। राजकीय मुद्रणालय या अधीक्षक इस समिति का सदस्य होता है।

८. वितरण - पाठ्य-पुस्तक समिति पुस्तकों के वितरण के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाती है। (१) विविध के प्रधान कार्यालय पर स्टोर बनाना, (२) पुस्तक विक्रेताओं द्वारा (३) विद्यालयों को सीधे पुस्तकें भेजना।

### पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न समस्याएँ

त्रिम उद्देश्य में पुस्तक का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय प्रान्तों में किया गया प्रतीत होता है कि उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी पाठ्य-पुस्तकों में वे ही दोष पूर्ववत् ही हैं। शिक्षा साहित्य का विचार है कि पाठ्य-पुस्तक के रूप में कोई आधुनिक गुण नहीं हुआ। राष्ट्रीयकरण में भी जनक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

(१) अध्यापक की स्वतन्त्रता समाप्त होना - भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का हम ईश्वर तथा मनुष्य राज्य समीक्षा की आदि स्वाभिव्यक्ति प्राप्त नहीं है। परिणामस्वरूप, भारतीय अध्यापक के पास कोई उपरदायित्वपूर्ण कार्य न होने में स्वतन्त्र रूप में विचार करने अधिकांश कार्य की योजना बनाने आदि की प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है। पुस्तक का राष्ट्रीयकरण ने पूर्व बार्ड द्वारा एक विषय में तीन-चार पुस्तकें स्वीकृत की जाती थी। अध्यापक को उनमें से किसी एक उपयुक्त पुस्तक का चुनाव की स्वतन्त्रता मिली हुई थी। परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने जिस पुस्तक का प्रकाशन किया है, वही अध्यापक का पढ़ानी पड़ती है। काशी अध्यापक न अध्यापक का पाठ्य-पुस्तक का चुनाव करने का स्वतन्त्रता देने के लिए ही यह मुद्रणालय १६ सरकार को भी एक विषय में तीन-चार पुस्तक प्रकाशित करती पाठ्यपत्र।

(२) राजनीतिक विचारों का प्रसार - भारतवर्ष में विविध राजनीतिक दल



हैं। वे अभी दल अपने नियमों एवं सिद्धान्तों का प्रचार करके उसको लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करते हैं। एक भय यह है कि जिस राजनीतिक दल के हाथ में शक्ति होगी वह पाठ्य-पुस्तकों को अपने विचारों का प्रचार करने के लिए प्रयोग में ला सकता है। इस प्रकार प्रजासत्तय के इस सिद्धान्त का हनन हो सकता है कि छात्र में स्वतन्त्र चिन्तन की शक्ति का विकास किया जाए ताकि वह भले-बुरे की पहिचान कर सके। केवल ये कम्युनिस्ट दल के हाथों में सत्ता आने पर उन्होंने पाठ्य-पुस्तकों के द्वारा छात्रों के कोमल मस्तिष्क पर कम्युनिज्म के सिद्धान्तों को बोधना आरम्भ कर दिया था।

यह पाठ्य-पुस्तकें ही यथार्थ रूप में प्रस्तुत करनी हैं। यह कहा भी जाता है कि शांतिपूर्ण समाज का दर्पण होता है। परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद पाठ्य-पुस्तकें भीमिन भावों के द्वारा लिखी जाने के कारण समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों को स्पष्टन प्रस्तुत नहीं करती हैं।

(४) पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब—राष्ट्रीयकरण के बाद भी पाठ्य-पुस्तकें छात्रों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। राजस्थान प्रान्त में ही अनेक पुस्तकें वर्ष के अन्त में छात्रों को मिल पाती हैं। पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब का कारण, पारसीतायाही है। राष्ट्रीयकरण की इतनी सखी प्रक्रिया बना रही है कि सभी स्वीडिनि अनेक विभागों में लेने के कारण प्रकाशन में विलम्ब होना स्वाभाविक ही है। प्रकाशन में विलम्ब के कुछ और भी कारण हैं, जैसे—

(१) पाठ्य-पुस्तक समिति का धन के लिए वित्त विभाग पर निर्भर रहना,

(२) कठोर नियमों के अधीन होना।

(३) पाठ्य-पुस्तकों के वितरण की समस्या—कभी-कभी यह होता है कि पाठ्य-पुस्तकें समय पर ही छपकर तैयार हो जाती हैं परन्तु उनके वितरण की कोई ठोस विधि न होने में वे भण्डार में ही रखी रहती हैं। सरकार को इन पाठ्य-पुस्तकों के वितरण के लिए पुस्तक विप्रेताओं की सहायता लेनी पड़ती है। पुस्तक विप्रेता इन पुस्तकों को कमी बढ़ाकर छात्रों से निश्चित मूल्य में अधिक मूल्य लेकर पुस्तकें लेते हैं या इन दल पर देते हैं कि पुस्तक के साथ उनके यहाँ की छपी हुई पुस्तकें

(६) भाषा एवं मुद्रण त्रुटियों का होना—सरकार ने पाठ्य-पुस्तकों का अवन अपनै हाव में उनका स्तर ऊँचा करने के उद्देश्य से लिया था। प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में भाषा सम्बन्धी असुद्धियाँ तथा मुद्रण त्रुटियाँ पाई जाती थीं। सरकार द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों में भी उसी प्रकार त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं। कुछ पाठ्य-पुस्तकों में विषय सामग्री का प्रस्तुतीकरण छात्रों के पूर्व-ज्ञान उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार नहीं है। परिणामस्वरूप, ये पुस्तकें छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित नहीं कर पाती हैं।

(७) पाठ्य-पुस्तक के मूल्य में कमी न होना—जिन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो गया उनका मूल्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के मूल्य से कुछ भी कम नहीं अभिभावकों का इस क्षेत्र में निरास हो होना पड़ा। सरकार पुस्तकों की छपाई अलग प्रेसों से करवाती है तथा सरकार कागज बाजार से खरीदती है। अतः ऐसी पुस्तकों में मूल्यों में कमी होना सम्भव नहीं है।

(८) लेखन प्रतिस्पर्धा सम्पन्न होना—पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण होने से लेखकों को जायात पड़ता है। प्रकाशक विभिन्न लेखकों से पुस्तकें लिखवाया करते हैं अतः लेखकगण प्रतिस्पर्धा के कारण उत्तम पुस्तक लिखने का प्रयास करते हैं। नवीन लेखकों को लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ ही अनेक लेखकों का पुस्तक लेखन एक व्यवसाय होता है। राष्ट्रीयकरण होने से ऐसे व्यक्तियों को बेकारों की समस्या का शिकार होना पड़ता है।

### राष्ट्रीयकरण की मफल बनाने के उपाय

अभी तक देश में शिक्षा-शास्त्रियों के दो वर्ग बने हुए हैं—एक वर्ग पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध है तो दूसरा वर्ग राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध वर्ग पुस्तकों के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका का उदाहरण देता है। संयुक्त राज्य अमरीका तथा इंग्लैण्ड की पाठ्य-पुस्तकें उच्च स्तर की मानी जाती हैं। किन्तु वहाँ पर पुस्तकें प्रकाशकों के द्वारा ही प्रकाशित की जाती हैं।

दूसरा वर्ग जो कि पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, हम का उदाहरण देता है। हम में सभी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। वहाँ की सरकार में हमारे देश के राज्यों के सामने उठने वाली समस्याओं जैसी ही समस्याएँ का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि वहाँ पुस्तकें धाकर भण्डारों में रखी थी क्योंकि वितरण की उचित व्यवस्था नहीं थी। परन्तु धीरे-धीरे वहाँ की सरकारी बर्मचारी पाठ्य-पुस्तक के व्यवसाय में प्रतिष्ठित हो गए और सभी पुस्तकें समाप्त हो गईं। इस वर्ग के लोगों का कथन है कि भारत में व्यक्तिगत रूप से पुस्तक प्रकाशन में पर्याप्त समय दिया गया, अतः राष्ट्रीयकरण की पुस्तकों को पुनरारंभ के लिए अक्षम वित्त का कारण है। राष्ट्रीयकरण की मफल बनाने के लिए सरकार को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए।

(१) सरकार को निजी प्रेस स्थापित करने चाहिए ताकि सरकार को पुस्तकों के मुद्रण के लिए व्यक्तिगत प्रेसों पर निर्भर न रहना पड़े।

(२) पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य में कमी करने का प्रयत्न सरकार को करना चाहिए। इसके लिए सरकार को कामचला भोधा मिन में खरीदना चाहिए। इसके शारीरिक चित्र आदि के नक्का का संयोजन स्थापित करना चाहिए।

(३) पाठ्य-पुस्तकों के स्तर को सुधारने के लिए सरकार को अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए। इन अनुसंधान केन्द्रों में विद्ये गए कार्यो के आधार पर श्रेष्ठ पुस्तकों को स्वीकार करके सरकार को पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन करवाना चाहिए। अनुसंधान कार्य के लिए सरकार द्वारा अध्यापकों को भी प्रोत्साहित किया जाए।

(४) पाठ्य-पुस्तकों पर नाम प्राप्ति करना सरकार का ध्येय रखते हुए सरकार को पुस्तकों के उत्पादन में 'न लाभ न हानि' के सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिए।

(५) अच्छे लेखकों को पुस्तक लेखन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार लेखकों को उच्च सम्मान दे तथा अधिक पारिश्रमिक दे। इन पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन इस प्रतिनिधि मण्डल ने उत्तम समझा जाता है और

(६) पाठ्य-पुस्तक लिखने के लिए लेखकों को अधिक समय दिया जाए। यदि पर पुस्तक लिखने को १ वर्ष से अधिक समय नहीं दिया जाता है जबकि हम लेखकों को एक पुस्तक लिखने के लिए कम से कम २ वर्ष का समय तथा अधिक से अधिक ५ वर्ष का समय दिया जाता है।

(७) कुछ लेखकों द्वारा लिखी गई तथा सरकार द्वारा स्वीकृत पुस्तक छात्रों को सीखने में सहायता देती हैं, क्योंकि छात्रों को लेखकों की लेखन शैली में विविधता नहीं मिलती है। सरकार को यह दोष दूर करने के लिए नए-नए लेखकों का चुनाव करने के लिए विभिन्न विधियाँ एवं साधन प्रयोग में लाने चाहिए।

(८) पाठ्य-पुस्तकों का चुनाव करने की स्वतन्त्रता देने के लिए सरकार के अन्य प्राधिकारियों में कम से कम तीन पुस्तकें प्रकाशित की जाएँ।

(९) भारतवासी स्वतन्त्र चिंतन वाले व्यक्ति हैं। ये इतनी सरलता में किसी विचारों से प्रभावित नहीं होते। अगर कोई राजनीतिक पार्टी पाठ्य-पुस्तकों को राजनीतिक विचारों का प्रचार करने का साधन बनाती है तो उसका तीव्र विरोध करना ही चाहिए। उदाहरण के लिए, केरल में वहाँ की जनता ने पाठ्य-पुस्तकों की न समीक्षा की माँग की।

(१०) सरकार को पाठ्य-पुस्तकों के वितरण के लिए पुस्तक विजेताओं पर

मूल्यों का स्रोत है। धर्म में ही उत्तम चरित्र और शील निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति का स्रोत ईश्वर के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम है। ये सत्य, निव, सुन्दरम् को धेष्ठ मानते हैं।

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल भुंशी ने धर्म को समझाते हुए लिखा है कि "धर्म मूलतः वह प्रक्रिया है जो हमारे सभी अनुभवों और कार्यों को भय, लोभ, लालसा तथा घृणा से दान-अर्न मुक्त करना है और पूर्णतः त्नाकर सुन्दरता प्रदत्त करता है।"

श्री किलपेंड्रिक ने लिखा है कि "धर्म का एक मास्कुलिक ढांचा है जो। अलौकिक तथा असाधारण से सम्बन्धों पर आधारित होता है, जैसा कि इस आस्था रखने वाले विविध व्यक्तियों द्वारा विचार किया जाता है।"

धर्म को स्पष्ट करते हुए भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक डॉ॰ राधाकृष्णन् लिखा है कि "किन्हीं मत-मतान्तर को मानना, भावनाओं को अनुभव करना या धार्मिक कृत्यों की पूर्ति करना धर्म नहीं है। यह तो एक परिवर्तित जीवन है।"

धर्म के मूल्य—कुछ विद्वानों ने धर्म के निम्नलिखित प्रमुख मूल्य बताये हैं

१. जीवन का संतुलित दर्शन जोकि स्वीकार करता है कि—

(अ) मानव इस सृष्टि का ही एक अंग है।

(आ) मनुष्य एक प्राणी है जोकि अपने साथी मनुष्यों के साथ काम करके सभी की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकता है।

(इ) मनुष्य अन्त तक पहुँचने की क्षमता रखता है।

२. ईश्वर तथा सृष्टि के प्रति प्रेम-सम्मान का भाव रखता जिसका मनुष्य भी एक अंग है।

३. नैतिक जीवन अन्वीत करना।

४. सभी को परस्पर सहयोग एवं सहकारिता के आधार पर रहना चाहिए।

५. मनुष्यित जीवन जो कि अनश्वर रचनात्मक शक्तियों तथा मानव जाति के साथ सम्बन्ध की अनुभूति पर व्यतीत होता है।

धर्म के उपर्युक्त प्रमुख मूल्य हैं जिसका समझना तथा स्वीकार करके अपने जीवन में पालन करना ही सही जीवन का मुख्य-मन्त्र है।

### धर्म तथा शिक्षा

का शिक्षा में गुणना सम्बन्ध है। धर्म ने सर्व विद्या को प्रभावित दोनों ही मनुष्य के आचरण का आधार करने है तथा उसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास करने हैं। धर्म और विद्या का सम्बन्ध अभी तक एक विषय है। विद्या विद्यार्थी का एक निविर धर्म की शिक्षा के प्रतिबन्ध है और दूसरी ओर एक निविर ऐसा भी है जो विद्या को मार्गक बनाने के

लिए उनका धर्म में संयोग करना अनिवार्य मानना है। शिक्षा तथा धर्म के सम्बन्ध को समझने के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा के कार्य को समझ लें। शिक्षा का एक कार्य मस्तिष्क की रक्षा करना भी माना जाता है। शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क की समृद्धि होती है। इसके साथ ही मानव को पशु जगत् में जन्म करने वाली शक्ति शिक्षा ही है। मानव को सभ्यता का पाठ सिखाया गया तथा शिक्षा ही सभ्यता का उच्चतम आदर्श स्थापित करती है। परन्तु विशेष बात यह है कि शिक्षा अपने इस धर्म का पालन तभी कर सकती है जबकि वह धर्म का महाराज है। धर्म और शिक्षा इमनिफ भी सम्बन्धित हैं क्योंकि—

१. इन दोनों का मानव जीवन में सम्बन्ध है।
२. शिक्षा तथा धर्म दोनों का मध्य मानवीय मूल्यों और गुणों को विकसित करना है।
३. सामाजिक वन्याय में दोनों का सहयोग रहता है। श्रीप्रकाश मर्मिनि ने भी अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि धर्म आज भी हमारे समाज में एक नैतिकता की शक्ति है।
४. धर्म तथा शिक्षा दोनों ही मानव-जीवन के भौतिक व आध्यात्मिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं।
५. धर्म एवं शिक्षा परस्पर एक-दूसरे में सम्बन्धित होकर मानव को चरित्र की दृढ़ता तथा पारस्परिक एकता का पाठ सिखाते हैं।

शिक्षा तथा धर्म का सम्बन्ध स्पष्ट करने हुए जी० जेडिग नामक एक उद्देश्ययन शिक्षाविद् ने कहा है कि 'राष्ट्रीय मस्तिष्कियों को मानविक उन्नत आदर्शकलाएँ पूर्ण करने की जितनी अधिक आवश्यकता इस समय है, पहले कभी नहीं थी। ये मानविक आवश्यकताएँ न केवल मीमेटाफिजिक्स तथा सूक्ष्म बौद्धिक हैं बल्कि वे नैतिक तथा धार्मिक भी हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में नैतिक मनुष्य के विकास में है। बौद्धिक तथा शारीरिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक तथा नैतिक गुणों का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति शिक्षा तभी कर सकती है जबकि उसमें धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय। इसी को स्पष्ट करने हुए स्पेन्स रिपोर्ट में भी लिखा है कि 'किसी बालक या बालिका को जब तक पूर्णतः शिक्षित नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसको जीवन की धार्मिक व्याख्या में अवगत न करा दिया जाय।'

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म तथा शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा धर्म के बिना शिक्षा अप्रग ही बनी रहती है।

### धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य

धार्मिक शिक्षा के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं

१. छात्रों में उच्च नैतिक तथा आध्यात्मिक गुण पैदा करना। राम ने भी लिखा है कि धर्म के बिना नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है।

११४

११४ (११४) ११४

१. धर्म की शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।
२. यह शिक्षा कि धर्म कि शिक्षा दी जाय, धर्म की शिक्षा दी जाय।
३. धर्म की शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।
४. शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।
५. धर्म की शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।
६. धर्म की शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।
७. धर्म की शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।
८. धर्म की शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।
९. धर्म की शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।
१०. धर्म की शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।

### धर्म शिक्षा का इतिहास

प्राचीन भारत प्राचीन भारत में धर्म का अग्रिम प्रचलन था। नई पाठ प्रमुख धर्म माना जाता था। उम समय भारतीय के जीवन का उद्देश्य न था आत्म-साक्षात्कार करना था। धर्म का प्रभाव प्रत्येक भारतीय के जीवन था। उम समय शिक्षा का उद्देश्य छात्र का ज्ञान या धन कमाने के लिए ही नहीं था बल्कि उसका उद्देश्य छात्र को आत्मा का ज्ञान करना था। धर्म शिक्षा का अर्थ निम्नलिखित था

१. धर्म श्रुति का माधन।
  २. शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास कर उसे मानव मान्यता का आधारकार करना।
  ३. आत्म-दर्शन व परब्रह्म प्रगति का मार्ग बनाना।
  ४. छात्रों में आत्म-अनुसामन पैदा करना।
- उम समय के दर्शन, कला, साहित्य, मनीन, नृत्य कला आदि सभी पर धर्म का प्रभाव था।

१. धर्म शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।  
 २. धर्म शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।  
 ३. धर्म शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।  
 ४. धर्म शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।  
 ५. धर्म शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।  
 ६. धर्म शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।  
 ७. धर्म शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।  
 ८. धर्म शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।  
 ९. धर्म शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।  
 १०. धर्म शिक्षा का उद्देश्य यह है कि धर्म की शिक्षा दी जाय।

चलित जाति प्रथा को बौद्ध धर्म में समाप्त करने का प्रयास किया गया।  
 गुण विहारों में विद्या-दान देने थे। इन विहारों में बौद्ध-धर्म के मिटान्तों का  
 छात्रों को कराया जाता था। धर्म सम्बन्धी शास्त्रों को त्रिपिटक कहते थे।  
 की बुद्धि व आध्यात्मिकता का विकास करना मुख्यों का कर्तव्य समझा  
 जाता था।

**मध्य काल—मुस्लिम काल में भी धर्म-शिक्षा की प्रधानता रही।** मुसलमानों  
 शिक्षा को धर्म-प्रचार का माध्यम बनाया था। इनके द्वारा भारतवर्ष में भक्तव  
 मदरसे स्थापित किये गये जिनमें कुरान व इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी।  
 मुस्लिम शासकों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए अधिक प्रयास किये। भक्तवों  
 छात्रों को कुशल शरीर की आयतें पटा दी जाती थी।

**अंग्रेजी काल—ईसाई मिशनरी—**भारतवर्ष में यूरोपियन निवासियों के  
 समय के उपरान्त ईसाई मिशनरियों ने यहाँ पर विद्यालयों की स्थापना की।  
 का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षा द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करना था। भारतीय  
 तत्वों को इन विद्यालयों में बड़े पैमाने पर ईसाई बनाना प्रारम्भ कर दिया।  
 लैण्ट, जर्मनी तथा अनरीका आदि देशों के मिशनरी यहाँ आकर ईसाई धर्म का  
 प्रचार करते थे।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में सामन आने पर उसने तटस्थता की नीति  
 अपनाई। कम्पनी की इस नीति का अंग्रेजों ने इंग्लैण्ड में विरोध किया।

सन् १८५८ के कुछ के शिक्षा घोषणा-पत्र में तटस्थता की नीति का समर्थन  
 था गया। उन्होंने निष्कारण की कि विद्यालयों तथा परीक्षाओं में धर्म शिक्षा को  
 ही स्थान नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म शिक्षा प्रदान करने  
 में विद्यालयों को सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलना चाहिए।

सन् १८५८ में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि भारत के धार्मिक  
 मामलों में ब्रिटिश सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस घोषणा में ईसाई मिश-  
 नरियों के धर्म प्रचार सम्बन्धी कार्य को धक्का लगा।

सन् १८८२ में इन्टर आरोग की निर्मुक्त की गई। इस अवधि में भी धार्मिक  
 शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध ही मुभाव दिया। इसका मुभाव था कि  
 सभी भी सरकारी विद्यालय में किसी धर्म विशेष की शिक्षा न दी जाकर प्रमुख  
 भाषा के प्रमुख मिटान्तों को शिक्षा दी जाय।

सन् १८५८ में केन्द्रीय शिक्षा गवर्नर मन्त्रि ने धर्म को पाठ्यक्रम का  
 निवार्य अंग बनाया। इस समिति की सन् १८८६ में पुन बैठक हुई जिसमें नैतिक व  
 आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालने हुए इसे धर्म, समाज व विद्यालय  
 का उत्तरदायित्व माना।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद—मन् १९८८ में राष्ट्राध्यक्षन आयोग ने पुनर्धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के प्रश्न को उठाया। इस आयोग ने इस समस्या का अध्ययन करके निम्नलिखित व्यावहारिक सुझाव दिये

१. हर विद्यालय में कार्यक्रम प्रारम्भ होने में पूर्व ५ मिनट की मौन प्रार्थना हो।
२. स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष में गौतम बुद्ध, चंकर, रामानुज आदि के जीवन-चरित्र व दर्शन का अध्ययन करवाया जाय।
३. स्नातक कक्षा के दूसरे वर्ष में विश्व के विभिन्न प्रमुख धर्मों के सामान्य तत्त्व पर लेख स्वीकृत किये जायें जिनका अध्ययन छात्रों को करवाया जाय।
४. अन्तिम वर्ष में धर्म सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्तों का अध्ययन छात्रों को करवाया जाय।

मन् १९५० में मविधान का निर्माण हुआ जिसके अनुसार भारतवर्ष को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। मविधान के परिच्छेद मस्या १६, २१ और २२ में भारतवर्ष में धार्मिक शिक्षा का स्थान स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान स्थान प्राप्त है। उर्माहित कहा गया है कि राज्य द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों में किसी प्रकार की भी धार्मिक शिक्षा छात्रों को नहीं दी जा सकती है। परन्तु सरकारी सहायता पर चलने वाले विद्यालयों पर यह प्रतिबन्ध नहीं है। इसके साथ ही यह भी कि किसी भी विनोय धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

मन् १९५२-५३ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन के १२५ पृष्ठ पर लिखा है कि “चरित्र के बिनाम में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योग है।” इसने नैतिक शिक्षा सिखाने के तीन प्रमुख साधन बताये हैं

- १ घर का प्रभाव,
- २ स्थानीय समाज तथा विद्यालय का वातावरण,
- ३ शिक्षकों का आचरण।

मन् १९५६ में १७ अवमन को केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने श्रीयुग श्रीप्रकाश श्री अन्ना में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की। इस को दो कार्य दिये गये

- (अ) यह जांच करना कि विद्यालयों में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता है कि नहीं।



(आ) शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए धार्मिक शिक्षा की पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करना ।

इस समिति द्वारा दिये गये सुझावों का वर्णन आगे किया गया है

## धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता

आज भारत में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अधिक अनुभव की जाने लगी है

(१) भौतिक प्रगति के साथ आत्मिक प्रगति—आधुनिक युग में विज्ञान तथा औद्योगिक विकास इतना अधिक हुआ है कि इसके कारण मानव जीवन भौतिकवादी बन गया है । आज हमने भौतिक उन्नति करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है । हम बाह्य सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । हमने आत्मिक प्रगति को पूर्णतः भुला दिया है । इस प्रकार के वातावरण में आध्यात्मिक मूल्य एवं मान्यताएँ खिल होनी जा रही हैं । आवश्यकता यह है कि दोनों में संतुलन रखा जाय । इस संतुलन को बनाने के लिए धार्मिक शिक्षा होना आवश्यक है ।

(२) सामाजिक सद्गुणों का विकास—आज हम शिक्षा में सामाजिकता के विकास की अधिक चर्चा करते हैं । प्रसिद्ध शिक्षा वास्तुश्री जीवी तो इसी कारण विद्यालय को समाज का लघु रूप बनाने के लिए कहते थे । वेस्टवुड रमण को कथन कि "धर्म ही सामाजिक सद्गुणों का प्रस्थान है ।" आज हमारे देश में व्यक्तियों की स्वार्थपरता की भावना अधिक विकसित हो गई है । इस भावना के कारण ही समाज की प्रगति अवरुद्ध हो गई है । मानवीय गुणों का विकास ही छात्रों को नहीं हो पाता है । धार्मिक शिक्षा के द्वारा मानवीय उद्दान गुणों का विकास किया जा सकता है ।

(३) अराजकता, अशिष्टता व छात्रों की उध्वृक्षता को रोकना—देश में आज सभी क्षेत्रों में चाहे राज्य कर्मचारियों का क्षेत्र हो या व्यापारियों का क्षेत्र, अप्रत्याचार तथा बेईमानी व्याप्त है । राज्य कर्मचारियों ने आज अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को भुला दिया है । प्रति वर्ष देश की विभिन्न भागों में छात्रों की हड़ताएँ होती हैं, राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुँचाई जाती है । छात्र अपने अध्ययन को अनादर करने में भी नहीं चूकते हैं । ऐसे छात्रों में जोकि कल के भावी नागरिक तथा देश के कणधार बनेंगे, हम देश के विकास की कंम जाया कर सकते हैं । छात्रों को सद्गुणों, कर्तव्यनिष्ठा तथा पूज्यजनों के प्रति सम्मान का भाव रखने की शिक्षा देने के लिए धार्मिक शिक्षा का सहारा ले लेना ही पड़ेगा ।

(४) चरित्र-निर्माण तथा जीवन के मूल्यों के विकास हेतु—छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास करने के लिए धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा देने की व्यवस्था विद्यालयों में होनी चाहिए । यह सत्य ही है कि जब किसी व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो जाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है । हर्बर्ट के मतानुसार छात्रों को इस प्रकार की

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद—मन् १९४८ में राष्ट्राव्ययन आयोग ने पुनः एक तथा नैतिक शिक्षा के प्रश्न को उठाया। इस आयोग ने इस समस्या का ध्यान करके निम्नलिखित व्यावहारिक मुझाव दिये

- १ हर विद्यालय में कार्यक्रम प्रारम्भ होने में पूर्व १ मिनट की मौन प्रार्थना हो।
- २ स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष में गीतम बुड, शकर, रामानुज आदि के जीवन-चरित्र व दर्शन का अध्ययन करवाया जाय।
- ३ स्नातक कक्षा के दूसरे वर्ष में विद्वत् के विभिन्न प्रमुख धर्मा के सामान्य तत्त्व पर लेख स्वीकृत किये जायें जिनका अध्ययन छात्रों को करवाया जाय।
- ४ अन्तिम वर्ष में धर्म सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्तों का अध्ययन छात्रों को करवाया जाय।

सन् १९५० में संविधान का निर्माण हुआ जिसके अनुसार भारतवर्ष को एक निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। संविधान के परिच्छेद मध्या १९, २१ और २८ में भारतवर्ष में धार्मिक शिक्षा का स्थान स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर सभी को समान स्थान प्राप्त है। इसीलिए कहा गया है कि राज्य द्वारा चलाने जा विद्यालयों में किसी प्रकार की भी धार्मिक शिक्षा छात्रों को नहीं दी जा सकती परन्तु सरकारी महाविद्यालय पर चलने वाले विद्यालयों पर यह प्रतिबन्ध नहीं है। साथ ही यह भी कि किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा प्रहण करने के लिए को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

सन् १९५२-५३ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा हस्त को स्वीकार किया। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन के १२५ पृष्ठ पर लिखा : “चरित्र के विकास में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योग है।” नैतिक शिक्षा सिखाने के तीन प्रमुख माधन बताये हैं

- १ घर का प्रभाव,
- २ स्थानीय समाज तथा विद्यालय का बानावरण,
- ३ शिक्षकों का आचरण।

सन् १९५९ में १७ अगस्त को केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने धीमे धीमे प्रकाश की धना में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की। इस समिति को दो कार्य दिये गये—

- (अ) यह जांच करना कि विद्यालयों में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा कहां तक उपयुक्त है।

नया धार्मिक अभिवृत्तियों को सक्तिमान बना सके। इस पाठ्यक्रम के निम्नलिखित कार्य हैं।

(अ) सार्वभौमिक तत्त्वों पर बल देना, (आ) ईश्वर के प्रति प्रेम तथा सम्मान एवं मित्रता का भाव पैदा करना, (इ) अच्छे तथा श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति बफादारी, भक्तिभाव तथा उनकी सहायता करने को तैयार रहना।

(३) सभी क्रियाएँ धार्मिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करती हैं। छात्रों का एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार हो तथा छात्रों के अपने घर पर तथा समाज में किये जा रहे व्यवहार में सच्चे मूल्य पाये जाते हों। विद्यालय की प्रत्येक क्रिया छात्रों को नैतिकता का पाठ सिखाने वाली हो।

श्रीप्रधान मन्त्रि ने भी धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के लिए व्यावहारिक सुझाव दिये हैं।

- १ जन-निष्ठा के प्रसार द्वारा घर की उचित व्यवस्था की चेष्टा की जाय क्योंकि सभी नैतिक कार्यक्रमों में घर के महत्त्व पर उचित ध्यान देना आवश्यक है।
- २ राष्ट्राकुलगन आयोग के इस सुझाव में सहमति प्रकट करना कि सभी विद्यालयों का कार्य कुछ मिनटों की धार्मिक प्रार्थना में प्रारम्भ हो।
- ३ प्राथमिक कक्षाओं में लेकर विश्वविद्यालय तक के लिए उचित पुस्तक तैयार की जाएँ। इनमें प्रत्येक धर्म के मुख्य सिद्धान्तों व प्रत्येक धर्म के प्रमुख प्रवर्तक की जीवन-गाथा का वर्णन हो।
- ४ शिष्टाचार के गुणों को प्रोत्साहन दिया जाय।
- ५ सह्यामी क्रियाओं को प्रोत्साहन दिया जाय।

समिति द्वारा विभिन्न स्तर पर सुझाव

### प्राथमिक स्तर पर

(१) साप्ताहिक गान, (२) धार्मिक नेताओं से सम्बन्धित रोचक, मरल कहानियाँ, (३) हृदय-श्रेष्ठ सामग्री की प्रदर्शनी जो मुख्य धर्मों से सम्बन्धित हो, (४) सप्ताह में दो घण्टे नैतिक शिक्षा का दिये जाएँ, (५) शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम हो।

### माध्यमिक स्तर पर

(१) प्रातः काल प्रार्थना मन्त्रा हो, (२) धर्म के आवश्यक तत्त्वों का अध्ययन पाठ्यक्रम का ही अंग मानकर हो, (३) महान् नेताओं को व्याख्यान के लिए आमन्त्रित किया जाय, (४) सभी धर्मों के मुख्य स्वीकारों का समारोह मनाया जाय, (५) छुट्टियों में सप्ताह समारोह हो।

### विश्वविद्यालय स्तर पर

(१) दीन ध्यान तथा पान्त चिन्तन; (२) विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, (३) समारोहों का भाव पैदा किया जाय।

शिक्षा दी जाय जिसमें उनके मन की बुरी प्रवृत्तियाँ धीरे-धीरे जाएँ तथा अच्छी प्रवृत्तियाँ निर्मित हो सकें। परन्तु केवल चार्मिक गुणों के निर्माण की ओर ही ध्यान देने में उत्तम बुराई की ओर ध्यान आकर्षित करने हुए डॉ० राधाकृष्णन ने कहा है कि “जीवन के मूल्यों एवं आदर्शों के ज्ञान के बिना चार्मिक गुण समाज की उन्नति के स्थान पर विनाश भी कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि छात्रों को चार्मिक गुणों की जीवन में उपयोगिता तथा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उनको प्रयोग में लाने का ज्ञान देना भी अनिवार्य आवश्यक है।” यह कार्य धार्मिक शिक्षा द्वारा सम्भव है।

(५) धर्म भारतीय संस्कार और जीवन का एक अंग—भारतवर्ष एक धर्म-प्रधान देश रहा है। यहाँ के संस्कार तथा मानव जीवन सर्वे धर्म में प्रभावित होने लगे हैं। जन-जीवन को आन्दोलित करने में धर्म का हाथ रहा है। विद्यालयों को जीवन का प्रतिबिम्ब माना जाता है। अतः बिना धर्म शिक्षा के ये संस्कार अधूरी ही मानी जायेंगी।

### विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का रूप

भारतवर्ष की धर्म-निर्पेक्षता के कारण आज यह निश्चित करना एक बड़ा समस्या हो गई है कि विद्यालयों में छात्रों को दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो। इसके सम्बन्ध में विचार करने पर ज्ञान होता है कि धार्मिक शिक्षा देने के अवसर निम्नलिखित वर्गों में आते हैं

(१) भक्ति या उपासना के घण्टे—यह कहा जाता है कि बिना पूजा के धर्म दर्शन मात्र ही रह जाता है। धर्म केवल आचार सम्बन्धी विज्ञान, दर्शन या सत्कृति ही नहीं है परन्तु व्यक्ति का ईश्वर के साथ सम्बन्ध भी धर्म ही है। यह वफादारी का पाठ मिलाना है। अतः इसका सम्बन्ध सवेग तथा इच्छा में होता है। पूजा का पाठ उदाहरण तथा उसमें भाग लेने में ही मिलाया जा सकता है। आन्तरिक अनुभव के बिना पूजा जीवचार्मिकता मात्र है। विभिन्न धर्मों के व्यक्ति एक उपासना तभी कर सकते हैं जबकि उपासना की सामग्री विस्तृत तथा सार्वभौमिक हो। पूजा या उपासना का एक साधन प्रतिदिन की सामूहिक प्रार्थना भी है। जब सभी शक्तिपूर्वक एकत्रित हों तो एका की भावना पैदा होती है। हुमायूँ कबीर ने भी एक स्थान पर लिखा है कि जिन विद्यालयों में प्रार्थना सम्भाले होती है उनमें अनुशासन अधिक पाया जाता है तथा छात्रों में परस्पर मंत्री भाव भी अधिक होता है।

(२) कक्षा में एक विशेष विषय—यह निश्चित करना बड़ा हो रहा है कि विद्यालयों में विभिन्न धर्मावलम्बी छात्रों के लिए धर्म की कौन-कौन-सी विषय का रूप दिया जाय। विद्वानों का मन है कि धर्म का अध्यापन एक विषय के रूप में करना के लिए आवश्यक है कि अध्यापक विस्तृत दृष्टिकोण वाले हों। धर्म का पाठ्यक्रम बनाने समय यह ध्यान रखा जाय कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक, नैतिक

तथा धार्मिक अभिवृत्तियों को क्षतिग्रस्त न हो सके। इस पाठ्यक्रम के निम्नलिखित कार्य हैं।

(अ) मार्वाभौमिक तत्त्वों पर ध्यान देना, (आ) ईश्वर के प्रति प्रेम तथा सम्मान गुरुत्व मित्रता का भाव पैदा करना, (इ) अच्छे तथा खेच्छ व्यक्ति के प्रति वफादानी, भक्तिभाव तथा उनकी महत्ता करने को तैयार रहना।

(३) सभी विद्यालय धार्मिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करनी हों। छात्रों का एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार हो तथा छात्रों के अपने घर पर तथा समाज में किये जा रहे व्यवहार में सच्चे मूल्य पाये जाते हों। विद्यालय की प्रत्येक क्रिया छात्रों को नैतिकता का पाठ सिखाने वाली हो।

श्रीप्रधान मन्त्रि ने भी धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के लिए व्यावहारिक सुझाव दिये हैं।

१. जन-शिक्षा के प्रसार द्वारा घर की उचित व्यवस्था की चेष्टा की जाय क्योंकि सभी नैतिक कार्यक्रमों में घर के सहत्व पर उचित ध्यान देना आवश्यक है।
२. राष्ट्रावृत्तिन आयोग के इस सुझाव में महत्प्रति प्रकट करना कि सभी विद्यालयों का कार्य कुछ मिनटों की धार्मिक प्रार्थना में प्रारम्भ हो।
३. प्राथमिक कक्षाओं में लेकर विश्वविद्यालय तक के लिए उचित पुस्तक तैयार की जाएं। इनमें प्रत्येक धर्म के मूल सिद्धान्तों व प्रत्येक धर्म के प्रमुख प्रवर्तक की जीवन-गाथा का वर्णन हो।
४. शिष्टाचार के गुणों को प्रोत्साहन दिया जाय।
५. महत्तामी क्रियाओं को प्रोत्साहन दिया जाय।

### समिति द्वारा विभिन्न स्तर पर सुझाव

#### प्राथमिक स्तर पर

(१) मातृहिक गान, (२) धार्मिक लेनाओं में सम्बन्धित रोचक, सरल कहानियाँ, (३) हृदय-अभ्य मासिकी की प्रदर्शनी जो मुख्य धर्मों से सम्बन्धित हो, (४) सप्ताह में दो घण्टे नैतिक शिक्षा को दिये जाएँ, (५) नारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम हो।

#### माध्यमिक स्तर पर

(१) प्रातः काल प्रार्थना सभा हो, (२) धर्म के आवश्यक तत्त्वों का अध्ययन पाठ्यक्रम का ही अंग मानकर हो, (३) महान् नेताओं का व्याख्यान के लिए आमन्त्रित किया जाय, (४) सभी धर्मों के मुख्य त्योहारों का समारोह मनाया जाय, (५) छुट्टियों में सगठित समाज-सेवा हो।

#### विश्वविद्यालय स्तर पर

(१) मौन ध्यान तथा शान्त चिन्तन, (२) विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, (३) समाज-सेवा का भाव पैदा किया जाय।

संक्षिप्त धार्मिक शिक्षा प्राथमिक यत्र प्रान दे। की बात है कि धार्मिक शिक्षा मनुष्य को न तो बर्ताए यत् निम्नोन्नीय प्राप्ति को पहुँचा सकता है।

१. संक्षिप्त धार्मिक शिक्षा छात्रों में मनुष्यिक मर्यादों की बातें बतानी है।
२. इस प्रकार की शिक्षा राष्ट्रीय एकात्मता को प्राप्ति को पहुँचाता है।
३. यह मनोवृत्ति के वास्तविक कारणों तथा अर्थोपपन्न मर्यादों के स्वरूप को बतानी है।
४. अधिवासी धर्म छात्रों में अस्वाभाविकता को दूर करने का प्रयत्न करता है।

साधनानिर्वाह धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक शिक्षा देने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं परन्तु हमें यह साधन मिलेंगे कि हमें सन्तानों तथा 'धार्मिक शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाय।' डॉ० राधाकृष्णन ने भी कहा है 'कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ अधार्मिक नहीं है। यह आवश्यक है कि कुछ साधनों के अभाव में ही जायें।'

१. सरकार प्राचीन धार्मिक शिक्षा को प्राप्ति को पहुँचाता है, मन् १९३० के 'राष्ट्रधर्म' में राष्ट्रीयता के सिद्धांतों के आधार पर धार्मिक शिक्षा के आधार पर सिद्धांतों को धर्मों में समान है तथा यह आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं।
२. पाठ्य-महाभाषी शिक्षा में अपने आप धार्मिक शिक्षा का समावेश करने का अवसर छात्रों को दिया जाय।
३. धार्मिक शिक्षा देने में अज्ञानों में सहनशीलता, विमूल्य भावना तथा विशाल-हृदयता होनी चाहिए।
४. धार्मिक शिक्षा की विधि तथा विषय स्वरूप के अनुसार होने चाहिए।

### नैतिक शिक्षा

नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में अभी तक यह विवाद का विषय बना हुआ है कि इसकी सीधे कक्षाओं में मिलाया जा सकता है या नहीं। हार्ट के शिक्षा विधि तथा मनोविज्ञान का यह परिणाम हुआ कि १९वीं शताब्दी के अन्त में यूरोप तथा अमेरिका में नैतिक शिक्षा-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इन नैतिक शिक्षा का पढ़ाना प्रारम्भ हो गया। परन्तु फोरेल ने इस प्रत्यक्ष का विरोध किया। उन्होंने कहा कि "बालकों को नैतिक आचरण की शिक्षा रूप में दी जाती चाहिए।" इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों को नैतिकतापूर्ण आचरण में रखा जाय। प्रत्यक्ष विधि का विरोध निम्नलिखित कारणों से हो गया।

१. प्रत्यक्ष विधि द्वारा छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान दिया जा सकता है, उनको व्यावहारिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। नैतिक भावों का

ज्ञान सभाज के सम्पर्क में जाने में प्राप्त होता है। अनुभव उम ज्ञान में वृद्धि करने है तथा त्रिमाणें उम ज्ञान को स्थायी बनाती है।

२. नैतिकता की आवश्यकता किसी एक निश्चित अवसर पर ही नहीं पड़ती है। जीवन के प्रत्येक उम में नैतिकता की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति कक्षा में एक घण्टा पढ़ा देने में ही नहीं हो सकती है।

बुद्ध भी हो, सभी एक बात में तो सहमत हैं कि नैतिकता का छात्रों में विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये। नैतिक तथा जात्यात्मिक मूल्यों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति विद्यालय तथा घर दोनों ही मिलकर कर सकते हैं। आज परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पढ़ने में अधिक बढ़ गई है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है

१. राजनीतिक जीवन में हो रहे विरोधों ने व्यक्ति की नागरिक कर्तव्यों की भावना को कमजोर बना दिया है। आज के राजनीतिक नेताओं में स्वाध्याय तथा भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया है। उनका ही अनुकरण जनसाधारण कर रहा है।
२. देश में औद्योगिक विकास हो रहे हैं। इस औद्योगिक समाज की कार्य की दशाओं ने व्यक्तिगत उत्प्रेरकत्व की भावना को कम कर दिया है। प्रत्येक कर्मचारी एक-दूसरे पर दोषारोपण करता है।
३. देश में हो रहे औद्योगिक विकास तथा राजकीय भगडन की दृष्टिकोण से व्यक्ति का अस्तित्व खोता गया है।
४. परिवार में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। बच्चों के अभिभावक कमजोर हो गये हैं। परिणामस्वरूप, उनका अपने बच्चों पर नियन्त्रण कम हो गया है। माता-पिता अपने बच्चों को ध्यान, स्नेह, निर्देशन, सुरक्षा आदि नहीं प्रदान कर पाते हैं।
५. चरित्रों का प्रचलन बढ़ गया है। प्रचार में काम भावना पर अधिक जोर दिया जाता है। चलचित्र तथा रंगमंचों पर कामोत्तेजक अभिनय अधिक होना लगे हैं।
६. अन्तरराष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है। धीनयुद्ध विभिन्न देशों के मध्य चल रहा है।
७. मशीनों का अधिक प्रयोग होने से कर्मचारियों के अवकाश के समय में वृद्धि हुई है। इस अवकाश के समय का सदुपयोग करने की समस्या बढ़ गई है।

उत्पुष्कित गरीबी कारणों से आज हमारे देश में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता बढ़ गयी है। आवश्यकता इस बात की है कि छात्रों को नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान करवाया जाय। नैतिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम उपयोगी हो सकना है

- १ नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य विद्यालय के उद्देश्य धारित रूप ज्ञाने। इन मूल्यों को निश्चिन्त करने के लिए अध्यापक-अभिभावक मण्डल, विद्यालय तथा समाज की काउन्सिल आदि की मीटिंग होनी चाहिए।
- २ अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों में अवगत करवा जायें। इसके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इन मूल्यों को सम्मिलित किया जाय। अध्यापक की नियुक्ति में चरित्र पर विशेष ध्यान दिया जाय।
- ३ नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए विद्यालय के सभी माधमों का प्रयोग होना चाहिए।

(अ) अनुभव तथा उदाहरण यह विद्यालय तथा अध्यापक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायगा।

(आ) बख्श—नाटक, वाक्य प्रतियोगिता, मधीत कवच आदि नैतिकता के विकास के लिए अवसर प्रदान करने हैं।

(इ) भाहितय तथा कला नैतिक मूल्यों को सिखाने का अच्छा अवसर प्रदान करते हैं।

(ई) खेल-कूद में छात्रों में साथी तथा गमानता का भाव विकसित होना है। धर्म तथा नैतिक शिक्षा को अलग-अलग नहीं देखना चाहिए। प्रसिद्ध शिक्षाविद् रायबर्मन ने लिखा है कि नैतिकता को धर्म में सम्मिश्रित किए बिना हमकी शिक्षा देना असम्भव है। वास्तव में धर्म के मित्रान्त नैतिकतापूर्ण चरित्र को अपनाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अतः इन दोनों को सम्मिश्रित रूप में सिखाना चाहिए।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

१. मुद्रानियंत्रण आयोग ने धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये हैं ?
२. धर्म-निरपेक्ष राज्य में धार्मिक शिक्षा देने में क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं ?
३. "नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा एक-दूसरे में पृथक् नहीं की जा सकती है।" इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए।
४. भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थितियों में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।



## राजस्थान विद्वद्विद्यालय की बी० एड० परीक्षा से पूछे गये प्रश्न

1. "This brings me to the third element in Nehru's philosophy, namely, his moralism. His morality hinges round two central ideas—the notion of duty, and the idea of humanity."

(S K Pandey)

"The ideologists' only message to the individual is that he should find his salvation in identifying his personal interests with the common weal, and this is cold comfort for ordinary mortals in trouble, and gives him no practical help of the kind offered him by Religion. This alone is sufficient to show that Religion cannot be written off as obsolete."

(Arnold Toynbee)

Suggest a workable system of imparting moral and religious education in India so as to realise both the ideals referred to above (1962)

2. (a) Suppose we define morality as doing to others as we like to be done by. Do you think whether precept or example or both can inculcate morality in your students?

Give three examples of how morality can be taught to the children and three more examples of how morality can be caught by them.

Also show how religion can be of use in fostering morality.

Or

- (b) Suppose that we define religion as the emotional relationship of the finite with the finite. Do you think whether this relationship—

(i) must be clear before it is acquired?

(ii) must be taken up even vaguely at first, and may be clearer in due course?

(iii) is disruptive of scientific attitude and should be tabooed?

(iv) stimulates intellectual growth and should be fostered?

(v) has no relationship with the intellectual growth or

scientific attitude and should be ignored by the teacher ?

Give your answer in not more than five words and if your reply to question (iii) is—

(a) in affirmative, establish your views with historical facts and reasoning, or (b) in the negative, build up a positive programme, which may be non-sectarian, for your students in order to foster their relationship with God. You are free to choose the age-group of your students (1964)

3 Write short notes—

(b) Religious education in a secular State (1963)

4 Analyse the problem of providing religious and moral education in our schools and formulate the line of action that you would like to adopt in your school in regard to this issue (1969)

५ यदि आप नैतिक शिक्षा को सामयिक शिक्षा के कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, तो इस शिक्षा का सर्वोत्तम रूप क्या होना चाहिए ? (१९६६)

६ क्या आप नैतिक शिक्षा के अभाव का छात्रों में अनुशासन का घटि पड़ने के लिए उत्तरदायी समझते हैं ? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए । (१९६७)

## अध्याय १४

### भारत में शैक्षिक प्रशासन की समस्याएँ

#### महत्त्व

शिक्षा के अग्य विभिन्न अंगों की ओर अभी तक जितना अधिक ध्यान दिया गया है, उतना शैक्षिक प्रशासन की ओर नहीं दिया गया। शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षण प्रविधि आदि अग्य विशेषज्ञता की अपेक्षा रखने हेतु शिक्षा का प्रशासन हर एक चला सकना है - यह विचार ही प्रचल रहा है। सरकारी प्रशासन में शिक्षा विभाग का भी महत्त्व कम ही रहा है। आरंभ भी शिक्षा विभाग में काम करने के लिए कोई भी अधिकारी भेज दिया जाता है। इस विचार का विक्षेपण करने हुए श्री मध्यम ने कहा है कि प्रवृत्ति हर एक मटे-मने अर्थों को प्रशासन के योग्य नहीं बनाती। विरोध रूप में शैक्षिक प्रशासन के काम को चलायाना एक जटिल कार्य है। शैक्षिक प्रशासनक एक साधारण नौकरशाही प्रवृत्ति वाला मनुष्य नहीं हो सकता, वह एक अधिकारी में कहीं अधिक प्रभावशाली और उच्चकोटि के व्यक्तित्ववाला मनुष्य होता है क्योंकि उममें मुख्य विशेष गुण होते हैं, जैसे व्यावहारिकता, सूझ-बूझ, मनुष्यों को परामर्श की योग्यता, वीर्यिक तथा नैतिक गुण, अन्तर्हृत् और दूरदर्शिता आदि। इन गुणों में युक्त अधिकारी ही शैक्षिक प्रशासन को चला सकता है। यदि शैक्षिक प्रशासनक अच्छा नहीं है, तो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

शैक्षिक प्रशासनक के व्यक्तित्व में परे, हमें कुछ उन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो शैक्षिक प्रशासन में सम्बन्ध रखती हैं। शैक्षिक प्रशासन एक जटिल प्रक्रिया है। बहुत में शिक्षाधिकारी और भाषान्यजन इस बात को नहीं समझते। उनके मन में, दफ्तर जाना, एक जनग कक्ष में बैठकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देना, जरूरी कामवातों पर हस्ताक्षर करना और फाइलों की जाँच करना ही शैक्षिक प्रशासन है। वास्तव में ऐसा नहीं है। शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया के

अनर्पित बहुत से काम आ जाते हैं, जिनकी जानकारी के बिना प्रशासन का काम अच्छी तरह नहीं चलाया जा सकता। वे कार्र हैं—नियोजन (Planning), संगठन, (Organization), कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति व उनमें काम सेना (Staffing), निर्देशन (Directing), समायोजन (Co-ordinating), प्रतिवेदन (Reporting) और अर्थ-व्यवस्था (Budgeting)। एक मध्य शिक्षाधिकारी को प्रशासन कार्य चलाते के लिए इन सभी बातों की ओर अच्छी तरह ध्यान देना पड़ता है। आज भारतीय शिक्षा के प्रशासनिक कार्य में बहुत सी अड़चने केवल इसलिए पैदा हो गई हैं कि हमारे पास कुशल प्रशासक नहीं हैं, जो मौलिक प्रशासन के कार्य को सम्भालें हों।

डी एस एस मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'Administration of Education in India' की भूमिका में लिखा है कि स्वतन्त्रता के बाद भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मायात्मक और गुणात्मक वृद्धि इसकी गंती में हुई है कि रोकथाम और उचित दिशा की दृष्टि में मौलिक प्रशासन का महत्व बहुत बढ़ गया है। वे लिखते हैं कि "यह बात अच्छी तरह समझ ली जानी चाहिए कि शिक्षा के पुनर्निर्माण की किसी भी योजना में जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का एक बड़े पैमाने पर विकास करना चाहती हो, उस मौलिक प्रशासन तब पर ध्यान रखना पड़ेगी है जो शिक्षा के विस्तार और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।" कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश में शिक्षा को समर्थ बनाने और उसका उचित लाभ दिलाने के लिए मौलिक प्रशासन को उचित सम्मान और महत्व देना होगा।

### भारतीय मौलिक प्रशासन की रूपरेखा

सर्वप्रथम महत्व— भारतीय मौलिक प्रशासन का स्वरूप बड़ा जटिल है। इस जटिलता का मूल कारण यह है कि भारतीय संविधान में शिक्षा की स्थिति अनिश्चित है। जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, संविधान बनाने वालों ने शिक्षा के महत्व को उस रूप में नहीं स्वीकार किया, जिस प्रकार किया जाना चाहिए था। इसके कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं। अंग्रेजों ने अपने सामन का तब में तब १९२१ और १९३७ के कानून द्वारा शिक्षा का विषय प्रांतीय (अब राज्य) को सौंप दिया था। संविधान में उसी स्थिति को कुछ हद-केर के साथ स्वीकार कर लिया गया। संविधान की भागों अनुसूची (Schedule) में शिक्षा को तीन सूचियों में शामिल कर दिया गया। वे हैं— केन्द्र सूची, राज्य सूची और संघवर्ती सूची। शिक्षा इन तीनों सूचियों के अनुसार कई सत्ताओं के कार्य क्षेत्र में शामिल हो गयी और इन के बीच सामंती के कारण कोई भी सत्ता शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि भारतीय शिक्षा सबसे अधिक उन्निव विषय है।

भारतीय मौलिक प्रशासन का अध्ययन करने वालों को उपर्युक्त तीनों सूचियों की पूरी जानकारी रखने के लिए उनका विवरण इस नीचे दे रहे हैं।

सघ (केन्द्र) सूची—इस सूची में बनारस विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्व-विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व की अन्य शिक्षा संस्थाएँ जिन्हें लोक सभा की मान्यता मिल जाय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा की संस्थाएँ जिन्हें भारत सरकार पूर्ण तथा आंशिक आर्थिक सहायता देती हो और जिन्हें लोक सभा राजनियम बनाकर राष्ट्रीय महत्व का करार देती हो, संघीय संस्थाएँ, जा पेमेंट, व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण देती हो, जैसे पुनर्निर्माण के प्रशिक्षण, या जो विधेय अध्यायन और शोध के लिए बनी हो या जो अपराध की जाँच और अन्वेषण में सहायक हो, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा सुव्वाओं और उच्च तथा शोध की संस्थाओं में समायोजन कार्य शामिल हैं।

राज्य सूची—इस सूची में उन संस्थाओं को छोड़कर जो सघ सूची में शामिल हैं, शेष शिक्षा विभाग में विषयविद्यालय की शिक्षा सम्मिलित है, दी गयी है।

समयसौ सूची—इस सूची में वे संस्थाएँ हैं जिनका सम्बन्ध आदारागद्दी, पाठान-पन, वैज्ञानिक अंतरता तथा अधिको की व्यावसायिक तथा प्रावधिक शिक्षा में है।

इन सूचियों के अनिवार्य विधान में स्पष्ट रूप में उल्लिखित है कि भारत सरकार शिक्षा के राष्ट्रीय नियोजन, अन्य दोनों के माध्यमिक और माहट्टनिक सम्बन्धों, विश्व सघ और यूनेस्को में भाग, शिक्षा सम्बन्धी नयी सूचनाओं तथा विचारों के एकत्रीकरण तथा प्रचार, सघ क्षेत्रों की शिक्षा, हिन्दी की शिक्षा तथा छात्र वृत्तियों के लिए जिम्मेदार है।

विधान में शिक्षा की दृष्टि स्थिति के कारण शिक्षा के प्रशासन में वह चुस्ती नहीं रह पाती जो होनी चाहिए। राज्य और सघ दोनों अपनी जिम्मेदारों का निर्वाह नहीं कर पाते। एक दोष यह भी पंदा हो गया है कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन नहीं रहा। वही जो अत्यधिक धन का व्यय हो रहा है, तो किसी क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। बहुत सी समस्याएँ ऐसी हैं जो अब तक उपेक्षित पड़ी हैं। उदाहरण के रूप में अध्यापकों के समान वेतन-क्रम की समस्या है। सघ सरकार एक सीमा के बाद आर्थिक अनुदान नहीं देना चाहती और राज्य सरकारें धन एकत्र करने में अपनी असमर्थता प्रकट करती हैं और अध्यापक इन दोनों पाटों के बीच रिय रहते हैं। इसी प्रकार अनेक सुधार कार्यान्वित नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा आयोगों और समितियों की समुत्तियों पर कोई भी सलाह अमल नहीं करती है।

केन्द्रीय शैक्षिक प्रशासन का विवरण—केन्द्रीय शैक्षिक प्रशासन शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक विभाग-कनारा मंत्रालय द्वारा चलाया है। शिक्षा-मंत्रालय के मण्डल के मुख्यालय में निम्न बातें जानव्य हैं

शिक्षा मंत्रालय का सर्वसाधारण सांख्यिक शिक्षा मंत्री है। उसके माध्य एक उपमंत्री तथा एक राज्य मंत्री हैं। इस मंत्रालय का शैक्षिक सचिव ही प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी है और वह सभी प्रशासनिक मामलों में भारत सरकार

का वैश्विक मलाहकार माना जाता है। मन्त्रालय में दो मुख्य शिक्षा का मलाहकार भी शामिल हैं। शिक्षा मन्त्रालय के विभाग हैं

- १ प्रशासनिक विभाग
- २ प्रागम्भिक और तुनिवादी शिक्षा विभाग
- ३ माध्यमिक शिक्षा विभाग
- ४ यूनेस्को और उच्च शिक्षा विभाग
- ५ सामाजिक शिक्षा और समाज कल्याण विभाग
- ६ छात्रवृत्ति विभाग
- ७ प्रायोगिक शिक्षा और मनोरंजन विभाग
- ८ हिन्दी विभाग
- ९ शोध और प्रकाशन विभाग।

इनके अतिरिक्त शिक्षा मन्त्रालय में दो यूनिटें भी हैं। तत्सम समायोजन यूनिट (Plan Co-ordination Unit) जिसका काम पञ्चवर्षीय के अन्तर्गत निर्धारित वैश्विक कार्यों पर ध्यान रखना है। दूसरा है- विशेष यूनिट (Special Reorganization Unit) जिसका काम शिक्षा प्रशासनिक क्षमता पर नजर रखना है और विभिन्न विभागों के पुनर्व्यवस्थापन करना है।

हर विभाग का एक अध्यक्ष होता है जो एक प्रकार से वैश्विक सहायक होता है। उनका पद उपमन्त्री के समकक्ष होता है। शिक्षा मन्त्रालय अधिकारी सहायक शिक्षा मलाहकार, शिक्षाधिकारी, अड्डर मैन्नेट्री, सहायक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उपाधिकारी, कार्यालय कहलाते हैं।

वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक क्रिया-कलाप मन्त्रालय का काम है विभागाध्यक्ष है

- १ प्रशासनिक विभाग
- २ वैज्ञानिक शोध विभाग
- ३ प्रावधिक विभाग
- ४ सांस्कृतिक विभाग
- ५ विदेश सम्पर्क विभाग
- ६ सांस्कृतिक छात्रवृत्ति तथा प्रकाशन विभाग।

इस मन्त्रालय का प्रमुख कार्य तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना है। चार कार्यालय कानपुर, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जैने रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय में सम्बद्ध कार्यालयों की संख्या तीन है। वे हैं—डायरेक्टोरेट ऑफ एक्स्टेंशन प्रोग्राम फॉर सेंट्रली गवर्नेड, सेंट्रल हिन्दी डायरेक्टोरेट और मोशन प्लेफ़िल्म एण्ड रीहैबिलिटेशन डायरेक्टोरेट।

राज्य शैक्षिक प्रशासन का विवरण—विभिन्न राज्यों में शैक्षिक प्रशासन की रूपरेखा कुछ हेर-फेर के साथ एक-समान है। हर राज्य के मंत्रिमण्डल में एक शिक्षा मंत्री होता है जो मंत्रिमण्डल के अनुसार शिक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए उपमंत्री और राज्यमंत्री होते हैं। राज्य के क्षेत्र में शिक्षा-नीति मंत्रिमण्डल में निर्धारित होती है। नीति सम्बन्धी बातों का नियन्त्रण शिक्षा मंत्री करता है जिसकी सहायता के लिए एक उपमंत्री भी होता है।

हर राज्य में एक शिक्षा विभाग होता है जिसके दो अंग होते हैं—एक मंत्रिमण्डल और दूसरा निदेशालय। मंत्रिमण्डल का सर्वोच्च अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है जो शिक्षा-नीति निर्दिष्ट करता है और निदेशालय का सर्वोच्च अधिकारी शिक्षा निदेशक होता है, जो शिक्षा-नीति को क्रियान्वित करता है। पूरा शिक्षा-विभाग राज्य में शिक्षा की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। यह शिक्षा सम्बन्धी स्तर, नियमावली और नियन्त्रण तथा निरीक्षण के उपाय निर्दिष्ट करता है। जहाँ पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, वहाँ पाठ्य-पुस्तकों की रचना और प्रकाशन की जिम्मेदारी भी शिक्षा-विभाग पर है।

शिक्षा निदेशालय शिक्षा के प्रशासन का मूल आधार है। इसकी ओर में सरकारी स्कूल चलाये जाते हैं, गैर-सरकारी स्कूलों को अनुदान मिलता है और उनका निरीक्षण किया जाता है। शिक्षा निदेशक एक अनुभवी व्यक्ति होता है जो अपने पद पर केवल दीर्घ अनुभव और योग्यता के बल पर ही पद पाना है। वह राज्य को शिक्षा के मामले में परामर्श देता है।

शिक्षा निदेशक के वही-कही दो पद हैं (जैसे राजस्थान में), एक कामेज शिक्षा का और दूसरा प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा का। प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत कई उपशिक्षा निदेशक होते हैं, यथा उपनिदेशक बुनियादी शिक्षा, उपनिदेशक योजना, उपनिदेशक प्रशासन, उपनिदेशक सामाजिक शिक्षा और उपनिदेशक स्त्री-शिक्षा। कितने-कितने राज्य में क्षेत्रीय उपनिदेशक होते हैं। उपनिदेशक प्रशासन के अन्तर्गत जिला स्तर पर एक अधिकारी होता है, जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक कहते हैं। जिला-विद्यालय निरीक्षक के अन्तर्गत दो प्रकार के उपविद्यालय निरीक्षक होते हैं जिनमें एक जूनियर माध्यमिक विद्यालयों और दूसरा प्राथमिक पाठशालाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। परीक्षा की व्यवस्था के लिए कुछ राज्यों में माध्यमिक शिक्षा परिषदें होती हैं जो माध्यमिक सार्वजनिक परीक्षा का संचालन करती हैं और पाठ्य-पुस्तकों को निर्धारित करती हैं। कुछ राज्यों में जिला परिषदें बनी हैं जिनमें





वारण आगे बढ़कर काम करने की इच्छा का अभाव और कभी-कभी अमहयोग की भावना— ये कठिनाइयाँ प्रशासन में बाधा पैदा करती हैं।

संविधान ने केन्द्रीय मौखिक प्रशासन को गतिशाली नहीं बनने दिया है। सार्वजनिक मर्यादों और स्थानीय मौखिक प्रशासन को संविधान ने पर्याप्त शक्ति और अधिकार दे रखा है, जिसमें केन्द्र प्रशासन निरंकुशता का रवैया नहीं अपना सकता और शिक्षा राज्य के हाथ की कठपुतली बनने से बच गयी है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने प्रसिद्ध लेख 'विबर्टी' (स्वतन्त्रता) में कहा है कि सामान्यतया जब शिक्षा राज्य के हाथ में चली जाती है, तो वह ऐसा माधन बन जाती है जिसमें राज्य नागरिकों को अपनी इच्छापूर्ति के लिए एक ही रास्ते में डालना प्रारम्भ करता है और फिर अन्त में उन पर निरंकुश तरीके से शासन करता है। हमारे संविधान ने केन्द्र प्रशासन को शिक्षा के प्रबन्ध करने में निरंकुश बनने की रांक लगा दी है। दूसरी ओर केन्द्रीयता में मौखिक प्रशासन को जो लाभ हो सकते हैं, उन्हें संविधान ने सुरक्षित कर दिया है। संविधान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि केन्द्रीय मौखिक प्रशासन बिना निरंकुश बने हुए राज्य तथा स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करे, उनका नेतृत्व करे, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न मौखिक समस्याओं को हल करे, मारे देश में मौखिक प्रश्नों का समाधान करे और समस्त मौखिक गतिविधियों पर नजर रखे।

भारतीय संविधान ने मौखिक प्रशासन को विकेंद्रित करने का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। हमने स्थानीय सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं को शिक्षा सम्बन्धी माधन जुटा कर शिक्षा की व्यवस्था करने का अवसर मिला है। हमने इस बात की सम्भावना उत्पन्न हुई है कि हमारे निर्धन देश में जनता मौखिक रूप में जाग्रत हो और शिक्षा के प्रति अपने अनुराग का परिचय दे। साथ ही संविधान ने एक कठिनाई भी उत्पन्न कर दी है। विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को खुली छूट देकर शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता पैदा होने की सम्भावना पैदा कर दी है। यदि स्थानीय सरकारें अपने आप को केन्द्र प्रशासन का प्रतिनिधि और साथ ही जनता का प्रतिनिधि नहीं समझती तो अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायगी। मौखिक प्रशासन की कार्यकुशलता नष्ट हो जायगी और स्कूलों तथा विशेष रूप में विद्यालयों के लिए काम चलाना कठिन हो जायगा।

केन्द्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों का सामंजस्य हमारे मौखिक प्रशासन में है। सामंजस्य दोनों की कुराहियों से बचने और गुणों को अपनाने की व्यवस्था संविधान ने की है। हमारे संविधान की मौलिक विशेषता प्रजातान्त्रिकता है। इसलिए मौखिक प्रशासन में सहयोग, समझौता, स्वेच्छा से काम करने, नेतृत्व करने और उत्तरदायित्व अनुभव करने पर जोर दिया जाता है। अधिकारी और कर्मचारियों में यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासन को 'समीन' न समझ कर मानवीय सम्बन्धों को स्थापित करने का माध्यम समझें और जनहित का लक्ष्य सामने रखें। विकेंद्रीकरण द्वारा प्रशासन

एक सदस्य जिले की प्राथमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। हर जिले में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पचायतें बनी हैं। ये पचायतें अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करती हैं।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राज्य स्तर पर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना का सुझाव दिया था। यह राज्यों में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रयत्नों के बीच समायोजन का काम तथा विविधतापूर्ण मन्त्रालयों के लिए बनाये जाने का था परन्तु सब राज्यों में ऐसा बोर्ड बन नहीं पाया। बिहार और केरल में अबतक ऐसे बोर्ड बनाये गये थे। कोटगरी शिक्षा-आयोग ने स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना का सुझाव दिया है। राज्य के शिक्षा-विभाग का एक अंग होगा और वर्तमान माध्यमिक शिक्षा-परिषद् तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ का काम करेगा। इस स्टेट बोर्ड के कई काम होंगे, जैसे विद्यालय शिक्षा के मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना, राज्य में स्थित स्कूलों को मान्यता देना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, मासिक परीक्षाओं का आयोजन करना, प्रतिभा की खोज के लिए विशेष परीक्षा लेना।

कोटगरी शिक्षा-आयोग ने हर राज्य में एक स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना का सुझाव दिया है। यह संस्थान शैक्षिक मामलों में बड़ी काम करेगा जो केन्द्र स्तर पर नेशनल बोमिन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग करती है। विद्वान सम्बन्धी पक्षों में यह जिला विद्यालय निरीक्षक को परामर्श देगा।

राज्य में एक स्वायत्त शासन प्रधान संगठन स्थापित करने की संसुति कोटगरी आयोग ने दी है, जिसका नाम स्टेट इवेलुएशन आरगनाइजेशन होगा। यह संगठन राज्य में शिक्षा के स्तर का निहावलोकन करने में सहायता देगा। इसकी सहायता में समय-समय पर शिक्षा-स्तर की जाँच होती रहेगी और यह जानकारी प्राप्त होगी कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो रहे हैं अथवा नहीं।

## भारतीय संविधान का शैक्षिक प्रशासन पर प्रभाव

भारतीय संविधान सहात्मक है और उसकी रचना पर अमरीकी संविधान का व्यापक प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजों के संविधान से भी भारतीय संविधान ने प्रेरणा ग्रहण की है। इस प्रकार शिक्षा के सम्बन्ध में संविधान विदेशी प्रभाव में अछूता नहीं रह पाया और शैक्षिक प्रशासन पर उसका कई प्रकार में प्रभाव पड़ा है।

सर्वप्रथम, शैक्षिक प्रशासन कई स्तरों में बँट गया। वे स्तर हैं—केन्द्रीय शैक्षिक प्रशासन, राज्य शैक्षिक प्रशासन और स्थानीय शैक्षिक प्रशासन। हर एक स्तर के प्रशासन की जिम्मेदारियाँ विधान में निश्चित कर दी गयी हैं और वे प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका जटा करती हैं। फिर भी तीनों स्तरों अलग-अलग नहीं हैं। उनके बीच साझेदारी है। फिर भी इस विभाजन के कारण शैक्षिक प्रशासन में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अधिकार क्षेत्रों की अस्पष्टता, माफेदारी के

कारण आगे बढ़कर कम करने की इच्छा का खभाव और कभी-कभी असहयोग की भावना—ये कठिनाइयाँ प्रशासन में बाधा पैदा करती हैं।

संविधान ने केन्द्रीय शैक्षिक प्रशासन को शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। मार्गजिनक सुस्थाओं और स्थानीय शैक्षिक प्रशासन को संविधान ने पर्याप्त शक्ति और अधिकार देने में है, जिसमें केन्द्र प्रशासन निरक्षरता का ख़र्चा नहीं अपना सकता और शिक्षा राज्य के हाथ की कठपुतली बनने में बाध पड़ी है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने प्रसिद्ध लेख 'निबर्ती' (स्वतन्त्रता) में कहा है कि सामान्यतया जब शिक्षा राज्य के हाथ में पड़ी जाती है, तो वह ऐसा माधन बन जाती है जिसमें राज्य नागरिकों को अपनी दृष्ट्यापूर्ण के लिए एक ही राई में डालना प्रारम्भ करता है और फिर अन्त में उन पर निरक्षरता लगीके से शासन करता है। हमारे संविधान ने केन्द्र प्रशासन को शिक्षा के प्रबन्ध करने में निरक्षरता बनने की रोक लगा दी है। दूसरी ओर केन्द्रीयता में शैक्षिक प्रशासन को जो लाभ हो सकते हैं, उन्हें संविधान ने सुरक्षित कर दिया है। संविधान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि केन्द्रीय शैक्षिक प्रशासन बिना निरक्षरता बने हुए राज्य तथा स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करे, उनका नेतृत्व करे, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तम शैक्षिक समस्याओं को हल करे, सारे देश में शैक्षिक प्रयत्नों का समायोजन करे और समस्त शैक्षिक गतिविधियों पर सज्ज रहें।

भारतीय संविधान ने शैक्षिक प्रशासन को विकेंद्रित करने का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसमें स्थानीय सरकार और मार्गजिनक संस्थाओं को शिक्षा सम्बन्धी माधन जुटा कर शिक्षा की व्यवस्था करने का अवसर मिलता है। इसमें हम बात की संभावना उत्पन्न हुई है कि हमारे निर्धन देश में जनता शैक्षिक रूप में जाग्रत हो और शिक्षा के प्रति अपने अनुराग का परिचय दे। साथ ही संविधान ने एक कठिनाई भी उत्पन्न कर दी है। विभिन्न प्रकार की शिक्षा सुस्थाओं को अपनी सूट देकर शिक्षा के क्षेत्र में असहजता पैदा होने की संभावना पैदा कर दी है। यदि स्थानीय सरकारें अपने आप ही केन्द्र प्रशासन का प्रतिनिधि और साथ ही जनता का प्रतिनिधि नहीं समझती तो अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी। शैक्षिक प्रशासन की कार्यकुशलता नष्ट हो जायेगी और स्कूलों तथा विद्यालयों में शिक्षकों के लिए काम चलाना कठिन हो जायेगा।

केन्द्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों का सामंजस्य हमारे शैक्षिक प्रशासन में है। यथामभव दोनों की बुराइयों से बचने और गुणों की अवनति की व्यवस्था संविधान ने की है। हमारे संविधान की मौलिक विशेषता प्रजातांत्रिकता है। इसलिए शैक्षिक प्रशासन में सहयोग, समझौता, स्वेच्छा में काम करने, नेतृत्व करने और उत्तरदायित्व अनुभव करने पर जोर दिया जाता है। अधिकारी और कर्मचारियों में यह ज़रूरी की जाती है कि वे प्रशासन को 'गंभीर' न समझ कर मानवीय सम्बन्धों को स्थापित करने का माध्यम समझें और जर्नालिस्ट का नख सामने रखें। विकेंद्रीकरण द्वारा प्रशासन



और इस देश में अभी भी विभिन्न आर्थिक सम्प्रदाय अपनी भिन्नता बनाये हुए हैं और आजादी के बाद उनके बीच अन्याय की प्रवृत्ति बढ़ी है। शिक्षा का सम्बन्ध धर्म में जुड़ा रहता है। इसलिए वर्तमान प्रजातन्त्रीय सरकार शिक्षा के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता की नीति पर चल रही है और वह शिक्षा के विकेन्द्रीकरण में ही अपना हित देखती है। विभिन्न प्रकार की शिक्षा मन्त्रालयों के प्रशासन में वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

शैक्षिक प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की ओर अग्रसर होने में जो कारण सहायक हुए हैं वे बहुत पवित्र नहीं हैं परन्तु आज हम उन्हें नये उद्भवजन रूप में पेश करना चाहते हैं। स्वयं कांग्रेसी शिक्षा आयोग ने इस बात को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिवेदन में कहा है कि विदेशी शासकों ने १९२१ के ईश शासन नियम तथा १९३७ के प्रान्तीय स्वशासन नियम के द्वारा शिक्षा की जिम्मेदारी प्रान्तों को सौंपने का निर्णय लिया था और वे गैर-सरकारी प्रयत्नों को ही अधिक सहस्व देना चाहते थे। स्वतन्त्र भारत के संविधान ने उस स्थिति में थोड़ा परिवर्तन अवश्य किया है परन्तु इसी अध्याय में अन्यत्र स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा को तीन विभिन्न प्रकार की सूचियों के अन्तर्गत शामिल किया गया है। केन्द्रीय सरकार शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन का भार राज्य तथा स्थानीय सरकारों की माभेदारी और उच्च शिक्षा का भार केन्द्र और राज्यों की माभेदारी पर छोड़ा गया है। यह सब उपेक्षा के प्रतिरूप है परन्तु इस विकेन्द्रीकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

इस विकेन्द्रीकरण का मिडान्त लोकप्रिय हो चला है और हमारे देश के शैक्षिक प्रशासन में इस सिद्धान्त पर अमल करने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। प्रजातान्त्रिक देश, जिसमें जनता हर प्रकार का उत्तरदायित्व स्वेच्छा से उठाना चाहती है क्योंकि राज्यसत्ता जनता में निहित होती है, विकेन्द्रीकरण के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित करते हैं। मनुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जो अग्रगण्य प्रजातन्त्रवादी देश हैं, शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण कर चुके हैं और इसमें उन्हें बहुत लाभ हुआ है। इसी प्रकार रूस और चीन जैसे समाजवादी देश भी शिक्षा के प्रशासन में विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त का व्यवहार कर रहे हैं। इन सभी बड़े और प्रगतिशील देशों में केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा के प्रशासन को छोटी-छोटी प्रशासनिक इकाइयों को सौंप दिया है। इसमें हमारे देश में शैक्षिक योजना, उत्पाद तथा प्रयत्न का स्तर घूट पड़ा है। इसी से उन देशों में निरक्षरता नष्ट हुई और जाशुनि पैदा हुई। विकेन्द्रीकरण की सफलता को देखते हुए भारत के शैक्षिक प्रशासन में उसे अपनाते का प्रयत्न होना स्वाभाविक है।

**विकेन्द्रीकरण के पक्ष में दिये जाने वाले तर्क**

१. भारत एक बहुत बड़ा देश है। उसकी जनसंख्या विधान और विविध प्रकार की है। हमारे देश की शैक्षिक आवश्यकताओं को केन्द्रीय सत्ता समझ नहीं

सकती। थोड़ी देर के लिए मान लें कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय २२ प्रकार की तथा हर स्तर की शिक्षा अपने हाथ में ले ले, तो क्या होगा ? मुद्रर राशियाँ और हर राज्य की स्थानीय उकाश्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना असम्भव हो जायगा। केन्द्रीकरण में ज्ञान यह होती है कि सरकार के अनेक प्रयत्न जना वश्यक और व्यर्थ मिट्ट हो रहे हैं। विकेन्द्रित प्रणाली में २२ स्थानीय इकाई अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था और प्रबन्ध कर सकती हैं।

२ यदि केन्द्रीय सरकार ही सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले, तो सामान्य जनता की मनोभावना यह हो जाती है कि हममें कोई मतलब नहीं है और शिक्षा की सारी व्यवस्था करना सरकार का काम है। वे स्वेच्छा में अपनी मस्तानों की शिक्षा के लिए साधन नहीं जुटाने। इसके विपरीत, यदि शिक्षा की सारी जिम्मेदारी स्थानीय सरकार और मन्त्रालयों को सौंप दी जाती है, तो स्थानीय जनो का उत्साह बढ़ता है। वे स्वयं साधन जुटाने और स्वावलम्बी बनते हैं। विकेन्द्रीकरण का एक लाभ अभी कुछ दिन पहले मद्रास राज्य में देखने को मिला है। शैक्षिक व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों पर छोड़ देने में जायिक नाश्रन बड़ी सरलता से जुटा लिये गए।

३ विकेन्द्रित शैक्षिक प्रणाली में स्थानीय जनो की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रयोग करने तथा स्वतन्त्र शैक्षिक विचारो को कार्यान्वित करने की छूट रहती है। यदि शिक्षा के स्वरूप, पाठ्यक्रम के निर्दिष्ट करने तथा पढ़ाने आदि के काम स्थानीय क्षत्ता पर छोड़ दिए जायें, तो बहुत से नये शैक्षिक नून विकसित होंगे। आचार्य विनोबा भावे ने विकेन्द्रीकरण का जोरदार समर्थन किया है। उनका विचार है कि विकेन्द्रित शैक्षिक प्रणाली में विचारो की स्वतन्त्रता को बढ़ावा देता है।

४ हमारे देश की शिक्षा में अभूतपूर्व विविधता है। अनेक प्रकार की शिक्षा सहाय्य है। उनमें अनेक प्रकार का प्रबन्ध है, विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणालियाँ हैं और विभिन्न शैक्षिक चिन्तन मूल है। विकेन्द्रीकरण से यह विविधता बनी रहेगी और विकसित होगी। इसमें शिक्षा स्वस्थ बनी रहेगी।

५ विकेन्द्रीकरण में वे अनेक दोष दूर हो सकते हैं जो केन्द्रीकरण में उत्पन्न होते हैं, जैसे जालफीताशाही, निर्णय लेने में देरी, मानवीय सम्बन्धो का अभाव तथा केन्द्रमत्ता का शिक्षा पर एकाधिकार और शिक्षा का प्रचार के रूप में दुर्प्रयोग।

**विकेन्द्रीकरण में क्या होता है ?**

विकेन्द्रीकरण के तत्त्व—श्री जी० ई० रास्ट (G. E. Rast) ने अपनी एक पुस्तक 'Co-operative Team-work in Administration' में लिखा है कि शिक्षा के प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण में नई नाने स्पष्ट दृष्टियोंवर होती है, यथा .

१. अफसरो की अपेक्षा कार्य में समझ रहने वाले जनों पर अधिक में अधिक जिम्मेदारी डाल दी जाती है। अफसरो में निदेशक, निरीक्षक और अधीक्षक मोंग आ जाते हैं। कागजी तौर पर प्रशासन के लिए यही मोंग जिम्मेदार माने जाते हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि प्रशासन का काम चलाते वाले वे कर्मचारी हैं, जो शासन के काम में लगे रहते हैं। विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत इन कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व का बोझ डाला जाता है।
२. आम तौर पर प्रशासन में एक के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विकेन्द्रीकरण में यह प्रथा समाप्त करके समान पद वाले कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं ताकि ऊँच-नीच का भाव समाप्त हो और प्रशासन का काम भाई-बारे के आधार पर चले।
३. शिक्षा सम्बन्धी नीति को निर्धारित करने, तत्पश्चात् निर्धारित करने तथा योजना बनाने में अधिक में अधिक उन कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है, जो प्रशासनिक बापों को चमकते हैं।
४. प्रशासन चलाते के लिए विभिन्न देशों के काम छोटे-छोटे दलों को मोंग किए जाते हैं और ये दल निर्णय लेते हैं।
५. प्रशासन के काम में कर्मचारियों को पक्ष-प्रदर्शन देने के लिए विशेष व्यवस्था कर दी जाती है। जहाँ फिटनाइयाँ आनी हैं, वहाँ उन्हें उचित मलाह दी जाती है।

विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने वाले तत्त्व—केवल विज्ञान के रूप में विकेन्द्रीकरण का स्वीकार कर लेने में कुछ नहीं होगा। शैक्षिक प्रशासन में विकेन्द्रीकरण की सफलता कई बातों पर निर्भर है। निम्न स्तरीय कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए और उन्हें अपना कर्तव्य विभागे के लिए तैयार करना चाहिए। अपने दायित्व के प्रति अभिरुचि और प्रेरणा उत्पन्न करना भी आवश्यक है। उन्हें जो भी कार्य दिया जाय, वह उनकी योग्यता तथा सामर्थ्य के अनुकूल होना चाहिए। वे चुनौती का अनुभव करे और सफलतापूर्वक काम कर दिखाने पर उन्हें पुरस्कार देना भी आवश्यक है। यह सभी सम्भव होवा जब उच्चाधिकारी अपनी मनोवृत्ति बदलें। अधिकारियों को उदारतापूर्वक और सहिष्णु बनकर अपने कर्मचारियों के बिपारी और उनकी कमजोरियों को सहन करना चाहिए। उन्हें समूह-मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और प्रशासनिक समूह पर जिम्मेदारी छोड़ने तथा उन्हें शक्ति और सत्ता मोंपने के लिए तैयार रहना चाहिए। विकेन्द्रीकरण की सफलता के लिए यह निम्न आवश्यक है कि स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को जागरूक बनाया जाय। उनमें काम करने की चेनना पैदा की जाय और उन्हें यह बताया जाय कि वे अपने कार्य-क्षेत्र में वर्तमान शैक्षिक माधमों की जानकारी प्राप्त करें और उनका उपयोग करें। उनमें स्वावलम्बन का भाव पैदा किया जाय। समज-





या पचायता से, तथा अनुदान, चंदे और सार्वजनिक आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्ति धन जमा होगा। विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिए अध्यापकों के तबादले बहुत कम कर दिए जाएँगे, सावधानीपूर्वक ही के दोष कम किए जाएँगे।

प्रशासनिक कार्यों के विकेन्द्रीकरण का दूसरा रूप यह होगा कि जिला-स्तर पर ध्यान मिला पूर्ण में जिला स्कूल अधिकारी (District school officer) को मौप दी जाएगी। यह अधिकारी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा। जिला स्कूल अधिकारी मौखिक मामलों में अपने क्षेत्र का नेता होगा। वह मौखिक स्तर, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों, अध्यापकों के हितों—उनके प्रशिक्षण, नियुक्ति, कार्य-स्थिति तथा निरीक्षण—के लिए जिम्मेदार होगा। वह अधिकारी मौखिक-शिक्षण का सफल बनाने के लिए विद्यार्थी शिक्षा की राज्य परिषद् तथा राज्य मूल्यांकन समिति जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग करेगा। इसका प्रमुख कर्तव्य निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण होगा।

कोटारी शिक्षा आयोग ने मौखिक प्रशिक्षण के विकेन्द्रीकरण के लिए ऊपर लिखे गए रूप में एक प्रक्रिया निर्दिष्ट की है। इसके अनुसार सत्ता जिला-स्तर पर बाँट दी जाएगी। आयोग ने विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय पैमाने पर एक कार्यक्रम तय किया है जिसके निम्नलिखित अंग हैं और जिसका लक्ष्य अध्यापकों, छात्रों तथा समाज की प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए तैयार करना है।

(क) स्थायी योजना बनाना—हर स्कूल को अपने विकास तथा उन्नति के लिए एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जो कई चरणों में पूरी की जा सके। इस नियोजन के काम में अध्यापकों, छात्रों और पाम-सहयोग के समाज में पूरी सहायता ली जाय और उनके परामर्श में योजना बने। योजना बनाने में यह ध्यान रखा जाय कि स्थानीय तथा उपलब्ध साधनों का उपयोग हो और यह देखा जाय कि इन साधनों के विकास में पाम-सहयोग के लाभ क्या सहायता कर सकते हैं।

(ख) बुद्धिमत्तापूर्वक आयोजन और प्रयत्न की निरंतरता—विकेन्द्रीकरण में यह आवश्यक है कि योजना बुद्धिमत्ता में बनायी जाय और विकास के लिए जो प्रयत्न हो, उन्हें जारी रखा जाय। विकेन्द्रीकरण प्रशिक्षण में सत्ता एक हाथ में दूसरे हाथ में जाती रहती है। परिवर्तनों में विकास रुक न पड़े, इसका ध्यान रखना आवश्यक है।

(ग) अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन—विकेन्द्रीकरण की सफलता के लिए अधिकारियों के दृष्टिकोण में मौखिक परिवर्तन ज़रूरी है। वे प्रायः तफ़्तीर के फकीर हुआ करते हैं। कुछ तो अपने कार्य के प्रति निष्ठा नहीं रखते। इसलिए इन लोगों में उत्साह और ईमानदारी का भाव उत्पन्न करना होगा।

(घ) प्रशासन में सहोत्साहन और प्रयोग—प्रशिक्षण की जड़ता दूर करना जरूरी है। इसके कारण नये विचार और विचारन गढ़ हो जाते हैं। प्रयोगों की परम्परा इसीलिए समाप्त होनी है। अब प्रशिक्षण के विकेन्द्रीकरण में नियमों की कठोरता को दूर करना होगा और प्रयोगों के लिए छूट देनी होगी।

## विकेन्द्रीकरण में निहित खतरे

विकेन्द्रीकरण में यदि कुछ लाभ है, तो कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं। यदि प्रशासन में उदासीनता और निष्ठा का अभाव नजर आने लगे तो समझने का हिा कि ज्ञानियाँ अधिक होंगी। यदि प्रबंध करने और गान जुटान की जिम्मेदारी स्थानीय ढकाटियों को गीव दी जाय पण्णु उनमें उनम्दायित्व ही भावना नहीं है, तो शिक्षा के लक्ष्य ही पूरे नहीं हो सकने। भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण हुआ है पण्णु देखा यह गया है कि उसमें लाभ नहीं हुआ है, उदाहरण के लिए जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं और पचायतों के नियमन में चलने वाले स्कूलों की दशा अच्छी नहीं है। इन स्कूलों में अध्यापकों को ठीक समय पर और पूरा वेतन नहीं मिल पाता। छात्रों की शिक्षा-बोधा भी अच्छी नहीं होती। इन स्कूलों में केवल निर्धन माना-पिता अपने बच्चों को भेजते हैं और जो सोम धन खर्च करने की क्षमता रखते हैं, वे निजी मन्वाओं में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ साधन जुटाने में असफल रही हैं और आज भी मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य तक हम नहीं पहुच सके हैं।

शिक्षा के विकेन्द्रीकरण में इस बात की सम्भावना है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीयता, जाति भेद, साम्प्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता की वृद्धि हो जाय। इसमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा पड़ने की ढका है। सारे देश में शिक्षा का एक समान स्तर नहीं होगा। साधन सम्पन्न इकाइयाँ अच्छे स्कूल चला सकेगी पर निर्धन इकाइयों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन होगा। प्रशासन का नूप विभिन्न हाथों में चला जाएगा और सारे देश में शैक्षिक सुधारों को एक साथ पूरा करना कठिन होगा। हमारे देश में शैक्षिक सुधार पूरे नहीं हो पाने जिसका कारण विकेन्द्रीकरण भी है।

## भारतीय शैक्षिक प्रशासन में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति

राष्ट्रीयकरण का नारा—समाजवाद और साम्यवाद के दर्शनो से न केवल वाणिज्य और उद्योग की दुनिया प्रभावित हुई है, वरन् शिक्षा पर भी इनका व्यापक प्रभाव पड रहा है। जिस प्रकार बड़े-बड़े उद्योगों और उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण की माँग की जा रही है, उसी प्रकार शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए नारे लगने आरम्भ हो गए हैं। बहुतों में लोगों का विचार है कि विकेन्द्रीकरण में शिक्षा में घोषण की प्रवृत्ति पनप रही है। गान-सत्ता पचायतों और स्थानीय प्रबंध समितियों की भीष देने में निजी मन्वाएँ व्यापारिक रूप ग्रहण कर रही हैं। यह सत्थाएँ मनमानो पौन लेती हैं और अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं देती। इनका प्रशासन ढीला है क्योंकि प्रबंधक राजनीतिक कुचक्र में फँसे रहते हैं। फल यह हुआ है कि व्यापारिक मन्वा की भाँति अध्यापकों और छात्रों के मध्य उपद्रव और हठता का महारो नैकर प्रशासन को चुनौती देने लगे हैं। इन मन्वा तथा कई शिक्षाविदों की ओर से शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की माँग की जा रही है।

शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का एक पहलू यह है कि शिक्षा के प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी भारत की केन्द्रीय सरकार ने। शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने, अध्यापकों की आर्थिक दशा सुधारने और अनुशासनहीनता को दूर करने में इसमें सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त आजादी के बाद अब तक जिनने भी शिक्षा-आयोग और शिक्षा-समितियाँ बंटीं उन्होंने बहुत से सुधारों की मसुदों दी परन्तु उनका कार्यान्वित नहीं किया जा सका। केन्द्रीकरण से सुधारों का काम सरल हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण के लिए केन्द्रीकरण एक प्रकार में आवश्यक बन जाता है।

केन्द्रीकरण की माँग—इधर पिछले कुछ वर्षों में यह निरन्तर अनुभव किया जा रहा है कि शिक्षा का विषय राज्यों के सुपुर्व कर देने में अव्यवस्था बढ़ी है और बहुत-सी बुराइयों पर निदग्ध नही हो पाता। शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की साझेदारी में निवाही जानी है और फल यह हो रहा है कि शिक्षा की ओर में हर स्तर की सरकार उदासीन है। शिक्षा में समायोजन की समस्या का बहुत कुछ कारण यही है कि शिक्षा का केन्द्रीकरण नहीं हुआ है। भारत विदेशी सरकारों द्वारा, विशेष रूप में हम में शैक्षिक प्रशासन के केन्द्रीकृत स्वरूप का अध्ययन करके अनुभव कर रहा है कि शिक्षा की तीव्र प्रगति के लिए केन्द्रीकरण आवश्यक है।

केन्द्रीकरण के लाभों की चर्चा करते हुए श्री एम० एन० मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'Administration of Education in India' में कहा है कि केन्द्रीकरण में सारे देश में एक समान शैक्षिक प्रगति सम्भव होगी, शैक्षिक प्रयत्नों में समायोजन होगा, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले शैक्षिक प्रयासों में व्यर्थ दुहराए जाने (Over-lapping) की आशंका न रहेगी। केन्द्र राष्ट्र की शैक्षिक आवश्यकताओं पर पूरी तरह रज्य सरकारों में समर्थ होगा और जहाँ कमी होगी, वहाँ आर्थिक सहायता देगा।

श्री एम० एन० मुकर्जी ने बताया है कि केन्द्रीकरण कई क्षेत्रों में उपयोगी होगा। क्षेत्र है—व्यक्तियों और राज्यों में वर्तमान असमानताओं को दूर करके बराबरी लाने का क्षेत्र, सूचना सेवाओं का संगठन और सूचना का वितरण तथा सूचना का एकत्रीकरण और प्रकाशन, सहयोगपूर्ण रूप से, साथ कार्य चलाया, शैक्षिक प्रयत्नों के सुधार और विकास में नैतिक प्रदान करना, उच्च-शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अन्तरराष्ट्रीय शैक्षिक सम्बन्ध (पृष्ठ २३)।

भारतीय प्रशासन में केन्द्रीकरण की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति—प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने भारतीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका—'Educational Quarterly', में प्रकाशित (दिसम्बर १९६६) के एक लेख में कहा है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय लगातार शैक्षिक मामलों में अगुआ बन रहा है और यह शैक्षिक मामलों के विवेचन, हल निकालने, नीति निर्दिष्ट करने में राज्यों तथा स्थानीय सरकारों को मार्गदर्शन दे रहा है। यह केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रमाण है।

वास्तव में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारतीय शैक्षिक प्रशासन केन्द्रीकरण

की जाय अवसर हासिल होना है। इसके कई कारण हैं। एक तो बंगलादेश की आर्थिक स्थिति गुरुकुल शासन से राज्य सरकारों को उनका मुँह लाटना पड़ा है। दूसरा, जनमानस और शिक्षाविदों के आग्रह से बंगलादेश की राजकीय शिक्षा में बड़ी है। डॉ० हो० राम० दत्ता ने जून १९६० में 'Varying Role of the Government of India in Education' में लिखा है कि १९६० के पश्चात् विदेशी प्रायश्चित्त से मुक्ति पान पर गिना में केन्द्रीय राजीब और बाबा की प्रतिक्रिया और उद्गार देने में बाधा है और शिक्षा में बंगलादेश का यह भाव मना एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। शिक्षा में केन्द्र की राजीब का एक प्रमाण पञ्चवर्षीय योजनाओं में मिलता है। नीगरी पञ्चवर्षीय योजना में कहा गया है "अन्तर्गत मनुष्य मर्दान में अत्यन्त है।" "मनुष्य पर (अर्थात् उनको शिक्षा में) पूर्ण विनियोग, भौतिक योजनाओं पर धन खर्च करने की अपेक्षा बड़ी अधिक महत्वपूर्ण है।"

केन्द्रीय प्रशासन के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति कई प्रकार में प्रकट होती है।

(१) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का विकास— १९०० में पूर्व अंग्रेजों ने बंगला को ही शिक्षा का विभाग नहीं माना था। मार्च कमेन्स ने १९०१ में डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन का पद नियमित किया जो आज के शिक्षा-मंत्रालय का बोज़ बन गया। मई १९१० में केन्द्र में शिक्षा-विभाग स्थापित हुआ और गवर्नर जनरल की कार्यवाहियों समिति का एक सदस्य शिक्षा का उत्तरदायित्व संभालने लगा। डायरेक्टर जनरल का स्थान सम्पन्न कर दिया गया। मई १९१५ में दुबारा डायरेक्टर जनरल का पद उत्पन्न किया गया। इस बार इसे एजुकेशन कमिशनर का नाम दिया गया। कुछ समय बाद शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग के साथ मिला दिया गया। यह स्थिति मई १९६५ तक रही। मई १९६७ में आजादी के बाद शिक्षा-मंत्रालय बन गया। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के चारु होने पर इसे शिक्षा तथा वैज्ञानिक सोध मंत्रालय का नाम दिया गया। मौलाना अब्दुलकलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा-मन्त्री थे। मई १९५८ में उनकी मृत्यु होने पर शिक्षा-मंत्रालय की दो शाखाएँ बना दी गयीं। एक है, शिक्षा-मंत्रालय और दूसरा है, वैज्ञानिक सोध और सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय। इस समय शिक्षा-मंत्रालय के यह दोनों पक्ष शिक्षा के प्रवर्ध में अधिकाधिक दिव्यचम्पी ले रहे हैं।

(२) केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री और नियंत्रक संस्थाओं का विकास— प्रशासकीय दृष्टि से शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य चलाने, सम्बन्धित इकाइयों को परामर्श देने तथा नियंत्रण रखने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय ने अनेक सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं की स्थापना की है। इनकी क्रिया-विधि में केन्द्रीय शिक्षा-प्रशासन की क्षमता में वृद्धि हुई है। यह शिक्षा-संस्थाएँ हैं—

(क) मन्दल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन,

(ख) यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन,

(ग) जाल इंडिया कोन्सिल फॉर एपीमेन्ट्री एजुकेशन,



देकर, धूनेम्को में सम्पर्क करके और मधीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसारण चलाकर केन्द्रीय शैक्षिक प्रसारण 'केन्द्रीकरण' की प्रवृत्ति का परिचय देता है।

(४) मधीय क्षेत्र में केन्द्रीय प्रशासन का शिक्षा पर आधिपत्य—केन्द्रीय शैक्षिक प्रसारण भारत के कई क्षेत्रों में मीधे शिक्षा की व्यवस्था करता है। वे क्षेत्र हैं—अडमान, निकोबार, नकादीव, मिनीकोय, मणीपुर, त्रिपुरा, नेफा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पाण्डिचेरी और दिल्ली के क्षेत्र। आँकड़ों में यह सिद्ध होता है कि केन्द्रीय शैक्षिक प्रशासन पर इन क्षेत्रों की शिक्षा की जिम्मेदारी होने में यह क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रगति कर गये हैं। इसके कारण बहुत से लोगों का विचार है कि शैक्षिक प्रसारण का केन्द्रीकरण हो जाने में शिक्षा की दशा सुधरेगी।

(५) केन्द्रीय अनुदान द्वारा नियन्त्रण—शैक्षिक प्रसारण में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति इस बात में लक्षित होती है कि केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता के लिए राज्यों और स्थानीय इकाइयों को केन्द्र का मुँह नाकना पड़ता है। आजादी के बाद में केन्द्र की आर्थिक क्षमता बहुत बढ़ गयी है और समुक्त राज्य अमेरिका की मधीय सरकार की भाँति शिक्षा के हर स्तर, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, वैज्ञानिक तथा सामाजिक, पर स्थानीय सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस सहायता में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है क्योंकि मधीय सरकार मविधान को सीमा-रेखा को लाँघकर प्रत्यक्ष रूप में राज्यों के शैक्षिक प्रसारण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती परन्तु आर्थिक अनुदान देकर वह राज्यों तथा स्थानीय इकाइयों को शैक्षिक गतिविधि पर परोक्ष रूप में नियन्त्रण रखने को इच्छुक है। बहुत से मामलों में स्थानीय तथा राज्य सरकारें शैक्षिक निर्णय केवल केन्द्र के मकेत पर लेती हैं और अनिच्छापूर्वक केन्द्र की इच्छापूर्ति करने को बाध्य होती हैं। धनभाव के कारण राज्य सरकारें बहुत सी योजनाओं को नहीं चला सकती हैं। इस आर्थिक नियन्त्रण के कारण केन्द्रीकरण में वृद्धि सम्भव हो गयी है। हर क्षेत्र में केन्द्र सरकार ५० प्रतिशत में कम अनुदान नहीं देती। उद्योग-उद्योग इस प्रतिमान में वृद्धि होती जाती है, केन्द्रीकरण बढ़ता जाता है।

(६) अखिल भारतीय शिक्षा-सेवा की वस्तुना—केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री श्री छागला शिक्षा में सुधार करना चाहते थे और उन्होंने यह अनुभव किया कि सुधारों में देरी का कारण यह है कि केन्द्र को शिक्षा के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मविधान में नहीं दिया है। इसका एक प्रभाव यह भी है कि शैक्षिक प्रसारण में अपेक्षित चुम्बी नहीं रहती। बहुत कुछ विचार करने के उपरान्त उन्होंने अखिल भारतीय शिक्षा-सेवा (All India Educational Service) लागू करने का निश्चय किया। इस सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर केन्द्र सरकार का नियन्त्रण होगा। इस प्रकार से सेवा केन्द्रीकरण में सहायक होगी। इस सेवा के अन्तर्गत वे सभी शैक्षिक अधिकारी और कर्मचारी होंगे जो शिक्षा-मन्त्रालय और

केन्द्रीय क्षेत्रों में काम करते हैं और साथ ही राज्यों तथा जिला-स्तरीय पर काम करने वाले वे अधिकारी और कर्मचारी होंगे जो राज्यों में अभी वेतन पाते हैं। इस प्रकार राज्यों के शिक्षा-निदेशक, उपशिक्षा निदेशक, जिला-विद्यालय निरीक्षक और सरकारी विद्यालयों के प्रिन्सिपल और प्रधानाध्यापक भी केन्द्रीय स्तर के प्रशासनिक नियन्त्रण में आ जायेंगे। यह सब केन्द्रीकरण में सहायक होगा। अभी तक इन अखिल भारतीय शिक्षा-सेवा का भविष्य अन्धकारमय है क्योंकि राज्यों ने इस चलाने की सहमति नहीं दी है। श्री छागला का स्वप्न पूरा नहीं हो पाया यद्यपि कांठारी शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस प्रकार की सेवा को लागू करने की मस्तुति दी है।

(७) कोठारी शिक्षा-आयोग द्वारा प्रस्तावित मेसनरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन—उच्च-शिक्षा पर केन्द्र का पर्याप्त नियन्त्रण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हो गया है। माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा पर नियन्त्रण रखने के लिए, कोठारी आयोग ने मेसनरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की है। यह बोर्ड विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों तथा स्थानीय सरकारों का परामर्श देगा, उनके प्रयत्नों में समायोजन, शैक्षिक विभागों के आदान-प्रदान और मूचना के प्रसारण में सहायक होगा। यह शिक्षा-स्तर को स्थिर करने, उसमें परिवर्तन करने, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-विधियों के विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इस पर केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का अधिकार होगा। इस बोर्ड में शिक्षा मन्त्रालय, मेसनरी बोर्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य-शिक्षा परिषदों के अध्यक्ष, तथा वरिष्ठ माध्यमिक तथा प्राथमिक अध्यापक शामिल होंगे। यह बोर्ड स्पष्ट रूप से केन्द्रीय शैक्षिक प्रशासन की शक्ति में वृद्धि करेगा और शिक्षा के केन्द्रीकरण में सहायक होगा।

## भारतीय शैक्षिक प्रशासन में अमानवीयता

### अमानवीयता की उद्भावना

श्री मध्यमेन एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद् हैं और वे काफी लम्बे अर्से तक शिक्षा-मन्त्रालय में शिक्षा-सचिव एवं भारत-सरकार के शैक्षिक महाद्वार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक 'एजुकेशनल रीकान्स्ट्रक्शन' के एक अध्याय में लिखा है कि प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए मैंने अनुभव किया है कि सारे प्रशासन को एक निर्जीव मशीन की तरह चलाया जा रहा है। शैक्षिक प्रशासन में यह हजारों अधिकारी और कर्मचारी निर्जीव पुर्जों की तरह उस मशीन में फिट हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि मानवीयता नष्ट हो गयी है। शिक्षाविचारियों और कर्मचारियों की मनोभावनाओं और उनके पारस्परिक मानवीय सम्बन्ध का कोई महत्त्व नहीं रह गया। दफ्तर की फाइलें और नियमावली के आगे मनुष्य विद्यमान है और उनकी जगह बन्द है। प्रशासन के हर निम्ब में यह नियम और पद्धति बाँपती हैं और

मनुष्य के दुःख-दुःख का कोई भी समाधान-विधान प्रभावशाली नहीं रहता। मनुष्य में यही 'अमानवीयता' है।

श्री० लाल० लाल० दिवकर ने मौखिक प्रवचन पर आधारित एक मास्टी में पढ़े गये ज्ञान एक लेख में कहा था "एक वक्ता के माया का विचार है कि किसी भी प्रकार का प्रभावशाली एक करता है। विचार का मैं अब हृदय पर स्वीकार करने है कि प्रभावशाली एक समूह या मनुष्यों के समूह में चलता है, न कि प्रभावशाली विचार का अंग्रेजी कला भी कहना होगा। मनुष्यों के माय सम्बन्धों का निर्धारण यात्रिक दृष्टि में नहीं हो सकता। सम्बन्धों का निर्धारण धन, पुनर्जात और मायवादी में किया जाना चाहिए। उसमें निर्ममता या कठोरता का कोई स्थान नहीं है।" दुर्भाग्य में हमारे मौखिक प्रभावशाली में मानवीय सम्बन्धों की उद्देश्य निर्धारण बढ़ती जा रही है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा मौखिक प्रभावशाली 'मानव-वैज्ञानिक' न बनकर फाइन-केंद्रित बनता जा रहा है। मध्यम मध्य में, अमानवीयता इनकी अधिक बढ़ती जा रही है कि कार्यालयों में अधिकारी जन इस मामले को नियंत्रण और फाइन के आधार पर नियंत्रण है और ज्ञान ज्ञान के कर्मचारियों को व्यक्तिगत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते। प्रसिद्ध जेम्स प्रभावशाली ग्रहण बावकोर ने कहा था कि मौखिक प्रभावशाली का उद्देश्य उच्चतम छात्रों को उच्चतम शिक्षा, उच्चतम अध्यापकों में राज्य की अधिक क्षमता के भोजन, इस प्रकार दिखाना है कि वे शिक्षा में अधिक में अधिक लाभ उठा सकें। इस उद्देश्य को पूर्ण अमानवीयता के कारण नष्ट हो गयी है।

यह अमानवीयता धीरे-धीरे व्यापक होती जा रही है। स्कूलों के प्रभावशाली में प्रधानाध्यापक, अध्यापक और छात्रों के सम्बन्ध, कार्यालयों में निरीक्षक, कर्मचारी तथा अधिकारियों के सम्बन्ध, मन्त्रालय और सचिवालयों में मंत्री महोदय और कार्यरत उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध— इन सब पर दृष्टिगत करने में यह पता चलता है कि विशेषज्ञता और अधिकार, दम्भ और श्रेष्ठता के भाव इनमें प्रबल हो गये हैं कि मानवीयता की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। विशेषज्ञों ने अपने मकुचित दापों में बन्द रहकर निर्णय लेना आरम्भ कर दिया है जिसमें लान्छनीताभाही बढ़ी है। विशेषज्ञता के भय में वरत कर्मचारीगण निर्णय लेने में प्रवृत्त हैं जिसमें समस्याओं को गुनगुनाने में देरी होती है। निर्भीकतापूर्वक जिम्मेदारी का निर्वाह करने की प्रवृत्ति नष्ट होती जा रही है। इसी में अमानवीयता का रोग मौखिक प्रभावशाली की जड़ों को निर्णय बना रहा है।

### अमानवीयता की उत्पत्ति के कारण

भारतीय मौखिक प्रभावशाली में अमानवीयता के उत्पन्न होने के कुछ ऐतिहासिक . . . है। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में कुछ परम्पराएँ डाल दी थीं। उनमें से एक परम्परा यह थी कि उन्होंने स्तर क्रम में अधिकारियों की नियुक्ति की थी और







९. उपरदायित्व का निर्वाह करने को तैयार रहना, मोघ निर्णय लेना, और परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना ।
७. अभिमानपूर्ण होना और मठयोग देने तथा मेने के लिए तैयार रहना ।
८. शायदशक्ति को याविक न बनने देना—इसके लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित आदेशों को न भेजकर व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा बनाया जाय, दूसरों की रिपोर्टों और अंकड़ों पर विश्वास न करके अपनी आँखों से देखकर विश्वास किया जाय । कल का कत्ता न होना ।
६. अपनी मजबूती के लिए दूसरों को न कुचलना ।
१०. सभी कर्मचारियों को समान समझना, किसी का पक्षपात न करना और समान भाव देना ।
११. नेतृत्व करने की योग्यता—अधीनस्थ जनता की प्रशंसा देना, उनकी टाँस तथा धारावाहिक मुभाज देना, उनके साथ समान स्तर पर मिलना, पूछने पर हर बात की व्याख्या करना, समूह की प्रवृत्तियों की समझना और मनोवृत्तियों के निदानों की जानकारी ।

मौखिक प्रशासन में अधिकाधिक प्रज्ञानाधिक विचारधारा का समावेश आवश्यक है। मौखिक प्रशासक का वर्तमान समय में केवल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों वरन् अध्यापकों, छात्रों और अभिभावकों तथा समाज का महारा लेना पड़ता है। यदि वह मानवीय भावों की उपेक्षा करता है तो प्रशासन-कार्य में उसे कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रकाशित एक नया पुस्तिका 'Leadership in Educational Administration' में बिना भाषक ने कहा है कि प्रशासक को अपने दफ्तर के बंद कमरे में बैठकर भव काम नहीं करना है। उसे शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों और योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं और मनोवृत्तियों की समझना होगा और इसके लिए उनके साथ रहना होगा। भारत के प्राचीन समाज का समझना विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि आम तौर पर लोगों की मर्यादा के बीच ऐसे प्रशासक लोगों के प्रति महानुभूति नहीं रखते। इस प्रवृत्ति को दूर करके ही प्रशासक अपने में मानवता उत्पन्न कर सकते हैं।

### मौखिक प्रशासन में समायोजन की समस्या

समायोजन की समस्या का स्वरूप—हमारा देश बहुत बड़ा है और उसके सारे क्षेत्र में बसने वाले ५० करोड़ मनुष्यों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध राज्य की विद्यालय के रूप में करना है परन्तु समुक्त राज्य अमरीका की भाँति हमारे देश की सरकार बहुत साधन-सम्पन्न नहीं है। धनभाव के कारण वह पूर्णरूप से शिक्षा का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं ले पाती। इसलिए, उमने मार्बेनिक तथा व्यक्तिगत गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के हाथों में शिक्षा का प्रबन्ध मौज रखा है। प्रज्ञानाधिक



हैं : यह तीन सरकारें हैं—केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकाय । शिक्षा के प्रशासन में इन तीनों की पारस्परिक साझेदारी और अलग-अलग मार्वाजनिक मस्याओं की साझेदारी में काम चलता है । हम सभी जानते हैं कि साझेदारी ममायोजन की शक्त है । उस प्रणालिकीय साझेदारी ने ममायोजन पर कुठाराघात किया है ।

शिक्षा का नियन्त्रण अकेले केन्द्रीय और राज्यीय शिक्षा विभागों के हाव में होता, वो भी थोड़ा ममायोजन रहता । भारत में स्थिति यह है कि अनेक सरकारी विभाग शिक्षा मस्याएँ चलाते हैं । कहने को शिक्षा मन्त्रालय है परन्तु उसका अन्य मन्त्रालयों और विभागों की शैक्षिक गतिविधियों पर कोई नियन्त्रण नहीं । रेलवे का केन्द्रीय विभाग सारे भारत में अपने कर्मचारियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय चलाता है । कृषि विभाग की ओर से कई उच्च शिक्षा मस्याएँ चलाई जा रही हैं । थम और उद्योग विभाग ने माध्यमिक स्तर पर छात्रों की व्यावसायिक कठिनाइयाँ हल करने के लिए बहुत-से व्यावसायिक स्कूल खोल रके हैं । आज भारतीय शैक्षिक प्रशासन अन्तरविभागीय विषय बन गया है और हर विभाग अलग-अलग व्यवस्था करता है । उनके बीच परस्पर बार्ता या विचार-विमर्श न होने से ममायोजन का अभाव होना स्वाभाविक है ।

शिक्षा की विभिन्न मस्याएँ विभिन्न उद्देश्यों से शिक्षा की व्यवस्था करती है । उनमें पुस्तकालय, कस्यान मेवाएँ, विकास खड, बडे-बडे औद्योगिक सस्थान, रेडियो, फ़िल्म तथा अन्य शिक्षा सगठन प्रमुख हैं । इनकी कार्य-प्रणाली अलग है और उनके मूल्य अलग हैं । यह विभिन्नता ममायोजन के मार्ग में बाधक है ।

अब शिक्षा के स्वरूप को लीजिए । सामान्य शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरों पर बँटी है । विधेय शिक्षा के कई स्वरूप हैं, जैसे तकनीकी शिक्षा, शोध, चिकित्सा, व्यावसायिक, सामाजिक, इजीनिपरिग तथा कला की शिक्षा । स्त्रियों, बालकों, शिशुओं, विकलांगों और अल्पकुटि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था अलग है । शिक्षा के विभिन्न मस्याओं के अनुसार नाना प्रकार के विद्यालय भारत में देखने को मिलेंगे, जैसे व्यावसायिक स्कूल, औद्योगिक स्कूल, पॉलीटेक्नीक पढिका स्कूल, संनिक स्कूल, भारतीय पद्धति पर चलने वाले पुराने ढग के स्कूल आदि । उच्च स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, मस्टुन विश्वविद्यालय जैसी सस्थाएँ हैं । इन विविध प्रकार की सस्थाओं के प्रशासन में ममायोजन का होना एक दुष्कर कार्य है, विधेय रूप से तब, जबकि शिक्षा का प्रशासन किसी एक मत्ता के हाथ में नहीं है ।

ममायोजन उत्पन्न करने के उपाय—पिछले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री छागला ने भारतीय शैक्षिक प्रशासन में ममायोजन की कमी अनुभव की और हम दिना में कुछ कदम उठाने का निश्चय किया, जिनमें अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का प्रस्ताव प्रमुख है । यद्यपि अभी तक हम सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो सका है, पर यदि



व्यक्ति और मंगलन को अपनी विचारधारा के अनुसार शिक्षा मन्त्रालयें चलाने की स्वतन्त्रता का अधिकार दे दिया है। इसके फलस्वरूप सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ धार्मिक, साम्प्रदायिक मण्डलों तथा अनेक सुदृढ़ स्वार्थों में प्रेरित जन मन्त्रालयें चलाने ली हैं। इनमें देश की भावनात्मक एकता को हानि पहुँच रही है और शिक्षा का स्तर तो गिरता ही है, समायोजन का काम कठिन हो रहा है। मन्त्रालय इन मन्त्रालयों को हस्तगत नहीं कर सकती क्योंकि सविधान ने उनके हाथ बाँध रखे हैं। कौटिली शिक्षा आयोग ने विद्यालयों में एकरूपता लाने तथा उन पर सरकारी नियन्त्रण लाने के कुछ उपयोगी सुझाव दिये हैं। उनमें से 'सामान्य स्कूल' (Common School) की स्थापना प्रमुख है। यह 'सामान्य स्कूल' सरकारी होगा और इसका शिक्षण स्तर, अध्यापकों के वेतनक्रम, उनकी योग्यता, काम करने की दशा, प्रवृत्ति आदि भारत में एक-व्यमान होगी। इनमें शिक्षा की उत्तमता 'उच्च कोटि की होगी जिसमें गरीब लोगों के बालकों को बढ़िया शिक्षा मिलेगी और अमीर लोगों को भी अपने बच्चों को विशेष स्कूलों में भेजने की आवश्यकता न रह जाएगी। फल यह होगा कि 'पब्लिक स्कूल' जैसी सम्झाएँ अपने आप नष्ट हो जाएँगी और विद्यालयों में एकरूपता आ जाएगी। यह भी कहा गया है कि धीरे-धीरे माध्यमिक स्तर तक शिक्षा मुक्त समाप्त कर दिया जाय। यदि ऐसा हो जाता है तो प्राइवेट मन्त्रालयें जो व्यावसायिक, धार्मिक और साम्प्रदायिक आधारों पर चल रही हैं, खड़ी नहीं रह सकेंगी क्योंकि शिक्षा मुक्त के समाप्त होते ही, वे स्वयं का बोझ न सम्हाल सकेंगी। वे स्वयं ही सरकार के अधीन हो जाएँगी, जो भी मन्त्रालयें बच जाएँगी उन पर सरकार प्रवृत्ति ममिति, मुक्त के निर्धारण, अनुदान, निरीक्षण और पत्र-व्यवहार द्वारा नियन्त्रण रखेगी। इस प्रकार सरकार के अप्रत्यक्ष नियन्त्रण में शैक्षिक प्रशासन में समायोजन करने बन जायगा।

इसी अध्याय में हम अन्यत्र बता आये हैं कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय की कई शाखाएँ हैं, जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण रखती हैं। वास्तव में यह विभाग और शाखाएँ जैसे प्रारम्भिक और बुनियादी शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, यूनेस्को और उच्च शिक्षा विभाग तथा सामाजिक शिक्षा और समाज-कल्याण विभाग आदि समायोजन के कार्य में सहायक हैं। इनके अतिरिक्त अब तक अनेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं का विकास हो चुका है जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन का काम करती हैं। इन संस्थाओं में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल कॉमिनिटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग और नेशनल काउंसिल ऑफ माइंटल एण्ड टेक्निकल रिसर्च प्रमुख हैं। इनके सम्बन्ध में पहले ही लिखा आ चुका है। इन संस्थाओं और विभागों द्वारा शिक्षा की समस्याएँ विविधियों पर नज़र रखी जाती है और परामर्श द्वारा शैक्षिक प्रयत्नों में समायोजन स्थापित किया जाता है।

इधर शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली अनियमितता की ओर लोक सभा का ध्यान आकर्षित हुआ। पिछले वर्ष एक सम्मानित लोक सभा सदस्य श्री लक्ष्मीनन्द मिश्र ने लोक सभा में सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की उत्तरदायित्व शून्य माफ़ेदारी के कारण शिक्षा का अपार अहित हो रहा है। इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाय। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की माँग की गयी। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर देने में केन्द्रीय रक्षक प्रशासन की शक्ति बड़ सकती है और इसमें रक्षक प्रशासन में समायोजन करना सरल बन सकता है। गुरु समिति ने इस सम्बन्ध में विचार करने के बाद अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यदि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को केन्द्र प्रशासन अपने हाथ में नहीं ले सकता, तो उच्च शिक्षा को तो समवर्ती सूची में शामिल करके अवश्य ही केन्द्रीय प्रशासन अर्थात् अधिकार में ले, तभी उच्च शिक्षा के प्रयत्नों में समायोजन सम्भव हो सकेगा।

रक्षक समायोजन का एक उपाय यह बताया गया है कि सारे रक्षक प्रयत्न नियोजन के आधार पर किए जायें। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के कार्यक्रम के लिए विचार प्रस्तुत किए जाते हैं परन्तु मुचाक रूप में रक्षक नियोजन एक राष्ट्रीय मस्या के स्तर में होना चाहिए। भारत स्थित एसियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकेशनल प्लानिंग नामक मस्या को राष्ट्रीय स्तर पर रक्षक नियोजन का कार्य भार सौंप दिया जाय और यह मस्या हर प्रशासनिक स्तर के लिए पहले में ही कार्य पड़ति, जिम्मेदारी और किये जाने वाले कार्य निश्चित कर दे। योजनाबद्ध रक्षक प्रयत्नों में अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होने पायेगी।

समायोजन के अभाव को दूर करने का एक उपाय यह हो सकता है कि हर पांच वर्ष बाद रक्षक कार्यक्रम का मिहावमोहन करने के लिए एक अलग भारतीय रक्षक सर्वेक्षण किया जाय। यह सर्वेक्षण शिक्षा के सारे क्षेत्रों में हो और एक ही मस्या या समिति जो शिक्षा आयोग या अध्ययन दल के रूप में हो, इस काम को करे। सर्वेक्षण के लिए हर क्षेत्र के लिए छोटे-छोटे अध्ययन दल (Study teams) बना दी जायें और सर्वेक्षण का कार्य शीघ्रता में कर लिया जाय। इसमें यह पता चल जायगा कि कहीं रक्षक प्रयत्नों की बरबादी (अव्यय) और कहीं अवरोधन है, कहीं प्रयत्नों की विविधता और कहीं तुरन्त प्रशासन द्वारा कदम उठाने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण द्वारा समायोजन का काम सुविधापूर्वक चलाया जा सकता है।

समायोजन के काम को प्रशासनिक स्तर पर सम्भर बनाने के लिए एक विचार यह प्रस्तुत किया गया है कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का पुनर्गठन किया जाय। इसके कार्यक्षेत्रों की भर्ती विभिन्न राज्यों में भी जाय। पंचम प्रतिपाद कमचारी राज्य के शिक्षा मन्त्रालय में ले लिये जायें और मोप की भर्ती मन्त्रालय



इच्छानुसार करें। विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ने से शिक्षा मन्त्रालय की राज्यों के शैक्षिक प्रशासन की जानकारी बनी रहेगी और ममायोजन का कार्य मन्त्रता में चल सकेगा।

## नियन्त्रण और निरीक्षण की समस्या

### समस्या का स्वरूप

भारत में शैक्षिक प्रशासन की अटिलता अनेक प्रकार की धार्मिक, मास्तुनिक और साम्प्रदायिक शिक्षा संस्थाओं की वर्तमानता और प्रबन्ध की विविधता के कारण शैक्षिक स्तर के गिरने की संभावना निरन्तर बनी रहती है। ऐसी अनेक संस्थाएँ हैं जिनका प्रबन्ध मार्बजिनिक हाथों में है। उन्हें सरकार में अनुदान मिलता है और हम बात की सम्भावना हो सकती है कि सरकारी धन का दुग्पयोग हो। इसलिये शिक्षा संस्थाओं पर नियन्त्रण और उनके शैक्षिक कार्यक्रम का निरीक्षण आवश्यक है। हम कार्य को पूरा करने के लिए राज्यों के शिक्षा विभाग द्वारा हर जिले में विद्यालय निरीक्षक नियुक्त किये जाते हैं। यह अधिकारी अपने क्षेत्र की सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के शिक्षण-स्तर, अध्यापकों की योग्यता और कार्यदमाओं, विद्यालय भवन और साज-सज्जा, सरकारी तथा मुक्त में प्राप्त धन के उपयोग आदि की जांच एक निश्चित अवधि पर करता है। जांच करने के उपरान्त वह अपना प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को भेज देता है और शिक्षा विभाग उस प्रतिवेदन के आधार पर संस्थाओं को चेतावनी देता है, उनका अनुदान घटाता-बढ़ता है। इसके अतिरिक्त वह समय-समय पर अपने कार्यालय द्वारा इन शिक्षा संस्थाओं से पत्र-व्यवहार द्वारा अनेक सूचनाएँ एकत्र करता है और राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गये आदेशों का पालन करवाता है। इस प्रकार जिला विद्यालय निरीक्षक अनेक क्षेत्र में नियन्त्रण और निरीक्षण का कार्य पूरा करता है। अपनी महायता के लिए वह अपने अधीनस्थ उप-जिला विद्यालय निरीक्षकों और कर्मचारियों का उपयोग करता है।

नियन्त्रण और निरीक्षण का यह कार्य विभिन्न प्रकार में पूरा किया जाता है। पंचम जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर एक अनुभवी व्यक्ति ही नियुक्त किया जाता

भावना का अभाव है। हम बात का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का नेतृत्व करने में असफल रहते हैं। विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में जब वे जांच निरीक्षण करने जाते हैं, तो उनका दृष्टिकोण यह नहीं होता कि वे संस्थाओं की सहायता करेंगे वरन् वे द्विद्वान्धेपी होते हैं। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और प्रशानाचार्यों तथा प्रबन्ध-समितियों को बातकिन करने में गौरव समझते हैं। निरीक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि निरीक्षक के आगमन को विद्यालय में

‘मैत्राट’ का आगमन समझा जाता है। उसके आगमन की सूचना पहले क्षेत्र की जाती है और संस्थाएँ जो वर्ष भर कभी नहीं करती, उसे दो दिनों के लिए करके भूटे प्रदर्शन की तैयारी कर लेती हैं। निरीक्षक महोदय विद्यालयों में चलने वाले सभी भ्रष्टाचारों में अवगत होने है परन्तु वे शिक्षा विभाग को दिग्वाने के लिए विद्यालयों की नकली मज-धज की सूचना देने हैं। अपने निरीक्षण के समय उन्हें कोई वृष्टि न दिखाई पड़े, इस बात का प्रबन्ध वे पहले में कर लेते हैं। कुछ निरीक्षकों में पेशेवर नैतिकता का इतना अभाव होता है कि वे निरीक्षण को केवल मना बनाने का माध्यम बना लेते हैं। कुछ निरीक्षण को ‘पिकनिक’ का रूप दे देते हैं। वे दो दिन के लिए किसी विद्यालय में जा पहुँचते हैं और वहीं ठहरते हैं। इस समय प्रधानाध्यापक और अध्यापक उनकी ‘हर प्रकार में सेवा’ करते हैं। यह है निरीक्षण और नियन्त्रण का स्वरूप।

मुद्रालय सामाजिक शिक्षा-आयोग ने नियन्त्रण और निरीक्षण की समस्या पर विस्तार में विचार किया है और इस मन्दर्भ में उस आयोग द्वारा प्रकट किये गये विचारों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। आयोग के मन में

(१) वास्तविक निरीक्षण नहीं होना। उसके स्थान पर पत्र-व्यवहार और आँकड़ों को एकत्र करके मन्त्रोप कर लिया जाता है। जिना विद्यालय निरीक्षक आम तौर में अपने कार्यालय में व्यस्त रहता है और विद्यालयों के कार्य की जानकारी स्वयं प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता है।

(२) वास्तविक निरीक्षण केवल दो-तीन में दिन कर लिया जाता है। यह निरीक्षण केवल औपचारिक होता है क्योंकि यह निरीक्षण आकस्मिक न होकर पूर्व सूचित होता है। निरीक्षक कक्षाओं में चलने वाले शिक्षण कार्य को देख कर टिप्पणी देता है। केवल हिमाव-किताब की जाँच अच्छी तरह होती है। शिक्षण को उत्तमता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यह ज्ञातव्य है कि केवल निरीक्षण के समय ही अध्यापक तैयारी के माय और शिक्षण-कला के सिद्धान्तों के अनुसार पढ़ाते हैं।

(३) निरीक्षक को अनेक संस्थाओं का निरीक्षण करना होता है और वह कार्य में अपने कार्य को पूरा करने में असमर्थ होता है। निरीक्षण में वस्तुनिष्ठता लाने और निरीक्षक का कार्यभार हल्का करने के लिए दलीय निरीक्षण (Panel Inspection) का दग अपनाया जाता है। इसमें एक नयी समस्या यह पँदा हो गई कि निरीक्षक-दल के सभी सदस्य जो प्रायः गैर-सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य और बसिष्ठ अध्यापक होते हैं, ईमानदारी और कर्तव्य-निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। इसमें निरीक्षण का महत्त्व ही समाप्त हो जाता है।

(४) निरीक्षकों में मानवीय गुणों का अभाव होता है। निरीक्षक प्रावधिकता और विनेपजशाही (Technocracy) का अग बनकर अध्यापकों और प्रबन्धकों को वास्तविक कठिनाइयों की अवहेलना कर देता है। वह मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक की भूमिका अदा नहीं करता।

(५) निरीक्षण और नियन्त्रण का एक उद्देश्य यह है कि विद्यालयों में अध्यापकों के साथ प्रबन्धक अभ्यास न करने पाये परन्तु यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। निरीक्षण की प्रमुख समस्या उनकी कानूनी कमजोरी है। निरीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा-विभाग प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता। निरीक्षक अध्यापकों की रक्षा नहीं कर पाता और न सार्वजनिक समस्याओं को नियम-मानन के लिए विवश कर सकता है।

(६) निरीक्षक आम तौर पर केवल शिक्षा निदेशक के परिपत्रों के अनुसार काम करता है और उसी के आदेशों का पालन करने में अपने कर्तव्य की इतिश्री समझता है। उसमें स्वेच्छा तथा अपने निर्णय के अनुसार काम करने, शैक्षिक समस्याओं को हल करने, तथा शोध या प्रयोग करने की प्रवृत्ति नहीं होती। वह 'लाल-फीमावाही' का गुलाम बनता है। इसलिए निरीक्षण और नियन्त्रण प्रभावहीन बन जाता है।

### समस्या-शमन के उपाय

मुद्रानिगर शिक्षा-आयोग ने निरीक्षण की समस्याओं के हल करने के लिए निरीक्षणालय (Inspectorate) के पुनर्गठन की सन्तुष्टि दी है। उसके मत में निरीक्षक

क्षण का कार्य सीपा जा सकता है।

दूसरे, निरीक्षक के कार्यभार को कम करना आवश्यक है। उनकी महायता के लिए विशेषज्ञ सहायकों की नियुक्ति करने में निरीक्षण और नियन्त्रण में सफलता होगी। यदि निरीक्षक कार्यालय और पत्र-व्यवहार के काम से छुट्टी पा जाय तो वह शैक्षिक और विद्वत्तापूर्ण विषयों की ओर अधिक ध्यान दे सकेगा।

तीसरे, निरीक्षण-दलों में शिक्षण-विधियों के विशेषज्ञों को सम्मिलित करना चाहिए ताकि यह विशेषज्ञ विद्यालयों में जाकर प्रत्येक विषय की शिक्षण विधि की जाँच अच्छी तरह कर सकें और अध्यापकों को उचित परामर्श दे सकें।

मुद्रानिगर आयोग ने यह भी बताया है कि निरीक्षकों में कौनसे व्यक्तिगुण

उनके मन पर चोट न पहुँचाये। निष्पक्ष होकर हर पहलू पर वह विचार करे और व्यावहारिक सुझाव देने की योग्यता रखे।

आयोग ने कहा है कि निरीक्षण सर्वाङ्गीण होना चाहिए। विद्यालयों के राज्यों के हर पहलू की जाँच की जानी चाहिए। शिक्षण या कार्यालय के अतिरिक्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान तथा खेल की सुविधाएँ तथा अन्य शैक्षिक प्रियाओं की जाँच करनी चाहिए। आयोग के इस मन के मदर्भ में यह बात देना बहरी है कि राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा 'एन्क्वेस्टन कोड' तैयार किये गये हैं और उनमें निरीक्षण के विषय स्पष्ट निश्चिन कर दिये गये हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के एन्क्वेस्टन कोड में निरीक्षण के निम्नलिखित विषय दिये गये हैं

१. अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता तथा शिक्षण क्षमता।
२. अध्यापन-कार्य के लिए उपकरण एवं व्यवस्था।
३. स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं पाठ्येतर प्रियाएँ।
४. विद्यालयों में अनुशासन।
५. पुस्तकालय को दशा।
६. पाठशाला और छात्रावास के भवन।
७. हर प्रकार के पुष्क की बमूली।
८. विद्यालय की आर्थिक स्थिरता।
९. प्रबन्ध-समिति का विधान।
१०. विद्यालय के रजिस्टर।
११. हिमाव-किताब के रजिस्टर तथा पत्र-व्यवहार की फाइनें।
१२. उपस्थिति के रजिस्टर।
१३. परीक्षा-परिणाम, शिक्षास्तर तथा पाठ्य-विषयों की व्यवस्था।
१४. अध्यापकों के निम्न कार्ड, उनके और प्रबन्ध के राजीनामे के फार्म, उनकी नियुक्ति-वर्त्तास्नयी, नियत बतन-भ्रम के अनुसार बतन की प्राप्ति आदि।

निरीक्षकों को निरीक्षण के समय इस प्रकार की सूची (Schedule) का ध्यान रखना चाहिए। कभी-कभी निरीक्षक को इन तमाम विषयों का आकस्मिक निरीक्षण करना चाहिए ताकि असली स्थिति का पता चल जाय। विद्यालयों की असली स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षक को छात्रों, छात्र-सभा के पदाधिकारियों और अध्यापकों से व्यक्तिगत साक्षात्कार करना चाहिए। उसे विशेष रूप से प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के पारस्परिक सम्बन्धों की जाँच करनी चाहिए। अच्छा हो यदि स्कूल के आम-पाम के समाज में विद्यालय के बारे में क्या धारणा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाय।

निरीक्षण के समय प्रधानाचार्य और अध्यापकों के साथ विचार-विमर्श, प्रत्यक्ष उपयोगी सुझाव, भय के बानावरण का जन्म, और महयोगपूर्ण दृष्टिकोण प्रदाना चाहिए। जॉन ए० बार्टकी ((John A. Bartkey) ने अपनी पुस्तक

'Supervision as Human Relations' में निरीक्षण के कई प्रकार बताये हैं, जैसे निरवुध निरीक्षण, जाँच-प्रधान निरीक्षण, प्रतिनिधित्वपूर्ण निरीक्षण, सहयोगात्मक प्रशासनिक निरीक्षण, वैज्ञानिक निरीक्षण और रचनात्मक निरीक्षण। आज के प्रशासनिक युग में निरीक्षण वैज्ञानिक और रचनात्मक होना चाहिए।

प्रशासकीय नियन्त्रण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रभावशाली उपाय वर्तमान हैं और उनका उपयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए। शिक्षा-विभागों को समय-समय पर शिक्षा समस्याओं में हर प्रकार की जानकारी पत्र-व्यवहार द्वारा प्राप्त करने रहना चाहिए। मान्यता प्रदान करने और अनुदान देने की शक्ति शिक्षा विभाग के हाथ में है। विद्यालयों को आदर्श कार्य करने के लिए शिक्षा विभाग दत्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है। विद्यालयों को मान्यता और अनुदान देने के समय शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निष्पक्ष होकर केवल उन्हीं विद्यालयों को महामता पहुँचानी चाहिए, जो सुचारु हो और अपना काम ईमानदारी से चलाने हों। मान्यता देने और अनुदान की धन-राशि निर्दिष्ट करने समय उन्हें यह देवना चाहिए कि विद्यालय निर्धारित बातों का पालन कर रहे हैं या नहीं। मार्बननिक परीक्षाओं के द्वारा भी शिक्षा विभाग अपने नियन्त्रण को मजबूत बना सकता है। इन परीक्षाओं में मन्वाओं की उपलब्धि, शिक्षा-स्तर तथा पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करने में सम्भव होती है। शिक्षा विभाग नियन्त्रण के लिए इनका उपयोग कर सकता है। नियन्त्रण का एक माधन एगूकेसन कोड है। इसके द्वारा प्रशासन नियन्त्रण को मजबूत बना सकता है।

शैक्षिक प्रशासन के नियन्त्रण और निरीक्षण को मजबूत बनाने के लिए कोठारी शिक्षा-आयोग ने कई सुझाव दिये हैं। उनमें से प्रमुख सुझाव है—जिला-स्तर पर मन्वा को डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड तथा जिला स्कूल अधिकारी को सौंपना। यद्यपि शिक्षा निदेशानलय राज्य भर के शिक्षा प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा परन्तु वह इन दो मन्वार्थों—बोर्ड और निरीक्षक (जिला स्कूल अधिकारी) का प्रशासन का एजेंट बनाएगा। जिला स्कूल बोर्ड अनुदान और मान्यता के द्वारा स्कूलों पर नियन्त्रण रखेगा तो जिला स्कूल अधिकारी निरीक्षण के द्वारा। यह अधिकारी निदेशानलय में आवधिक मामलों में और शैक्षिक मामलों में स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ एगूकेसन में पथ-प्रदर्शन प्राप्त करेगा। इसकी संस्तुति पर ही विद्यालयों को अनुदान पाने का हक होगा। इनकी महामता में प्रशासनिक नियन्त्रण और निरीक्षण का काम अच्छे ढंग में हो सकेगा।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

1. भारतीय शैक्षिक प्रशासन की दो प्रमुख समस्याओं का उन्नेत कीजिए। उनकी व्याख्या कीजिए और उन्हें हल करने के उपाय बताइए।
2. शैक्षिक प्रशासन को प्रशासनिक बनाने का क्या उद्देश्य है? यदि भार-

नीय शैक्षिक प्रशामन को प्रजातान्त्रिक बना दिया जाय तो आप किन परिणामों की आशा करते हैं ?

३. "अधिकांश समस्याएँ जैसे विद्याधियों की अनुशासनहीनता, अभ्यासकों का जमहूयोग, अभिभावकों की उदासीनता, शिक्षण की उत्तमता को कमी और पाठशाला के माधनों का दुरुपयोग आदि शैक्षिक प्रशामकों के दूरित दृष्टिकोण से पैदा होती है।" इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं ? अपने विचार प्रकट कीजिए।
४. भारतीय शैक्षिक प्रशामन में एकमूर्तता (Co-ordination) की समस्या क्यों उत्पन्न हुई है ? इसे हल करने के लिए क्या किया जा सकता है ?
५. 'अमानवीयता' की समस्या का स्पष्टीकरण कीजिए। शैक्षिक प्रशामन में किन गुणों के होने में यह अमानवीयता (Dehumanization) बूर हो सकती है ?
६. शैक्षिक प्रशामन के लिए केन्द्रीकरण के पक्ष में कौन मुख्य तर्क दिये जाते हैं ? केन्द्रीयकरण हो जाने में कौन प्रमुख दोष पैदा हो सकते हैं ?
७. आधुनिक युग में शैक्षिक प्रशामन के विकेन्द्रीकरण का समर्थन क्यों किया जाता है ? भारत में शैक्षिक प्रशामन के विकेन्द्रीकरण के लिए किये गये प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए।
८. केन्द्रीय शैक्षिक प्रशामन (भारत में) का मक्षेप में विवरण दीजिए और बताइए कि उसमें कौन सी प्रवृत्तियाँ (Trends) स्पष्ट होती हैं ?
९. संविधान ने शिक्षा-प्रशामन का बँटवारा किम प्रकार केन्द्र और राज्यों के बीच करने की व्यवस्था की है ? इसमें क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं ?

**राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न**

1. Discuss and give your comments on the 'experiment of decentralization of primary education in Rajasthan. Do you think this experiment should be extended to secondary education as well ? If so, how and in what stages ? (1961)
2. Discuss the relationship between (a) the Central Government and State Government, and (b) the State Government and the local bodies, the Panchayat Samities or Private Agencies with reference to (i) Financial Control and Educational Planning and (ii) Professional guidance. (1962)

3. Write short notes on :—

- (a) Primary Education with Panchayats—its credit side and its debit side. (1964)
- (b) Role of the Government in the field of education in a welfare state. (1963)
- (c) Decentralization of educational administration (1963)
- (d) Impact of decentralization of primary education in Rajasthan. (1965)
- (e) Creative administration (1965)

4. Formulate your views regarding the desirability and the possibility of involving schools in the development of local communities. (1965)

५. बलवत राय मेहता समिति (१९५७) के विवेक मुभाष क्या थे ? इसका ममान आपके राज्य के प्राथमिक शिक्षा के प्रजातन्त्रात्मक प्रशासन के विवेकीकरण पर क्या पडा है ? (१९६६)

६. मपर समिति ने यह मुभाष दिया था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती मूषो में समावेश किया जाय । इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपका क्या दृष्टिकोण है ? (१९६७)

७. आपके विचार में आपके क्षेत्र के निरीक्षणानय तथा गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की प्रद्वय समितियों में क्या मध्यम्य होना चाहिए ? वर्तमान सम्बन्ध में ऐम कौनसे तत्व है जिनमें आप मनुष्य नहीं हैं ? (१९६८)

८. शैक्षणिक योजनाओं की रचना और परिपालन के लिए वर्तमान मनीतरी (ध्वस्त) में मुधार के लिए क्या करना चाहिए ? (१९६८)





आन्दोलन (Literacy Movement) के रूप में हुआ। पराधीन भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी और उसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के ६५% लोग निरक्षर हो बने रहे। जब गांधीजी के नेतृत्व में देश में करबट बदली, तो यह अनुभूति देश में पैदा हुई कि निरक्षर जनता को 'स्वतन्त्रता' का स्वाद कैसे मानूँ हो सकता है? इसलिए स्वतन्त्रता-संग्राम के लिए जो रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए, उनमें साक्षरता प्रसार का आन्दोलन प्रमुख था। गांधीजी ने जिस प्रकार अछूतोद्धार, महात्माजी और साम्प्रदायिक महिष्णुता के आन्दोलनों को स्वराज्य-प्राप्ति का साधन बनाया था, उसी प्रकार साक्षरता-प्रसार को भी उन्होंने जाजादो पाने का अस्त्र माना।

प्रारम्भ में गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने साक्षरता के अन्तर्गत देश के किसानों और गृहस्थों के मजदूरों को अक्षर-बोध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। देश-मेवा की भावना में प्रेरित होकर हजारों की संख्या में कांग्रेस के स्वयं-सेवक इस काम में लग गए। उत्साह इतना था कि रात में लानटर्न लेकर वे लोग अंधेरे गाँवों में जाते और साक्षरता का प्रचार करते। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि गांधीजी 'साक्षरता' को ही एकमात्र लक्ष्य नहीं मानते थे। उन्होंने सामाजिक शिक्षा के सर्वाङ्गीण महत्त्व को पूरी तरह समझा था। उनका कहना था कि अंग्रेजी काल में प्रचलित जन भी नौकरी पाने या व्यवसाय में लगने के बाद अज्ञानता के अन्धकार में घिरकर निरक्षर बन जाते थे। उनका विचार था कि सामाजिक शिक्षा अपने व्यापक अर्थों में साक्षर और निरक्षर सभी प्रकार के लोगों के लिए है। उसका उद्देश्य निरंतर हर जन-मानस को ज्ञान के आलोक में प्रकाशित रखना है। उन्होंने अपने एक लेख में कहा है—“सामाजिक शिक्षा जो निम्नी प्रकार भी मारी जनता की शिक्षा में कम नहीं है, केवल रात्रि पाठशालाएँ चलाने या कच्चे मादे मजदूरों को सिखाना-पढ़ाना मित्याने तक सीमित नहीं है।”

सन् १९२१ में अंग्रेज सरकार ने शिक्षा का विषय जनप्रिय मन्त्रियों को सौंप दिया। इसमें साक्षरता आन्दोलन को कुछ उत्तेजन मिला। सन् १९२२ में जब कि परशास्त्र यह ज्ञान हुआ कि साक्षरता केवल ८-२०% ही हो पायी। फिर भी प्रयत्न जारी रहे। सन् १९२७ में अध्यापक विश्व-अर्थ-मंदी के कारण इस आन्दोलन को गहरा धक्का लगा। इसके बाद ही अखिल एशिया शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने पर जोर दिया गया। श्री डी० एन० कृष्णैया और श्री पायल जैम बत्ताओं ने छात्रों और अध्यापकों से अनुरोध किया कि वे साक्षरता आन्दोलन को सफल बनाएँ। उनमें देहातो में जाकर पुस्तकालय चलाने, स्वास्थ्य और स्वच्छता की ओर ध्यान दिलाने, मत्स्यपान तथा मुकदमेबाजी की सुराई को दूर करने का आन्दोलन चलाने का आग्रह किया गया।

सन् १९३७ में प्रांतीय स्वायत्त मामलों की स्थापना के बाद भारत के अनेक प्रांतों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों को शासन मिला। इसमें यह आभा हुई कि अब माधरता-प्रसार में सरकार द्वारा अधिक सहायता मिलेगी। इसी वर्ष प्रथम भारतीय प्रौढ-शिक्षा मण की स्थापना हुई और अगले वर्ष इसका अधिवेशन हुआ। मणि देश में माधरता-प्रसार की धूम मच गयी। इसके दो प्रमुख परिणाम हुए। एक, अब 'माधरता-प्रसार' को 'प्रौढ-शिक्षा' का नाम दे दिया गया और दूसरे, इस शब्द में अनेक जनमेवी समस्याओं जैसे Y M C A तथा सरकार ने भी भारी दिलचस्पी लेनी आरम्भ की।

**प्रौढ-शिक्षा**—सन् १९३७ में प्रौढ-शिक्षा मण की स्थापना हुई तो 'माधरता' ने प्रौढ-शिक्षा का रूप ले लिया। सन् १९३९ में विद्ययुद्ध छिड़ गया और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने श्वाभ-यत्र दे दिया। देश के भीतर भी आजादी के लिए मर्ष तेज हो गया। अतः प्रौढ-शिक्षा के प्रति आम जनता की दिलचस्पी कम हो गयी। फिर भी युद्ध के दौरान भारतीय शिक्षा को सुधारने के लिए जो मर्जेंट योजना सरकार की ओर में पेश की गई, उसमें प्रौढ-शिक्षा के विकास के लिए २० वर्षीय कार्यक्रम का उल्लेख था। इसमें स्पष्ट होता है कि विदेशी सरकार को भी प्रौढ-शिक्षा की ओर ध्यान देना अनिवार्य जान पड़ने लगा था।

प्रौढ-शिक्षा के अन्तर्गत इस शिक्षा का अर्थ व्यापक बनने लगा। केवल निरक्षर जन ही इसके कार्यक्रम के अंग न थे, इसका उद्देश्य सामान्य जनता के मुखनाशक ज्ञान का स्तर ऊँचा करना था। उन्हें इस योग्य बनाना था कि वे देश-विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें, उन्हें स्वास्थ्य के विषयों की जानकारी हो जाय और वे बीमारियों से बच सकें। समय का सदुपयोग करना भी उन्हें सिखाया जाय। यह कार्यक्रम सामान्यजन के लिए रोचक था और अनेक जनमेवी समस्याओं में इसे अपनाया। अनेक प्रकार की जनमेवी समस्याओं ने प्रौढ-शिक्षा के लिए प्रयत्न आरम्भ किए। इनमें पुस्तकालय मण, रामकृष्ण मिशन, विवेकानन्द सोसाइटी, राधास्वामी मठ, आदिवासी सेवा समिति, उत्तर भारत मजदूर मण, अध्यापक मण, स्त्री मण, क्रिश्चियन मिशन, हरिजन सेवक मण्डल, आर्यममाज, हिन्दी साहित्य समिति तथा ऐसी ही अनेक संस्थाएँ गिनी जा सकती हैं। प्रौढ-शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थाओं ने सहाय्य कार्य किया है।

**सामाजिक शिक्षा**—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद प्रौढ-शिक्षा को सामाजिक शिक्षा के नाम में पुकारा जाने लगा। सन् १९४९ में श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में एक समिति प्रौढ-शिक्षा पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई। इस समिति ने प्रौढ-शिक्षा को सामाजिक शिक्षा का नाम देने की संसुति दी। इसके अतिरिक्त उसने समाज-शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किये

१. नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करना।

- ७ जनतन्त्र के प्रति उनमें प्रेम उत्पन्न करना, उन्हें जनतन्त्रीय जीवन और धामन प्रणाली की शिक्षा देना ।
- ८ नागरिकों को देश तथा विश्व की समस्याओं में अवगत कराना ।
- ९ इतिहास-भूगोल और साम्प्रतिक शिक्षा द्वारा भारतीय सभ्यता के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना ।
- १० गायन, नृत्य, कविता, नाटक तथा साम्प्रतिक कार्यों के माध्यम में नागरिकों के लिए स्वस्थ मनोरंजन के अवसर प्रदान करना ।
- ११ साम्प्रतिक वाद-विवाद और पठन-पाठन के माध्यम में नैतिक धर्मों का परिचय देना ।
- १२ विज्ञान-गणना और मणिक का साधारण ज्ञान देना ।
- १३ हस्तकारी की शिक्षा देकर नागरिकों की आर्थिक क्षमता बढ़ाना ।
- १४ महयोग की भावना में वृद्धि करना ।
- १५ पुस्तकालय, विचार-मोल्दी, जनता-महाविद्यालय तथा शिक्षा समितियों के विस्तार द्वारा शिक्षा की निरन्तरता बनाये रखना ।

मोहनलाल समेत समिति ने सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में कई सुझाव भी दिये, यथा अपने ५ वर्षों में ५०% निरक्षरता हर राज्य दूर करे, सन् १९४६ में हर राज्य सरकार निरक्षरता-निवारण की योजना जप्रेल में बनाये, इस योजना के अन्तर्गत १२ वर्ष में लेकर ४५ वर्ष की आयु के व्यक्तियों को सामाजिक शिक्षा देने का कार्यक्रम बनाया जाय, राज्य अपने कर्मचारियों के लिए सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था करे । प्रत्येक प्राथमिक छात्रा में एक और माध्यमिक छात्रा में दो सामाजिक शिक्षा के केन्द्र चलाये जायें तथा अध्यापकों को कुछ पारिधमिक भी दिया जाय । प्रौढ़-साहित्य की रचना की जाय और प्रौढ़-शिक्षण की विधियों पर दोष की जाय ।

सन् १९४६ में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय की ओर से राज्यों के मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन में सामाजिक शिक्षा की एक निर्देशिका योजना (Guide Plan) प्रस्तुत की गयी और उसे स्वीकार किया गया । केन्द्र सरकार ने विनीय महायत्ना देने का वचन दिया ।

सन् १९४६ में सामाजिक शिक्षा अधिकारियों का सम्मेलन हुआ । इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय किये गये । एक उप-समिति नियुक्त हुई जिसे सामाजिक शिक्षा के अध्यापकों, विधियों और पाठ्यक्रम पर विचार करने का भार सौंपा गया । ६० दिनों का पाठ्यक्रम तैयार किया गया और प्रतिदिन दो घण्टे कार्य के लिए निर्धारित किये गये । १२ से ४० वर्ष की आयु के लोग इस कार्यक्रम में शामिल करने का निश्चय हुआ । प्रति अध्यापक ३० प्रौढ़-जन की सहायता लय हुई । सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम को चलाने के लिए स्वयंसेवक अध्यापकों के साथ-साथ प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापकों का सहयोग देने का निश्चय स्वीकार हुआ । इन अध्यापकों के



पंचवर्षीय योजनाएँ और सामाजिक शिक्षा—प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया गया। यह कहा गया कि सामाजिक तथा बुनियादी शिक्षा में अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिए। लक्ष्य की प्रगति के लिए पाँच सामुदायिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव था। साथ ही पुस्तकालयों और जनता विद्यालयों के विकास पर जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सह-सम्बन्धित पुस्तकालय सेवा के अन्तर्गत हर मोहल्ले में (महरो में) और गाँवों में बोयाल, पचासतपर, पाठशाला या लोकप्रिय नागरिक के घर में पुस्तकालय की स्थापना का प्रस्ताव था। इसमें प्रौढ़-बच्चों की रचि के अनुकूल गृहकान्ति, कुटीर उपयोग तथा स्वास्थ्य में सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध करने तथा नागरिकों में समाज शिक्षा के प्रति अभिरुचि पैदा करने का लक्ष्य रखा गया। इन पुस्तकालयों के साथ संचल पुस्तकालयों का उपयोग करने की समस्या पर विचार किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनता कालेजों के चलाने का उल्लेख था। इन जनता कालेज का मक्षिप्त विवरण देना जरूरी है। यह एक ऐसी गस्था है जो समीपवर्ती जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें लोक जीवन अपने असली रूप में उतर आता है। लोक-गृह, लोक-मन्दिर, मनोविनोद, सिविल आदि का इस जनता कालेज में प्रबन्ध होता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियम यहाँ बताये जाते हैं। स्थानीय लोगों की समिति इसका संचालन करती है। इसका प्रधानाचार्य कोई अनुभवी आदमी होता है। रुपि और दस्तकारी की शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। स्थियों की शिक्षा के लिए गृहविज्ञान की पढ़ाई यहाँ होती है। शिक्षा नि शुल्क दी जाती है। जनता कालेज कई उपयोगी आन्दोलनों को भी समर्थित करता है, जैसे स्वच्छता-अभियान, धर्मदान द्वारा मन्दिर-निर्माण, सामाजिक सेवा, साक्षरता, फिल्म-प्रदर्शन, अन्तर्गमि खेलकूद आदि।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक केन्द्रों के विकास की व्यवस्था की गयी। कुछ चुने हुए प्राथमिक स्कूलों में यह केन्द्र खोलने का विचार किया गया। यह केन्द्र सामाजिक शिक्षा के प्रमुख माधन बनने वाले थे। इनमें मास्टरिक कार्य-क्रमों का माहुर्य होना चाहिए जिनमें स्त्री-पुरष भाग ले सकें। मनोविनोद प्रधान कार्यक्रमों, जैसे खेलकूद, गृह, भजन, समूहगान और नाटक के द्वारा जनता की दिलचस्पी शिक्षा में जगाने का विचार था। रेडियो, फिल्म तथा प्रदर्शनी की सहायता से शिक्षा देने की बात कही गयी थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामाजिक शिक्षा के विकास के लिए १५ करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई और सारे देश में सामुदायिक विकास-केंद्रों की स्थापना के लिए १० करोड़ रुपये खर्च करने का निर्देश किया गया। दिल्ली में जापाररून शिक्षा केन्द्र (Fundamental Education Centre) खोलने की अवसर से व्यवस्था की गयी। इन चार सामाजिक शिक्षा को बहुमुखी बनाने का प्रयास करने पर विशेष ज़ोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुमुखी सरकारी

मर्यादाएँ ठग काम में लगाने हुईं । इसके अतिरिक्त हमारे देश में चलने वाले समाज-कल्याण, हरिजन-कल्याण, बाल-कल्याण, महिला-कल्याण, मजदूर-कल्याण की सेवाओं के माध्यम से भी सामाजिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार तेजी में होने लगा । अन्य गार्वजनिक समस्याएँ, जैसे ग्राम विनाश परियोजना, सर्वोदय सत्र और भारत में एक समाज का योगदान भी पर्याप्त मात्रा में रहा ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि 'समाज शिक्षा का मतलब है, सामुदायिक प्रयत्न द्वारा समाज के उत्थान का सर्वव्यापी प्रयत्न' । अतः यह स्वीकार किया गया कि सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत साक्षरता, स्वास्थ्य, मनोरंजन, बचस्वों के गार्हस्थ्य जीवन के कार्यक्रम, नागरिकता का प्रतिष्ठान, आर्थिक क्षमता-वृद्धि के लिए मार्गदर्शन आदि बाने आ जाती है । इस बार यह भी स्वीकार किया गया कि भारत में प्रजातन्त्र के विकास और पुनर्निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए समाज शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है । इसका कारण यह बताया गया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला-स्तर और संघ-स्तर पर पचासवीं राज्य स्थापित हो जायगा । यदि बचस्क जन निरक्षर रहने दें तो निश्चय ही पचासवीं राज्य सकल नहीं हो सकेगा । उनके पढ़े-लिखे होने में ही उत्पत्ति संभव है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्यों की जिम्मेदारी समाज शिक्षा के सम्बन्ध में निर्धारित कर दी गयी । केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का अपना अलग कार्यक्रम होगा । वह राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केन्द्र का विकास एक राष्ट्रीय शिक्षा सस्था के रूप में करेगा । नवमासिकों के लिए साहित्य का निर्माण और प्रकाशन स्वच्छिक संगठनों को जो सामाजिक शिक्षा के पुनीत कार्य में सलग हैं, आर्थिक सहायता देना और पुस्तकालयों की सुविधा बढ़ाना, केन्द्र की जिम्मेदारी निश्चित कर दी गयी । राज्यों की जिम्मेदारी यह तय की गयी कि वे अपने क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से पुस्तकालय खोलें, सम्पर्क स्थापक वर्गों की सहायता करें, बचस्क विद्यालय चलायें । इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए २५ करोड़ रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट कहा गया कि बहुत बड़े राष्ट्रीय पैमाने पर सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाये वर्यैर यह भारे लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकते । इसे जन-आन्दोलन का रूप देना होगा । आन्दोलन में वेग लाने के लिए शिक्षा-विभागों तथा सामुदायिक विकास-खण्डों के अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग अपेक्षित बताया गया । गाँवों के विद्यालय समाज शिक्षा के केन्द्र हों, पचासवीं, सहकारी समितियों और स्वच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाय और माध में अन्य गार्वजनिक समस्याओं को भाग लेने की प्रेरणा दी जाय । इन बातों पर विशेष बल दिया जाय ।

चतुर्थ योजना में साक्षरता की स्थिति पर बड़ी चिन्ता प्रकट की गयी है । सन् १९११ में साक्षरता १७ प्रतिशत थी और सन् १९६१ में इसका प्रतिशत २४ हुआ

परन्तु साथ में निरक्षरता भी बढ़ी। सन् १९२१ में २९८० लाख व्यक्ति निरक्षर थे, तो १९६१ में ३३४० लाख निरक्षर हुए। इसका कारण तेज़ गति में आवादी में वृद्धि है। यह एक दुःखद स्थिति है। असाधारण गति में आवादी की वृद्धि सामाजिक शिक्षा के मार्गे प्रचलित पर पानी केर रही है। चतुर्थ योजना में यह स्वीकार किया गया है कि बिना साक्षरता आन्दोलन चलाये देश की उन्नति नहीं हो सकती। इति कामों और कारखानों में यदि उत्पादन बढ़ाना है तो सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम सफल बनाया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सामाजिक शिक्षा को जनता के कार्य और जीवन से सम्बद्ध किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाई जाय और भारत की विभिन्न भाषाओं में भवमाक्षरों के लिए भारी संख्या में पुस्तकें तैयार करायी जायें। सामाजिक शिक्षा के प्रसार में जन-सहयोग प्राप्त करना आवश्यक बनाया गया।

चतुर्थ योजना में सामाजिक शिक्षा को अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है। सन् १९६१ में साक्षरता का प्रमाण था कि अमुक व्यक्ति पढ़-लिख सकता है। छपे-लिखे हुए अक्षर पढ़ सकता है। परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है, जो कुछ ज्ञान है, उसका उपयोग करता है। इन ज्ञान को चौथी योजना में माना गया है पर उनके साथ कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, जैसे साक्षरता-प्रसार के काम में सलग्न जनों का प्रशिक्षण, पुस्तकालय-कर्मचारियों का प्रशिक्षण। यह भी कहा गया कि इस समस्या के समाधान के लिए राजनैतिक तथा नैतिक के स्तर पर युद्ध किया जाय। यह संकेत दिया गया कि राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा मण्डल की स्थापना की जायगी ताकि राष्ट्रीय पैमाने पर सामाजिक शिक्षा के काम को अच्छी तरह में बनाया जा सके। राज्यों में भी वयस्क शिक्षा मण्डल बनाये जायें जो सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम को जन-आन्दोलन का रूप देंगे। इन बात का पूरा प्रयत्न किया जायगा कि सभी क्षेत्रों में गैर-सरकारी सहयोग प्राप्त किया जाय। विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता भी ली जायगी।

### सामाजिक शिक्षा और सामुदायिक विकास-संघ योजना

सामुदायिक विकास-संघ योजना का विचार हमारे देश में पश्चिम में आया है। इस योजना का उद्देश्य समाज की विभिन्न इकाइयों को छोटे-छोटे सामाजिक समूहों के रूप में इस प्रकार विवर्गित करना है कि हर एक के सदस्य स्वच्छता में अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज की उन्नति में योगदान दे। इस योजना को देश में ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए लागू किया गया था। प्रति गो ग्रामो को एक मूल में बाँधने के लिए एक विकास-संघ खोला गया जो सामूहिक चेतना का केन्द्र बन सके। इसके माध्यम में ग्रामवासियों में नवीनतम ज्ञान पतुवाने की व्यवस्था की गई। इति के क्षेत्र में होने वाले प्रयोगों के परिणामों, अनुपालन की विधियों, हस्तोद्योग, स्वास्थ्य के नियम तथा जीवनोपयोगी अनेक बातों का समझने के लिए विकास

मस्वाण इस काम में मग्न हुई । इसके अनिर्गुण हमारे देश में चलने वाले समाज-कल्याण, हरिजन-कल्याण, बाल-कल्याण, महिला-कल्याण, मजदूर-कल्याण की सेवाओं के माध्यम में भी सामाजिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार नेत्री में होने लगा । अन्य मार्वाजनिक मस्वाण, जैसे ग्राम विकास परियोजना, सर्वोदय मज और भाग्य मेवक समाज का योगदान भी पर्याप्त मात्रा में रहा ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि 'समाज शिक्षा का मतलब है, सामुदायिक प्रयत्न द्वारा समाज के उत्थान का सर्वव्यापी प्रयत्न' । अब यह स्वीकार किया गया कि सामाजिक शिक्षा के जननगत माधुगता, स्वास्थ्य, मनोरंजन, बयस्वो के गार्तस्थ्य जीवन के कार्यक्रम, नागरिकता का प्रशिक्षण, आर्थिक क्षमता-वृद्धि के लिए मार्गदर्शन आदि जाने आ जाती है । इस बार यह भी स्वीकार किया गया कि भारत में प्रजातंत्र के विकास और पुनर्निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए समाज शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है । इसका कारण यह बताया गया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला-स्तर और गड-स्तर पर पचासवीं राज्य स्थापित हो जायगा । यदि बयस्क जन निरक्षर रहने दें तो निश्चय ही पचासवीं राज्य सकल नहीं हो सकेगा । उनके पढ़े-लिखे होने में ही उत्थान सम्भव है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्यों की जिम्मेदारी समाज शिक्षा के सम्बन्ध में निर्धारित कर दी गयी । केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का अपना जलम कार्यक्रम होगा । वह राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केन्द्र का विकास एक राष्ट्रीय शिक्षा सस्था में करेगा । तबमाक्षरो के लिए माहिन्य का निर्माण और प्रकाशन स्वीच्छक गठनों को जो सामाजिक शिक्षा के पुनीत कार्य में सलम है, आर्थिक महायत्ना देना और पुस्तकालयों की सुविधा बढाना, केन्द्र की जिम्मेदारी निश्चित कर दी गयी । राज्यों की जिम्मेदारी यह तय की गयी कि वे अपने क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से पुस्तकालय खोलें, सम्पर्क स्थापक वर्गों की सहायता करें, बयस्क विद्यालय चलायें । सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए २५ करोड रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट कहा गया कि बहुत बडे राष्ट्रीय पमाने सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाये वगैर यह सारे लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके । इसे जन-आन्दोलन का रूप देना होगा । आन्दोलन में वेग लाने के लिए विभागों तथा सामुदायिक विकास-संघों के अधिकारियों और कर्मचारियों का अपेक्षित बताया गया । गांवों के विद्यालय समाज शिक्षा के केन्द्र हों, गांव के सरकारी ममिनियों और स्वीच्छक मगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाय । गांव में अन्य मार्वाजनिक मस्वाओं को भाग लेने की प्रेरणा दी जाय । इन

पर बडी चिन्ता प्रकट की गयी है । मज १९६१ में इसका प्रतिदान २४ हुआ



परन्तु साथ में निरक्षरता भी बढ़ी। सन् १९५१ में २६८० लाख व्यक्ति निरक्षर थे, तो १९६१ में ३३४० लाख निरक्षर हुए। इसका कारण तेज गति में आबादी में वृद्धि है। यह एक दुःखद स्थिति है। जमाखारण गति में आबादी की वृद्धि सामाजिक शिक्षा के मागे प्रयत्नों पर पानी फेर रही है। चतुर्थ योजना में यह स्वीकार किया गया है कि बिना साक्षरता आन्दोलन चलाये देश की उन्नति नहीं हो सकती। कृषि फार्मों और कारखानों में यदि उत्पादन बढ़ाना है तो सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम सफल बनाया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सामाजिक शिक्षा को जनता के काम और जीवन में सम्मिलित किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की सहाय बसाई जाय और भारत की विभिन्न भाषाओं में नवसाक्षरों के लिए भारी मस्या में पुस्तकें तैयार करायी जायें। सामाजिक शिक्षा के प्रसार में जन-सहयोग प्राप्त करना आवश्यक बताया गया।

चतुर्थ योजना में सामाजिक शिक्षा को अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है। सन् १९६१ में साक्षरता का प्रमाण या कि अधिक व्यक्ति पढ़-लिख सकता है। छपे-लिखे हुए अक्षर पढ़ सकता है। परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है, जो कुछ जान है, उसका उपयोग करना है। इन बातों को चौथी योजना में माना गया है पर उसके साथ कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, जैसे साक्षरता-प्रसार के काम में मलान जनों का प्रशिक्षण, पुस्तकालय-कर्मचारियों का प्रशिक्षण। यह भी कहा गया कि इस समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक तथा नेतृत्व के स्तर पर युद्ध किया जाय। यह मकैत रिया गया कि राष्ट्रीय बयस्क शिक्षा मण्डल की स्थापना की जायगी ताकि राष्ट्रीय पैमाने पर सामाजिक शिक्षा के काम को अच्छी तरह में चलाया जा सके। राज्यों में भी बयस्क शिक्षा मण्डल बनाये जायेंगे जो सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम को जन-आन्दोलन का रूप देंगे। इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायगा कि सभी क्षेत्रों में गैर-सरकारी सहयोग प्राप्त किया जाय। विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता भी ली जायगी।

## सामाजिक शिक्षा और सामुदायिक विकास-खण्ड योजना

सामुदायिक विकास-खण्ड योजना का विचार हमारे देश में पश्चिम में आया है। इस योजना का उद्देश्य समाज की विभिन्न इकाइयों को छोटे-छोटे सामाजिक समूहों के रूप में इस प्रकार विकसित करना है कि हर धटक के सदस्य स्वेच्छा में अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज की उन्नति में योगदान दें। इस योजना को देश में ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए लागू किया गया था। प्रति गाँव ग्रामों को एक मूत्र में बाँधने के लिए एक विकास-खण्ड खोला गया जो सामूहिक चेतना का केन्द्र बन सके। इसके माध्यम से ग्रामवासियों में नवीनतम ज्ञान पहुंचाने की व्यवस्था की गई। कृषि के क्षेत्र में होने वाले प्रयोगों के परिणामों, पशुपालन की विधियों, हस्तोद्योग, स्वास्थ्य के नियम तथा जीवनोपयोगी अनेक चीजों को सम्मान के लिए विकास

खण्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई। यह ज्ञाना प्रकट की गई कि यह लोग ग्रामवासियों में नई चीज़ें पैदा करेंगे और देश की पंच-वर्षीय योजनाओं के प्रति दिलचस्पी जाग्रत करेंगे। इस प्रकार सामुदायिक विकास योजना मूलतः सामाजिक शिक्षा की एक व्यापक योजना है। इसका गार्ग कार्यक्रम दीक्षक है और विभिन्न उपायों से सामाजिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है।

सामुदायिक विकास-ग्रन्थ में अनेक अधिकारी शामिल हैं, जंग कृषि, बीज, विहित्ता, पशु-चिकित्सा, कुबकुर-पालन, पशुपालन आदि के अधिकारी। इनके साथ-साथ सामाजिक शिक्षा के महिला तथा पुरुष अधिकारी भी होते हैं। सामाजिक शिक्षा के अधिकारी पर गाँवों के पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता-प्रसार की जिम्मेदारी होती है। यह लोग गाँवों-गाँवों का दौरा करते हैं और निरक्षरता के उन्मूलन का पूरा प्रयत्न करते हैं। सामाजिक शिक्षा अधिकारी को सहायता के लिए ग्रामसेवक, ग्रहणशी और ग्रामसेविकाएँ होती हैं और इनकी सहायता में साक्षरता-अभियान चलाया जाता है। स्त्री-पुरुषों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम होते हैं। दोनों के लिए अलग-अलग साक्षरता बधाई चलाई जाती है। बड़ी आयु के पुरुषों के लिए जो नवसाक्षर बन जाते हैं, समाज-सदन बना दिया जाता है और इनके लिए खेल-कूद, उद्योग तथा विपणन-वर्षा की व्यवस्था की जाती है। तरुण वयस्कों को तरुण सभ के रूप में संगठित कर लिया जाता है। इन उल्लाही नवयुवकों के लिए स्कूलाडिंग, सेवा-ममिति, सुरक्षा दल और उद्योग आदि के कार्यक्रमों में लगाया जाता है। महिलाओं के लिए अलग महिला समिति बना दी जाती है, जो साक्षरता बधाई चलाती है, भजन-गीत, गृह-व्यवस्था, पाक धास्न, मिलाई और कटाई के कार्यक्रम चलाती है। बाल-शिशुमदन भी बनाये जाते हैं जिनमें माटेनरी और किडरगार्टन पद्धति से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। सामुदायिक विकास-खण्डों में विज्ञान मन्दिर भी बनाये जाते हैं जिनके द्वारा नये आविष्कारों का ज्ञान कराया जाता है।

सामाजिक शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। भारत के कई स्थानों, जैसे नीलखंडी और यक्षों का तालाब, लखनऊ में प्रशिक्षण केंद्र हैं जहाँ सामाजिक शिक्षा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हीं दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग करना, प्रोडों को मदन का मनोविज्ञान और विधियों का प्रयोग करना तथा संगठन कार्य करना आदि सिखाया जाता है। यह अधिकारी गाँवों की परिस्थितियों के अनुरूप मनोविज्ञानात्मक कार्यक्रमों, जैसे भजन, कीर्तन, नाटक, मोटरी, मेला, प्रदर्शनी, चार्ज, वाद-विवाद और कथा-वाचन आदि के द्वारा शिक्षा-प्रचार करते हैं। आधुनिक साधनों, जैसे रेडियो और फिल्म का भी यह प्रयोग करते हैं।

**सामाजिक शिक्षा में कार्यरत संस्थाएँ तथा वर्तमान स्थिति**

हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या निरक्षरता है। एक तो यह देश बहुत बड़ा

हैं और इसकी जनसंख्या विघाल है। दूसरे, हजारों वर्षों से यह शिक्षा की सुविधाओं से वंचित रहा है। आजादी के बाद से माध्यम-प्रसार का महान् यत्न आरम्भ हुआ है परन्तु हमारे प्रयत्न उमी प्रकार नगण्य मिद्ध हो रहे हैं, जैसे एक पक्षी ने समुद्र को बान्ने में पाटने का प्रयत्न किया था। फिर भी बड़े पैमाने पर प्रयास जारी है। इसका प्रमाण उन प्रिया-कन्ताओं में मिलता है, जो सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे हैं।

इस समय हम शिक्षा का अर्थ 'पुस्तक पढ़ना' ही लगाते हैं परन्तु यदि इसका अर्थ आदिमक विज्ञान मान लिया जाय तो पता चलेगा कि निरक्षर रहते हुए भी मनुष्य बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारे देश में बड़े-बड़े मन्त्र और महात्मा हुए हैं परन्तु वे निरक्षर रहकर भी ज्ञानी बने। निरक्षर जन भी भाषा बोलते और समझते हैं। माधुरता में लाभ यह होता है कि वे पुस्तकों में लाभ उठा सकते हैं। निरक्षर जन में यदि चेतना है तो वह अनुभव तथा मस्तिष्क में कहीं अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह बात प्राचीन काल में अनुभव की गई थी और हमारे यहाँ 'संन्यास आश्रम' की व्यवस्था सम्भवतः इसीलिए की गई थी कि समाज में ऐसे अनुभवों और विरक्त जनों का एक वर्ग पैदा हो जो समाज में शैक्षिक चेतना फैलाता रहे। हर मनुष्यी एक प्रकार का सामाजिक शिक्षा अधिकारी है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। वह कर्तव्य-भावना में प्रेरित होकर गाँव-गाँव घूमता है। कहीं टहरता उसके लिए पाप होना है। जिस गाँव में धाम हो गई, वहाँ वह किसी गृहस्थ के घर टहर गया। जाति-वन्धन से वह मुक्त होता है। वह गृहस्थ के यहाँ भोजन कर लेता है। रात में घासीन जन मनुष्यी का आगमन जान कर एकत्र हो जाते हैं और वह उन्हें धर्म तथा समाज के प्रति सचेत करता है। इसी प्रकार गाँव-गाँवों में हमारे देश में देवालय और तीर्थ-स्थान हैं और विशेष पर्वों पर नांग वहाँ एकत्र होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। वर्ष भर में अनेक त्योहार तथा पर्व मनाये जाते हैं जिनको मनाते समय नाना प्रकार की कथाएँ सुनायी जाती हैं। वर्तमान के दिनों में जब हफ्ते के दिनों के काम में छुट्टी पाता है, तो रामायण-महाभारत की कथाएँ गाकर सुनाने वाले पण्डित जा पहुँचते हैं और महीनो कथा का क्रम चलता है। भजन-कीर्तन तो गाँवों में होते रहते हैं। संक्षेप में, हमारे देश की पुरानी सामाजिक शिक्षा की संस्थाएँ बड़ा उपयोगी काम करती रही और निरक्षर जन भी भारत की सांस्कृतिक सम्पदा को बराबर पाने रहे और उन्हें बनाये रहे। दुर्भाग्य से 'मनुष्यी' प्रथा और धर्म की भावना का ह्रास होने से निरक्षरता 'अज्ञानता' में बदल गई। इस समय आवश्यकता यह है कि हम अपनी प्राचीन परन्तु स्वस्थ परम्पराओं का पुनरुद्धार करें।

विज्ञान की उन्नति और विवेका के प्रभाव से हम सामाजिक शिक्षा के लिए नई प्रकार की संस्थाएँ बना रहे हैं। डा० मोहनसिंह मेहता ने अपने एक लेख ('Adult Education and Its Growth', प्रौढ़ शिक्षा अर्क, नया शिक्षक, अक्टूबर

६१) में इन सम्भावनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने सामाजिक शिक्षा को पाँचे दो प्रकार की माना है—एक सरकारी और दूसरी गैर-सरकारी। यह सभी पाँचे विभिन्न सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इनमें बड़ी विविधता है और इनके प्रयत्नों में समायोजन का काम कठिन हो रहा है।

सामाजिक शिक्षा का प्रचार करने वाली सबसे बड़ी मस्था सरकार है, अर्थात् उसके अनेकानेक विभाग सामाजिक शिक्षा के प्रचार में लगे हुए हैं। केन्द्र तथा सरकारों ने इस काम के लिए कई विभाग खोल रखे हैं, जैसे केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल (Social Welfare Board), श्रमिक मस्थान (Worker's Guild) इन्दीर, राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र आदि। सामाजिक शिक्षा का मूल रूप में केन्द्र सरकार में सामुदायिक विकास मन्त्रालय के हाथ में है। राज्यों में तो राज्य विभाग भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। प्रशिक्षण मन्त्रालय की ओर से हॉटेलों में शिक्षा-प्रसार के प्रयत्न किये जाते हैं। इसकी ओर से नवमासिकों के लिए और अंग्रेजी में पाठ्य-पुस्तकें छपायी जाती हैं। केन्द्रीय मूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के माध्यम से प्रौढ़-जनों के लिए अनेक कार्यक्रम प्रसारित कराता है, चायतनपर, श्रमिकों तथा किसान भाइयों के लिए, गृहलक्षितियों के लिए प्रारंभिक और आधुनिक। फिलिम डिवीजन की ओर से तैयार किये गये वृत्त-चित्र जो तबूत रूप से हर मिनेमा घर में दिखाये जाते हैं, सामाजिक शिक्षा के उत्तम साधन हैं। स्वास्थ्य मन्त्रालय की ओर से स्वास्थ्य शिक्षा का प्रयत्न है और आजकल तो इस पर नियन्त्रण करने के लिए परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रचार तथा शिक्षा के दृष्टिकोण से सामाजिक शिक्षा का प्रयत्न इसी विभाग द्वारा किया जा रहा है। और उद्योग मन्त्रालय ने रोजगार प्रशिक्षण के उपरेस्ट्रूट गोलका के अन्तर्गत का काम आगे बढ़ाया है। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय की ओर से काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय ने विज्ञान मन्दिर और संग्रहालय गोलने में काम किया है। १९६१-६२ में प्रौढ़ जनो की विज्ञान की प्रगति का परिचय देने के लिए १५६९९ से २३ तक जेना सम्मेलन हुआ है कि अनेक सरकारी विभाग इस में सामाजिक शिक्षा के काम में योगदान दे रहे हैं।

राज्य के आचार्य, डॉ० सी० ज० नेत्री सभाएँ सामाजिक विद्या के काम में रही हैं। उनमें सामाजिक विद्या, भारत सेवा समिति, मंसूर राज्य प्रोड्यूसर्स, बम्बई गणर सामाजिक विद्या समिति, सेवा-मदन, पूना जीर विद्येयी युनियन आदि प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिनमें सामाजिक विद्या के कार्यक्रम में हुई है। गणराज्य की १९२१ की हाउस ने इस क्षेत्र में उन्नेयनीय है। यह पूर्ण रूप से भाषाओं और सामाजिक विद्या के काम में 'विज्ञान' - चरारा जा रहा है। महारत्ना गांधी की प्रेरणा में प्रगति अमरीकी

प्रकार मुई किसर की शिक्षा ने इसे बताया है। इस मस्ये का आधार राष्ट्रीय बताया जाता है और वह प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, प्रकाशन और विस्तार के कार्यक्रम चला रही है। यहाँ सामाजिक शिक्षा के अध्यापकों का प्रशिक्षण होता है और प्रौढ़ साहित्य की रचना कराती जाती है। हृदय-श्रव्य शिक्षा का एक केन्द्र है जो इन हृदय-श्रव्य साधनों की रचना में योग देता है।

सामाजिक शिक्षा के कार्य में बहुत से व्यावसायिक सम्थान भी भाग लेते हैं, जैसे समाचार-पत्र, मिलें और कारखाने, बीमा कम्पनियाँ आदि। समाचार-पत्र पृष्ठ का एक भाग प्रौढ़-जनों के लिए सुरक्षित रख लेते हैं और उनके द्वारा प्रौढ़-जनों की शिक्षा के साहित्य को छापते हैं। इसमें समाचार-पत्रों की विक्री बढ़ जाती है। मिलें और कारखाने अपने श्रमिकों के लिए तकनीकी ज्ञान की व्यवस्था करते हैं ताकि उनके श्रमिक कार्यकुशल बन जायें। ऊप्रा सिलाई मशीन की कम्पनी महिलाओं को सिलाई की शिक्षा मुफ्त देती है जिसके लिए नगरों में केन्द्र खोले जाते हैं। यहाँ महिलाएँ ऊप्रा मशीन पर सिलाई करती हैं। इसमें कम्पनी के माल की विक्री बढ़ती है। बीमा कम्पनी अपने साहकों में स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी फैलानी है ताकि वे दीर्घायु हों और उन्हें कम से कम धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़े। इस प्रकार निम्न है कि व्यापारिक सम्थान सामाजिक शिक्षा में लाभ उठाने हैं और अपने हित में सामाजिक शिक्षा का प्रचार करते हैं।

कुछ अप्रत्यक्ष साधनों में भी सामाजिक शिक्षा के प्रचार में बड़ी सहायता मिलती है। वे हैं—पुस्तकालय, संग्रहालय और प्रदर्शनी। बड़े-बड़े नगरों में मार्क्स-जिनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था होती है जिनमें सैकड़ों प्रौढ़-जन आकर समाचार और पुस्तकें पढ़ते हैं। अथवा अनेक सरकारी दफ्तरों और विभागों में पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले गये हैं ताकि कर्मचारी मनोरंजन के लिए साहित्य पढ़ें और ज्ञान को विकसित करें। रेलवे के अनेक कार्यालयों में यह व्यवस्था है। संग्रहालयों की सहायता से सामान्य जनता के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रदर्शनों के द्वारा नये-नये विकसित साधनों और जीवनोपयोगी वस्तुओं का परिचय कराया जाता है। लोग यहाँ मनोरंजन के लिए जाते हैं परन्तु उनका ज्ञान बढ़ता है। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष साधन सामाजिक शिक्षा के प्रचार में अत्यन्त सहायक हैं।

सामाजिक शिक्षा की कुछ नयी सत्वाएँ उत्पन्न हो रही हैं। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय अपन ऊपर यह जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं। वे अध्यापकों और छात्रों की सहायता में लम्बे अवकाशों में यह जानांजन आगे बढ़ाएंगे। कुछ विश्व-विद्यालय 'पत्राचार द्वारा शिक्षण' का कार्यक्रम चलायेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह महत्त्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ कर भी दिया है। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए उपयोगी है जो शिक्षित हैं और किसी न किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन लोगों को नव

विकसित ज्ञान को नहरों में स्नान कराना है ताकि वे समय में पीछे न रह जायें। पत्राचार द्वारा वे विश्वविद्यालयों के निकट रह सकेंगे और वे नयी उपाधियाँ पाकर उन्नति भी कर सकेंगे। इसी प्रकार की एक अन्य योजना है 'हवाई विश्वविद्यालय' की। यह विश्वविद्यालय रेडियो तरंगों की सहायता में चलेगा। पूरे वर्ष के लिए आकाशवाणी की सहायता में दैक्षिक भाषणों का प्रसारण किया जायगा। सभी विषयों पर यह भाषण होंगे। प्रौढ़ जन घर बैठे यह भाषण उसी प्रकार सुनें जैसे विश्व-विद्यालय में कक्षा भवनो के भीतर छात्र प्राध्यापकों के भाषण सुनते हैं। वर्ष के अन्त में वे परीक्षा दे सकेंगे। इन नवीनतम साधनों के प्रयोग से सामाजिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लायी जायगी।

भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं के विकास पर जोर दिया है। उसके प्रतिवेदन में बताया गया है कि यद्यपि सरकार को प्रौढ़ शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथापि इसका भार अन्य सामाजिक संस्थाओं को ओढ़ना पड़ेगा। जिन संस्थाओं की ओर सकेत किया गया है, वे हैं—बड़े-बड़े कारखाने तथा कृषि-कामों के मालिकों द्वारा संचालित सामाजिक शिक्षा की संस्थाएँ, पञ्चवर्षीय योजनाओं के चलाने के लिए बनायी गयी सरकारी संस्थाओं की इकाइयाँ, छादी-उद्योग, समाज-कल्याण, सामुदायिक विकास एण्ड, शिक्षा संस्थाएँ, पेटेकर लोगो जैसे डाक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों के संगठन, रूलर ईस्टीमेट, विद्यापीठ (जैसे मैसूर में काम कर रहे हैं), विश्वविद्यालयों के सामाजिक शिक्षा के विभाग, पुस्तकालय संगठन तथा पचायते आदि।

### वर्तमान समय में सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व

सामाजिक शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र—प्रो० हुमायूँ कबीर ने कहा है कि सामाजिक शिक्षा अध्ययन का एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य नागरिकता की चेतना पैदा करना तथा सामाजिक संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। यह एक ऐसा नियमित अनुभव है जो व्यक्तियों की सामूहिक कार्यों में भाग लेने की क्षमता में वृद्धि करता है। यह एक ऐसा मौखिक कार्यक्रम है, जो उस औपचारिक शिक्षा से भिन्न है, जो स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कालेजों में दी जाती है। सामाजिक शिक्षा उनके लिए है, जिन्हें औपचारिक शिक्षा मिलना या तो बंद हो चुका है या फिर जिन्हें औपचारिक शिक्षा मिलने का भुवनेश्वर ही नहीं मिल पाया। यह ठीक है कि इस प्रकार की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य निरक्षरता के किलों को ध्वस्त करना है परन्तु इसका उद्देश्य उस अज्ञानता को भी नष्ट करना है, जो भारत में प्रायः सभी शिक्षित जनता को पुनः के समान लगकर जर्जर बनाती रहती है क्योंकि अपने-अपने पेजे में लगे जान के बाद वे ज्ञानात्मक विचारों की ओर से उदासीन हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश में अधिकांश शिक्षित जन अज्ञानता के गड्ढे में पुनः गिर जाते हैं और उनकी शिक्षा-दीक्षा बेकार हो जाती है। अब सामाजिक शिक्षा ऐसी श्रृंखला है जो

हर नागरिक के मन में ज्ञान की ली जीवन भर जगमग रमती है। वह उसको क्षमताओं और योग्यताओं के विकास में बराबर सहायता करती रहती है।

सामाजिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। यह जीवन के हर कोने को छूती है। इसके कार्यक्रम के अन्तर्गत वे कदवी उम्र के लड़के-लड़कियाँ भी आ जाते हैं जिनके माता-पिता उन्हें शिक्षा नहीं दे पाते परन्तु विशेष रूप में वे सभी बचस्क इसमें लाभ उठाते हैं जिन्हें औपचारिक शिक्षा का अवदान नहीं मिला। इसके अनिर्दिष्ट सामाजिक शिक्षा उन सुशिक्षित, सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत जनों के लिए भी है, जो ज्ञान के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। इस प्रकार सामाजिक शिक्षा में सबसे बड़ा गुण निरंतरता का है।

आवश्यकता और महत्त्व—सभी प्रगतिशील तथा पिछड़े हुए देशों में सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। विश्व मंच की प्रमुख मस्था यूनेस्को सभी देशों में, विशेष करके पिछड़े हुए देशों में, सामाजिक शिक्षा के काम में बड़ी दिनचर्या में रही है और हर प्रकार की आर्थिक सहायता पहुँचा रही है। यह बात उचित ठहरी है क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जब विश्वमंच का निर्माण हुआ तो यह अनुभव प्रकट किया गया कि युद्ध की उत्पत्ति मानव मन के भीतर होती है। इसलिये यदि सहायकारी युद्धों को नष्ट करना है तो मनुष्य के मन का परिष्कार शिक्षा के द्वारा करना है। हर मनुष्य तक शिक्षा के उत्तम प्रभावों को पहुँचाने के लिए सामाजिक शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है।

प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ती हुई दुनिया मानसिक रूप में स्वस्थ नहीं है। इसके दो प्रमुख कारण हैं—एक तो निरंतर मनुष्य के दिमाग पर झूलता हुआ विनाश का भय जो आणविक युद्ध की आशंका में उत्पन्न हुआ है, दूसरा है, विज्ञान तथा नई भौतिक विचारधारा के कारण उत्पन्न मूल्यों की दून्यता। पुराने मूल्यों पर मनुष्य की आस्था नहीं रही है और नये मूल्यों का स्थायी रूप नहीं बन पाया। इस दून्यता के कारण मनुष्य विचार-विमूढ़ बन गया है। समार की इन विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य को पालन बनने में रोकने के लिए इस समय सामाजिक शिक्षा जैसे कार्यक्रम की अत्यन्त आवश्यकता है। यही कारण है कि सभी देशों में सामाजिक शिक्षा के द्वारा मनुष्य को दिग्भ्रमित होने से बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत इसका अपवाद करने हो सकता है ?

सर्व्व भारत के भीतर कई परिस्थितियाँ वर्तमान समय में ऐसी उत्पन्न हो गयी हैं, जिनके कारण सामाजिक शिक्षा का महत्त्व नई गुना ज्यादा बढ़ गया है। सबसे पहली बात यह है कि यह देश कई सदियों के बाद आजाद हुआ। गुलामी की हालत में यह आर्थिक, सामाजिक तथा ज्ञान की दृष्टि में अन्य देशों में बहुत पिछड़ गया। उन्नति की दौड़ में भारत बहुत पीछे है और अब आजादी के बाद उसे प्रगतिशील देशों के साथ कदम में कदम मिलाकर दौड़ना है। यदि ऐसा नहीं होता, तो हमारी

विकसित ज्ञान को सहज में स्नान कराना है ताकि वे समय में पीछे न रह जायें। पंचाचार द्वारा वे विश्वविद्यालयों के निकट रह सकेंगे और वे नयी उपाधियाँ पाकर उत्तम भी कर सकेंगे। इसी प्रकार की एक अन्य योजना है 'हवाई विश्वविद्यालय' की। यह विश्वविद्यालय रेडियो तरंगों की सहायता में चलेगा। पूरे वर्ष के आकाशवाणी की सहायता में दैक्षिक भाषणों का प्रसारण किया जायगा। सभी बिप पर यह भाषण होंगे। प्रौढ़ जन घर बैठे यह भाषण उसी प्रकार सुनते हैं जैसे विश्वविद्यालय में कक्षा भवनो के भीतर छात्र प्राध्यापकों के भाषण सुनते हैं। वर्ष के अन्त में वे परीक्षा दे सकेंगे। इन नवीनतम साधनों के प्रयोग में सामाजिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लायी जायगी।

भारतीय शिक्षा-आयोग ने सामाजिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं के विकास पर जोर दिया है। उसके प्रतिवेदन में बताया गया है कि यद्यपि सरकार को प्रौढ़ शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथापि इसका भार अन्य सामाजिक संस्थाओं को ओढ़ना पड़ेगा। जिन संस्थाओं की ओर सकेत किया गया है, वे हैं—बड़े-बड़े कारखाने तथा वृषि-फार्मा के मालिकों द्वारा संचालित सामाजिक शिक्षा की संस्थाएँ, पंचवर्षीय योजनाओं के चलाने के लिए बनायी गयी सरकारी संस्थाओं की इकाइयाँ, खादी-उद्योग, समाज-कल्याण, सामुदायिक विकास खण्ड, स्टील्यूट, विद्यालोट (जैसे मंगूर में काम कर रहे हैं), विज्ञानियों के संगठन, हरल शिक्षा के विभाग, पुस्तकालय संगठन तथा पंचायत आदि।

**समान समय में सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व**

सामाजिक शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र—प्रो० हुमायूँ कबीर ने कहा है कि सामाजिक शिक्षा अध्ययन का एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य नागरिकता की स्थापना करना तथा सामाजिक संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। यह एक ऐसा विषय अनुभव है जो व्यक्तियों की सामूहिक कार्यों में भाग लेने की क्षमता में वृद्धि करता है। यह एक ऐसा दैक्षिक कार्यक्रम है, जो उस औपचारिक शिक्षा से भिन्न है, जो औपचारिक शिक्षा मिलना या तो बढ़ हो चुका है या फिर बिना औपचारिक शिक्षा मिलने का मुअवजर ही नहीं मिल पाया। यह ठीक है कि इस प्रकार के प्रमुख उद्देश्य निरक्षरता के किलों को ध्वस्त करना है परन्तु यह भी नष्ट करना है, जो भारत में प्रायः सभी वर्गों में पाया जाता है। यह नष्ट कर ज़रूर बनाती रहती है क्योंकि अपने-अपने स्वार्थ के विनाश की ओर में उदासीन हो जाने है। यह देश में अधिकांश निश्चित जन अज्ञानता को दूर करने का साधन है। शिक्षा-दीक्षा बेकार हो जाती है।



त्रिकों द्वारा जन-मानस को विक्षिप्त और मूर्च्छित होने में बचाया जा सकता है। प्रचार की जगह शक्ति को सशक्त शिक्षा नियंत्रण में रखा सकती है।

हमारे देश में एक तीसरी परिस्थिति देश के विभाजन में पैदा हुई है। इस घटना ने अनेक लोगों को बेघर-बार कर दिया और पाकिस्तान में शरणार्थियों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, वे अभी भुलाए नहीं जा सके हैं। गांधी की मर्यादा में आए हुए यह शरणार्थी देश के कोने-कोने में बसे हैं। उनके मन में अमनोप और दुष्टता है; जिन लोगों ने उनके मोर्चे के समारंभों में घूमने में मिलाया है, उनके मर्यादा भी भारत में बहुत बड़ी समस्या में हैं। उनके प्रति शरणार्थियों के मन में कभी भावनाएँ हैं, यह महज ही समस्या जा सकती है। इस परिस्थिति के कारण मात्र देश में सामाजिक तनाव है। अत्यंत शक्ति युक्त मानसों में भय और प्रतिस्पर्धा का भाव है। यह परिस्थिति देश की एकता के लिए घातक है। तनाव, उत्तेजन, प्रतिस्पर्धा और दुर्भावना के साथ-साथ भय का अनुभव करना आवश्यक है। सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम द्वारा इन शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों के मन को शांति पहुँचाई जा सकती है। इसी प्रकार युद्ध में लोटे घायल सैनिकों, नौकरी में हटाए गये सैनिकों को पुनः जीवन में प्रवेश कराना और उन्हें मानसिक रूप में स्वस्थ रखने का काम भी सामाजिक शिक्षा कर सकती है।

एक सामाजिक परिस्थितियों को मॉडल। वर्तमान दुनिया बदल चुकी है और घरे परिवर्तन इनकी तेजी में होने हैं कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी समय में पिछड़ा जाता है। सामाजिक शिक्षा के द्वारा इन परिवर्तनों में अवगत कराया जाता है। इस मशीनी युग में मनुष्य के पास पर्याप्त अवकाश होता है। यदि इस अवकाश का अच्छी तरह सदुपयोग नहीं किया जाता, तो अपराधवृत्ति बढ़ती है। सामाजिक शिक्षा के द्वारा अवकाश का उपयोग मानवर्धन के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से इन समय कला और संगीत जैसे स्वर्गीय कलाओं में व्यापार की भावना प्रवेश कर गयी है और मनुष्य की सौन्दर्य बोध की शक्ति कुटिल होनी जा रही है। यह सब धन-लोभुपना और राजनीतिक प्रचार के कारण हो रहा है। सामाजिक शिक्षा का मुख्यतः कार्यक्रम इन दुष्टवृत्तियों को रोकने में सफल हो सकता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ समाज में बड़ी तेजी से मानवीय मूल्यों जैसे प्रेम, करुणा, ईश्वरी, सहानुभूति और सेवा का क्षय होता जा रहा है। शिक्षित जनों का जीवन धीरे-धीरे मरुभूमि बनता जा रहा है। श्री सी० ई० एम० बोंड ने अपनी पुस्तक 'अवाउट एक्स्पोज़र' में लिखा है

“प्रतिष्ठित मन तथा विकसित सचियों वाले मनुष्य के लिए यह सभार ज्यादा बड़ा और स्फुटिदायक बन जाता है। वह हममें कहीं अधिक सुन्दरता, विविधता, वेगता है और शिक्षा पात्र में पूर्व जैसी उसकी स्थिति थी, उसमें नहीं अधिक वह अपनी महानुभूति और समझ की गहराई देख सकता है। उसकी अनु-

आजादी गनरे में रहेगी। गारे विद्रोहण को दूर उनके समय को पहुँचा है। इनविण्ण दण में पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ हुआ है। पञ्चवर्षीय योजनाएँ बनी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए देश गारे साधन जुटा रहा है परन्तु उनकी मद्धता जन-महयोग पर निर्भर है। जन-महयोग अज्ञानता के कारण नहीं मिल रहा है क्योंकि सामान्य जन पुनर्निर्माण के महत्त्व को नहीं समझता। देश में फँसी निरक्षरता और अज्ञानता देश की उन्नति में बाधा रखे कर रही है। गान्ध दा गान्ध म विद्यान्व जनसम्प्रदाय को कैसे उन स्तर पर लाया जाय, जिन पर अन्य देशों के लोग पहुँच चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि किया गया जाय। प्रो० हुमायूँ कबीर का कहना है कि हमें मिथा के प्रसार का दृष्टिकार नहीं करना है। निरक्षरता-निवारण के लिए कोई तत्कालीन कार्यक्रम चाहिए जो सामाजिक मिथा के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। इसके द्वारा ही भारत की विद्यान्व जनता का देश के पुनरुद्धान में लगाया जा सकता है।

देश के भीतर दूसरी परिस्थिति प्रजातंत्र की स्थापना में पैदा हुई है। हमने मविधान बनाकर प्रजातन्त्र स्थापित करने का प्रण तो कर लिया परन्तु जनमानस को प्रजातन्त्रिक जीवन के लिए तैयार नहीं किया। यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है। डा० मन्मथेन ने अपनी पुस्तक 'एङ्ग्लेसतन गोकान्स्टुशन की समस्याएँ' में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि जब तक देश के काम में सामान्य जनता दिलचस्पी में नै, जनतंत्र पन नहीं सकता। सामाजिक मिथा के द्वारा अध-विश्वास, स्वार्थ और रुढ़िवादिता का समाप्त करके सामान्य जनो को सहयोग देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अनिश्चित प्रजातन्त्र के मार्ग में जीर कई बाधाएँ हैं। जैसे, जनता को अपनी राय कायम करने की स्वतन्त्रता तो है परन्तु सामान्य लोग बड़ी आसानी से अपना स्वतन्त्र चिन्तन खो बैठते हैं। वे राजनीतिक और साम्प्रदायिक विचारों के शिकार आसानी से बनते हैं। मिनेमा, रेडियो, समाचार-पत्र तथा प्रकाशित साहित्य विचारों को बढी बना लेने में बडे सधन हैं। निरक्षर सरकारें इनका उपयोग करके मिथित जनो की विचार-स्वतन्त्रता को मूच्छित करके मुत्ता देनी हैं और उन पर राज्य करती हैं। हमारे देश में, एक ओर जनता अधिक्षित है और दूसरी ओर इन सामूहिक प्रचार साधनों का प्रयोग राजनीतिज्ञ अपने लान के लिए कर रहे हैं। और इन प्रकार जनतन्त्र पर बडा भारी धनरा मंडग रहा है। श्री मन्मथेन के मन में "एक अधिक्षित प्रजातन्त्र (जैसे भारत) जो कट्टरता और पक्षपात के यदा-कदा भोको से हिल उठता है और स्वार्थी प्रचारकों के चतुर उपायों को समझ नहीं पाता, की मुख-शान्ति और मुरक्षा के लिए बहुत बडा खतरा है।" दूसरी ओर सामूहिक प्रचार के साधन "विचारों की स्वतन्त्रता और निर्णय पर हावी हो जाते हैं और करोड़ों मनुष्यों के भीतर कुछ निश्चित प्रकार के व्यवहार और विचार उत्पन्न करने में, कुछ लोग इन प्रचार साधनों की महायत्ना में सफल हो जाते हैं।" (जैसा कि हम या धोन में हो चुका है) इन नभाम खतरों में बचने का एकमात्र साधन सामाजिक मिथा है

जिनके द्वारा जन-मानस को विभिन्न और मूर्च्छित होने में बचाया जा सकता है। प्रचार की प्रणाली शिक्षा को समाज शिक्षा नियंत्रण में रख सकती है।

हमारे देश में एक तीसरी परिस्थिति देश के विभाजन में पैदा हुई है। इस घटना ने अनेक लोगों को बेघरबार कर दिया और पाकिस्तान में घटनाधियों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, वे अभी भुलाए नहीं जा सके हैं। लोगों की समस्या में आये हुए यह शरणार्थी देश के कोने-कोने में बसे हैं। उनके मन में अमनोप और दुष्टा है; जिन लोगों ने उनके मोने के समार को धून में मिटाया है, उनके सहधर्मों भारत में बहुत बड़ी मर्यादा में हैं। उनके प्रति शरणार्थियों के मन में कभी भावमाएँ हैं, यह सहज ही समझा जा सकता है। इस परिस्थिति के कारण सारे देश में सामाजिक-आर्थिक तनाव है। अल्पसंख्यक मुसलमानों में भय और प्रतिकार का भाव है। यह परिस्थिति देश की एकता के लिए घातक है। तनाव, उत्तेजन, प्रतिहिमा और दुर्भावना के साथ-साथ भय का उन्मूलन करना आवश्यक है। सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम द्वारा इन घटनाधियों और अल्पसंख्यकों के मन को शांति पहुँचाई जा सकती है। इसी प्रकार युद्ध में लोटे घायल सैनिकों, लोकरों में हटाये गये सैनिकों को पुन जीवन में प्रवेश कराना और उच्च मानसिक रूप में स्वस्थ रहने का काम भी सामाजिक शिक्षा कर सकती है।

यह सामान्य परिस्थितियों को लोंगिए। वर्तमान दुनिया बदल चुकी है और सारे परिवर्तन हमनी तेजी से होते हैं कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी समय में पिछड़ जाता है। सामाजिक शिक्षा के द्वारा इन परिवर्तनों में अवगन कराया जाता है। इस मशीनी पुन में मनुष्य के पास पर्याप्त अवकाश होता है। यदि इस अवकाश का अच्छी तरह सदुपयोग नहीं किया जाता, तो अपराधवृत्ति बढ़ती है। सामाजिक शिक्षा के द्वारा अवकाश का उपयोग जानबूझने के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से इस समय कला और मशीन जैसे स्वर्गीय तत्वों में व्यापार की भावना प्रवेश कर गयी है और मनुष्य की मीठय बोध की शक्ति कुटिल होती जा रही है। यह सब घन-नोनुपना और राजनीतिक प्रचार के कारण हो रहा है। सामाजिक शिक्षा का सुगठित कार्यक्रम इन दुष्टवृत्तियों को रोकने में सफल हो सकता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ समाज में बड़ी तेजी से मानवीय मूल्यों जैसे प्रेम, करुणा, मैत्री, महानुभूति और सेवा का क्षय होता जा रहा है। विभिन्न जनों का जीवन धीरे-धीरे मरभूमि बनता जा रहा है। श्री सी० ई० एम० जोड ने अपनी पुस्तक 'अवाउट एन्डकेमन' में लिखा है

“प्रशिक्षित मन तथा विषमिन् रचियों वाले मनुष्य के लिए यह समार प्यादा बड़ा और स्फूर्तिदायक बन जाता है। वह इसमें कहीं अधिक सुन्दरता, विविधता देखता है और शिक्षा पाने में पूर्व जैसी उमकी स्थिति की, उसमें कहीं अधिक वह अपनी महानुभूति और समझ की सफलता देख सकता है। उसकी अनु-

भूति प्रवल हो जाती है और वह दण्ड, कारगुन और कर्मशास्त्र की तुच्छ दुनिया को एक रहस्य भरे विश्व तथा सुन्दरता के कोप में बदल देती है।”

मनुष्य जिस प्रकार इस जड़ मय्यता के जगुन में फँस कर स्वयं जड़ बनता जा रहा है, उसमें बड़ी हानि यह होगी कि मानवता ही नष्ट हो जायगी। सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम द्वारा उसे बचाना होगा।

आज सामाजिक शिक्षा पर बहुत बड़ा उन्मत्तभाव है। यह औपचारिक शिक्षा को बल पहुँचाने वाली है। समाज और परिवार के दूषित वातावरण के कारण बच्चों की शिक्षा सफल नहीं हो पा रही है। इस परिस्थिति में सामाजिक शिक्षा के द्वारा ही सुधार लाया जा सकता है। परिवारों में होने वाली टूट-फूट, बेचैनी और सकट के कारण उत्पन्न वातावरण को, जो शिक्षा के लिए हानिकारक है, सामाजिक शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। नागरिकों के मनोबल को पुष्ट करने, उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता का विकास करने तथा चरित्र-निर्माण करने का साधन भी सामाजिक शिक्षा है।

सामाजिक शिक्षा एक रचनात्मक प्रभाव है जो धीरे-धीरे परन्तु हड़तापूर्वक परिवर्तन लाता है। हमारे देश को इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह हमारी अनेक भावात्मक समस्याओं को हल कर सकती है। यदि इस देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है तो ज्ञान, सम्प्रदाय, धर्म और संस्कृति के भेदों को कम करके एक सामान्य भारतीय परम्परा को लोकप्रिय बनाना होगा जो विभिन्नताओं के बीच सबको स्वीकार्य हो। यह कार्य सामाजिक शिक्षा के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सामाजिक शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए डा० बी० के० आर० बी० राव, योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य, की पुस्तक 'Education and Human Resource Development' का एक अंग इस प्रकार उद्धृत किया है

“प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षण के बिना न तो आर्थिक और सामाजिक विकास की उस गति और दूरगामीता के साथ पूरा कर सकते हैं, जो अपेक्षित है और न इस आर्थिक और सामाजिक विकास में यह तत्त्व या उत्तमता या विशेषता होगी, जो इसे कल्याण तथा भूख की दृष्टि में उपयोगी बना सकते हैं। अतः आर्थिक और सामाजिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में प्रौढ़-शिक्षा और प्रौढ़-शिक्षण को अग्रिम स्थान मिलना चाहिए।”

तदनुसार शिक्षा आयोग का यह मन है कि “वह समाज जो आर्थिक विकास, सामाजिक पुनरोदय और प्रभावशाली सुरक्षा की स्थिति पैदा करने के लिए हित-मय हो उस समाज में कार्य सम्पन्न वा प्रमुख अंग यह होगा कि यह अपने लोगों को स्वच्छतापूर्वक, बुद्धिमानी और मशमला के साथ विकास के कार्यक्रमों में भाग ले के लिए उनमें शिक्षा प्रदान करे। ऐसा उस समाज के लिए (जो भारत में है)

विशेष रूप से आवश्यक है जिसमें सामान्य जनो की शिक्षा न मिली हो और जहाँ की शिक्षा विधामात्रक आवश्यकताओं से तालमेल न रखती हो।"

हमारे देश की विभिन्न समस्याएँ हैं, जो देश के विकास में रोड़ा अटका रही हैं। उदाहरण के लिए, अन्न की कमी और जनसंख्या की वृद्धि को नें। जायोग का मत है कि अधिश्रित जनता को इन दोनों समस्याओं की भयानकता की जरा भी अनुभूति नहीं है। न तो वे इनकी सम्भीरता को समझते हैं और न उन्हें हल करने के नवीनतम उपायों की जानकारी रखते हैं। इस समय बहुतों दुई आबादी को रोकने के लिए केवल दण्ड का सम्भालने की प्रणाली में काम लेना उचित नहीं है और न इससे समस्या हल होगी। अब तक सामान्य जन इन समस्याओं में जाने वाले कुपारणामों को नहीं समझ पाते, उन पर नियन्त्रण पाने के उपाय नहीं जानते और अपनी जिम्मेदारी नहीं सम्झ पाते, सरकारी प्रयत्न मजबूत नहीं हो सके। जल्द राष्ट्रीय समस्याओं का अन्तिम हल शिक्षा के हाथ में ही रहेगा। आयोग ने बताया है—

"कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा का काम केवल पुलिस और सेना को नहीं सौंप सकता। अधिकांश तोर पर राष्ट्र की सुरक्षा नागरिकों की शिक्षा, राष्ट्र की नीति की जानकारी, उनके चरित्र, उनके अनुशासन और सुरक्षा के लिए अपनाए गए उपायों में समान रूप से नागरिकों के भाग लेने पर निर्भर है।"

इस दृष्टि में शिक्षा की महान् जिम्मेदारी है परन्तु हमारे देश में निरक्षरता बढ़ती जा रही है। जिस गति से आबादी बढ़ रही है, उस गति में साक्षरता नहीं बढ़ रही। इस स्थिति पर नियन्त्रण पाने का उपाय सामाजिक शिक्षा ही है।

### सामाजिक शिक्षा के लक्ष्य

सामाजिक शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए जुलाई १९४६ में ही विभिन्न राज्यों के सामाजिक शिक्षा अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में यह तय हुआ था कि एक समिति को यह काम सौंप दिया जाय। वह समिति सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक ऐसी पुस्तिका तैयार करे जो इस क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करके समाज-शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए मिली गयी हो। इस समिति के सदस्य थे डा० बी० एम्० भा, डा० आई० आर० खान, श्री के० जी० सम्मदन, श्री एम्० आर० किरवई और श्री के० एल्० जोशी। इस समिति के द्वारा वित्तित एक पुस्तिका शिक्षा मन्त्रालय में प्रकाशित की। उसमें सामाजिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—

उद्देश्य—राष्ट्रीय महत्त्व की दृष्टि से निर्धारित किसे तीन सामान्य उद्देश्य हैं—  
(१) सामाजिक संपर्क (Social Cohesion)—इसकी आवश्यकता इसलिए है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण भारतीय समाज के सदस्यों में अंतर्भाव और पूर्वाग्रह

। समाज में अनेक वर्ग इसी कारण बने हैं, जैसे भाषाई, धार्मिक, हरी-देहानी, शिक्षित-अशिक्षित, धनी-निधन आदि। सामाजिक शिक्षा वर्तमान अलग-अलग को दूर करके सारी भारतीय जनता के बीच एक का भाव उत्पन्न करना है। (२) राष्ट्रीय कार्यक्षमता (Nationality)—भारत एक नवोदित राष्ट्र है। इसकी मुक्त शक्तियों को जागृत करना अभी वह चेतनापूर्ण तथा उत्पादक राष्ट्र बन सकेगा। (३) राष्ट्रीय विकास का विकास (Development of National Resolution)—और विश्वास उत्पन्न करना आवश्यक है ताकि उनकी अपनी शक्ति का और वह उनका भरमक उपयोग कर सके।

—सामाजिक शिक्षा के प्रत्यक्ष लक्ष्य कई हैं, जैसे

साधारण कुशलताओं का विकास (जैसे भाषा का पढ़ना, लिखना और गणित जोड़ना)।

सामान्य जनता की व्यावसायिक क्षमता का विकास, जैसे महुरों में कृषि की तथा औद्योगिक ज्ञान वस्तु देहानों में कृषि और कुटीर उद्योग का ज्ञान प्रचारित करना।

स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना, सागतीर पर स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए बीमारियों के उन्मूलन के उपाय प्रदान करना।

सामाजिक कुशलताएँ उत्पन्न करना, जैसे परिवार तथा समाज के प्रति उत्तरदायी और अधिकारों की चेतना पैदा करना।

समोदजन के स्वस्थ उपायों की जानकारी देना ताकि अवकाश का उपयोग न्यायिक कर सके। समोदजन के रूप में प्रचलित सरासरी, भ्रम, गपधप तथा अनेक झूठों के स्थान पर स्वस्थ मार्गदर्शक पद्धतियों और विधियों में मान उठाने, गैर-बुद्ध और भ्रमपूर्ण भावों के उपायों का परिचय देना।

धार्मिक विचारों की सुविधाएँ प्रदान करना जैसे साहित्यिक चेतना उत्पन्न करके नागरिकों में ईमानदारी की भावना मजबूत करना, नैतिक तथा नैतिक स्वार्थों में ऊपर उठकर उत्तम सुझाव और आदर्शों के प्रति प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति पैदा करना आदि।

आ के मार्ग में उत्पन्न बाधाएँ और समस्याएँ

सामाजिक शिक्षा के सामने भारत में सबसे बड़ी कठिनाई निम्नलिखित की अपेक्षाओं का निराकरण करना है कारण सामाजिक शिक्षा के माध्यम से न केवल सामान्य जनता को शिक्षित करना है, बल्कि यह है कि यह एक ऐसा प्रयत्न है, जो प्रचलित गैर-न्यायिक विचारों को दूर करने का प्रयत्न है।

लाभ नहीं उठा सकते। जब उनमें बुनियादी भाषाई मुश्किलता ही नहीं है, तो वे उद्देश्यों और मन्त्रों की पूर्ति ही नहीं कर सकते।

(२) दूसरी समस्या बड़ती हुई आबादी की है। इस देश की विशाल जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जितने बच्चे पैदा होत हैं, उन मन्त्रों लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर सकना असम्भव है। इसलिए निरक्षरता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय की कृपासे ने अभी कुछ दिन पूर्व विद्युत् समस्या पुनेस्को द्वारा आयोजित साक्षरता दिवस के अवसर पर इस समस्या का उल्लेख करते हुए कहा था कि बड़ती हुई आबादी हमारे साक्षरता प्रयत्न पर पानी फेरे दे रही है।

(३) पाठ्यक्रम की समस्या तीसरी है। प्रौढ-जनों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार निम्ने गये साहित्य का हमारे देश में बड़ा अभाव है। इन लोगों के लिए सामाजिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी स्थिर नहीं हुआ। नवसाक्षरों के लिए पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ तथा पाठ्य-सामग्री का उत्पादन नहीं हुआ है। यह समस्या और भी अधिक जटिल हो गयी है क्योंकि इस देश में अनेक भाषाएँ हैं और उन सभी में पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में लिखना बहुत कठिन काम है।

(४) चौथी समस्या शिक्षण-विधि की है। स्कूलों में जिस शिक्षण-विधि का प्रयोग किया जाता है, वह प्रौढ-जनों के उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रौढ-जनों का मनोविज्ञान भिन्न प्रकार का होता है। यह लोग बड़ी हुई उम्र के कारण निमने-पढ़ने में उरमाह नहीं रखते, सीखने समय उनमें प्रतिरोध की भावना होती है, उनकी रुचियाँ स्थायी हो जाती हैं, वे परिवार की जिम्माओं में प्रस्त होते हैं, उनमें अह का भाव अत्यधिक विकसित होता है। ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षण-विधि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रौढ-जनों की कुछ कठिनाइयाँ हैं, जैसे समय की कमी, जिम्मेदारी का बोध, अर्धाभाव, और रुचियों का प्रभाव। शिक्षण-विधि को इन कठिनाइयों के अनुकूल बनाना आवश्यक है और अभी तक आदर्श शिक्षण विधि का विकास नहीं हो पाया है।

(५) पाँचवी कठिनाई अध्यापकों की कमी है। सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्पादक सामाजिक कर्मकर्ता या प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च-शिक्षा के अध्यापक ही काम कर रहे हैं। यह लोग सामाजिक शिक्षा की समस्याओं और प्रौढ-जनों की मनोवैज्ञानिक स्थिति में परिचित नहीं होते। सामाजिक शिक्षा देने के लिए लाखों की संख्या में जिस प्रकार के प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए, वे उपलब्ध नहीं हैं। सामाजिक शिक्षा देने वाले अध्यापक में उत्साह, नेतृत्व, सहिष्णुता, भाईचारा और सहयोग के गुण होने चाहिए। इन गुणों में युक्त अध्यापक काफी संख्या में नहीं मिलते।

(६) छठी समस्या साधनों की है। सामाजिक शिक्षा को सफल बनाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। वे हैं - फिल्म, फिल्मछात्र, लावटेन

की स्लाइडें, चित्र, चार्ट, फोन्ट, रेगानिच, प्रदर्शनी, गचन प्रदर्शनी, सप्रह पुस्तकालय, गचन पुस्तकालय, रेडियो, टेलीविजन, पत्र-पत्रिकाएँ, नव-माधुर्य साहित्य, ग्रामोफोन रेकार्ड, वार्ता, गोप्टी, गाम्बुनिक कार्यक्रम, मेले, भजनमण्डल, नृत्य-मंचीय समारोह, धार्मिक उत्सव, यात्राएँ, गुरुवर्ती यात्राएँ, देश-दर्शन नाटक आदि। इन विविध प्रकार के माधुनों की कमी हमारे देश की सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम में अनुभव हो रही है। यह समस्या धनानाश के कारण उत्पन्न हुई है।

(७) मानवी समस्या जनता की गरीबी की है। हमारे देश का जीवन-और आय बहुत नीचे बिन्दु पर है। यदि उनमें अपनी शिक्षा की प्रति धनना उत्पन्न हो तो प्रौढ आयु में वे हम मद में खर्च करने की योग्यता नहीं रखते। महँगे और धनानाश के कारण वे अपनी प्राथमिक आवश्यकताएँ ही नहीं पूरी कर अपनी शिक्षा पर वे कहाँ में व्यय कर सकेंगे।

(८) आठवी समस्या उत्तरदायित्व की है। हम पहले ही बता चुके हैं सामाजिक शिक्षा का काम अनेक सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संस्थाओं में फैला हुआ है। कोई एक मत्ता ऐसी नहीं है जो सामाजिक शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। इसमें हर संस्था जो कुछ कर पाती है, करती है परन्तु कोई पूरा उत्तरदायित्व नहीं अनुभव करता।

(९) नवी समस्या सरकार की असमर्थता और उदासीनता की है। एक बार हम अन्य प्रसङ्गों में बता चुके हैं कि कई देशों की सरकारें शिक्षा पर दिल खोल खर्च करती हैं, क्योंकि वे इसे 'पूँजी निवेश' (Investment) मानती हैं। भारत सरकार ने अभी तक शिक्षा के प्रति वही कदम अपना रखा है, जो विदेशी सरकारें का था। वह देश के आर्थिक विकास और सुरक्षा पर ही ध्यान केन्द्रित कर रही है और यह अनुभव नहीं करती कि शायद यह सारे कार्यक्रम सामाजिक शिक्षा के बिना सफल नहीं हो सकेंगे। सरकार के साधन सीमित हैं और उनकी कठिनाईयाँ भी इस उपेक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। सामाजिक शिक्षा को सफल बनाने के लिए सरकार के सारे कार्यक्रम बुद्ध के पैमाने पर चलाना पड़ेगा परन्तु यह अनुभूति सरकार में पैदा नहीं हुई है।

### समस्याओं का हल

सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का जो विवरण ऊपर दिया जा चुका है, उसमें यह स्पष्ट हो जायगा कि देश और भारतीय जनता की जाति-धर्मता को देखते हुए, उनका हल निकालना बड़ा कठिन है। फिर भी समय-समय पर विद्वानों ने जो उपाय सुझाए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

'नया शिक्षक' (बीकानेर में प्रकाशित) के प्रो. ए. व. सामाजिक शिक्षा के विरोधाभास में श्री एन० के० पन्त ने एक लेख में कहा है कि आकाशीय विश्वविद्यालय (Radio or Air University) के माध्यम से शिक्षा देना और यह



साधन है। मत्त २० वर्षों में हम देश में सहृदी जनता ने रेडियों के भेट खरीदे ही है, देहानो में इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पचायतो और सामुदायिक विकास मण्डो में मार्गजनिक रेडियो सेट उपलब्ध हैं जिनमें हर व्यक्ति लाभ उठा सकता है। जब यह सम्भव है कि देश के कोने-काने तक सामाजिक शिक्षा का एक-मधान (Uniform) कार्यक्रम आवाशवाणी के द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालयों की भाषणमाला के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए यह आकाशीय विश्वविद्यालय कहा जायगा। विभिन्न विषयों की शिक्षा घर बैठे लोग ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में कई लाभ हो सकते हैं, जैसे मस्ते में शिक्षा का पूरा होना, नवको शिक्षा के गमान अवसर मिलना, प्रौढ़-जनो के अवकाश का, शिक्षा के लिए मनुष्योम, राष्ट्रीय माधमों पर कम से कम दबाव तथा शिक्षा का लचीलापन। आकाशीय विश्वविद्यालय की सहायता से अध्यापकों की कमी, प्रौढ़ों की कठिनाह्या, जनमस्या की विमालना तथा प्रौढ़ों की निरक्षरता (जिनके कारण वे पढ़ने में असमर्थ हैं) आदि समस्याओं का सरलता में हल हो जाना है। इसके लिए केवल आवाशवाणी का एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है और पुराणों, स्थियों और धुवकों के लिए भिन्न-भिन्न समय पर कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकते हैं।

अपने एक लेख (प्रयांजनमशील प्रौढ़-शिक्षा 'भारतीय शिक्षा', मार्च १९६६) में राजकीय मिशन सस्थान, उदयपुर के निदेशक श्री वास्तवीविद निवारी ने कहा है कि हमारे देश का निरक्षर जन उनमा मूर्ख नहीं है, बितना हम समझते हैं। वास्त-विकता यह है कि हम उसे अपने हरादो के पीछे द्विरो ईशानदारी का विश्वास नहीं करा पावे हैं। हमारी सामाजिक शिक्षा की योजनाएं प्रयोजनमशील न होने में आम भारतीयों की आकृष्ट नहीं कर पा रही हैं। दोष उन आयोमको का है जो सामान्य जनता को प्रेरित करने में असफल रहे हैं। हमारे, हम उनकी समस्याओं और कठिना-ह्यों को समझने का प्रयत्न नहीं करते। प्रौढ़-जन सामाजिक शिक्षा से होने वाले लाभो को नहीं पहचानते, उनके पास समय की कमी है, वे नियमित रूप में पढ़ाई जारी नहीं रख सकते, सुविधाएं भी कम हैं और वे उनमें लाभ भी नहीं उठा पाते। इनके विरुद्ध हमने जिन लोगों को प्रौढ़ शिक्षा की जिम्मेदारी मीपी है, वे 'हुवम' देना जानते हैं, सरकारी अफमरों में झु-बाम और अलगाव की भावना है, जन-सहयोग का न तो वे अर्थ समझते हैं और न वे वास्तव में कोई काम करना ही चाहते हैं। इसलिए सम-म्याओं को हल करने में हम अमफल रहे हैं।

श्री निवारी ने पूरी समस्या पर विचार करने के बाद कई उपयोगी उपाय सुझाये हैं, यथा—(१) सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम क्यानुसार बनाया जाय, और जिन वय-वर्ग के लिए जमी शिक्षा की आवश्यकता हो, उनका प्रबन्ध किया जाय। हर वय-वर्ग में वर्तमान शिक्षा की कमजोरी को दूर किया जाय। (२) शिक्षा को

मनोरंजन-प्रधान बनाया जाय, जैसा कि भारत में आदिकाल में होता आया है। (३) प्रौढ़-शिक्षा का कार्यक्रम उपयोगितापूर्ण होना चाहिए। प्रौढ़-जन जो भी मीने, वह उनके दैनिक जीवन और कारोबार के लिए मार्गक सिद्ध हो। ऐसा तर होना जर उनके लिए बीमारी, स्वास्थ्य, पेय, सफाई, कुटीर उद्योग, बच्चों का भरण-पोषण, माणभायी, पशु-चिकित्सा और मरम्मत के काम आदि विषयों पर साहित्य दिया जाय और उनके माध्यम में शिक्षा दी जाय। (४) अध्यापकों को सेवा कार्य के दक्षिण लाभ, पद और सम्मान मिलना चाहिए। (५) लम्बी-लम्बी बाने करने वाले नेतागण उत्तम नेतृत्व-प्रदान करें और बड़ प्रेरणाप्रद हो। हवाई बाने न करके वे यथायं की भूमि पर उतरें तो अच्छा हो। (६) हम अपने माने कार्यक्रम को देन और काल के साथ में जान कर बनाये, विदेशों की नकल में काम नहो चल सकता।

भारतीय शिक्षा आयोग ने प्रौढ़-शिक्षा की समस्या पर विस्तार में विचार किया है। उसके प्रतिवेदन में बताया गया है कि प्रौढ़-शिक्षा के कार्यक्रम का चूट बड़ पैमाने पर एक साथ चलाना हम देश में सम्भव नहीं है। हम काम को चूट-चरणों (Stages) में चलाना चाहिए। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में यह कार्य कार्यक्रम भिन्न-भिन्न समय पर हो चुका हो सकेगा। किन्तु भी यह याद रखना है कि साक्षरता और प्रौढ़-शिक्षा के लक्ष्य का पूरा करने में बहुत समय न लगाया जाय। लक्ष्य-निर्धारण के प्रथम में आयोग ने जून १९६३ में उद्घाटन में पुनर्स्था के लक्ष्यारधान में जान वाले निम्नलिखित उद्घाटन विद्वत् सम्मेलन द्वारा विषय अनेक देश के शिक्षा मन्त्रियों ने भाग लिया था, सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में बताया गया तीन लक्ष्यों का उल्लेख किया है। वे हैं-

(१) साक्षरता का कार्यक्रम जहाँ तक सम्भव हो, 'कार्यपरिधि' (Work-based) जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य व्यापक में अभिवृत्तियों और विषयों परीक्षा करना और निपुणताएँ तथा सुव्यवस्था प्रदान करना है जिससे यह विषय काम में लाया है, उसे सुव्यवस्थापूर्वक करके में समर्थ हो।

(२) हमें निम्नलिखित जन का गानु की महत्त्वपूर्ण समस्याओं में विचार लेना था हमें एक सामाजिक एक सामाजिक जीवन में भाग लेने में सहायता मिले।

(३) हमें व्यक्ति का शिक्षित, पढ़ने और विचार का दाना जाना था और कि वह बहुत ही जाय अपनी शिक्षा विधियों में किसी प्रकार आगे चल गए।

निम्नलिखित की समस्या का हम करने का लिए आशय न करे जाना सुधार है। यह उद्घाटन सामाजिक शिक्षा का सुविधाएँ हम एक का प्रदान हो कार्य साक्षरता जाना न पूँछ न जाना जाना हमारे का विचार था नकलपुरक प्रारम्भिक शिक्षा में लाना हमें यह है। एक लिए साक्षरता (Part-time) शिक्षा की व्यवस्था का जाना। हमारे लिए जोह बना का कुछ शिक्षा मिलता है, परन्तु वह व्यवस्था है, एक लिए साक्षरता जाना साक्षरता शिक्षा की व्यवस्था था। हमें शिक्षा सुधार का जाना था। हमारे का 'एक ही शिक्षा विधियों कायम का जाना जाना' एक व्यवस्था (Scholarship) का जाना था। एक (Merit) शिक्षा का जाना था हमें यह विचार किया गया है।

व्यवसायिक विधि के अन्तर्गत कारखानों तथा उद्योगपतियों द्वारा अपने श्रमिकों के लिए, सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत लगे कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा, पारो तथा अन्य उद्योग प्रतिष्ठानों के द्वारा अपने कार्यकर्त्ताओं के लिए, सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था का विधान रखा गया है। मापूहिक विधि के अन्तर्गत राजनीतिक और सामाजिक नेताओं, सभी मुक्तिजित जनों, शिक्षा मस्थाओं, रेडियो, फ़िल्म तथा अन्य महायुक्त उपकरणों द्वारा किये गये प्रयत्न जा जाते हैं। इन सबका उपयोग नियोजित ढंग से होना चाहिए।

साक्षरता का प्रकार सामाजिक शिक्षा का केवल एक प्रारम्भिक कार्य है। हम पहले बता चुके हैं कि सामाजिक शिक्षा जीवन-व्यापी शिक्षा है। औपचारिक मस्थागत शिक्षा को समाप्ति में शिक्षा का अन्त नहीं होता, उसका मूल भाग बतकर सामाजिक शिक्षा मेंभालती है। इस प्रकार के कार्य को हम सतत शिक्षा (Continuing Education) कह सकते हैं। अध्यापक, बकील, डाक्टर, उद्योगपति, इंजीनियर, और प्रधानक सभी को इस सतत शिक्षा की आवश्यकता है त्रिमके बिना वे समय में पीछे रह सकते हैं। इस सतत शिक्षा का चलाने का भार विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक मस्थानों पर है। यह सब छोटे-छोटे पाठ्यक्रम चला सकते हैं और उनके द्वारा नवीनतम ज्ञान का प्रचार समाज में हो सकता है। यह पाठ्यक्रम कई प्रकार से चलाये जा सकते हैं। साम्यकालीन पाठ्यक्रम ऐसे होंगे जिन्हें मस्थाओं में चलाया जाय और जिन्हें आवश्यकता हो, वे वही जाकर अध्ययन करें। अध्ययन के उपरान्त अभ्युत्ताओं को उपाधियाँ, प्रमाणपत्र और डिप्लोमा दिये जायें। इसमें लोगों को प्रेरणा मिलेगी। दूसरे पाठ्यक्रम वे होंगे जिन्हें पत्राचार (Correspondence) के द्वारा चलाया जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों को रेडियो, फ़िल्म और टेलीविजन के द्वारा अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इन्हें मफल बनाने के लिए कार्यक्रमित शिक्षण (Programmed Instruction) की विधि का प्रयोग किया जाय। आयोग में पत्राचार द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों को अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा तकनीकी ज्ञान के प्रसार के लिए उपयोगी बताया है। इनकी व्यवस्था विश्वविद्यालयों द्वारा होनी चाहिए। पत्राचार द्वारा शिक्षा में खूबी यह है कि हर व्यक्ति अपने देश में बने रहकर अपने ज्ञान का विकास कर सकता है।

शिक्षा-आयोग का मत है कि सामाजिक शिक्षा के विकास के लिए पुस्तकालय का एक जाल विद्यन की आवश्यकता है। विविध रूप से देहावों में ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि पुस्तकों के द्वारा ही ग्रामीण जनों में कुछ जागृति लायी जा सकती है। पुस्तक ज्ञान-प्रसार का मस्था परन्तु स्वायी माचन है। अभी तक बड़े-बड़े नगरों में सार्वजनिक पुस्तकालय हैं परन्तु गांवों में उनका अभाव है। जिला और पंचायत स्तर पर उनका विकास जरूरी है। गांवों में पुस्तकालयों के साथ रेडियो, टेपरेकार्डर, ग्रामोफोन और फ़िल्मों की व्यवस्था भी रहनी चाहिए। पुस्तकालयों के अलग उपयोग

क लिये आता है। दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति को, इसके आधार पर विचार विमर्श करने, वर्तमानक चर्चा-विमर्श, आचार और प्रतिपत्ति का आकाश देना होता है।

प्रोड शिक्षा के लक्ष्य में अनुसंधान का काम विशेषरूप से इस में रहना चाहिए। प्रथम एक विश्वविद्यालय अथवा सामाजिक सुधारक असा नही कर पाता है। समाज का अनुसंधान सर्वोपरि का है। यह भी पता चलता है। यह अनुसंधान विश्वविद्यालय का हीर में समाहित होना चाहिए। दूसरा, सर्वोपरि इसमें सामाजिक शिक्षा के द्वारा और प्रसार में भाग लेना है। इस शिक्षा के अधिक और सामाजिक विभाग में हीर बढ़ाना चाहिए। नव ज्ञान के प्रसार, नागरिकता की चेतना सामान्य बनाने की जरूरत और अभिवृत्तियों के परिष्कार, जनसंख्या नियंत्रण और नव जीवन शैली आदि के लक्ष्य में विश्वविद्यालय बहुत उपयोगी काम कर सकता है। वे संस्था के समय कक्षाएं खोला सकते हैं, अंग्रेजी और अरबी के प्रयोग कर सकते हैं, भाषण, गान, विभिन्न सेवा में संलग्न और विभाग के आदान-प्रदान का व्यवस्था कर सकते हैं। इन सब कार्य को शिक्षा के लिए यह विश्वविद्यालय में प्रोड-शिक्षा का एक बड़ा काम कर सकता है। दूसरे विश्वविद्यालय के इस विभाग का एक प्रतिनिधि रहना प्रोड शिक्षा के लिए आवश्यक है। इससे शिक्षा के लक्ष्य का अन्वेषण रहना चाहिए। यह होगा कि इस विश्वविद्यालय में प्रोड-शिक्षा का विभाग स्थापित हो जाय, ऐसा कि शिक्षा की गति-विधि विश्वविद्यालय में हो सके।

सार देना में प्रोड शिक्षा के लक्ष्य में समाचारन मान के लिए सामाजिक शिक्षा का वैज्ञानिक ढंग स्थापित करना चाहिये। इसमें सभी समाचारों को प्रतिनिधित्व प्रदान हो। शिक्षा समाचारों का अनुसंधान करना चाहिए। इसका काम वैज्ञानिक और समाचारों को प्रसारित देना, प्रोड-शिक्षा के लक्ष्य पर ध्यान देने वाली संस्थाओं का सहायता देना, विभिन्न सामाजिक शिक्षा की संस्थाओं में समाचारन मान और सहायता देना आदि है। इस बार्ड के समान ही राज्य और शिक्षा-मंत्र पर सामाजिक शिक्षा की परिपक्व स्थापना की जाय। यह परिपक्व सामाजिक संस्थाओं को अधिक सहायता देकर प्रेरणा दे सभी प्रोड-शिक्षा का कार्यक्रम सफल होना। यह मेरा विचार है कि सामाजिक संस्थाएं आजादी के बाद धीरे-धीरे नष्ट होनी जा रही हैं। इसका कारण यह है कि सरकार अपने लक्ष्यों में अधिक से अधिक सहायता करने जा रही है। पर यह स्पष्ट है कि सरकार की कार्यवाही और अधिकारी बेतनभोगी हैं और उनमें गवा-भाव की कमी है। सामाजिक संस्थाएं प्रेरणापूर्ण इस में काम करनी हैं और उनका महत्त्वपूर्ण स्थान मिलेगा।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामाजिक शिक्षा के लक्ष्यों की एक सूची बनाइए। इन लक्ष्यों को पूर्ति के लिए भारत में स्तम्भ-प्रकार के चार क्या-क्या कार्य चिये गये हैं ?

२. सामाजिक शिक्षा की क्या समस्याएँ हैं ? उनको हल करने के उपाय बताइए ।
३. सामाजिक शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों अधिक है ?
४. भारत में सामाजिक शिक्षा के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए । इस समय 'सामाजिक शिक्षा' को क्या धारणा (Concept) स्वीकार की जाती है ?
५. सामाजिक शिक्षा कहाँ तक देश की दो निम्नलिखित प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है—  
(क) सार्वजनिक (Universal) शिक्षा,  
(ख) प्रजातन्त्र के लिए शिक्षा ?
६. सामुदायिक विकास-खण्ड सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान देते हैं ? विकास-खण्डों की उपसमिधियों पर विचार प्रकट कीजिए ।
७. सामाजिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए कौन-से संस्थान (Agencies) प्रयत्न कर रहे हैं ? सामाजिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार को लेना चाहिए अथवा सार्वजनिक संस्थाओं को ? अपने तर्क दीजिए ।
८. "सामाजिक शिक्षा देश की मूर्खा की दूसरी रक्षा-पट्टि है ।" इस कथन के सदर्भ में सामाजिक शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए ।

### राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

1. What are the various agencies of social education in India ? Discuss the role of Community Development Projects in social education ? (1961)
2. Show the importance of adult education in India of today with reference to—  
(a) the needs of democracy  
(b) the effect on children's education and enrolment  
(c) the improvement in the personal life of the adults  
Bring out the distinction between adult literacy, adult education and social education (1964)
3. Write short notes on  
(a) Adult and social education in India (1963)  
(क) जनता कविज (१९६३)

୫. ଗ୍ରନ୍ଥ ଲିଖନୀଙ୍କୁ ଏହି ଲିଖନୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ଲିଖନୀ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥକାରୀ ? ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁ କହୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲିଖନୀଙ୍କ ମତରେ, ଲିଖନୀଙ୍କ କହୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ (Employer) ପରିଷଦ ମତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କହୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ (Employee) । (୧୯୬୬)
୬. ଗ୍ରନ୍ଥ ଲିଖନୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖନୀ କିମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ? ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କହୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କହୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ (Employee) । (୧୯୬୬)
୭. ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଲିଖନୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ? ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କହୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କହୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ (Employee) । (୧୯୬୬)

## अध्याय १६

### भारत के पब्लिक स्कूल

#### पब्लिक स्कूल क्या है ?

सामान्य धारणा—आम लोग पर पब्लिक स्कूल के अर्थ के विषय में बहुत-से लोग के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। वे समझते हैं कि यह एक ऐसा स्कूल होगा जिसमें साधारण जनो के बच्चे पढ़ते हैं। यह भ्रम इसलिए होता है कि कुछ देशों में ऐसे पब्लिक स्कूल हैं जो सर्वसाधारण के लिए ही बने हैं और सरकार इन स्कूलों को जनहित के उद्देश्य में चलाती तथा इनका पूरा खर्च उठाती है। भारत के 'पब्लिक स्कूल' कुछ दूसरे ही प्रकार के हैं। 'पब्लिक स्कूल' एक ऐसा स्कूल है जिसके द्वार सर्वसाधारण के बच्चों के लिए बन्द होते हैं, इनमें मुविधा-प्राप्त उच्चवर्गीय बालक पढ़ते हैं और प्रायः इस पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता क्योंकि इस स्कूल के पास धन की कमी नहीं होती। हमारे देश में इस प्रकार के अनेक स्कूल हैं, जो बड़े शहरों में बने हुए हैं और जिनमें अधिकारियों, पूँजीपतियों तथा मुविधा-प्राप्त जनो के बालक संकड़ी रुपये प्रतिमास खर्च करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनमें से अधिकांश नाबालीय भी है अर्थात् इनमें पढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को उनके घरों में हटा कर इस स्कूलों के छात्रावास में रखा जाय तथा उनमें कठोर अनुशासन का पालन कराया जाय। कुछ पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्रावास में रहना अनिवार्य है परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जिनमें स्थानीय बालक घरों में रहते हैं परन्तु उन्हें दिन का अधिकांश भाग स्कूल में ही बिताना पड़ता है।

पब्लिक स्कूल की परम्परा—आम लोग पब्लिक स्कूल के सम्बन्ध में जो धारणा रखते हैं उनमें इस प्रकार के स्कूल को ठीक-ठीक समझना सम्भव नहीं है। कुछ स्कूल ऐसे हो सकते हैं, जिनमें उच्चवर्गीय के बालक पढ़ते हों, खर्च भी ज्यादा लगता हो, छात्रावासों में रहना पड़ता हो परन्तु फिर भी वे पब्लिक स्कूल न हों।





जीवन में नेतृत्व करने का प्रशिक्षण छात्रों को दिया जाता है। यहाँ छात्रावास की सुविधाएँ अवश्य होती हैं क्योंकि बिना छात्रावासों में रहे, छात्रों के भीतर नेतृत्व और चरित्र के उत्तम गुण नहीं पैदा किये जा सकते। इन स्कूलों का केम्ब्रिज और आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में सम्पर्क होता है। यह दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा-भरती की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और यह पब्लिक स्कूलों के छात्रों को मजबूती में प्रवेश दे देते हैं। कारण, पब्लिक स्कूल का छात्र योग्यता और बुद्धि में श्रेष्ठ माना जाता है। यह स्कूल सरकार का मुँह नहीं ताकते। वे आर्थिक महायत्ना नहीं लेते, अतः वे राजकीय नियंत्रण से मुक्त रहते हैं। श्री डेव ने भी गहनगम इन्हीं विरोधवादी का उत्तम पब्लिक स्कूल की चर्चा में किया है।

पब्लिक स्कूलों में छात्रों के लिए प्रवेश पाना बड़ा कठिन होता है। इसके कई प्रमुख कारण हैं। एक, इनमें वही छात्र प्रवेश मजबूती में पाते हैं, जिनके पूर्वज यहाँ पढ़ चुके हैं। यहाँ पूर्व छात्रों का मेधा रहता है और उनकी मन्त्रालयों को प्रवेश में बरीयता दी जाती है। दूसरी कठिनाई यह है कि पब्लिक स्कूल में शुल्क बहुत ज्यादा होता है। एक छात्र पर हजार रुपये में भी अधिक प्रतिमान खर्च बैठता है। इसलिए अमीर मापन वाले लोग ही बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। तीसरी कठिनाई यह है कि यहाँ का शिक्षा-स्तर भी ऊँचा होता है। पहले ३-४ वर्ष तक बालकों को 'प्रेपेरेटरी स्कूल' (जहाँ उन्हें बड़े परिश्रम में तैयार किया जाता है) में रखा जाता है। यह स्कूल पब्लिक स्कूल से सम्बद्ध होते हैं। फिर इतना समय मराने के बाद ही वे हम मापन बनते हैं कि पब्लिक स्कूल में चल सकें।

इन स्कूलों का कार्यक्रम बड़ा नियंत्रित तथा धर्म-माध्य होता है। मंचों में लेकर घाम तक छात्रों को कठोर नियंत्रण में रहना पड़ता है। स्नान, भोजन, कक्षा, स्वाध्याय और खेलने आदि सभी कामों का समय बँधा होता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाता है। यहाँ सार्वभौम विषय पढ़ाने पर जोर देते हैं यद्यपि अब आधुनिक भाषाओं और विज्ञान का प्रवेश भी यहाँ हो गया है।

इन पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों की श्रेष्ठता का परिचय उनकी उपलब्धियों से मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार इंग्लैण्ड के सर्वश्रेष्ठ लेखकों, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों, बौद्धिकों तथा प्रभावकों में से अधिकांश इन ही बड़े पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए छात्र हैं। साथ ही हमने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि पब्लिक स्कूल की शिक्षा की उत्तमता के कारण ही ऐसे महान् पुण्य उत्पन्न हुए, उचित न होगा। निकोलस हैन्स के मत में, इन स्कूलों की श्रेष्ठता कुछ कारणों में है, जैसे इनमें अग्रज जाति के चुने हुए बालक पढ़ते हैं, इनमें प्रवेश पाने में पहले इन बालकों को जरूरतमंद नौसारी करायी जाती है, इनके घर बड़े सम्पन्न होते हैं और उनके बौद्धिक विवरण के लिए प्रचंडी व्यवस्था की जाती है। तभी यहाँ के छात्र पढ़ने-लिखने में अच्छे होते हैं; यहाँ का शिक्षा-स्तर अद्वितीय हो, ऐसी बात नहीं है।

पब्लिक स्कूल में उत्पन्न स्थिति का ही कारण है। इस पब्लिक स्कूल में शिक्षा पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तकें ही हैं, वे स्वभाव में धर्मनिरपेक्ष, नैतिक, इतिहासिक, दार्शनिक और उदात्त होते हैं। एक मूल्य अर्थों की परिभाषा में हुए अर्थों के लिए साहित्यिक मूल्य नया ज्ञान माना जाता है जो कुछ किताबें हैं जो इन पुस्तकों में पढ़े हुए लोगों में फैली है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में शिक्षा के उद्देश्य के लिए जिस दार्शनिक राजा (Philosopher King) की पर्याय की है, उसका अर्थ ही 'मूल्य व्यक्ति' होता है, जो पब्लिक स्कूल की शिक्षा देने में सक्षम है।

इन स्कूलों में स्वाभाविक प्रधान कार्यक्रमों तथा नैतिक-मूल्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ छात्र-छात्रों में दृष्ट-पुष्ट हो जाना ही है, साथ ही उनमें परस्पर हार्दिक करने, दूसरों पर दायित्व करने और दूसरों में आदर्श बनने की आवश्यकता होती है। इन लोगों ने ही जाति-धर्म-अर्थों की सामाजिक की स्थापना की और अर्थों की सभ्यता के आधार स्वरूप बन गये। यह सब कैसे होता है? क्योंकि उच्च में बान्धवों की उनके पढ़ने में दूर रखा जाता है, वे मातृ-स्नेह और माता के संस्कार प्रभावों में बचने रह कर यहाँ के उच्च कक्षाओं के छात्रों के दुर्भवा का आदी बन जाता है। फिर आगे चल कर अपने में नीची कक्षाओं के बान्धवों का अज्ञान-जनन बन कर मनोप पाते लगते हैं और बहुत कुछ हद तक नवोदनात्मक बन जाता है।

परम्परा के विरुद्ध प्रतिक्रिया—उन्नीसवीं शताब्दी में पब्लिक स्कूल की परम्परा इंग्लैण्ड में पतन रही थी क्योंकि यहाँ के पढ़े-लिखे लोगों ने अर्थों की सामाजिकवाद का विस्तार सारे समाज में किया था। साथ ही देश के भीतर इनके विरुद्ध एक भीषण प्रतिक्रिया का आरम्भ भी हो गया। हमने जिन प्रगतिवादी शिक्षा की जन्म दिया था और प्रजातन्त्र की भावना का जिस प्रकार में विकास हो रहा था, उसमें बहुत में लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा था। पब्लिक स्कूलों की संकुचित और दमन-प्रधान शिक्षा इन नव-विकसित शिक्षा के आदर्शों में मेल नहीं खाती थी। इसलिए बीसवीं शताब्दी में इस परम्परा के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन आरम्भ हो गया।

पब्लिक स्कूलों के लोगों को जनता के सामने स्पष्ट करने वाले वे लोग थे जो प्रगतिवादी शिक्षा का आन्दोलन चला रहे थे। नमूने के तौर पर इन आन्दोलनकारियों में में श्री एल० बी० पैकिन के विचारों का विस्तार हम करेंगे। इनकी पहली पुस्तक 'पब्लिक स्कूल, उनकी असफलता और उनका सुधार' सन् १९३२ में प्रकाशित हुई तो चारों ओर धूम मच गयी।

श्री पैकिन ने लिखा है कि प्रायः पब्लिक स्कूलों की प्रशंसा में लिखना एक सम्मान की बात समझी जाती है। केवल कुछ लोग ही ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि इन भी सराशियों है जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। उन सराशियों में एकों का छात्रों के साथ असहिष्णुता और घमंड का व्यवहार, उनके

ऊपर शारीरिक दंड के अत्याचार, सेनो की जी उबाने वाली मुखतापूर्ण पूजा, विपंली असामाजिक शिक्षण पद्धति, संकुचन पाठ्यक्रम, लैंगिक भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन आदि। धायद सामान्य जनता इन पर विस्वाम न करे परन्तु यह तथ्य है और इन स्कूलों में पढ़े लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं।

इसी प्रकार प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक बर्टेंड रसेन ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा और समाज व्यवस्था' (Education and Social Order) में इन पब्लिक स्कूलों की मनु आलोचना की है। उनका कहना है कि पब्लिक स्कूल के पढ़े तथाकथित महापुरुषों ने अन्य लोगों में केवल पगुना और बहूको के बल पर अपना कडा याडा धा, अपनी मानवता के बल पर नहीं। साम्राज्यवाद के 'इजन' के हर में पब्लिक स्कूल विफल रहा है। यहाँ के पढ़े लोगों में 'बुद्धि' के प्रति घृणा होती है, वे सोचने और स्वतन्त्रता-पूर्वक सोचने के विरुद्ध आदी नहीं होते। विद्यार्थी जीवन में उन्हें केवल कुछ स्थिर मूल्यों का पालन करना सिखाया जाता है। अनुकरण और आज्ञापालन करते-करते वे कुछ भी सीखने में असमर्थ बन जाते हैं। इन लोगों में मनोवैज्ञानिक असामान्यताएँ भी पैदा हो जाती हैं क्योंकि लिंग के प्रति बड़ा ही अस्वस्थ दृष्टिकोण यहाँ होता है। यहाँ के छात्रों में समलैंगिकता तथा हस्तमंथन के अवगुण पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण वे अपने विवाहित जीवन में असफल रहते हैं। इस असफलता और निराशा की प्रतिक्रिया के कारण यह लोग आगे चलकर साम्राज्यवादी बर्बरता का प्रदर्शन करने लगते हैं।

इन विद्वत्तापूर्ण और साथ ही यथार्थवादी आलोचनाओं का परिणाम यह हुआ कि पब्लिक स्कूलों की 'पवित्र मूर्ति' खंडित होने लगी और इनमें मुधारों को आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इंग्लैण्ड में सन् १९४४ के ऐक्ट और इसी वर्ष दी गयी फेर्नमिंग रिपोर्ट में, यद्यपि इन स्कूलों की मवदा नष्ट कर देने की प्रवृत्ति का विरोध किया गया परन्तु इनमें कुछ मुधार करने पर भी बल दिया गया। इन स्कूलों के द्वार उन छात्रों के लिए खोलने की सिफारिश की गयी, जो मध्यम वर्ग के हैं परन्तु धनाभाव के कारण इन स्कूलों में पढ़ नहीं पाते। ऐसे छात्रों की मस्या कम से कम २५% होता आवश्यक बताया गया। पब्लिक स्कूलों ने भी अपनी कमजोरी ममभी और उन्होंने स्वयं अपने कार्यक्रम और पाठ्यक्रम में अपेक्षित परिवर्तन कर डाले। फिर भी यहाँ २०वीं शताब्दी में इन स्कूलों की प्रगिष्टा में अधिक कमी नहीं हुई, वहाँ यह भी स्पष्ट है कि शिक्षा की उत्तमता की दृष्टि में वे अप्रतिम नहीं हैं।

**भारत में पब्लिक स्कूलों की स्थापना और उनका संक्षिप्त इतिहास**

इंग्लैण्ड का अधिकार भारत पर हा गया और वहाँ की शिक्षा-प्रणाली इस देश में लागू हो गई। यहाँ के शासन-सम्पन्न लोग इंग्लैण्ड में जाकर पढ़ने लगे। उनका परिचय इन पब्लिक स्कूलों में हुआ। भाग्यीयों के मन में इन स्कूलों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। बहुत में पनी वर्ष के लोगों ने अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ने के

लिए भेजा। प० जवाहरलाल नेहरू द्वैरो नामक पब्लिक स्कूल की उगज थे। परन्तु, भारतीयों को इन स्कूलों में प्रवेश पाने में कठिनाई होती थी। परिणाम यह हुआ कि यहाँ के राजा-महाराजाओं, बड़े-बड़े जागीरदारों और पूँजीपतियों के मन में यह इच्छा हुई कि भारत में ही पब्लिक स्कूल के नमूने के स्कूल खोले जायें। ऐसे स्कूलों के लिए इन लोगों ने मुन्नहस्स होकर धन और सम्पत्ति दान की, उन्हें बनाने के लिए इंग्लैण्ड में अंग्रेजों को प्रधानाचार्यों के पदों पर काम करने के लिए बुलाया, इनमें अंग्रेजी संस्कृति और अंग्रेजी भाषा को प्रधानता दी और इनके दरवाजे यहाँ की शिक्षा को लचीला बनाकर सामान्य वर्ग के बालकों के लिए बंद कर दिए। इन्हें चीफ्स कालेज कहकर पुकारा गया। अजमेर का मेयो कॉलेज इसका एक नमूना है।

गुड्ड रूप में 'पब्लिक स्कूल' भारत में स्थापित हों, यह विचार कलकत्ता के एक प्रख्यात वकील श्री एम० भार० दाम के मन में उत्पन्न हुआ। वे चाहते थे कि यह पब्लिक स्कूल केवल राजकुमारों के लिए ही न रहे बरन् इसके द्वार हर योग्य भारतीय के लिए खुले रहे ताकि वे उच्च पदों का, शिक्षा पूरी करने के बाद पा सकें। इसलिए श्री दाम ने सन् १९२९ में इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया और जनता में १४ लाख रुपये खर्च के रूप में एकत्र कर लिया। यद्यपि श्री दाम अपने निधन के कारण इस काम को पूरा न कर सके, तथापि १९३५ में उनकी प्रेरणा के प्रभाव में देहरादून में दून पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई।

चीफ्स कालेज अलग चमक रहे थे और उन्हें सरकारी अनुदान मिल रहा था। १९३० के बाद के दशक में भारत में राष्ट्रवादी आन्दोलन जोर पकड़ रहा था और प्रजातांत्रिक विचारधारा भी प्रबल होती जा रही थी। इसलिए सरकार के सामने बराबर यह प्रश्न उठाया गया कि इन सुविधा-प्राप्त वर्गों के स्कूलों को सार्वजनिक कोष में धन क्यों दिया जाता है। इस माँग की प्रगतिता से विवश होकर चीफ्स स्कूलों को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान सरकार ने बन्द कर दिया। अब जो आर्थिक संकट इन स्कूलों के सामने आ गया, उसमें परेशान होकर इनके प्रबंधकों को नये ढंग में सोचना पड़ा। एक नया आन्दोलन इन स्कूलों की ओर से खला कि इन स्कूलों को पब्लिक स्कूलों के रूप में बदल दिया जाय। इस आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले थे, मिथिया स्कूल के प्रिन्सिपल श्री एफ० सी० पियर्स। इन्होंने अपने स्कूल को 'पब्लिक स्कूल' के नाम में पुकारने की घोषणा कर दी। श्री पियर्स ने क्षीप्र ही 'इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ़ेस' बनाने का निश्चय किया और सन् १९३६ में इनके प्रयासों में सफलता में इस प्रकार के स्कूलों के प्रधानाचार्यों की एक सभा हुई। इस सभा में तत्कालीन भारतीय सरकार के शिक्षायुक्त श्री जे० पी० मार्जेट ने भी भाग लिया था।

इस सभा में कई बातों पर विचार हुआ, जैसे मातृमय शिक्षा संस्थाओं की समस्याएँ, भारतीय पब्लिक स्कूलों के एमोमिएशन का निर्माण तथा इन स्कूलों में भी भारतीय संस्कृति का समावेश। सन् १९३६ में ही ग्वानियर में पहले की तरह की

एक बैठक और हुई और इण्डियन पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस की स्थापना हो गई। चीफ स्कूलों के प्रधानाचार्य इनके सदस्य बने और उनके स्कूल पब्लिक स्कूल बने। इस बैठक में दून पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य थी फुट उपस्थित थे परन्तु वे दून कांफ्रेंस के सदस्य नहीं बने। श्री सार्जेंट भी उपस्थित थे और उन्होंने भारत में पब्लिक स्कूलों के विनाश की महत्वपूर्ण बताया। उनका तर्क यह था कि भविष्य में नेतृत्व का गुण भारत में पैदा करना आवश्यक है क्योंकि उन्हें कभी न कभी स्वायत्त-शासन प्राप्त करना है और ऐसे लोग तैयार करने की जिम्मेदारी पब्लिक स्कूल ही दे सकते हैं जो मराठा का नेतृत्व कर सकें।

इण्डियन पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस की स्थापना के बाद एमीशन कॉलेज, लाहौर, राजकुमार कॉलेज, राजकोट, राजकुमार कॉलेज, रायपुर, डेली कॉलेज, इन्दौर, भोयने मिलिट्री स्कूल पूना, पब्लिक स्कूल घोषित कर दिये गये। अब इन स्कूलों ने यह आवश्यक समझा कि इन्हें राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन भी मिल जाय। इसलिए राजकुमार त्रिम स्कूल, रायपुर के प्रधानाचार्य श्री स्मिथ ने गांधीजी से इन स्कूलों में पढ़ाने का आग्रह किया परन्तु गांधीजी ने पब्लिक स्कूल की परम्परा का समर्थक होता स्वीकार नहीं किया। फिर भी श्री स्मिथ ने सहमत नहीं छोड़ा और इन परम्परा को जमाने का प्रयत्न जारी रखा। उनका क्वाल था कि गांधी के अनिर्दिष्ट अन्य कांग्रेसी नेता पब्लिक स्कूल के विरोधी नहीं हैं और वे गांधीजी की मुनिपादी मिथा से सहमत नहीं हैं।

उपर इण्डियन पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस तो बन गई पर चीफ स्कूलों के प्रधानाचार्य इनके सदस्य बनने में इन्कार कर रहे थे। स्वयं मेयो कॉलेज के प्रिन्सिपल स्टो का कहना था कि उनका कॉलेज एक विशिष्ट वर्ग की संस्था है और उसका सदस्य बनना सम्भव नहीं है। दून पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य थी फुट ने भी उसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। अब प्रयत्न जारी रहा और सन् १९४० के अक्टूबर मास में रायपुर में एक बैठक हुई जिसमें इण्डियन पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस का स्मृतिपत्र तैयार किया गया। इसकी सदस्यता के लिए आवश्यक शर्तें तय कर दी गई। यह भी निश्चय किया गया कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भारतीय भाषाओं में परीक्षा की व्यवस्था की जाय। इस बैठक के पश्चात् मार्वन स्कूल, दिल्ली; मेयो कॉलेज, अजमेर, सार्दल स्कूल, बीकानेर ने इस संस्था की सदस्यता स्वीकार कर ली। इस संस्था के बनने के बाद नये पब्लिक स्कूल खुलने का क्रम आरम्भ हो गया। नये स्कूलों में प्रमुख हैं—महाराणी गायत्री देवी स्कूल, जयपुर (१९४३); बिड़ला पब्लिक स्कूल, पिनानी (१९४४); बिड़ला विद्या मन्दिर, नैनीताल (१९४७), मादवेन्द्र पब्लिक स्कूल, पटियाला (१९४८)। सन् १९४९ में दी सॉरेंस स्कूल, मनावर और सॉरेंस स्कूल, लखनऊ को जो सुरक्षा विभाग के हाथों में थे, मिशा मन्त्रालय ने ले लिया परन्तु सन् १९५३ में उन्हें स्वयंशासन समितियों को सौंप

लिए भेजा। १० जवाहरलाल नेहरू हैरो नामक पब्लिक स्कूल की उपज थे। परन्तु, भारतीयों को इन स्कूलों में प्रवेश पाने में कठिनाई होती थी। परिणाम यह हुआ कि यहाँ के राजा-महाराजाओं, बड़े-बड़े जागीरदारों और पूँजीपतियों के मन में यह इच्छा हुई कि भारत में ही पब्लिक स्कूल के नमूने के स्कूल खोले जायें। ऐसे स्कूलों के लिए इन लोगों ने मुश्किलें होकर धन और सम्पत्ति दान की, उन्हें चयाने के लिए इंग्लैण्ड में अंग्रेजों को प्रधानाचार्यों के पदों पर काम करने के लिए बुलाया, इनमें अंग्रेजों मस्कृति और अंग्रेजी भाषा को प्रचलना दी और इनके दरवाजे यहाँ की शिक्षा को खर्चीला बनाकर सामान्य वर्ग के बालकों के लिए बंद कर दिए। इन्हें चोपम कालेज कहकर पुकारा गया। जजमेर का मेयो कालेज इसका एक नमूना है।

युद्ध रूप में 'पब्लिक स्कूल' भारत में स्थापित हो, यह विचार कलकत्ता के एक प्रख्यात वकील श्री एम्. आर. दाम के मन में उत्पन्न हुआ। वे चाहते थे कि यह पब्लिक स्कूल केवल राजकुमारों के लिए ही न रहे बल्कि इसके द्वार हर योग्य भारतीय के लिए खुले रहे ताकि वे उच्च पदों को, शिक्षा पूरी करने के बाद पा सकें। इसलिए श्री दाम ने मन् १९२२ में इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया और जनता में १४ लाख रुपये चंदे के रूप में एकत्र कर लिया। यद्यपि श्री दाम अपने निधन के कारण इस काम को पूरा न कर सके, तथापि १९१५ में उनकी प्रेरणा के प्रभाव में देहरादून में दून पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई।

चोपम कालेज अलग चल रहे थे और उन्हें सरकारी अनुदान मिल रहा था। १९३० के बाद के दशक में भारत में राष्ट्रवादी आन्दोलन जोर पकड़ रहा था और प्रजातान्त्रिक विचारधारा भी प्रबल होनी जा रही थी। इसलिए सरकार के सामने बग़ल यह प्रश्न उठया गया कि इन मुविधा-प्राप्त वर्गों के स्कूलों को मार्वाजनिक कोष में धन क्यों दिया जाता है। इस माँग की प्रशंसा से विवश होकर चोपम स्कूलों को दिया जाने वाला सरकारी अनुदान सरकार ने बन्द कर दिया। अब जो आवधिक महत् इन स्कूलों के सामने आ गया, उसमें परेशान होकर इनके प्रबन्धकों को नये ढंग में सोचना पड़ा। एक नया आन्दोलन इन स्कूलों की ओर से बना कि इन स्कूलों को पब्लिक स्कूलों के रूप में बदल दिया जाय। इस आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले थे, निधिया स्कूल के प्रिन्सिपल श्री एफ. मो. पियर्स। इन्होंने अपने स्कूल को 'पब्लिक स्कूल' के नाम से पुकारने की घोषणा कर दी। श्री पियर्स ने सीधे ही 'इंडियन पब्लिक स्कूल काँग्रेस' बनाने का निश्चय किया और मन् १९३६ में इनके प्रयासों में निमग्न में इस प्रकार के स्कूलों के प्रधानाचार्यों की एक सभा हुई। इस सभा में तत्कालीन भारतीय सरकार के शिक्षायुक्त श्री जे. पी. मार्टेट ने भी भाग लिया था।

इस सभा में कई बातों पर विचार हुआ, जिनमें माध्यम शिक्षा समस्याओं की समस्याएँ, भारतीय पब्लिक स्कूलों के एसोसिएशन का निर्माण तथा इन स्कूलों में भी भारतीय मस्कृति का समावेश। मन् १९३६ में ही स्थापित में पढ़ने की तरह की

एक बेंचक और हुई और इण्डियन पब्लिक स्कूल कान्फ्रेंस की स्थापना हो गई। चौपस स्कूलों के प्रधानाचार्य इसके सदस्य बने और उनके स्कूल पब्लिक स्कूल बने। इस बेंचक में दून पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य थी कुट उपस्थित थे परन्तु वे इस कान्फ्रेंस के सदस्य नहीं बने। श्री सार्जेन्ट भी उपस्थित थे और उन्होंने भारत में पब्लिक स्कूलों के विकास को महत्वपूर्ण बनाया। उनका तर्क यह था कि भविष्य में नेतृत्व का गुण भारत में पैदा करना आवश्यक है क्योंकि उन्हें कभी न कभी स्वायत्त-शासन प्राप्त करना है और ऐसे लोग तैयार करने की जिम्मेदारी पब्लिक स्कूल ही ले सकते हैं जो समाज का नेतृत्व कर सकें।

इण्डियन पब्लिक स्कूल कान्फ्रेंस की स्थापना के बाद एमीगन कालेज, लाहौर, राजकुमार कानेज, राजकोट, राजकुमार कानेज, रायपुर, डेमी कालेज, इन्दौर, भोमले मिनिट्री स्कूल पूना, पब्लिक स्कूल घोषित कर दिये गये। अब इन स्कूलों ने यह आवश्यक समझा कि इन्हें राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन भी मिल जाय। इसलिए राजकुमार प्रिम स्कूल, रायपुर के प्रधानाचार्य श्री सिमथ ने गांधीजी में इन स्कूलों में पढ़ाने का आग्रह किया परन्तु गांधीजी ने पब्लिक स्कूल की परम्परा का समर्थक होना स्वीकार नहीं किया। फिर भी श्री सिमथ ने साहम नहीं छोड़ा और इस परम्परा को जमाने का प्रयत्न जारी रखा। उनका क्या था कि गांधी के अनिश्चित अग्र काप्रेसी नेता पब्लिक स्कूल के विरोधी नहीं हैं और वे गांधीजी की बुनियादी शिक्षा में सहमत नहीं हैं।

उधर इण्डियन पब्लिक स्कूल कान्फ्रेंस तो बन गई पर चौपस स्कूलों के प्रधानाचार्य इसके सदस्य बनने में इन्कार कर रहे थे। स्वयं मेयो कालेज के प्रिन्सीपल स्टो का कहना था कि उनका कालेज एक विशिष्ट वर्ग की संस्था है और उसका सदस्य बनना सम्भव नहीं है। दून पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री कुट ने भी उसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। अब प्रयत्न जारी रहा और मई १९४० के अक्टूबर मास में रायपुर में एक बेंचक हुई जिसमें इण्डियन पब्लिक स्कूल कान्फ्रेंस का समुत्थपन तैयार किया गया। इसकी सदस्यता के लिए आवश्यक शर्तें तय कर दी गईं। यह भी निश्चय किया गया कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भारतीय भाषाओं में परीक्षा की व्यवस्था की जाय। इस बेंचक के पश्चात् माडर्न स्कूल, दिल्ली; मेयो कालेज, अजमेर, शार्दूल स्कूल, बीकानेर ने इस संस्था की सदस्यता स्वीकार कर ली। इस संस्था के बनने के बाद नये पब्लिक स्कूल खुलने का क्रम आरम्भ हो गया। नये स्कूलों में प्रमुख हैं—महाराणी पायत्री देवी स्कूल, जयपुर (१९४३); बिड़ला पब्लिक स्कूल, पिलानी (१९४४); बिड़ला विद्या मन्दिर, नैनीताल (१९४७), यादवेन्द्र पब्लिक स्कूल, पटियाला (१९४८)। मई १९४९ में दो सॉरेंट स्कूल, मनावर और सरिस स्कूल, लखनौ को जो मुरझा विभाग के हाथों में थे, शिक्षा मन्त्रालय ने ले लिया परन्तु मई १९५३ में उन्हें स्वयंचालित समितियों को सौंप

दिया गया। वेगमपेठ स्थित जागीदार कालेज का स्थानान्तरण मन् १९५० में हैदराबाद कर दिया गया और वह हैदराबाद पब्लिक स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

मन् १९४७ में स्वतन्त्रता के पश्चात् ऐसा जान पड़ने लगा था कि इस देश में पब्लिक स्कूल की परम्परा को नष्ट होना पड़ेगा क्योंकि यह विभिन्न वर्गों की समस्याएँ हैं और भावी प्रजातन्त्र के लिए चुनौती हैं। साथ ही इनमें ब्रिटिश रीति-रिवाजों की प्रधानता तथा अंग्रेजी के माध्यम का होना, पुरानी दामता का प्रतीक और भारतीय संस्कृति का अपमान है, परन्तु उच्च पदस्थ अधिकारियों और अंग्रेजों की प्रेमियों द्वारा इस परम्परा का पोषण प्रारम्भ हो गया क्योंकि 'नेतृत्व' और अपनी नौकरियों को बनाए रखने में उनका अपना स्वार्थ है और पब्लिक स्कूलों की शिक्षा पाठ्य के अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करना चाहते हैं।

पब्लिक स्कूलों का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा में है। इसलिए मन् १९५२-५३ में मुद्रानियंत्रण कमीशन ने इन स्कूलों पर विचार किया। कमीशन ने इसमें वर्तमान कई दोषों का उल्लेख तो किया परन्तु इनकी प्रशंसा में कह डाला कि नेतृत्व के गुणों के विकास में इन स्कूलों का जो विशेष योगदान है, उसे नकारना बुद्धिमानी न होगी। उसने इनमें सुधार करने के उपाय भी सुझाए।

स्वतन्त्रता के बाद भारतीय नेताओं में राष्ट्रीयता के स्थान पर अन्तर-राष्ट्रीयता का भाव प्रबल हो गया। इस अन्तरराष्ट्रीयता के प्रवाह में नेता और माशारण जन उल्टी दिशा में बहने लगे। अभी तक अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सभ्यता के प्रति जो घृणा का भाव था, वह बदल गया। विदेश-गमन और महायत्ना-प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा-भाषियों की सहानुभूति-अर्जन आदि के कारण अंग्रेजी भाषा का महत्त्व बढ़ा और इस बात ने पब्लिक स्कूलों का महत्त्व बढ़ा दिया। बड़े-बड़े नगरों में जाली पब्लिक स्कूल खुल गए जिन्होंने अपने नाम के साथ 'पब्लिक' शब्द जोड़ कर जनता का ध्यान आकर्षित करना प्रारम्भ किया। फंडेशन-प्रेमी, महत्वाकांक्षी और पैसों वाले गहरी लोभ इन स्कूलों में अपनी मन्तानों को पढ़ाना गौरव की बात मानते हैं।

आज शिक्षा के क्षेत्र में 'पब्लिक स्कूल' विवाद का विषय बना हुआ है। कौटुम्बिक शिक्षा-आयोग ने इन स्कूलों को अनावश्यक ठहराया है और उन्हें 'वर्ग शिक्षा' का प्रतीक बना कर इनका कार्यान्वयन करने पर जोर दिया है। पब्लिक स्कूलों की अग्रजातान्त्रिक परम्परा को समाप्त करके 'सामान्य स्कूल' की परम्परा स्थापित करने की संसुति इस आयोग ने दी है। इस विषय पर जब लोकसभा में विचार चला, तो वहाँ पब्लिक स्कूलों के कई कट्टर समर्थक निकल आए। वर्तमान केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डा० त्रिगुणमन चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली निर्धारित हो जाय और कोई भी ऐसी परम्परा (जैसी पब्लिक स्कूलों की है) उस प्रणाली का उपहास करने वाली न बनी रहे। कारण यह है कि यह स्कूल कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्ग के अड्डे बन



रहेंगे। साथ ही सामान्य स्कूलों की दशा भी न मुधरेगी जब तक उनमें उन वर्गों के बालक पढ़ने न जायेंगे जिनके हाथों में सत्ता है। जब तक सामान्य स्कूल में प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के घर के बालक नहीं पढ़ेंगे, उनकी दशा नहीं मुधर सकती। दूसरे शब्दों में, पब्लिक स्कूलों के कारण सामान्य स्कूल नहीं मुधर रहे हैं।

### भारत के पब्लिक स्कूल

भारत में इस समय ५२ पब्लिक स्कूल हैं। इनमें से २४ ऐसे हैं जो इंडियन पब्लिक स्कूल काउंसिल के सदस्य हैं, ६ अर्द्ध-सदस्य और ७ सैनिक स्कूल हैं। पब्लिक स्कूल की परम्परा १९ किंग जार्ज स्कूल तथा कई मिशनरी स्कूल भी चलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय पब्लिक स्कूलों के नाम निम्नलिखित हैं

१. दून स्कूल, देहरादून,
२. ईली स्कूल, इन्दौर,
३. लॉरेन्स स्कूल, मुम्बई,
४. लॉरेन्स स्कूल, लखनऊ,
५. बिड़ला पब्लिक स्कूल, पिलानी;
६. बिड़ला विद्या मन्दिर, नैनीताल,
७. मेयो कालेज, जयपुर,
८. महारानी गायत्री देवी वर्ल्स पब्लिक स्कूल, जयपुर,
९. माडरन स्कूल, बीकानेर,
१०. माडरन स्कूल, नई दिल्ली,
११. हैदराबाद पब्लिक स्कूल, हैदराबाद,
१२. राजकुमार कानेज, रायपुर,
१३. राजकुमार कानेज, रायकोट,
१४. मिन्धिया स्कूल, भुवनेश्वर;
१५. गिवाजी प्रेसिडेंसी मिनिस्ट्री स्कूल, पूना,
१६. विकास विद्यालय, रांची,
१७. यादवेंद्र पब्लिक स्कूल, पटियाला।

### पब्लिक स्कूल का कार्यक्रम तथा विशेषताएँ

पब्लिक स्कूल एक सावामीय संस्था है। सभी छात्रों को अपने २४ घण्टे इस विद्यालय के भीतर पूर्ण नियन्त्रण में बिताना होते हैं। एक सप्ताह में कुल १६८ घण्टे होते हैं जिनका ८ अर्थात् ३७ घण्टे कक्षा के भीतर व्यय होते हैं। दोपहर १२१ घण्टे बालकों को छात्रावास में रहना पड़ता है और इस बीच उन पर विद्यालय के अधिकारियों का पूर्ण नियन्त्रण होता है। प्रधानाचार्य २४ घण्टे का दैनिक कार्यक्रम नियत करता है और बालकों को प्रातः ४-५ बजे में लेकर रात ८-९ बजे तक निश्चित समय-वस्त्र के अनुसार रहना पड़ता है। श्रीक, स्नान, कलेवा, अध्ययन, भोजन और

दिनांक १९८०

खेल-कूद आदि गवर्धे समय पर होते हैं। चूँकि बालक वही रहते हैं, इसलिए कार्यक्रम में हेर-फेर करने में कोई जम्बुविधा नहीं होती।

पठन-पाठन के अनिरिक्त पब्लिक स्कूल छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की बहुमुखी क्रियाओं का आयोजन करना है; जैसे—तैरना, घुड़सवारी, कुस्ती, व्यायाम, मेन-कूद, मनपसन्द के काम (Hobbies), गोष्ठी, फोटोग्राफी, कला तथा दस्तकारी आदि। पाठ्य विषयों में, जो यहाँ पढ़ाये जाते हैं, गणित, भाषा, इतिहास, भौतिकी, रसायन आदि प्रमुख हैं। इन सभी प्रकार के क्रिया-कलापों में ऊँची कक्षाओं के छात्र अपने में नीचे छात्रों का नेतृत्व करते हैं और उन्हें अध्यापकों में बराबर नेतृत्व तथा निर्देशन मिलता रहता है। सभी छात्र अध्यापकों का अनुकरण करते हैं। छात्रों में सहयोगपूर्वक तथा एकदलीय तथा सघबड़ होकर काम करने की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए विषय समितियाँ हैं तथा स्वयमेवक, स्काउट, सरस्वती यात्रा तथा घूमने आदि के माध्यम काम में लाये जाते हैं। इन सभी क्रियाओं में सहयोग, प्रतियोगिता और उत्तरदायित्व निर्वाह करने के गुणों के विकास पर जोर दिया जाता है। मारे छात्रों को कई वर्गों में बाँटे हैं जिन्हें 'भवन' कहते हैं। इन भवनों में कई पद होते हैं जिन पर योग्य छात्र नियुक्त किए जाते हैं और वे नेतृत्व करते हैं। भवनों तथा कक्षाओं में प्रीफेक्ट नियुक्त होते हैं जो अनुशासन का उत्तम आदर्श प्रस्तुत करते हैं। 'भवनों' का बनावरण ऐसा होता है कि छात्रों को पारिवारिक जीवन की समीचीनी होनी, छात्रावास का अविपत्ति मयमें चित्ररूप व्यवहार करता है।

पब्लिक स्कूल के पास अपरिमित माध्यम होते हैं। मुख्य तथा भव्य भवन, सुसज्जित कक्षाएँ, सहायक सामग्री, हॉल, प्रयोगशालाएँ, सप्रहालय, प्रीडाइन, व्यायाम-घाला, तरणनाम, छात्रावास, हरे-भरे घास के मैदान और उद्यान आदि, सभी इन विद्यार्थन को उत्तम्य होने हैं। यहाँ का अध्यापक वर्ग सभी सुविधाएँ पाता है और उन्हें उच्चवैयन मिलता है। उन्हें यहाँ रहने तथा भोजन के लिए धन नहीं व्यय करना पड़ता। यहाँ का प्रधानाचार्य भी बहुत अधिक वेतन पाता है। उसे पूरी अधिकार होने हैं और वह एक प्रकार में सर्वोच्च होता है। अध्यापकों की नियुक्ति-प्रोन्नति और छात्रों के प्रवेश और निष्कासन आदि में उसे पूरी स्वतन्त्रता होती है।

इन सब बातों के देखते हुए यह अनुमान लगाना महत्व है कि यहाँ मुक्त बहुत ज्यादा होगा। अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए, यह स्कूल यथासम्भव सरकारी अनुदान नहीं लेने। लगे दशा में वे ज्यादा मुक्त न में नों काम न चले। इसी मुक्त में इन्हें कुछ परिमित छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों का भी प्रबन्ध करना पड़ता है।

### पब्लिक स्कूल के गुण

पब्लिक स्कूलों की प्रणाली में बहुत कुछ कहा गया है। 'स्वतन्त्र भारत में शिक्षा' पुस्तक में श्री हुमायूँ कबीर ने इस प्रकार के स्कूल का समर्थन करते हुए कहा है कि यह हमारे प्राचीन अधिष्ठानों की परम्परा में है जो स्वतन्त्र रहकर देशों

को जीवन के लिए तैयार करने से। हमारे देश में सामान्य माध्यमिक स्कूलों की हालत बड़ी खराब है, उनमें शिक्षण का स्तर तथा छात्रों के विकास की सुविधाएँ सभी असन्तोषजनक हैं। ऐसे विद्यालयों के लिए पब्लिक स्कूल प्रकाम-स्नभ का काम दे सकते हैं। यहाँ छात्रों पर जैसा नियन्त्रण रहता है, जिस प्रकार की उनकी नियमित दैनिक चर्या होती है और जैसा यहाँ का वातावरण है, वह सर्वव्यतिरिक्त के विकास के लिए उत्तम अवसर प्रदान करता है। यहाँ की भवन प्रणाली तथा प्रीपैक्ट पद्धति में छात्रों में नेतृत्व तथा स्वेच्छा में काम करने की प्रवृत्ति पैदा हुंगी है। अध्यापकों और छात्रों के बीच बनिष्ठ सम्बन्ध होने में अध्यापक के उत्तम प्रभाव उन पर पड़ते हैं और उनका अनुकरण करने हुए छात्र बहुत में गुणों का विकास करने हैं।<sup>1</sup> चूँकि यह स्कूल सरकारी नियन्त्रण से मुक्त रहते हैं और इनके पास साधनों की प्रचुरता होती है, इसलिए यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता का आदर्श बना रह सकता है और साथ ही साथ इन्हें नये-नये प्रयोग करने का अवसर मिलता है।

आज की दुनिया में स्कूल की कल्पना बदल चुकी है। जॉन डेवी का कहना है कि स्कूल को समाज का समुदाय होना चाहिए। इस विचार का आशय यह है कि

देखने को नहीं मिलता क्योंकि वहाँ छात्र उसी प्रकार आते हैं, जैसे हम मेले, मिनेमा-घर और स्टेडान में कुछ देर के लिए जाते हैं और वहाँ मौजूद लोगों से कोई आनन्द या एकता की भावना का अनुभव नहीं करते। इन स्कूलों के व्यक्तिगत स्वार्थ-होके हैं। कक्षाओं में पढ़ने वाले ४० छात्रों में भी 'मौहात्र' नहीं होता। इसके विपरीत, पब्लिक स्कूल एक ऐसा समाज है जिसकी व्याख्या डेवी ने की है कि यहाँ २४ घंटे छात्रों का रहना, विभिन्न भवनों की मददगारता और अनेक सामाजिक क्रियाएँ उन्हें यह अनुभव कराती हैं कि हम सब एक ही समाज के सदस्य हैं और हमें अपने समाज के प्रति उत्तरदायी ज़रूरत है।

थी आर० एम्० जेम्स ने (NIE Journal), जुलाई १९६७ अंक, लेख 'The Public School in the Indian Community' में पब्लिक स्कूल को एक मर्यादित समाज माना है। (सामान्य स्कूलों का समाज विग्रसल होता है।) इसके सदस्य सच्चे अर्थों में सामाजिक चेतना का अनुभव करते हैं, सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, उन्हें इस समाज पर गर्व होता है और उनका सकल्प भी सामाजिक ही होता है। सभी क्रियाओं, जैसे खेल-कूद, बुद्धि, कला, फोटोग्राफी आदि में सब सहयोगपूर्वक भाग लेते हैं। अवकाश का समय भी गण लटाने के लिए नहीं होता, अवकाश बिताने का समुचित कार्यक्रम इस समाज के लिए होता है। इस समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसके सदस्य विभिन्न योग्यताओं, आयु और रक्तियों के साथ-साथ विभिन्न पृष्ठभूमि के होते हैं। यह विविधता परिवार में नहीं पाई जा सकती। इस विविधता-



तात की प्रबन्ध समिति के वे सदस्य रहें। देहली कानून में उन्होंने पढ़ाया। अपने अनुभव के आधार पर वे कहते हैं

“इनमें से पूरे हुए जो जोय निकले हैं, उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में मास्ट्रिस्ट हो गये हैं? उनमें से कितने ऐसे हैं जो पब्लिक स्कूल में आये हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश-सेवा की है, चाहे स्वाधीनता के सुप्रासू में या अन्य किसी प्रकार में? कितने लोग पब्लिक स्कूलों से निकले हैं जिन्होंने अपने चरित्र में, और बात में, साबित किया हो कि वे तो बड़े ऊँचे प्रकार के मनुष्य हैं? ऐसे अगर आप देखेंगे, तो बहुत छोटा परसेन्टेज निकलेगा, बहुत नीचा परसेन्टेज निकलेगा। कोई न कोई बजह तो होगी।”

यह कोई नक नहीं है कि पब्लिक स्कूल महान् पुरुषों को जन्म देता है, यदि यह सच होता तो अमरीका और रूस आदि देशों में महान् पुरुष होते। हमारे देश में पब्लिक स्कूलों ने एक पागड़ी समाज को जन्म दिया और उनमें बिस्मिल की कमी है क्योंकि पब्लिक स्कूलों के प्रति उनकी आस्था बनी ही है अंग्रेजी मंदिर के प्रति होती है। यह कहना भी सरासरी गणन है कि पब्लिक स्कूल भारतीय जनता के लिए नेतृत्व का प्रणिधान थे रहे हैं। जहाँ के छात्र सामान्य भारतीय जीवन में बिस्मिल बनग रहकर गरीबी और अभाव का अनुभव नहीं करते वे जनता का नेतृत्व नहीं कर सकते। यदि अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया है, तो भारतीय ‘पब्लिक स्कूल’ मफेद पोगाक पहनें यानि प्रशासकों के पागड़ी समाज का जन्मदाता है जो आज भी सामान्य जन-जीवन से अलग रहा है और देश की समस्याओं को हल करने में अक्षम रहा है। प्रजातन्त्र में भेद-भावों की दुनिया को समतल बनाया जाता है, परन्तु पब्लिक स्कूल समाज में यह समतल स्थिति पैदा नहीं होने दे रहे हैं वरन् ऊँचे टीलों को जन्म दे रहे हैं।

### भारतीय पब्लिक स्कूल द्वारा उत्पन्न समस्याएँ

१. माध्यमिक स्तर पर बोहुरी शिक्षा प्रणाली—शिक्षा के कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान, चरित्र और बुगलता की दृष्टि में उत्तम कोटि के नागरिक तैयार होते हैं। प्रयातन्त्र की रक्षा यही नागरिक कर सकते हैं। सामाजिक जीवन के धुन्धों की रक्षा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जन करते हैं। देश के नेतृत्व और प्रसासन को यह पत्रबून बनाने हैं। इस दृष्टि में माध्यमिक शिक्षा की एक सामान्य प्रणाली देश में होनी चाहिए। हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जो सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और गैर-सरकारी स्कुलों में पनप रही है। इस माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की दगा अच्छी नहीं है। भवन, साधन, माजमज्जा और अध्यापका की दृष्टि से यह शिक्षा प्रणाली उत्तम परिणाम नहीं दे रही है। करोड़ों किशोर बालक-बालिकाएँ इस शिक्षा प्रणाली के बीच होकर गुजर रहे हैं। देश को बड़े नागरिक मिलने चाहिए, वैसे नहीं मिल रहे हैं।

इस सामान्य माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के ठीक समानान्तर पब्लिक स्कूल प्रणाली है। इस प्रणाली पर चलने वाले भाष्यीय पब्लिक स्कूल, मैट्रिक स्कूल और मिशन स्कूल हैं जो भवन, माधन, गाइडमज्जा और अध्यापकों की दृष्टि में सामान्य स्कूलों में धोखे हैं। यद्यपि यह दावा किया जाता है कि इन स्कूलों के पड़े हुए छात्र धोखे होते हैं परन्तु इस दावे में कितनी गच्चाई है, यह हम डा० सम्पूर्णानन्द के कथन में जान चुके हैं। वास्तविकता यह है कि यह स्कूल धनी वर्ग तथा अधिकारी जनो की गलतियों के लिए खल रहे हैं।

इस प्रकार भारत में दो प्रकार की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है, एक सामान्य जनो के लिए और दूसरी माधन-मध्यम जनो के लिए। प्रजातंत्र में शिक्षा के लिए समान अवसर मिलने की जैसी व्यवस्था होनी चाहिए त्रैयी नहीं हो पा रही है। कुछ चुने हुए लोगों को विशेष सुविधाएँ शिक्षा के लिए प्राप्त हैं और अनेक जन उन सुविधाओं से वंचित हैं। पब्लिक स्कूलों के मोह के कारण यह दोहरी प्रणाली कायम है। सरकार ने अभी कुछ वर्ष पहले ही कोटारीजी की अध्यक्षता में शिक्षा-आयोग की नियुक्ति की और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन पब्लिक स्कूलों के सम्बन्ध में अपना मत देते हुए कहा है

“परम्परागत अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली भिन्न रही है और उसमें गैर-सरकारी प्रबन्ध के संचालन में एक अच्छी प्रकार की शिक्षा को चलने का अवसर दिया गया है जो उन लोगों के लिए मुरशिब है जो अधिक शिक्षा-मुक्त अदा करने की सामर्थ्य रखते हैं, परन्तु अभी हाल में तथाकथित पब्लिक स्कूलों की आलोचना इंग्लैंड में हुई है और यह बात असम्भव नहीं है कि वहाँ इन्हे अधिक प्रजातांत्रिक बनाने के लिए इनमें मौलिक परिवर्तन कर दिये जायें। ब्रिटिश प्रशासकों ने सगभग उसी प्रकार की (पब्लिक स्कूल) प्रणाली इस देश में लागू कर दी और हम अब तक उससे चिपटे हुए हैं क्योंकि हमारे समाज के मोपानात्मक (Hierarchical) संगठन के अनुकूल थी। इसका जो भी इतिहास (सानदार ?) रहा हो, हमारी नयी प्रजातांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था में जिसकी रचना हम करना चाहते हैं, इस प्रणाली का कोई औचित्यपूर्ण स्थान नहीं है।”

आयोग का स्पष्ट मत है कि पब्लिक स्कूलों को समाप्त हो जाना चाहिए और इस आयोग ने मारे भारत के लिए सामान्य विद्यालय (Common School) और निकटस्थ विद्यालय (Neighbourhood School) का विचार प्रस्तुत किया जो माध्यमिक शिक्षा में एकरूपता उत्पन्न करेगा। खेद है कि पब्लिक स्कूलों के प्रति मोह इतना बड़ा है कि कांग्रेस के समदीय दल ने तथा लोक सभा के अनेक सदस्यों ने इन स्कूलों को बनाये रखने का समर्थन किया है और सामान्य स्कूल का विरोध किया है। यह स्पष्ट है कि प्रजातंत्र के लिए दोहरी शिक्षा प्रणाली का होना खतरनाक है और पब्लिक स्कूल इस समस्या की उत्पत्ति रहे हैं।

२ पब्लिक स्कूल एक—परोपजीवी वृक्ष—जिम प्रकार एक परोपजीवी वृक्ष अपनी गुराक दूसरे वृक्ष के रस से प्राप्त करता है और इस दूसरे वृक्ष को मुत्ताकर स्वयं निंदा रहता है, उसी प्रकार 'पब्लिक स्कूल' सामान्य जनता के स्कूलों की अधोगति का कारण है। यह पोषक और अनुत्पादक वर्ग का स्कूल है जिनके पास अमीय साधन हैं और इन वर्ग की साधन—सम्पत्ति ने ही पब्लिक स्कूल के पास भी प्रचुर साधन होने हैं। इन वर्ग में ही यह क्षमता होती है वह शिक्षा पर व्यय कर सके और यह वर्ग पब्लिक स्कूलों में रुचि रखता है जिसका परिणाम यह होता है कि एक पब्लिक स्कूल पर जितना व्यय होता है उतने में कई सामान्य स्कूलों जम्मा हो सके हैं। जब इन साधन-सम्पत्ति लोगों को मतान इन स्कूलों में सर्वोत्तम सुविधा पाकर पड़ सक्ती है, तब अन्य सामान्य स्कूलों की ओर उन्हें ध्यान देने की जरूरत क्या है? आज प्रधानमंत्री, मंत्री, उच्च सरकारी अधिकारी, मेड-मास्टर तथा उद्योगपतियों को मन्त्रालय इन पब्लिक स्कूलों में पढ़ती है, ऐसी दशा में उन लोगों स्कूलों की ओर इनका ध्यान नहीं जाता जो अपने छात्रों के लिए साफ-सुधरे कमरों, श्यामपट्टों, पीने के पानी तथा अच्छे भूषणों की व्यवस्था नहीं कर पाते। इन उच्चवर्गीय लोगों को विद्या के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रह जाती क्योंकि उनकी समस्त अच्छी शिक्षा या लेती है और पब्लिक स्कूल उनके लिए बने हैं। आज यह लोग सरकारी स्कूल केवल परोपकार के लिए बना रहे हैं इसलिए वे भारतीय जनता के बच्चों पर शिक्षा के मद में सर्व करने में घबराने हैं। जैसे एक हनुवा-गुड़ी माने वाला व्यक्ति भित्तारी को एक सूखी रोटी देकर अपने बर्तव्य की इनिश्री समझ लेता है, उसी प्रकार यह उच्चवर्गीय लोग सामान्य जनो के बालकों के लिए निरर्थक शिक्षा की व्यवस्था करके संतुष्ट हैं। ज्यों की बात है कि भारतीय शिक्षा-आयोग ने इन तथ्य को समझा है।

जब तक पब्लिक स्कूल विद्यमान हैं, उच्चवर्गीय लोगों का ध्यान जन विद्या-मयों की ओर नहीं जायगा। इसी विचार में आयोग ने इन परोपजीवी पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने और सामान्य तथा निकटस्थ विद्यार्थी बनाने का मुभाव दिया है, ताकि अमीर-गरीब बिना किसी भेदभाव के यहाँ पढ़ सकें। भेद की बात यह है कि इन पब्लिक स्कूलों का समर्थन ही रहा है। समर्थन करने वालों में वे लोग हैं, जो यहाँ शिक्षा पाकर अपने को थोड़ा समझते हैं, उनका अपना वर्ग है और इस वर्ग की वे बनाये रखना चाहते हैं। कुछ सामान्य वर्ग के लोग 'पब्लिक स्कूल' में अपनी संज्ञानों को पढ़ाकर उच्च वर्ग के समर्थन बनना चाहते हैं। भारत में अंग्रेजी भाषा के समर्थक और यहाँ उच्च वेतन पाने वाले अध्यापक भी उन्हें बनाये रखने में अपना स्वार्थ देखते हैं।

३. 'शिक्षा के समान अवसर' के सिद्धान्त के उत्संघन की समस्या—यदि यह मान भी लिया जाय कि पब्लिक स्कूल की शिक्षा उत्तमता की दृष्टि से थोड़ा है, तो

भी यह समस्या नहीं रहती है कि यह उत्तम शिक्षा क्या कुछ मांग का ही विषय होती है। यह शिक्षा कुछ मांग सम्पन्नता के साथ-साथ सौंदर्य या मर, या भी इन पक्षिक स्त्रियों का शरीर उचित दृष्टिगत या मर का है परन्तु सामाजिकता या यह है कि यह उत्तम शिक्षा इन मांगों का विषय है जो मर के मर है। प्रजापति मर का शरीर अस्वस्थ नहीं है। इन स्थिति के शरीर में प्रभाव यह पड़ा है कि अनेक मांग या उत्तम शिक्षा के अधिकांश हैं, इन शिक्षा में अधिकांश हैं। यद्यपि कुछ मांग छात्रों का निष्कर्ष या छात्रवृत्ति के द्वारा इन स्त्रियों में शिक्षा दिवाने की व्यवस्था है, परन्तु इनमें समस्याएँ ही नहीं होती। इन बातों को डॉ० समुच्चानन्द के शरीर में सुनिश्चित-

" इन शरीरों का मर अथवा इन कुछ स्त्रीवर्गों के द्वारा कुछ मर का भी व इन स्त्रियों में, आज भी मर के पड़ा है किन्तु २० प्रतिशत, १० प्रतिशत शरीर मरों का भी मर, या क्या शरीर के विषयों का, 'ऊँट के मुँह में खीर' पानी बन जाती है। अथवा शरीरस्थान में इन स्त्रियों इन प्रकार के ही शरीरों में भी मर के पड़ा है जो प्रजापति का मर है। शरीरस्थान में शरीर मर के पड़ा है या बहुत उपाय है। अथवा प्रतिभा या मर मर शरीर मर का मर बहुत उपाय है।

स्पष्ट है कि कुछ छात्रवृत्तियों में इन में शरीर तथा प्रतिभाशाली छात्रों को उत्तम शिक्षा दिवाने की समस्याएँ ही नहीं हो सकती। इन समस्याओं का ही यह पड़ा है कि पक्षिक स्त्रियों के समान ही उत्तम शिक्षा इन मांगों की व्यवस्था मर का शरीर मांगों के विषय में या फिर इन पक्षिक स्त्रियों का समाप्त करें। प्रजापति और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम पर समाज के कुछ लोगों को यह छूट देना कि वे उत्तम शिक्षा देकर अपनी सम्मानों को जीवन की शीघ्र में अपने पहुँचा मर, भागी अस्वस्थ है। उत्तम शिक्षा इन के साथ-साथ शरीर की साथ, यह प्रजापति के विद्यालय के अनुक्रम नहीं है।

४ पक्षिक स्त्रियों द्वारा भाषा-समस्या की जटिलता में वृद्धि—आज हमारे देश में भाषा की समस्याएँ के उत्पन्न होने का मूल कारण यह है कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त जन अंग्रेजी में काम करने के जादी बन जाते हैं। उन लोगों का एक अलग वर्ग बन जाता है। इन वर्गों को सरकारी नौकरियाँ पाने में सुविधा होती है क्योंकि सरकारी काम-काज अंग्रेजी में चलता है। अंग्रेजी के इस महत्त्व के कारण पक्षिक स्त्रियों में माध्यमिक शिक्षा भी अंग्रेजी में दी जाती है और अंग्रेजी का अध्ययन बली-भक्ति कराया जाता है। यहाँ के पड़े हुए छात्र उच्च शिक्षा में केवल माध्यम (अंग्रेजी) पर विशेष अधिकार रखने के कारण सामान्य तथा पेशेवर शिक्षा में बाजी मार लेते हैं। इसलिए इन पक्षिक स्त्रियों की मांग बढ़ रही है। इस देश में सरकारी नौकरी भी एक पेशा है और उसमें सुख-सुविधाओं के होने में हर आदमी नौकरी चाहता है। नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी की सीढ़ी पर चढ़ना आवश्यक है। इसमें नौकरशाही वर्ग के लोग अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान कराने के लिए अपनी सन्तान को इन पक्षिक



स्कूलों में भेजने हैं और वे अपनी मन्तान का अच्छी नौकरी दिलाने के लिए अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। साथ ही वे पब्लिक स्कूल का भी समर्थन करते हैं।

पब्लिक स्कूलों ने अपने अस्तित्व में और विशेष रूप में अंग्रेजों का माध्यम के रूप में बनाये रखकर देश में भाषा-विवाद की समस्या को उभारा है। अंग्रेजी भाषा के समर्थन वाले समर्थक फ्रैंक एन्थोनी ने इस बात पर बड़ा ध्यान दिया है कि इन स्कूलों तथा इस प्रणाली पर चलने वाले सैनिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ न हों, अंग्रेजी ही माध्यम के रूप में इन स्कूलों में जारी रहे। आज सरकार राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना चाहती है और शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाना चाहती है परन्तु पब्लिक स्कूलों को या तो छूट देनी होगी या फिर पब्लिक स्कूल के समर्थकों के विरोध का सामना करना होगा।

५. एक विशिष्ट वर्ग की उत्पत्ति—पब्लिक स्कूल का जैसा जीवन होता है अर्थात् उनमें रहे कर विद्यार्थी जितना धन खर्च करता है, जैसा उत्तम भोजन पाता है और जैसा कपड़े पहनना तथा सुख-सुविधाओं का उपयोग करता है, उसे देखते हुए वह समझने में देर नहीं लगेगी कि यहाँ का पढ़ा हुआ छात्र शोषक वर्ग का सदस्य बनेगा। जिस देश में इतनी गरीबी हो, जहाँ इतना आर्थिक मकड़ हो, वहाँ ऐसे सुखमय जीवन बिताने वाले लोग कैसे अपना गामजस्व स्थापित कर सकते हैं। वे लोग अपने काँ करोड़ों दीनहीन नर-नारियों में अलग ही समझते हैं। यह लोग सरकारी नौकरियों पर अपनी निगाह रखते हैं, कोई रचनात्मक या उत्पादक कार्य वे नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की सपना तो तब होती जब भारत एक साम्राज्यवादी देश होता और पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए लोगों का हमारे देशों में भारत का साम्राज्य चलाने के लिए भेजा जाता। १९वीं सताब्दी में इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूल इसलिए जन्म गये क्योंकि हमने उत्पन्न विशिष्ट वर्ग की आवश्यकता थी, उन्हें इंग्लैण्ड की सरकार भारत तथा अन्य उपनिवेशों में शासन चलाने के लिए भेज देती थी। वे इंग्लैण्ड के समाज के लिए कोई खतरा न पैदा करते थे। हमारे देश में पब्लिक स्कूल के द्वारा उत्पन्न समाज ने एक शोषक वर्ग की स्थापना की है। वह वर्ग बराबर बढ़ता ही जा रहा है।

इस सम्बन्ध में एक बड़ा विचित्र तर्क दिया जा रहा है। श्री० डी० आर० ए० माउण्टफोर्ड ने अपने एक लेख 'अज्ञानता का शिकार' (D. M. A. Mountford : 'A Victim of Ignorance', हिन्दुस्तान टाइम्स, ता० २५ अगस्त सन् १९४७ के अंक में प्रकाशित) में कहा है कि हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार प्रजातन्त्र में होता है कि वह अपनी मन्तान को जैसी शिक्षा चाहें दिलावे और इस प्रकार हर एक को स्वतन्त्रता है कि वह अपनी मन्तान को पब्लिक स्कूल में पढ़ाये। यही बात एक बार अपने भाषण में मेयो कालेज के प्रिंसिपल पिचमन ने कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि कोई अमीर आदमी अपनी मन्तान की शिक्षा पर हजार रुपया प्रतिमास खर्च करता है, तो प्रजातन्त्र में उसे रोका कैसे जा सकता है ?



जोड़ दिया गया। श्री मार्वेटफोर्ड ने अपने मेम्बर में पब्लिक स्कूल को अज्ञानता का शिकार बताया है परन्तु उसके समर्थक कितने अज्ञानी हो सकते हैं, इसका परिचय उनके विचारों में मिलता है।

हमारे देश में पब्लिक स्कूल की उपलब्धियाँ मन्दोद्धारपद हैं। फिर भी उसके पक्ष में तर्क दिये जाते हैं। पब्लिक स्कूल के द्वारा ममाज में भेदभाव उत्पन्न होते हैं, इस बात को इस परम्परा के समर्थक नहीं स्वीकार करते। श्री दीनदयाल ने 'The Public School of India—Boon or Bane' NIE Journal, जुलाई सन् १९६७ के अंक में प्रकाशित) अपने लेख में तर्क देते हुए कहा है कि भेदभावपूर्ण ममाज पब्लिक स्कूल को देन नहीं हैं, यह भेदभाव पारिवारिक बानावरण की भिन्नता में उत्पन्न होता है। अपने समर्थन में उन्होंने हैरो (इंग्लैण्ड) पब्लिक स्कूल के वर्तमान हेडमास्टर डॉ० जेम्स के विचारों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के माना-पना के बानावरण की भिन्नता में भेद पैदा होते हैं। यदि इस तर्क को मान लिया जाय तो यहाँ के छात्रों की श्रेष्ठता का कारण पब्लिक स्कूल नहीं, घरेलू तथा स्कूल का उत्तम बानावरण है। यदि उत्तम बानावरण में उत्तम व्यक्ति पैदा होता है, तो यह उत्तम बानावरण कुछ जुनं हुए लोगों को ही क्यों मिलना चाहिए ?

यह स्पष्ट है कि पब्लिक स्कूल भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं। मुद्रातिथर शिक्षा-आयोग ने वर्तमान काल में इन स्कूलों का होना एक ऐनिहामिक भूल (Anachronism) बताया है। बड़े से बड़े पब्लिक स्कूल के समर्थक यह स्वीकार करते हैं कि पब्लिक स्कूल के स्वरूप को बदलना आवश्यक है। स्वयं श्री मार्वेटफोर्ड ने कहा कि पब्लिक स्कूल की परम्परा के अनुकूल भारतीय पब्लिक स्कूल नहीं चल रहे हैं। उनके मत में यह मोचना अनुचित है कि कुछ लोग ईर्ष्या-द्वेष के कारण इन पब्लिक स्कूलों का विरोध कर रहे हैं। इनमें मुभाव अपेक्षित है और उन्हें भारतीय परम्परा के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।

'पब्लिक स्कूल' की समस्याओं को हल करने के लिए मुद्रातिथर शिक्षा आयोग द्वारा सुझाये गये उपाय—मुद्रातिथर आयोग ने इन पब्लिक स्कूलों के मध्यम में कहा है कि यदि इनका पुनः सगठन कर दिया जाय तो बहुत-सी समस्याएँ हल हो सकती हैं। आयोग के मुभाव निम्नलिखित हैं।

(१) पब्लिक स्कूल केवल एक विशिष्ट वर्ग के स्कूल न रहें। ऐसी व्यवस्था हो कि इन स्कूलों में कुशाग्रबुद्धि के निर्धन छात्र प्रवेश पा सकें। इसके लिए छात्रवृत्तियों की परम्परा कायम की जाय। इससे इन स्कूलों की विशिष्टता नष्ट हो जायगी।

इन मुभाव के विरुद्ध डॉ० मधुपूर्णानन्द की दलील यह है कि यदि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्रवृत्तियों को पाकर पढ़ने भी लगे, तो उन अमकर मेधावी बालकों का क्या होगा जिन्हें पब्लिक स्कूलों में जगह नहीं मिल सकती क्योंकि इन स्कूलों



(४) आयोग ने यह सुझाव दिया कि राज्य तथा केन्द्र में इन स्कूलों को अनुदान दिया जाय परन्तु उनकी मात्रा कम कर दी जाय। हममें यहाँ का विनाशिता-पूर्ण वातावरण मुझे मिला।

श्री इमाम खदीर

ज्वीर ने अपनी पुस्तक  
स्थाओं के निराकरण

ज्वीर पब्लिक स्कूल  
बाहरी स्वरूप तथा  
परम्पराओं और  
तरीकों प्रमुख है, इसे

प्रणाली के अधिक  
ने के उपाय लोके

१। हममें सामान्य  
हुनियादी स्कूलों में  
कारी का समावेश

२, इसकी व्यवस्था  
छात्रों का चुनाव

ला विद्यालय के  
देश में कुछ ऐसे  
एव उत्पन्न करने  
भिन्न वातावरण  
इसला विद्यालय  
जायगा।

ओ का आकार  
र दिया जाय।

१ भेजना काफी  
चुने जायें और

ज्वीर का आधार न  
ज्वीर बाहरी-देहानी,

ते, धन तथा प्रभाव के भेदों के कारण केवल कुछ लोग इनसे लाभ न

1) पब्लिक स्कूल की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी न रहे, चाहे अंग्रेजी के विद्यार्थी को भी शिक्षा दी जाय। यहाँ छात्रों के प्रवेश में अंग्रेजी बहुत बड़ी बाधा होगी। पब्लिक स्कूल स्थित हों, वही की भाषा माध्यम के रूप में प्रयुक्त माध्यम प्रदान देने में, पब्लिक स्कूल की हालत बदल जाएगी। यहाँ के वातावरण में परिवर्तन होगा और वास्तविक रूप में प्रतिभाशाली छात्र होंगे। भारत के पब्लिक स्कूलों का निरीक्षण करने वाले एक अंग्रेज मज्जन स्वरूप प्रकट करते हुए कहा था कि अंग्रेजी के माध्यम के द्वारा भारतीय छात्रों में वह गुण पैदा नहीं कर सकते, जो उन्हें पैदा करने चाहिए।

2) पब्लिक स्कूल में एक श्रेष्ठ प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, यह बात है और इसके लिए साधन जुटाए जायें, जैसे उत्तम भवन, प्रयोगशालाएँ, दान आदि, परन्तु उत्तम साधनों के नाम पर किताबखर्ची न होने पायें। धर्म-धर्म की ओर में छात्रों को विमुख किया जाय। खान-पान और परीक्षा कम कर दिया जाय। केवल इस आधार पर कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन पर प्रतिभाशाली अत्यधिक धन व्यय करना अनुचित है। यही तो बड़ा बुराई है। यहाँ 'मादा जीवन उच्च विचार' के आदर्श की प्रतिष्ठा नहीं। यदि कोई अमीर घर का प्रतिभाशाली छात्र यहाँ पढ़ता है तो उसे जीवन बिताने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हमारे देश की पुरानी शिक्षा और है। धीरूषण सादीपन मुनि के आश्रम में पढ़ने जाते हैं, तो वे साधु बने बिना ही और जगहों में लकड़ी एकत्र करते हैं। जहाँ अब ऐसा है, तो इतना अवश्य हो सकता है कि पब्लिक स्कूल में सादगी भरा जीवन अभिवाक के सामाजिक पद की परवाह न करके हर छात्र को सादा जीवन देने को बाध्य करना चाहिए।

3) यहाँ के अध्यापकों और सामान्य स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम में अंतर न होना चाहिए। वेतन अधिक पाने के कारण यहाँ का अध्यापक अपने को 'शान्ति' का सम्मान है और उसका प्रभाव बालकों पर पड़े बिना नहीं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए आवास, भोजन और पुस्तकों की अनिवार्य आवश्यकता है। आज यहाँ के अध्यापक के मन में वेतन अधिक पाने में शिक्षा-होना है, विद्वान और ज्ञान के लिए कितना अध्यापक विख्यात है जो पब्लिक स्कूल में पढ़ें। अध्यापकों के बचन में केवल उपाधि का विचार न करके, अध्ययन, कर्म-कर्म तथा बालकों की शिक्षा में विशेष रुचि रखने वाले हो नियुक्त किया जाय।

4) पब्लिक स्कूल 'सामाजिक' होना है। यह बात हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों की। छात्रों के लिए स्कूल के छात्रावासों में रहना अनिवार्य होना एक

विशेष महत्त्व की बात है; इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों पर परिवार तथा समाज के कुप्रभाव न पड़ने पायें। हम मावासीय शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता तभी बढ़ सकती है, जब छात्रों के संस्कार भारतीय हों, यदि उन्हें अंग्रेजी तीर-नगी के में हार ममय रहना पड़ता है तो वे आगे चलकर भारतीय समाज में नहीं मध सकेंगे। इसलिए पब्लिक स्कूल की जीवन शैली भारतीय संस्कृति के अनुकूल अविनय कालन की आवश्यकता है।

(७) विनोबाजी का विचार है कि शिक्षा का काम निजी प्रयत्नों में ही तो स्वतन्त्रता का भाव बना रहेगा। पब्लिक स्कूलों की वर्तमान आर्थिक स्वतन्त्रता इस विचार में अच्छी है। हम पहले कह चुके हैं कि इन स्कूलों में सभी वर्गों के छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि इन पर सरकारी नियंत्रण हो और इन पर मार्शनीय कोष में धन खर्च हो। एसी दशा में इन स्कूलों की धार्मिक स्वतन्त्रता बनाये रखना आवश्यक है। इनके सरकारी फाइलों और निग्राधिकारियों की काम में मुक्त रचना आवश्यक है। यहाँ के प्रध्यापकों को असीम अधिकार मिलने चाहिए। उद्देश्य यह हो कि स्कूल के पास पर्याप्त धन रहे और यहाँ शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग हों। समाज-सेवा और शिक्षा, अध्ययन-अपवापन की विधियों, अध्यापक-शिक्षा सम्बन्ध और चरित्र-निर्माण आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नूतन प्रयोगों की आवश्यकता है और यह उत्तरदायित्व पब्लिक स्कूलों को उठाना चाहिए।

हम महान् परिवर्तनों की देहली पर खड़े हैं और युव-परिवर्तन के दौर में पब्लिक स्कूल अपने 'अंग्रेजी' स्वरूप में खड़ा नहीं रह सकता। डा० मधूपानिन्द के शब्दों में, "मवान तो ऐसा है कि अंग्रेजी राज्य के चले जाने के बाद भी अंग्रेजी संस्थाओं की नकल करने की प्रवृत्ति हमारी बनी हुई है, बिना सोचे-समझे। लेकिन देन एक दिन सोचेंगा ज़रूर और जब सोचना शुरू करेगा तब देन के सामने मवान होगा कि आखिर यह चीज क्यों? यदि इन पब्लिक स्कूलों के जगिये से कोई विशेषता नहीं, यही भारी ऐसी विशेषता जिसे कहना चाहिए मुर्मावा विशेषता, जो प्रत्येक की समक में आ जाय, जिसके ऊपर सबकी निगाहें जार्य।" पब्लिक स्कूलों को अस्तित्व के लिए मर्ष करना होगा, दम छोड़ना होगा और तभी वे बच सकेंगे।

### अध्यात्माथे प्रश्न

१. भारत में 'पब्लिक स्कूल' की स्थापना और विकास का मक्षेप में इतिहास लिखिए। पब्लिक स्कूल की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
२. "आज के प्रजातान्त्रिक युग में पब्लिक स्कूल का होना एक ऐतिहासिक मूल है"—इस कथन को स्पष्ट करते हुए अपने विचार लिखिए।

३. गवर्नर स्कूल का भारतीय दृष्टिकोण से क्या है ? क्या यह गवर्नर स्कूल वही है जो भारत में अस्तित्व में है ?
४. गवर्नर स्कूलों का विद्यार्थी भारत में विदेशी शिक्षा या शास्त्रीय शिक्षा से गवर्नर स्कूल से क्या भिन्न है ?
५. गवर्नर स्कूल का 'इंग्लिश मीडियम स्कूल' (Anglo-medium school) क्या होता है ? 'इंग्लिश मीडियम स्कूल' का इंग्लिश मीडियम क्या होता है ?
६. भारत में कुछ प्रसिद्ध गवर्नर स्कूलों के नाम लिखिए। गवर्नर स्कूलों का उद्देश्य क्या है ?

राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

1. What is a Public School and what are its special features ? Discuss the place of Public Schools in Indian education and their contribution to it. (1961)
2. Trace the historical development of Public Schools and describe their contribution to education in India, explaining also what place they occupy in Indian education today. (1963)
3. Write short notes on—  
 (a) What the Public School System can give to ordinary Schools ? (1964)  
 (b) पारिवर्तनिक विद्यालय (Public Schools) । (1966)
४. भारत में पारिवर्तनिक स्कूलों की आवश्यकता किम प्रकार प्राप्ति हुई ? इनके प्रमुख अंगदान (Contribution) क्या है ? हमारे देश में ये क्यों अभी तक नहीं बढ़े हैं ? (1966)



## अध्याय १७

### भारत में राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता और शिक्षा

समस्या क्या है ?

आज हमारे देश में चारों ओर से यह आवाज आ रही है कि राष्ट्र पर जहाँ बाहरी शत्रुओं के आक्रमण का भय है, वहाँ हमारे भीतर विघटनकारी तत्व मौजूद हैं। जब भारत आजाद होने लगा था, तो उसका एक अंग उसमें कटकर अलग हो

रूप में वर्तमान है, अपनी 'स्वतन्त्र मता' को बनाये रखने की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रही हैं। इस समय मद्रास राज्य में द्रविड मुन्नेत्रकडगम नामक राजनीतिक दल का राज्य है, मत्तारुद्ध होने पर उसकी उन्मुखता में कमी आयी है परन्तु उसकी अलगवा की प्रवृत्ति मल्ट नहीं हुई। उन्होंने 'मद्रास' के स्थान पर 'तमिलनाडु' शब्द चुना है। 'आकाशवाणी' और 'महिर्वाग्य' जैसे अखिल भारतीय प्रयोग वाले शब्दों के स्थान पर मंचे शब्द रख कर अपनी पृथक् मता की घोषणा के साधन कर रहे हैं और अंग्रेजों की भाषा और मस्तिष्क को अपनाये में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार पुगने पत्राव के टुकड़े पाकिस्तान बनने पर हुए ही थे, अवशिष्ट पत्राव भी दो टुकड़ों में पुन बँट गया। पत्राव के बाकी भाग में स्वतन्त्र 'मिम्बिस्तान' की माँग है और पूर्व में 'स्वतन्त्र नागार्लण्ड' का कुषक चल रहा है।

नामाग्न जीवन के स्तर पर भारत के नागरिकों की विविध स्थिति है। हर भारतीय अपने 'स्व' को दीवारों के बीच बन्दी है। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नीचे में नीचे स्तर तक, पशु के स्तर तक आ सकता है। एक स्वामिभक्त कुत्ता ममप पड़ने पर अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता है परन्तु

इस पर अब संकट है और साथ-साथ जात्रमन करने का भी है, या जो देश के कुछ बर्तक विरोधियों ने भारत सरकार परी का समर्थन दिया मकर है, परी में संनिव मरुष की मुपनामों की नहीं, पादम भी इ मकर है। उनके मन में जरा भी नई अनुर्दी नहीं होती है और का ही जना जिन है। इस समय इस पर अज्ञान की भगनक द्वारा यह रही है, सर्वत्र अज्ञान ही, निर्धन दम सिंह रर है और मर्यादा के बाध में सामान्य ज्ञा की समर दूर रही है। उस समय भी भारत के कुछ लोग मुनाता-मोरी, पादशाही और मंधय के द्वारा ज्ञान बर्तनमर म्मम तथा नई का मनुष्ट कर है, या यह समय ज्ञान आगान है कि इस में भावनात्मक लका की बर्मी है। य कुछ लोग समर्थ भारत के दूर का ज्ञान दूर मरी समझत। कहा गया है कि 'कुमुदिता, विप्र कर्माँ पात्रम्' परन्तु अराष्ट्रीय जन पैर भग ज्ञान पर नाना प्रकार के पात्र करने है।

इसी प्रकार एक भाषा बोलने वाले, एक धर्म का मानने वाले, एक जाति के और एक धर्म के लोग अनी-अनी भाषा, धर्म, जाति और वर्ग के दावे में रह रह है। राष्ट्रीय जीवन के विज्ञान समुद्र में यह जगवर द्वीप ज्ञान निर ऊँचा बिन्दु दृष्ट रह है और उस समुद्र की सहर उन द्वीपों के तटों में केवल टकरा कर लोट जाती है। राष्ट्रीय जीवन के उस विज्ञान समुद्र का धुनोरी देने वाले इन द्वीपों का बना रहना ही 'भारत में राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की समस्या' है। इस देश के भीतर बसने वाले ६० करोड़ लोग जब तक सहर बन कर इस विज्ञान समुद्र में निरोहित नहीं हो जाते, यह समस्या हमेशा-हमेशा बनी रहेगी। जिस प्रकार एक जीवित शरीर में पैर के अंगूठे में तेकर निर के एक-एक ज्ञान तक जितने सूक्ष्म में सूक्ष्म अंग हैं, जीवित शरीर में जलम अनी पृथक् मत्ता नहीं रहने हैं, उसी प्रकार हर नागरिक की चेतना राष्ट्रीय चेतना में पृथक् अपनी मत्ता नहीं रखती। पैर के अंगूठे में जरा भी छोट लगने ही शरीर भर झनझना उठता है। इसी प्रकार की वेदना, हर व्यक्ति को राष्ट्र के सकट के अवसर पर हमी धाहित। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है, यही राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की समस्या है। दुर्गन्ध के इतिहास की एक घटना है, 'वेनहिल्ल इयर।' एक समुद्री यात्री जेकिन एक जेनम में अपना रुठा हुआ बान लेकर दुर्गन्ध की संक्रमण में प्रस्तुत होता है और कहता है कि स्पेनबामिथो ने एक अणु का कान काट करके दुर्गन्ध का अपमान किया है। सारा राष्ट्र स्पेन में मुड़ करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार का भाव हमारे देश में अभी नहीं पैदा हुआ है। विदेशों में भारतीयों का अमान होना है परन्तु हमारे नेता कायरतावश इसका प्रतिकार नहीं कर सकने और राष्ट्रीय एकता के आदर्श का प्रचार करते हैं।

### राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की प्रक्रिया

भारत में रहने वाले समस्त जनों के हृदयों में परस्पर सम्बद्ध रहने की भावना की कभी राजनीतिक नेताओं की आजादी के दम वर्षों के बाद होने लगी और

सन् १९६१ में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन (National Integration Conference) का आयोजन श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इस सम्मेलन द्वारा दी गई रिपोर्ट में राष्ट्रीय एकता के भाव की व्याख्या इस प्रकार की गई

“राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक तथा वैश्विक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत जनता के हृदयों में एकता, मघटन और समष्टि (Cohesion) की भावना, एक-समान नागरिकता की अनुभूति तथा राष्ट्र के प्रति बफादारी (निष्ठा) की भावना का विकास आ जाता है।”

सरल शब्दों में हम बात को हम यों समझें कि राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता का भाव एक मानसिक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति (Attitude) है जो सीखने से और अनुभव करके धीरे-धीरे उदय होती है। इसके विकास में शिक्षा का सबसे अधिक योगदान होता है। इस अभिवृत्ति के अस्तंगत कई बातें आ जाती हैं, जिन एक देश में रहने वाले सभी जन धार्मिक, सामाजिक, भाषाई तथा जातिगत सभी भेदों को भुलाकर परस्पर भाई-भाई होने की भावना में प्रेरित हो उठते हैं। वे समझते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में चाहे वह व्यक्तिगत स्वार्थ या विदेशी क्षत्र के इशारे में उत्पन्न हुई हो, एक-दूसरे से दूट कर अलग नहीं होंगे। हमारा एक देश है, हम उसके नागरिक हैं और नागरिक की हैमियन में हमारी जिम्मेदारी है। उस राष्ट्र के साथ हम किसी भी दशा में घोखाघड़ी नहीं करेंगे।

राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की यह प्रक्रिया केवल प्रचार या व्याख्यान में नहीं पैदा होती है। किसी भी देश के समस्त नागरिकों के हृदयों को एक तन्त्र में बांधने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। इस कार्य में कई तत्त्व सहायक होते हैं। इन तत्वों का उल्लेख डा० निकोलस हैन्स ने अपनी पुस्तक ‘तुलनात्मक शिक्षा’ (Comparative Education) में किया है। संक्षेप में उन पर विचार कर लेना उपयोगी होगा।

डा० हैन्स के मत में राष्ट्रीय एकता का एक प्रमुख तत्व है—निश्चित भौगोलिक सीमा। जब कोई निश्चित भू-भाग कुछ भौगोलिक सीमाओं (प्राकृतिक सीमाओं) में घिरा होता है, उस भू-भाग के रहने वाले परस्पर एकता का भाव अनुभव करने लगते हैं। यदि यह भू-भाग एक ही सामन गत्ता के अधीन हो तो यह भाव अधिक पुष्ट होता है। दूसरा तत्व है—वर्ण तथा जाति का। संसार में नरेंद्र, काली और पीली जातियाँ हैं। उन्हें हम आर्य, मंगोल और द्रविड़ जातियों के नाम में पुकारते हैं। क्योंकि शरीर-रचना की दृष्टि में एक जाति के लोग समान होते हैं। यदि किसी भू-भाग में एक ही वर्ण या जाति के लोग हों, तो वे परस्पर एकता का अनुभव करने लगते हैं। तीसरा तत्व धर्म और संस्कृति का है। यदि किसी भू-भाग के रहने वाले एक ही धर्म को मानते हैं और अपना सांस्कृतिक जीवन अर्थात् खान-पान, वेशभूषा,

नाम महापिपासु' में भी है। यहाँ क ब्रह्म ज्ञान महाबाध्या, जगत्समापन्न और महाभारत, देश की एकता की अनुभूति जगत् के लिए विभिन्न सत्ता के वर्तन दत्त है और उनकी प्रतिष्ठा मान है। जगत्समाधी जगत् दक्षिण में जाकर बुधार्थ अतीत पर समुद्र और फिर वो अर्चना करने है। पादरक्षण माने दत्त का धर्मन करने वह आमान देत है कि यह मान देत एक है। बहुत म ब्रह्मवा न भाग्य माना भी बहुत मूर्ति का मात्रक वर्णन करने हुए विभिन्न प्रकृत वस्तुओं का भाग्य माना का अर्थ और प्रमाण माना है, जगत् विमानय भाग्य मी का मुद्रा है, मया-यमुना ब्रह्म है, विद्याधन मयता है, हरे-भरे भैरव धानी अचल है और बुधार्थ अतीत उनके वर्णन है विज्ञान रत्नाकर अपने पवित्र जल में निरंतर धारा बरता है। भाग्य माना की यह मूर्ति जो यहाँ के कलाओं लोगों के दुःख में निवास करती है हमारी राष्ट्रीय मत्त आत्मामक पचना का दृष्ट आधार है। उस प्रादेनिक जगत्ता का बोध करण कांच देश के कानि-कानि में वर्तमान तीर्थ है जिसकी मत्ता जागो में है और भाग्यसामी, चाट दिग कानि म रहने ही, उनके प्रति श्रद्धा रखने है। भाग्य के चारों कानि पर स्थानि चारों ज्योतिर्मत्त जिसकी पत्रिमा के लिए जागो की मत्ता में प्रति बरं नर-नारी प्राचीन काल में उमड़ने चने आत है हमारी राष्ट्रीय पचना का मवय है।

प्रादेनिक अवज्ञता का भाव मत्त में हमारे हिन्दू, मुसलमान शासक के मन में वर्तमान रहा है यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने विध्वंस उत्पन्न करने के लिए उस भावना की साम्राज्यवादी भावना बनाया है। बड़-बड़े हिन्दू मन्त्राद् इन प्रादेनिक एकता की प्राप्ति करने की परमावस्था की अवस्था यत्त के द्वारा प्रकट करने थे। अशोक, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, विजयनादित्य और हर्ष आदि सम्राटों ने प्रादेनिक अवज्ञता के लिए बराबर प्रयत्न जारी रखे थे। यद्यपि अनेको द्वारा लिखे गए इतिहास ने हिन्दू, मुसलमान की पृथक्ता बनाय रखने के लिए मुसलमानों का विज्ञान के रूप में चित्रित किया है और उनके द्वारा हिन्दुओं को पदनिष्ठ करने के चित्र प्रस्तुत किए हैं परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि यवन सम्राट भी भारत में आकर प्रादेनिक अवज्ञता के लिए बराबर प्रयत्न करते रहे। अक्सर महान् के मन में इस देश की राष्ट्र के रूप में एक तन्वीर थी और वह माने देश को एक भेड़ के नीचे लाने के लिए बराबर प्रयत्नशील रहा।

कई हजार मील लम्बा और चौड़ा यह भारत विभिन्न विचारों, धर्मों, गस्कुतियों और भाषाओं की जन्म-भूमी हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। याव ही प्राचीन काल में लेकर अब तक इन विभिन्नताओं को एकता में आत्ममान कर लेने की प्रवृत्ति चल रही है जिसे हम ममत्व की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। हमारे कबीर कहते हैं— 'अनेकता में एकता भारतीय ममत्व और मस्ति की विशेषता है। हिन्दू समाज-व्यवस्था अपने आप में इस सिद्धान्त का विशिष्ट उदाहरण है। इसी के कारण परम्पर विरोधी विद्वानों और मनो के लोग भी एक ही समाज के सदस्य रहे हैं। हिन्दू समाज ने तब तक न तो नास्तिकों का बहिष्कार किया

और न एकेस्वरवादियों का और न अनेकेश्वरवादियों का जब तक कि उन्होंने कुछ सामाजिक आचारों का पालन किया। इस प्रकार उसने सामाजिक आचार के निश्चित ढाँचे के पालन पर बल देते हुए बौद्धिक मनभेदों को अधिकतम छूट दी। ध्वजहार में भी विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों और वर्गों में अधिकतम अनेकता को छूट दी गयी।"

विरोधों को बने रहने देने के कारण भारत में कभी भी विस्फोटक स्थिति नहीं पैदा हुई और राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की प्रक्रिया को निरन्तर बल मिलता रहा जिसके पत्रस्वरूप हर प्रकार के अतिविरोधी तत्त्व निकट आने का प्रयास करने लगते थे। उदाहरण के लिए, प्रारम्भिक काल में देवामुर सशस्त्र चला परन्तु बाद में यह मुर-अमुर का भेद मिट गया। ऋग्वेद के काल में लेकर अथर्ववेद के काल तक आते-आते भारत की आर्य और अनार्य जातियों के विरोध कम होने लगे गये और दोनों जातियों ने एक-दूसरे के आचार-विचार ग्रहण कर लिये। इस देश में वर्तमान विभिन्न जातियाँ उपहास की वस्तु बन गयी हैं परन्तु हम भारत की यह सूची है कि यहाँ यह मारी जातियाँ महाम्मदियत के मिठाई का पालन करने हुए अपनी भीमाओं के भीतर जीवित हैं। जहाँ यूरोप में विभिन्न जातियों को समूल नष्ट करने या उन्हें दान बनाने की प्रथा थी वहाँ हम देश में विरोधी तत्त्वों को जीवित रहने के अधिकार दिये जाते थे, जाति प्रथा के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों निम्न स्तर पर अपनी गुत्ता बनाये रखने का अधिकार मिल ही जाता था। यहाँ विभिन्नता को मिटाने का प्रयत्न कभी नहीं हुआ। यह क्रम मुसलमानों के आगमन के भी चलता रहा। यद्यपि कुछ मुसलमानों ने धर्मपूर्वक हिन्दू मन्त्रों को नष्ट करने का प्रयत्न किया परन्तु सामान्य जन-जीवन के स्तर पर हिन्दू, मुस्लिम संस्कृतियों के विरोधों को नष्ट करने का प्रयत्न हिन्दू, मुस्लिम सन्त बराबर करते रहे। इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा प्रतिनिधि साम्राट अकबर था जिसने हिन्दू, मुसलमानों के भेदभाव को अपनी उदार नीति में मिटाने के लिए भरमक प्रयत्न किए थे। उसका दीनइसाही मत ममन्य की कृपा का प्रमाण है। मुगल साम्राज्य के अन्त के समय हिन्दू, मुसलमान अपने मतभेद बहुत कुछ भुला चुके थे परन्तु अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद विदेशी शासकों की कूटनीति ने उन दबे हुए भेदों को पुनः उभार दिया और प्रचार द्वारा ऐसा विष फैलाया कि देश दो टुकड़ों में बँट गया।

भारत की भारतीयता या जिससे हम 'राष्ट्रत्व' कह सकते हैं, नहीं चीज नहीं है। बहुत से लोग अज्ञानभाव में रहते हैं कि राष्ट्रीयता का भाव भारत में पश्चिम से आया है और अंग्रेजी पढ़ने से जाजादी की प्यास भारतीयों में पैदा हुई। बहुत प्राचीन काल में 'भारतीयता' अथवा भारत के राष्ट्रीय जीवन की एक परम्परा को विदेशियों ने अनुभव किया था। इन बातों का समर्थन करते हुए प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने कहा है कि जब मेसोपोटामिया, फारिया और हनुनाग जैसे प्राचीन यहाँ आए, तो उन्होंने यहाँ जातियों और सम्प्रदायों की भिन्नता देखी परन्तु फिर भी उन्होंने उन सबको भारतीय

मता के रूप में स्वीकार किया। बाबर यहाँ आया और उसने भी 'भारतीयता' को हचाना। उसने भारत की जीवन शैली को अन्य देशों की जीवन शैली से भिन्न जानते हुए, उसे हिन्दुस्तानी कहा। तात्पर्य यह है कि इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों में चाहे जितनी भिन्नता हो, उनमें एक भौतिक एकता है। वही एकता सन् १८५७ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में और १९४२ में क्रान्ति के रूप में प्रकट हुई, वही एकता चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों के समय या देश पर सिकट आने के समय प्रकट हुई थी। आज भी वह भावना विद्यमान है यद्यपि वह कभी-कभी मिला पड़ जाती है।

### राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाली बाधाएँ

(१) देश की विशालता—भारत एक लम्बा-चौड़ा देश है। उसकी सीमाएँ ई हजार मील लम्बी हैं। यद्यपि प्राचीन काल में धर्मयात्रा, तीर्थयात्रा और व्यापार परम्पराओं के कारण देश के एक कोने के लोग दूसरे कोने तक जाते रहे हैं परन्तु उनकी संख्या कम रही है। यातायात के साधन कभी विकसित नहीं रहे और मार्ग में दियौ, पर्वत और रेगिस्तान बाधाएँ उत्पन्न करके आवागमन को कठिन बनाते रहे। १९वीं सदी के आखिरी में जब रेल, मोटर, हवाई जहाज तथा अन्य साधनों के विकास में हम बाधाएँ दूर हुईं और समय कम लगने लगा तो भी इस देश के दो-चार तैंगस लोग ही सारे देश का घूबर लगाकर यह अनुभव कर सकते हैं कि उनका देश कहीं से कहीं तक फैला है। जब इस देश में एक छोटे से गाँव में रहने वाले लोग एक-दूसरे के साथ भावनात्मक एकता का अनुभव नहीं करते, तो इस विराट देश में कश्मीर का निवासी केरल अथवा बंगाल के निवासी के साथ एकता का अनुभव कैसे कर सकता है ?

(२) धर्म, सम्प्रदाय, संस्कृति और जातिभेद के ऐतिहासिक तत्त्व—भारत में मान्यता करने वालों के बीच वर्तमान अनेक भेदभावों के कारण ऐतिहासिक है। इस देश का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह मान्यता प्रकार की जातियों और धर्मों की अस्तित्व तथा आगमन का केन्द्र रहा है। यहाँ हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई धर्मों का साथ-साथ बौद्ध और जैन मान्यताओं भी रहने हैं, जो हिन्दू संस्कृति से अधिक भिन्न नहीं रहते। धर्म के भेद में सम्प्रदाय और संस्कृति भेद भी उत्पन्न हो गए। हिन्दू-मता में जातिप्रथा प्राचीनकाल में जारी रही और यह मता द्वारा जातियों को बाँटा है जिसका आधार जन्मगत है। इतिहास के सम्बन्ध में यह मान्यता भेद उत्पन्न है और इतिहास ने सामान्य शिक्षाओं में इनमें परिचित है। धर्म, सम्प्रदाय, संस्कृति और जाति के आधार पर बने यह घटक (Units) राष्ट्रीय जीवन में जगमग अपनी ता मानते हैं और उनके प्रभाव में विधीन हो जाने से इनकार करने हैं। इतिहास मान्यता है कि यह मान्यता घटक अपनी स्वतन्त्र मता के लिए बराबर लड़ते जाएँ हैं। इतिहास के लिए, मुसलमानों का जन्म से हिन्दुओं ने अपनी मता बनाए रखने के लिए

बराबर भयर्प किया। इस स्वतन्त्रता गवाह के दिनों में राष्ट्रीय प्रवाह में अलग रह कर मुसलमानों ने 'मुस्लिम लीग' के नेतृत्व में चलकर अपने अस्तित्व की पृथक्ता को प्रधान लक्ष्य बनाया। जिन्ना माहूब ने तो 'द्विराष्ट्र का विद्वान्त' बना कर पाकिस्तान की माँग की। मुसलमानों को यह भय था कि स्वतन्त्र भारत में उनके धर्म, सम्प्रदाय तथा मस्जिद का नोच हो जाएगा। मिक्लो की सिद्धिस्तान की माँग और शक्ति जाति के लिए तमिलनाड की माँग उन ऐतिहासिक कारणों की देन है।

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। धर्म, सम्प्रदाय, जाति और मस्जिद के भेद, इस भारतीय इतिहास-काल के दौर में उत्तम वेगभासी नहीं है, जितना हम समझते हैं। यह राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता में उन्हें बाधक नहीं हैं जितना हम समझते हैं। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकता की बाधाएँ बुनियादी तौर पर दूरी हैं। इन ऐतिहासिक भेदों का उभारने की चेष्टा की जाती है। हमारे देश में गमन्य की प्रक्रिया के फलस्वरूप धर्म, सम्प्रदाय और जाति के भेद समाप्त हो नहीं हुए थे पर उनके बीच सह-अस्तित्व का भाव अवश्य पैदा हो गया था। दुर्भाग्य से अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और धर्मको की कूटनीति ने इन सह-अस्तित्व के भाव को नष्ट किया है। भेद उत्पन्न करके राज्य करने और विभिन्न श्वाइयो को एक दूसरे के विरुद्ध उठा कर खड़ा कर देने की राजनीति ने राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुँचायी है परन्तु हम 'कारण' को न देखकर परिणामों को देखते हैं। पुराने और निर्बल ऐतिहासिक भेदों की मजबूती है, इस राजनीति ने। यदि हम देश में धर्म, सम्प्रदाय, मस्जिद और जातियों के भेद इतने मजबूत थे, तो अंग्रेजों ने पहले यहाँ के लोगों में साम्प्रदायिक और भाषाई दंगे क्यों नहीं हुए? यूरोप में धर्मयुद्ध हुए हैं और एक धर्म के मानने वालों ने दूसरे धर्म के मानने वालों की जिंदा जलावा है। सम्प्र अंग्रेजों के दलों में यह सब हुआ परन्तु हमारे देश में नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि मजबूतकारी राष्ट्रीय प्रवृत्ति के कारण हम देश में धर्म-सम्प्रदाय-जाति के भेद निर्बल पड़ गए थे परन्तु उन भेदों का जानबूझ कर उभारा गया और बुझी हुई आग में घी डाला गया।

(३) राजनीति का खेल—हम पहले बता चुके हैं कि विदेशी शासन में भारतीय जनता में वर्तमान मौलिक एकता जो सह-अस्तित्व के रूप में प्रकट हो चुकी थी, उनके लिए एक खतरा थी जिसका आभास उन्हें सन् १९५७ के विद्रोह में मिला। तब से अंग्रेजों ने राजनीति का प्रयोग पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और जातियों के भेदों को उभारने में किया परन्तु कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता ने उन भेदों के सफेदों को नाकर आजादी प्राप्त कर ली। विदेशियों की वह राजनीति उनकी दृष्टि से उचित थी क्योंकि वे यहाँ की जनता का दोषण करना चाहते थे। आजादी के बाद 'राजनीति' का स्थान 'राजधर्म' का लेना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं हो पाया। दुर्भाग्य से और तत्काली शिक्षा के अभाव से यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय चेतना सबसे नहीं हो पाई और यहाँ के अनेक बर्ग ऐसे बन गए हैं, जो शासन को अपने हाथ में रख कर मनमाने

इस गंभीर उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह वर्ग राष्ट्रीय तथा भावनारमक प्रश्नों के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। यह वर्ग है राजनीतिक दल, गुटिया-गुटिया नौकरशाही, और पूँजीपति वर्ग। यह वर्गों वर्ग नष्ट हैं और यह धर्म, जाति, संस्कृति और सम्प्रदाय के भेदों से अनुप्राणित न होकर राज्य तथा, विशेष गुटिया और धन के आधार पर इन हैं और अपने स्वार्थ साधन के लिए पुराने ऐतिहासिक भेदों का सामान्य जनता में उभार कर अपना उन्मुक्त मोर्चा करना चाहते हैं। इन वर्गों में और इनके नेताओं में जाति, धर्म और संस्कृति की भिन्नता का कोई विचार नहीं। उदाहरण के लिए, नौकरशाही समझता है यद्यपि उनके सदस्य हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी हैं और विभिन्न संस्कृतियों के हैं। वास्तव में राजनीतिक दल है परन्तु उसमें सभी सम्प्रदायों और संस्कृतियों के लोग शामिल हैं। यह वर्ग निर्धार जनता के पुराने भेदों को उभार कर उन पर लागू करना चाहते हैं। यह राजधर्म नहीं, राजनीति का एक भ्रष्ट रूप है।

भारत में राष्ट्रीय तथा भावनारमक प्रश्नों का अभाव है- यह विचार सबसे पहले राजनीतिज्ञों की ही मूढ़ता। राष्ट्रीय जनता सम्मेलन का आयोजन नामक दल की ओर से हुआ। सभी राजनीतिक दलों ने इस सम्मेलन पर चिन्ता प्रकट की और बार-बार यही दल इसके लिए आकाश उड़ाने हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि अपने स्वार्थों के लिए यह दल राष्ट्रीय जनता पर बहुत बड़ा आघात पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राजनीतिक दल केवल एक सम्प्रदाय या संस्कृति-विशेष के आधार पर संगठित हैं और खुले आम प्राचीन ऐतिहासिक भेदों को उभारने का प्रयत्न करते हैं। कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं, जिनमें विभिन्न सम्प्रदायों, जातियों और धर्मों के लोग शामिल हैं परन्तु उन दलों के नेता चुनाव के समय साम्प्रदायिक और जातिगत भेदों के आधार पर बहुमत पाने का प्रयत्न करने हैं और वे जिन आदमों पर गये हैं, उन्हें भूल जाते हैं। यह राष्ट्रीय जनता पर आघात पहुँचाता है।

कार्ल मार्क्स के द्वारा बनाये गये वर्ग-संघर्ष को यदि हम ध्यान में रखें, तो भी सामान्य अनुभव यह बताता है कि एक प्रकार के स्वार्थों के आधार पर वर्ग तो बनते ही हैं। इस प्रकार के वर्ग हमारे देश में मढ़ा रहे हैं और अब भी हैं। उदाहरण के लिए, राज-महाराज और जमींदारों के वर्ग जिनकी पैतृक सम्पत्ति थी और जो हर प्रकार से सुसज्जित थे। वे मिलकर अपनी शक्ति राजनीति की सहायता से बनाये रखना चाहते थे। वे जाज्बो के पूर्व बराबर अंग्रेजों की सहायता करते थे और राष्ट्रभावना का विरोध। स्वतन्त्रता के बाद यह वर्ग नष्ट हो गए हैं परन्तु उनके स्थान पर पूँजीपति वर्ग और नौकरशाही वर्ग आ गया है। पूँजीपति वर्ग स्वार्थवश और धन के लिए सामान्य जनता का शोषण अनेक प्रकार से करता है और अपनी शक्ति बनाये रखने के लिए राजनीति में प्रवेश करता है। यही बात नौकरशाही पर भी घटित होती है। इन लोगों का संगठन विशेष गुटियाओं और पद के आधार पर बना हुआ है। यह लोग अपनी शक्ति बनाये रखने के लिए राजनीति का सहारा लेंगे



है। वे खुलकर सामने नई नई मकने परन्तु वे नये-नये उपायों में काम लेने हैं जिनका मध्ये में उल्लेख आवश्यक है।

(क) भाषाई विवाद—अब यह स्पष्ट हो चला है कि भाषाई विवाद के पीछे दलगत राजनीति है। केन्द्र के प्रशासन में जो नौकरशाही जमी हुई है, वह चाहती है कि उसकी मर्यादा ही जमी रहे। यह अभी सम्भव है जब अंग्रेजी बनी रहे क्योंकि यह निश्चय है कि सामान्य वर्ग के नवयुवक अंग्रेजी पर उनका अधिकार नहीं रख सकते जितना हिन्दी तथा अपनी मातृभाषाओं पर रखते हैं। अंग्रेजी रहती है तो प्रशासन में नये खून और नये वर्गों का प्रवेश सम्भव न होगा। इस प्रकार शिक्षा, सामरिक विश्वविद्यालय तथा तकनीकी विद्या के स्तर पर जो ऊँचे-ऊँचे वेतन पा रहे हैं और हर प्रकार की सुविधाएँ अंग्रेजी के माध्यम के रूप पर पा रहे हैं, वे हिन्दी के आ जाने में सकट में पड़ सकते हैं, और विरोध का जन्म इसी भावना में हुआ है।

(ख) क्षेत्रीयता—भाषा-विवाद की नीजता के कारण आजादी के बाद देश में भाषाई प्रान्त (राज्य) बना दिये गये। इसमें क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिला। यह प्रान्त भी राजनीति की देन हैं। हर भाषा क्षेत्र के लोग संगठित होकर अपनी शक्ति का बड़ाये रखना चाहते हैं। इसका एक नमूना 'द्विविधमुनेत्रकद्वयम्' दल है। वह केवल महान् राज्य तक सीमित है। भाषा और मस्तिष्क के आधार पर वह भाग में पृथक् अपना अस्तित्व समझता है। बंगाल और महाराष्ट्र के लोग अंग्रेजी के बल पर अंग्रेजी के शासन काल में प्रशासन के माध्यम में अपनी श्रेष्ठता बनाये हुए थे। यही दो क्षेत्र अब अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए भाषा के मोर्चे पर खड़े हुए हैं।

इन दोनों उदाहरणों में राजनीति के खेल का स्पष्टीकरण हो जाता है। उन हिन्दी का विरोध केवल 'स्वमातृभाषा' प्रेम के कारण नहीं है या त्रिविम्बान-तमिलनाडु की भांग केवल अपने क्षेत्र-विरोध के प्रेम के कारण नहीं है, बल्कि उनके पीछे उन वर्गों की राजनीति है, जो अपनी मता और शक्ति को किसी प्रकार बनाये रखना चाहते हैं। अस्तित्व-रक्षा के लिए मड़ना तो हर वर्ग के अधिकार है परन्तु जब केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर बलपूर्वक अधिकार जमाने की प्रवृत्ति हो और राष्ट्रीय चेतना के साथ मिलकर चलने की अम्बीवार करने की प्रवृत्ति हो, तो उसमें भावनात्मक एकता पर आघात पहुँचता है।

(ग) देश की बदली परिस्थितियों तथा मनोवृत्तियों का भय—आजादी प्राप्ति होने के बाद राष्ट्रीय चेतना के निर्बल होने का एक कारण यह था कि वह 'एकोद्देश्यता' (आजादी पाने का उद्देश्य) जो सब विभिन्न विभागों वाले लोगों को एक सूत्र में बाँधे हुए था, नष्ट हो गया। बायें दल की इस दृष्टि में उपयोगिता नष्ट हो गई परन्तु वह दल सामन्तवाद हुआ। यह दल देश को एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं दे सका। जिस लगन, त्याग और सेवा की भावना में प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई,

यह भावना एक दिशा में समान में हम जगमर्ग रहे और वह बिगड़ गई। हम जगमर्ग पर जल्दी यह था कि हम भावना के 'देन को पुनर्निर्माण' के मध्य की ओर मोड़ना था पर परिस्थितियाँ ने ऐसा नहीं होने दिया। वह परिस्थितियाँ क्या थीं ?

आजादी के बाद अधिकार मिले। यह अधिकार प्रागजन्म, धन, सुविधाएँ तथा मौकियों के रूप में थे। देन के निर्माण की ओर किसी का ध्यान नहीं गया और सब इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए जातुर हो उठे और इनके दिए दीना-भाटी प्रारम्भ हो गई। एक-दूसरे को निर्माण के प्रयत्न में फूट, घृणा और विरोध का भाव प्रबल हो गया जिससे राष्ट्रीय एकता पर चोट पहुँचना अवश्यमभाव्य था। यह एक ऐसी विरोध परिस्थिति है जिसने देन में विद्यावियों के आदर्शवादों, मजदूरों की हड़ताला, कर्मचारियों के उपद्रवों और असहयोग और भापाई दलों की जन्म दिया है। आज हर वर्ग की भूल बढ़ी है। जिन्हें कभी अधिकार, मुग और सुविधाएँ नहीं मिली थी, वे उन्हें पाने के लिए लड़ने लगे हैं और जो उन पर अधिकार जमा चुके हैं, वे अपने स्थान पर जमे रहकर महत्वाकांक्षी वर्ग में लड़ने पर जासूस है। इस मनोवैज्ञानिक स्थिति ने मध्य को जन्म दिया है।

अधिकार और सत्ता के मध्य में जो वर्ग सबल तथा बहुमत में होगा, उसमें कुछ वर्ग, आत्मविश्वास और आजा की भावना होती है। परन्तु जो अल्पमत में है, उसमें निराशा और भय का होता स्वाभाविक होता है। कभी बहुमत तथा सबल वर्ग के द्वारा पवित्र भी हो सकते हैं और कभी सारे अधिकार हथप जाने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। इसके विपरीत, अल्पमत तथा निर्बल वर्ग में यह भय नहीं हो सकता है कि कहीं उनका अहित न हो और कभी इस वर्ग में वनपूर्वक बहुमत वाले वर्ग पर वनपूर्वक सदे रहने की प्रवृत्ति हो सकती है। इस मनोवैज्ञानिक मध्य के मंदिर में राष्ट्रीय एकता की समस्या की समस्या आवश्यक है।

भारत में हिन्दू सम्प्रदाय का बहुमत है और प्रजातन्त्र में सभी सम्प्रदाय को अधिक लाभ मिलना स्वाभाविक है और न्याययुक्त भी है। दूसरी ओर मुसलमान, ईसाई और सिख सम्प्रदाय अल्पमत में हैं और अनुपात में इन्हें कम लाभ मिलना स्वाभाविक तथा न्याययुक्त है परन्तु इस स्थिति को कोई बड़ी समस्या पा रहा है। हिन्दू सम्प्रदाय धन की दृष्टि से अधिक सबल है और इसके कुछ उच्च स्तरीय वर्गों में सारी सुविधाएँ हड़पने की प्रवृत्ति है। और अगर यह प्रवृत्ति न हो तो भी वे अपनी ईमानदारी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर मुसलमान, ईसाई तथा सिख केवल एक शताब्दी पूर्ण पहले अल्पमत होने पर भी बहुमूल्य सम्प्रदाय पर राज्य कर चुके हैं और अब वे लड़ने में अधिक भाग की कामना करते हैं। उहे यह भय है कि कहीं वे बिल्कुल न मिट जायें। ऐसा भय कभी-कभी 'मिथ्या भय' का रूप ले लेता है, जो बड़ा घातक हो सकता है। मिथ्या भय जात्रामक होता है, मिटने के भय में अपने में सबल मनु को मिटा देने की प्रवृत्ति ने दक्षिण भारत में भापाई दंगे







विपक्ष है, हिन्दी को मद्रास में उम्लाड फेंकने के पीछे भयजनित आश्रामक प्रवृत्ति काम कर रही है।

श्री हुमायूँ कबीर ने अपने लेख 'राष्ट्रीय एकता का आधार' में अल्पमत वाले वर्गों के भय का विश्लेषण करते हुए उसका दबे स्वर में समर्थन किया है। वे कहते हैं—“कभी-कभी ऐसा लगता है कि विभिन्न भाषाई और क्षेत्रीय वर्ग इस एकता का विरोध कर रहे हैं, किन्तु हम यदि उनके रवियों का मायधानी से विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे कि वे एकता के विरोधी नहीं बल्कि अपनी पृथक् मता के मांग के विरोधी हैं। अल्प-संख्यक वर्ग आम तौर पर अपने पृथक् स्वल्प की रक्षा के लिए अधिक भवैश्वर्यशील और आसही है। यही भय भारत में ज्ञान के जमाने में भाषा के प्रश्न पर दिखाए गये भावनाओं के उग्र आदेश के पीछे भी था।”

अब अल्पसंख्यकों के भय विमूलित हैं या असन्नी, इसका निश्चय बड़ा कठिन है। हुमायूँ ने श्री हुमायूँ कबीर जैसे लोग इस प्रकार के भय को उचित समझते हैं। वे कहते हैं कि बहुमत वाले वर्ग के हित या दृष्टिकोण को सर्वोपरि नहीं समझा जा सकता क्योंकि वे इसे राष्ट्रीय रूप देने हैं जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग पर उनका प्रकाशान्तर में यह अभिव्यक्ति है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के पीछे, उसकी स्वायत्त वृत्ति है। यदि उसका यह दृष्टिकोण सही है, तो इस समस्या का क्या हल है? श्री कबीर यह भी नहीं कहते कि अंग्रेजी की स्थानापन्न रहनी चाहिए पर कोई मुझाव न देकर कहते हैं कि सभी भाषाओं को विकसित होने देना चाहिए। वे भाषा का सम्बन्ध धर्म और सभ्यता से जोड़कर यह तर्क देते हैं कि भाषा की स्वतन्त्रता जरूरी है। हर भाषा के विकास की गारंटी भविष्यतः देता है पर जहाँ 'मिश्रण' और 'आलस्य' हो, उसके दूर करने का और क्या उपाय हो सकता है? वास्तव में श्री कबीर राष्ट्रीय हित की न तो व्याख्या कर पाते हैं, जिस पर सभी वर्ग एकमत हो और न वे कोई हल दे पाते हैं। उनके पूरे लेख में जिस 'पृथक्त्व की भावना' की मजबूत हृदय में निन्दा है, उसी का अन्त में विभिन्न रूप में समर्थन है। इसका कारण शायद यह हो कि एक अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य होने के कारण राष्ट्रीय भावना में पूर्ण होने पर भी, उनके अचेतन मन में पृथक्त्व की दबी हुई भावना मौजूद रही है।

(५) पृथक्त्व की होड़—विभिन्न वर्गों के पृथक्त्व का प्रश्न राष्ट्रीय एकता की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। हमारा देश एक बहुत बड़ा वृत्त है जिसके भीतर असंख्य छोटे-छोटे वृत्त नाथ रहे हैं। इसका कारण हमारा 'व्यक्तिवादी' जीवन-दर्शन है। इस देश का हर व्यक्ति अपनी पृथक् सत्ता की अनुभूति करता है। इसलिए वह अगर अपने 'स्व' से आगे बढ़े, तो जानि तथा धर्म या परिवार के छोटे वृत्त में बन्दी बनकर रह जाता है। फिर यह 'वृत्त' या वर्ग अपनी स्वतन्त्र मता के लिए प्राण-पण के लड़ता है। यह समन्वय के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। हम जान-बूझकर अल्पसंख्यक राष्ट्रीयकरण श्री हुमायूँ कबीर ने किया है। उन्होंने बताया है कि हिन्दू सम्प्रदाय ने

अपना एक अलग गुण बना दिया और उस दायरे में हिन्दी अन्य सम्प्रदाय के सदस्य का प्रवेश मंजूर है। अपनी संस्कृति के साथ उनमें अन्य संस्कृतियों के सम्मिश्रण की क्षमता भी है। दूसरी ओर भारतीय मुसलमानों और ईसाइयों ने भी अपने संस्कृतित दायरे में निरन्तर एक भारतीयता की विज्ञापन धारा में स्थान बनने में दूसरा कर दिया और अब तक भी कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय सम्प्रदायों और लोगों को उस प्रकार नहीं स्वीकार दिया जिस प्रकार हिन्दुओं को मुसलमानों ने दिया था। इससे राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हो रही है। श्री हुमायूँ कबीर ने अपने एक लेख ('National Integration in India', Careers and Courses, Nov. 1961) में कहा है

"हमें भारतीय बहूत पसंद है, जो भारत की समस्त सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करते हैं, अधिकांश भारतीय ऐसा हैं जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के कुछ अंगों और परम्पराओं पर गर्व करने और उनमें प्रेरणा लेते हैं।"

यह बात हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई आदि सभी सम्प्रदायों के लिए एक कटु सत्य है और इस भावना में राष्ट्रीय एकता टुकड़ों में बँट गयी है।

(६) एक आर्थिक सवाल — इस समय राष्ट्रीय एकता में धर्म और जाति के तत्त्व इनके बाधक नहीं हैं, जिनका आर्थिक विषमताएँ। एक ओर तो भारतीय समाज आर्थिक रूप से अल्प देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। दूसरी ओर भारत में जो कुछ आर्थिक विकास की सुविधाएँ हैं, उनका समान रूप में वितरण नहीं है। श्री हुमायूँ कबीर ने आर्थिक विषमता की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक माना है। उनका कहना है कि यद्यपि भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक को अपने विकास की पूरी सुविधा मिलेगी परन्तु ऐसा हो नहीं रहा है। हर भारतीय नागरिक को यह विश्वास नहीं है कि उन्हें अपने मनचाहे स्तर तक उठने की सुविधा मिल सकेगी। इसका प्रमाण यह है कि हमारे अनेक सुशिक्षित नागरिकों को उपयुक्त वेतन नहीं मिल पाता। फिर उनके मामले कोई चारा नहीं रह जाता निवाय इसके कि वह धर्म, सम्प्रदाय और भाषा के नाम पर भगदड़ खड़ा करें और विशेष सुविधा या अधिकार की माँग करें। यह सब राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुँचाने में सहायक होता है।

अभी हाल के होने वाले भाषाई दंगे और विवाद की जड़ में यही आर्थिक प्रश्न काम कर रहा है। आज तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध केवल इसलिए है कि वहाँ के लोग अंग्रेजी में अच्छी प्रगति रखते हैं और विदेशी भाषा के चल पर केन्द्रीय शासन में वे जमे हुए हैं। अंग्रेजी जाने का अर्थ है उनकी रोजी का जाना। जब तक यह विश्वास न हो जाय कि हिन्दी के आने से उनकी आर्थिक समस्या हल हो जायगी, हिन्दी का विरोध करते रहेंगे। पेट की भूख प्रबल होने पर राष्ट्रहित भूल ही जायगा। तमिलनाडु तमिल का प्रेष न दिखाकर अंग्रेजी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं

क्योंकि तबिय भी उनकी आर्थिक बर्तनार्थ की इन नहीं कर सकती। इसी प्रकार आन्ध्र राज्य में इत्यादि के कारणों से भी अन्धप्रवासी होता है क्योंकि यदि वह आन्ध्रवासी किसी दूसरे राज्य में हो, तो आन्ध्रवासी को नौकरी या अवसर कम मिलेगा। महाराष्ट्र में 'शिवसेना' की उत्पत्ति इसीलिए हुई है कि वही उनके राज्य में दूसरे प्रदेशों के लोग अत्यन्त आर्थिक अवसर पा रहे हैं। उत्तर मुमयमान उद्ग के नाम पर समझि हो रहे हैं क्योंकि वे अपने को उत्तरीय अनुभव कर रहे हैं। इन मारे भारतीय बायो की जड़ में आर्थिक समस्याएँ हैं।

कारण में इन युग में उपर्युक्त मारी प्रगतिशीलता का विवेचन करना पूरी तरह सम्भव नहीं है क्योंकि इनमें बड़ी अतिवृत्ति है। मारी प्रगतिशीलता एक दूसरे में इस प्रकार जुड़ी है कि अलग-अलग उन्हें समझना बर्तन है। फिर भी हमने उन्हें यथा-सम्भव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।

## चारित्रिक सकट और राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों की व्याख्या हम कर चुके हैं परन्तु यदि अधिक गहराई में विचार करने देया जाय तो धर्म, जाति, भाषा, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भय और आर्थिक स्वार्थ के कारण राष्ट्रविघ्न का ध्यान न करने का मूल कारण है चरित्र की दुर्बलता। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ० गणधन्य मुक्तजी ने अपने एक लेख ('An Ethical Basis for Integration', *Careers and Courses*, अगस्त १९६४) में कहा है कि राष्ट्रीय एकता की समस्या मूलतः एक नैतिक समस्या है। जब किसी राष्ट्र के लोगों का चारित्रिक पतन हो जाता है और वे अपने धर्म स्वार्थों में ऊपर न उठ कर राष्ट्र की हित की हानि पहुँचाने लगते हैं तो समाज में भावनात्मक एकता नष्ट होने लगती है। यह बात कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो सकती है।

आज हमारे देश में उपयोग्य वस्तुओं का अभाव है। जीवन की अत्यन्त मौलिक आवश्यकताएँ, जैसे खाद्यान्न, वस्त्र और आवास भी हम एक को मुश्किल है परन्तु कुछ सुविधा-प्राप्त वर्ग जैसे पूँजीपति और अधिकारी वर्ग, किसी भी प्रकार में इन अभावों में परेशान नहीं है। इस वर्ग में चारित्रिक दुर्बलता के कारण ही स्वार्थ-परता है। वे अभावग्रस्त वर्गों के दुःखों का अनुभव नहीं करते हैं और वे अपने मुल की ही सर्वोपरि धारते हैं। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जन 'परदुस्वकर्त' (दूसरों के दुःखों से दुःखी होने वाला) होता है। इसी प्रकार एक उच्च पदाधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के चुनाव में अपने धर्म, जाति या भाषा का विचार करके ही अपने आदर्शों को नियुक्त करता है तो यह उसके चरित्र की दुर्बलता है। चरित्रवान अधिकारी वह है जो न्यायानुसार योग्य तथा पद के उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त करता है।

जब एक बड़ा वर्ग, जो बहुमतवर्क है, मार्मिक लोग पर चारित्रिक दोष का



शिकार बन जाना है तो निरंकुश हों जाना है और अन्य अल्प मन वाले समुदायों के हितों को नुचलने लगना है। उसमें दम और स्वार्थ प्रबल हों जाने हैं। यह भी चारित्रिक दुर्बलता का प्रमाण है। यदि चरित्र की उच्चता होगी तो उदारता और महिष्णुता के गुण होंगे। इसी प्रकार अल्पमन्यवों में भी चारित्रिक दोष हों सकते हैं। हमारे देश के अल्पमन्यवः रुढ़िवादियों और स्वार्थ में ग्रस्त हैं। यदि वे राष्ट्र की व्यापक विचारधारा में धर्म और संस्कृति की सुरक्षा की आवाज उठाकर अलग रहना चाहते हैं तो यह उनकी मनुचिन्तित मनोवृत्ति है। भारत में कई सम्प्रदाय इस दोष में मुक्त नहीं हैं। निर्वाचनों के समय अल्पमन के लोग धर्म और जाति के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार की चारित्रिक दुर्बलता अज्ञानता और स्वार्थ के कारण उत्पन्न हुई है। अधिकारीवर्ग को राष्ट्र के कोप से बेतन मिलना है परन्तु वे जनता के हित की उपेक्षा करके उत्कोच (बुल) प्रवृत्त कर लेते हैं और वे उन समाज-विरोधी मत्त्वों को खुली छूट दे देते हैं जो समाज का क्षोभ करते हैं। भारत में बोर-बाजारी, मद्रह और मुनाफाखोरी के कारण आम जनता बड़े कष्ट में है जिसके लिए अधिकारीवर्ग और व्यापारीवर्ग जिम्मेदार है। चरित्रहीनता के कारण यह दुर्गुण पैदा हो गए हैं और आम जनता का विश्वास इन पर से उठ गया है।

इन कुछ उदाहरणों ने स्पष्ट हो जायगा कि चारित्रिक संकट हमारे देश में वर्तमान है और हमारे देश के कुछ नेता इस संकट का अनुभव भी कर रहे हैं। यो तो चरित्र एक व्यापक गुण है परन्तु समझने की दृष्टि से उसकी कुछ विशेषताओं को सहज ही समझा जा सकता है। चरित्र के अन्तर्गत ईमानदारी, निस्वार्थभाव, त्याग, मया-प्रेम, निष्पक्षता, मन की दृढ़ता और कष्ट-सहन जैसे गुण आते हैं जिनके बिना मनुष्य चरित्रवान् नहीं कहला सकता। खेद की बात यह है कि हमारे देश में इन गुणों का सामान्य जनो में अभाव है। चरित्र की दृष्टि से हमारे देश में महान् पुरुष अवश्य हुए हैं परन्तु सामान्य जनता में इनकी कमी है। विचार करने में यह बात निश्चय ही आती है कि अतीत काल में भारत ने अपनी आजादी चरित्र-हीनता के दुर्गुण में लौई है। यहाँ के लोगो में चौरता का अभाव न था परन्तु मुद्दी भर विदेशी यहाँ आकर सबको पराजित कर गए। कारण यह था कि स्वाध, ईर्ष्या-द्वेष, दम और अन्याय के कारण एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग को गिराने का प्रयत्न करते थे और विदेशियों का स्वागत करते थे। गिबन्दर के आक्रमण में लेकर अंग्रेजों के आगमन तक हर बार यहाँ के चरित्रहीन लोगों ने स्वार्थजन विदेशियों को मने लगाया है। यह प्रवृत्ति आज भी वर्तमान है। पाकिस्तान और चीन के आक्रमणों के समय भारत के भीतर ही कुछ ऐसे लोग रहे हैं, जो सन्तुओं के प्रति महानुभूति रखते रहे थे और यह आशा रखते थे कि उन सन्तुओं की विजय में हमारा लाभ होगा, सामन्यता पर हमारा अधिकार हो जायगा। संक्षेप में यही चारित्रिक संकट है। हमें हर समय सचेत रहना है कि कहीं हमारे अपने भाई ही हमारे साथ विश्वासघात न करें। चारित्रिक समस्याओं के

कारण हम एक-दूसरे पर विद्वान नहीं करते जिसमें राष्ट्रीय एकता पर आधारित पहुँचना है।

## शिक्षा की जिम्मेदारी

भारत में इस समय एक गुरुत्वमानता है। राज्य के शासकों में गंगा और पुनिय की शक्ति है और यह व्यवस्थागत गाने भाग्यवागियों को एक मूल में बाँध कर रख सकते हैं। यह विचार धन प्रतिष्ठित ठीक नहीं है। एक नो धामनमूल राक्ष-नीतिशों के हाथ में होता है और प्रशासन में धामन दत्त बदलता रहता है। धामन प्रायः व्यवस्था में काम करता है। इसमें गाने जलना के हृदय में वह परिवर्तन नहीं कर पाता यद्यपि उनके हाथ में प्रचार के प्रयोग साधन हैं, जैसे फिल्म और रेडियो। प्राचीन काल में धर्म एकता का आधार था पर उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। समाज-सेवी संस्थाओं का आन्दोलनक ज्ञान आकाशी के बाद हुआ है। इसका एक प्रमाण भाग्य वैश्वक-समाज जैसी संस्था और भूदान आन्दोलन हैं। सामान्य जनता में इनके प्रति बहुत कम आकर्षण है। ऐसी हालत में हमारा ध्यान शिक्षा की ओर जाना है क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया में करोड़ों लोग स्वच्छता में लाभ उठाते हैं और उसमें प्रभावित होते हैं। वर्तमान काल में शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के उत्पन्न करने का उत्तम साधन बताया जा सकता है। इस सम्बन्ध में 'राष्ट्रीय एकता सम्मेलन' की रिपोर्ट में कुछ वाक्यों को उद्धरित करना उचित है—

"राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने में शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। चूँकि एकता की या राष्ट्रीय संघटन की समस्याएँ धूलक विभिन्न समूहों या समाज के बड़े अंगों के दृष्टिकोण में सम्बन्धित हैं और चूँकि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा की दृष्टिकोणों या अभिवृत्तियों (Attitudes) के बदलने या प्रभावित करने का दक्षिणाली साधन माना गया है इसलिए सम्मेलन के विचार में शिक्षा की प्रक्रिया और उसके गोपित रूप को अहाँ वह आवश्यक हो, प्रथम महत्त्व दिया जाना चाहिए।"

शिक्षा कहीं तक राष्ट्रीय एकता में सहायक हो सकती है, इस सम्बन्ध में विचार प्रकट करने हुए कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बेदर ने अपने एक लेख ('Process of National Integration, Careers and Courses, अप्रैल १९६४) में कहा है कि मनुष्य का मन अपने अतीत के सम्बन्ध की वृत्ति रखने के कारण छोटे-छोटे वृत्तों में कार्य करने का आदी हो गया है। चूँकि मनुष्य उन सीमित वृत्तों के मनुचित दायरे में घूमा करते हैं, वे व्यापकता और विनाशिता के एक अंग को ही देख पाते हैं। साथ ही उन छोटे वृत्त में भी व्यक्तिगत स्वार्थ का दृष्टिकोण प्रबल धन जाता है। दूसरी ओर प्रवृत्ति संबंधात्मक स्तर पर कार्य करनी है और परिणाम यह होता है कि वे छोटे वृत्त इस व्यापक वृत्त के विरोधी बन जाते हैं। इस तथ्य का अर्थ यह है कि भारत में अनेक सामाजिक वर्ग हैं और उनका अपना अलग-अलग इतिहास है। हर वर्ग अपने इतिहास की याद रखकर अपने छोटे दायरे में रह जाता है और



आयोजन किया। इसमें इस समस्या के आर्थिक पहलू पर विचार किया गया और राज-नीतिक दलों के लिए एक समान आचार संहिता (Code of Conduct) की आवश्यकता पर बल दिया गया। सन् १९६१ इस समस्या पर विचारों के आदान-प्रदान की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष ३१ मई में १ जून तक होने वाली राष्ट्रीय एकता समिति (National Integration Committee) की बैठक, ना० १० अगस्त में १० अगस्त तक होने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन, अक्टूबर १९६१ में ही होने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपति-सम्मेलन तथा मिनस्टर-अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रीय एकता सम्मेलन (National Integration Conference) में इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार किया गया। इन सबसे विघटनकारी प्रवृत्तियों जैसे जातिवाद, सम्प्रदायवाद, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषाई निष्ठा, सम्पत्तियों के भय तथा उच्च शिक्षाओं पर विस्तार में विचार-विमर्श किया गया। इन सब आयोजनों के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हो चला कि राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने में शिक्षा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। इन सभी समितियों और सम्मेलनों में जो शैक्षिक उपाय बताये गये, उनका उल्लेख हम नीचे कर रहे हैं।

### उपकुलपति सम्मेलन, अक्टूबर १९६१ में चर्चित शैक्षिक उपाय

१. अखिल भारतीय अभिवृत्ति तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करने के लिए हर विश्वविद्यालय अपने यहाँ भारत के विभिन्न भागों के छात्रों के कुछ प्रतिगत को अवश्य प्रवेश दे और उन्हें छात्रावास में रहने की सुविधाएँ प्रदान करे।
२. नागरिकशास्त्र, सामाजिक अध्ययन, इतिहास और भाषा के विषयों को पढ़ाने के लिए ऐसी पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जायें जिनमें उदात्तापूर्वक सारे देश की प्रवृत्तियों को स्थान मिले, यद्यपि ऐतिहासिक तथ्यों का बलिदान न किया जाय और एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश में श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति पैदा न हो। यह पुस्तकें प्राथमिक स्तर में लेकर उच्च स्तर तक पढ़ायी जायें।
३. विश्वविद्यालयों को साम्प्रदायिक रूप में 'विश्व' भावना में परिपूर्ण होना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालयों के साम्प्रदायिक रूप को प्रभावित किया जाय।
४. छात्र मधो को सम्पादक कर दिया जाय। इसमें छात्रों से फूट पैदा होती है। उनके स्थान पर वाद-विवाद तथा सांस्कृतिक कार्यों की प्रतिनिधिता चलायी जायें।
५. दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलें जायें और इसमें योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ हों। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो या हिन्दी।

उसके स्थापित करने का अर्थ बन जाता है। उसका राष्ट्र का एक स्वातन्त्र-विस्तृत दायरा है परन्तु यह इच्छे के अन्तर्गत है। उस दायरे में अन्तर्गत करने है। इसी में राष्ट्रीय एकता की समस्या पैदा होती है। यही ध्यान देने में है कि विरोधों और मिश्रणों को दूर करने का एकमात्र उपाय शिक्षा ही हो सकती है जिसके माध्यम से वे इन-अन पर इन विरोधों का गठन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय एकता पर विचार प्रकट करने हुए भी ह्यूमायूँ बबीर ने शिक्षा की भूमिका के सम्बन्ध में लिखा है "भारतीय राष्ट्रीयता का कर्मी-कर्मो विचारक गान्धी जी ने पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया है। उनका कारण यह है कि हम कोई भी औद्योगिक प्रणाली नहीं विकसित कर जिससे विभिन्न विचारों के अन्तर्गत स्थित प्राप्त कर सकें। भारत के विद्वत्विद्वानों को औद्योगिक आचार पर मन्त्रियों के मन्त्रियों के लिए एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति का काम करना पड़ा। आज हमारे पास भारत में प्राप्त करने वाले विभिन्न मतों के औद्योगिक विचारों का ही अभाव नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली जैसी बुनियादी आवश्यकता का अभाव है। इसके अभाव ही हमें यह कहना पड़ा कि बहुत से भारतीयों में आज भी प्रादेशिक, भाषाई या साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नज़र आता है।

इन सब बातों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से शिक्षा पर है क्योंकि यह दानिपूर्ण तथा धीरे धीरे में उन विरोधों को समाप्त कर सकती है जिससे विभिन्न दल अन्तर्गत के पूर्ण भाग में विभाजित हो चुका है। शिक्षा के माध्यम से उत्तम नागरिक पैदा किये जा सकते हैं जो पारिवारिक दुर्बलताओं में ऊपर उठ कर राष्ट्र की सेवा में प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसे चरित्रवान् नागरिक स्वयं एक मूल में आकर हो सकते हैं और एकतावाद का अनुभव कर सकते हैं। उनमें वर्तमान निस्वार्थभाव, लक्ष्यता, निष्ठा और ध्यान के गुण होंगे और उनके मन में मिश्रण-भाव नहीं होगा, उनमें आक्रामक और सौम्य प्रवृत्तियाँ नहीं होंगी और वे राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत प्रवाह में अपने को निमग्नित कर दते। शिक्षा मनुष्य के मन का सहकार करती है, उनमें वर्तमान धृष्टता को दूर करके उदारता, चिन्तन और महत्त्व का गुण पैदा करती है। इसलिए भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा का सबसे बड़ा अवसर है। यदि हमें प्राचीन भारत की समस्यव्यवस्था प्रकृति को पैदा करना है तो उसके लिए शिक्षा के अस्त का प्रयोग करना होगा। यह सब कैसे हो? इसके लिए बहुत से उपाय सुझाए गये हैं और योजनाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। इनका महत्त्व विवरण नीचे प्रस्तुत है।

### शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की अभिवृद्धि

देश की राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है—इस तथ्य की अनुभूति आज्ञा के १० वर्षों बाद होने लगी। मई १९५८ में विद्वत्विद्वानों के अनुदान आयोग ने 'राष्ट्रीय एकता' विषय पर एक उपनिषद् (Seminar) का

आयोजन किया। इसमें इस समस्या के आर्थिक पहलु पर विचार किया गया और राज-नीतिक दलों के लिए एक समान आचार संहिता (Code of Conduct) की आवश्यकता पर बल दिया गया। मई १९६१ इस समस्या पर विचारों के आदान-प्रदान की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष ३१ मई से १ जून तक होने वाली राष्ट्रीय एकता समिति (National Integration Committee) की बैठक, तारीख १० अगस्त से १२ अगस्त तक होने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन, अक्टूबर १९६१ में ही होने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपति-सम्मेलन तथा गिनम्बर-अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रीय एकता सम्मेलन (National Integration Conference) में इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार किया गया। इन सबमें विघटनकारी प्रवृत्तियों जैसे जातिवाद, सम्प्रदायवाद, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषाई निष्ठा, अल्पसङ्ख्यकों के भय तथा उचित सिवायकों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इन सब आयोजनों के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने में शिक्षा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। इन सभी मामलों और सम्मेलनों में जो मौखिक उपाय बताये गये, उनका उन्मुख हम नीचे कर रहे हैं।

### उपकुलपति सम्मेलन, अक्टूबर १९६१ में चर्चित शैक्षिक उपाय

१. अखिल भारतीय अभिवृत्ति तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करने के लिए हर विश्वविद्यालय अपने यहाँ भारत के विभिन्न भागों के छात्रों के कुछ प्रतिनात को अवश्य प्रवेश दे और उन्हें छात्रावास में रहने का सुविधाएँ प्रदान करे।
२. नागरिकतात्मक, सामाजिक अध्ययन, इतिहास और भाषा के विषयों को पढ़ाने के लिए ऐसी पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जायँ जिनमें उधारनापूर्वक सारे देश की प्रवृत्तियों को स्थान मिले, यद्यपि ऐतिहासिक तथ्यों का बलिदान न किया जायँ और एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति पैदा न हो। यह पुस्तकें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पढ़ायी जायँ।
३. विश्वविद्यालयों की वास्तविक रूप में 'विश्व' भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालयों के साम्प्रदायिक रूप को समाप्त किया जाय।
४. छात्र-सूचों को समाप्त कर दिया जाय। इसमें छात्रों से पूछ पैदा होनी है। उनके स्थान पर नाइ-विवाद तथा आस्तविक तथ्यों की निर्णयें चलायी जायँ।
५. दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जायँ और इनमें योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ हों। निशा का माध्यम अंग्रेजी हो या हिन्दी।

६. विश्वविद्यालयों को छात्रों में धार्मिक महत्त्व का गुण उत्पन्न करना चाहिए ।
७. देशीय की भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था विश्वविद्यालयों में की जाय ।

### राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा सुझाये गये उपाय

राज्य के शिक्षा मन्त्रियों का सम्मेलन इस समस्या पर विचार के लिए हुआ और उसने डा० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता समिति नियुक्त की । इस समिति ने राष्ट्रीय भावनात्मक एकता में शिक्षा के योगदान का निश्चय करने के लिए १००० लोगों की जिनमें विश्वविद्यालयों के उपकुलपति तथा विद्यालयों के प्रधानाचार्य शामिल थे, एक प्रश्नावली (Questionnaire) वितरित की । फिर उनका अध्ययन करके दिगम्बर १९६१ में अपना प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालय को भेजा । उसमें निम्न-लिखित सुझाव थे

१. राष्ट्रीय एकता को अज्ञानता में बढ़ावा मिलता है । इसलिए प्राथमिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाय । अनुसूचित और पिछड़ी जन-जातियों के लिए १० वर्ष तक शिक्षा की विशेष सुविधाएँ दी जायें । प्रति १० वर्ष बाद इस कार्य का मूल्यांकन करके सामाजिक गौर पर पिछड़े लोगों को विशेष सुविधा दी जाय ।
२. शिक्षा मन्त्रालयों में प्रवेश तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था संयोजन के आधार पर हो, जाति, धर्म और सम्प्रदाय का विचार न किया जाय ।
३. छात्रावासों में किसी एक वर्ग या जाति के लोग न रहे जायें और शिक्षा मन्त्रालयों के धार्मिक स्वरूप को बदल दिया जाय ।
४. प्रवेश के लिए निर्धारित प्राधनार्थियों में 'जाति' और 'धर्म' के बॉण्डों को निर्यात दिया जाय ।
५. हर राज्य में दूसरे राज्यों के छात्रों को बिना बाधा के प्रवेश दिया जाय । एक प्रदेश में जम्मू तथा निवाग की अवधि के विचार रखा दिये जायें ।
६. प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर भाषाई अल्प-महसुसों का उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा दी जाय ।
७. सामयिक शिक्षा आयोग द्वारा समन्वित निभाया गुण सर्वत्र लागू कर दिया जाय ।
८. भारतीय भाषाओं पर लक्ष्य करने के लिए एक अलग भारतीय भाषा मन्त्रालय स्थापित किया जाय जो सभी भाषाओं में सत्य लेखकों को एक बुनियादी सन्दर्भ (Basic Hindi) पर कार्य करे ।
९. भाषा व सामाजिक अन्तर्जन पर विशेषता द्वारा पुनर्जागरित जायें ।

१०. वर्ष में दो बार शिक्षा सत्वाओं के प्रधानों को छात्रों तथा अध्यापकों को एकत्र करके निम्नलिखित प्रतिज्ञा कर्त्वानी चाहिए

“भारत मेरा देश है। सभी भारतीय मेरे भाई और बहिन हैं। मैं अपने देश में प्रेम करता हूँ और मुझे इसकी सम्पन्न तथा विविधतापूर्ण संस्कृति पर गर्व है। मैं मेरा देश के योग्य बनने का प्रयत्न करता रहूँगा। मैं अपने माना-पिता, अध्यापकों तथा सभी गुरुजनों का सम्मान दूँगा और हर एक के साथ शिष्ट व्यवहार करूँगा। मैं पशुओं पर दया करूँगा। अपने देश और राष्ट्रवागियों के लिए मैं अपनी पूर्ण निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उनके मूल और उन्नति में ही मेरा मूल है।”

११. प्रतिदिन शिक्षा सत्वा का कार्य अध्यापकों, छात्रों और प्रधानाचार्य के सामूहिक एकत्र होने में कार्यक्रम हो। इस सभा में प्रधानाध्यापक मुख्य महापुरषों के जीवन और कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा करे और सभा का अन्त राष्ट्रमान में हो। राष्ट्रीय भण्डे और गीत की कहानी से सबको परिचित कराया जाय।

१२. छात्रों के लिए एक वस्त्र-विन्यास (Uniform), धास्तुतिक कार्यक्रमों, जैसे इतिहास के उत्तम अंशों पर आधारित नाटकों की व्यवस्था की जाय।

१३. इतिहास और भूगोल को अध्ययन का अनिवार्य विषय बना दिया जाय और इन पर लिखी पुस्तकों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करना हो।

१४. हार्टस्कूल तथा इण्टर में छात्रों के लिए जो हर राज्य के हों, एक ऐसा पुरस्कार रखा जाय जो उस छात्र को प्रदान किया जाय जो अपने राज्य के अनिरिक अन्य राज्य की संस्कृति पर सर्वश्रेष्ठ निदग्ध लिखे। इसका विषय किसी राज्य के लोगों की विशेषताएँ, अथवा योजना, सामाजिक प्रथा आदि हो।

इस समिति ने राष्ट्रीय संघटन (National Integration) शब्द को अनुपयुक्त

बनाया।

## ✓ राष्ट्रीय एकता सम्मेलन

२५० प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के आमन्त्रण पर २८ नवम्बर से १ अक्टूबर तक दिल्ली स्थित विज्ञान-भवन में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। १५३ प्रमुख शिक्षाविदों, विद्वानों, राजनीतिज्ञों और नागरिकों को बुलाया गया। जिसमें से केवल १३० उपस्थित हो सके। इसका उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने कहा—

“राष्ट्रीय एकता को ईंट और पत्थर, आगि और हथौड़े में नहीं तैयार किया





हों पर यदि अन्तरराष्ट्रीय सन्ध्यावली स्वीकार कर ली जाय तो माध्यम को घोष्य बदन दिया जाय ।

- ९ शिक्षा को समवर्ती (Concurrent) सूची में शामिल कर दिया जाय अर्थात् शिक्षा पर केन्द्र तथा राज्यों का समान अधिकार रहे । साथ ही अखिल भारतीय शिक्षा-मेला नाशु कर दी जाय ।
- १० एक राज्य के विदर्शविद्यालय दूसरे राज्य के छात्रों को प्रवेश दें और उन्हें छात्रवृत्तियाँ प्रदान करें ।
- ११ शिक्षा की उत्तमता, अनुशासन, महिष्णुता, उत्सर्गादिष्व की भावना तथा वर्तक्यवों का विकास करने के लिए शिक्षा का पुनर्गठन और न्य-परिवर्तन किया जाय । "शिक्षा का राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र का अंग होने का भाव विकसित करना चाहिए ताकि हमारे नवयुवक उत्तम नागरिक बन सकें । वेलेवर तथा विद्वत्सालुर्ण शिक्षा का समन्वय केवल एक उद्देश्य के लिए— भारतीयता का भाव उत्पन्न करने के लिए हो ।"
- १२ हर राज विद्यालयों का कार्य राष्ट्रमान के साथ प्रारम्भ हो ।

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण बात पर गौर किया जिसका उल्लेख आवश्यक है । उसने यह बताया कि अनेक शिक्षा राष्ट्रीय एकता के गम्भीर दादित्व को नहीं समझ सकती । शिक्षा की सफलता के लिए राजनीति और अर्थनीति का सहयोग मिलना चाहिए । इसलिए सम्मेलन में राजनीतिक दलों के लिए समान आधार गहिता बनाने, उनका पालन करने तथा उनके निरन्तर विकास करने पर ज़ोर दिया गया । साथ ही आर्थिक दृष्टि में सभी राज्यों के समान विकास की आवश्यकता भी बताया गयी । राष्ट्रीय एकता पर अधिक महर्गई से विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता कौमिल नियुक्त कर दो गई जिसके सदस्य प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री, राजनीतिक दलों के साथ नेता, कापेरा महामन्त्रा द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता समिति की अध्यक्ष श्रीमती पाथी, विदर्शविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, दो शिक्षाविद्, भाषाई अल्प-संख्यकों के आयुक्त आदि थे ।

### कुछ बिद्वज्जनों के विचार

(१) श्री हुमायूँ कबीर ने राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने के लिए स्कूलों में चलने वाले पाठ्यक्रम में सुधार को आवश्यक बताया है । उनके मत में यह पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो वर्गीय भेदों का उन्मूलन करे, जैसे स्कॉटलैन्ड में विभिन्न जातियों का सम्भव सम्भव हुआ है । भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान करने के लिए अनुवादों को लोकप्रिय बनाया जाय । फिल्मों के जरिए विभिन्न राज्यों की सस्कृतियों के विनिमय को सम्भव बनाया जाय । गृहस्थान्तों का उपयोग इन कार्य के लिए किया जाय । श्री कबीर का कहना है कि देश के औद्योगिक विकास में अनेक सुखवर पैदा हुए हैं परन्तु कुछ वर्ग शिक्षा के अभाव में उन अवसरों में लाभ नहीं

उठा गकने क्रिममे निराशा और सोम की भावना बढ़ती है। इसलिए उचित यह होगा कि सभी वर्गों की शिक्षा के समान अवसर मिलें और सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के शिक्षित जनों को स्थान दिया जाय।

राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने में, श्री हुमायूँ कबीर के भा सं, विद्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा है। भारत के विद्वविद्यालयों को कोई ऐसी बौद्धिक प्रणाली विकसिली चाहिए जिसमें विभिन्नपुर्ण विचारों को उद्धारतपुर्णक स्थान मिले। वे विभिन्न मसूतियों के मन्वेपन का काम कर सकने हैं। विद्वविद्यालयों के भीतर ऐसे मसूत कायम किये जायें जिसमें बिना धर्म या मसूति के भेद के छात्र शामिल हों, जैसे अन्वविद्यालय मुक्क समारोह। उक्क शिक्षा के छात्रों में एकोद्वेगता का भाव भी पैदा करना आवश्यक है, यह एक उद्देश्य है भावी भारत का निर्माण। विद्वविद्यालयों के छात्रों में स्थान की भावना का विकास कर देने में भी एका की समस्या हल हो सकती है। उनमें परस्पर सार्ज तथा स्वाभं के बा पर अवगरो में लाभ न उठाकर योग्यता के आधार पर ही लाभ उठाना चाहिए। इनमें सभी वर्गों के द्वेय समाप्त होंगे।

श्री हुमायूँ कबीर ने राष्ट्रीय एका के लिए 'सामयिकता की महत्त्वपूर्ण यता हल कहा है कि विद्वविद्यालयों को इन दिना में बहुत काम करना है। अन्नामर्षी विद्वविद्यालय के १९५६ के दीक्षा भागण में उन्होंने कहा था कि अतीत काय में भारत की पराजय ज्ञान की कमी के कारण हुई है। यहाँ के लोगों न जब भी ज्ञान विज्ञान का लका सोचा, सभी उक्त अपमानित शासक। इनके अनिरिक्त ज्ञान की कमी के कारण दण में पुन पड़ी। अब विद्वविद्यालय इन लोगों को मुख्य रूप में दो तरह दूर कर सक है। एक छात्रों में उद्धारता का भाव उत्पन्न करके यह काम किया जा सकता है। उद्धारता और मरिष्णुता के दुनों में युक्त छात्र स्वार्थी, धार्मिक, जाति और मजहब के छान्ने में बन्द न रह सकेंगे। आज का बहुरा और अगतन-लीकता हमारे देश में है उस लक करन का काम विद्वविद्यालयों का काम है। दुमरे, विद्वविद्यालय विज्ञान की उक्क शिक्षा देकर छात्रों में महत्त्वता, यस्कुतिता (Objectivity) और निष्पक्षता में विकास करने की लानि पैदा कर है। इनमें समय और शिक्षा विकास का मकन करने की सम्भावता बढ़ती है। अन्य विद्वविद्यालय महत्त्वता महत्त्वता की दृष्टिमें हम लक होती है। इनमें राष्ट्रीय एका का विकास हो सक मिलता।

(२) नुर्तुर्ब कस्टम मितायरी श्री हुमायूँ न अन्नामर्षी ने 'National Needs Educational Integration Careers and Courses, अगुस्त १९५६) में बताया है कि इन दण में अन्नामर्षी का भाव एक मात्र लीकमिष और म दूरा है, जैसे कि दुमलकयन का काम है। इस विज्ञान तथा शिक्षा के छात्र दूर किया जा सकता है। बताया है इन दण में दुर्विज्ञान लेन का बहुरा महत्त्वता नहीं, ली की। ५.३.५. अन्नामर्षी का अन्नामर्षी दुर्विज्ञान लेन और उद्धारतपुर्ण मरिष है।

सारारत भरत इतिहास लिखा। इसकी दो विशेषताएँ हैं—एक यह कि मुसलमान हिन्दुओं पर अत्याचार करते रहे और एक हजार वर्ष तक हिन्दू इसका प्रतिरोध करते रहे। दूसरे, उत्तर के सभी सम्राटों ने दक्षिण पर अपना साम्राज्यवादी अधिकार स्थापित करने की चेष्टा की। वास्तव में यह दृष्टिकोण अनुचित है। श्री हुमायूँ कबीर ने स्पष्ट कहा है कि मुसलमान धर्मको मे परस्पर बड़ी अधिक मुद्र हुए हैं, हिन्दुओं ने उनका इतना संघर्ष नहीं रहा। इसी प्रकार कई प्रसंगों में मुसलमानों ने हिन्दुओं के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ संघर्ष किया है। उदाहरण के लिए, हुमायूँ ने राजपूतों की महायुद्धा मातवा के मुसलमान शासक के विरुद्ध की या स्वयं मोहम्मद गौरी के भाई ने राजपूतों का साथ दिया था। अंग्रेजों द्वारा लिखे गये इतिहास में जान-बूझकर ऐसे तथ्यों की अवहेलना की गयी है ताकि हिन्दू-मुसलमानों में एकता का भाव पैदा न हो।

(३) प्रो० हबीब ने राष्ट्रीय एकता के लिए भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता बतायी है। अध्यापकों को छात्रों के समक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए। इस मद्द्दे में अशोक और अश्वरजस सम्राटों की महत्ता स्पष्ट करना आवश्यक है। साहित्य, धर्म और संस्कृति में वर्तमान ममत्व की प्रवृत्तियों को उभार कर लाया चाहिए। इतिहास में औरगजेय और शिवाजी के चरित्रों को साम्प्रदायिकता के रस में रंगकर प्रस्तुत करके उनके उद्देश्यों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसी प्रकार इतिहास में देश की कहानी के रूप में सभी प्रदेशों की महत्ता के सूत्रों को उपस्थित करके छात्रों के मन में सारे राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा करना चाहिए।

### भारतीय शिक्षा आयोग

डा० दीनानाथ कोटारी की अध्यक्षता में नियुक्त भारतीय शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता को पर्याप्त महत्त्व दिया है। उसके द्वारा १९६६ में प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया है कि देश की सामाजिक बनावट तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए भारत की एकता अत्यन्त आवश्यक है। इस कार्य में शिक्षा सहायक हो सकती है।

राष्ट्रीय एकता के कई तरंग हैं जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हैं और एकता का भाव उत्पन्न करने के लिए विभिन्नलिखित बातें आवश्यक हैं

(क) राष्ट्र के भविष्य में विश्वास।

(ख) सामान्य जनता के जीवन-स्तर में उन्नति, बेरोजगारी में कमी और देश के सभी भागों के विकास में असमानता में कमी ताकि हर एक को यह अनुभव हो कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में हमें समान अवसर प्राप्त हो रहा है।



‘समाज-सेवा’ का कार्य करें। आसानी से बाद उम्मा प्रवाह बहने लगा और बुद्धिवादी वर्ग युव सेवा कार्य में विरक्त हो रहा है। इन प्रवृत्ति की नीवना चाहिए।

छात्रों में सेवा की भावना बढ़ाने के लिए शिक्षाविद् का ध्यान कुछ दिशाओं की ओर गया किसे शिक्षा का अंग बनाने का निश्चय हुआ। ॥॥ सेवाएँ दो प्रकार की हो सकती हैं, एक वे जो कर्मी-कर्मिणी तब वर्ष में और केवल दिन के कुछ भाग में समायी जा सकती हैं और दूसरी वे हैं जो सम्पूर्ण शिक्षाक्रम में स्थान हो और निरन्तर चलती रहें। इन विचार पर सर्वप्रथम श्री सी० डी० दत्तमूल की अध्यक्षता में नियुक्त एक राष्ट्रीय सेवा समिति (National Service Committee) में विचार किया। विचारविमोचन में अध्यक्षता की जाने वाली अध्यक्षता में प्रवेश करने के पत्रों द्वारा प्राप्त के लिए समग्र १ वर्ष का सेवा-कार्यक्रम संसार दिया गया परन्तु यह लोचनीय न हो सका। बाद में एक ० सी० सी० का विचार आया। शिक्षा-संस्थानों में विभिन्न ऐसी जैसे युगोन्मादविद्या, भौतिकशास्त्रविद्या, प्रसंगी, ज्ञान, संयुक्त राज्य प्रसंगी, दृष्टिकोण, स्थिति तथा मार्ग में प्रचलित छात्रों की सेवाओं का अध्ययन किया और एक नियोई (National Service for Youth) प्रस्तावित की। इन नियोई में यह कहा गया कि यह सेवाएँ लक्ष्य हैं और विविध प्रकार की हैं। इन सेवाओं की मात्र पाठ्यक्रम सामाजिक तथा उच्च स्तर पर जारी रखने की आवश्यकता थी।

इन राष्ट्रीय सेवाओं के कई रूप हैं, जैसे छात्रों को एक गांव शिक्षायात्री ॥॥ वर्ष में रहकर गांव काम करना (ज्ञान की धारि)। इसमें सामाजिक जीवन बिना के आश्वासन होगा। दूसरी सेवा सामुदायिक विकास में भाग लेने की हो सकती है। प्रतिवर्ष १० दिन छात्रों में बाहर छात्रों में सफल, अथवा वर्ष, समाज-सेवा कार्य इसके अंग होते। ० सी० सी० सी० सभी छात्रों के लिए एक सेवा के रूप में होती ताकि कुछ का काम केवल एक विशेष वर्ष तक ही न सीमित रहें।

इन सेवाओं में छात्रों में अहं का भाव नष्ट होना और वे गांव देश की अपना देश समझेंगे। सामाजिक अध्ययन दूर होगा। इसमें राष्ट्रीय नवजागरण का भाव पुष्ट होगा। शिक्षा प्राचीन ने इन सेवाओं की इमीति आवश्यक बताया।

(३) भाषा नीति का विचार - भारत में भाषा का प्रश्न अत्यन्त भावनात्मक बन गया ॥॥ कई बार भाषाई दंगे हो चुके हैं। अभी तक यह नहीं मथ हो पाया कि शिक्षा में भाषाओं की पुराई की क्या व्यवस्था हो। इसमें राष्ट्र में घुट उत्पन्न हो रही है। भाषा का प्रश्न राजनीति के साथ उत्पन्न गया है। अतः शिक्षा आयोग ने भाषा नीति स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इस नीति के मुख्य अंग यह हैं (क) वर्तमान भारतीय भाषाओं का समान विकास किया जाय ताकि प्राथमिक तथा औद्योगिक ज्ञान हर एक को समान रूप में प्राप्त हो सके। शिक्षा का माध्यम हर स्तर पर सामुदायिक हो जैसा कि स्थितिनाथ ठाकुर तथा महात्मा गांधी ने कहा था। अंग्रेजी के माध्यम में एक वर्ष चल गया है जो सामान्य जनता में अनर्थ रहता है और



१३. भारत में कुछ ऐसी सामयिक घटनाएँ हो रही हैं जो एकता को नष्ट करने वाली हैं, जैसे भापाई विवाद, क्षेत्रीय विवाद और साम्प्रदायिक भेद आदि। अध्यापक को इन विवादों का बौद्धिक विश्लेषण करके, इनसे सम्बन्धित उभरी तथा उत्तेजित भावना को कम करना चाहिए।
१४. विद्यालय-भवन तथा कक्षा को ऐसे चित्रों से सजाया जाय, जो देश के गौरव का भाव जगाती हों। विभिन्न राज्यों के महापुरुषों के चित्र तथा वहाँ होने वाले विकास कार्यों के चित्र लगाना उपयोगी रहेगा।
१५. शिक्षण की व्यक्तित्ववादी पद्धति के स्थान पर सामूहिक शिक्षण का प्रयोग किया जाय, जैसे छोटे-छोटे समूहों में बैठकर छात्रों द्वारा विचार-विमर्श और विचारों का आदान-प्रदान, प्रोजेक्ट्स, कर्मदाना और उपनिषद् आदि।

## राज्य का दायित्व

कुछ कार्य ऐसे हैं, जिन्हें सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कर सकती है और जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में गंवायता पहुँचा सकते हैं। इनके निम्नी समस्याओं पर छोड़ना उचित नहीं है। उदाहरण के लिए, हमारे देश में अनेक साम्प्रदायिक विद्यालय हैं, इनके स्वरूप तथा वित्तपोषण को बदलना सरकार की जिम्मेवारी है। सारे देश में देश की एक-समान प्रणाली चलनी चाहिए। भारतीय शिक्षा-अयोग की समुक्ति को सामान्य विद्यालय के सम्बन्ध में दी गयी है, अविलम्ब स्वीकार की जाय। सारे देश में अध्यापकों के वेतन-क्रम एक-समान हो। अब तक वेतन के आधार पर अध्यापकों में जाति प्रथा चलती है, उनमें राष्ट्रीय भावना नहीं पैदा होगी और इसका प्रभाव छात्रों पर पड़ता रहेगा। एक-समान देशव्यापी नियुक्ति-स्तर रखने के लिए राष्ट्रपत्रों का भी पुनर्गठन करना आवश्यक है। छात्रों के लिए एक ही पोशाक हो और हर विद्यालय में राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रगान और मणिधान के प्रति मतभ्रमक होना हर छात्र का अनिवार्य कर्तव्य माना जाय। सारे देश के लिए सरकार एक अग्रिम भारतीय शिक्षा सेवा (All India Educational Service) चलाती जाय। भेद है कि सरकार उसी प्रकार रहता से काम नहीं ले रही है, जैसे भापा-विवाद के सम्बन्ध में हुआ है। सरकार की रहना की कमी में भी एकता की समस्या पैदा हुई है।

राज्य के शिक्षा विभागों में बड़े दोष हैं। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग में फाइलो में उलझे रहने और मिथ्याचरण की आदतें पड़ गयी हैं। बहुत-नी उत्तम योजनाओं को धनाने में वे असमर्थ रहते हैं क्योंकि उनमें नेतृत्व के गुणों का सर्वथा अभाव होता है। वे अध्यापकों के प्रति 'नौकरों' जैसा व्यवहार करते हैं और





१३. भारत में कुछ ऐसी सामयिक घटनाएँ हो रही हैं जो एकता को नष्ट करने वाली हैं, जैसे भापाई विवाद, क्षेत्रीय विवाद और साम्प्रदायिक भेद आदि। अध्यापक को इन विवादों का बौद्धिक विश्लेषण करके, इनमें सम्बन्धित उभरी तथा उत्तेजित भावना को कम करना चाहिए।
१४. विद्वान्-मंडल तथा कक्षा को ऐसे विषयों में मजबूत किया जाय, जो देश के गौरव का भाव जगाती हैं। विभिन्न राज्यों के महापुरुषों के चित्र तथा वहाँ होने वाले विज्ञान कार्यों के चित्र लगाना उपयोगी रहेगा।
१५. शिक्षण की व्यक्तिवादी पद्धति के स्थान पर सामूहिक शिक्षण का प्रयोग किया जाय, जैसे छोटे-छोटे समूहों में बैठकर छात्रों द्वारा विचार-विमर्श और विचारों का आदान-प्रदान, कोष्ठियाँ, कर्मस्थान और उपनिषद् आदि।

## राज्य का दायित्व

कुछ कार्य ऐसे हैं, जिन्हें सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कर सकती है और जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सहायता पहुँचा सकते हैं। इन्हें निम्नी समस्याओं पर छोड़ना उचित नहीं है। उदाहरण के लिए, हमारे देश में अनेक साम्प्रदायिक विद्यालय हैं, इनके स्वयं तथा वित्तपोषण का अद्वयन सरकार की जिम्मेवारी है। सारे देश में शिक्षा की एक-समान प्रणाली चलनी चाहिए। भारतीय शिक्षा-आयोग की समिति जो सामान्य विद्यालय के सम्बन्ध में दी गयी है, अविनम्य स्वीकार की जाय। सारे देश में अध्यापकों के वेतन-भ्रम एक-समान हो। जब तक वेतन के आधार पर अध्यापकों में जाति प्रथा चलती है, उनमें राष्ट्रीय भावना नहीं पैदा होगी और इसका प्रभाव छात्रों पर पड़ना रहेगा। एक-समान देशव्यापी शिक्षण-स्तर रखने के लिए पाठ्यक्रम का भी पुनर्संरचना करना आवश्यक है। छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम हो और हर विद्यालय में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान और गविधान के प्रति मनमत्तक होना हर छात्र का अनिवार्य कर्तव्य माना जाय। सारे देश के लिए सरकार एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा (All India Educational Service) धरायी जाय। यह है कि सरकार उसी प्रकार दृष्टा से काम नहीं ले रही है, जैसे भाषा-विवाद के सम्बन्ध में हुआ है। सरकार की दृष्टा की कमी से भी एकता की समस्या पैदा हुई है।

राज्य के शिक्षा विभागों में बड़े दोष हैं। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग में फाटली में उलझे रहने और मिथ्याचरण की आदतें पड़ गयी हैं। बहुत-सी उत्तम योजनाओं को चलाने में वे असमर्थ रहते हैं क्योंकि उनमें नेतृत्व के गुणों का सर्वथा अभाव होता है। वे अध्यापकों के प्रति 'नौकरों' जैसा व्यवहार करते हैं और



Suggest some positive educational programmes to strengthen them and to ward off the tendencies which come in the way of their development (1962)

2 Was India one ?

Is India one ?

Shall India be one ?

What do you mean by India ?

Give reasons for your belief and show what you can do as a teacher to serve India in the best possible way by shaping the patriotic sentiments of your students (1963)

3 Is there a 'crisis of character' today in India ? Support your view with reasons and suggest educational measures to remedy the evil if it exists. (1964)



में मगाई है, उसके अनुकूल यहाँ की सांस्कृतिक भूमि ठहरती नहीं। इसी से इस प्रणाली ने एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया है जिसके कुछ लक्षण वन २० वर्षों में होने वाले छात्र-आन्दोलन और भाषाई विवाद में देखने को मिलते हैं। यदि इन समस्याओं को हल करना है तो वर्तमान भारतीय शिक्षा-प्रणाली के मूल को बल पहुँचाने वाली पाश्चात्य शैक्षिक विचारधाराओं को अच्छी तरह समझना होगा। उन विचारों को राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के स्वर्ध में, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जड़ित करना होगा। यह इसलिए आवश्यक है कि भारतीय संस्कृति की धारा में यह पाश्चात्य शिक्षा परम्परा धुल-मिल नहीं पा रही है। यही शिक्षा के क्षेत्र में बेचैनी का कारण है।

### पाश्चात्य शैक्षिक विचारधारा की निरन्तरता

बहुत प्राचीन काल में पश्चिम में शैक्षिक चिन्तन का क्रम चलता आया है। यूनानी सभ्यता के दौर में स्पार्टा और एथेन्स के नगर-राज्यों में नवयुवकों की शिक्षा को व्यावहारिक बनाने का प्रयत्न हुआ। यह परम्परा वर्तमान काल में इटली, जर्मनी और जापान के तानाशाहों ने फिर से ज़िन्दा की जिसके फलस्वरूप विश्वयुद्ध हुए। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिकों—सुकरास, प्लेटो और अरस्तू—ने ज्ञान-विज्ञान प्रदान शिक्षा को समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक बनाया और उसकी स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। रोमन काल में शैक्षिक चिन्तन की विचार-प्रधान परम्परा लुप्त हो गयी परन्तु ईसाई धर्म प्रचारकों ने शिक्षा की अमूल्य शक्ति का उपयोग धर्म-प्रचार के लिए किया। फिर भी शिक्षा का चिन्तन करने वाले स्वतन्त्र रूप से भी अपने विचार प्रस्तुत करते रहे जिनमें एनेस्थस, अबेलार्ड, मैगलस, ऐंकीनास आदि प्रमुख हैं।

ज्ञान के पुनरोदय से यूरोप में शिक्षा के चिन्तन में नया मोड़ आया। मानवतावाद का व्यापक प्रभाव शिक्षा पर पड़ा। इसमें उदार तथा साहित्य प्रधान शिक्षा की विचारधारा बनपी जिसके आधार-स्तम्भ हैं, इरास्मस, रोजर ऐसस, इनिगट आदि। ज्ञान के पुनरोदय में ईसाई धर्म सुधारवादी आन्दोलन के धक्के खाकर बड़ी उबल-पुपल के दौर में गुँजरने लगा।

रखता है। मुख्य

दिया। ३

अथवा

१. विवेकता

२. पर जोर

३. शिक्षा में

कट किये।

उत्तर हुआ जब

१. ३ मुख्य रूप से

अभिप्रेत हो है।

२. और ठेकी

३. जाने-बिज-य-



'प्रकृति की ओर वापसी' एक अद्भुत विचार है और इसे समझने में प्रायः भ्रम हो जाता है। बहुत से लोग यह समझ बैठते हैं कि हमें सम्राज-विरोधी या और वह मनुष्य की उस दशा को पार करना था जिसमें वह नंगा और भूखा, पशुओं की भाँति जंगलों और घाटियों में मारा-मारा घूमना पड़ा था। ऐसी बात नहीं है। इसका मूल्य न था कि वह मनुष्य को सामाजिक प्राणी न मानता हो। वह केवल उस 'समाज' का विरोधी था, जिसे उसने पेरिस में देखा था और जिसमें मिथ्या आदम्बर, झूठता, शोषण, अनाचार और स्वार्थपन के अवशेष थे। उसका स्पष्ट मत था कि अच्छी शिक्षा में ऐसा समाज बाधक है क्योंकि ऐसे सामाजिक परिवेश में मनुष्य 'मनुष्य' नहीं बन सकता। ऐसे समाज में रहने से बेहतर यह है कि महाशय, जंगलों और नहरों के बीच बसावरण में बंधों को छोड़ दिया जाय ताकि उनके भीतर वर्तमान भौतिक तत्त्व लट न हों।

हमों ने विचार है कि आदर्श शिक्षा तब हो सकती है जब मनुष्य, प्रकृति और विभिन्न वस्तुओं के सामंजस्य की स्थिति में खड़े रहें। इसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य की महत्त्व शक्तियों, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बीच ताल-मेल होता है तो शिक्षा उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है, परन्तु दुर्भाग्य से मनुष्य की महत्त्व शक्तियों और सामाजिक वातावरण में विरोध होता है और समाज मनुष्य की प्रकृत शक्ति को लट करने का प्रयास करता है। इसलिए हमों की विषय होकर 'प्रकृति की ओर वापसी' का निर्णय लेना पड़ा। यदि समाज मनुष्य का विरोध करे, तो 'समाज' को लट होना चाहिए। हाँ, यदि प्रकृति समाज हो अर्थात् समाज उसी नियमों के अनुसार चले जो प्रकृति में चलते हैं, तो ऐसा समाज शिक्षा की दृष्टि में उपयोगी है, चट्टी समाज ऐसा होता क्यों है ?

'प्रकृति की ओर वापसी' के मूल का एक दूसरा अर्थ भी है। प्रकृति अर्थात् मानव प्रकृति का शिक्षा में स्थान रखा जाय। मानव प्रकृति महत्त्व रूप में भावना-प्रधान है। इसलिए बालकों की भावना को शिक्षा के माध्यम में उत्पन्न करना चाहिए, बुद्धिवादी और तार्किक होना एक बनावटीपन है। दुर्भाग्य से शिक्षा में बुद्धिवाद की प्रधानता है। इसी बुद्धिवाद की दृष्टिमता में शिक्षा को मुक्त रखने का समर्थन करता है। मनुष्य की प्रकृति उसकी मूल प्रकृतियों और आवश्यकताओं के मिश्रण में बनी है परन्तु हमों ने देखा कि बच्चों की मूल प्रकृतियों और महत्त्व आवश्यकताओं की अवहेलना शिक्षा में होती है। 'प्रकृति की ओर वापसी' का तात्पर्य यही है कि बच्चों की महत्त्व आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से की जाय और उनका दमन न करके उन्हें प्रशुद्धि होने दिया जाय।

हमों ने इस विचार के प्रति बहुत से लोग आकृष्ट हो गए। अद्वैती बौद्ध बौद्धधर्म ने तो स्वयं चट्टी जीवन में लट कर जीनों के प्रदेय में जाकर रहना प्रारम्भ कर दिया। हमें अपनी कविताओं जैसे 'साहचर्य' में चट्टी जीवन की भ्रष्टता और



(२) प्रहृति की ओर बाधनी—अभी यह सुनाई न गिशा-बिनास। का यह था कि गिशा का टाकींग मनुष्य की भाव और सुमार्जन बनाने का विना बिना जाना चाहिए। कभी ने इसमें अनुभव बिना कि मनुष्य और सुमार्जन बनाने वाली गिशा की बाधनी में गिशा मनुष्य का जीवन-व्यवस्था में है। प्रहृति ने मनुष्य की दृष्टि और सुमार्जन बनाया है। परन्तु गिशा के माध्यम में मनुष्य ने उनकी व्यवस्था और सुमार्जन का अर्थ बनाने का विना है। कभी न बता कि गिशा, विज्ञान, मनुष्य और कला के माध्यमों द्वारा मनुष्य की-साध बनाया है। यह 'मनुष्य' विज्ञान, सुमार्जन, विज्ञान, शोधक और मनुष्यारी जनों की प्रधानता है। गरी सुमार्जन की जड़ है। इसलिए उम्मेद हम 'मनुष्य' के हाथ में गिशा की गति का जीवन में का मनुष्य बिना और बता कि मनुष्य की प्रहृति की ओर बाधनी जाना चाहिए और गिशा का काम प्रहृति की ही गति देना चाहिए। 'एमीन' में हम न इसी बात की व्यवस्था है।

‘प्रकृति की ओर वापसी’ एक अद्भुत विचार है और इसे समझने में प्रायः भ्रम हो जाता है। बहुतों में सोच यह समझ बैठती है कि हमें समाज-विरोधी था और वह मनुष्य की उस दशा को पसंद करता था जिसमें वह नंगा और भूखा, पशुओं की भाँति जंगलों और घाटियों में घात-भाग घूमा करता था। ऐसी बात नहीं है। इतना भ्रम न था कि वह मनुष्य को सामाजिक प्राणी न मानता हो। वह केवल उस ‘समाज’ का विरोधी था, जिसे उसने पेंथ में देखा था और जिसमें मिथ्या आडम्बर, क्रूरता, शोषण, अनाचार और स्वार्थपरता के अवशेष थे। उसका स्पष्ट मत था कि अच्छी शिक्षा में ऐसा समाज बाधक है क्योंकि ऐसे सामाजिक परिवेश में मनुष्य ‘मनुष्य’ नहीं बन सकता। ऐसे समाज में रहने में बेहतर यह है कि पहाड़ों, जंगलों और नदियों के बीच वातावरण में बच्चों को छोड़ दिया जाय ताकि उनके भीतर वर्तमान नैसर्गिक तरंग नष्ट न हों।

हमने जितना है कि आदर्श शिक्षा तब हो सकती है जब मनुष्य, प्रकृति और विभिन्न वस्तुओं के सामग्र्य की स्थिति के बीच रहे। हमका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य की सहज शक्तियों, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बीच ताल-मेल होता है तो शिक्षा उत्तम प्रभाव उत्पन्न करती है, परन्तु दुर्भाग्य में मनुष्य की सहज शक्तियों और सामाजिक वातावरण में विरोध होता है और समाज मनुष्य की सहज शक्ति को मल्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए हमें को विचार होकर ‘प्रकृति की ओर वापसी’ का निर्णय लेना पड़ा। यदि समाज मनुष्य का विरोध करे, तो ‘समाज’ को मल्ट होना चाहिए। हाँ, यदि सहज समाज हो अर्थात् समाज उन्हीं नियमों के अनुसार चले जो प्रकृति में चलते हैं, तो ऐसा समाज शिक्षा की दृष्टि में उपयोगी है, सहज समाज ऐसा होता कहाँ है ?

‘प्रकृति की ओर वापसी’ के मूल का एक दूसरा अर्थ भी है। प्रकृति अर्थात् मानव प्रकृति का शिक्षा में ध्यान रखा जाय। मानव प्रकृति सहज रूप से भावना-प्रधान है। इसलिए बालकों की भावना को शिक्षा के माध्यम से उत्प्रेरित करना चाहिए, बुद्धिवादी और तार्किक होना एक बनावटीपन है। दुर्भाग्य में शिक्षा में बुद्धिवाद की प्रधानता है। हमें बुद्धिवाद की कृत्रिमता में शिक्षा को मुक्त रखने का समर्थन करना है। मनुष्य की प्रकृति उसकी मूल प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं के मिश्रण में बनी है परन्तु हमने देखा कि बच्चों की मूल प्रवृत्तियों और सहज आवश्यकताओं की अवहेलना शिक्षा में होती है। ‘प्रकृति की ओर वापसी’ का तात्पर्य यही है कि बच्चों की सहज आवश्यकताओं की पूर्ण शिक्षा के माध्यम में की जाय और उनका दमन न करके उन्हें प्रस्तुत होने दिया जाय।

हमने के इस विचार के प्रति बहुतों में योग आकृष्ट हो गए। अंग्रेजी बलि कई वर्षों में तो स्वयं सहज जीवन से हट कर भीनों के प्रदेश में जाकर रहना प्रारम्भ कर दिया। उसने अपनी बलिताओं जैसे ‘माइकेल’ में सहज जीवन की भ्रष्टता और



कि बच्चों के विकास के मोमानों के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए। जन्म में लेकर बचपनावस्था तक पहुँचने के क्रम को हमने चार मुख्य मोमानों में बाँटा है। वे हैं—प्राथमिककाल, बाल्यकाल, बाल्यांतरकाल और विमोक्षणकाल। इन मोमानों पर चढ़ने हुए बालक का जैसा विकास होता है, उस विकास की प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा देने का उगने पूरा विवरण प्रस्तुत किया है जिस पर हम प्रसमवश प्रकाश डालेंगे। उसने यह बताया है कि शिक्षा के लिए एक निर्धारित 'समय' होता है। यहाँ 'समय' का अर्थ यह है कि जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप में तैयार हो, तभी शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों ने बहुत पहले 'विकासमूलक मनोविज्ञान' के सूत्र तथ्यों, जैसे प्रौढ़ता (Maturation) तथा धानडाहक के मुख्य सिद्धान्त 'प्रस्तुतता' (Readiness) का पूर्ण गहने दे दिया था।

निषेधात्मक शिक्षा—मनुष्य के विकास के प्रारम्भिक चरण में जिस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है, उसे निषेधात्मक शिक्षा (Negative Education) कहते हैं। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ समझ में आना आवश्यक है, अन्यथा हम सम्बन्ध में भ्रम हो सकता है। 'निषेधात्मक शिक्षा' का अर्थ यह नहीं है कि बालकों को शैक्षिक प्रभावों से बचाने के लिए शिक्षा दी न दी जाय। शिक्षा तो दी जानी चाहिए यदि मनुष्य को मनुष्य बनने में मनुष्य बनाना है। हमने 'स्वतन्त्रता' का हर प्रकार में समर्थन किया है। वह कहना है कि सत्ता में सबसे उत्तम चीज 'शक्ति' नहीं, स्वतन्त्रता है। 'स्वतन्त्र' मनुष्य वही है, जो उन्हीं बातों की इच्छा करता है जिन्हें पूरा करने की शक्ति रखता है और वह वे ही बातें करता है जिनकी वह इच्छा करता है।

कुर्माय में इस प्रकार की स्वतन्त्रता का भाव पुराने संघ की शिक्षा में नहीं पाया होता। पुरानी शिक्षा दमन प्रधान होती है और वह मनुष्य की इच्छाओं को ही नष्ट करती है, तब 'स्वतन्त्रता' का अनुभव कोई अर्थ नहीं रखता। अब उस पुरानी शिक्षा के स्थान पर बच्चों निषेधात्मक शिक्षा की रूपरेखा निश्चित करता है। इस शिक्षा का सीधा-आधा फल यह है कि बच्चों की मत्त या उत्तम सिद्धान्तों की शिक्षा में देकर, केवल उनके मन की बुराइयों और मस्तिष्क को भ्रमों में बसाया जाय। इसमें उनकी स्वतन्त्रता बनी रहेगी।

निषेधात्मक शिक्षा द्वारा बच्चों को बुराइयों में बँधे सुरक्षित रखा जाय इसका एक उदाहरण है—'आदत' का निर्माण। बच्चों ने कहा है कि बच्चों में फेबल 'एक आदत' पैदा करनी चाहिए और वह यह है कि वह किसी आदत का गुलाम न बने। इसी से उन्हें अपनी स्वतन्त्रता मिलेगी। वह अच्छी आदत का विरोधी नहीं है क्योंकि वह शिक्षा को एक अच्छी आदत मानता है परन्तु वह बुरी आदतों का अवश्य विरोधी है, यह ठीक भी है क्योंकि मनुष्य में बुरी आदतें ही पड़ती हैं। वह अच्छी आदतों को प्रकृत (Natural) कहता है। इनके अन्तर्गत सफाई, शौच, स्नान आदि की आदतें आती हैं जिन्हें निषेधात्मक शिक्षा उत्पन्न करती है।



कि बच्चों के विकास के सोपानों के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए। जन्म से लेकर वयस्कवस्था तक पहुँचने के क्रम को हमों ने चार मुख्य सोपानों में बाँटा है। वे हैं—शैशवकाल, बाल्यकाल, बाल्योत्तरकाल और किशोरकाल। इन सोपानों पर चढ़ते हुए बालक का जैसा विकास होता है, उस विकास की प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा देने का हमने पूरा विवरण प्रस्तुत किया है जिस पर हम प्रसंगवश प्रकाश डालेंगे। हमने यह बताया है कि शिक्षा के लिए एक निर्धारित 'समय' होता है। यहाँ 'समय' का अर्थ यह है कि जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो, तभी शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार हमों ने बहुत पहले 'विवामात्मक मनोविज्ञान' के मूल तत्त्वों, जैसे प्रौढ़ता (Maturation) तथा धार्मिकता के मुख्य सिद्धान्त 'प्रस्तुतता' (Readiness) का पूर्व मकेल दे दिया था।

**निषेधात्मक शिक्षा**—मनुष्य ने विकास के प्रारम्भिक चरण में जिस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है, उसे निषेधात्मक शिक्षा (Negative Education) कहते हैं। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ समझ लेना आवश्यक है, अन्यथा इस सम्बन्ध में भ्रम हो सकता है। 'निषेधात्मक शिक्षा' का अर्थ यह नहीं है कि बालकों को दैक्षिक प्रभावों से बचित कर दिया जाय या उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा ही न दी जाय। शिक्षा तो दी जानी चाहिए यदि मनुष्य भी अच्छे अर्थों में मनुष्य बनाना है। हमों ने 'व्यक्ति की स्वतन्त्रता' का हर प्रकार में समर्थन किया है। वह कहता है कि सत्ता में सबसे उत्तम चीज 'शक्ति' नहीं, स्वतन्त्रता है। 'स्वतन्त्र मनुष्य' वही है, जो अपनी बातों की इच्छा करता है जिन्हें पूरा करने की शक्ति रखता है और बड़ के ही बातें करता है जिसकी वह इच्छा करता है।

दुर्भाग्य से इस प्रकार की स्वतन्त्रता का भाव पुराने देव की शिक्षा में नहीं पैदा होता। पुरानी शिक्षा दमन प्रधान होती है और वह मनुष्य की इच्छाओं को ही नष्ट करती है, तब 'स्वतन्त्रता' का अनुभव कोई अर्थ नहीं रखता। अब उस पुरानी शिक्षा के स्थान पर हमों निषेधात्मक शिक्षा की रूपरेखा निम्नलिखित करता है। इस शिक्षा का सीधा-मादा लक्ष्य यह है कि बच्चों को सत्य या उत्तम सिद्धान्तों की शिक्षा न देकर, केवल उनके मन की बुराइयों और मस्तिष्क को भ्रमों में बसाया जाय। इससे उनकी स्वतन्त्रता बनी रहेगी।

निषेधात्मक शिक्षा द्वारा बच्चों को बुराइयों से कैसे मुक्ति मिलेगा इसका एक उदाहरण है—'आदत' का निर्माण। हमों ने कहा है कि बच्चों से केवल 'एक आदत' पैदा करनी चाहिए और वह यह है कि वह किसी आदत का गुलाम न बने। इसी में उन्हें अच्छी स्वतन्त्रता मिलेगी। वह अच्छी आदत का विरोधी नहीं है क्योंकि वह शिक्षा को एक अच्छी आदत मानता है परन्तु वह बुरी आदतों का अवश्य विरोधी है, यह ठीक भी है क्योंकि मनुष्य में बुरी आदतें ही पड़ती हैं। वह अच्छी आदतों को प्रकृत (Natural) कहता है। इनके अन्तर्गत गफाई, धोब, स्नान आदि भी आदतें आती हैं जिन्हें निषेधात्मक शिक्षा उत्पन्न करती है।



कि बच्चों के विकास के मोपानों के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए। जन्म से लेकर बयस्कत्वतक तक पहुँचने के क्रम को रूगों ने चार मुख्य मोपानों में बाँटा है। वे हैं—शैशवकाल, बाल्यकाल, बाल्योत्तरकाल और विद्योत्तरकाल। इन मोपानों पर चढ़ते हुए बालक का अँगमा विकास होता है, उम विकास की प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने का उमने पूरा विवरण प्रस्तुत किया है जिम पर हम प्रममवदन प्रकाश डालेंगे। उमने यह बताया है कि शिक्षा के लिए एक निर्धारित 'ममय' होता है। यहाँ 'ममय' का अर्थ यह है कि जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो, तभी शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार हमों में बहुत पहले 'विकासात्मक मनोविज्ञान' के मूल तत्त्वों, जैसे प्रौढन (Maturation) तथा वानडाइक के मुख्य मिडान्त 'प्रस्तुतता' (Readiness) का पूर्व संकेत दे दिया था।

निषेधात्मक शिक्षा—मनुष्य ने विकास के प्रारम्भिक चरण में जिस प्रकार की शिक्षा का समर्पण किया है, उसे निषेधात्मक शिक्षा (Negative Education) कहते हैं। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ ममक लेना आवश्यक है, अन्यथा इस सम्बन्ध में भ्रम हो सकता है। 'निषेधात्मक शिक्षा' का अर्थ यह नहीं है कि बालकों को शैक्षिक प्रभावों में वचित कर दिया जाय या उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा ही न दी जाय। शिक्षा तो दी जानी चाहिए यदि मनुष्य को मरचे अर्थों में मनुष्य बनाना है। हमों ने 'व्यक्ति की स्वतन्त्रता' का हर प्रकार में समर्पण किया है। यह कहता है कि ममान में सबसे उत्तम चीज 'शक्ति' नहीं, स्वतन्त्रता है। 'स्वतन्त्र मनुष्य वही है, जो उन्ही बातों की इच्छा करता है जिहें पूरा करने की शक्ति रखता है और वह वे ही बातें करता है जिनकी वह इच्छा करता है।

दुर्भाग्य में इस प्रकार की स्वतन्त्रता का भाव पुराने ढग की शिक्षा में नहीं पँदा होता। पुरानी शिक्षा दमन प्रधान होती है और वह मनुष्य की इच्छाओं को ही मरु करती है, तब 'स्वतन्त्रता' का अनुभव कोई अर्थ नहीं रखता। अतः उम पुरानी शिक्षा के हवान पर हमों निषेधात्मक शिक्षा की रूपरेखा निमिचन करता है। इस शिक्षा का मीषा-मादा लम यह है कि बच्चों को मरु या उत्तम मिडान्तों की शिक्षा न देकर, बैबल उनके मन की बुराइयों और मस्तिष्क को भ्रुतों से बचाया जाय। इससे उनकी स्वतन्त्रता बनी रहेगी।

निषेधात्मक शिक्षा द्वारा बच्चों को बुराइयों से र्कमे मुरशित रखा जाय इसका एक उदाहरण है—'आदत' का निर्माण। हमों ने कहा है कि बच्चों में केवल 'एक आदत' पँदा करनी चाहिए और वह यह है कि वह किसी आदत का गुलाम न बने। इसी से उन्हें सच्ची स्वतन्त्रता मिलेगी। वह अच्छी आदत का विरोधी नहीं है क्योंकि वह शिक्षा को एक अच्छी आदत मानता है परन्तु वह बुरी आदतों का अवयव विरोधी है, यह ठीक भी है क्योंकि मनुष्य में बुरी आदतें ही पड़ती हैं। वह अच्छी आदतों को प्रकृत (Natural) कहता है। इनसे अन्तर्गत गफाई, धीच, रमान आदि की आदतें अली हैं जिन्हें निषेधात्मक शिक्षा उत्पन्न करती है।





है कि "उसे विज्ञान सिखाया न जाय वरन् उसे अपने आप खोज करने दी जाय।" तात्पर्य यह कि 'ह्यू रिस्टिक' (स्वशोध) पद्धति से पढ़ाया जाय। यो तो रूसो पुस्तकों का धोर विरोधी है परन्तु डेनियल टोको के प्रसिद्ध उपन्यास 'रॉबिन्सन क्रूसो' का पढ़ाने पर वह जोर देता है क्योंकि इस पुस्तक में यह दिखाया गया है कि प्रकृति के बीच में रहकर मनुष्य किम प्रकार उत्तम जीवन व्यतीत करता है। उस काल की सारी शिक्षा 'श्रिया' द्वारा सम्पन्न होनी चाहिए। सारे पाठ व्यावहारिक हों और पुस्तकों का सहारा तभी लिया जाय जब कोई पारा न रहे। बच्चों को दस्तकारी की शिक्षा अवश्य दी जाय। दस्तकारी के कामों में उसे बड़ईगीरी सबसे ज्यादा पसन्द है। यह दस्तकारी बालक को स्वाधत्तम्बी बनाना है।

बारह वर्ष तक बालकों को सामाजिक प्रभावों से दूर रखा जाना चाहिए परन्तु किशोर काल में उसे मानवीय सम्बन्धों का ज्ञान कराना आवश्यक हो जाता है। मानवीय सम्बन्धों का ज्ञान भी दस्तकारी के माध्यम में कराया जा सकता है क्योंकि कई लोग सहयोग करके वस्तुएँ तैयार करने हैं। मानवीय सम्बन्धों की शिक्षा का दूसरा उपाय यात्रा है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के समाजों के जीवन का परिचय मिलता है।

(घ) पन्द्रह से बीस वर्ष की शिक्षा—इस काल में 'हृदय' की शिक्षा का ध्यान रखा होगा। यह नैतिक्ता और धर्म की शिक्षा का उपयुक्त अवसर होता है। 'म्व' में केन्द्रित बालक को अब 'पर' की ओर उन्मुख करना है। मानवीय सम्बन्ध यहाँ में आरम्भ होता है और धर्म तथा नैतिक्ता इस सम्बन्ध के माध्यम हैं। मानवीय सम्बन्धों के लिए हमने भावना को आवश्यक बताया है। धर्म का आधार भी भावना है। धर्म की शिक्षा देने समय उसने कर्मकांड और धार्मिक कृत्यों में किन्तोरों को अलग रखने की सलाह दी है। उसके मन में मनुष्य ईश्वर का भ्रम है और ईश्वर हर पदार्थ में विद्यमान है। इस बात का अनुभव प्रकृति की निकटता से होता है। यही धर्म की शिक्षा है।

सामान्य जन की शिक्षा—रूसो अभिज्ञान वर्षों से समाज की भ्रष्टता का अनुभव पेरिस में कर चुका था। वह सामान्य जन को इसीलिए अधिक महत्त्व देता था। प्लेटो आदि ने उच्चवर्ग की शिक्षा की व्याख्या की। रूसो ने उच्चवर्गों के बच्चों को शिक्षा के द्वारा सामान्य जन की कोटि में लाने का विचार प्रकट किया। वह सामान्य जन की इसीलिए शिक्षा देना चाहता था कि वे भाग्य अथवा लक्ष्मी के सहारे रहकर नष्ट न हो जायें। उनका यह विचार प्रजातान्त्रिक शिक्षा का मूलधार बन गया।

रिश्तों की शिक्षा—'एमोन' में रूसो ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट किये हैं। वह स्त्री और पुरुष की शिक्षा में अन्तर रखने का पक्षपाती है और यह अन्तर 'सोफी' की शिक्षा में स्पष्ट हो जाता है। वह कहता है कि पुरुष की शिक्षा प्रकृत हानी चाहिए और स्त्री की परम्परागत (Conventional)। वास्तव









मिथाना चाहिए। उसका कहना था कि बालकों को पहले वे शब्द मिथाने चाहिए जिन्हें वे बोलने समय सरलता से प्रयोग में ला सकेंगे ही। शब्द-ज्ञान केवल 'भाषा सीखने' के लिए नहीं बल्कि जीवन में व्यवहार करने के लिए कराया जाना है। रट्टू तोने की तरह बिना अनुभव के शब्द-ज्ञान कराने का वह घोर विरोधी है। निरर्थक शब्दों को बच्चों के दिमाग में भरना हानिकारक है।

भाषा की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए पेस्तालॉजी ने शब्द-चयन का मार्ग सुझाया। अध्यापक को पहले मज्ञा अर्थात् ऐसे शब्दों को चुनना चाहिए जो विभिन्न वस्तुओं, गुणों और क्रियाओं के नाम हों। ऐसे शब्द उसने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे प्रकृति, इतिहास, भूगोल, मानवीय सम्बन्धों और पेशों में चुने। इन शब्दों का तात्कालिक अनुभव संभव है। इसी आधार पर शब्द-चयन का वह पद्धति है। फिर दूसरा कदम है, इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाना जिसमें विभिन्न वस्तुओं का सम्बन्ध ज्ञात हो जाय। शब्दों को मिथाने से उगने ध्वनियों का विश्लेषण किया और उन्हें ध्वनि-ग्रहण द्वारा मिथाने पर जोर दिया।

वस्तु-पाठ—पेस्तालॉजी ने तात्कालिक अनुभव के प्रशिक्षण के लिए 'वस्तु-पाठ' (Object lesson) की विधि नैवार की। इसके अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं का भली प्रकार निरीक्षण कराया जाता है। जब कोई वस्तु शालक के सामने प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें तीन गुण उसे अनुभव कराये जाते हैं, वे हैं—वस्तु की सत्ता, उसका आकार और उसका नाम। अब इस विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाने में पहले उन्हें यह बताया जाता है कि यह वस्तु एक इकाई है और इसकी सत्ता एक है। इस प्रकार की अनेक वस्तुएँ हैं जिन्हें गिनना बताया जाता है। फिर उस वस्तु के आकार और रूप का अनुभव कराया जाता है। उसकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, आकृति, रूप और रंग का निरीक्षण बच्चे करते हैं। बाद में उन्हें यह शब्द बताया जाता है जिसके द्वारा उस वस्तु का वर्णन किया जाता है और जिससे उस वस्तु का बोध होता है। इस प्रकार तात्कालिक अनुभव द्वारा एक वस्तुओं की भिन्नता का ज्ञान बालकों को हो जाता है।

वस्तु-पाठ की सबसे बड़ी विशेषता है, उसकी यथार्थता। स्थूल वस्तुओं की शिक्षा में बच्चे इसका ध्यान रखा जाता है, वह हम बता चुके हैं। नैतिक पाठों में भी यथार्थ का पूरा स्थान रहता है। उदाहरण के द्वारा नैतिक आचरणों को प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट किया जाता है। जैसे, प्रति शनिवार को नाम की गट्टूड बच्चों को एकत्र करती है और वह उनसे पूछती है कि सप्ताह भर में तुमने कोई बुरा काम तो नहीं किया। यदि बच्चे नहीं समझ पाते तो वह उनके दुर्बलहारी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनका अनौचित्य मिट्ट करती है। यह भी एक प्रकार का वस्तु-पाठ ही है।

इन वस्तु-पाठों की सफलता का वर्णन करते हुए हरबार्ट ने अपनी टायरी में रखा है कि पेस्तालॉजी के स्कूल में पढ़कर निकलने के बाद बच्चे हर वस्तु और शब्द को जिनकी अर्थों तरह समझते हैं, उनको अच्छी तरह वे शब्दों द्वारा की गयी शब्दों की

व्याख्या को नहीं समझने। वह अपने अनुभव के आधार पर कहता है कि मुझे कभी-कभी वेदनामाँत्री की शिक्षण विधि पर अविश्वास होता था परन्तु वक्ता की प्रशंसा और उनके समझने की क्षमता का विश्वास देकर मुझे पश्चिन्न रह जाना पड़ता था।

### ३. हरबार्ट

#### सामान्य परिचय

हरबार्ट को अपने जीवन में पुनरा संघर्ष नहीं करना पड़ा जितना वेदनामाँत्री को करता पड़ा था। उसने अपना अधिकांश जीवन विम्वविद्यालयों में अध्यापन करने तथा बिनन करने हुए बिताया। शिक्षा में उसकी दिलचस्पी थी, इसका प्रमाण यह है कि वह कुछ समय तक वेदनामाँत्री के साथ उसके स्कूल में काम करता रहा। विम्वविद्यालय में उसने वैशेषिक उपनिषदों का आयोजन किया और पाठ्यपूर्ण भाषण भी दिये। उसकी लिखी हुई पुस्तकों में 'शिक्षा का विज्ञान' और 'वैशेषिक शिक्षालय की व्यवस्था' प्रमुख हैं।

हरबार्ट की प्रगति का सबसे बड़ा आधार उसकी पक्षपदी शिक्षण विधि है। हम विधि को 'उमने गीमने के' मनोविज्ञान का आधार देकर इनका छाया बना दिया कि आज भी कुछ जेम्स के साथ सभी अध्यापक इसका प्रयोग करते हैं। उसने शिक्षण की प्रक्रिया का जो विश्लेषण किया है, उसी में अध्यापक प्रशिक्षण की परम्परा शामिल। शिक्षा में यह भारी व्यावहारिकता पैदा करने हुए भी वह मूल रूप से दार्शनिक था और उसकी रसि आचरण दार्शनिक में अधिक थी। इसका बहुत प्रभाव उसके वैशेषिक चिन्तन पर पड़ा है।

#### हरबार्ट का वैशेषिक चिन्तन

शिक्षा का उद्देश्य-चरित्र-निर्माण—हरबार्ट ने एक स्थान पर कहा है कि मारी शिक्षा के भाव को वेबम एक प्रत्यक्ष 'वैशेषिकता' के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। मरम शब्दों में, हरबार्ट ने मरानुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के चरित्र का निर्माण है। मनुष्य के व्यक्तित्व को जँचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें सच्चाई, पवित्रता और मनमनमाहून के गुण पैदा किये जायें। मरगुणों की व्याख्या करने हुए उसने उनकी पाँच मर्यादा बताई। वे मरगुण (Virtues) हैं—१. आंतरिक स्वयन्मर्यादा जिसका अर्थ है मरक्य और इच्छा तथा अनहर्षि और विश्वास के बीच मरन्वय; २. रक्षणता अथवा पूर्णता, ३. उच्चरुदयता, ४. म्याय, और ५. मारम्य हर्षि। मनुष्य का चरित्र इन्हीं मरगुणों में बनता है।

चरित्र का प्रमुख आधार संकल्प (Will) है जो एक मरगुण है। मनुष्य में यदि मरक्य गुण पैदा हो जाय तो उसका चरित्र उच्चरुदयि का होता। यह संकल्प बहुमुखी रचियी (Many sided interest) और इच्छाओं पर निर्भर है और इन दोनों की उत्तानि का आधार उत्तम विचार वृत्त (Right circle of ideas) है।





उममे मकल्प के माय दिगी काम मे डटे रहने की शक्ति पैदा हो जाती है। इस प्रकार रचि एक ऐसी मानसिक स्थिति पैदा कर देती है कि मनुष्य अत्यन्त नीरस और चपटमाय्य काम में लगा रहता है और उसे पूरा करने का प्रयत्न करना रहता है।

रचि की मरुता स्पष्ट करने के बाद हरबार्ट यह कहता है कि मनुष्य, के लिए एक रचि नहीं बल्कि बहुतसारी रचियों की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की रचि एक बाल में नहीं, अनेक बालों में होनी चाहिए ताकि वह मानव मरुति के विभिन्न पहलुओं को प्रकट कर सके। यदि एक ही रचि उत्पन्न होती है, तो मनुष्य का व्यक्तित्व एकाना और समुचित बन जाता है। रचियाँ बहुमुखी होनी चाहिए और उनके समन्वित होने में मकल्प और चरित्र बनते हैं। रचियों के समन्वित के लिए उममे प्रस्तुतीकरण (पाठ्य-मापकी) में गानुधन्य (Correlation) की आवश्यकता बतायी। इस सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे।

अध्यापन विज्ञान—हरबार्ट ने चरित्र-निर्माण के लिए खूबसूरत कई पद स्थिर किये हैं, यथा चरित्र, सत्त्व, रचि, दृष्टि, विचारवृत्त तथा प्रस्तुतीकरण। इनमें से प्रथम पाँच तो आन्तरिक क्रियाएँ हैं, जिनका सम्बन्ध मन में है और छठा प्रस्तुतीकरण बाह्य क्रिया है जो अध्यापक के हाथ में है और इसी की सहायता से उममे मन की आन्तरिक क्रियाओं पर नियन्त्रण करने की जो व्यवस्थित पद्धति निबाली उसे अध्यापन विज्ञान कहते हैं। उममे शिक्षा के लिए इस अध्यापन विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। बिना अध्यापन के शिक्षा की न तो कल्पना हो सकती है और न अध्यापन ही मार्गक है जब तक उसके द्वारा शिक्षा का काम पूरा नहीं होता। इस विचार में हरबार्ट ने अध्यापन को एक विज्ञान का रूप देने का निश्चय किया। हरबार्ट ने पहले जेम्स ह्यूट मगठन के मदरसों में शिक्षण का व्यवस्थित किया था परन्तु हरबार्ट ने अध्यापन विज्ञान की जो परिष्कृत रूप दिया, वैसा किसी ने अब तक नहीं किया था।

हरबार्ट के मन में चरित्र-निर्माण की आधार-सिद्धि अध्यापन है क्योंकि अध्यापन द्वारा ही प्रस्तुतीकरण (Presentation) अर्थात् विषय सामग्री छात्रों के सामने प्रस्तुत की जाती है। इस प्रस्तुतीकरण में विचारवृत्त बनते हैं, जो चरित्र-निर्माण में सहायक होते हैं। उत्तम अध्यापन यह है जिसके परिणामस्वरूप उत्तम प्रत्यय (Concepts) और ज्ञान में स्पष्टता, संगर्भ (association) और प्रणाली आदि गुण हो ताकि विचारों में लचीलापन उच्चतम अंश में वर्तमान रहे। तात्पर्य यह है कि अध्यापन के द्वारा उत्पन्न विचारों में स्पष्टता, परस्पर-सम्बद्धता और उनका क्रम आदि बातों की स्पष्ट रहें। इसमें उनकी रचियाँ भी समन्वित रहे ताकि मकल्प की शक्ति अच्छी तरह क्रियाशील रहे - अन्त में उममे अध्यापन चरित्र और आचरण पर प्रभाव डालता है।

(क) अध्यापन और प्रस्तुतीकरण—अध्यापन का मूल कार्य 'प्रस्तुतीकरण' है। हरबार्ट ने इसी अध्यापन विधि के पाँच पद या मोमान निश्चित किये हैं।

फिर हरबार्ट ने यह बताया कि उनमें विचार वृत्तों की उत्पत्ति के लिए गहरी प्रस्तुतीकरण (Presentation) की आवश्यकता है। इस प्रकार पूरे क्रम को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि चरित्र-निर्माण की मूल जड़ प्रस्तुतीकरण है जिसकी अवहेलना करना किसी अध्यापक के लिए उचित नहीं है। हरबार्ट ने चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया के प्रत्येक अंश की स्पष्ट व्याख्या की है। जिन पर हम क्रमशः विचार करेंगे।

(क) संवरण—पुर्गने जिज्ञासियों का विचार था कि मनुष्य के मन में संकल्प की एक फंक्शनी (विभाग) होती है जो जन्मजात है, परन्तु हरबार्ट इस बात पर विश्वास नहीं करता। उसका कहना है कि संवरण जन्मजात नहीं है। यह दृष्टान्तों और रचियों के अनुसार बनता है। "जब दृष्टान्तों निश्चय का रूप ग्रहण कर लेती हैं और मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि वह अपने निश्चय को पूरा कर सकता है तो संवरण की उत्पत्ति होती है।" नास्तिक यह है कि पहले मनुष्य दृष्टा करता है, फिर वह उसे पूरा करने का निश्चय करता है और जब वह उस निश्चय को क्रियान्वित करने की शक्ति भी रखता है, तो संकल्प जाग्रत हो जाता है। हरबार्ट स्पष्ट कहता है कि मनुष्य की महानता केवल जानने पर निर्भर नहीं है बल्कि उसके सकलप करने में है।

मनुष्य के भीतर संकल्प का निर्माण बाह्य प्रभावों से होता है और यह बाह्य प्रभाव प्रस्तुतीकरण से उत्पन्न होते हैं। हरबार्ट का कहना है कि अध्यापकों को प्रस्तुतीकरण के समय तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चों के आगे पाठ्य-सामग्री उपस्थित की जाती है, तो उनके मन में तीन क्रियाएँ होती हैं, वे हैं—दृष्टा करना, निरीक्षण करना, और कल्पना करना। इनमें से वह प्रथम और मूल्य की सफल-निर्माण में बाधक मानता है क्योंकि यह मनुष्य को भ्रम में डालने वाली होती है। निरीक्षण को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए वह पेन्सिलवर्गी के तारकालिक अनुभव के मिथ्यात्व के अनुसार ही निरीक्षण कराने को सलाह देता है। निरीक्षण में संकल्प के निर्माण में महामत्ता मिलती है।

(ख) बहुमुखी रचियाँ—चरित्र-निर्माण और संकल्प का निर्माण रचियों के आधार पर होता है। इसलिए हरबार्ट के मतानुसार यदि शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य चरित्र-निर्माण है, तो तारकालिक उद्देश्य 'रचि' है। अभी तक रचि के बारे में लोगों का विचार अस्पष्ट था या फिर उसे वे अत्यन्त साधारण बात समझते थे। हरबार्ट ने स्पष्ट बताया है कि रचि 'मनोवृत्त वृत्ति' का पर्याय नहीं है। उसने रचि की व्याख्या मने तरीके से की। 'उमके मन में 'रचि प्रस्तुतीकरण (पाठ्य-सामग्री) के आत्मगत (Self realization) करने की प्रक्रिया के साथ-साथ होने वाली केवल-वस्था है।' इस बात को स्पष्ट करने हुए उसने बताया कि 'रचि', 'उदासीनता' का उल्टा है। जब कोई सामग्री प्रस्तुत की जाती है, तो मन में उत्तेजन होता है। मन उस वस्तु को आत्मगत करना चाहता है तो उसे पाने की आशा में ही रचि का उदय होता है। उस वस्तु को पाने की दृष्टा और प्रयत्न में बाधा पड़ने से रचि पैदा होती है। यह रचि ही मनुष्य का प्रयत्न करने के लिए निवृत्त करती है और

उममे मवरूप के गाय विगी काम मे डटे रहने की शक्ति पैदा हो जाती है। इस प्रकार रचि एक तेगी माननिक स्विति पैदा कर देती है कि मनुष्य अत्यन्त नीरम और कष्टमाध्य काम मे लगा रहता है और उसे पूरा करने का प्रयत्न करता रहता है।

रचि की मरणा स्पष्ट करने के बाद हरबार्ट यह कहता है कि मनुष्य, के निग एक रचि नहीं बरन् बहुमुखी रचियों की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों मे, मनुष्य की रचि एक बान मे नहीं, अनेक बानों मे होनी चाहिए ताकि वह मानव मरहटि के विभिन्न पहलुओं को आरमगत कर सके। यदि एक ही रचि उत्पन्न होती है, तो मनुष्य का व्यक्तित्व एकामी और संकुचित बन जाता है। रचियाँ बहुमुखी होंगी चाहिए और उनके संघटित होने मे मवरूप और चरित्र बनने हैं। रचियों के मघटन के निग, उमने प्रस्तुतीकरण (पाठ्य-सामग्री) मे मानुष्य (Correlation) की आवश्यकता बनायी। इस सम्बन्ध मे हम आगे विचार करेंगे।

अध्यापन विज्ञान—हरबार्ट ने चरित्र-निर्माण के निग अमम कई पद स्थिर किये हैं, यथा चरित्र, मवरूप, रचि, दृष्टि, विचारवृत्त तथा प्रस्तुतीकरण। इनमे मे प्रथम पाँच तो आन्तरिक क्रियाएँ हैं, जिनका सम्बन्ध मन मे है और छठा प्रस्तुतीकरण बाह्य क्रिया है जो अध्यापक के हाथ मे है और इसी की सहायता मे उमने मन की आन्तरिक क्रियाओं पर नियन्त्रण करने की जो स्ववर्धन पद्धति निबाली उसे अध्यापन विज्ञान कहते हैं। उनम शिक्षा के निग इस अध्यापन विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। बिना अध्यापन के शिक्षा की न तो कल्पना हो सकती है और न अध्यापन ही मार्गक है जब तक उमके द्वारा शिक्षा का काम पूरा नहीं होता। इस विचार मे हरबार्ट ने अध्यापन को एक विज्ञान का रूप देने का निश्चय किया। हरबार्ट ने पहले जेमुट्ट मघटन के सदस्यों ने शिक्षण का प्रम निदिचित किया था परन्तु हरबार्ट ने अध्यापन विज्ञान को जो परिष्कृत रूप दिया, र्थमा किर्मा ने अब तक नहीं किया था।

हरबार्ट के मउ मे चरित्र-निर्माण की आधार-शिला अध्यापन है क्योंकि अध्यापन द्वारा ही प्रस्तुतीकरण (Presentation) अर्थात् विषय सामग्री छात्रों के सामने प्रस्तुत की जाती है। इस प्रस्तुतीकरण मे विचारवृत्त घलते हैं, जो चरित्र-निर्माण मे सहायक होते हैं। उत्तम अध्यापन यह है जिनके परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रत्ययों (Concepts) और ज्ञान मे स्पष्टता, संगर्भ (association) और प्रणाली आदि गुण हो ताकि विचारों मे लचीलापन उच्चनम अंशो मे वर्तमान रहे। तात्पर्य यह है कि अध्यापन के द्वारा उत्पन्न विचारों मे स्पष्टता, परस्पर-सम्बद्धता और उनका प्रम आदि बानवों की स्पष्ट रहे। हममे उनकी रचियाँ भी मघटित रहे ताकि मवरूप की शक्ति अच्छी तरह क्रियाशील रहे अलन उनम अध्यापन चरित्र और आचरण पर प्रभाव डालता है।

(क) अध्यापन और प्रस्तुतीकरण—अध्यापन का मूत्र कार्य 'प्रस्तुतीकरण' है। हरबार्ट ने अपनी अध्यापन विधि के पाँच पद या सोथान निदिचन किये हैं।

इसीलिए हरवार्ट की विधि पंचपदी शिक्षण विधि कहलाती है। इस विधि पद हैं—१. तैयारी या भूमिका (Preparation), इस सोपान में बालको ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप में तैयार किया जाता है। इस मानसिक तैयारी के काल में बालको के मन में वर्तमान पूर्व ज्ञान को जाग्रत किया जाता है और वर्तमान पाठ का सम्बन्ध जोड़ा जाता है। २. प्रस्तुतीकरण (Presentation) सोपान के काल में नवीन पाठ्य-सामग्री क्रमानुसार छात्रों के आगे प्रस्तुत की जाती है। ३. संलग्न (Association), इस सोपान में पूर्वज्ञान और वर्तमान ज्ञान सम्बन्धित पकड़ा कर दिया जाता है। नये ज्ञान का पूर्वानुवर्ती ज्ञान के साथ सम्बन्ध देने में इस बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। ४. प्रणाली (System); इस सोपान में अध्यापक इस बात का प्रयत्न करता है कि पाठ्य-सामग्री का विश्लेषण करके क्रम पंदा करे, जटिलता को दूर करे, पड़े हुए उदाहरणों में तुलना के आधार पर निकाले। ५. अनुप्रयोग (Application), पड़े हुए ज्ञान का नयी स्थितियों में प्रयोग करके यह देखना आवश्यक है कि बालको के लिए नये ज्ञान का क्या लाभ मिलेगा।

प्रस्तुतीकरण उत्तम अध्यापन का प्रमुख अंग है। क्योंकि इस प्रक्रिया में हरवार्ट ने निश्चित पदों में बाँट दिया और उस तक पहुँचने की विधि भी निर्धारित कर दी, इसलिए उसकी विधि वैज्ञानिक बन गई। अध्यापक बनने के लिए इस विधि के अंगों और उसकी प्रक्रिया जानना जरूरी बन गया। फल यह हुआ कि अत्यन्त अल्पकाल में अध्यापक-प्रशिक्षण की परम्परा खालू हुई और ट्रैनिंग कातेजों में अध्यापकता की शिक्षा दी जाने लगी। हरवार्ट ने पाठ्य-सामग्री के प्रस्तुतीकरण के दो प्रकार भी स्पष्ट कर दिये, वे हैं—सूचनात्मक (Informing kind), और प्रेरणात्मक (Inspiring kind)। सूचनात्मक सामग्री वह है जिसमें कुछ सूचनाएँ होती हैं जो उसका चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेरणात्मक प्रस्तुतीकरण चरित्र पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए यही श्रेष्ठ है।

(क) अध्यापन की व्यवस्था—हरवार्ट ने अध्यापन को विज्ञान का एक शास्त्र के साथ यह भी बताया कि अध्यापन की सफलता के लिए दो बातों की जरूरत है एक है शासन (Government) और दूसरे प्रशिक्षण (Training)। शासन के अर्थ दोनो शब्दों का अर्थ, जो है उसके लिए हम दूसरे शब्द प्रयोग में लाते हैं। 'शासन' का अर्थ है वास्तविक अनुशासन और 'प्रशिक्षण' का अर्थ है आध्यात्मिक अनुशासन। यह समझ लेने पर हरवार्ट के विचार स्पष्ट बन जाते हैं।

हरवार्ट कहता है कि अध्यापन के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय 'शासन' हो। इस शासन का तात्कालिक उद्देश्य यह है कि शास्त्र बचे और अध्यापन बिना बाधा के चला सके। शासन दमनपूर्ण होता है और कभी-कभी दमन की आवश्यकता पड़ती है। यह एक आवश्यक अवस्था (Necessary evil) है और अशासन (Anarchy) में हर शासन में अन्धता है। इसके विरुद्ध, प्रशिक्षण या आध्यात्मिक अनुशासन का सदैव दमन और व्यापक है। इसका सम्बन्ध शासन से है और यह अध्यापन का सदैव दमन और व्यापक है। इसका सम्बन्ध शासन से है और यह अध्यापन का सदैव दमन और व्यापक है।

आत्मनियन्त्रण और मोहस्थिता से उत्पन्न होता है। इसकी निरंतरता इसकी प्रमुख विशेषता है। बहुत से लोग प्रशिक्षण को ही अध्यापन समझ लेने को भूल कर बैठते हैं। प्रशिक्षण केवल अध्यापन का माध्यम है और एकमात्र प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। अध्यापन में विचारों के बीच बोल जाते हैं, इसकी सहायता में ज्ञान के अकुर उत्पन्न होते हैं। प्रशिक्षण अध्यापन का माध्यम मात्र समझा जाना चाहिए।

(ग) अध्यापन के प्रकार—हरवार्ट ने अध्यापन के दो प्रकार बताए हैं, एक को उसमें विस्लेषणात्मक और दूसरे को संश्लेषणात्मक बताया है। विस्लेषणात्मक अध्यापन की आवश्यकता इसलिए है कि जब बच्चों के सामने पाठ्य-पुस्तक प्रस्तुत की जाती है तो उसमें स्पष्टता और कुछ का कुछ समझ लेने के दोष पैदा हो जाते हैं, तो यह विस्लेषण के द्वारा स्पष्टता पैदा करता है और विचारों को शुद्ध करता है। इसके विपरीत, संश्लेषणात्मक अध्यापन का उद्देश्य विचारों को संगठित करना और उनके बीच एक सम्बन्ध स्थापित करना है। इसके द्वारा विभिन्न विचारों के बीच क्रम और व्यवस्था पैदा की जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि इन दोनों प्रकारों को अलग-अलग प्रयोग में लाया जाय। उचित यह होगा कि इन दोनों प्रकारों को अध्यापन क्रिया का अंग बना लिया जाय पहले विस्लेषणात्मक और बाद में संश्लेषणात्मक अध्यापन का प्रयोग किया जाय।

अध्यापन की मनोवैज्ञानिकता—अध्यापक पढ़ाये और बच्चे सीखें, यह शिक्षण की मूल समस्या है। हरवार्ट ने चरित्र-निर्माण के लिए शिक्षण की आवश्यकता बताई तथा शिक्षण के कार्य को अध्यापन तथा प्रस्तुतीकरण पर अवलम्बित बनाया। परन्तु यह सब काम सफलतापूर्वक पूरा कैसे किया जाय? जब तक बालक सीखता नहीं, या दूसरे शब्दों में, जब तक वह प्रस्तुतीकरण के प्रभाव को ग्रहण नहीं कर सकता, चरित्र-निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हरवार्ट ने यह भी स्पष्ट करने की चेष्टा की कि बच्चे प्रभाव किस प्रकार ग्रहण करते हैं।

हरवार्ट ने पेस्तालोत्ती के स्कूल में काम किया था। पेस्तालोत्ती ने अपने प्रमुख सिद्धान्त—तार्कानिक अनुभव के द्वारा ग्रहण करने अथवा सीखने की प्रक्रिया की कुछ श्राव्यता की भी जिस पर हम पीछे प्रकाश डाल चुके हैं। हरवार्ट ने अपनी डायरी में इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि शब्दों, वाक्यों और परिभाषाओं की जब बच्चे सीखते थे, तो मुझे यह सन्देह रहता था कि वे कुछ सीखते भी हैं। मैं जब यह सन्देह पेस्तालोत्ती के आगे प्रकट करता, तो यह पृथक्ता कि यदि बच्चे इन्हें समझते नहीं तो वे इन्हें क्यों प्रसन्नता तथा धीमत्ता से सीख लेते हैं? मैं यह अवश्य देखता कि बच्चे उन बातों को समझते अवश्य है। फिर भी मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह सब कैसे हो जाता है और फिर मैं यह मान लेता कि बच्चे किसी आन्तरिक क्रिया (Inner activity) द्वारा सीखते हैं।

जब हरवार्ट ने अपने अध्यापन सम्बन्धी सिद्धान्त स्थिर किये तो उसने 'आन्तरिक क्रिया' का विचार छोड़ दिया। उसे सौंर्य का विचार उठाया उचित जान पड़ा जिसके

अनुसार साधक का मन बारी बारी (Tubular Rasa) माना गया है और जिस पर बाह्य प्रभावों का संवेदनाश्रय न होकर अविचार होने है। इन विचारों में विचार उत्पन्न होने है। हरवार्ट ने इन विचारों का उपाय का व्यापक स्वीकार किया। हमने कहा कि मन का स्वभाव और प्रकृति स्वभाव नहीं है। विचारों में मन की प्रकृति स्थित होती है। मन में जो चिन्तित आत्मा कहलाती है वह वास्तव में अनेक मानसिक प्रक्रियाओं का एक संज्ञा है।

हरवार्ट के मन में मन में जो प्रभाव है और न दृष्टा। यह अन्तर्गत और बाह्य बाह्य प्रभावों में घटता है। इन विचारों के अनुसार मन की महत्वपूर्ण विशेषता प्रत्यक्षीयता (Assimilation) है। इनके प्रतिस्पर्ध, दूसरी प्रमुख विशेषता है, मन का अन्तर्गत भीतर आने वाले प्रभावों का सम्बन्ध करना। मन की इन दोनों विशेषताओं का अन्तर्गत भाग में समेट लेने वाले 'पूर्वानुवर्ती अभिवोध पुत्र' (Apperception Mass) की कल्पना हरवार्ट ने कर दी। इन पूर्वानुवर्ती ज्ञान भी कहते हैं परन्तु मन की उपर्युक्त दोनों विशेषताओं का साथ करना वाले 'पूर्वानुवर्ती अभिवोध पुत्र' वास्तव में प्रयोग उपयुक्त है। हमका मत है कि वास्तविक प्रकाश में वस्तु के मन में पड़ने जो संस्कार जमा होते हैं, उनका एक पुत्र बन जाता है। यह पुत्र मन की प्रत्यक्षीयता का कारण है। वस्तु का मन केवल उन्हीं प्रभावों की प्रत्यक्षीयता और धारण करता है, जो पूर्व-स्थापित संस्कार पुत्रों में समावेशित रहता है। विद्वान् प्रभावों में उत्पन्न इस पूर्व-स्थापित अभिवोध पुत्र के विरुद्धी संस्कार को मन कभी ग्रहण नहीं करता। अब हमने पहले में जो कहा था मन्दा है कि मनुष्य आरम्भ में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें समावेशित रहने वाले नवीन ज्ञान को वह मरतता में मीथ लेता है। समावेशित विचार उस पुत्रों ज्ञान में विरुद्धी होने जान है और ज्ञान का भंडार बढ़ता जाता है।

'पूर्वानुवर्ती अभिवोध पुत्र' के कारण मन की प्रत्यक्षीयता (मीथने) तथा धारणा शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके अनिश्चित वह अवधान (Attention), रचि और बोध शक्तियाँ भी पैदा करता है। यह बात भी व्यावहारिक जीवन में स्पष्ट होती है। वस्तु के मन में जो बातें पढ़ने में रहती हैं, उन्हीं में मिलनी-जुलनी वाले के आगामी में मीथने हैं, उन्हीं में रचि रहते हैं और उन्हीं के द्वारा में मुक्त हैं।

हरवार्ट के इस 'पूर्वानुवर्ती अभिवोध पुत्र' के मीथने की प्रक्रिया को एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जो बड़ी लोकप्रिय बन गयी। इसके आधार पर ही 'ज्ञान में अज्ञान की ओर' या 'परिचित में अपरिचित की ओर' जैसे सूत्र शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न हुए। प्रसिद्ध महाविद्यालयों में हरवार्ट की पाठ-योजना का प्रचलन हुआ और हर प्रशिक्षार्थी को यह बताया जाता है कि वह वस्तु के पूर्वज्ञान से नवीन ज्ञान का सम्बन्ध स्थापित करे।

शास्त्र-विषयों में समुचित—हम पहले ही देख चुके हैं कि चरित्र-निर्माण के लिए हरवार्ट ने मकल्प को बहुत अधिक महत्त्व दिया। संकल्प 'द्विविधा' का विरोधी

है। मनुष्य के मन में सकल्य शक्ति सभी पैदा होती है जब इसका मन बहुत में विकल्यो में फैला न रहे। अनेक विकल्यो के कारण ही मनुष्य के मन की चेतना शक्ति दुबडी में बैठ जाती है। हरबार्ट ने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करने हुए यह कहा था कि विचार वृत्तों और बहुभुयी रचियों में सकल्य बनता है परन्तु जब विचार वृत्त और रचियाँ अनेक होंगी, तो उनमें परस्पर विरोध होने का भय हो सकता है। यदि विरोधी तत्त्व पैदा हो गये तो यह निश्चय है कि सकल्य नष्ट होगा। इस दोष से बचने के लिए हरबार्ट ने 'सानुबन्ध' (Correlation) का सिद्धान्त निश्चिन किया। सानुबन्ध के द्वारा चेतना शक्ति की एकता बनाए रखकर सकल्य शक्ति को उत्पन्न करता आवश्यक है। इस सिद्धान्त के अनुसार जब बालकों के आगे पाठ्य-सामग्री प्रस्तुत की जाय तो उनके बीच वर्तमान सम्बन्ध का बोध बालकों का अवश्य कराया जाय। इससे यह लाभ होगा कि 'पूर्वानुयती अभिवोध पुंज' संघटित बना रहेगा। अब अध्यापक को यह चाहिए कि वह विभिन्न विषयों के बीच समन्वय या सानुबन्ध उत्पन्न करने का प्रयत्न करता रहे।

अध्यापन में 'सानुबन्ध' का उपयोग करने के लिए हरबार्ट ने दो बातें आवश्यक बनायीं, एक एकाग्रिकरण (Concentration) और दूसरी समापोजन (Correlation)। एकाग्रिकरण का अर्थ है, किसी विषय पर लगातार अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को केन्द्रित करना और समापोजन का तात्पर्य है, समान प्रभावों में क्रम उत्पन्न करना। इन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए हरबार्ट ने केन्द्र विषय (Core Subject) की कल्पना की और बताया कि 'इतिहास' ही ऐसा विषय है जिसकी सहायता से सारे पाठ्य-विषयों के बीच कड़ी या सम्बन्ध उत्पन्न हो सकता है। इतिहास अत्यन्त बहुवैधपूर्ण विषय है क्योंकि यह मानव संस्कृति का खजाना है और इतिहास स्वी क्रॉम में सारे पाठ्य-विषय जुड़े जा सकते हैं। यदि सारे पाठ्य-विषय मोती हैं तो इतिहास वह डोर है जिससे यह सभी मोती परोए जा सकते हैं। इतिहास की मृच्छमूर्ति में सभी विषयों को पढ़ाने में मनुष्य की मन की एकता पैदा होती है।

#### ४. फ्रोबेल

##### सामान्य परिचय

बहुचर्चित और प्रसिद्ध 'किंडरगार्टन' पद्धति के स्कूल में शायद ही कोई परिचित न हो। किंडरगार्टन फ्रोबेल का सबसे बड़ा परिचय है। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सभ्य देश होगा जिसमें किंडरगार्टन स्कूल न हों। राजनीतिक दर्शन की भिन्नता के बीच इन स्कूलों का होना, बिना देश, जाति और संस्कृति की भिन्नता के विचार में इनका अपनाया जाना फ्रोबेल के विचारों की श्रेष्ठता का प्रमाण है।

फ्रोबेल आदर्शवादी दार्शनिक और भौतिकवादी या। उसने जर्मनी के प्रसिद्ध



आर्य दार्शनिकों जैसे बाल, सीरीस, हीगेल, हिस्ट और फील्डिंग आदि के दार्शनिक साहित्य का अनुशीलन किया जिसकी सहायता द्वारा उनके विचार-दर्शन पर पड़ी है। साथ ही उनमें कुछ समय तक ग्रेन्टावादी के स्वभाव से भी बंधा दिया। यही उनमें बाप स्वभाव का मुख्य परिवर्तन किया और यही उनके मन में दार्शनिक गुणों का पूरा करने का उद्देश्य पैदा हुआ। यह ग्रेन्टावादी के विचारों में पूर्ण तरह परमन स हो गया। अतः ही उनमें केवल बाप स्वभाव का संस्कार एक विमान की भाँति में एक स्वतंत्र वायाना प्रारम्भ किया। उनके मन में एक नये प्रकार के स्वतंत्र की अनुभूति पैदा हुई। लगभग ८-१० वर्षों तक प्रयोग करने-करने उनमें इस विचार का मुदं रूप पैदा प्रारम्भ किया। अतः ही उनमें स्वतंत्रता में एक स्वतंत्र माना किने उनमें बिस्मार्क के नाम में पुनर्जाता प्रारम्भ किया। फोरेल के विचारों में विचार उगरी पुनर्जात 'मनुष्य की शिक्षा' (Education of Man) में गहरी है।

### फोरेल का दार्शनिक चिन्तन

जैसे-जैसे की एकता फोरेल एक अद्वैतवादी दार्शनिक था। उनका मन है कि विश्व एक सत्य में बना है। ईश्वर, जीव और प्रकृति सभी उन्हीं एक सत्य में बने हैं और यह जीवन सत्य की एकता का प्रमाण है। यह एकता ही सत्य और चिन्तन है। उनमें बनाया है कि जीव और प्रकृति उन सत्य स्वतंत्र के अंग हैं। अतः निदान्त की व्याख्या करने हुए उनमें दिया है

"मृष्टि के सभी पदार्थों पर एक शास्त्रन नियम व्याप्त होकर सामान्य करता है। यह सर्वसाधारण नियम निम्न ही किमी सर्वसाधारण, स्थितिमान, सजीव चेतन तथा सार्वभौम अभिप्राय या 'एकता' पर अवलम्बित है। यह एक एकता ही भगवान है। सत्य पदार्थ उन्हीं विगत देवी चेतना में प्रादुर्भूत है और उन्हीं में उनका मूल है। सब पदार्थ उन्हीं देवी एकता या ईश्वर में बंधे रहकर जीते रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में जो देवी स्फुरण होता है, वही उन पदार्थ का चेतन सत्व है।"

इस 'एकता' का बोध किस प्रकार हो—यही फोरेल के दार्शनिक चिन्तन का मुख्य विषय है। इस पर कुछ अधिक बातें आवश्यक है।

(क) 'एकता' के विचार की उत्पत्ति—फोरेल के समय में नेपोलियन के आक्रमणों में सत्तातीव्र जर्मनी देश की असाधारण क्षति हुई थी। वह देश टुकड़ों में बँट गया और जर्मन निवासियों की एकता नष्ट हो गई। जर्मन दार्शनिकों को इसमें बड़ा शोक पड़ा और उन्होंने जर्मन जाति की एकता का आधार ढूँढ निकाला। वह आधार था, जीवन सत्व की एकता। उन्होंने बनाया कि यद्यपि जर्मन लोग राजनीतिक कारणों से टुकड़ों में बँट गये हैं तथापि वे एक हैं क्योंकि उनके शरीरों में वह 'एकता' का सत्व मौजूद है। यह विचार फोरेल ने काट, हीगेल, हिस्ट आदि दार्शनिकों से ले लिया।

(स) अनेकता की व्याख्या—भौतिक जगत् में हम अनेकता और विविधता देखते हैं। प्रोवेस ने इन दोनों बातों की जो 'एकता' की विरोधी हैं, व्याख्या की जो 'विकाशवाद' के मन में बहुत मिलती-जुलती है। उसका कहना है कि जन्म के समय प्रारम्भिक दशा में वस्तुएँ एक-ही होती हैं परन्तु विकास के दौरान भिन्नता पैदा हो जाती है। यह भिन्नता केषल उपरी है और किसी तरह भी वास्तविक नहीं। प्रोवेस का यह विचार आगे चलकर डार्विन के 'विकाशवाद' की गृष्टभूमि बना।

(ग) एकता का बोध कराने के उपाय—प्रोवेस ने 'एकता का बोध कराना' शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य निश्चिन किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उनमें प्रकृति को प्रमुख माधन माना। उसका विचार था कि चूँकि हम महान् एकता में मनुष्य और प्रकृति दोनों उत्पन्न हुए हैं, इसलिए 'प्रकृति' के माध्यम में मनुष्य को एकता का बोध कराया जा सकता है। विङ्गमार्टन के बच्चों की शिक्षा में प्रकृति के अध्ययन (Nature Study) को हमने सर्वोपरि स्थान दिया। अध्यापिकाएँ बच्चों को फूल, पेड़, सूर्य, आकाश तथा प्रकृति के अन्य अंगों के प्रति आकृष्ट करती हैं।

छोटे बच्चों की प्रकृति के विज्ञान जगत् में ले जाना सम्भव नहीं है। इस-लिए प्रोवेस ने प्रकृति के अध्ययन को ही 'एकता' की अनुभूति का एकमात्र माधन नहीं माना। बक्षाओं में हम तख्त का बाध कराने का एक सुन्दर उपाय उनकी समझ में आया और वह था—'उपहार'। यह उपहार एक प्रकार की सहायक सामग्री है परन्तु उसे बालक बहुत पसन्द करते हैं और उनके खेलने में वे काम आते हैं, इसलिए हम शिक्षोपयोगी सामग्री का नाम उपहार रखा। इन उपहारों की संख्या २० है परन्तु हममें से मात्र मुख्य है। यह मात्र उपहार भी तीन आकृतियों, यथा लम्बवर्ती, गोला और घन के रूपान्तरमात्र हैं। यह उपहार लेव में काम आते हैं परन्तु इनका मूल उद्देश्य 'एकता' का बोध कराना है। उदाहरण के लिए, 'गेंद' को लें। गेंद की लम्बाई चौड़ाई, ऊँचाई या मोटाई इसके विशेष आकार के कारण स्पष्ट नहीं है। कहाँ इसका आरम्भ है और कहाँ अन्त, यह भी नहीं मान्य। इसलिए यह इकाई का प्रतीक है। इसकी सहायता में छोटे बच्चे 'एकता' का बोध करते हैं और यह भी मंचते हुए। इसी प्रकार दूसरा उपहार 'घन' (Cube) एकता के अनेकता में विभाजन और अनेकता के एकता में रूपान्तर का बोध कराने में सहायक है। यह घन छोटी-छोटी इकाइयों से बनता है और उन इकाइयों में नई प्रकार की धक्कें बन जाती हैं। हममें यह स्पष्ट हो जाता है कि एकता अनेकता का रूप ग्रहण करती है।

एकता का बाध कराने के लिए प्रोवेस ने एक अन्य बात पर काफी धन दिया है। उनमें बताया कि हर व्यक्ति के विकास में चार प्रकार के विरोधी तत्व क्रियाशील रहते हैं। वे हैं—(१) माना-पिता की प्रकृति और उनके मरकार, (२) परमात्मा और प्रकृति की चेतना, (३) परिवार की सम्पत्ति और प्रवृत्तियाँ, तथा (४) मानवता की प्रवृत्ति और सम्पत्ति। इन चारों तत्वों का समायोजन बच्चों के मनस्

नहीं। लोगों ने भी यही समझा था कि जो याद रखनी पड़ेगी उसे याद रखनी है। उसे बचने भूल जाने है। परन्तु त्रिम यात को सीगने में धम होता है, यह याद रखनी है। दूसरे धम द्वारा रचनात्मक काम हो सकता है। फॉरेन के मन में रचनात्मक काम आध्यात्मिकता का अंग है। इंग्लिश किङ्गमार्टन गढ़नि में धम करने का अभ्यास न केवल बागवानों के द्वारा परन्तु उन सभी प्रियाओं द्वारा किया जाता है। त्रिममें बचने भाग लेने है। कर्मन्ता द्वारा बचने का धम करने है त्रिमने उनका स्वास्म बनना है और उनके मन का परिवर्तन भी होता है।

### ५. हरबर्ट स्पेंसर

#### सामान्य परिचय

शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रारम्भ १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में फ्रांसिस बकन ने किया था और तब से इन्द्रियजन्य ज्ञान का महत्त्व स्पष्ट करके विज्ञान की उन्नति का मार्ग खोल दिया था। इसके परिणामस्वरूप मानव जीवन में जो परिवर्तन उत्पन्न हुए, उनके अनुस्यू शिक्षा को क्या मोड़ देना चाहिए, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। हरबर्ट स्पेंसर ने इस आवश्यकता का अनुभव किया और शिक्षा के कार्यक्रम का पुनर्गठन करने की आज्ञा उठाई। वह शिक्षा में उत्पन्न होने वाली वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वह एक महान् चिन्तक भी था जिसके शिक्षा सम्बन्धी विचार उसकी पुस्तक 'शिक्षा—बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक' में देखने का मिलते हैं। वैज्ञानिक विषयों का महत्त्व निम्न करते हुए भी वह इन बातों को नहीं भूल पाया कि मानव जीवन में नैतिकता और संस्कृति का महत्त्व है। वह बात अवश्य रही कि वह नैतिकता और संस्कृति के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही रखता था।

#### स्पेंसर का शैक्षिक चिन्तन

बचलता हुआ मानव जीवन और शिक्षा—इन्द्रियजन्य ज्ञान और प्रवृत्ति के नियमों की जानकारी ने मनुष्य के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया था। इस परिवर्तन का सूत्रपात अठारहवीं शती के अन्तिम धरण में इंग्लैण्ड में प्रारम्भ हुआ और उसे इतिहास में औद्योगिक क्रान्ति कहते हैं। इस क्रान्ति का जन्म वैज्ञानिक आविष्कारों से हुआ था। अभी तक मनुष्य हाथों से काम करता आया था परन्तु अब मशीनों के मन जाने से उसके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति आ गयी और मशीनों के धरा पर उसने अपनी सुख-सुविधा में वृद्धि की। पिछले हजारों वर्षों में भोजन, वस्त्र, आवास, मानावाहक तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में मनुष्य ने अनेक सुविधाएँ प्राप्त कर ली और साथ ही प्रवृत्ति की शक्तियों को उसने गुलाम बना लिया।  
- उसका जीवनक्रम बदलने लगा।

विज्ञान की उन्नति में मनुष्य के विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके का दंग ही बदल गया। परन्तु वह 'अनुमान' और 'अन्तर्दृष्टि' को ज्ञान का

साधन मानना था परन्तु अब प्रत्यक्ष अनुभव और पर्यवेक्षण के माध्यम तर्क पद्धति का प्रयोग करने वह अपनी समस्याओं को हल करने लगा। इसका फल यह हुआ कि धार्मिक कृतियाँ और प्रचलित अपविष्टतन्त्र नष्ट होने लगे। अभी तक दर्शन, धर्म और साहित्य में जो कुछ लिखा था, उस पर अग्नि बन्द करके विस्तार कर लेने की प्रवृत्ति का अन्त होने लगा। इस बात का प्रमाण हमें बोधगिनिकम्, गौडीयियों और द्वारविन के विचारों में मिलता है। इसका स्पष्ट प्रभाव यह हुआ कि मानव समाज में दर्शन, धर्म और साहित्य का वह सम्मानपूर्ण स्थान नहीं रह गया, जो पहले था। पुरानी मान्यताओं और सूत्रों के प्रति संदेह के पैदा होने में विचार जगत् में जो हलचल पैदा हुई वह ईगर्गन्ध के कवियों, जैमिनीयन और आरनोन्ध, की कृतियों में देखने की मिल सकती है। इन लोगों ने मनुष्य के बदलते हुए जीवन के प्रति निराशापूर्ण दृष्टिकोण प्रकट किया तो स्मरण में उसका आत्मवादी पक्ष सामने प्रस्तुत किया।

मानव जीवन बेड़ी में बंदन रहा या परन्तु तदनुत्पन्न शिक्षा नहीं बदल रही थी। शिक्षा का काम जीवन की सहायता है और यदि जीवन बदलता है तो शिक्षा को भी बदलना चाहिए। यह परिवर्तन शिक्षा के उद्देश्यों, विधियों और पाठ्यक्रम में आने चाहिए। 'इन्द्रियमन्त्र ज्ञान' की महत्ता विज्ञान ने बढ़ाई थी। ज्ञान-प्राप्ति के ढङ्ग बदल गये थे। इन विधियों की ओर शिक्षा को मोड़ने का काम पैम्फालोंजी और हरबार्ट ने किया था परन्तु पाठ्य सामग्री में क्या परिवर्तन हों, ताकि शिक्षा बदलने हुए मानव जीवन के अनुकूल बन जाय, इस बात की ओर स्पेन्सर ने मकेन किया।

पाठ्यक्रम का पुनर्गठन—स्पेन्सर ने ईगर्गन्ध के स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषयों की कटु आलोचना की क्योंकि वे मनुष्य के बदलते हुए जीवन में फेल नहीं माने थे। इन स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले प्रमुख विषय थे—धर्म, दर्शन, इतिहास और साहित्य। स्पेन्सर ने इन विषयों की वैशेषिक उपयोगिता पर संदेह प्रकट किया। उसने कहा कि ज्ञान दो तरह का हो सकता है—१ साधक ज्ञान (Instrumental knowledge), और २ साध्य ज्ञान अथवा विषयक ज्ञान (Positive knowledge)। साधक ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वह साध्य ज्ञान को पाने का एक साधन है। असली महत्व तो साध्य ज्ञान अथवा विषयक ज्ञान का है, जो मानव जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। साधक ज्ञान पाने के लिए धर्म, दर्शन और साहित्य तथा भाषा के विषय पढ़ाये जा सकते हैं और साध्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए विज्ञान-विषयों का पढ़ाना जरूरी है। इस दृष्टि में ईगर्गन्ध में पढ़ाये जाने वाले दर्शन, भाषा और साहित्य विषय गौण हुए और विज्ञान-विषय प्रमुख हुए। स्पेन्सर ने संक्षेप प्रकट करते हुए कहा कि विज्ञान-विषयों को शिक्षा में महत्व नहीं दिया जा रहा है जिससे भावी पीढ़ी घाटे में रहेगी। अच्छा यह होगा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया जाय और विज्ञान के विषयों को उसमें सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाय।

विज्ञान-विषयों के पक्ष-समर्थन में हरवर्ट स्पेंसर ने वे सभी तर्क दिये जो साहित्यिक विषयों के समर्थन में मदियों में दिये जाते रहे हैं। उसने कहा कि वैज्ञानिक विषयों की व्यावहारिक उपयोगिता है। उनके पढ़ने में मानव जीवन में सुख की वृद्धि होगी और नया ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इन विषयों का गुरुशास्त्रिक मूल्य है अर्थात् इनकी जानकारी जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक सुरक्षा की गारंटी हो सकेगी। उसने विज्ञान-विषयों के पक्ष में दूसरा तर्क यह दिया कि साहित्यिक विषयों की अपेक्षा मानविक शक्तियों के उत्थान में विज्ञान-विषय कहीं अधिक समर्थ है, इसलिए उनका अस्थासत्त्विक मूल्य (Disciplinary value) भी अधिक है। उसका तीसरा प्रबल तर्क यह था कि विज्ञान-विषयों का सांस्कृतिक मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक है। मानव सभ्यता वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बढ़त चुकी है और उस सभ्यता का ज्ञान नौसवान पीढ़ी को विज्ञान-विषयों के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है।

**शिक्षा का उद्देश्य**—सर्वांगीण जीवन विज्ञान-विषयों का महत्त्व स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर एक चरम और आगे बढ़ा। उसने वही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया जो शिक्षा के सम्बन्ध में आदि काल में उठाया जाता रहा है, अर्थात् शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए अथवा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर उसने 'सर्वांगीण जीवन की संप्राप्ति के लिए' मूल द्वारा दिया। शिक्षा का काम, उसके मत में, मनुष्य को सर्वांगीण जीवन के लिए तैयार करना है।

सर्वांगीण जीवन (Complete living) का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ स्पष्ट करने हुए स्पेंसर ने कहा है कि सर्वांगीण जीवन वह है जो महत्त्व प्राप्त में पाँच बातों के लिए समर्थ हो, वे हैं—(१) अस्तित्व रक्षा में समर्थता, (२) मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थता, (३) मजबूती रक्षा में समर्थता, (४) सामाजिक सम्बन्धों का निर्वाह करने में समर्थता, और (५) आसोद-प्रसोद की समर्थता।

इन पाँच बातों के महत्त्व क्रम के आधार पर स्पेंसर ने विषयों को भी महत्त्वक्रम में विभाजित किया। चूँकि अस्तित्व रक्षा सबसे अधिक आवश्यक है, इसलिए हम कार्य में सहायक विज्ञान विषय सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। दूसरा स्थान मूल आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राप्त है जिसके लिए व्यावहारिक और औद्योगिक विषय पढ़ाना जरूरी है। तीसरा स्थान स्वास्थ्य के संरक्षण रक्षा को दिया है जिसमें दुर्ग-विज्ञान का महत्त्व बड़ा। चौथा स्थान सामाजिकता का है जिसके विभाग के लिए सामाजिक विषय पढ़ाने चाहिए और अन्तिम स्थान जीवन में आसोद-प्रसोद को है जिसके लिए साहित्य और दर्शन पढ़े जा सकते हैं। हम बर्गीकरण में एक बात स्पष्ट है कि अभी तक स्कूलों में पढ़ाये गये विषय जैसे धर्म, साहित्य, भाषा, दर्शन और दर्शन का महत्त्व सबसे अधिक था, वहीं स्पेंसर के मत में सबसे कम महत्त्व के बन गए।

वास्तव में स्पेन्सर का दृष्टिकोण सर्वथा नवीन था। अभी तक शिक्षा केवल कुछ वर्गों तक सीमित थी जो अवकाश तथा धन की सुविधा का उपयोग कर रहे थे। स्पेन्सर के मन में एक ऐसी शिक्षा की कल्पना पैदा हुई जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो। सुविधा-प्राप्त जनों के लिए, जो जीवन के मध्य में बने रहते थे, साहित्य और दर्शन जैसे विषय पढ़ना स्वाभाविक था। अब प्रजातन्त्र के उदय में जनसाधारण का महत्त्व बढ़ा और उनको ऐसी शिक्षा चाहिए थी जो उन्हें जीवन के मध्य में सफलता दिला सके। इसीलिए हरबर्ट स्पेन्सर ने सर्वांगीण जीवन की पैदारी का उद्देश्य लेकर शिक्षा में आमूल परिवर्तन की सम्भावनाओं उत्पन्न कर दी।

स्पेन्सर के विचारों को पढ़ने के बाद कुछ ऐसा ज्ञान पढ़ने लगना है कि वह बिगुल रूप में भौतिक और उपयोगितावादी चिन्तक है और उसकी मजहो में दर्शन और साहित्य का कोई स्थान नहीं है। ऐसा विचार भ्रमात्मक है। स्पेन्सर नैतिकता का उनका ही समर्थक था जिसका हर्बर्ट रहा था।

प्रकृत परिणामों का मिथ्यान्त—स्पेन्सर का विचार था कि बालकों में नैतिकता का भाव उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। हमने भी लगभग यही बात कही थी परन्तु 'प्रकृत परिणामों का नियम' स्पेन्सर की ही देन है। उनके विचार के सम्भीत वैज्ञानिक परिणाम हुए हैं। बच्चों की शिक्षा में 'स्वतन्त्रता' और माप-माप में सब 'मध्यम' का महत्त्व इस मिथ्यान्त में प्रकट होता है। उन्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान प्रकृति करा देनी है—यह विचार पूरी तरह में ग्राह्य भी नहीं है यद्यपि इसमें एक आकर्षण है।

स्पेन्सर की मान्यता यह है कि प्रकृति अच्छे काम का पुरस्कार सुख के रूप में और बुरे काम का दंड कष्ट के रूप में देनी है। प्रकृति के निर्णय प्रगमनीय होते हैं क्योंकि वे अनिवार्य होते हैं अर्थात् बुरा काम करने पर दंड और अच्छा काम करने पर पुरस्कार मिलेगा ही। साथ ही परिणाम समानुपातिक भी होता है, अर्थात् जिस सीमा तक आचरण बुरा होगा, उन्ही सीमा तक दंड कटोर होगा। प्रकृति का दंड या पुरस्कार अपवाद शून्य है अर्थात् ऐसा कभी नहीं होगा कि बुरे काम का दंड किसी स्थिति में न मिले। प्रकृति का यह नियम हर वान और हर स्थान पर इसी प्रकार चलता आया है।

प्रकृति के परिणामों का मिथ्यान्त नर्क की दृष्टि में बड़ा घमण्कारी ज्ञान पड़ता है परन्तु जब स्पेन्सर उसे बच्चों की शिक्षा पर घटित करता है, तो उसमें कई दोष नजर आने लगते हैं और इस मिथ्यान्त की सीमा स्पष्ट होने लगती है। उदाहरण के लिए, यह कहना है कि यदि कक्षा में दिये गये काम को कोई बालक नहीं करता, तो उसका प्रकृत परिणाम यह होना चाहिए कि बालक को स्कूल समाप्त होने के बाद घर जाने में रोक लिया जाय। अब इस प्रकार के उदाहरण से यह बात पैदा होती है कि ठीक से काम न करने या न पढ़ने पर बालक को घर न जाने देना का क्या प्राकृतिक परिणाम मिला जाना चाहिए। दूसरे, इस प्रकार का परिणाम किसी प्रकार शिक्षाप्रद



हार्टवर्ट तथा फोरेल के शैक्षिक साहित्य की अच्छी तरह पढ़ा। इसके बाद जॉन ड्यूवी ने शिक्षा के चलते विद्यालयों में असन्तुष्ट होकर एक नया विद्यालय खोला जो 'प्रयोगशाला विद्यालय' अथवा ड्यूवी स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

ड्यूवी का शिक्षा-दर्शन उनकी पुस्तकों, यथा 'विद्यालय और समाज' (School and Society), 'प्रजातन्त्र और शिक्षा' (Democracy and Education) तथा 'हम कैसे सोचते हैं' (How We Think) में विकसित हुआ है।

## ड्यूवी का शिक्षा-चिन्तन

ड्यूवी ने अपने दर्शन का विकास प्रत्यक्ष अनुभव तथा प्रयोग के आधार पर किया है। यद्यपि उन्होंने अध्ययन और मनन किया है, परन्तु वे उन लोगों में नहीं हैं जो आप्तवचन (Authority) को बिना समझे-बूझे मान लेते हैं। जो विचार उन्होंने ग्रहण किया वह अनुभव की प्रामाणिकता के आधार पर और उसकी जाँच करने के पश्चात्, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को यही सलाह दी कि वे छात्रों को इस प्रकार तैयार करें कि वे मर्यादाओं की परख में कुशल बनें। ड्यूवी का यह विचार मूलरूप में प्रकट हुआ, जिसे प्रयोगशाला विद्यालय कहते हैं। अन्तु, संक्षेप में इन विद्यालय के त्रिधा-कलाप की जानकारी आवश्यक है।

**प्रयोगशाला-विद्यालय—**यह विद्यालय ड्यूवी ने क्लिफोर्ड में अपनी पत्नी के सहयोग में मई १८९६ में खोलना प्रारम्भ किया। इसमें ४ वर्ष से लेकर १४ वर्ष की आयु तक के छात्र थे। छात्रों की संख्या कम थी। पहले इस नये प्रकार के विद्यालय का लोगो ने मजाक बनाया परन्तु धीरे-धीरे जब इसके उत्तम परिणाम स्पष्ट होने लगे और विद्वानों ने इस विद्यालय की श्रेष्ठता स्वीकार की। इन विद्यालय की कई प्रमुख विशेषताएँ थीं।

(क) विद्यालय समाज का लघुरूप—इन विद्यालय में ड्यूवी ने छात्रों को एक छोटे-से समाज के रूप में संगठित किया। छात्रों को यहाँ के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भाग लेने के लिए यहाँ प्रेरित किया गया। साथ ही, सारे विद्यार्थियों को यह अनुभव कराया गया कि वे एक सार्थक तथा उपयोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

(ख) क्रियात्मक कार्यक्रम—इन प्रयोगशाला विद्यालय की दूसरी विशेषता है—क्रियात्मक कार्यक्रम (Activity programme)। यहाँ का पाठ्यक्रम पूर्व-निर्धारित नहीं होता। बालकों के वर्तमान जीवन पर विद्यालय का सारा कार्यक्रम आधारित है। मौखिक पढ़ाई का निरस्कार करके व्यावहारिक कार्यों और प्रत्यक्ष अनुभवों की यहाँ की शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया गया। ड्यूवी का यह विश्वास था कि शिक्षा के कार्यक्रम का स्रोत बालकों की गृह्य क्रियाएँ और रुचियाँ हैं। यहाँ पर पढ़ने, लिखने तथा गणित जैसी बौद्धिक क्रियाओं को विभिन्न क्रियाओं (activities)



के माध्यम में मिलाने की व्यवस्था थी। यहाँ की निद्याप्रद क्रियाओं में संग, रचना-त्मक कार्य, आत्मविश्वसक्ति (Self expression) और प्रहृति का अध्ययन प्रमुख है।

इसकी के विद्यालय के त्रियात्मक कार्यक्रम की उपयोगिता निम्नलिखित है :

१. 'क्रिया के द्वारा सीखना' (Learning by doing) मूल का प्रयोग सीखने की शक्ति बढ़ाना है। पाठ्य-विषय को क्रिया के रूप में बदल कर उसे प्रत्यक्ष करने और अनुभव करने हुए बालक की हर शक्ति अच्छी तरह सक्रिय में आ जाती है।
२. यहाँ बालकों को यह अवसर मिलता है कि वे अपने अनुभवों की जाँच कर लें। केवल अनुभव मात्र काफी नहीं है, बालकों को यह ज्ञानना चाहिए कि कौन-सा अनुभव शुद्ध है और कौन-सा अशुद्ध ?
३. बालक यहाँ जो कुछ सीखते हैं उसकी प्रत्यक्ष उपयोगिता प्रमाणित हो जाती है। सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार करके उपयोगिता की परख कर ली जाती है।
४. विद्यालय का बालावरण पुराने प्रकार के स्कूलों में बिल्कुल बदला हुआ होता है। विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हुए छात्र एक-दूसरे में सहयोग करते हैं परन्तु स्वार्थपूर्वक कार्य करते हैं। ऐसा ज्ञान पड़ता है कि वे आपसी मनोबोध भूल गये हैं और खुद कर एक उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं। इससे उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है।
५. छात्र निष्ठा प्राप्त करने हुए प्रयोगात्मक (Experimental) दृष्टिकोण अपनाने हैं। वे किसी भी तथ्य को बिना सोचे-समझे नहीं ग्रहण करते।

शिक्षा का दायित्व—इसकी एक प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। वे दर्शन में 'आप्तवचन' को प्रमाण नहीं मानते थे, मर्य की प्रामाणिकता की कमीटी उनके मन में कुछ दूसरी है। वे कहते हैं

(४) सत्य की हम हर दसा में जाँच (Verification) कर सकते हैं।

(५) जो विचार जाँच की कमीटी पर गिरा उनसे, वही सत्य है।

(६) सत्य हर दसा में उपयोगी होता है।

(७) जो विचार उपयोगिता की कमीटी पर गिरा उनसे वही सत्य है।

कोई भी सिद्धान्त या विचार स्थायी रूप में सत्य नहीं होता, हमारे दावों में, सत्य परिवर्तनशील है। इसलिए उस विचार की सत्यता और प्रामाणिकता को जाँचने की आवश्यकता है। यह कार्य कैसे हो ? इसकी वे बताया कि दर्शन में बताये गये मूल्यों की जाँच विद्यालय में हो सकती है। 'शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है' इस मूल का अर्थ यह है कि इसकी की माय्यता के अनुसार शिक्षा के माध्यम में ही सत्य की 'सत्यता' की परख की जा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा का प्रमुख दायित्व सत्य की जाँच-पड़ताल करना है।

शिक्षा का दूसरा उत्तरदायित्व यह है कि वह दर्शन की 'उपयोगिता' की परम्परा भी तब दार्शनिकों का विचार यह था कि दर्शन 'ज्ञान' प्रदान करता है और इस कार्य में सहायक होती है। जो 'ज्ञान' छात्रों को प्राप्त होता है, उसमें वे 'ज्ञान' हैं ('ज्ञान' शब्द 'ज्ञा' धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना है)। इसीलिए कि 'ज्ञान' केवल मनुष्य को कुछ मूल्यों की जानकारी मात्र नहीं कराता। मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि वह अपनी परिस्थितियों को नियन्त्रण में ला सके और जिस दुनिया में रहता है, उसे और अच्छा बना सके। यही ज्ञान की उपयोगिता है। इसी ने अपनी पुस्तक 'दर्शन का पुनर्निर्माण' (Reconstruction of Philosophy) में लिखा है।

"यदि विद्वान्, विचारों, नियमों या विधियों से, परिस्थिति को अपने अनुकूल और कठिनाइयों या समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है तो उन्हें और निर्भरमान समझना चाहिए। यदि वे इस काम में सफल हो सकें, तो उन्हें जीवन, विश्वसनीय, सत्य और अच्छा समझना चाहिए। यदि उनमें अस्पष्टता होगी तो दूर करने में सहायता न मिले, या उनके अनुसार काम करने पर और अधिक अस्पष्टता और परेशानी बढ़ जाय, तो उन्हें 'भ्रूषी' और 'असत्य' समझना चाहिए।"

अतः, शिक्षा का दायित्व यह भी है कि वह पढ़े जाने वाले मूल्यों, विचारों, नियमों और विधियों की उपयोगिता की जाँच भी करे। दूसरे शब्दों में यह निम्न करे कि 'दर्शन' कहाँ तक व्यावहारिक है या यों कहें कि शिक्षा का व्यावहारिक रूप है (Education is the practical side of Philosophy)।

शिक्षा का तीसरा दायित्व यह है कि वह ज्ञान तथा अनुभव का प्रत्यक्ष सम्पर्क जोड़ दे। इसी ने अपनी पुस्तक 'प्रमाणन और शिक्षा' में बताया है कि ज्ञान का उद्देश्य 'मानव संस्कृति का हस्तांतरण' (Transmission of Culture) तरह उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। पाठ्य विषयों के रूप में मानव संस्कृति की प्रतीति के समान प्रस्तुत की जाती है परन्तु छात्रों को यह कदापि अनुभव नहीं कि उनके पूर्वजों का यह ज्ञान क्या था और उसे कैसे जीवन में प्रत्यक्ष रूप में प्रयोजित किया जा सकता है? ज्ञान अनुभवमूल्य होने पर बेकार हो जाता है। हमारे पास एक प्रकार की दुकान है जिसमें सड़े-गले अनुभवमूल्य ज्ञान की बिक्री होती है। असली शिक्षा वह है जिसके माध्यम से छात्रों को यह जानने का मौका मिलता है कि कौनसे ज्ञान के तत्त्व अनुभव-प्रधान हैं और उन्हें कहाँ तक स्वीकार करना चाहिए? हमने उन्हें दर्शन के मूल्यों का अनुभव के आधार पर पुनर्गठन करने का मौका मिलना है। इस अर्थ में शिक्षा अनुभव का पुनर्गठन है (Education reconstruction of experience)।

शिक्षा का चौथा दायित्व है—शिक्षा में व्याप्त विरोधों को समाप्त करना। द्यूबी का कहना है कि प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि समाज तथा शिक्षा में वर्तमान कई प्रकार के विरोधों को समाप्त किया जाय। विरोध रूप में प्रजातन्त्र, उद्योग और विज्ञान के बीच विरोध उत्पन्न हो गया है। प्रजागान्त्रिक जीवन में उद्योग और विज्ञान को सहायक होना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए, उद्योगों के विकास में पूँजीवाद विकसित हो रहा है, जो प्रजातन्त्र को सार्थक नहीं होने देता। घन कुछ लोगों के हाथों में पहुँच जाता है और वे पूँजीपति जनता के प्रतिनिधियों को खरीदने का प्रयत्न करते हैं और कहीं-कहीं वे तथ्यांकपति लोक सभाओं पर अधिकार करके साधारण जनता का रक्त घूमते हैं। इसी प्रकार विज्ञान की सहायता में प्रजातन्त्र में अनेक प्रकार की मृग-मुविधाएँ सामान्य जनता को मिल सकती हैं परन्तु होता कुछ और है। विज्ञान की शक्ति को कुछ राजनीतिज्ञ बन्दी बना लेते हैं और वे भयानक शास्त्रास्त्रों की सहायता में प्रजातन्त्र को नष्ट करके अधिनायकतन्त्र (Dictatorship) चलाते हैं। शिक्षा का काम प्रजातन्त्र को उबारना है। शिक्षा सामान्य जनता को विवेक-सम्पन्न बनाकर यह परिस्थितियाँ अपने नहीं देती अर्थात् पूँजीपतियों और अधिनायकों की शक्ति बढ़ने नहीं देती।

विचार जगत् में कई अन्तर्विरोध हैं, जैसे 'स्कूल और समाज' में, 'रक्षि और प्रयत्न' (Interest and effort) में, 'व्यक्तिवाद और सामूहिकतावाद' में और 'बालक तथा पाठ्यक्रम' में। शिक्षा पर इन अन्तर्विरोधों को समाप्त करने की जिम्मेदारी है। अभी तक 'स्कूल' को समाज का अंग नहीं समझा जाता, हर स्कूल के चारों ओर बनी दीवारें इसका प्रमाण हैं। द्यूबी के मत में स्कूल समाज का लघु रूप है। समाज की सारी प्रक्रियाएँ स्कूल में खूबकर, इस अन्तर्विरोध को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार सामान्य धारणा यह है कि रक्षि 'वहाँ होगी वहाँ प्रयत्न न होगा' अर्थात् जो काम रक्षिकर होता है, वह धर्मसाध्य नहीं होता और बिना प्रयत्न के किया जाता है और जो काम धर्मसाध्य हो या जिसमें बड़ा प्रयत्न करना पड़े, वह रक्षिकर नहीं होता। यह विरोध भी निरर्थक है। शिक्षा के द्वारा हर धर्मसाध्य कार्य को रक्षिकर बनाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा यह भी प्रयत्न रूप में दिखाया जा सकता है कि व्यक्ति और समाज में कोई विरोध नहीं है, जैसा प्रयोग-शास्त्र के विवरण में प्रकट है। समाज व्यक्ति का रक्षक है और उसके विकास में सहायक है तथा व्यक्ति समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इसी प्रकार 'बालक और पाठ्यक्रम' के विरोध को शिक्षा समाप्त करती है। पूर्व-निर्धारित पाठ्यक्रम तो बालक की गति को नहीं स्वीकार करता परन्तु क्रियात्मक पाठ्यक्रम में तो सब कुछ बालक की क्रिया में निहित है और दोनों में कोई विरोध नहीं रह जाता।

शिक्षा और बालक—द्यूबी ने शिक्षा का गुन वेन्द बालक को माना है। यह उनके त्रिपादमक कार्यक्रम में ही प्रकट हो जाता है, वे बाल्य में शिक्षा के सारे

पाठ्यक्रम तथा क्रियाकलाप का उद्गम बालक को ही मानने हैं। इसके अनिश्चित एक बाल और भी विचारणीय है। 'सत्य की उपयोगिता' की जाँच के बारे में हम बना चुके हैं और वह चुके हैं कि इयूवी के अनुसार शिक्षा का एक उत्तरदायित्व 'सत्य की उपयोगिता' की जाँच है। इयूवी महोदय इस प्रश्न को और आगे ले जाते हैं। शिक्षा में बालको को जो सत्य बनाये जाते हैं, उन 'सत्यो की उपयोगिता' किमके लिए है? यह प्रश्न भी विचारणीय है।

वही विचार, सिद्धान्त या सत्य उपयोगी है, जो 'मनुष्य' के लिए उपयोगी है। अब इस बात का धार्मिक परिणाम यह निकलता है कि हमें बालको को वही कुछ पढ़ाना या सिखाना है, जो 'उनके' लिए उपयोगी है। इस दृष्टि से भी 'बालक' का महत्व बढ़ जाता है। सारा धार्मिक कार्यक्रम वही होना चाहिए जो छात्रों के लिए उपयोगी हो। पाठ्यक्रम के अनुसार बालको को सोचना-मोचना नहीं है बल्कि बालकों के हित की दृष्टि से पाठ्यक्रम को बदलना है।

दूसरी बात यह है कि हर मनुष्य हमेशा के लिए उपयोगी नहीं रहता। आज जो मनुष्य उपयोगी है, काल की बदली हुई परिस्थितियों में अनुपयोगी सिद्ध हो सकता है। यही बात सारे सिद्धान्तों और ज्ञान के तत्वों पर घटित होती है। यदि समय परिवर्तन के कारण 'उपयोगिता' नष्ट हो सकती है, तो 'भूत' और 'भविष्य' का महत्व नष्ट हो जाता है। इनके स्थान पर वर्तमान की महत्ता बढ़ जाती है। दुर्भाग्य से शिक्षा का एक उद्देश्य अति प्राचीनकाल से 'आवी जीवन की तैयारी' रहा है। आवी जीवन की जो बरपना है वह आकार होगी भी या नहीं, इसका विचार किए बिना बालक के मुनद वर्तमान की उपेक्षा होती रही है। इयूवी ने स्पष्ट रूप से बताया कि 'भूत-भविष्य' का ध्यान न करके बालको के वर्तमान जीवन की दृष्टि से उपयोगी बातों को सिखाना विद्यालय का प्रथम कर्तव्य है।

शिक्षा एक अनिवार्य क्रिया है—प्रयोगशाला विद्यालय में शिक्षा 'जीवन का प्रतिरूप' है, यह हम पहले ही देख चुके हैं। परम्परागत शिक्षा में यह बात नहीं है क्योंकि वहाँ शिक्षा को जीवन से अलग एक प्रक्रिया माना गया है। इयूवी के मत में जिस प्रकार जीवन का क्रम निरंतर चलता रहता है उसी प्रकार शिक्षा का क्रम भी निरंतर चला करता है। इन अर्थ में शिक्षा एक अनिवार्य क्रिया है।

इस दृष्टि से शिक्षा का दायित्व यह है कि वह छात्रों को मानव सस्कृति के मूल, उपयोगी तथा मुक्त तत्वों में अवगत कराए। यह काम मशीनी तरीके से नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी पुरानी धारणा कि मानव सस्कृति एक धरोहर है और उसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे जाती है, सर्वथा गलत है। विज्ञान मानव सस्कृति कोई ईंट या रोटा अवयव मोने का आभूषण नहीं है, जिसे एक हाथ में दूसरे हाथ में दिया जा सके। संस्कृति अनुभवों का अमूल्य कोष है और 'अनुभवों' के प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान आ सकता है अर्थात् प्रत्यक्ष जीवन के सन्दर्भ में ही हम

अनुभव की तारीफ़ी को जान सकते हैं। इस दृष्टि में शिक्षा एक अनिवार्य क्रिया बन जाती है।

शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है—इंग्लैंड के प्रयोगशाला विद्यालय में 'समाज के लघु रूप' की चर्चा हम पढ़ने कर चुके हैं। इसके अनिश्चित हम यह भी बता चुके हैं कि इस स्कूल में छात्रों को महयोगपूर्ण ढंग से सामाजिक जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इस दृष्टि में शिक्षा एक सामाजिक क्रिया बन जाती है। स्कूल के समाज का वातावरण धीमे-धीमे बालकों के अन्तर्मन पर प्रभाव डालता है। इस समाज में रहकर वे 'सफलता', 'असफलता', 'मान' और 'अपमान' के भावों का अनुभव करता है। यही उसे भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। इस समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि मारे ध्यान मिल-जुल कर एक उद्देश्य के पीछे चलते हैं।

पुराने ढंग के स्कूल में 'समाज' का संस्था स्वरूप देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ हर छात्र उस प्रकार कुछ समय के लिए आता है जैसे मेटे में या स्टेशन पर लोग आते हैं। उनके बीच में कोई अटूट सम्बन्ध नहीं होता। इन स्कूलों में 'भीड़' (Crowd) या समूह होता है, समाज नहीं। उसमें शिक्षा देने वाले स्कूल का समाज संघटित होता है, उसके मारे सर्वस्य महयोग, महानुभूति, भानुभावना और एक उद्देश्य की ओर में बंधे होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सामाजिक वातावरण को नियोजित रूप से उत्पन्न करना है।

इंग्लैंड ने प्रजातान्त्रिक समाज की ही सच्चा समाज माना है। इसलिए वह शिक्षा में प्रजातान्त्रिक वातावरण की रचना करने पर विशेष धन देता है। प्रजातान्त्रिक समाज की श्रेष्ठता इस बात में है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वाङ्गीण विकास के लिए समान अवसर मिलते हैं। इंग्लैंड का विचार है, शिक्षा को यह सारी सामाजिक क्रिया नियोजित होनी चाहिए। इसके कई कारण इंग्लैंड ने बताये हैं।

समाज में तीन प्रकार के प्रमुख प्रयोजन (Motive) देखने को मिलते हैं। प्रथम, मनुष्य मात्र में स्नेह (Affection) की आवश्यकता प्रयत्न होती है। समाज इस स्नेह के सूत्र में बंधा होता है। दूसरा प्रयोजन है, सामाजिक विश्वास की भावना अर्थात् हर मनुष्य यह कामना करता है कि वह मानव-हित के लिए प्रयत्न करे। तीसरा प्रयोजन है, जीव की इच्छा अर्थात् मनुष्य हर अनुभव को परखना चाहता है। यदि तीन प्रयोजन न हों तो समाज न चले। इस दृष्टि में यह निम्न आवश्यक है कि योजनापूर्वक विद्यालय में इन तीनों प्रयोजनों को आधार मानकर सामाजिक जीवन बिताने की व्यवस्था की जाए।

शिक्षा विकास के रूप में—इंग्लैंड ने शिक्षा को 'विकास' (Growth) का एक रूप माना है। शिक्षा की प्रक्रिया के बीच बालक का विकास होता है। समग्र यही विचार प्रयोजन का भी था परन्तु विशेष आदर्शवादी था और उसने 'विकास' की

व्याख्या रहस्यवादी ढंग में की। वह ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करता था और यह मानता था कि मनुष्य उस सत्ता का एक अंग है। इसलिए उसका यह तर्क था कि उस अंग का विकास स्वतः होता है। इसके विपरीत, इयूवी ने डार्विन के विकासवाद में ज्यादा योश्या। इसलिए उसका मन यह था कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का विकास होता है या यो कहें कि बालक की शिक्षा सामान्य में विकास की प्रक्रिया का एक अंग है।

चूँकि इयूवी विकास को किसी अलौकिक (Supernatural) शक्ति पर छोड़ देने में विश्वास नहीं करता, इसलिए यह शिक्षा के नियोजन और निर्देशन को बहुत अधिक महत्व देता है। इस सम्बन्ध में इयूवी के कई तर्क हैं।

(क) परिवार तथा स्कूल के बाहर समाज में बालक केवल चलते, दैनिक तथा वर्तमान चीजों, विद्वानों और परम्पराओं का ज्ञान प्राप्त करता है परन्तु स्कूल में उसे अनेक ऐसी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है जिसका सम्बन्ध भूत और भविष्य से है। स्कूल बालक के अनुभव का दायरा बहुत अधिक बढ़ाने में समर्थ है। यह न तो सभी सम्भव है, जब शिक्षा का नियोजन हो।

(ख) स्कूल की एक विशेषता यह है कि यहाँ प्रत्येक स्थिति, विचार या निश्चय को सरल कर (Simplified) बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि ऐसा न हो, तो बालकों का ज्ञान ठीक से विकसित ही न हो पाए। नियोजन में हर पाठ्य विषय सरल और बोधगम्य बनता है।

(ग) स्कूल में जो भी ज्ञान या प्रभाव बालकों के आगे प्रस्तुत किया जाता है, वह चयन (Selection) के द्वारा प्राप्त होता है। हर उचित-अनुचित, उत्तम या अधम बात उनके आगे नहीं रखी जाती क्योंकि हमारे शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। चयन के कार्य के लिए भी नियोजन आवश्यक है।

(घ) स्कूल का सारा वातावरण समुचित (Balanced) होता है अर्थात् हर आवश्यक ज्ञान के तत्त्व को बालकों की शिक्षा में स्थान दिया जाता है ताकि बालकों के विकास में असंतुलन न पैदा होने पाये। यह भी नियोजन का ही महत्व प्रदर्शित करता है।

बालकों के समुचित विकास के लिए शिक्षा का वातावरण नियोजित होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हर शैक्षिक कार्यक्रम सोईश्व होना चाहिए। हर्बर्ट ने भी नियोजन (Planning) को महत्व दिया है परन्तु हर्बर्ट और इयूवी के विचार में अन्तर यह है कि हर्बर्ट नियोजन के मूल को व्यापक के दायरे में दे देता है और सारे कार्यक्रम में व्यापक की प्रधानता रहती है जबकि इयूवी का सारा नियोजन बाल-केन्द्रित है। स्कूल के वातावरण को नियोजित बनाने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं।

(क) निर्देशन (Direction)—बालकों के हर कार्य को एक समुचित दिशा देनी चाहिए ताकि वह स्थिर हो और उनकी चालों का ध्यान न हो।



मे शिक्षण इसी विधि द्वारा होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि बंगल और मनन के स्थान पर शिक्षा में प्रयोगों का बाहुल्य हुआ। अमरीकी शिक्षा पर इसकी के दैशिक विचारों का व्यापक प्रभाव हुआ है और आज प्रयोगात्मक शिक्षा को ही वहाँ अधिक महत्व दिया जाता है।

### पाश्चात्य चिंतन का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव

इन समय पाश्चात्य दैशिक प्रभाव बड़ी तेजी में भारत पर प्रभाव डाल रहे हैं। उन प्रभावों को कुछ गोमात्रों के भीतर ग्रहण करने में जहाँ अधिग्रहण है, वहाँ उग्रे बिना गोपे-ममके ग्रहण करने में अपना अहित भी कर रहे हैं और इन प्रवृत्ति के कारण हमारे देश में अनेक दैशिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। इन सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ विचार प्रकट करना आवश्यक है।

### दैशिक मूल्यों में परिवर्तन

हमारे देश में शिक्षा का आदर्श बड़ा ऊँचा रहा है। यहाँ प्राचीन काल में शिक्षा का गोपा सम्बन्ध धर्म और आध्यात्म में रहा। मनुष्य के प्रकृत रूप में परिवर्तन करके उसका सत्कार-मुधार शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व रहा है। इसके फल-स्वरूप अति प्राचीन काल में भारतीय जाति में अनेक नर-रत्न उत्पन्न किये थे जिनकी पाक आज भी संसार मानता है। हमारा तमाम वैदिक, पौराणिक और माहित्यिक बाहुल्य इस बात का प्रमाण है। उन शिक्षा पद्धति में ऐसे लोगों को जन्म दिया था जिन्होंने वृत्तर भारत का निर्माण किया था। उन प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में भौतिक मुक्त की ओर से मनुष्य को विमुक्त करके उच्च सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदर्शों की ओर प्रेरित किया जाता था। पाश्चात्य शिक्षा के विचारों से प्रभावित होकर आज हम उन आदर्शों को छोड़ रहे हैं। आज यह कहा जाता है कि वे आदर्श पुराने पत्र गये हैं और शिक्षा को रोखी की ममदमाओं को हल करना चाहिए। विद्युत् केड़ से बर्षों में शिक्षा का सम्बन्ध 'रोजी कमाने' में भी नहीं हुआ, अब तो वह शिक्षा नीकरशाही का एक दोपक बर्ग तैयार करती जा रही है, इस नीकरशाही में स्वार्थपराता, चरित्र की निर्बलता और प्रणामन की अधमता है। आज देश में व्यापक रूप में चरित्र का संकट है। इस घोर संकट की घड़ी में हमें यह सोचना है कि पाश्चात्य भौतिक शिक्षा के मूल्यों में हमारे देश को लाभ हो रहा है या नहीं? हमें यह सोचना होगा कि इसकी का पृष्ठ प्रयोजनवादी और उपयोगितावादी शिक्षा-दर्शन हमारी समस्याओं को हल कर सकता है? क्या वह स्वयं अपने देशवासियों का हित करने में सफल हुआ है?

इसो, पेन्नालोंजी और इसुवी ने सामान्य जन की शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। इनके विचारों में प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्व बढ़ाया है। आज पाश्चात्य देशों में यह विद्वान प्रकट हो गया है कि शिक्षा पाला हर नागरिक का अधिकार है और राज्य को शिक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वहाँ शिक्षा को 'निवेश' (Invest-



ment) माना है। कुछ देशों में शिक्षा के 'राष्ट्रीयकरण' की माँग भी प्रचल है। यह प्रवृत्तियाँ हमारे देश में भी जड़ पकड़ रही हैं। हर ओर से माँग है कि शिक्षा पर अधिक से अधिक धन लगाया जाय पर हमारी बज्जिनाइयाँ हैं—एक तो हमारी आर्थिक तबीयतें विवश कर रही हैं परन्तु दूसरी ओर हमारे सामक यह पूरी तरह अनुभव नहीं करने कि शिक्षा का भार उठाना राष्ट्र की जिम्मेदारी है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के कार्यक्रमों को बड़ा महत्त्व नहीं दिया है, जो उसे दिया जा रहा है। ऐसी हालत में हमें यह गोपना चाहिए कि हमें वास्तविक प्रजातांत्रिक शिक्षा के आदर्शों को स्वीकार करना कहीं तक सम्भव है।

दूसरी बात शिक्षा का प्रसारवादी दर्शन हम भारतीयों के लिए बड़े प्रचोभन की वस्तु है। शिक्षा की समस्याओं को प्रायोगिक दृष्टि से हल करने के लिए हमने 'शोध' और प्रयोग का मार्ग अपनाया है। हम अपने मौलिक माधमों में आसीम पाठ्यों की प्राप्ति में जुटे हैं और कराँटों कराँट दान शोध कार्यों पर लगा रहे हैं। विशेष रूप से हमारी रचि लगी प्रकाश की सम्पुनित शिक्षा-प्रणाली, शिक्षण-तथ्य, पाठ्यक्रम का पुनः संगठन, पाठ्य-पुस्तक लेखन, धार्मिक कर्मशास्त्रों तथा पद्य-प्रदर्शन मेराओं की ओर बढ़ती जा रही है और यह सब बाँटें अमरीका में उधार लेकर हम अपने देश में लागू कर रहे हैं। इनमें अक्षय्याइयाँ हैं परन्तु इन प्रवृत्तियों को व्यापकतापूर्वक रूप से देखे के लिए और उनमें पुनः-पुनः माधम उठाये के लिए बिना माधमों की आवश्यकता है, उनके माधम हमारे पास नहीं हैं। यह यह हुआ है कि करोड़ों रुपयों की धनराशि बरबाद हुई है। यह एक महत्त्वपूर्ण बात समस्या के रूप में उभरती हुई है।

### नये शिक्षक विद्या-वत्साय

वास्तविक शिक्षा-दर्शन में 'आपदे-इव शिक्षा का महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जमा पञ्चासवीं, छेड़न तथा द्वावी इन सभी न हम बात पर जोर दिया है कि शिक्षा में आपका के शिक्षण, 'उनको प्रवृत्ति और विद्या' का विशेष स्थान होगा। इन शिक्षण न शिक्षण-विधियों और पाठ्यक्रम पर बहुत प्रभाव डाला है। मनोविज्ञान का विकास करने आपकों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत में इन 'आपदे-इव शिक्षा' को महत्त्व देना शुरू नहीं है। हमारे पास शिक्षणदर्शन, माधमरी, मनोविज्ञान और दार्शनिकता की आवश्यकता बढ़ती जा रही है परन्तु इन प्रकार की प्रवृत्तियों में केवल कुछ धन-सन्तानें लागू हो जा सकती हैं। लाभ उठाते हैं। उन करोड़ों माधमों के विकास का प्रयत्न हम नहीं कर रहे जा रहा है। वास्तविक प्रभाव में बढ़ती की शिक्षा में 'आपदे-इव' का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। आपका के शिक्षण, यह भी बढ़ती जा रही, बढ़ती बढ़ती शिक्षण बढ़ती जा रहा है। शिक्षण बढ़ती शिक्षा प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

हमारे देश में 'शिक्षक' की कल्पना कुछ और रही है। इस क्षेत्र में प्रायः बड़ी सोच आने लगे हैं, जो 'स्वायत्त-सेवा' की भावना में प्रेरित हो। इस भौतिक युग में 'स्वायत्त-सेवा' के पीछे मर मिटने की प्रवृत्ति नष्ट होती जा रही है। पाश्चात्य देशों में शिक्षण एक पेशा बन गया है, वह धन कमाने का एक माध्यम है। हम अपने आदर्श को यह बहुर धोड़ रहे हैं कि शिक्षक भूखा नहीं मर सकता। शिक्षक को जीने के लिए आवश्यक माध्यम तो चाहिए परन्तु हमारे शिक्षक केवल बेतन-भोगी बनने जायें और 'उनमें वर्तमान-भावना' नष्ट होती जाय, यह दुःख लक्षण नहीं है। अध्यापन एक पेशा बन गया परन्तु वेतन-संरक्षितता का भाव अध्यापक में जाग्रत न हो और दुनियाँ कामेन्द्रों में हटबार्ट के 'पंच भोगानों' वाली शिक्षण-पद्धति का अभ्यास कराया जाय परन्तु अध्यापकों में चिन्तन, मनन और अध्ययन की प्रवृत्ति को न विकसित किया जाय, तो माध्य के स्थान पर हानि होगी और यही हो रहा है।

हमने पाश्चात्य शिक्षा में कुछ 'नारे' (Slogans) लिये हैं, टीक उठी तरह में जैसे हमने राजनीति में 'प्रजातन्त्र', 'व्यक्तिगत स्वायत्त', 'समानता' और 'राष्ट्रीय एका' के नारे अनाये हैं। हमने शिक्षा में 'चलचित्र और रेडियो' का उपयोग (प्रचलन-प्रचारण), 'खेल-कूद तथा पाठ्य-प्रियाय', 'स्वास्थ्य की जाँच', 'पाठ्य-पुस्तकों की रचना आदि अनेक नारे भारतीय शिक्षा में लगाने प्रारम्भ कर दिये हैं परन्तु इनका हमारे नवयुवकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात की जाँच करने की आवश्यकता नहीं अनुभव की। इसी प्रकार हमारी शिक्षा में 'धर्म-निरपेक्षता' (Secularism) का नारा भी प्रचल है। इस देश में धर्म और शिक्षा का बहुत सम्बन्ध रहा है परन्तु हमने पश्चिम के प्रभाव में इस सम्बन्ध को तोड़ दिया। 'धर्म' का बहिष्कार करके हमने कुछ सोचा है, धर्म की अगती आत्मा को न पहचान कर हमने उसे 'सम्प्रदाय' समझ लिया है। विभिन्न सम्प्रदायों के अनुयायियों की एक-समान शिक्षा का कार्यक्रम भी हम नहीं बना पाये और न वर्तमान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एका और बेतन का विकास कर सके। पश्चिम का अध्यापकण करके और वहाँ के ज्ञान-विज्ञान को ही सब कुछ मान कर आज हमने देश में एक विदेशी भाषा की शिक्षा का माध्यम बना रखा है, जो अपने आप में एक बड़ी विस्फोटकारी समस्या है। संक्षेप में, हमने पाश्चात्य शिक्षा से 'कुछ' पाया है भी 'कुछ' ऐसी समस्या भी लड़ी कर दी है, जो इस नवोदित राष्ट्र के लिए रोग बन गयी है।

### समन्वय का प्रयत्न

अंग्रेजों के सामन्त-काल में जिस तेजी से वैश्विक प्रभावों का आगमन यूरोप से हुआ, उसमें यहाँ के कई महापुरुष चिन्तित हुए जैसे दयानन्द सरस्वती और निलक आदि। इन महान् आत्माओं का विचार था कि हमें अपनी भारतीय शिक्षा-पद्धति को



- भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला है ? स्कूलों के समाजीकरण के लिए भारत में क्या कार्यक्रम अपनाये गये हैं ?
९. आपको पाश्चात्य शिक्षा की विचारधाराओं का अध्ययन करने में क्या लाभ हुआ ? भारतीय शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में आप पाश्चात्य शिक्षक विचारों को कहीं तक ग्रहण करना उचित मानते हैं ?
१०. "जीवन की तैयारी" के रूप में शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में किन विद्वानों ने इस तत्त्व पर जोर दिया है ? उनके विचार स्रोतों में लिखिए।
११. निष्पाद्य शिक्षा का क्या अर्थ है ? १२ वर्ष तक के बालकों के लिए हस्तोद्धार तैयारी की गई निष्पाद्य शिक्षा की योजना का वर्णन कीजिए। यह योजना कहीं तक व्यावहारिक है ?
१२. पेस्तालोत्ती ने भाषा की शिक्षा को इतना अधिक महत्त्व क्यों दिया है ? भाषा सिखाने के लिए उसने किम विधि का प्रयोग किया ? कुछ उदाहरणों द्वारा इस विधि को स्पष्ट कीजिए।
१३. चरित्र के विकास में अध्यापन (Instruction) का क्या योगदान है ? हर्बार्ट द्वारा वर्णित अध्यापन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
१४. 'शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है।'—इयूबी के इस कथन का स्पष्ट करते हुए एक निबन्ध लिखिए।
१५. शिक्षा को ज्ञानार्जन का माध्यम किन यूरोपीय शिक्षाविदों ने माना है और क्यों ? बालकों को ज्ञानार्जन कराने में अध्यापक किन बातों का ध्यान रखेगा ?
१६. इयूबी ने बच्चों की शिक्षा में 'अनुभव' पर क्यों अधिक बल दिया है ? यदि आपको किसी विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना दिया जाय तो आप 'अनुभव' के तत्त्व को किम प्रकार दैनिक कार्यक्रम में प्रयोग करेंगे ?

राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

1. Give a brief sketch of the historical development of the Activity Movement in Europe and India (1961)
2. Explain the effects of western educational thought on the present day educational thinking in India. (1962)
3. Trace the evolution of educational thought in the West and show how far it can solve our educational problems today.



## अध्याय १८

### प्राचीन गुरुकुल प्रणाली और आधुनिक भारतीय शिक्षाविद्

#### गुरुकुलों के प्रति ध्यानाकर्षण

जब अंग्रेजों का सामन भारत में पूरी तरह खम गया तो उनका ध्यान यहाँ के निवासियों की शिक्षा की ओर गया। अपने देश में वे शिक्षा की प्रणाली का निर्माण कर रहे थे और उन्होंने यह उचित समझा कि अपने देश की शिक्षा प्रणाली ही यहाँ चलाई जाय। शासकों के अतिरिक्त यूरोप और विशेष रूप में इंग्लैण्ड में जाने वाले ईसाई धर्म-प्रचारकों ने भी भारत में शिक्षा का प्रचार करना आरम्भ किया और इन आदमों ने वे ईसाई धर्म में हिन्दू-मुसलमानों को दीक्षित करना चाहते थे। इन लोगों ने भी विदेशी शिक्षा-प्रणाली का सूत्रपात यहाँ किया। अंग्रेज सरकार और धर्म-प्रचारकों की शिक्षा-प्रणाली में भारतीय भाषाओं और मस्कुति की घोर अवहेलना हुई थी जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत अधिक संख्या में भारतीय अपने धर्म और मस्कुति से विमुख होने लगे।

यद्यपि पाश्चात्य शिक्षा के मोह से पड़ने वाले भारतीय जनो की संख्या कम न थी, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें भारतीय मस्कुति और प्राचीन शिक्षा की परम्परा के प्रति बड़ा प्रेम था। इनमें से स्वामी दयानन्द मन्मथी, ज्ञान महाधर तिलक, गीतानाथ टागोर, महात्मा गांधी, श्री अरविन्द और महर्षि कर्वे प्रमुख हैं। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के विषमग्र प्रभावों को समझा और उनका ध्यान भारत की प्राचीन गुरुकुल पद्धति की ओर गया। उन्होंने बढते हुए युग और परिस्थितियों को समझ कर उस प्रणाली में परिवर्तन करके नये प्रकार की शिक्षण-संस्थाएँ चलाई जो आज भी चल रही हैं। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रति हमारे मन में प्रबल आकर्षण है। महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व बुनियादी शिक्षा पद्धति का निर्माण किया था और यह आज्ञा की थी कि बुनियादी शिक्षा

ही परिवर्तन में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख भ्रम बनेगी परन्तु वास्तविक शिक्षा के अभावोद्घम यह बर हमने बुनियादी शिक्षा प्रणाली की दृष्टि बनायी। यही नहीं, बल्कि महापुरुषों ने शिक्षा ■ भारतीयता माने का प्रयास किया था, उस प्रक्रिया को हम मन्द करने जा रहे हैं। उनके द्वारा चलाई गई संस्थाओं में आज यह ध्वंसा नहीं है, जो उनके समय में थी। गुरुकुल कागड़ी, विद्वत् भारती तथा अन्य ऐसी ही संस्थाएँ अब वास्तविक अर्थ पर ध्वंस करने की दिशा में चल रही हैं। यह एक दुःख अनुभव है।

शिक्षा-प्रणाली का नेतृत्व हमारे मन में बड़ा संकल्प-विकास बन रहा है। हमारा कारण यह है कि हम वास्तविक दीक्षित विचारधारा के प्रति आकर्षित अवसर हैं परन्तु हमारे मन में प्राचीन दीक्षित प्रणाली के प्रति आदर की भावना गर्वका मन्द नहीं हुई है। हमारे सामने बाह्य-बाह्य यह प्रश्न उठ गया होगा कि हमारे लिए क्या अपनी दीक्षित परम्पराओं को स्थापित करना उचित और उपयोगी है, या कि उनका क्षीर पीने की योजना ही है। राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग ने, जिसमें भारतीय शिक्षाविद् के साथ-साथ विदेशी शिक्षा-विशेषज्ञों ने काम किया है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के महत्व को स्वीकार किया है और पुराने दीक्षित आदर्शों को स्वीकार करने की संझुति दी है। हमने स्पष्ट है कि पुरानी शिक्षा-प्रणाली और विद्वत् रूप में गुरुकुल प्रणाली के प्रति हमारे शिक्षाविद् के मन में आकर्षण मौजूद है। यही कारण है कि हम भारतीय तथा वास्तविक दीक्षित आदर्शों के बीच समन्वय करना चाहते हैं।

### गुरुकुल प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारतीय शिक्षा का उत्कृष्ट रूप है। निरवयव ही इसके उत्कृष्ट रूप का विकास समय और समय के घेरे में बन कर ही हुआ होगा। जैसा कि हमका नाम है, यह प्रणाली 'गुरु' के प्रणाली में हुई होगी। ज्ञान तथा अनुभव में श्रेष्ठ विद्वानों को 'गुरु' का नाम दिया गया था। यह महान् आत्माएँ अपना जीवन ज्ञान और सत्य की खोज को अर्पित कर देती थी। इनका 'स्व' समाज के प्रति उनकी कल्याण भावना में विलीन हो जाता था। अतः समाज इनके प्रति अगाध श्रद्धा रखता था और इनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखने के साथ-साथ नयी नवजवान पीढ़ी की शिक्षा-दीक्षा का भार इनकी सौंप देता था। इन विद्वानों ने शिक्षा देने की एक परम्परा डाली। वे छात्रों को अपने घरों पर बुला कर ही पढ़ाते थे। शिक्षा अधिक से अधिक प्रभावशाली बन, इसलिए वे छात्रों को अपने परिवारों में ही रख लेते थे। छात्र उनके यहाँ घर पर विद्यार्थी जीवन व्यतीत करते थे। चूँकि यह महान् शिक्षाविद् निस्पृह जीवन बिताते थे, इसलिए वैभवपूर्ण नगर के जीवन के प्रति उनके मन में विराग होता था और वे नगरों में बाहर अपने आश्रम स्थापित करके रहते जहाँ अधिक गरुवा में छात्रों को रहने में सुविधा होती थी। धीरे-धीरे यह शिक्षा-प्रणाली 'गुरुकुल' प्रणाली के रूप में विकसित हो गयी।

भारतीय साहित्य जैसे महाकाव्यों, पुराणों तथा जादूशानों में अनेक 'गुरुकुलों' का जिक्र आता है। प्रत्येक गुरुकुल के साथ किसी एक मनीषी विद्वान् का नाम जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, 'रामायण' में वर्णित विश्वामित्र के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके राम-लक्ष्मण ने रावण जैसे आततायियों का वध किया था। श्रीमद्भागवत में मान्दीपनि ऋषि के गुरुकुल का उल्लेख है जहाँ राजवशी कृष्ण ने निर्धन गुदामा के बेटे साथ रहकर शिक्षा पायी। महाभारत में धौम्य ऋषि के गुरुकुल का वर्णन है जिसमें अरुण और उपमन्यु जैसे आदर्श विद्यार्थी रहे थे। महाभारत की कथा में द्रोणाचार्य का प्रसंग है, जिन्होंने अपना गुरुकुल इस्तिनापुर नगर के पास बनाया था और कौरवों तथा पांडवों को युद्ध-कौशल सिखाया था। इन गुरुकुलों के कुलपतियों में वसिष्ठ, परशुराम, विश्वामित्र, कण्व, वाल्मीकि तथा धौम्य आदि भारतीय साहित्य में सदा अमर रहेगे। इन गुरुकुलों में शिक्षा पाए हुए विद्वानों और वीरों की कथाएँ भी उनकी ही महत्त्वपूर्ण हैं। गुरु-मेधा और अनुमानन के अद्वितीय उदाहरण यहाँ के छात्र प्रस्तुत करते थे। उदाहरण के लिए, द्रोणाचार्य की इच्छा-पूर्ति के लिए अर्जुन अकेले द्रुपद में युद्ध करके उन्हें बन्दी बनाकर ले आने है, उनका भीम निष्य एकत्रण उनके आदेश पर अपना अश्व दौड़ा काट कर दक्षिणा के रूप में दे देना है, कर्ण परशुराम की निद्रा के समय अपनी जीभ पर में मूँही हटाना यद्यपि उनकी जीभ को एक भयंकर कीड़ा काटता रहता है, आरणि धौम्य ऋषि के बचनों को आशीर्वाद मान कर भयंकर वरमात में सेन का पानी रोकने के लिए मेड़ बनकर सेटा रहता है और उपमन्यु बिना कुछ लाग-पिये गायों को चराना फिरना है। मक्षेप में, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का इतिहास अत्यन्त उज्ज्वल है।

गुरुकुल प्रणाली की विशेषताएँ—गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की अद्वितीय सफलता का कारण उसकी कुछ विशेषताएँ हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। यह विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(१) गुरुकुल प्रणाली में सावामीय शिक्षा का होना उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यद्यपि अंग्रेजों के यहाँ पब्लिक स्कूलों में 'सावामीय' शिक्षा है अर्थात् छात्रों के लिए, यही स्कूल के प्रागण में स्थित छात्रावासों में रहना आवश्यक होता है, फिर भी गुरुकुल में छात्रों का निवास अपनी असल विशेषता रखता है। भारतीय गुरुकुलों में छात्र उभी प्रकार विकास करता था, जैसे वह अपने घर में रहता हो। यहाँ रहकर उसे स्नेह का अभाव कभी नहीं रहता था। वह अपने गुरु और गुरुपत्नी में वही स्नेह पाता था, जो माता-पिता में मिलता है। इन गुरुकुलों में दंड, दमन और नियंत्रण के साथ-साथ विनाशिता के वे दोष नहीं थे जो वर्तमान पब्लिक स्कूलों में पाए जाते हैं।

(२) गुरु-शिष्य का आदर्श सम्बन्ध गुरुकुल प्रणाली की दूसरी प्रमुख विशेषता थी। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच पिता-पुत्र का सम्बन्ध था। शिक्षक अपने छात्र



के साथ कभी दुर्घट्यहार नहीं करता था, यद्यपि वह समय-समय पर उसके आचरण की कठोर परीक्षा लिया करता था। आज विद्यालयों में त्रिम प्रकार की अनुशासन-हीनता और दुर्भावना छात्रों में दिखाई देती है, उसका गुरुकुलो में सर्वथा अभाव था। अध्यापक के स्नेहसिक्त हृदय में छात्र के प्रति हिन कामना वर्तमान रहती थी। हर छात्र को 'द्विज' कहा जाता था। 'द्विज' वह है त्रिमका दो बार जन्म होता है, छात्र एक बार माता-पिता से पैदा होता है परन्तु वह दुबारा अध्यापक के द्वारा भी पैदा होता है। अथर्ववेद में सूत्र है—आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भयन्त अर्थात् जब छात्र को गुरुकुल में अध्यापक के पास ले जाया जाता है तो आचार्य उसे पुन अपने गर्भ में धारण करता है। तात्पर्य यह है कि अध्यापक छात्र को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि अध्यापक छात्र को पुत्रवत् माने।

(३) गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक न था। यहाँ छात्र को सत्य का अनुभव कराया जाता था। आज यह कहा जाता है कि गुरुकुलों की शिक्षा धर्म-प्रधान थी और आध्यात्मिकता के सत्त्वों की अधिकता के कारण वह वर्तमान जीवन के अनुकूल नहीं है। यह आलोचना अनुचित है। यदि शिक्षा का अर्थ संस्कार है, या फिर शिक्षा वह है जो मनुष्य को मुक्त करती है (या शिक्षा या विमुक्तये) तो निश्चय ही उसे ज्ञान-प्रधान होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ पुस्तकों की रट्टाई नहीं है। 'ज्ञान' हमारे जीवन में सट्टखना, चिन्तन और निस्पृह भावना उत्पन्न करता है और प्लेटो के राज्यों में ज्ञानदायिनी शिक्षा 'दार्शनिक राजा' (Philosopher king) पैदा करती है। ऐसी ही शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और छात्र में यह योग्यता पैदा हो जाती थी कि वह उचित-अनुचित, सत्य-असत्य की जाँच करने लगता था। उस शिक्षा की आवश्यकता इस समय कहीं अधिक है।

(४) गुरुकुलों में व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ बौद्धिक शिक्षा दी जाती थी। छात्रगण आचार्य के साथ विविध स्थानों की यात्रा करते थे। वे नगरी, राज-मन्नाओं, तीर्थ स्थानों, स्वयंशरी और उत्सवों में अपने आचार्य के साथ उपस्थित होते थे और अनुभव करते थे। विद्वामित्र अपने शिष्यों—राम और लक्ष्मण को जनकपुर में होने वाला सीता के स्वयंवर में ले जाने हैं और वहीं उन दोनों का विवाह हो जाता है। जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान छात्रों को अनुभव के द्वारा कराया जाता है। हिन्दी के उपन्यासकार श्री भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'चित्रलेखा' में एक महत्व-पूर्ण संक्षिप्त प्रदत्त पर प्रकाश डाला गया है और वह यह है कि ज्ञान को अनुभव की बमोटी पर गढ़ना पड़ता है। आचार्य रत्नगिरि अपने दो शिष्यों—स्वैताक और बिगावदेन को पाप-पुण्य का सांख्यिक अर्थ समझाने के लिए बीजगुण और कुमारगिरि योगी के पाप ले जाने हैं। दोनों शिष्यों को विविध अनुभव यह होता है कि रिगाव और वैभव के बीच पुण्य हो सकता है और लोभन में पाप। उपन्यास के अन्त में आचार्य अपने शिष्यों को गरीब निरक्षर किसानों में सहायता देना है।

नी के कई उद्देश्य थे। गुरुकुल में सभी प्रकार के छात्रों के बीच भेदभाव के लिए पद-मर्यादा का ध्यान रने बगैर हर छात्र को शिक्षा माँगनी पड़ती। ऐसे छात्रों का मिथ्या गर्व दूर होना और उनमें विनय का गुण पैदा होना। वे उन्हें यह भी अनुभव होना था कि वे समाज के श्रेणी हैं। विद्यार्थी जीवन में भरण-पोषण समाज में प्राप्त होता है और शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें रण को चुकाना है। 'शिक्षा' लेना छात्रों के हित में था तो शिक्षा देना समाज में भी। समाज को यह अनुभव होनी था कि शिक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारी गुरुकुल समाज के लिए उत्तम प्रकार के नागरिक तैयार करता था तो समाज उसी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता था।

गुरुकुल का ह्दय—ऊपर गुरुकुल प्रणाली का उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत किया है। उस प्रणाली में भारतीय समाज को उन्नति के गिरर पर पहुँचाया था। गुरुकुल आगे चलकर इसका ह्दय आरम्भ हो गया। महाभारत काल में ही यह प्रिया आरम्भ हुई। महाभारत की कथा में हम पढ़ते हैं कि गुरुकुल नगर के निकट जाने लगे। द्रोणाचार्य का गुरुकुल हस्तिनापुर के निकट स्थापित हुआ। आचार्य राजाओं का बेटन-भोगी भूय बन गया था। द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, एकलव्य और कर्ण के प्रति उनका उघेसा भाव इस बात का प्रमाण है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य अन्धाय को जानने हुए भी दुर्बोधन का पक्ष लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसके पिता का अप्र स्वाया था। स्पष्ट है कि गुरुकुल की स्वतन्त्रता और आचार्य की महत्ता में गिरावट आने लगी थी। यह ह्दय की प्रक्रिया निरन्तर चलती रही और भारत के ऐतिहासिक सम्राटों के काल में, ऐसे गुरुकुलों का जीवन लगभग समाप्त हो गया। जब किसी देश की शिक्षा-प्रणाली निर्जीव हो जाती है तो उस देश की शक्ति नष्ट होने लगती है। भारत में ऐसा ही हुआ। लगभग एक हजार वर्षों से भारत बार-बार घानुओं के द्वारा पददलित हुआ और प्राचीन काल के गौरव को गँवो बैठा। इसका कारण भी स्पष्ट है अर्थात् उसने शिक्षा की शक्तिसाली प्रणाली की उपेक्षा की जिससे सामान्य जनो का मनोबल घटता रहा।

**वर्तमान भारत की आवश्यकताएँ तथा उनके अनुरूप गुरुकुल प्रणाली का संशोधन**

हम पढ़ते वक्ता चुके हैं कि हमारे देश के कुछ आधुनिक शिक्षाविदों ने गुरुकुल प्रणाली के पुनरुद्धार की आवश्यकता अनुभव की और इस प्रणाली की विशेषताओं का समावेश अपनी शिक्षा पद्धतियों में किया। उनमें स्वामी दयानन्द सरस्वती, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और आचार्य कर्वे प्रमुख हैं। इन मभी ने गुरुकुल को महत्त्वपूर्ण समझा परन्तु स्वामी दयानन्द को छोड़कर किसी ने भी विशुद्ध गुरुकुल प्रणाली को अपनाना उचित नहीं समझा। उन्होंने यह स्पष्ट समझा कि वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। स्वयं स्वामी दयानन्द



इस प्रणाली के कई उद्देश्य थे। गुरुकुल में सभी प्रकार के छात्रों के बीच भेदभाव न रहे, इसलिए पर-मर्यादा का ध्यान रखे वगैरह छात्र की शिक्षा मांगनी पड़ती थी। इसमें छात्रों का मिथ्या गर्व दूर होता और उनमें विनय का गुण पैदा होता। साथ ही उन्हें यह भी अनुभव होता था कि वे समाज के ऋणी हैं। विद्यार्थी जीवन में उन्हें भरण-पोषण समाज में प्राप्त होता है और शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें इस ऋण को चुकाना है। 'मिक्षा' लेना छात्रों के हित में था तो भिक्षा देना समाज के हित में। समाज को यह अनुभव होनी था कि शिक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। गुरुकुल समाज के लिए उत्तम प्रकार के नागरिक तैयार करता था तो समाज गुरुकुलों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता था।

गुरुकुल का ह्रास—ऊपर गुरुकुल प्रणाली का उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत किया गया है। उस प्रणाली में भारतीय समाज को उन्नति के निसर पर पहुँचाया था परन्तु आगे चलकर इसका ह्रास आरम्भ हो गया। महाभारत काल में ही यह प्रक्रिया आरम्भ हुई। महाभारत की कथा में हम पढ़ते हैं कि गुरुकुल नगर के निकट आने लगे। द्रोणाचार्य का गुरुकुल हस्तिनापुर के निकट स्थापित हुआ। आचार्य राजाओं का बेटन-भोगी भूषण बन गया था। द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देने थे, एकलव्य और कर्ण के प्रति उनका उपेक्षा भाव इस बात का प्रमाण है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य अभ्यास को जानते हुए भी दुर्वोधन का पक्ष लेते हैं क्योंकि उन्होंने उनके पिता का अप्र त्यागा था। स्पष्ट है कि गुरुकुल की स्वतन्त्रता और आचार्य की महत्ता में गिरावट आने लगी थी। यह ह्रास की प्रक्रिया निरन्तर चलती रही और भारत के ऐतिहासिक सम्राटों के काल में, ऐसे गुरुकुलों का जीवन लगभग समाप्त हो गया। जब किसी देश की शिक्षा-प्रणाली निर्जीव हो जाती है तो उस देश की शक्ति नष्ट होने लगती है। भारत में ऐसा ही हुआ। लगभग एक हजार वर्षों में भारत बार-बार शत्रुओं के द्वारा पददलित हुआ और प्राचीन काल के गौरव को लो बँठा। इसका कारण भी स्पष्ट है अर्थात् उसने शिक्षा की शक्तिशाली प्रणाली की उपेक्षा की जिससे सामान्य जनो का मनोबल घटना रहा।

**वर्तमान भारत की आवश्यकताएँ तथा उनके अनुरूप गुरुकुल प्रणाली का संशोधन**

हम पहले बताना चुके हैं कि हमारे देश के कुछ आधुनिक शिक्षाविदों ने गुरुकुल प्रणाली के पुनरुद्धार की आवश्यकता अनुभव की और इस प्रणाली की विशेषताओं का समावेश अपनी शिक्षा पद्धतियों में किया। उनमें स्वामी दयानन्द सरस्वती, रवीन्द्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी और आचार्य कर्वे प्रमुख हैं। इन सभी ने गुरुकुल को महत्वपूर्ण समझा परन्तु स्वामी दयानन्द को छोड़कर किसी ने भी विस्तृत गुरुकुल प्रणाली को अपनाना उचित नहीं समझा। उन्होंने यह स्पष्ट समझा कि वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। स्वयं स्वामी दयानन्द

ने भी 'वर्तमान' की पूर्ण रूप में उपेक्षा नहीं की बल्कि यह चिन्ता की कि प्राचीन वैदिक शिक्षा आधुनिकता के गाँवे में फिट हो जाय।

### स्वामी दयानन्द द्वारा अनुमोदित शिक्षा-प्रणाली तथा गुरुकुल

स्वामीजी के शैक्षिक विचारों का मूल—स्वामी दयानन्द ने 'वेदों' का ज्ञान अपनी कुल परम्परा और अपने दीर्घ अध्ययन में प्राप्त किया। उन्होंने ५ वर्ष में काम की आयु में ही वेदों के मंत्र और वेद भाष्य के अग्न बन्धन का निषेध। ८ वें वर्ष के बाद उपनयन संस्कार होने पर उन्होंने यजुर्वेद का अध्ययन किया। १४ वर्ष की आयु तक उन्होंने व्याकरण और पाठ्यरूपवाची और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मरुतन के भाषा तत्वों और उत्तमोत्तम ग्रन्थों पर पूर्ण अधिकार पाने के लिए काशी जाने की इच्छा से पूरी न कर मके परन्तु २१ वर्ष की आयु में वे अश्वत्थ, निम्न, निषण्ड, पूर्व भीमामा और यजुर्वेद में पारंगत हो गये। फिर भी वे मनुष्य नहीं हुए। गृहत्याग के बाद अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए दयानन्द ने प्रसिद्ध विद्वानों से प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया और अन्त में मथुरा आकर आर्य-ग्रन्थों के प्रबल समर्थक और अद्भुत प्रतिभा-सम्पन्न स्वामी विरजानन्द के साथ रहकर लगभग ६-७ वर्ष तक वैदिक साहित्य का अध्ययन करके पूर्णतया निष्णान हो गए।

स्वामी दयानन्द के संस्कार और उनकी शिक्षा-दीक्षा विशुद्ध रूप में प्राचीन आर्य साहित्य द्वारा सपोषित थे। इसलिए प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के प्रति आस्था होना स्वाभाविक था। साथ ही हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि वे कूपर्मक न थे। केवल वेदादि का अध्ययन करने ने ही वे प्राचीन शिक्षा के अन्धभक्त नहीं बन गये। उन्होंने भारत की वर्तमान अधोगति की अपनी आँखों से देखा और हिन्दू जाति के पतन के कारणों की अच्छी तरह समझकर प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में प्राण प्रविष्टा करना ही देश के कल्याण का एकमात्र उपाय समझा। हर महान् सुधारक और चिन्तक की तरह स्वामीजी ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया। उनका विचार था कि शिक्षा के माध्यम से इस भूमि में निवास करने वाले सभी निवासियों का कल्याण हो सकता है।

स्वामीजी के शिक्षा सम्बन्धी विचार—स्वामी दयानन्द ने अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन करते समय देश और काल के वृहत् सदर्भ पर पूरी तरह ध्यान रखा। उन्होंने देखा कि भारत में अनेक प्रकार के धर्म और सम्प्रदाय हैं जो परस्पर विरोधी हैं। हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, पारसी—इन सबमें बना समाज तीव्र भेदों के कारण गुणवृद्धि नहीं हो सकता तथा निरन्तर विदेशियों के अधीन बना रहेगा। स्वयं हिन्दू धर्म भी अनेक भ्रम-मतान्तरों में बँटा है। साथ ही अंधविश्वास और कुरीतियों ने हिन्दू जाति की नीच को खोखला बना दिया है और हमारे आक्रमणकारी धर्म जो विदेशों की उपज है, भारत में प्रतिष्ठित होकर हिन्दुओं को अपने में आत्ममात् करने जा रहे हैं। इन सब दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने भारत की

प्राचीन अभ्युन्नय रत्नराशि वेदों की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा के करने लगे और इस कार्य के लिए वे शिक्षा को साधन बनाने लगे। विद्याध्ययन के बाद ही अपनी विचारधारा के प्रसार और प्रचार के लिए जहाँ भी वे गये, उन्होंने वैदिक पाठशालाओं को बनाया। स्पष्ट है कि वे प्राचीन आर्य ग्रन्थों की शिक्षा का ही देश के उद्धार का मूल साधन मानते थे।

(क) वैदिक शिक्षा का महत्त्व—स्वामीजी वेदों को अनौपेय मानते हैं। शिरोधार्य रूप में वेदों का गहिना भाग ईश्वरवृत्त है। मनुष्यवृत्त समस्त साहित्य भूषा है और उन्नी के कारण अनेक यत्न-मगान्तर पैदा हो गए हैं। इसलिए जो समाज वेदों की शिक्षा ग्रहण करेगा, वही सत्य का पोषक होगा। दूसरे, उनका विचार है कि समस्त ज्ञान-विज्ञान का स्रोत वेद है। अरविन्द घोष ने भी दयानन्द के विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि वेदों में ज्ञान-विज्ञान अपनी पूर्णता के साथ वर्तमान है। स्वामीजी ने वेद-साहित्य की श्रेष्ठता को स्वीकार करके कहा है कि हमें वेदों की ओर लौटना होगा। यदि वेदों को स्वीकार कर लिया जाय तो हमारे मानवमात्र में एकता भी स्थापित हो सकती है। उनके मन में वेदज्ञान सम्पूर्ण व्यक्ति, चाहे किसी सम्प्रदाय का हो, आर्य है। अन्तु, उनका आर्यसमाज केवल हिन्दुओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मावलम्बियों के लिए ब्राह्म है। स्वामीजी ने अधविश्वास और कुप्रथाओं का खंडन किया है, चाहे वे किसी सम्प्रदाय की हों। वैदिक शिक्षा द्वारा सत्थानुराग पैदा किया जा सकता है। इसी के द्वारा सभी वेदों को नष्ट करके मानव-समाज में एकता पैदा की जा सकती है।

स्वामीजी ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध इसलिए किया कि वह किसी प्रकार भी प्रगतिशील नहीं करी जा सकती। पाश्चात्य शिक्षा भौतिकता प्रधान है और वह सम्पत्ता की पहली सीढ़ी के अनुकूल है। इसके विपरीत, भारत में आध्यात्म का विकास हो चुका है और भारतीय शिक्षा में आध्यात्म के तत्त्वों की प्रधानता होनी चाहिए परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे सामने जो कुछ वर्तमान है, उसकी उपेक्षा होनी चाहिए। वैदिक शिक्षा में आधुनिकता का समावेश करके भारतीय शिक्षा को समर्थ बनाया जा सकता है—यैसा विश्वास दयानन्द का था।

(ख) वैदिक शिक्षा का स्वरूप—भारत में वेदों का अध्ययन-अध्यापन स्वामीजी ने पहले प्रचलित था परन्तु उस अध्ययन से समाज का कोई लाभ नहीं होता था। पंडित और ब्राह्मण वैदिक ग्रन्थों को पढ़ने, रटते, शास्त्रार्थ और वाद-विवाद करते परन्तु उन ज्ञान का मानव समाज को कोई लाभ नहीं मिलता था। व्यक्ति के आचरण और व्यवहार पर भी वेदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यदि ऐसा होता तो भारत का पतन न होता। दूसरे, वेदों का ज्ञान कुछ छोटे से लोगों तक सीमित रह जाता था। स्वामी दयानन्द वेदों की शिक्षा हर एक को देने के पक्षपाती थे। उन्होंने उन पुराने विचारों का खंडन किया जिनके अनुसार दूतों और स्त्रियों के लिए वेदों की शिक्षा वर्जित थी। उनका कहना था कि दूत और स्त्रियाँ भी वेद पढ़ने के अधिकारी

है। स्वामीजी कितने प्रगतिशील थे, इसका अनुमान उनके तर्क में लगना है। स्थियों और दूतों को वैदिक शिक्षा में वचन करके भारत के बहुत बड़े समाज की निष्प्रिय बनाना उनके समान व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक ज्ञान मस्कृत भाषा में था जो अब भारत में धीरे-धीरे जड़भूत होती जा रही थी। स्वामीजी ने पहले हिन्दी ने भी इन बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रचलित भाषाओं का प्रयोग वैदिक शिक्षा के लिए किया जाय। उन्होंने पहले संस्कृत की शिक्षा का माध्यम बनाने का निश्चय किया परन्तु व्यावहारिक कहानियों को समझ कर और ब्रह्म समाज के नेता केदारबद्ध मेन के परामर्श में हिन्दी की शिक्षा का माध्यम बनाने का निश्चय किया। हर एक को वेदों का ज्ञान हो और वह मस्कृत के माध्यम में हो—यह कभी भी सम्भव न हो सकता था। इसलिए स्वामी दयानन्द ने धर्माध्यवाद का आश्रय लिया।

स्वामीजी वैदिक शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनका विश्वास था कि वेदों का ज्ञान प्राप्त करने में आचरण और व्यवहार पर अवश्य प्रभाव पड़ना चाहिए। उन्होंने शिक्षा और चरित्र-निर्माण के सम्बन्ध पर बल दिया। इसलिए मध्य और उच्च-अनुचित का प्रमाण वेदों की रीतिरिवाज के प्रमाण सत्यार्थप्रकाश में ४ बनाए गये हैं—वेद, वेद-सम्मान स्मृति, वेदविहित व्यवहार जो महापुरुष करते आए हैं, और अन्नगत्ता। वेदों में मानवीय आचरण के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह शाश्वत सत्य है परन्तु शिक्षा की दृष्टि से उनकी तबीयत और देश-काल के अनुकूल व्याख्या करना दयानन्द ने आवश्यक समझा। उदाहरण के लिए, 'धर्म' का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि धर्म केवल एक पूजा-उपासना या कर्मकाण्ड नहीं है; धर्म मनमा बाधा कर्मणा सदाबद्ध होकर स्थायीचित्र व्यवहार करना है। 'अर्थ' का तात्पर्य धर्माधर्म का विचार किये बिना धन-संग्रह करना नहीं बरन् नैतिक दृष्टि से धनार्जन करना है, अन्याय और धूर्तता से पैदा किया गया धन 'अनर्थ' है। उन्होंने 'वर्ण' और 'आश्रम' का आधार योग्यता बताया। 'देव' का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान और जानी हो। उन्होंने 'अग्निहोत्र' का समर्थन स्वास्थ्य विज्ञान के आधार पर, यज्ञ और धर्मयात्रा का समर्थन समाजशास्त्र और राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया। इन प्रकार स्वामीजी ने वैदिक साहित्य की अनेक मान्यताओं की नई व्याख्या करके शिक्षा में प्राति पैदा की।

वैदिक शिक्षा केवल कर्मकाण्ड की शिक्षा नहीं रही, जैसा कि पहले था। स्वामी दयानन्द ने उसे चरित्र की शिक्षा का रूप दिया। अपनी शिक्षा में उन्होंने १२ यमों का अन्याय आवश्यक बताया, वे हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अमरग, हो, असचय, आश्रित्य, ब्रह्मचर्य, मीन, स्वर्ग्य, क्षमा और अमय। यह गुण मानवीय चरित्र की दृढ़ आधारशिला हैं। पादचात्य शिक्षा साहित्य में, इन सबकी इनकी मूढ व्याख्या शायद हो उपलब्ध हो सके। दयानन्द द्वारा वर्णित शिक्षा के यह मुख्य भारत की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति में गहायक हो सकते हैं। इस समय भारतीय समाज में हिमा,

भूठ, चोरी, लपटता, निर्भयता, उपयोगी बस्तुओं का मन्त्र और चोरबाजारी, ईश्वर-चिन्तन का अभाव, कामुकता और अश्लिष्टता, व्यर्थ की बकवास, अश्विचरता, बदने की भावना और अथ आदि दुर्गुण पनप रहे हैं और अब में १०० वर्ष पूर्व महापद्म दयानन्द ने इन बातों को समझकर वैदिक शिक्षा का समर्थन किया था। यदि आज भी उन पर ध्यान कर लिया जाय तो देश की सारी समस्याएँ हल हो सकती हैं।

(ग) शिक्षा का संगठन—स्वामी दयानन्द पुर्ण विचारों के लक्ष्मिवादी व्यक्ति न थे। उनकी प्रगतिशीलता का परिचय उनके शिक्षा-मन्त्रों में स्पष्ट रूप से मिलता है। वे आधुनिक विचारों की तरह मानते थे कि राज्य की शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्राथमिक स्तर में लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए। वे यह भी मानते थे कि शिक्षा की प्रक्रिया बड़ी व्यापक है। इसका आरम्भ मनुष्य के गर्भ में आने ही हो जाता है। इसलिए बच्चों की शिक्षा में माता-पिता का गम्भीर उत्तरदायित्व उन्होंने माना है। सत्यार्थप्रकाश में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि माता का चरित्र गर्भस्थित बच्चे के चरित्र पर प्रभाव डालता है। इसलिए बच्चे का लाज-शालन गर्भ में प्रारम्भ सम्भूत चाहिए। गर्भाधान के बाद और पहले भी माता-पिता को सहायक और अनास्तिक भोजन जो बाल-विकास पर पुनर्भाव डालते हैं, नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने भोजन में घृह दूध, मिष्ठान तथा पीस्टिक पदार्थ रखना चाहिए, जो बच्चे के स्वास्थ्य, शक्ति, बुद्धि तथा चारित्रिक गुणों के विकास में सहायक हो। जन्म के बाद माता शिक्षा दे, बच्चे को मुदुभाषी, वितकी, शिष्ट, मुद उच्चारण में पटु और मयमी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन सब बातों में स्पष्ट है कि स्वामीजी मनोविज्ञान के आधुनिक सिद्धान्तों, जैसे वृत्तानुक्रम और वातावरण, के महत्व में पूर्ण-परिचित थे। इनसे उनकी अप्रगतिशीलता ही मिट जाती है।

प्राचीन काल में जिस प्रकार गुरुकुल नगरी में दूर जगहों में स्थित थे, उसी प्रकार आजकल भी विद्यालयों की नगरी में दूर रहने का समर्थन स्वामीजी करते थे। सम्भूत वे केवल अनुकरण के लिए ऐसा करना उचित नहीं समझते थे। उन्होंने यह देखा था कि अजकल के कोलाहलपूर्ण तथा उर्ध्व-प्रधान सम्भूत के कारण दूषित नगरी में विद्यालयों की दूर रहना कहीं अधिक आवश्यक है। कच्ची आयु के बालकों की शहरों की विनाशिता और कामुकता किन्तु प्रकार भ्रष्ट करने वाली है, इन बातों को आज हर आम व्यक्ति समझता है। छात्रों में बढती हुई अनुशासनहीनता और अपराधवृत्ति इन बातों का प्रमाण है। आज भी पब्लिक स्कूलों और मातामयी विद्यालयों को, जो नगरी में बाहर स्थित होते हैं, अच्छा सम्भूत जाना है। अमरीका और रूस जैसे प्रगतिशील देशों में—विद्यालय नगरी में बाहर स्थित होते हैं और छात्रों के लिए सुन्दर मातामयी की व्यवस्था करके उन्हें धान वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। यतः स्वामीजी ने प्राचीन गुरुकुलों के आदर्श को अपनाने में इन सभी बातों पर विचार किया। दूरी बात की 'ब्रह्मचर्य' की, जिसके कारण विद्यालयों की नगरी में





विज्ञान का व्यावहारिक ढंग में शिक्षा के द्वारा विकास करके, गोरक्षात्मक देशों में हर क्षेत्र में आगे जाने का प्रयत्न वे हन नहीं कर सकते थे। यह काम तो उन लोगों का है, जो उस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान-विज्ञान का विकास कर सकते हैं, उन्होंने केवल रास्ता दिखाया है।

### रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गुरुकुल

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का विचार था कि भारत की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का एकमात्र हल 'तपोवन आश्रम' के पुनरुद्धार में प्राप्त हो सकता है। उन आश्रमों का वह महान् आदर्श—गांधी जीवन उच्च विचार—कविबर्ग को निर्लज्ज प्रेरणा देता रहा। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है—

"जंगलों में निवास करने वाले धोष्ठ शिक्षकों की स्मृति अब भी हमारे मनों में निवास करती है। आधुनिक मद्रासियों के अर्थ में उन शिक्षकों के नरोदन न तो स्कूल थे और न मठ। जिस प्रकार मूल्य ग्रहों को वसपूर्वक धारण करना है, उसी प्रकार वे प्रकाश और ज्ञान के केन्द्र थे।" (Gardener)

विश्वभारती पत्रिका न० १० में गुरुदेव ने लिखा है कि शान्ति निकेतन में बना उनका विद्यालय प्राचीन गुरुकुल की प्रतिलिपि है। वे कहते हैं—“अपने बालकों को आध्यात्मिक मस्कुनि प्रदान करना ही शांति निकेतन स्थित स्कूल की चमत्ता मेरा उद्देश्य है। अपने मन में ऐसे स्कूल का विचार रखते हुए जो घर भी हो और मन्दिर भी हो, मैंने यह स्थान चुना जो नगर की समस्त विहूलियों से दूर है और उस पवित्र जीवन की स्मृतियों में व्याप्त है जो ईश्वर की गता में एकात्मकता रखते हुए बहुत पढ़ने बिताया जाता था।”

रवीन्द्रनाथ का उन प्राचीन गुरुकुलों के प्रति आकृष्ट होने का कारण यह था कि उनमें आध्यात्मिकता का वातावरण था और वर्तमान शहरी स्कूलों के दूषित वातावरण में बालकों की जो दुर्दशा होती है, उसमें वे पूरी तरह अवगत थे। उनका विचार था कि जब तक बालक ऐसे प्रभावों के बीच में रहते हैं, जो उन्हें सत्य के मार्ग में विचलित करते हैं, उन्हें शिक्षा देने का प्रयत्न करना मूर्खता है। इस सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ के विचारों का उल्लेख करते हुए श्री जे० चट्टोपाध्याय ने (रवीन्द्रनाथ और उनका आश्रम-स्कूल) कहा है कि वे पुराने गुरुकुल के प्रशंसक इमीलिए थे कि गुरुकुल शहरों से दूर स्थित होने थे। शहरों के संघर्षपूर्ण जीवन में स्वार्थपरता और दृष्टिमत्ता से विनाशितापूर्ण जीवन बिताने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए बालकों को वहाँ से हटाने ऐसी जगह रखना आवश्यक है जो उनके विकास के अनुकूल हो, जहाँ उनका आध्यात्मिक वन बढ़ाने की सम्भावनाएँ हो और मानवीय सृष्टि के बहुमुख्य मन्त्रों का उन्हें बोध हो सके।

गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य और धर्मपालन पर जिस प्रकार बल दिया जाता था, वह रवीन्द्रनाथ का बहुत पर्वद था। वे परीक्षा पाम करने मात्र को शिक्षा नहीं

मानने थे। सभी शिक्षा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता, वे उच्च मानते थे। इनके विद्वद् ज्ञान है कि प्राचीन गुरुकुल शिक्षा के परम्परागत थे। मान ही यह न मानते तो भी आसानी से यह जैसा महानु विचार कहिये जाय। वे प्राचीन शिक्षा की शिक्षा के समर्थक नहीं थे। वे उद्योगवादी विचारक थे। इनके वे परम्परागत शिक्षा की अवधि काया का पटन कर गता उच्च मानने थे। उनकी शिक्षा-परम्परा विचारधारा उनके मार्गदर्शक मन्त्रों के विरुद्ध हुई है। उनके आधार पर हम उनके शिक्षा-दर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं।

(१) प्रकृति-प्रेम प्राचीन गुरुकुल लोगों ने दूर प्रकृति के प्रेम के स्थान होने थे। यह बात भी ठाकुर का बहुत पसन्द थी। इन विषय में अपने विचार व्यक्त करने हुए उन्होंने बताया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जन्म जंगलों में हुआ था। लोगों ने यह है कि भारतीय धर्म, आचार-विचार, दर्शन और कलाएँ गुरुकुलों में विकसित हुई। इन सबका ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य स्थान भ्रमर स्थित गुरुकुल थे। प्रकृति इस सभ्यता और संस्कृति का प्रणय प्रदान करती थी। यदि हमें भारत की सभ्यता और संस्कृति की पुनर्स्थापना करनी है तो हमें अपनी शिक्षा के केन्द्रों का जगहों में ही स्थापित करना होगा। यही तो युग की सभ्यता महो का देन है और इसका विकास परिचायक म हुआ है। यह सभ्यता भारतीयता के प्रतिरूप है। हम, दुर्भाग्य से, इसी सभ्यता को अपना रहे हैं और सभी हमने अपने विचारों के जगहों में बना रहे हैं। वर्तमान शिक्षा का दोगा यही है कि यह भारतीयता में दूष्य है। इसी विचार का नेतृत्व रवीन्द्रनाथ ने अपने स्कूल की स्थापना प्राचीन परम्परा के अनुसार की थी।

प्राचीन गुरुकुलों के आदर्श की प्दान में रखने हुए श्री रवीन्द्रनाथ ने शिक्षा में प्राकृतिक वातावरण प्रस्तुत करने का समर्थन किया। उनका विचार था कि प्रकृति जीवनमय है। वे यह जगदीशचन्द्र बनू की भाँषों में प्रभावित होकर कहते हैं कि इस महानु वैज्ञानिक ने प्राचीन ऋषियों के कथन को मिट्ट कर दिया है जिससे अनुसार वृक्षां में जीवन होता है। वृक्षां में जीवन का अनुभव करने का सम्मरण निराने हुए उन्होंने एक रवान यह कहा है कि हमारे घर की चहारदीवारी के निचर खड़े हुए कुछ नारियल के वृक्ष जो इस पृथ्वी पर आक्रमण करने वालों की सेवा में बन्दी बनाये गये मैनिकों की भाँति प्रतीत होते थे, मानो यह कहते थे कि वृक्षां के सपात्र और मानव-नमात्र के बीच सम्बन्ध है। इसीलिए मेरे मन में जंगलों के आभरण की शक्ति अनुभव होती थी। शिक्षा की दृष्टि से यह विचार महत्त्वपूर्ण है। शान्ति निवेदन जैसी मस्या का नगर में दूर जगत की मोद में पनपता इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर महोदय प्रकृति को शिक्षा का माध्यम मानने थे।

(२) जीवन की सहजता—प्राचीन गुरुकुल में परिवार और शिक्षालय दोनों का कार्य मिला-जुला होता था। यह बात रवीन्द्रनाथ को उपयोगी तथा उपयुक्त जैसी

थी। गुरुकुल में विद्यार्थी इस प्रकार रहता था मानो वह अपने परिवार में रहे हो। इसके विपरीत, शहरी स्कूलों में छात्रों को स्नेह नहीं मिलता। स्वयं भी ठाकुर को स्कूल की नीरमता का अनुभव हो चुका था। वे 'अपने स्कूल' (My School) के सम्बन्ध में लिखते हुए कहते हैं कि मुझे जीवन, प्रकृति अपने चारों ओर के वातावरण से सहज प्रेम है क्योंकि उसमें मेरे अपने प्रियजन और परिवार-जन रहते हैं। इस प्रकृत वातावरण में दूर हटाया जाना और स्कूल को भेजा जाना जो मेरे लिए एक प्रकार में प्रवास या देश निकास के समान था, मुझे पसन्द न था और प्रतिदिन मुझे इसमें भय लगता था। स्कूल को सप्ताह दीवारी के बीच रहते हुए मुझे जीवन की महजता का अनुभव नहीं होता था।

रवीन्द्र ठाकुर के अपने व्यक्तिगत अनुभवों ने उन्हें शहरी स्कूलों का विरोधी बना दिया। इन स्कूलों में विषयों की शिक्षा कृत्रिम होती है। भूगोल, भाषा, व्याकरण उन्हें इस प्रकार पढ़ाया जाता है कि शिक्षा के माध्यम से उन्हें इनका कोई सम्बन्ध नजर नहीं आता। वह कहानी पढ़ना चाहता है परन्तु उसको इतिहास के नीरम तथ्य पढ़ने हैं। यह कृत्रिमता शिक्षा में दूर करना रवीन्द्रनाथ आवश्यक समझते थे। इससे उनका ध्यान प्राचीन गुरुकुलों की ओर गया। उनमें समय-चक्र, विषयों की नीरमता, रटारट और बन्धन न था। अपने स्कूल में उन्होंने प्राचीन गुरुकुल का वातावरण उत्पन्न किया। वे लिखते हैं (Personality)

"मेरे स्कूल में बच्चों ने वृक्षों की रचना का महत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बिना स्पर्श किये हुए वे जान लेते हैं कि वृक्ष की अनाकूल जल पर कहाँ पैर जमाया जा सकता है। वे यह जानते हैं कि इन शाखाओं के माध्यम से कहाँ तक विलंबाव किया जा सकता है और लघुशाखाओं पर बोझ न पड़े, इस प्रकार वे अपने भार को बाँटना भी जानते हैं। फलों को एकत्र करने में, विधायक करने तथा पीछा करने वालों में अपने को छिपाने में भी बालक वृक्षों का उपयोग करना जानते हैं।"

स्पष्ट है कि श्री ठाकुर शिक्षा में जीवन की महजता चाहते हैं। प्राचीन गुरुकुलों में इसी प्रकार तो बालक विचरण करने रहे होंगे।

(३) शांति की उपासना—रवीन्द्रनाथ ठाकुर का विचार था कि जगत् का एकान्त जीवन मर्याद में परे रह कर शांति अनुभव किया जा सकता है। गुरुकुलों को शहरी से दूर बनो में, इसी कारण, स्थापित किया गया होगा। उन्होंने अपनी शिक्षा संस्था का नाम 'शांति निकेतन' रख कर पुष्पनी परम्परा का पालन किया है। शांतिपूर्ण वातावरण में मनुष्य के आन्तरिक व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। शहरी के कोलाहलपूर्ण जीवन में मनुष्य की आत्मिक शक्तियाँ दब कर कुंठित हो जाती हैं, वही भेदभाव पैदा होने है। यही कारण है कि आज की शहरी शिक्षा मनुष्य-मनुष्य में भेद उत्पन्न करने के जीवन को अज्ञान बना रही है। इसके विपरीत, प्राचीन गुरुकुलों में शांति की अनुभूति ने मनुष्य में प्रेम और आत्मीय की भावना जमायी थी। 'वसुधैव कुटुम्बकम्'



वास्तव में रवीन्द्रनाथ को आध्यात्मिकता पर बड़ी आस्था थी। उन्हें यह देखकर बड़ा दुःख होता था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में बालकों के बौद्धिक विकास पर तो जोर दिया जाता है परन्तु आध्यात्मिक भावों की उपेक्षा की जाती है। उनके मन में बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक—सभी प्रकार का विकास आवश्यक है। केवल बुद्धि पर जोर देने में बालक की स्वार्थी एक विराफ के समान हो जाती है जिसकी सर्वेन शरीर के अनुपान में बड़ी होती है। नानार्थ यह है कि जिस प्रकार जिसका पशु के रूप में अस्वाभाविक दिखाई देता है, उसी प्रकार केवल बुद्धि पर जोर देने में बच्चों का विकास असंतुलित हो जाता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति का दोष यह है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान उसमें नहीं रखा जाता। इसके विपरीत, गुरुकुलों में छात्रों का सर्वांगीण विकास हो पाता था। रवीन्द्रनाथ ने स्पष्ट किया है कि शान्ति-निवेदन में स्कूल चलावे का मेरा मुख्य उद्देश्य बालकों को आध्यात्मिक संस्कृति प्रदान करना है।

रवीन्द्रनाथ के मन में वास्तविक संवत्स के स्कूल फँट्टी के समान है जिसमें एक विशेष प्रकार के निर्जीव मनुष्य रहते हैं। वेद की बात यह है कि आजकल के भारतीय बालक प्राचीन भारतीय आध्यात्म को खोलते जा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी सिन्धी पीढ़ी पूर्वजों और प्राचीन इतिहास के सिन्धों में रहते बालों धारा का मार्ग अवलोक कर रही है। आगे चलकर भारत की वह पानी नहीं मिल सकेगा जो उनकी संस्कृति को उर्वर बनाता था, जिसमें उनकी शक्ति और सुन्दरता बड़ी थी। इसलिए मूल रूप में वे आश्रम पद्धति को शिक्षा में वापस लाना चाहते थे। उनका कहना है—“शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मृत्यु की एकता का अनुभव कराना है। पहले जब जीवन में मादगी थी तो मनुष्य की प्रकृति के विभिन्न अर्थों में समन्वय हो जाता था। जब जीवन जटिल हो गया तो बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पक्ष अलग-अलग हो गये और स्कूलों में बौद्धिक विकास पर ज्यादा बल दिया जाने लगा। हमने मानव प्रकृति के विभिन्न पक्षों में अलग-अलग पैदा हुआ और आध्यात्मिक पक्ष की शिक्षा में उपेक्षा की जाने लगी।” इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने प्राचीन आश्रम का वास्तविक अपने स्कूल में उत्पन्न किया। उनका विचार है कि आदर्श स्कूल एक प्रकार का आश्रम होना चाहिए जिसमें सभी मनुष्य शान्तिमय प्रकृति के बीच जीवन के उच्चतम आदर्श की पूर्ति के लिए एकत्र हो, जहाँ जीवन में केवल चिन्तन प्रधान हो बल्कि क्रियाओं में जागरूक हो। ‘जहाँ पर युवक और वृद्ध, अध्यापक और छात्र एक स्थान पर मिल कर भोजन करें और जीवन सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करें।

(६) अनुशासन तथा चरित्र का महत्त्व—रवीन्द्रनाथ ठाकुर को प्राचीन गुरुकुल के आदर्श प्रिय थे। उन बात का प्रमाण ब्रह्मचर्य के प्रति उनकी आस्था से मिलता है। वे शिक्षा को ब्रह्मचर्य श्रुत और धर्मव्रत मानते थे। अनुशासन और चरित्र के विकास के लिए वे शिक्षा में दमन की नीति के विरोधी थे। उनका विचार था

जि बान्हो को स्वतन्त्रता का अनुभव करा कर आत्मानुत्तमान का अभ्यास कराया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि बच्चे स्वावलम्बी बनें। वे अपने हाथ से अपना काम करने आत्म-विश्वास पैदा करें। रवीन्द्रनाथ धार्मिक शिक्षा के समर्थक थे परन्तु इस प्रकार की शिक्षा में वे धार्मिक कृत्यों और कर्मकांड का समावेश करने के विरोधी थे। उनका ईश्वर पर विश्वास था और ईश्वर की निकटता पाने का प्रयत्न ही वह धर्मपात्र मानते थे। साथ ही वे बार-बार कहते थे कि ईश्वर के निश्चय पहुँचने का माधन पूजा-यात्र नहीं है, माधना-ध्यान में यह काम हो सकता है या मानवमान की सेवा में बशोर्ति मनुष्य ही भगवान का मन्दिर है। सेवा और ध्यान में मन पवित्र होता है और चरित्र का बन चढ़ता है। अब उन्होंने अपनी सस्था में इन बातों की आरम्भ करने दी। छात्रों के पारिवारिक विभाग में वे अर्थ और सामाजिक हित में सम्बन्धित पंदा करने के पक्षधारी थे। अपने विद्यालय के सम्बन्ध में वे कहते हैं

“हमारे बच्चों में व्यापक मंत्री और निम्नार्थ भावना में दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक पायी जाती है, उतनी उन छात्रों में देने के को गरीब मित्रों को शिक्षा की सर्वोत्तम सुविधाएँ पाने हैं। लक्ष्य को देखकर वे समझते हैं कि जीवन में नैतिक सिद्धांतों की जितनी आवश्यकता है, आदि।”

### गुरुकुल के सम्बन्ध में गांधीजी के विचार

गांधीजी ने अपने शिक्षा सम्बन्धी लेखों में कहा भी प्रत्यक्ष रूप में यह नहीं दिया है कि बुनियादी शिक्षा की कल्पना में मुझे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्रेरणा मिली है। फिर भी उनके मन में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रति अनेक विचार थे और वे भारत के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली चाहते थे, जो उनकी अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुकूल हो। उनकी बुनियादी शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली के कुछ लक्षण समाहित हैं और उन पर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं।

समाजवादी भावों के मन में बुनियादी शिक्षा का विचार उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुआ है। समाजवादी शिक्षा का सम्बन्ध समाज में अनेक बच्चों को स्वयं सहाय बनाने से है। उनके लिए शिक्षा के माध्यम से समाजवादी आशय में बुनियादी शिक्षा का प्रयत्न करने में प्रयोग किया और उनकी महत्त्वात्मा होगी। इन बातों के मन में ‘परिवार-सूत्र’ का विचार हुआ है। बुनियादी शिक्षा एक एक लड़के को परिवार सूत्र है जिसमें एक अध्ययन और बच्चा के साथ रहता है और उन्हें पढ़ाता है। समाजवादी विचार गुरुकुल प्रणाली के लक्ष्य को समझते हैं। बुनियादी शिक्षा एक प्रकार की जीवन प्रणाली है, जिसमें शिक्षा है। सभी प्रकार के शिक्षा का कोई एक लक्ष्य नहीं है। समाजवादी शिक्षा एक लक्ष्यवादी शिक्षा है और यह लक्ष्य बुद्धि-समाधान है। गुरुकुल में जीवन की शिक्षा अर्थात् समाज में एक समाजवादी की परम्परा है। यह एक लक्ष्यवादी शिक्षा है बुनियादी शिक्षा में समाजवादी की और एक

अज्ञान पर स्वाभाविक नीबूने की त्रिया को शिक्षण का प्रमुख आधार बनाया। इसने यह स्पष्ट हो जाना है कि प्राचीन गुरुकुल प्रणाली और बुनियादी शिक्षा में कुछ मौलिक समानताएँ हैं और गांधीजी ने देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस पुरानी पद्धति को कुछ बदलकर नये रूप में प्रस्तुत किया है।

**स्वावलम्बन का सूत्र**—हमारे प्राचीन गुरुकुल स्वावलम्बी हुआ करते थे। यद्यपि समय-समय पर दासक तथा राजा लोग गुरुकुलों को पर्याप्त अधिक सहायता दिया करते थे, तथापि वे शिक्षा मस्यौदा आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर होती थी। उनके पास भूमि और पशु की पूँजी काफी मात्रा में होती थी जिसमें वहाँ के कुलपति तथा आचार्यों का भरण-पोषण आसानी से हो जाता था। 'अनुदान' के लिए वे सरकार तथा राज्य का भुँह नहीं लाफते थे। 'शिक्षा' की इस स्वतन्त्रता के कारण नाना प्रकार के प्रयोग हो सकते थे और तत्कालीन अध्यापक के पास विचारों की स्वतन्त्रता का अधिकार था। यदि राज्य शिक्षा को अनुदान देना है तो वह स्कूलों की स्वतन्त्रता नहीं रहने देना। अनिवार्य और मुक्त शिक्षा की व्यवस्था राज्य करे तो वह शिक्षा 'राज्य' के प्रचार और नियंत्रण का अंग बन जानी है। गुरुकुल कभी भी राज्य के अधीन नहीं रहे।

गांधीजी शिक्षा की स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। इसलिए उन्होंने 'स्वावलम्बन' के सूत्र को बुनियादी शिक्षा का प्रमुख अंग बनाया। ऐसा उन्होंने भारत की वर्तमान आवश्यकताओं को देखकर किया था। जब भारत पराधीन था तो यह आवश्यक था कि शिक्षा की स्वतन्त्रता के लिए उसे स्वावलम्बी बनाया जाना। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा-प्रणाली द्वारा ऐसा एक वर्ग उत्पन्न करने की चेष्टा की थी, जो परावलम्बी हो; नौकरी पाने के लिए उनका मुँह देखता रहे और उनकी गुलामी सहन करे। आजादी के बाद भी शिक्षा का वही रुत है। पढ़ने-लिखने के बाद हर भारतीय नौकरी चाहता है और सरकार की गुलामी करने की तैयार होता है। इनके विचारों की स्वतन्त्रता नष्ट होती है। इस विचार से गांधीजी को कष्ट हुआ और उन्होंने मनुष्य को स्वतन्त्र बनाने वाली स्वावलम्बी शिक्षा का सूत्रपात किया। यह शिक्षा पुराने गुरुकुलों की शिक्षा के समान ही है।

**दस्तकारी का सूत्र**—गांधीजी ने दस्तकारी को अपनी बुनियादी शिक्षा का केन्द्रीय विषय माना है। यह एक ओर हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप है तो दूसरी ओर यह हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुरूप भी है। दुर्भाग्य से गुरुकुल प्रणाली के ह्रास के बाद से शिक्षा में बौद्धिकता का तत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया और अंग्रेजों के शासन काल में 'शिक्षा' जीवन की व्यावहारिकता से ओर अधिक दूर हट गयी। आज की शिक्षा केवल 'सप्रेमपोष' व्यक्ति तैयार करती है, जो दूसरों का शोषण करके त्रिप्ता रहता है क्योंकि वह स्वावलम्बी नहीं होता। गांधीजी ने स्वावलम्बन के सूत्र को सफल बनाने के लिए 'दस्तकारी' का समावेश शिक्षा में किया,



ताकि हर शिक्षित जन अपने आप केवल थोड़े से माधनो में रोजी के मामले में आत्म-निर्भर बन जाय।

दस्तकारी को शिक्षा का केन्द्रीय विषय मान लेने में शिक्षा-प्रणाली गुरुकुल के अत्यन्त निकट आ जाती है। अध्यापक केवल बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करके बुनियादी शिक्षा का काम नहीं चला सकता। वह किसी दस्तकारी में अत्यन्त कुशल कारीगर होगा और साथ ही वह हर विषय का बौद्धिक ज्ञान भी प्राप्त करेगा तब वह एक आदर्श अध्यापक बनेगा। ऐसे अध्यापक की अपनी 'कर्ममासा' होगी जिसमें वह शिक्षण का कार्य करेगा। यह एक प्रकार का 'गुरुकुल' होगा जिसमें छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहाँ यह भ्रम दूर कर देना आवश्यक है कि गुरुकुल में केवल वेदशास्त्र पढ़ाये जाने थे। गुरुकुलों में दस्तकारी का प्रमुख स्थान था। गोपालन, गोमंथर्धन, कृषि और वागवानी यहाँ की शिक्षा के प्रमुख अंग थे और गांधीजी ने इन्हें की बुनियादी शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया है। हमारा प्राचीन साहित्य बताता है कि गुरुकुलों में अनेक प्रकार की दस्तकारी सिखाई जानी थी, जैसे दमनवसनाङ्गराग (रथ, भजन, मेहदी, महावर बनाना), गंधयुक्ति (झाड़ि बनाना), तक्षु'कर्म (कताई-धुलाई), तक्षण (बढ़ईगरी व परंथर तराशने का काम), चाम्पुविद्या (पर बनाना), हथपरान परीक्षा (सोने, चाँदी, रत्नों की जाँच), धातुवाद, आकरज्ञान (खानों की विद्या), यन्त्रमातृका (यन्त्र बनाना) आदि। बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी का समावेश गुरुकुल परम्परा का पालन कहा जा सकता है।

सादा जीवन उच्च विचार—प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में जीवन की सादगी और विचारों की उच्चता पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। वह आदर्श बुनियादी शिक्षा में स्वीकार किया गया है। गांधीजी ने इस 'प्राचीन युग' में दस्तकारी को प्रधानता केवल इसलिए ही दी है कि दस्तकारी मनुष्य को विलासिता में डूर रखती है। मशीन के कारण उत्पादन बढ़ा और उत्पादन के साथ ही कुछ लोगों के हाथों में आगये जिससे समाज में कुछ अमीर लोग अनेक गरीबों का शोषण करते हैं। यह कुछ लोग विलासिता के दुर्गुण समाज में उत्पन्न करते हैं। दस्तकारी सादगी और सुन्दरता के साथ रचनात्मक जीवन का आधार है। आचार्य कृपलानी के मन में दस्तकारी आध्यात्मिकता का खोल है और यह उच्च विचारों को जन्म देती है। दस्तकारी के काम में लगा व्यक्ति कभी दुर्गुणों में नहीं पड़ता। आचार्य विनोबा ने भी कहा है कि दस्तकारी प्रधान शिक्षा में ब्रह्म-विद्या आती है। सत्यकाम और उग्रान्यु प्राचीन गुरुकुलों में गांधी को चराने गये और उन्हें ब्रह्म-विद्या प्राप्त हो गयी। धीरे-धीरे भी गोचारण की कला में दक्ष थे और उन्होंने हमें गीता के उपदेश दिये। कबीर और नामदेव जैसे गुरु भी दस्तकारी को अपना कर इतने महान् पुरुष बन सके। बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी का समावेश करके गांधीजी ने जीवन की सादगी और विचारों की महानता को वापस लाने का प्रयत्न किया। यह हमारे प्राचीन गुरुकुलों के ध्येय आदर्श थे और उन्हें बुनियादी शिक्षा में स्वीकार किया गया है।

देश में इस समय जिस प्रकार अभाव का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए प्राचीन गुरुकुल की इन्द्रियनिग्रह प्रधान तथा मादयीपूर्ण शिक्षा का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। जीवन-स्तर बढ़ाने के चक्कर में हम भौतिकता को बढ़ावा देने जा रहे हैं। इसी में समाज में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। डामोस और विनामिता हमारे जीवन के अङ्ग बन गये हैं जिससे अभाव अधिक बढ्त्कारक जान पड़ने हैं। परि शिक्षा के माध्यम में इस चक्र को उल्टी दिशा में घुमाया जा सके, तो देश का साम होना। बुनियादी शिक्षा इस कार्य में सहायक हो सकती है। बहुत से लोगों ने बुनियादी शिक्षा में आध्यात्मिकता और चरित्र विकास के लिए कोई स्थान नहीं देखा पाया है और उनकी आलोचना की है परन्तु इसमें मादगी और उच्च विचारों को महत्त्व दिया गया है जिनमें आध्यात्मिकता और चरित्र की पवित्रता अपने आप उत्पन्न हो सकती है।

अप्य शिक्षा—बुनियादी शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा में कुछ अन्य समानताएँ भी हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। जिस प्रकार प्राचीन काल में त्रियाशीलता की शिक्षा में अलग न करके विभिन्न दैनिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, वह 'मानुबंध' का एक तरीका था। बुनियादी शिक्षा में इस विद्यालय को स्वीकार किया गया है। अध्यापक-छात्र सम्बन्ध का आधार ओ गुरुकुली में था, वही बुनियादी शिक्षा में है। दोनों एक रचनात्मक त्रिधा में समान रूप में भाग लेते हैं। जिस प्रकार गुरुकुलों में आचार्य निरन्तर छात्रों का नेतृत्व करते हुए उनका पथ-प्रदर्शन करना रहता था, उसी प्रकार बुनियादी शिक्षा में अध्यापक छात्रों का महायक परामर्शदाता होता है। इस समय हमारे देश में अध्यापक और छात्रों के सम्बन्ध निरन्तर बिगड़ते जा रहे हैं जिनमें अनुमानमहीनता में तृटि हो रही है। इस समय यह आवश्यक है कि हम अपने अध्यापक-छात्र सम्बन्ध के प्राचीन आदर्श को अपना लें। बुनियादी शिक्षा में इस आवश्यकता का ध्यान रखते हुए अध्यापक-विषय सम्बन्ध को वही आधार दिया गया है।

प्राचीन काल में अध्यापक का जो महत्त्व था, वह नष्ट होना जा रहा है। यह एक दुःखद घटना है। आज हमारे बीच में वाल्मीकि, बसिष्ठ और विश्वामित्र जैसे आचार्य नहीं रहे जिनके आगे समाज थड़ा में निर मुक्तता था। इस कमी को अब भारत में अनुभव किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग ने सकेत दिया है कि हमें 'पुराने शिक्षक' की महानता को वापस लेना है। जब तक भारतीय अध्यापकों में त्याग और चरित्र के आदर्श नहीं उभरते, देश में वह मुक्तता नहीं हो सकती जिसकी हम सभी कामना करते हैं। बुनियादी शिक्षक इस अभाव की पूर्ति करेगा। पर यह अध्यापक आध्यात्म बल तथा दम्नकारी के कौशल में उनका ही महान् होगा जितना हमारे प्राचीन ऋषि हुआ करते थे। इसका कारण यह है कि वह स्वावलम्बी होगा और स्वतन्त्र चिन्तन में वह विश्वास रखेगा। 'शिक्षण' उसका पेशा न होगा। दस्तकारी में उसकी आजीविका की समस्या हल होगी और 'शिक्षण' का

कार्य यह समाजसेवा के लिए रहेगा। ऐसा अध्यापक शिक्षा का सर्व समाजसेवा और छात्रों की सामाजिक जात प्रदान रहेगा।

पुस्तकों में पुस्तकों की पढ़ाई और ग्राह्य पर उपाय ध्यान नहीं दिया जाता था। पुस्तकालय शिक्षा में भी पुस्तकों को उपाय महत्व नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय का विचार है कि अध्यापक स्वयं अपनी पुस्तक विनयेता और छात्र पुस्तकों का अधिक प्रयोग करेगा। छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, अध्यापक के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। इस बात में यह स्पष्ट होता है कि हमारी वर्तमान शिक्षा में पुस्तकों की अनावश्यक महत्व मिल गया है जिसे दूर करने की आवश्यकता है और हमें इसे ही राष्ट्रीय ने हमारी को शिक्षा का माध्यम बनाया है।

### आचार्य कर्ष के विचार

आचार्य कर्ष ने स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय कार्य किया है और उनके द्वारा स्थापित भारतीय महिला विश्वविद्यालय उनकी इन सेवा का प्रतीक है। इस संस्था के द्वारा शिक्षा की स्त्रियों में अनुपूर्व जागृति हुई। उनकी स्थापना मन् १९१५ में हुई। अपने समय में यह विषय स्त्रियों का पुनर्जागर करने में लिए हुई थी तब में इसका निरन्तर विकास होता रहा। पूना स्थित इन संस्था का उत्तरीनर विकास होता गया। मन् १९३० में इसे बम्बई स्थानालयित कर दिया गया। वर्ष के एक करोड़रति ने अपनी माना की पुण्य स्मृति में इस संस्था को अनुप धनराशि प्रदान करके विश्वविद्यालय का रूप दे दिया। मन् १९५१ में इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई।

मूल रूप में यह संस्था आचार्य कर्ष ने भारतीय पद्धति में स्त्रियों की शिक्षा सम्पन्न करने के लिए प्रारम्भ की थी। यह शिक्षा भारतीय परम्परा के अनुरूप है। कर्ष का विचार था कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों की शिक्षा का प्रवर्ध भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा एक समान होती है, इनका परिणाम यह होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच वैचारिक समर्थ उत्पन्न होता है। दूसरे, भारतीय लोक जीवन में स्त्री-पुरुष के बीच जिम्मेदारियों का अंतरागत प्राचीन काल में कर दिया गया था और स्त्री को 'शुद्ध लक्ष्मी' के रूप में प्रतिष्ठित करना उचित माना गया था। पाश्चात्य शिक्षा में ऐसी मान्यता नहीं है। इसलिए पाश्चात्य शिक्षा पाने वाली भारतीय नारी सच्ची गृहिणी नहीं बन सकती। इस विचार से आचार्य कर्ष ने अपनी संस्था में भारतीय स्त्री-समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा देने का प्रवर्ध किया। यहाँ पढ़ाये जाने वाले विषयों में संगीत, चित्रकला, नाट्यकला, गृह विज्ञान आदि प्रमुख हैं जो स्त्रियोंयोग्य हैं। इस संस्था के अन्तर्गत छात्रावास, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय चलते हैं। यहाँ की परीक्षाओं में प्राप्ति के लिए पर महिलाएँ बैठ सकती हैं।

आचार्य जबें ने स्त्री शिक्षा में भारतीय संस्कृति के नस्बों का समावेश करना उचित समझा था। उनका विचार था कि स्त्री-शिक्षा का कार्य एक महिला को गुरुशिषी बनाना है। साथ ही गांधीजी की भाँति वे उन्हें स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं, हिन्दू स्त्रियों में बिचबा स्त्री की दशा सबसे अधिक दयनीय होती है। अन्तः स्वावलम्बन का मूल उनको शिक्षा की दृष्टि में बहुत अधिक महत्व का है। हमारे देश में स्त्री शिक्षा की जमी में स्त्रियों के समाज में एक प्रकार की निष्प्रियता आ गयी थी। घरी की जहाददीवारी में बन्द रह कर उनका व्यक्तित्व अतिरिक्त रह जाता था। वे बिचबा यदि न भी हो तो भी उनकी दशा होन हो रहती थी। अन्तः आचार्य जबें ने समस्त भारतीय महिला समाज के लिए स्वावलम्बी बनाने वाली शिक्षा योजना की हम संस्था के रूप में लक्ष्य रखा।

आचार्य जबें, वास्तव में, प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्शों के अनुरूप ही स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था करने में विद्वान् कहते हैं। प्राचीन काल की गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों की कल्पना उनके मन में बस कर रही थी। उन्हें यह ऐश्वर्य्य कर महान् शोभन हुआ था कि आधुनिक भारत में स्त्रियाँ निरक्षरता और अज्ञानता के बाँध पन के गर्त में गिम्मी जा रही हैं। आचार्य जी के मन में स्त्री शिक्षा की जो कल्पना थी, उसको साकार करने के लिए विशेष प्रकार की अध्यापिकाओं की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने इस संस्था में अध्यापक प्रशिक्षण पर भी धन दिया।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात हम संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि आचार्य जी महिला शिक्षा के पक्षपाती न थे, जो आधुनिक यूरोपीय शिक्षा प्रणाली में उत्पन्न हुई है। यद्यपि वे चाहते थे कि शिक्षा-दीक्षा में भारतीय स्त्री पुरुषों में किसी प्रकार होन न हो तथापि वे समुप्यमान में वर्तमान समजोरी में अवगत थे। उनका विचार था कि मौखिक काल में स्त्री-पुरुष का सम्पर्क हानिकर होता है और पारिवारिक दुर्बलता उत्पन्न होने पर संघट स्त्रो हो सकते हैं। इसलिए स्वामी दयानन्द की भाँति वे स्त्रियों की शिक्षा को पुरुषों की शिक्षा में अलग रखने के समर्थक थे। भारतीय समाज में सतीत्व की पवित्रता के आदर्श को प्रतिष्ठा बनाये रखने में उनका विश्वास था। इसी दृष्टि में उन्होंने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।

उपसृत बातों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना उचित न होगा कि महर्षि जबें पूर्णतया सड़वादी थे और आधुनिक युग की आवश्यकताओं को नहीं समझते थे। उनके मन में 'स्वावलम्बन' का महत्व वर्तमान था और वे स्त्री को भीमिन क्षेत्र में रखना अनुचित समझते थे। वे जानते थे कि क्या तथा अनुभव प्राप्त करने पर भावी समाज में स्त्रियों को पुरुषों के साथ मिलकर काम करना होना। साथ ही उन्हें पुरुषों के साथ होन भी करनी होती। उधर समाज में पारिवारिक शिक्षा के प्रभाव में विश्वविद्यालयों की उपाधियों का महत्व बढ़ता जा रहा था जो होन में सहायता पहुँचाती हैं। इसलिए वे महिलाओं को विश्वविद्यालय की उपाधि देना-दिलाना

आवश्यक समझते थे। हमने स्पष्ट है कि भारतीय बच्चे किसी प्रकार भी दूरिदायकी रिवाजों के हैं।

### अभ्यासाध्य प्रश्न

1. प्राचीन गुरुकुल पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का स्पष्टीकरण कीजिए। भारत में वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल उन विशेषताओं की किन बातों ने अपने मौखिक प्रयोगों में प्रयोग किया है? वे प्रयोग क्यों तक गहन हो गये हैं?
2. दयानन्द के मौखिक दर्शन की विवेचना कीजिए। क्या यह वर्तमान भारतीय परिस्थिति के लिए उपयुक्त है? भारत ने इसे क्यों नहीं स्वीकार किया?
3. यह कहना क्यों तक उचित है कि भारतीय संस्कृति की अमरता का कारण प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली की श्रेष्ठता है? प्राचीन भारत के मौखिक विद्वानों की कथा गुरुकुल प्रणाली के मर्म में कीजिए।
4. "भारत की राष्ट्रीय शिक्षा का मूल भारतीय संस्कृति तथा प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में होना चाहिए।" इस कथन में आप कहीं तक सहमत हैं? गुरुकुल शिक्षा के प्रयोग में अपने विचार स्पष्ट कीजिए।
5. प्राचीन गुरुकुल और गांधीजी के बुनियादी मूल में क्या समानताएँ और भिन्नताएँ हैं? बुनियादी शिक्षा कहाँ तक भारत की वर्तमान स्थिति के अनुकूल है?
6. रबीन्द्रनाथ टागोर की विद्वत्भारती के मौखिक कार्यक्रम और व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसमें तथा गुरुकुल में आपको क्या समानताएँ दिखाई देती हैं?
7. वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की माँग करने वाले शिक्षाविद्दों जैसे दयानन्द, रबीन्द्रनाथ और गांधी की आप प्रतिक्रियावादी (Reactionary) कहेंगे या प्रगतिशील (Progressive)? इन तकनीकी तथा प्रजातान्त्रिक युग के अनुकूल उनके विचार कहीं तक सगत हैं?

### विश्वविद्यालय की बी० एड० परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

1. Describe the educational ideals of Gurkul System or of Shantiniketan, and show how improvement in your school

can be brought about by placing these ideals before your pupils (1962)

2 Write short notes on —

(f) Dayanand, Tagore, Gandhi or Karve as an educationist  
(choose only one of these) (1963)

(e) What you can take in your school from Gandhi, Karve or Dayanand ? (1964)

(ग) गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था (१९६६)

(घ) श्री आर्यभट्ट अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र (१९६६)

(ङ) बंगाली शिक्षा व्यवस्था (१९६६)

(च) विवेकभारती (१९६३)

प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य

**प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्व**

[illegible][illegible]

मिना के लिए प्रमुख विभिन्न राष्ट्रीय को मध्य में के बाद इस मध्य में  
करीबी मई बुध उभित। पर विचार करना उचित है कि मिना के महान पर  
प्रधान पड़ता है। एक मूल है।

मुया बहनि लोचोदयं ताहन् भूतभूजम्  
ममत्र भूजन् पत स्यादेतन्न सरस्वती ।

यह सामान्य ध्येय रहने है कि पान पानने से मुग की सोभा होती है, मनुष्य में मुग की सोभा तो सराबरी है। (गिरिजा प्राण्य कर्त्तिक अब भोजन है तो अधिक प्रभाव पड़ता है, पान पानने जाने से बच्चों का मीठय नहीं बढ़ता।)

एक दूसरी मूर्ति है

स्वयंयवनसम्पन्ना विज्ञानकुसुतसम्भवाः

विद्याहीनानां शोभन्ते निर्मया इव किशुकाः ।

वे लोग जिनके पास यौवन है, रूप है, वंश परिवार है परन्तु 'शिक्षा' नहीं, उमी प्रकार मान-सम्मान नहीं पाने जैसे गधरहित बैल के बूँत ।

एक मूर्ति इन प्रकार है

कि कुलेन विज्ञानेन विद्याहीनस्य देहिनिः

विद्यावान् पुण्यते लोके विद्याहीनः पशुर्भवेत् ।

अशिक्षित मनुष्य का कुल बड़ा और ऊँचा भी हों तो क्या ? अशिक्षितजन पशु के समान हैं परन्तु शिक्षित जन की मारे समाज में पूजा होती ॥

शिक्षा मनुष्य के लिए सब कुछ कर सकती है । पद्यपुराण में कहा गया है

विद्यायां प्राप्यते सौख्यं यज्ञः कीर्तिस्तथापुत्रा

मानं स्वर्गः सुनोखवच्च तस्माद्विद्यां प्रसाधय ।

विद्या से सुख, यज्ञ, अतुल कीर्ति, ज्ञान, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होते हैं । इसलिए शिक्षा प्राप्त करने का पूरा यत्न करो ।

इसी प्रकार 'मनु'हरि' कहते हैं

विद्यानाम नरस्य ह्यपमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनं

विद्या भोगकरी यज्ञ सुखकरी विद्या शुक्लां गुरु

विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परं देवत

विद्या राजानु पुण्यते नहि धनं विद्याविहीनः पशुः ।

विद्या मनुष्य का बड़ा हुआ सौन्दर्य है, उसका सुरक्षित और गुप्त धन है, विद्या भोग, यज्ञ और सुख दिलाने वाली शुक्ला की गुरु है । विद्या ही सच्चा मित्र और बंधु है, जब मनुष्य विदेश में हो, विद्या श्रेष्ठ देवता है, विद्या की पूजा राज-वरवारो में होती है, धन की नहीं । विद्याविहीन मनुष्य पशु के समान है ।

शिक्षा का महत्त्व एक श्लोक में इस प्रकार बताया गया है—

मातेव रक्षति पित्रैव हिते निगुह्यते

कान्तेव चाभिरमयत्पनीयं लेखम् ।

सदमी तनोति वितनोति च विदुः कीर्ति

किं किं न साधयति नृस्यसतेव विद्या ॥

शिक्षा माना के समान रक्षा करती है, पिता के समान दुःख कार्यों में मनुष्य को लगाती है, परनी के समान कुछ दूर करके आनन्द देती है, धन बढ़ाती है, दिशाओं-दिशाओं में नाम बढ़ाती है—शिक्षा एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो मनुष्य को मनचाहो वस्तु प्रदान कर सकती है ।



यह सूक्तियाँ केवल कुछ उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं जो शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालती हैं। निरक्षरता को इस देश में पाप और पशुत्व माना गया था। शिक्षा के अभाव में मनुष्य उस प्रकार ठोकरें खाता है और इसी प्रकार भटकता है, जैसे अंधेरे में एक दूसरे के द्वारा ले जाए गये अंधे भटकते हैं—ऐसी यहाँ मान्यता रही है।

### भारतीय शिक्षा के प्रमुख आदर्श

प्राचीन भारतीय शिक्षा में कुछ मूल्यों को निश्चित रूप में स्वीकार किया गया था। इन मूल्यों पर शिक्षा को आधार करके उसके प्रभाव को बढ़ाने की चेष्टा की गई थी। अतः उन आदर्शों तथा मूल्यों पर विचार करना आवश्यक है।

(क) समतात्मकता—भारतीय शिक्षा का एक प्रमुख आदर्श समतात्मकता है जिसका अर्थ यह है कि हर एक आम छान के लिए शिक्षा का द्वार नहीं खोल देना चाहिए। इसका कारण यह है कि हर एक मनुष्य में शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता नहीं है। आज की दुनिया में सार्वजनिक शिक्षा (Universal Education) का आदर्श अपनाया गया है जिसका अर्थ यह समझाया जाता है कि हर एक को बिना भेदभाव के शिक्षा पाने का अधिकार मिलना चाहिए। वास्तव में इस आदर्श का सच्चा अर्थ यह होगा कि यदि शिक्षा से लाभ उठाने की क्षमता है तभी यह अधिकार मिलना चाहिए। मनोविज्ञान में कुछ वर्षों के लिए ऐसे शोध कार्य में निहित हुआ है कि ऐसे मनुष्य भी हैं जो असुबुद्धि होते हैं और वे शिक्षा से लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे लोगों को सामान्य बुद्धि वाले जनों के साथ रख कर पढ़ाने में अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। इस दृष्टि में सार्वजनिक शिक्षा का आदर्श पूर्ण नहीं कहा जा सकता और हम धीरे-धीरे समतात्मकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्राचीन काल में कुछ ही लोगों को ही शिक्षा देने का आदर्श व्यापक इमीनिए स्वीकार किया गया था। यूरोप में धीरे-धीरे धार्मिक पंथों द्वारा दलित शिक्षा में समतात्मकता को ज़िम्मेदार में स्वीकार किया गया है, वह आधुनिक है क्योंकि उसमें शिक्षा का अधिकार केवल सामर्थ्यवानों को दिया गया है। भारत में समतात्मकता का आधार कुछ दूसरे रूप में है, जो अनेकानेक व्यापक है। वर्गीक लोगों वर्ग-विरोध के लिए शिक्षा का अधिकार सीमित न था। यह ठीक है कि 'वर्ग-व्यवस्था' भारत में थी और वास्तव ही शिक्षा के अधिकारी माने जाते थे परन्तु 'वर्ग' विचार वर्ग न था। वास्तव का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति में है जिसमें बुद्धि है और जो पढ़न-पाठन में रुचि रखता हो। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए शिक्षा का द्वार खोलना स्याद है और ऐसे लोगों के लिए शिक्षा के द्वार बंद करना अग्राह्य नहीं है जो शिक्षा से लाभ नहीं उठा सकते। यह बात इस संदर्भ में व्यापक बन जान पड़ती है कि उस प्राचीन काल में शिक्षा कौटुंबिक, गाँविय और सामुदायिक थी और शिक्षा के स्थान इनके विद्यमान न थे कि उनका आभार दिया जाय।

चरनात्मवत्ता का आदर्श कई कारणों से अपनाया गया था। उसका मनोवैज्ञानिक आधार ऊपर स्पष्ट किया गया है। अब सामाजिक आधार पर विचार करें। प्राचीन भारतीय समाज को वर्णव्यवस्था ने आधार पर बँटा दिया था और उसको सुगठित बनाने के लिए एक ऐसा बर्ग चुना गया जिसके हाथ में समाज का नैतिक तथा आध्यात्मिक नेतृत्व सौंप दिया गया। यह वर्ग 'ब्राह्मण' के नाम से पुकारा गया। इसका नाम सामाजिक नियमों की रचना करना था। यह लोग अपना उत्तरदायित्व सभी भूत कर सकते थे, जब उनका विशेष प्रकार से प्रशिक्षण हो। इन विनिष्ट भयावह हुए लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोले गये। उन जमाने का ब्राह्मण अपनी कुछ विशेषताओं के कारण 'ब्राह्मण' था, किसी कुल या जाति से जन्म लेने के कारण नहीं। यह बात बराबर ध्यान में रखने की है। महाभारत में मुचिष्ठिर और दक्ष के संवाद में कहा गया है—ए यज्ञ, मुनि। निश्चयन नृप मे वैबल आचरण मे ही किसी का 'ब्राह्मणत्व' प्रकट होगा है, पवित्र धर्म-ग्रन्थों के अध्ययन और वेदों के ज्ञान से नहीं। इसी प्रकार मुचिष्ठिर और नृप संवाद में भी कहा गया है कि दूध न तो आवश्यक रूप से दूध है और न ब्राह्मण, ब्राह्मण है। केवल वही ब्राह्मण ॥ जिसमें कुछ विशेषताएँ हैं और जब उसमें वे गुण न हों, तो वह दूध है।

ऊपर दिए गये विवेचन से स्पष्ट है कि चरनात्मवत्ता का यह सामाजिक आधार पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक भी है। दूसरा आधार है, 'पात्रता' का। शिक्षा मुपात्र को दी जानी चाहिए। कहा गया है—विद्या मार्गस्य अभियेन न विद्यामूपरे वपेन, अपान् विद्या की लिये हुए भर जाना अच्छा है परन्तु उसे ऊपर में बीना अच्छा नहीं है। ठान्से यह है कि मुपात्र को ही शिक्षा देनी चाहिए। इन सम्बन्ध में 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् में कहा गया है :

वेदान्ते परमं गृह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम् ।

नाप्रज्ञान्ताय शतवर्षं नापुत्रापासिष्यान् वा पुनः ।

वेदान्त में जो भी प्राचीन काल में गूढ़ तथा रहस्यमय मय बनाया गया है, उसे न तो तेने व्यक्ति को प्रदान किया जाय जिसने अपनी बामनाओं को जान नहीं किया है और न अयोग्य पुत्र और अयोग्य सिष्य को।

इसी प्रकार मंत्रायणी उपनिषद् में एक स्थल पर विद्या (शिक्षा) एक ब्राह्मण के पास आकर कहती है कि मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी अपूत्य निधि हूँ। किसी ऐसे दृष्ट को मुझे मन भीषी ताकि मेरी शक्ति अधुण्य बनी रहे। मनु ने भी अपनी स्मृति में कहा है कि विद्या उसी को देनी चाहिए जो पवित्र, संयमी और सदा को बुद्धिमान से युक्त हो। यदि किसी ब्रह्मचारी (शिक्षक) के पास जीविका न हो तो भी उसे ज्ञान किसी भी मुपात्र को नहीं देना चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षक तब तक किसी छात्र को शिक्षा नहीं देता था जब तक वह यह अच्छी तरह गिद्ध न कर दे कि उसमें योग्यता, मानसिक और नैतिक बल है और शिक्षक इसमें सन्तुष्ट न हो जाय। इन सम्बन्ध में श्वेताश्वतर का वह प्रसंग उल्लेखनीय है जिसमें नचिरेता आत्मज्ञान प्राप्त

करने के लिए यम के पाग जाना है और यम सभी उमे जीवन-मृत्यु का रहस्य बताते हैं, जब ये उगरी निष्कण्टका और ज्ञान के प्रेम की जाँच कर लेते हैं। नचिकेता किमी भी प्रलोभन में नहीं पड़ता और केवल ज्ञान-पिपासा क्षान करने का आग्रह यम से करता है। शिक्षा पाने की पावना के सम्बन्ध में अनेक आख्यायिकाएँ हैं, जैसे गरुडकाम जायानि तथा उपकोशन, प्रजापति तथा इन्दु और बरोचन, याज्ञवल्क्य और जनक, शाक्ययन और वृहद्रथ के प्रसंग। जिस शिक्षार्थी में शान्ति, स्थिरता, आत्मसंयम, निग्रह, नतोष और समोदित्व के साथ-साथ शुद्ध भोजन के प्रभाव में मन्त्र-शुद्धि (प्रकृति की शुद्धता), शिरोघ्न (अग्नि को मिर पर रखने का व्रत या कंसाहीन रहने का व्रत) पूरा कर लेने के गुण हों, वही शिक्षा पाने का अधिकारी है। इसमें स्पष्ट होता है कि शिक्षा को केवल सुने हुए लोगों को देने का आदर्श भारतीय शिक्षा में स्वीकार किया गया था।

(क) विचार और व्यवहार अथवा शिक्षा और जीवन की एकत्वता—प्राचीन भारतीय शिक्षा में इस बात पर अधिक बल दिया गया था कि व्यवहार और विचार के बीच किसी प्रकार की त्वाई न रहने पावे। आज की शिक्षा-प्रणाली के ठीक विपरीत छात्रों को शिक्षा काल में एक प्रकार का ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता था जिसमें उन्हें जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान हो जाय और यह प्रशिक्षण असली परिस्थितियों के बीच जीवन जीते हुए प्राप्त करना होता था। इसमें छात्रों को शिक्षा खोलकी और नकली नहीं जान पड़ती थी। शिक्षा के सभी केन्द्रों में चाहे वे गुरुकुल हो या विहार या विद्याविद्यालय, छात्रों को रहना पड़ता था। जीवन का महत्वपूर्ण अंश इन शिक्षा-केन्द्रों में व्यतीत करके उन्हें अनुभव करते हुए जाना-जान करना पड़ता था। कठोपनिषद् में कहा गया है

मायमात्मा प्रवचनेन सभ्यो न मेधया न बहुता धृतेन ।

आत्मा अथवा जीवन का रहस्य प्रवचन, वेदादि के अध्ययन और दूसरों के अनुभव सुनकर नहीं जाना जा सकता, उसे तो स्वयं अपने जीवन के माध्यम से ही समझा जाता है। इसलिए भारत की प्राचीन शिक्षा में जीवन को अवश्य ही प्रतिबिम्बित किया जाता था। भ्रमवश कुछ लोगों का यह विचार है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा संस्थाएँ, जैसे आश्रम, गुरुकुल, विहार तथा विश्वविद्यालय नगरो से बाहर बनी और एकान्त उपर्यक्त ओ में स्थित थे और उनका जीवन से सम्बन्ध न था। इस भ्रम का निवारण आवश्यक है। इन शिक्षा-केन्द्रों में रहने वाले ऋषिपण और आचार्य गुफाओं में बैठ कर आँख बन्द करने ध्यानस्थ रहने वाले जीव न थे, इन ऋषियों का ऐसा चित्त हमारे मन में व्यर्थ ही जम गया है। वास्तविकता तो यह है कि यह सभी लोग एक समाज बना कर रहते थे, वे अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ स्त्रियाँ भी थी और बच्चे भी। वे इस प्रकार संसार के प्राणी थे परन्तु संसार से कुछ अलग यों में कि वे भोगविलास और धनलिप्सा से दूर रहते थे। यह लोग प्रायः नगरो में जाते रहते थे, राज-मन्त्रियों और राजाओं के होने वाले उत्सवों में शिष्यों

गृहित शामिल होने थे। उनके बच्चे जिय्यों के साथ हिल-मिल कर रहते, उनके साथ वे लोग मिलकर परिचय करते, हर कार्य में भाग लेते। वे घन और जीविका के चिन्ता से मुक्त रहते थे क्योंकि उनका भरण-पोषण राजाओं और धानों की दक्षिण पर निर्भर था। यह लोग बूँक स्वस्थ विवाहित जीवन व्यतीत करते थे, उन कुटुम्ब का शिकार नहीं बनते थे, जो मानसिक सन्तुलन को बिगाड़ देती हैं। प्राचीन शिक्षा का सम्बन्ध जीवन से जुड़ा था, यद्यपि शिक्षा मर्यादों नगरों से बाहर थी, आज हमारा शिक्षा मर्यादों नगरों में स्थित होने हुए भी जीवन में अलग हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारी इतनी खोली है कि वह असली मानव जीवन में मेल नहीं खाती।

प्राचीन भारतीय शिक्षा-केन्द्रों के जीवन का जिसमें सादगी और उच्च चिन्ता की प्रधानता थी, हमारे महाकवियों ने महाकाव्यों में सुन्दर वर्णन किया है। वाल्मीकि और भवभूति ने इनका मुख्य रूप प्रस्तुत किया है जिनमें 'चेतन' और 'जड़' का अद्भुत मेल हुआ है। पागदार महिला में पारासर मुनि के ब्रह्मकाश्रम का वैज्ञानिक चित्रण है। महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिक्षा-केन्द्र प्रकृति की गोद में स्थापित किये थे जिनमें उषधेला, धावस्ती का जेनवन, पुष्पाराध, धोपिनाराम और महाबल प्रमुख थे। यदि शिक्षा-केन्द्रों के चारों ओर प्रकृति का वातावरण प्रधान था तो उसका यह अर्थ नहीं था कि शिक्षा को जीवन में अलग रखा जाए। श्री रवीश्वरनाथ ठाकुर ने अपने एक भाषण में कहा था कि तत्कालीन आश्रमों और गुफाओं को इसलिए शहरों से दूर रखा गया था ताकि वे शहर के जीवन को उच्छेद रूप में देख सकें। इन जंगलों में बने आश्रमों में मानव-समाज का गरुड वह मुक्त वातावरण में सीम में बाला समाज था। हमारे शिक्षा में जीवन में अलग-अलग की प्रवृत्ति नहीं पैदा होती थी। उल्टे, इस मानव-समाज में अधिक जीवन्तता के दर्शन हो सकते थे। यदि ऐसा होता तो इस शिक्षा-केन्द्रों में भारत का वैदिक और ब्राह्मणिक का साहित्य उत्पन्न हुआ होता। इन जंगलों में ही सम्पत्ति और मरुति की अलग पारा पड़ी थी जिसने सारे भारत को आप्लावित कर दिया था।

श्री रवीन्द्र ने जीवन और शिक्षा के मेल के इस प्राचीन आदर्श की पुनर्प्रतिष्ठा करने का औरतार समर्थन किया है और शान्ति निकेतन उसका एक प्रमाण भी है। उनका कहना है कि इसलैण्ड के आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में उस प्राचीन भारतीय आदर्श को अपनाया है और इसी ने वे इनमें महान् बन सके। आजकल के शहरी विश्वविद्यालय शहरी शोरमुल के बीच फँस कर अपनी शक्ति खो बैठे हैं। उनमें सम्भीर चिन्तन-प्रधान जीवन-दर्शन पैदा करने की आशा नहीं की जा सकती। यह बात धूमरी है कि वे आविष्कारों और यन्त्रों की सम्पत्ति पैदा कर रहे हैं।

शिक्षा और जीवन के अमोल्याश्रित सम्बन्ध द्वारा उचित होना। बाणभट्ट ने अपनी वर्णन किया है। जो



और कर्पूरमजरी में है, गौतम का आश्रम जो मिथिला के निकट था और जहाँ राजा जनक प्रायः जाते थे, व्यास का आश्रम जहाँ के स्नानको में मुमुक्षु, वैशम्पायन, जमिनी और शुक्र जैसे विद्वान् थे।

यदि इन आश्रमों में जीवन और शिक्षा का बहुत सम्बन्ध न जोड़ा गया होता तो इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों में वृहत्तर भारत का निर्माण करने की योग्यता न पैदा होती। यहाँ की शिक्षा ने बड़े-बड़े विस्तृत दार्शनिक, साधक, धीर योद्धा, कला-बुधस जन के साथ-साथ सामान्य जन के व्यक्तित्व को उभारने और विकसित करने में महान् योगदान दिया था। हनुमान् ने इस शिक्षा में उत्पन्न व्यक्तियों के सम्बन्ध में लिखा है—जब यह लोग अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं और तीन वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उनका चरित्र निर्माण हो चुकता है और उनका ज्ञान परिपक्व हो जाता है। वे लोग ऐसे हैं जो प्राचीन ज्ञान में निष्णात होते हैं और ज्ञान के प्रति इनकी साम्यता रखते हैं कि एकान्त और सत्य के जीवन में ही वे सन्तुष्ट रहते हैं। वे संसार में प्रवेश करने और उसमें बाहर आते रहते हैं, जीवन व्यापार की गलियों में गुजर कर भी वे उसमें दूर रहते हैं। उन्हें सम्मान और असम्मान की जरा भी चिन्ता नहीं रहती, यद्यपि उनका मन दूर-दूर तक फैल जाता है। उनका परिवार सम्पन्नता का जीवन बिनाता है परन्तु वे स्वयं धूम-धाम कर और भिक्षा माँग कर जीवन बिना देने में संकोच नहीं करते। परिश्रम करने रहते हैं, उन्हें लज्जा नहीं आती और अपने मन के अन्वेषण पर उन्हें गर्व होता है। सामन्त-गण उनका बड़ा सम्कार करते हैं परन्तु उन्हें अपने दरबारी में बुला नहीं सकते।

इन शिक्षित जनों का प्रभाव सारे समाज पर पड़ा और सामान्य जन के जीवन स्तर में उद्वाह आया। सभी विदेशी यात्रियों ने भारतीय जनो की नैतिकता की प्रशंसा की है। इस शिक्षा ने मरुत्प्रेमी, मारुती-पसन्द, ईमानदार, मित्रव्ययी, हृदय का शुद्ध निष्कपट, न्याय पर चढ़ने वाला, बापदे का सम्मान, मानसिद्धि, निर्भीक, कर्तव्यपरायण व्यक्ति पैदा किये थे। यदि शिक्षा और जीवन का ऐसा संबंध न होता तो ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हो सकता था।

(ग) विद्यार्थी-जीवन का आदर्श—वर्तमान शिक्षा में विद्यार्थी को किसी एक प्रकार का जीवन नहीं सिखाया जाता। उनके लिए कोई आधार मॉडल नहीं है परन्तु प्राचीन भारतीय शिक्षा में विद्यार्थी के लिए अनेक आदर्श स्थिर कर दिये गये और उनके लिए एक विशेष प्रकार की जीवन-पद्धति निश्चित कर दी गयी थी। वास्तव में ऐसा पाठ्यक्रम इसलिए किया गया था कि जीवन और शिक्षा का सम्बन्ध बना रहे।

विद्यार्थी के मन में यह बात जमाना आवश्यक था कि वह एक 'विद्यार्थी' है। इसलिए विद्यार्थी-जीवन का प्रारम्भ 'उपनयन' संस्कार में होता था। 'उपनयन' शब्द का अर्थ है—(गुरु के) निकट ले जाना। अथर्ववेद और धातुषष्टि ब्राह्मण में इस संस्कार के प्रारम्भ का उल्लेख है। प्रथा यह पड़ी कि विद्यार्थी बनने के लिए युवक

गमिया और अग्नि मेजर उपाध्याय ने पाग जादू । यह जिया इन बात का प्रमाण है कि यह शिक्षा प्राप्त करना चाहता है । यह आचार्य में करता है कि मैं आचार्य पाग आया हूँ, आप विद्यार्थी के रूप में मुझे स्वीकार करें । आचार्य अपने अपने धर्म आदि की गुरु-नाम करता है । इस अवसर पर उसे विद्यार्थी जीवन के कर्तव्य बताते जाते हैं, जैसे अग्नि में गमिया दानों, जग में आत्मस्थ छुड़ि करो, सेवा करो, दिन में न सोओ, गम्बर के समान रह जाओ आदि । विद्यार्थी के रूप में उसे स्वीकार करने के बाद आचार्य दण्ड, शरण और गरमजी में प्रार्थना करता है कि उसे 'मिया' प्राप्त हो । इसी अवसर पर वह यज्ञोपवीत धारण करता है ।

विद्यार्थी-राम में छात्र को अनिवार्य रूप में गुरुगृह में रहना पड़ता था । इस नियम में किसी को छूट नहीं दी जाती थी । इस बात का उद्देश्य अथर्ववेद, गणपति प्राश्न, तेजोप, मैत्रिणीय और अन्य ब्राह्मणों में है । इन्द्राय में छात्र के लिए 'आचार्यदुर्वागिन्' और 'अन्धेवागिन्' विशेषणों का प्रयोग बताया है कि छात्र का गुरु के घर निवास करना एक आवश्यक धर्म थी । इस धर्म का उद्देश्य मनु, ऋग्वेद, श्राम और धर्मिक गतिमात्रों में है । गुरुगृह निवास की विशेषता यह थी कि छात्र को पारिवारिक जीवन की भाँति यहाँ भी स्नेह और गुरुता का अनुभव होता था । यह एक ऐसी विशेषता थी, जो वर्तमान सामाजिक शिक्षा समस्याओं में नहीं पायी जाती ।

विद्यार्थी जीवन में छात्र को भिक्षावृत्ति करनी पड़नी थी । यह एक नियम था और चाहे जितने वर्ग का विद्यार्थी हो, उसे भिक्षा माँगने के लिए जाना पड़ता था । उद्देश्य यह था कि अध्यापक के भरण-पोषण का भार उस पर रहे, उसमें विनय का गुण उत्पन्न हो और समाज को यह अनुभव हो कि शिक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी है । छात्रोप उपनिषद् अथर्ववेद, गणपति प्राश्न, आपस्तम्ब, मनु, श्राम और मातृ आदि में इस नियम का उल्लेख है । यदि स्वस्थ दगा में मान दिन नष्ट कोई विद्यार्थी भिक्षा नहीं माँगता, तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता था । मनु ने कहा है कि छात्र को पहले अपनी माता, बहन, भोगी या किसी ऐसी स्त्री से भिक्षा माँगनी चाहिए जो उसका अपमान न करे (मायद इनलिए कि पहली बार भिक्षा न पाने से ही उसमें हीनता का भाव पैदा हो जायगा) । माथ ही श्राम संहिता में कहा गया है कि नमक और बासी भोजन छोड़कर दैनिक भोजन मात्र स्वीकार करना चाहिए । चाहे जैना मकट हो पर किसी हालत में भिक्षा के द्वारा धन संग्रह नहीं करना चाहिए । भिक्षा वृत्ति ने जो कुछ प्राप्त हो, उसे छात्र अपने पास नहीं रख सकता था, उसे आचार्य के पास जमा करना पड़ता था ।

छात्र का एक कर्तव्य यह था कि वह यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रहे । अग्नि को प्रज्वलित रखना इस बात का प्रतीक था कि छात्र को हर समय जिज्ञासा-रूपी अग्नि में मन को जाग्रत रखना चाहिए ।

अध्यापक की सम्पत्ति और घर की देखभाल करना छात्र का प्रमुख उत्तरदायक समझा जाता था। छान्दोग्य उपनिषद् में वर्णित मन्थकाम की कथा में प्रकट होता है कि एक छात्र को किस प्रकार क्यों नाम धरानी पड़ी थी? आर्यगिरि तथा उरमन्थु की कथाओं में प्रकट है कि छात्र को गुरु के परिवार में रहकर उसकी भेटी की देखभाल, पशुपन की रक्षा और गुरु की अनुपस्थिति में उसके बान्धव-भक्तों की देखभाल भी करनी होनी थी। पशु के लिए चारा-पानी, फूल, गोबर, मिट्टी और कुश आदि की व्यवस्था का भार उस पर होता था। यहाँ उसके धर्म की घोर परीक्षा होनी थी जैसा कि गुत्ताचार्य के परिवार में रहने वाले कच और आचार्य की पुत्री देवपानी की कथा में प्रकट होता है। उसे बहुत बड़े घर्म-मंकट में पार होना पड़ना था।

छात्र को मनमा वाचा कर्मणा अध्यापक की सेवा करनी पड़ती थी। मनु ने स्पष्ट बताया है कि छात्र को अपने अध्यापक के हित के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य संहिता में कहा गया है कि गुरु की सेवा के द्वारा छात्र अमरत्व प्राप्त कर सकता है। हागीन और व्यास संहिताओं में यही बात बताई गयी है। अपने अध्ययन और कार्य का स्थान करके भी विद्यार्थी को गुरु की सेवा में लगना चाहिए। छान्दोग्य में कहा है कि तप्य को अध्ययन तभी करना चाहिए जब उसे अध्यापक के कार्य में छुट्टी (गुरो कर्मान्निरोधे वा) मिले।

अध्यापक के घर में निवास करते हुए छात्र का जीवन एक विदोष ब्रम के अनुसार बीतता था। उसे उषा काल में उठना पड़ना था और तारो के विलीन होने में पहले भस्पा कर्म कर लेना होता था। मनु के अनुसार इन कार्य में असफल होने पर प्रायश्चित्त करना जरूरी था। दूसरा काम छात्र का यह था कि वह दिन में तीन बार प्रार्थना करे। मन और शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करने का नियम था। विष्णु संहिता में दो बार और वाशिष्ठ तथा कामदकीय नीतिनार में तीन बार स्नान करने का नियम बताया गया है। छात्रों के लिए वस्त्र-विश्राम निश्चित थे। श्रिजानि के लिए धवन सूती या रेशमी वस्त्र पहनना अच्छा समझा जाता था। उत्तरीय के रूप मृगधर्म धारण करना पड़ना था, वेस्त्रा धूँज की बननी थी जो कमर में पहनी जाती थी, धनोपवीत पहनना अनिवार्य था, हाथ में एक इन्डा रखना पड़ता था जो पवित्रता और प्रकाश का प्रतीक था। ब्राह्मण, शत्रिय और वैश्यों के लिए यह वेशभूषा अलग-अलग थी। छात्रों को गिर पर बान्धन रखना परन्तु चोटी का रखना आवश्यक था या फिर जटाएँ रखनी पड़नी थीं। गाय में कर्मजन्तु रखने का नियम था। अधिक वस्त्र पहनना, मजाबट करना, रंग लगाना, अस्त्र में अस्त्र धारण करना, तेल लगाना, मानिश करना, छोर कर्म, दर्शन में मुख देखना, फूलों को मारना पहनना, सुगन्धि लेप करना, चन्दन लगाना, झूले पहनना, छाता ले चलना आदि छात्र के लिए वर्जित था। शरीर का आकर्षण न बढ़ने पाये, इसलिए वाशिष्ठ संहिता में यहाँ तक



शिक्षा है कि छात्र को अपने दीन, उन्मत्तियों और मातुल भी मान ली जाने चाहिए। इन सब विषयों के साथ रहने की सीढ़ी का सामना यह है कि विद्यार्थी जीवन में ऐसे दुःख मुला से दूर रहे और उनके मन में किसी प्रकार भी मातुल न उत्पन्न हो।

छात्रों के लिए भोजन के माध्यम से भी नियम को से। उन भोजन भोजन के रूप में अपने द्वारा प्राप्त शिक्षा का एक अंग मिल जाता था। प्राचीन, मनु और दश-साधन गतिशास्त्रों में कहा गया है कि छात्र को जो भी भोजन मिले, उसका निरादर हिट बिना, वह उस भोजन को सम्मान करने, उसे दमन हो उसका स्वागत करे हुए प्रगल्भ प्रकट करे। मनु का कहना है कि पुत्रों के उदात्त गणों तथा भोजन लाल और वीर प्रकाश करता है। मैगिरीय उपनिषद् में भोजन की प्रार्थना दी हुई है। उनमें मनु देवता की प्रार्थना के साथ-साथ भोजन की विभिन्न स्था में वर्तुन की गयी है। भोजन के माध्यम से कई नियम हैं, जैसे पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने में मनुष्य दीर्घांगु होता है, जो दक्षिणाभिमुख होकर भोजन करने में घटा मिलता है प्राप्ति। भोजन की गणों के सम्बन्ध में वाग्विष्ट गतिशास्त्र कहती है कि विद्यार्थी को दुग्धा पर भोजन करना चाहिए। एक बेल, विद्यार्थी और ब्राह्मण गान के बाद ही काम कर सकते हैं। छात्र गतिशास्त्र में एक बार का भोजन जो ब्रह्मचर्य के अनुकूल हो और मनु में दो बार का भोजन उचित बताया गया है। हर प्रातः में अधिक भोजन अनुचित बताया गया है। भोजन की अधिकता भोजन को धीन करने वाली बनायी गयी है। भोजन में चावल को शामिल न करने की सलाह दी गयी है। विद्यार्थी के लिए माँ, मधु, मिष्टान्न, पान तथा बानी भोजन वर्जित थे।

सोने के विषय में मनु, प्राचीन तथा सामान्य गतिशास्त्रों में कहा गया है कि विद्यार्थी को भूमि पर सोना चाहिए। अपने अन्धकार के सोने के बाद उसे सोना और उसके उठने में पहले जामना चाहिए। दिन में सोना सूर्य तथा संध्या के समय सोना जीवन की हानि करने वाला बताया गया है।

विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य समझा जाता था। इसलिए सभी गतिशास्त्रों ने छात्रों को स्त्रियों के सम्पर्क से दूर रहने का नियम निर्दिष्ट किया है। किसी प्रकार भी वीर्य का क्षय न करने का आदेश है। वीर्य को स्वास्थ्य और शक्ति के लिए आवश्यक मान कर उसकी रक्षा करने का निर्देश है। ब्रह्मचर्य को शिक्षा से ऊँचा दर्जा देने हुए कहा गया है कि केवल ब्रह्मचर्य साधन करने ही विद्यार्थी को समस्त विद्याएँ मिल हो जाती हैं।

विद्यार्थी के लिए उच्चतम मानसिक और नैतिक अनुशासन की आवश्यकता बनायी गयी है। गोप्य ब्राह्मण में बताया गया है कि छात्रों को जानीय गर्व, यश कामता, श्रेष्ठ, निद्रा, सौन्दर्य-प्रतापन, वस्तुतः मुख तथा बालों से बच कर रहना चाहिए। अनुशासन की दृष्टि से वामना, तुल्या, क्रोध, असत्य, भय, घृणा, मान, आलस्य, मद, मोह, चपलता, झूठता, अमूया, आह, धर्म का विवाद, अस्वीक

भाषण, अज्ञानता, कटु बचन, परनिन्दा, मद्यपान, स्त्रियो से वार्त्तावाप आदि में बचना आवश्यक है। छात्र को पञ्चापात्ररहित, मृदुभाषी तथा उन्माही होना चाहिए। छात्र के लिए घुड़गवारी, हस्ति या अन्य सवारी, स्वर्ण या कमल की पंखों के नीचे लाना, नाचना, गाना, घून्तरीश, पशुहत्या आदि वर्जित हैं।

गुरु के प्रति आदर और उमकी आज्ञा का पालन करना छात्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती थी। महाभारत, मनु, गौतम, वसिष्ठ, विष्णु संहिताओं तथा घुन्तरीतिमार में बार-बार यह कहा गया है कि विद्यार्थी को शिक्षक का किसी प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए। सभी गुरुजनों में अध्यापक ही श्रेष्ठ माना जाता था। उमकी सेवा में सभी विद्यार्थी अपने आप मित्र हो जाती थी। उमके नीचे आसन ग्रहण करना, उमके आगे मुक कर खान करना, विनम्रपूर्ण प्रश्न पूछना आदि नियमों का पालन छात्र को करना पड़ता था। भारतीय माहित्य में आदर्श छात्र की परम्परा राम, कृष्ण, अर्जुन, एकनभ्य, उदयगु, आरणि, नरयकाम और कच जैसे व्यक्तियों के रूप में देखने को मिलती है।

(घ) अध्यापक का आदर्श—प्राचीन भारत में अध्यापक को बहुत ऊँचा स्थान प्रदान किया गया था। आत्रकन की तरह उम पर दामन, प्रणामकीय विभाग, राज-नीति, अर्थ, पाठपत्रम, परीक्षा तथा नियमावली का कोई नियन्त्रण नहीं था। वह स्वतन्त्र चिन्तक था। राज्य और समाज उम हरे प्रकार की सुविधा प्रदान करते थे। माप ही अध्यापन का कार्य बहुत पवित्र माना जाता था। इसलिए उम कार्य को ब्राह्मण वर्ग के लोग ही प्राप्त अपनाने में क्योकि मयमी, अपरिग्रही, ब्राह्मविदु, विरागी, तत्त्वहृष्ट और स्वाध्यायरत होते थे। मनु ने स्पष्ट निम्ना है कि केवल ब्राह्मण ही शिक्षण कार्य करने के अधिकारी हैं, अन्य वर्गों की किसी भी दशा में यह ऐसा नहीं अपनाना चाहिए। ब्राह्मणों को अध्यापन का अधिकार उनके गुणों के धन पर दिया गया था। माप ही उम नियम के अपवाद भी थे। यदि ब्राह्मणेतर वर्ग के व्यक्ति में अमाधारण ज्ञान हो तो उमे नि सकोच निम्नाने का अधिकार प्राप्त था। यहाँ कयो-वृद्ध दूर द्विजानि की तुलना में सम्मान या श्रद्धा था। राजा जनक और विद्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी कितनों को शिक्षा देने रहते थे। गौतम संहिता में कहा गया है कि ब्राह्मण शक्ति पड़ने पर अत्राह्मण से कला और विज्ञान सीख सकता है।

प्राचीन भारत में अध्यापन को घनार्जन के साधन के रूप में 'पेशा' नहीं माना जाता था; वह कार्य 'विद्यादान' समझा जाता था और विद्यादान हर प्रकार के दान में श्रेष्ठ था। महाभारत में घन के बदले शिक्षा देना बुरा बताया गया है और उन अध्यापकों को दूर कहा गया है, जो घन के बदले शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा कर्ना 'उपपापक' समझा जाता था। विद्या देने के बदले जो दम लोक में घन लेता है, उमका परलोक विमर्श जाता है। भासविकानिमित्रम् में कहा गया है कि जिनने केवल घनार्जन के लिए ज्ञान प्राप्त किया है, वह व्यापारी है 'और' 'व' करता है। इसीलिए जब राजा

देने के

लिए विष्णु धर्मा को धनशासन (अर्थान् धन) देने की वान कही तो तेजस्वी विष्णु धर्मा ने कहा—“नाहं धामनसनेनापि विद्याविश्रयं करिष्यामि ।” (मैं धन लेकर विद्या नहीं देचूँगा ।)

इन सब बातों का यह तात्पर्य नहीं है कि अध्यापक धन नहीं लेता था । हम आदर्श को स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि अध्यापक में धननिष्ठा पैदा न हो । धननिष्ठा से शिक्षण की दमना नष्ट हो जाती है । यह स्थिति हम आज भारत में प्रत्यक्ष देख रहे हैं । उन काल में अध्यापक निर्धनी होता था । फिर भी उसे छात्रों से बहुत कुछ स्वीकार करने का अधिकार था । छात्रों को शिक्षा पूरी करने के बाद दक्षिणा के रूप में भूमि, गुचर्ण, गोधन, अश्व, धाना, जूने का जौड़ा, धान, शाक, वस्त्रादि जो भी उसे देने की सामर्थ्य हो, अध्यापक को देना चाहिए । कहा गया है—‘दक्षिणा श्रद्धा ददाति, श्रद्धया आप्यति ज्ञान ।’ फिर भी अध्यापक को जो मिले, समीप-पूर्वक लेना चाहिए । ‘रघुवंश’ में कालिदास ने कौत्स की कथा में बताया है कि शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गुरु से दक्षिणा माँगने की याचना करने लगा । निर्धन कौत्स को असमर्थ समझ कर गुरु ने उसमें चले जाने के लिए आज्ञा दी । वह हठ करने लगा । गुरु को क्रोध आ गया और उन्होंने उसमें कई लाख स्वर्ण मुद्राएँ माँगी । कौत्स निराश नहीं हुआ । वह राजा रघु के पास जाता है परन्तु उनके कोप में इनका धन न था । राजा ने कौत्स—एक विद्यार्थी—की माँग पूरी करने के लिए कृवेर पर बर्खास्त की और उनका सारा कोप कौत्स को लाकर दिया । कौत्स ने सारा कोप गुरु को अर्पित किया परन्तु उन्होंने गिन कर स्वर्ण मुद्राएँ ले ली । न कम न ज्यादा और शेष कौत्स अपने साथ ले गया । यह था भारतीय निर्धन शिक्षण का आदर्श ।

अध्यापक को शिक्षा काल में विद्यार्थी से शुल्क नहीं मिलता था, उसकी ‘सेवा’ ही शुल्क थी । वह सेवा करना और बदले में शिक्षा पाता । सेवा करने के लिए वह प्राण तक देने को तैयार था । रघुवंश में राजा दिलीप वासिष्ठ की गाय मदिनी की रक्षा के लिए अपना शरीर शेर को महर्षि अर्पित करते हैं ।

प्राचीन भारत में तीन प्रकार के अध्यापक थे—गुरु, आचार्य और उपाध्याय । ‘गुरु’ का स्थान सर्वोच्च था । ‘गुरु’ का अर्थ है भारी, जो ज्ञान में भारी हो और आचरण में श्रेष्ठ हो, और जो सारे मस्कारों को पूरा कराके वेदों की शिक्षा दे । ऐसे गुरु के लिए ही संभवतः महात्मा कबीरदास ने कहा है

गुरु गोविन्द दोनों सड़े काके लागूँ पाए,  
बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविन्द दिया बताए ।

आचार्य एक ऐसा शिक्षक था, जो केवल उपनयन मस्कार कराने के बाद वेदों की शिक्षा देता था । मनु और व्यास ने अपनी संहिताओं में बताया है कि एक ऐसा ब्राह्मण जो नित्यप्रति तपश्चर्या करता है और होम करना है और कल्प साहित्य वेदों तथा रहस्यों की शिक्षा देता है, आचार्य कहलाता है । आचार्य शब्द ‘चर’ धातु से बना है । अतः आचार्य वह है जो दूसरों को उत्तम आचरण में प्रशिक्षण देता है या

जो धर्म का मोल होता है (धर्मं आचिनोति इति आचार्य)। आचार्य स्वयं उत्तम आचरण का आदर्श नमूना होता था और अपने शिष्यों को धर्माचरण में प्रशिक्षण देता था। ऐसे गुरुओं और आचार्यों की श्रेणी में आने वाले वसिष्ठ, विश्वामित्र, सान्दीपनि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परशुराम और कश्यप आदि हैं जिनका उल्लेख रामायण और महाभारत में है।

उपाध्याय का विशेषण उग्र अध्यापक को दिया जाता था जो केवल वेद का एक अंग ही पढ़ा सकता था। विष्णु महिता में लिखा है कि जो धुत्क लेकर सम्पूर्ण वेद तथा बिना धुत्क के आशिक वेद पढ़ाता हो, वही उपाध्याय है। मातृय महिता में भी धन लेकर वेदाध्ययन कराने वाले को उपाध्याय कहा गया है। लगभग यही मत मनु का भी है।

तत्कालीन शिक्षक के लिए अनेक गुणों में युक्त होना आवश्यक बताया गया था। एक सफल शिक्षक में निम्नलिखित गुण हो

प्रवृत्तवाक् चित्रकथः अहवान् प्रणिभावान्  
आशुर्ग्रन्थस्य वक्ता च यः सर्वज्ञित उच्यते।

अध्यापक को हाजिरजवाब होना चाहिए, छात्र जो भी प्रश्न पूछे, तुरन्त वह उत्तर दे सके। उनके पास चित्र-चित्र कहानियों का कोष हो ताकि वह अपनी बात या विचार को कहानियों के माध्यम से स्पष्ट कर सके। उसमें ओजस्विता हो, कक्षा पर वह अपने तेज से प्रभाव डाल सके, विचारों को मौलिक ढंग में प्रस्तुत करने की प्रणिभा हो, मुँहजबानी वह पुस्तक रचना करने में समर्थ हो। ऐसा पण्डित कुशल अध्यापक होता है।

मुँहकोपनिषद् में कहा गया है कि अध्यापक को श्रोत्रिय होना चाहिए, सात्पर्य यह है कि अध्यापक वह हो सकता है जिसकी तीन पूर्व पीढ़ियाँ वेदों के ज्ञान में निष्णान रही हो और वह ब्रह्मवेत्ता हो। ऋग्वेद में अध्यापक की बौद्धिक क्षमता के बारे में कहा गया है कि अध्यापक सभी बनना चाहिए जब वह निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कर ले और ब्रह्मचारी के सारे कर्तव्यों का पालन कर ले। शास्त्रार्थ में उसे निपुण होना चाहिए। उसे घोर परिश्रम करना चाहिए और सर्वाङ्गीण ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करना चाहिए। शिष्यों के साथ वह पुत्रवत् व्यवहार करे। उपनिषदों में बताया गया है कि अध्यापक को अपनी शिक्षा के अनुरूप व्यवहार और आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उसे अपने छात्रों में कोई सत्य छिपाना नहीं चाहिए। छात्र के चरित्र और बुद्धिभ्रमना के अनुरूप उसे सभी मूल बातें और सच्चा ज्ञान भिन्नाना चाहिए। उसमें 'विनय' का गुण होना आवश्यक है। शिष्य के प्रश्न पूछने पर यदि वह उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे अपनी त्रुटि स्वीकार कर लेनी चाहिए। प्राचीन काल में अध्यापक भूटे पाण्डित्य और ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता था। एक बार उदात्तक आश्विन के पास १ ब्राह्मण विश्वामित्र विद्या सीखने आये, तो वह विद्या

प्रदान करने में अगममर्थता प्रकट करते हुए उन्होंने उन्हें राजा अश्वपति के पास भेज दिया ।

अध्यापक के ऊपर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व छात्र के जीवन-निर्माण का होता था । वह एक प्रकार में जननी के समान छात्र को दूसरा जन्म देता था । अथर्ववेद में कहा गया है—आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण कृणुते गर्भमन्य । ब्रह्मचारी अपने गुरु को पिता के तुल्य मानता था, ऐसा प्रदर्शनीपत्र में कहा गया है । अध्यापक को अपना कार्य सच्चे हृदय से करना चाहिए । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट निर्देश है कि अध्यापक को अपने निजी स्वार्थ के लिए छात्र में कोई काम नहीं लेना चाहिए । अध्यापक को छात्र की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए, उसे यह बताना चाहिए कि वह कौनसे गुण अर्जन करे और किन अवगुणों में दूर रहे, किन बातों की उपेक्षा करे और किन बातों को स्वीकार करे । उसे अपने छात्र को सोने, स्वास्थ्य तथा भोजन के नियम बताने चाहिए । उसे यह भी बताना चाहिए कि वह किन लोगों के सम्पर्क में रहे, किन प्रदेशों का भ्रमण करे और किन प्रकार निर्भीक होकर रहे । शिष्य द्वारा भूल करने पर अध्यापक मरमता में क्षमादान दे । कोई चूटि होने पर अध्यापक छात्र को निकाल भी सकता है परन्तु क्षमा-याचना करने पर उसे मदद हो जाना चाहिए ।

अनेक यूरोपीय इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय शिक्षकों की प्रतिभा की प्रशंसा की है । उनका कहना है कि उन काल में जो कुछ भी शिक्षा दी जाती थी, उत्तम शिक्षकों द्वारा दी जाती थी । श्री सन्तोषकुमारदास के अपनी पुस्तक (The Educational System of Ancient Hindus) में हिन्दू शिक्षकों के गौरव का वर्णन करते हुए कहा है—नैतिक और धार्मिक गुणों के कारण उन काल का अध्यापक वास्तव में शिक्षक कहलाने योग्य था । उनकी सादगी, उच्चचिन्तार, समयपूर्ण दिनचर्या, इन्द्रियनिग्रह, मानसिक सन्तुलन और सबसे अधिक उद्देश्यों की स्पष्टता और सच्चाई उसको सफलता दिलाने वाले प्रमुख गुण थे । यह ऐसे गुण थे जिनके कारण उसका सर्वत्र सम्मान होना अनिवार्य था । वे अपने छात्रों के समक्ष जीते-जागते आदर्श के रूप में वर्तमान रहते थे । उस युग में जब सरकार आजकल की तरह शिक्षा की व्यवस्था नहीं करती थी, एक उत्तम शिक्षा पद्धति की उन लोगों ने जन्म दिया । यों तो यूरोप में जेमुइट सगठन तथा बौद्धकाल में भिक्षु सगठन ने भी आदर्श शिक्षकों की एक महत्त्वपूर्ण परम्परा का निर्माण किया था परन्तु हिन्दूकालीन अध्यापकों की अद्भुत विशेषता यह है कि उनका जीवन अत्यन्त स्वाभाविक था; वे पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे, गृहस्थ बन कर भी वे शिक्षक बने रहे । इसके विपरीत, जेमुइट और बौद्ध शिक्षकों के जीवन में एक प्रकार की कृत्रिमता थी, ब्रह्मचर्य और अलगाव का जीवन बिताने के लिए पीछे उनमें नैतिक पतन का दोष उत्पन्न हो गया । हिन्दूकालीन शिक्षक योग और योग के मन्त्रव्य का आदर्श लेकर चला था, इसी में उसे गौरव प्रदान करने वाली सफलता मिली थी । उनका मानसिक

जीवन संयुजित और स्वस्थ था, हमी से वे भारत को ऐसा जीवन-दर्शन दे गये जो आज भी हमें प्रेरित करता है।

(४) शिक्षण-कला—बहुत से लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में शिक्षण-कला को पूर्णता तक पहुँचाने का पूरा प्रयत्न किया गया था। केवल मौखिक रूप से यहाँ शिक्षण-नार्थ नहीं होता था। अनेक यूरोपीय इतिहासकारों ने ध्रमवश यह लिख मारा है कि भारत में शिक्षण केवल व्याख्यान और रटाई के रूप पर चलता था। जिन विदेशियों ने प्राचीन भारत का भ्रमण किया है और यहाँ के शिक्षा केन्द्रों से आकर अध्ययन किया है, उनके वर्णनों से हम बात का प्रमाण मिलता है कि भारतीय अध्यापक माना प्रकार की शिक्षण-विधियों का प्रयोग करते थे। शिक्षण में मनोवैज्ञानिकता का पूरा ध्यान रखा जाता था, शिक्षण के अनेक मूत्र थे और शिक्षण को एक कला माना जाता था। कई यूरोपीय यात्रियों ने जब भारतीय पाठशालाओं का अवलोकन किया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि छोटे बच्चों की शिक्षण पद्धति में यहाँ बड़े सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तत्वों का समावेश था। एक फ्रामीसी यात्री पियेट्रा डीला वैले (Pietra della Valle) ने दक्षिण भारत के एक मन्दिर से सम्बद्ध पाठशाला में छोटे बालकों को पढ़ते हुए देखा था और उसका वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि मैंने एक विचित्र तरीके से छोटे बच्चों को गिनती सीखते हुए देखा। चार बच्चे थे और वे गिनती याद कर रहे थे। उनमें से एक बड़े संगीतमय स्वर में गिनती पढ़ता और हर अंक को बाजू में निम्नता और हमारे बच्चे उसका अनुकरण करते। फर्क पर गहरी बाजू इसी उद्देश्य से बिज्रा दी गयी थी। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा स्पर्श और गति के माध्यम से सीखना एक उत्तम उपाय कहा जा सकता है।

प्राचीन काल में छात्र को पढ़ाने में पहले मानसिक रूप में तैयार करने के लिए कुछ नियम निश्चित थे, जैसे रात्रि के अन्तिम प्रहर में अरण्योदय से पूर्व उठना, स्नान करके होम करना, उनके मुद्र वस्त्र धारण करना, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आचमन करना, हाथ जोड़ना, अध्यापक के शरणों का स्पर्श करना, गायत्री और प्रणव मन्त्र का उच्चारण करके अध्ययन प्रारम्भ करना आदि। यह सारी क्रिया केवल मानसिक तैयारी का मापन है। वैदिक शिक्षा में अध्यापक मन्त्रों को पढ़ता और छात्र उसे दोहराते थे, मन्त्रों को इन प्रकार कठस्थ कराया जाता था। मास ही सभी मन्त्रों की सूक्ष्म व्याख्या की जाती थी और अर्थ समझाया जाता था। वेदों में कहा गया है कि द्विजानि में श्रेष्ठ जन को वेचन वेदपाठ में सन्तोष नहीं करना चाहिए। जो वेदों का अध्ययन उचित प्रकार से नहीं करता, उन पर ममक कर पूरा अधिकार नहीं करना, यह अपने परिवार सहित छूट बन जाता है। दश संहिता में वेदाध्ययन के पाँच पद बनाए गए हैं—वेदों की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, उन्हें अच्छी तरह समझना, अध्ययन करना, कठस्थ करना और फिर शिष्यों को यह ज्ञान प्रदान करना। हर मन्त्र को पढ़ाने के लिए उसे हर 'पद', 'वाक्य' और 'प्रमाण' का स्पष्टी-

करण किया जाता था। दस विधि में ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्र को 'पद वाचक-प्रमाणज्ञ' कहा जाता था।

बेड़ों के मून पाठ को पढ़ाने में पाँच पद आते थे, वे हैं—अध्ययन (जो कुछ पढ़ाया जाय, उसे सुनना), दण्ड (अर्थों को समझना), ऊट (नर्क द्वारा सामान्य नियम निकालना), गृह्यप्राप्ति (अध्यापक अथवा मित्र में उग नियम का समर्थन प्राप्त करना) और दान (उग नियम का प्रयोग)। कार्मदकी में शिक्षण के मान पद इन प्रकार बताए गए हैं—

गुध्रूया ध्वणं चंद ग्रहणं धारणं तथा  
उहापोहार्थं विज्ञानं तत्त्वज्ञानञ्च धो गुणः ।

गुध्रूया (गुनने की इच्छा), ध्वणं (जो कुछ पढ़ाया जाय, उसे सुनना), ग्रहणं (जो कुछ पढ़ाया जाय उसे समझना), धारणं (जो कुछ पढ़ाया जाय उसे याद करना), उहापोह (पठित विषय पर विचार-विमर्श), अर्थविज्ञानम् (सम्पूर्ण भाव को अच्छी तरह जानना), तत्त्वज्ञान (गहरा या तत्त्व को धारण करना)—यह मान पद यही हैं, जिन्हें हरबर्ट की पंचपदी विधि में स्वीकार किया गया है।

प्राचीन भारतीय शिक्षा में व्याख्यान विधि का प्रचलन नहीं था। उसके स्थान पर आधुनिक मेमीनार (उपनिषद्, गोंट्री), मिणोरेजियम (परिचर्या) का ही चलन था। व्याख्यान विधि के दोषों को देख-समझ कर उस काल में इन विधियों का प्रयोग किया गया था, हमारे लिए यह सब कुछ गया नहीं है। इसी प्रकार सांश्रेंटीज की प्रश्नोत्तर विधि (इंक्वायिटिव विधि) हमारे देश में बहुत प्राचीन काल में प्रयोग में आती रही थी। गुरुकुलो, आश्रमों और पाठशालाओं में प्रश्नोत्तरों द्वारा पढ़ाई होती थी। महाभारत की कथा में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनमें इन विधि का परिचय मिलता है। युधिष्ठिर-यज्ञ, युधिष्ठिर-मर्ष तथा भीष्म-युधिष्ठिर के सम्वादों में यह विधि देखने को मिलती है। 'केन' और 'कठ' में तो इसी विधि द्वारा शिक्षा दिए जाने का उल्लेख है।

'स्वशिक्षा', 'स्वप्रयत्न' का तत्कालीन शिक्षण में वही महत्त्व था जो आज की शिक्षा में माना जाता है। छात्र के लिए स्वैच्छा और स्वप्रयत्न द्वारा शिक्षा पूरी करने का विधान था। मनु ने कहा है—

आचार्यात्पादमापस्ते पादं शिष्य स्वमेधया  
पादं सङ्गृह्यचारिभ्य पाद कालक्रमेण तु ।

विद्यार्थी की समस्त शिक्षा चार अंगों में विभाजित की गई है। उनका एक अंग अध्यापक से, दूसरा शिष्य के निजी प्रयत्न से, तीसरा अपने सहपाठियों से और चौथा जीवते हुए समय के दौरान अनुभव करने में प्राप्त होता है। प्राचीन शिक्षण में शिष्य का व्यक्तिगत प्रयत्न महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। तैत्तिरीय उपनिषद् में वरुण अपने पुत्र वृणु को केवल कुछ सामान्य संकेत दे देने है और उसको अपने आप

उन्हें समझने और जानने का आदेश देने हैं। छात्रों में आलोचना और जिज्ञासा उत्पन्न करना शिक्षण का प्रमुख अंग था।

स्वाध्याय और स्वशिक्षा तीन प्रकार की हो सकती है। उत्तम प्रकार की स्वशिक्षा श्रम, गाय और पृथ्वी की भाँति होती है, अर्थात् उत्तम स्वशिक्षा में छात्र हम की भाँति विवेकपूर्वक ज्ञानार्जन करता है, अथवा गाय की भाँति जुगापी करता है अर्थात् जो कुछ पकता है उस पर अनेक प्रकार से चिन्तन करने हुए विषय को आरमभान करता है, अथवा वह पृथ्वी के समान परिश्रम के अनुरूप फल देता है, मध्यम प्रकार की स्वशिक्षा में छात्र मोने के समान गूँथता है और पूट्टे पड़े के समान ज्ञान लपी जब को बहा देता है, अधम प्रकार की स्वशिक्षा वह है जिसमें छात्र भ्रम के समान मीखे गए ज्ञान को सँदना बना देता है। सुभाषित में कहा गया है कि जो छात्र बटख करता है, लिखता है, निरीक्षण करता है, प्रश्न करता है और विद्वानों की सगति में रहता है, उसकी बुद्धि का विकास उसी प्रकार हो जाता है, जैसे कमल का विकास सूर्य की किरणों से होता है।

विद्वान्तां, नियमों और सूक्ष्म विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए अध्यापक 'मूल में सूक्ष्म की ओर' या 'विशेष में सामान्य की ओर' जैसे सूत्रों का उपयोग करते थे। मरुतुन गाहिराय में अक्षर-विधान का महत्त्व इसी दृष्टि से है। उपमा, रूपक, उपेक्षा और हृष्टान्त का उपयोग शिक्षण में इसी सूत्रों के अनुसार किया जाता था। विषय को स्पष्ट करने के लिए कहानियाँ, पद्य-आख्यानों और हृष्टान्तों का उपयोग होता था। पंचतन्त्र और हितोपदेश के आरम्भ इस बात का प्रमाण है। शिक्षण की तीव्रता दूर करने में दूत तन्त्रों में बड़ी सहायता मिलती रही होगी। प्राचीन अध्यापकों ने अपने अनुभवों के आधार पर ही यह उपाय निकाले होते।

भारत में व्याख्यान-प्रणाली में शिक्षा देने का चयन बाद में आरम्भ हुआ। जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार से सम्बन्ध रखने वाली शिक्षा में व्याख्यान का महत्त्व बढ़ गया था। उसमें पहले भारत में व्यक्तिगत शिक्षण ही अधिक लोकप्रिय था। छात्र अध्यापक के पास अपनी कठिनाई लेकर उपस्थित होता था, प्रश्न करता था और अध्यापक उसे समझाता था। व्यक्तिगत मित्रता के अनुरूप शिक्षण में परिचर्चन कर लेने की क्षमता अध्यापकों में होती थी। पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के दुष्ट पुत्रों को पढ़ाने का दायित्व विष्णु शर्मा पर आ पड़ा। राजकुमार कनूवरबाजी के शौरीन थे। इस व्यसन के अनिरक्त उन्हें कोई दूसरा काम पसंद न था। चतुर विष्णु शर्मा ने तुरन्त शिक्षण का ढंग बदल दिया। उसने उनको कनूवर पालने और रखने को ही कहा। फिर उसने हर कनूवर के पंख पर देवनागरी की वर्णमाला लिख दिया और अक्षरों की सहायता से उन्हें बुद्ध कनूवरों के वर्णमाला पढ़ाने में सहायता दी।



चित्रकारी, वास्तु और शिल्प तक मिला दिया। शिक्षण में छात्र की आवश्यकता और रचि के प्रयोग का यह अनुपम उदाहरण है।

भारत में योजना-विधि में पढ़ाई का ढंग प्रचलित था। 'यज्ञ' एक वैश्विक योजना थी जिसमें सभी छात्र मिल-जुल कर सीखते थे। यज्ञ के लिए शारीरिक और मानसिक त्रियाएँ तथा प्रवृत्तियाँ निर्दिष्ट थी और छात्रों को सहयोगपूर्वक उन्हें पूरा करना पड़ता था। ग्रीस के माक्रेटोन की शिक्षण विधि जो 'डायलेक्टिक' विधि कहलाती है और जिसमें विरोधी के विचारों का खंडन करके अपने विचारों का प्रतिपादन अध्यापक करता था, बौद्धकाल में यहाँ प्रचलित थी। स्वयं महाराम बुद्ध ने इसका प्रयोग किया था। एक बार ३००० छात्रों को शिक्षा देने वाला निगरोध नामक परिब्राजक बुद्ध जी की परीक्षा लेने आया और उनमें वह उनके निर्वाण मिद्धान्त की व्याख्या करने का आग्रह करने लगा। उसका विचार था कि बुद्ध जी के मन का तड़न हो सकेगा क्योंकि वे एकान्तवासी होने के कारण सभा में साम्प्रार्थ पद्धति में अनभिज्ञ होंगे। बुद्ध जी ने बड़ी अनुरता से निगरोध के मिद्धान्तों पर ही चर्चा आरम्भ की और उनका खंडन करते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया।

व्याख्यान विधि का समुचित विकास बौद्धकाल में हुआ। जूनेमाग के वर्णनों में ज्ञात होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए १०० मंच बने थे। उन मंचों में भाषण हुआ करते थे और उन भाषणों को विद्यार्थी सुनते थे। इनकी प्रसिद्धि सर्वत्र थी। छात्रों और आचार्यों के बीच व्यतिरिक्त सम्पर्क भी रहता था। 'एथेटोरियल' की प्रथा उस समय थी। इसमें वे अपने वर्णनों में लिखा है कि किस प्रकार वह अध्यापकों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करता था। छात्र पहले अध्ययन करके 'मोटम' ले लेते थे और बाद में उनके आधार पर अध्यापक से विचार-विमर्श करने थे। बाद-विवाद और विचार-विनिमय शिक्षण की प्रमुख विधियाँ थी जिनका प्रयोग नालंदा विश्वविद्यालय में प्रतिदिन होता था। जूनेमाग ने ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है जिनमें बाद-विवाद के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। एक बार जूनेमाग के अध्यापक शीलभद्र ने उसे योगशास्त्र के कुछ पहलू समझाने की आज्ञा दी। जब वह इस पर परिचर्या करने लगा तो एक अन्य विद्वान् 'मिधरसामी' ने उसके विरुद्ध विचारों का प्रतिपादन करना आरम्भ किया। दोनों में बाद-विवाद हुआ और मिधरसामी को हाँकर नालंदा में भागना पड़ा।

भारत में 'सिशन' का एक उच्चकोटि का उपाय था—'मोनोटोरियल' प्रणाली। इसका विकास गुप्तकाल में हुआ और बाद में मद्रास राज्य में इसका प्रयोग उस समय तक होता रहा जब तक अंग्रेज यहाँ आने लगे थे। बेल नामक अंग्रेज ने इस प्रणाली को बहुत उपयोगी समझा क्योंकि इसमें अध्यापकों की कमी की समस्या दूर की जा सकती है और माधुरता प्रसार में इसका उपयोग हो सकता है। बेल ने इंग्लैंड में इस प्रणाली का विकास किया और वह इतिहास में बेल-सिस्टम प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में यह अपने शुद्ध रूप में भारत में ही विकसित हुई। दग

तत्कालीन शिक्षण में इन्द्रियनिग्रह पर अत्यधिक बल दिया जाता था। आज कल मनोविज्ञान मानवीय प्रवृत्तियों का दमन हानिकारक बनाना है। इस दृष्टि से प्राचीन शिक्षा में छात्रों का जीवन जो अत्यधिक दमन और सहज प्रवृत्तियों के अवरोधन पर निर्भर था, कुछ अपनोर्वैज्ञानिक जैविकता है परन्तु आधुनिक मनोविज्ञान भी प्रवृत्तियों के उपशयन और बोधन को उचित मानता है। इस समय छात्रों को किस प्रकार विलासितापूर्ण जीवन बिताने की सुझी छूट दे दी जाती है, उसके भयकर परिणाम अब दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा समस्याओं का बानाबस इस प्रकार नियोजित और नियन्त्रित होता था कि छात्रों की दुष्प्रवृत्तियों का स्वतः दमन हो जाता था। उनके मन में यह बात अच्छी तरह जमा दी जाती थी— 'सुवर्द्धिने कुतो विद्या, विद्याविन कुतो मुनयः'। प्राचीन भारतीय शिक्षण-सिद्धि में इन्द्रिय निग्रह पर बल देने का एक प्रमुख कारण यह था कि युरोपीय शिक्षाविदों की भाँति भारतीय शिक्षाविदों ने यह कभी नहीं माना कि मनुष्य का मन शुभ्य है (Tabula Rasa के सिद्धान्त से वे सहमत न होंगे)। वे यह अवश्य मानते हैं कि ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से आने वाले प्रभाव मन पर पड़ने हैं परन्तु वे यह नहीं स्वीकार करते कि ज्ञानेन्द्रियों से आने वाले प्रभाव शुभ ही हैं, वास्तव में उनकी भावना यह है कि ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से आने वाले बाह्य प्रभाव उत्तेजक और बाधक होते हैं। उनका यह विचार था कि मनुष्य का मन सहज शक्ति-मय है और यदि उसे ध्यान, प्रार्थना और मुद्राचार के द्वारा त्रिषाणीय बना दिया जाय, तो उसका उत्तम रूप से विकास होगा। माय ही इस विकास पर ज्ञानेन्द्रियों के उत्तेजन युक्त प्रभावों का कुप्रभाव पड़ने पाये, इसलिए इन्द्रिय सुप्तों में छात्रों को दूर रखने का प्रयत्न किया जाना था। यही कारण है कि भारतीय शिक्षा में आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता बनी रही। शिक्षण में धर्म, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जैसे अष्टांगों का होना प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान के उपयुक्त विशेष दृष्टिकोण के कारण स्वाभाविक था। पातञ्जलि के योगसूत्र में इसका विवरण दिया हुआ है।

### भारतीय शिक्षा के उद्देश्य

प्राचीन भारतीय शिक्षा के किस आदर्शों का उल्लेख किया गया है, उनकी सम्प्राप्ति कोई सरल बात नहीं। इन महान् आदर्शों की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित और स्पष्ट उद्देश्य स्थिर किये गये थे। हमारे आचार्यों ने जीवन के रहस्य को समझा था, वे जानते थे कि मानव जीवन में भोग और त्याग का सन्तुलित समन्वय होना चाहिए, सभी जीवन की व्यवस्था वायव्य रह सकती है। इस सन्तुलन को बनाये रखने के लिए उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किये हैं। उन पर विशेष में प्रकाश डालना आवश्यक है—

(१) सर्वाङ्गीण विकास—यहाँ कहा गया है—'विद्या दयानि विनयं' अर्थात् विद्या विनय प्रदान करती है। आम तौर पर 'विनय' को एक गुण माना जाता है।

मुभाषित रत्नावली में कहा है—

मस्यनारित स्वयं प्रज्ञा शास्त्रोक्त कि करिष्यति  
 तोचमाभ्या विहोतस्य वर्णनः कि करिष्यति ।  
 वितरति गुरुः प्राप्ते विद्यां मयं व तथा ज्ञे  
 न च सखु तपोजनि शक्ति करोत्यपहन्ति वा ।

जिम व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, उसे छात्रन वचन बताने से क्या लाभ हो सकता है। जैसे अन्धे को दीया दिखाने में कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार बुद्धिहीन व्यक्ति को शिक्षा देने में कोई लाभ नहीं है। (यही बात लो मिरिसवर्ट जैसे विद्वानों ने अपने बुद्धि परीक्षकों द्वारा सिद्ध की है।) अध्यापक जड़ और बुद्धिवान् दोनों को समान रूप में शिक्षा देना है, वह इन दोनों के ज्ञान में वृद्धि या कमी करने में समर्थ नहीं है।

स्पष्ट है कि प्राचीन शिक्षा में बुद्धि तत्त्व के महत्त्व को पहचान कर ही शिक्षा देने का विधान था। गुरुकुलों में छात्रों की प्रारम्भिक परीक्षा लेकर ही उनकी भर्ती की जाती थी।

शिक्षा में वातावरण के नियन्त्रण पर विशेष बल दिया जाता था। उस युग में आचार्यों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि परिवार का शिक्षा की दृष्टि में अत्यधिक महत्त्व है। यदि परिवार में बच्चे का सात्वत-भाव न हो, तो उसका बौद्धिक तथा हर प्रकार का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यही बात इधर पायड आदि में सामने रखी है परन्तु परिवार के वातावरण को बिना प्रकार शिक्षा की दृष्टि में नियोजित किया जाय, इस पर यूरोपीय विद्वान् कोई स्वल्प योजना बनाने में सफल नहीं हो पाये हैं जबकि प्राचीन भारत में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया। गर्भाधान में लेकर गुरुकुल में जाने की आयु तक शिक्षा की दृष्टि में कई संस्कार निश्चित किये गये थे, जैसे गर्भाधान, भीमस्नोषण, ज्ञानकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, वृद्धावर्ध इत्यादि। इन संस्कारों का उद्देश्य यह था कि बालक के आत्ममनोबोध (Self concept) और अहं के विकास (Ego development) में कोई बाधा न पड़े और भावी शिक्षा के लिए गृष्टभूमि तैयार हो जाय।

प्राचीन भारतीय शिक्षा में शोदन (Maturation), तैयारी का सिद्धान्त (Principle of Readiness) और विकास (Growth) आदि मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। इसीलिए यहाँ औपचारिक शिक्षा आरम्भ करने की आयु निश्चित थी। यहक में कहा था कि पाँच वर्ष की आयु के बाद विद्यारम्भ का समय ठीक रहता है। किन्तु पुत्रों के अनुसार पाँच वर्ष तक बच्चे को गणना बालिका और उसके बाद पढ़ाई आरम्भ की जाय। बुद्धि बुद्धि बालकों के लिए तीन वर्ष की आयु में वर्तमान और गणना का ज्ञान बनाने की अनुमति थी। विद्यारम्भ की आयु निश्चित करने का उद्देश्य यह था कि बच्ची उम्र में शिक्षा आरम्भ कर देने में सक्षम पर अनुचित दबाव पड़ता है।

तत्कालीन शिक्षण में इन्द्रियनिग्रह पर अत्यधिक बल दिया जाता था। आज कल मनोविज्ञान मानवीय प्रवृत्तियों का दमन हानिकारक बताया है। इस दृष्टि से प्राचीन शिक्षा में छात्रों का जीवन जो अत्यधिक दमन और सहज प्रवृत्तियों के अवरोधन पर निर्भर था, कुछ अमनोवैज्ञानिक ज्ञेयता है परन्तु आधुनिक मनोविज्ञान भी प्रवृत्तियों के उपशमन और बोधन को उचित मानता है। उन समय छात्रों की शिक्षा प्रकार विषयानुसार जीवन विधान की सुर्ती छूट दे दी जाती है, उनके भयक परिणाम अथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा सत्याग्रहों का वातावरण इस प्रकार नियोजित और नियन्त्रित होता था कि छात्रों की दुष्प्रवृत्तियों का स्वतः दमन हो जाता था। उनके मन में यह बात अच्छी तरह जमा दी जाती थी— 'मुखाग्निं कुतो विद्या, विद्याग्निं कुतो मुक्षम्'। प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति में इन्द्रिय निग्रह पर बल देने का एक प्रमुख कारण यह था कि यूरोपीय शिक्षाविदों की भाँति भारतीय शिक्षाविदों ने यह कभी नहीं माना कि मनुष्य का मन धूर्ण है (Tabula Rasa के सिद्धान्त में वे सहमत न होंगे)। वे यह अवश्य मानते हैं कि ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से आने वाले प्रभाव मन पर पड़ने हैं परन्तु वे यह नहीं स्वीकार करते कि ज्ञानेन्द्रियों से आने वाले प्रभाव शुभ ही हैं, वास्तव में उनकी मान्यता यह है कि ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से आने वाले बाह्य प्रभाव उत्तेजक और बाधक होते हैं। उनका यह विचार था कि मनुष्य का मन महज शक्ति-मण्डल है और यदि उसे ध्यान, प्रार्थना और गुहाचार के द्वारा क्रियाशील बना दिया जाय, तो उनका उत्तम ढंग में विकास होगा। माय ही इस विकास पर ज्ञानेन्द्रियों के उत्तेजन युक्त प्रभावों का कुप्रभाव न पड़ने पाये, इसलिए इन्द्रिय मुखों में छात्रों को दूर रखने का प्रयत्न किया जाता था। यही कारण है कि भारतीय शिक्षा में आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता बनी रही। शिक्षण में धर्म, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रणालार, धारणा, ध्यान और समाधि जैसे अष्टांगों का होना प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान के उपर्युक्त विमोह दृष्टिकोण के कारण स्वाभाविक था। पारंगत के योगसूत्र में इसका विवरण दिया हुआ है।

### भारतीय शिक्षा के उद्देश्य

प्राचीन भारतीय शिक्षा के त्रिन आदर्शों का उल्लेख किया गया है, उनकी सम्प्राप्ति कोई सरल बात न थी। इन महान् आदर्शों की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित और स्पष्ट उद्देश्य स्थिर किये गये थे। हमारे व्याचार्यों ने जीवन के रहस्य की समझाया था, वे जानते थे कि मानव जीवन में भोग और त्याग का मूलनित समन्वय होना चाहिए, सभी जीवन की स्वस्थता वायव्य रहे सकती है।

के लिए उद्देश्य शिक्षा के

आवश्यक

अर्थात्  
जाना है।

'गर्व' का विलोम है 'विनय'। अभिमानमूल्य होना विनय है। यह उग्र शब्द का संकुचित अर्थ है। विनय शब्द 'नी' धातु से वि उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। इसका वास्तविक अर्थ है—“विशेष रूप से मे जाना” अर्थात् मनुष्य की मूल्य आन्तरिक शक्तियों को बहिर्गत करना। शिक्षा का उद्देश्य है—मनुष्य की प्रमुख शक्तियों का समुचित विकास करना। यह उद्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल है। प्राचीन शिक्षा छात्रों के सर्वाङ्गीण विकास के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ प्रस्तुत करती थी। विकास की दृष्टि से ही मनुष्य के जीवन को चार आधमों में विभाजित कर दिया गया और ब्रह्मचर्य आश्रम को शिक्षा के लिए अलग कर दिया गया। इस काल में ब्रह्मचर्य का पालन करके शारीरिक विकास को, पारि-रिक सुखों और सामाजिक प्रबोधनों में दूर रख कर मानसिक विकास को और गुरुगृह में स्नेह प्रदान करके संवेगात्मक विकास को चरम सीमा तक पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता था। यह सब इसलिए किया जाता था कि छात्रों के मन में किसी प्रकार का समर्प पंदा न होने पाये और उनके विकास में कोई अवरोध न उत्पन्न हो।

(२) ज्ञान-प्राप्ति—भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था—ज्ञान-प्राप्ति। 'विद्या' अर्थात् शिक्षा को ज्ञान-प्राप्ति का साधन माना गया है। विद्या दो प्रकार की बताई गई है। एक है—अपरा विद्या जिसके अन्तर्गत चारों वेदों और छ वेदांगों का अध्ययन आ जाता है। दूसरी विद्या है पराविद्या जिससे 'आत्मन्' का ज्ञान प्राप्त होता है। 'अपरा' और 'परा' दोनों प्रकार की विद्या महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके द्वारा अज्ञान का विनाश होगा है परन्तु अपरा विद्या 'ज्ञान' नहीं प्राप्त करा सकती। पराविद्या 'आत्मन्' का ज्ञान कराती है और यही श्रेष्ठ है। अपरा विद्या केवल लौकिक है और पुण्यकीय ज्ञान प्राप्त करा सकती है, इसलिए यह श्रेष्ठ नहीं है। छान्दोग्य उपनिषद् में एक स्थान पर नारद मनकुमार से कहते हैं कि मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ महाकाव्य, पुराण, व्याकरण, गणित, आध्यात्म, इतिहास, तत्त्वशास्त्र, नीति, धर्मशास्त्र, ज्योतिष और ललित कलाएँ—सभी कुछ निखा है। मैं 'मन्त्रविद्' तो हूँ पर 'आत्मविद्' नहीं। इसलिए मैं दुःखी हूँ।

सच्चे ज्ञान का अर्थ यह है कि मनुष्य को आत्मविद् होना चाहिए। इसलिए वेद-वेदांगों के अध्ययन का अर्थ आनर्जन नहीं है। छान्दोग्य में श्वेनकेतु की कथा में यही प्रकट होता है। श्वेनकेतु ने १२ वर्षों तक सभी वेदों का अध्ययन किया था परन्तु उसमें ज्ञान नहीं पैदा हुआ। शब्दज्ञानमात्र में आत्मज्ञान नहीं पैदा होता; पुण्यको के पदों, मन्त्रों के रटने, उनकी व्याख्या करने, कर्मकांड की क्रिया जानने में कुछ नहीं होता। गृहदाण्ड्यक और तैत्तिरीय उपनिषदों में इन सबको सुच्छ मूल्यता धनया गया है। 'आत्मज्ञान' क्या है? इसकी व्याख्या करना सहज नहीं है। प्राचीन साहित्य में इसकी व्यापक नीर में चर्चा की गई है। 'आत्मन्' का स्वरूप सहज बोधगम्य नहीं है।

अन' इस प्रसंग को उठाना अप्रासंगिक है। 'आत्मन्' के स्वर्ण्य को समझाना और उसे समझने की शक्ति प्रदान करना प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।

(३) जीवन की पूर्णता—शिक्षा को सम्पूर्ण जीवन के लिए तैयार करने का साधन माना गया है। जीवन की पूर्णता चार बातों की निष्ठि पर निर्भर है, वे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह जीवन के चार पुरुषार्थ हैं। इन्हें मिट्ट करने के लिए मनुष्य को तैयार करना भारतीय शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। पाश्चात्य देशों में जीवन केवल दो में से एक ही दिशा में चले की प्रणाली थी और है, या तो मनुष्य सम्पूर्ण रूप में सुखवादी बनता है या फिर पूर्ण रूप में निग्रह और निवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। जीवन की यह दोनों दिशाएँ एकान्ती हैं और एक दिशा में जाना जीवन को असंतुलित बनाना है। भारत में जीवन की पूर्णता इन दोनों विरोधी मार्गों के बीच समन्वय करके उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है, जिसका प्रमाण यह चार पुरुषार्थ हैं। भारतीय जीवन में नीतिक्रिया और पागनीक्रिया दोनों का सुन्दर समावेश भी है कि जहाँ मनुष्य धर्म और मोक्ष की साधना करके तपस और सुखोपभोग में दूर निग्रह की स्थिति में आता है, वहाँ 'अर्थ' और 'काम' की साधना करके सासारिक सुखों का पूरा आनन्द भी लेता है। शिक्षा के माध्यम में इन पुरुषार्थों का महत्व छात्रों के सामने स्पष्ट किया जाता था।

महामातृ के शिक्षाप्रद प्रसंगों में कहा गया है—“धर्म, अर्थ और काम का समान रूप में मेवना करना। जो पुरुष इनमें से एक का ही मेवना करता है, वह कनिष्ठ है। इनमें से दो करने वाला मध्यम है और जो तीनों में लगा है वह उत्तम है।” “मनुष्य को केवल धर्मपरायण नहीं होना चाहिए, और अर्थपरायण भी नहीं होना चाहिए, उन्ही तरह कामपरायण भी नहीं होना चाहिए। दिन के पूर्व भाग में धर्म, मध्य भाग में अर्थ और अन्तर्भाग में काम आचरण करना—यह दाम्भिकृत विधि है।”

इन पुरुषार्थों को मिट्ट करने के लिए भारतीय शिक्षा में कई स्तरों की ओर छात्र का ध्यान आकर्षित किया जाता था। महाभारत में कहा ही गया है कि प्रतिदिन मनुष्य इन पुरुषार्थों का साधन करे, प्रातः धर्म, दोपहर अर्थ, दिनान्त में काम का साधन किया जाय। मानव जीवन की चार आध्रभों के बीच गुजारने की शिक्षा एक दूमरा स्तर है। सम्पूर्ण जीवन के स्तर पर इन पुरुषार्थों का साधन करने के लिए ही आश्रम व्यवस्था बनायी गयी। इसके अनुसार जीवन के प्रथम तपः में अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम में मनुष्य को धर्म साधन, अर्थ और काम साधन तथा मोक्ष के रहस्यों का परिचय आदि के बारे में बताया जाता था। जीवन की सम्पूर्णता प्राप्त करने का यह समय था। गृहस्थाश्रम जीवन का वह काल है जिसमें मनुष्य अर्थ और काम का साधन करे तथा वानप्रस्थ और मन्त्याम आश्रमों में मोक्ष की ओर अग्रसर हो। समाज के स्तर पर भी इन पुरुषार्थों का साधन करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गयी, यद्यपि भारतीय समाज में हर व्यक्ति के लिए चाहे पुरुषार्थों का साधन

आवश्यक माना गया था पर अतिमूल्य क्षमता की दृष्टि में ब्राह्मण के लिए धर्म तथा मोक्ष, शीतल के लिए काम और वेदा के लिए अर्थ का मापन आवश्यक था। इस प्रकार जीवन की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के वर्ग के लिए प्रथम-प्रथम तरह की शिक्षा का विधान था।

(४) चरित्र-निर्माण और अनुशासन - प्राचीन भारतीय शिक्षा का चौथा उद्देश्य था, मनुष्य का चरित्र-निर्माण तथा आन्तरिक अनुशासन की शक्ति पैदा करना। विद्यार्थी जीवन में छात्र जिस प्रकार का संयमपूर्ण तथा बड़ी-बड़ी शक्तिमान बनना था, उसका वर्णन हम दृष्टि अपेक्षा के पूर्व भाग में कर चुके हैं। उस वर्णन में क्या चलना है कि हर छात्र को चरित्र निर्माण बनाने के लिए ही अनेक प्रकार के इन्द्रियसंयम गुणों में दृढ़ रहना पड़ना था। धीरे-धीरे उसे ऐसा अभ्यास ही जाना था कि वह अपनी चित्तवृत्तियों और प्रवृत्तियों को स्वयं नियंत्रण करने लगता था। यही मन्वा अनुशासन भी था। महाभारत में कई स्थानों पर कहा गया है—“शिक्षा मे उत्तम चरित्र और आचरण उत्पन्न होता है।” युधिष्ठिर ने यश में कहा था कि “यश, गुणों। ब्राह्मण (विद्यार्थी) बनने के लिए उच्च शैक्षिक चरित्र त्रिपदा आवश्यक है, उनका ‘जानि’ अथवा ‘विद्वत्ता’ नहीं। अतः हर एक को जोर दिव्य रूप में ब्राह्मण को बड़ी मावधानी से चरित्र का निर्माण करना चाहिए। यदि किसी ब्राह्मण का चरित्र भ्रष्ट है, तो वह दूध है। चाण्डाल मृत्ति में कहा गया है कि जो मनुष्य कुछ आचरण बिहीन है, उसे वेद भी पवित्र नहीं बना सकते। मनुस्मृति में लिखा है कि स्मृति और श्रुति के द्वारा जो मनुष्य बड़ा गुण मनुष्य में पैदा होता है, वह है चरित्र। उत्तम आचरण में ही ब्राह्मण को वेद पाठ का ध्येय नहीं मिलता है। कौटिल्य कहते हैं कि अध्ययन और अनुशासन जो शान्तिद्वय के नियंत्रण पर निर्भर हैं, कामना, क्रोध, लोभ, मान, मद और ईर्ष्या का त्याग कर देने में अधिक सफल बन जाते हैं। जो चरित्रहीन है और जिसकी इन्द्रियाँ उसके बस में नहीं हैं, वह शीघ्र ही भ्रष्ट हो जायगा, चाहे चाहे दिशाओं तक फैली हुई पृथ्वी का वह स्वामी हो। अत्रि ने कहा है कि पाँच प्रकार के ब्राह्मण (विद्यार्थी)—प्रारम्भिक, चापलूस, धोखेबाज, क्रूर और लोभी कभी भी प्रशंसनीय नहीं हैं, चाहे ज्ञान में वे बृहस्पति के समान बनें ॥ हो। युष्मन्तीतिमात्र में कहा गया है कि इन्द्रियों के हाथी को, जो मोक्ष पदार्थों के बीच विनाशायक गति में दीड-धूप करना रहता है, ज्ञान के अकुल में अनुशासन में रखना चाहिए।

प्राचीन भारतीय शिक्षा में चरित्र पर अत्यधिक बल दिया गया था और चरित्र का अर्थ आत्मानुशासन था। इसके साथ ही चरित्र का सम्बन्ध कर्तव्यपालन में भी जोड़ा गया था। ऐसी कल्पना अन्यत्र मिलना कठिन है। भारत में कर्तव्यपालन को ‘ऋण की अदायगी’ के समान आवश्यक माना गया था। विद्यार्थी जीवन हर छात्र के मन में यह बात अच्छी तरह जमा दी जानी थी कि उसे तीन प्रकार ऋण अपने जीवन काल में अदा करने हैं। इन्हें अदा करना उसका परम कर्तव्य







### अध्यासार्थ प्रश्न

१. प्राचीन भारत में शिक्षा को कबो अधिक महत्त्व प्रदान किया गया था ? तत्कालीन समय में शिक्षा के उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालिए ।
२. प्राचीन भारतीय शिक्षा मार्क्सवादी थी अथवा बुद्ध दृष्टि योग्य के लिए ? अपने उत्तर के पक्ष में नर्क दीजिए ।
३. शिक्षा और जीवन के पारस्परिक सम्बन्ध पर और देने में प्राचीन काल में भारत को क्या लाभ मिला ? कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए ।
४. प्राचीन भारतीय शिक्षार्थी जीवन के आदर्श की विवेचना कीजिए । उस आदर्श को पुनः अपनाया कहाँ तक उचित है ?
५. आधुनिक अध्यापक और प्राचीन भारतीय अध्यापक की तुलना कीजिए । आप दोनों में से किसे पसन्द करते हैं और क्यों ?
६. शिक्षण-तन्त्र का क्या स्वरूप प्राचीन भारत में प्रचलित था ? उसमें तथा वर्तमान शिक्षण-तन्त्र में क्या भेद है ?
७. प्राचीन शिक्षण-तन्त्र किस सीमा तक मनोवैज्ञानिक थी ? कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए ।
८. प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का स्पष्ट करने हुए उनके महत्त्व पर प्रकाश डालिए ।



